वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

जून 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक

© Reserve Bank of India
All rights reserved. Reproduction is permitted provided an acknowledgment of the source is made.

The publication can also be accessed through Internet at **https://www.rbi.org.in**

Feedback of this report may be mailed to **cgmfsd@rbi.org.in**

Published by Financial Stability Department, Reserve Bank of India, Mumbai 400 001 and designed and printed at Jayant Printery LLP, 352/54, Girgaum Road, Murlidhar Temple Compound, Near Thakurdwar Post Office, Mumbai - 400 002.

प्राक्कथन

वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली को दो बड़ी ताकतें बदल रही हैं—बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में तेज़ी से हो रही उन्नति से आया तकनीकी बदलाव। लगातार संघर्षों और आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों के बावजूद, वैश्विक अर्थव्यवस्था मज़बूत बनी हुई है—जिसमें एआई के फलस्वरूप उत्पादकता बढ़ने की उम्मीदों का भी योगदान है। हालांकि, तेज़ी से बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच निकट भविष्य का नज़रिया अनिश्चित बना हुआ है।

इस माहौल में, वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम ज़्यादा बने हुए हैं। महंगाई के दबाव के कारण बड़ी विकसित अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों को आक्रामक नीति अपनानी पड़ सकती है, जिससे वैश्विक वित्तीय हालात और कड़े हो सकते हैं। साथ ही, ज़्यादा सरकारी कर्ज़, बॉन्ड मार्केट की कमज़ोरी, आस्तियों के बहुत ज़्यादा मूल्यांकन और लेवरेज्ड गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थों की बढ़ती मौजूदगी भविष्य के दबावों के असर को बढ़ा सकती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली ने बड़े बाहरी आघातों का सामना करने के बावजूद मज़बूती दिखाई है। मज़बूत वृद्धि, कम महंगाई, वित्तीय और गैर-वित्तीय कंपनियों के बेहतर तुलनपत्र और पर्याप्त बफ़र्स ने व्यापक -वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में मदद की है। फिर भी, हम बदलते बाहरी और घरेलू जोखिमों को लेकर सतर्क हैं और अपनी अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली को संभावित आघातों से बचाने वाले सुरक्षा उपायों को और मज़बूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का यह संस्करण घरेलू वित्तीय प्रणाली की मज़बूती को पुन: पुष्टि करता है। बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान मज़बूत बने हुए हैं, जिन्हें मज़बूत पूँजी और चलनिधि की स्थिति, बेहतर लाभप्रदता-क्षमता, अनर्जक आस्तियों का कम स्तर और मज़बूत ऋण वृद्धि का सहारा मिला है। दबाव परीक्षण यह बताते हैं कि वित्तीय संस्थान कठिन आघातों का सामना करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण उतार-चढ़ाव के बावजूद, वित्तीय बाज़ार व्यवस्थित तरीके से काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर, वित्तीय प्रणाली वास्तविक अर्थव्यवस्था और भारत की संवृद्धि की गति के लिए मज़बूती और समर्थन का एक मुख्य स्रोत बना हुआ है।

हम मानते हैं कि प्रतिकूल बाहरी आघातों का जोखिम बढ़ गया है, जिसमें भू-राजनीतिक संघर्षों और तनाव नीति-निर्माताओं के लिए मुख्य चुनौतियां बनकर उभरे हैं। इस माहौल में, वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, वित्तीय प्रणाली को मज़बूत करना और प्रणाली की आघात -सहनीयता को मज़बूत करना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है।

हम समझते हैं कि वित्तीय प्रणाली में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए सिर्फ़ वित्तीय व्यवस्था का विवेकपूर्ण मज़बूत बने रहना ही पर्यपात नहीं है। निष्पक्ष व्यवहार को बढ़ावा देने वाली और ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने वाली नीतियां भी उतनी ही ज़रूरी हैं। इसलिए, हमारा उद्देश्य अपरिवर्तित है : हम एक ऐसी वित्तीय प्रणाली बनाना चाहते हैं जो न सिर्फ़ मज़बूत और स्थिर हो, बल्कि कुशल, समावेशी और गतिशील भी हो—एक ऐसी प्रणाली जो अच्छी तरह से काम करने वाली अर्थव्यवस्था में कारोबारों और परिवारों को भाग लेने और आगे बढ़ने में मदद करे।

संजय मल्होत्रा
गवर्नर
30 जून 2026

विषय-वस्तु

		पृष्ठ सं.
प्राक्कथन		
चुनिंदा संक्षेपाक्षरों की सूची		**i-iv**
विहंगावलोकन		**1**
अध्याय I	**: समष्टि वित्तीय जोखिम**	**3**
	ग्लोबल और घरेलू पृष्ठभूमि	3
	ग्लोबल समष्टि वित्तीय संवेदनशीलता	6
	बॉन्ड मार्केट भंगुरता	7
	उच्च परिसंपत्ति मूल्य निर्धारण और संकेंद्रित एक्स्पोज़र	9
	एनबीएफ़आई से उत्पन्न जोखिम	13
	घरेलू समष्टि आर्थिक स्थिति	**15**
	वित्तीय बाजार	19
	बैंकिंग प्रणाली	32
	एनबीएफ़सी क्षेत्र	38
	कॉर्पोरेट क्षेत्र	41
	घरेलू क्षेत्र	44
	उपभोक्ता क्रेडिट खंड	47
	बॉक्स 1.1: साइबर जोखिम और वित्तीय स्थिरता	**52**
	बॉक्स 1.2: उधारकर्ता आघात -सहनीयता – आय स्तर विश्लेषण	**56**
अध्याय II	**: वित्तीय संस्थान: सुदृढ़ता और आघात-सहनीयता**	**60**
	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी)	60
	जमाराशियां और ऋण	61
	आस्ति गुणवत्ता	63
	क्षेत्रवार आस्ति गुणवत्ता	64
	बड़े उधारकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता	64
	आय और लाभप्रदता	66
	पूंजी पर्याप्तता	68
	चलनिधि-	70
	आघातसहनीयता – समष्टि दबाव परीक्षण	70
	संवेदनशीलता विश्लेषण	72
	लघु वित्त बैंकों का संवेदनशीलता विश्लेषण- क्रेडिट जोखिम	78
	बॉटम-अप दबाव परीक्षण: डेरिवेटिव पोर्टफोलियो	79
	बॉटम -अप दबाव परीक्षण : ऋण ,बाजार और चलनिधि जोखिम	80
	प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक	**82**
	दबाव परीक्षण	85
	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)	**86**
	दबाव परीक्षण - ऋण जोखिम	91
	दबाव परीक्षण- संक्रेंदण जोखिम	92
	दबाव परीक्षण -चलनिधि जोखिम	92
	म्यूचुअल फंड के लिए दबाव परीक्षण	93
	समाशोधन निगमों पर दबाव परीक्षण का विश्लेषण	94

		पृष्ठ सं.
	वित्तीय नेटवर्क और संक्रमण विश्लेषण	94
	वित्तीय प्रणाली नेटवर्क	95
	संक्रमण विश्लेषण	102
	बीमा क्षेत्र	**103**
	आकार और संरचना	104
	वित्तीय दृढ़ता	106
	परिदृश्य विश्लेषण	114
	बीमा क्षेत्र में दबाव के उभरते क्षेत्र	119
अध्याय III	**: वित्तीय क्षेत्र में विनियामकीय पहल**	**120**
	वैश्विक विनियामकीय पहल	120
	बैंकिंग	120
	गैर -बैंक वित्तीय मध्यस्थता (एनबीएफ़आई)	121
	वित्तीय बाजार	122
	विकेंद्रीकृत वित्त और डिजिटल आस्ति	122
	जलवायु वित्त	123
	कृत्रिम बुद्धिमत्ता	123
	घरेलू विनियामकों/प्राधिकरणों की पहलें	124
	संबंधित पक्ष को ऋण देने से संबंधित निर्देश	124
	भारत में जमा बीमा के लिए जोखिम-आधारित प्रीमियम ढांचा	124
	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	124
	विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता में (बैंक) जमा के लिए स्वैप सुविधा	125
	बाह्य वाणिज्यिक उधार और विदेशी मुद्रा में विदेश से उधार के लिए स्वैप सुविधा	125
	प्राधिकृत डीलर की खुली स्थिति /जोखिम की स्थिति	125
	वित्तीय बाज़ार में विशिष्ट पहचानकर्ता – निर्देश	126
	भारतीय रिज़र्व बैंक (आरक्षित नकदी निधि अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) द्वितीय संसोधन के निर्देश , 2026	126
	जोखिम प्रबंधन और अंतर -बैंक लेनदेन	126
	अधिकृत डीलर श्रेणी – I बैंकों द्वारा संबंधित पक्ष के लेनदेन की रिपोर्टिंग – निर्देश	127
	वाणिज्यिक बैंकों के लिए आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और आय मान्यता पर निर्देश	127
	पर्यवेक्षी अनुदेशों का समेकन	127
	'आरक्षित निवेश में उतार-चढ़ाव पर संशोधन' संबंधित निर्देश	127
	27 अप्रैल, 2026 को जारी किए गए भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - ऋण जोखिम के लिए पूंजी प्रभार – मानकीकृत दृष्टिकोण) निदेश, 2026	127
	वित्तीय क्षेत्र में क्वांटम प्रौद्योगिकियां	128
	केवाईसी (केवाईसी) निर्देश, 2025 में संशोधन	128
	प्रौद्योगिकी-सक्षम केवाईसी: ग्राहक सुविधा और जोखिम प्रबंधन के बीच संतुलन	129
	वित्तीय क्षेत्र साइबर सुरक्षा रणनीति – प्रगति पर अद्यतन	129
	विश्वसनीय विदेशी निवेशकों के लिए स्वचालित और सामान्यकीकृत पहूंच एकल विंडो (स्वागत -एफ़आई) – एफपीआई और एफवीसीआई के लिए रूपरेखा	129

		पृष्ठ सं.
	बाजार अवसंरचना संस्थानों (एमआईआई) के अभिशासन को सुदृढ़ करने से संबंधित प्रावधान।	129
	भारत में एनआरआई के लिए पुन: केवाईसी करने में भू-टैगिंग की अपेक्षा में छूट।	130
	निवेश करने में सुगमता – भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और अमूर्तिकरण के लिए विशेष प्रावधान।	130
	सेबी (व्यापार बैंकर) विनियमन, 1992 में संशोधन और ऐसे संशोधनों के संबंध में पारिणामिक अपेक्षाओं का विनिर्दिष्टीकरण।	130
	गूगल प्ले स्टोर पर सेबी के साथ पंजीकृत ब्रोकरों के स्टॉक ट्रेडिंग ऐप्स के लिए 'सत्यापित लेबल'।	130
	परियोजना सुदर्शन - कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रेरित धोखाधरी को चिन्हित करना।	130
	किसी अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामक के क्षेत्राधिकार में आने वाले वित्तीय साधनों की रेटिंग करते समय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) पर दायित्व	131
	बीमा क्षेत्र में भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी एएस) का कार्यान्वयन	131
	आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन) विनियमन ,2024 के तहत जारी मास्टर परिपत्र में संशोधन	131
	नीतिधारक शिक्षा और संरक्षण कोष की स्थापना	132
	वार्षिक शुल्क के भुगतान और पंजीकरण के प्रमाणपत्र (मध्यस्थ) जारी करने के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्था	132
	सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान मोटर थर्ड पार्टी (एमटीपी) बीमा पर अभियान (11 से 17 जनवरी, 2026)	132
	स्वास्थ्य बीमा परिदृश्य में प्रणालीगत मुद्दों को हल करने के उपाय	132
	बीमाकर्ताओं के निवेश के लिए नियामक विकास	132
	बुनियादी ढांचा क्षेत्र में शामिल पब्लिक लिमिटेड विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) में निवेश	133
	आईएफएससीए (निधि प्रबंधन) (संशोधन) विनियमन, 2026	133
	अन्य गतिविधियां	133
	उभरते फ्रंटियर एआई मॉडल का विकास	133
	ग्राहक संरक्षण	134
	प्रवर्तन	135
	जमा बीमा	136
	कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया	137
	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में विकास	140
	पेंशन फंड	141
अनुबंध 1	: **कार्यविधियाँ**	143
अनुबंध 2	: **महत्वपूर्ण घरेलू विनियामकीय उपाय**	160
	भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)	160
	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)	162
	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई)	168
	पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)	170
	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)	171
	अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफ़एससीए)	175

पृष्ठ सं.

चार्ट की सूची

अध्याय I

1.1	वित्तीय बाजार में आशावाद	3
1.2	बाजार निहित मौद्रिक नीति पथ	4
1.3	भुगतान संतुलन	5
1.4	वित्तीय बाजारों का परीक्षण किया गया, लेकिन सुदृढ़ बने रहे	6
1.5	भारत की सुदृढ़ समष्टि आर्थिक मूलभूत	7
1.6	वैश्विक सार्वजनिक ऋण बढ़ रहा है, जबकि राजकोषीय घाटा अधिक बना हुआ है	8
1.7	बॉन्ड यील्ड में वृद्धि	8
1.8	बॉन्ड बाजार की प्रवृत्ति	9
1.9	उच्च लेवरेज के बीच सॉवरेन के लिए हेज फंड के एक्सपोज़र में वृद्धि	10
1.10	वित्तीय बाजार आशावादी बना हुआ है	10
1.11	उच्च आस्ति मूल्य -निर्धारण और संकेंद्रित एक्सपोज़र	11
1.12	एआई कंपनियों द्वारा बढ़ता ऋण वित्तपोषण	13
1.13	कैरी ट्रेड द्वारा संचालित पूंजी प्रवाह	13
1.14	ग्लोबल एनबीएफआई फुटप्रिंट का विस्तार	14
1.15	अमेरिकी ट्रेजरी बाजार में सापेक्ष मूल्य ट्रेड	14
1.16	निजी क्रेडिट फंड से बाहर निकलने की कोशिश में खुदरा निवेशक	15
1.17	चालू खाता में रुझान	16
1.18	पूंजीगत लेखा में रुझान	17
1.19	सीमित बाह्य भेद्यता (वलनरेबिलिटी) और पर्याप्त आरक्षित	18
1.20	तेल की कीमत के आघात से उत्पन्न राजकोषीय दबाव	19
1.21	विदेशी मुद्रा बाजार के रुझान	19
1.22	मौद्रिक नीति संचरण में सतत कुछ घर्षण	21
1.23	सॉवरेन बॉन्ड मार्केट में रुझान	22
1.24	सरकारी बॉन्ड बाजार में मांग-आपूर्ति की गतिशीलता	23
1.25	भारतीय इक्विटी बाजार प्रदर्शन और स्वामित्व	24
1.26	बढ़ी हुई भू-राजनीतिक जोखिमों के बीच एफपीआई इक्विटी का बहिर्वाह	25
1.27	संस्थागत मांग द्वारा लचीला इक्विटी बाजार बैकस्टॉप	26
1.28	मूल्यांकन में मॉडरेशन और आय डाउनग्रेड	26
1.29	निफ्टी 50 – प्रतिफल अपघटन	27
1.30	प्रतिफल और बैंक ऋण में वृद्धि के बीच कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करने में गिरावट	27
1.31	कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के रुझान	28
1.32	कॉर्पोरेट बॉन्ड स्प्रेड और रेटिंग	29
1.33	घरेलू म्यूचुअल फंड उद्योग का बढ़ता एयूएम	30
1.34	आघात सह एसआईपी प्रवाह	30
1.35	म्यूचुअल फंड स्कीम में निवल प्रवाह	31
1.36	घरेलू निष्क्रिय निधि प्रवाह	31

पृष्ठ सं.

1.37	सुदृढ़ वित्तीय , बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करते हैं	32
1.38	आस्ति की गुणवत्ता और ऋण लागत में सुधार से ऋण वृद्धि को बढ़ाना	33
1.39	देयता प्रोफ़ाइल विकसित करना और निधियों की लागत पर प्रभाव	33
1.40	लाभप्रदता और चलनिधि पर घटती जमा फ्रेंचाइजी का प्रभाव	34
1.41	सीएएसए की साझीदारी में गिरावट के बावजूद बैंकों ने अपने मार्जिन दबाव को नरम किया	35
1.42	अनुकूल आस्ति गुणवत्ता के साथ सुदृढ़ ऋण वृद्धि	35
1.43	सूक्ष्म वित्त क्षेत्र - सक्रिय उधारकर्ताओं में गिरावट के बीच ऋण में सुधार	36
1.44	बैंकिंग प्रणाली आघात -सह बनी हुई है	37
1.45	एनबीएफसी क्षेत्र - प्रमुख वित्तीय मापदंड	38
1.46	सुदृढ़ खुदरा ऋण और कम ऋण लागत के बीच एनबीएफसी की ऋण वृद्धि में कमी	38
1.47	एनबीएफसी ने फंडिंग लागत को नियंत्रित करने के लिए अपने फंडिंग विकल्पों को पुनर्संतुलित किया	39
1.48	एनबीएफसी में आस्ति गुणवत्ता में सुधार	40
1.49	एमएसएमई और सूक्ष्म वित्त क्षेत्रों को एनबीएफसी ऋण	40
1.50	फिनटेक फर्मों ने बढ़ते अपराध के बीच छोटे मात्रा वाले व्यक्तिगत ऋण आरंभ किए	41
1.51	गैर-बैंकिंग स्थिरता संकेतक और मानचित्र	41
1.52	सांकेतिक बिक्री वृद्धि - सूचीबद्ध निजी गैर-वित्तीय कंपनियां	42
1.53	सूचीबद्ध निजी कॉरपोरेट्स की ऋण-उपयोगिता	42
1.54	सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों के अनुपात का चयन करें	43
1.55	निजी कॉर्पोरेट निवेश और क्षमता का उपयोग	43
1.56	भारत का घरेलू ऋण अपेक्षाकृत कम है और मुख्य रूप से गैर-आवास खुदरा ऋणों से प्रेरित	44
1.57	उपभोग ऋण की आवास ऋण से अधिकता	45
1.58	बढ़ते लेवरेज़ के साथ गोल्ड लोन से अभिप्रेरित पुनरावृत्त उपभोक्ता	45
1.59	उपभोक्ता खंड के ऋण की वृद्धि मजबूत बनी हुई है	46
1.60	उपभोक्ता खंड के ऋण के आस्ति की गुणवत्ता में सुधार	47
1.61	गोल्ड लोन से अभिप्रेरित उपभोक्ता खंड ऋण में वृद्धि	48
1.62	बढ़ते लेवरेज़ के साथ गोल्ड लोन से अभिप्रेरित पुनरावृत्त उपभोक्ता	49
1.63	Gold Loans Driven by Repeat Customers with Rising Leverage	50
1.64	बैंक और गैर-बैंक के एलटीवी अनुपात में सुधार	51
1.65	जोखिम भरे उधारकर्ता श्रेणियों में बढ़ते गोल्ड लोन और व्यक्तिगत ऋण में संतुलन	51

अध्याय II

2.1	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की जमाराशियां एवं ऋण प्रोफ़ाइल	61
2.2	चुनिंदा आस्ति गुणवत्ता संकेतक	63
2.3	क्षेत्रवार आस्ति गुणवत्ता संकेतक	65
2.4	बड़े उधारकर्ताओं के चुनिन्दा आस्ति गुणवत्ता संकेतक	66
2.5	एससीबी के चुनिन्दा निष्पादन संकेतक	67

पृष्ठ सं.

2.6	पूंजी पर्याप्तता	69
2.7	चलनिधि अनुपात	70
2.8	व्यापक परिदृश्य आकलन	71
2.9	सीईटी1 पूंजी अनुपात का पूर्वानुमान	71
2.10	सीआरएआर पूर्वानुमान	72
2.11	जीएनपीए अनुपात का अनुमान	72
2.12	ऋण जोखिम – आघात एवं परिणाम	73
2.13	ऋण संकेंद्रण जोखिम- उधारकर्ता एक्स्पोज़र	74
2.14	शीर्ष 100 उधारकर्ताओं द्वारा प्रदर्शित ऋण संकेंद्रण जोखिम	74
2.15	एएफ़एस और एफ़वीटीपीएल (एचएफ़टी सहित) पोर्टफोलियो और बैंक-समूहों का हिस्सा	75
2.16	एचटीएम पोर्टफ़ोलियो – रचना	76
2.17	एचटीएम पोर्टफ़ोलियो –31 मार्च 2026 तक अप्राप्त लाभ/हानि	76
2.18	इक्विटी मूल्य जोखिम – प्रणाली स्तर सीआरएआर में गिरावट	77
2.19	एलसीआर आधारित चलनिधि दबाव परीक्षण	78
2.20	एसएफ़बी के लिए ऋण जोखिम – आघात एवं परिणाम	79
2.21	कुल डेरिवेटिव पोर्टफोलियो (पी एंड एल पर प्रभार्य) का निवल एमटीएम	80
2.22	चुनिंदा बैंकों के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर आघातों का एमटीएम प्रभाव	80
2.23	डेरिवेटिव पोर्टफोलियो से आय	81
2.24	ऋण और बाज़ार जोखिम	81
2.25	चलनिधि जोखिम – चलनिधि आस्ति अनुपात	82
2.26	यूसीबी – कार्यनिष्पादन और स्वास्थ्य संकेतक	82
2.27	यूसीबी के दबाव परीक्षण	85
2.28	एनबीएफसी - प्रमुख वित्तीय मापदंड	87
2.29	एनबीएफ़सी – लेयर वार - प्रमुख वित्तीय मापदंड	89
2.30	एनबीएफ़सी में क्रेडिट जोखिम -प्रणाली स्तर	92
2.31	क्रेडिट संक्रेंदण जोखिम – एक्सपोजर	92
2.32	एएमसी द्वारा एएमएफआई निर्धारित सीमाओं से अधिक बनाए गए एलआर-आरएआर और एलआर-सीआरएआर की रेंज (अधिशेष (+)/ घाटा (-)) (प्रति शत)	93
2.33	वित्तीय प्रणाली में संस्थाओं के बीच द्विपक्षीय एक्सपोजर	96
2.34	वित्तीय प्रणाली में संस्थाओं के बीच लिखत-वार एक्सपोजर	97
2.35	वित्तीय प्रणाली का नेटवर्क प्लॉट – मार्च 2026	97
2.36	संस्थाओं की श्रेणियों द्वारा निवल प्राप्य (+)/देय (-)	98
2.37	अंतर-बैंक बाज़ार	98
2.38	निधि आधारित अंतर बैंक बाजार की संरचना	99
2.39	भारतीय बैंकिंग प्रणाली की नेटवर्क संरचना (एससीबी+एसयूसीबी) – मार्च 2026	99
2.40	बैंकिंग प्रणाली (एससीबी) के कनेक्टिविटी सांख्यिकी	100
2.41	वित्तीय प्रणाली से एएमसी-एमएफ की सकल प्राप्तियां - शीर्ष 4 उधारकर्ता समूहों की साझीदारी	100

पृष्ठ सं.

2.42	वित्तीय प्रणाली से बीमा कंपनियों की सकल प्राप्तियां - शीर्ष 3 उधारकर्ता समूहों की साझीदारी	100
2.43	वित्तीय प्रणाली को एनबीएफ़सी का सकल देय	101
2.44	वित्तीय प्रणाली को एचएफ़सी का सकल देय	101
2.45	वित्तीय प्रणाली को एआईएफ़आई की सकल देयता	102
2.46	समष्टि आर्थिक आघातों का संक्रामक प्रभाव	104
2.47	कुल प्रीमियम	104
2.48	बाज़ार साझेदारी	105
2.49	एयूएम का निधि वार घटक	105
2.50	निधि वार वृद्धि दर	106
2.51	जीवन – निवेश स्तर वार घटक	106
2.52	समान्य – निवेश स्तर वार घटक	107
2.53	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा भुगतान किए गए लाभ	107
2.54	गैर-जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा किए गए निवल दावे	108
2.55	जीवन बीमाकर्ता का व्यय	108
2.56	गैर-जीवन बीमाकर्ता का व्यय	109
2.57	शीर्ष 10 जीवन बीमाकर्ताओं की निधि वार सकल प्रतिफल	109
2.58	शीर्ष 10 जीवन बीमाकर्ताओं की सकाल प्रतिफल	110
2.59	जीवन और सामान्य बीमाकर्ताओं के इक्विटि शेयर पूंजी	111
2.60	जीवन बीमाकर्ताओं की लाभप्रदता	111
2.61	सामान्य बीमाकर्ताओं की लाभप्रदता	112
2.62	जीवन और सामान्य बीमाकर्ताओं की शिकायतें	113
2.63	शीर्ष 10 जीवन बीमाकर्ताओं के एएसएम की संरचना	114
2.64	शीर्ष 10 सामान्य बीमाकर्ताओं के एएसएम की संरचना	115
2.65	शीर्ष 10 जीवन बीमाकर्ताओं के एएसएम के लिए परिदृश्य विश्लेषण	116
2.66	शीर्ष 10 सामान्य बीमाकर्ताओं के एएसएम के लिए परिदृश्य विश्लेषण	117
2.67	शीर्ष 9 निजी जीवन बीमाकर्ताओं के लिए नियामक न्यूनतम ऋण शोधन क्षमता से अधिक पूंजी बफर	118
2.68	शीर्ष 10 सामान्य बीमाकर्ताओं के लिए नियामक न्यूनतम ऋण शोधन क्षमता से अधिक पूंजी बफर	118

अध्याय III

3.1	एनपीएस और एपीवाई – अभिदाता और एयूएम प्रवृत्ति	141
3.2	एनपीएस और एपीवाई एयूएम: आस्ति श्रेणी-वार विभाजन	142

पृष्ठ सं.

सारणी की सूची

अध्याय I

1.1 बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) प्रवाह 18
1.2 भारतीय प्रतिभूति बाजार के माध्यम से संसाधन जुटाना 24
1.3 व्यक्तिगत ऋण - जोखिम श्रेणियों के लिए स्कोर माइग्रेशन 46

अध्याय II

2.1 हेल्थ ट्रैकर– अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) 61
2.2 संवेदनशीलता विश्लेषण – उद्योग उप-क्षेत्र स्तर 75
2.3 एएफ़एस और एफ़वीटीपीएल (एचएफ़टी सहित) पोर्टफोलियो का पीवी 01 75
2.4 ब्याज दर जोखिम – बैंक-समूहों पर दबाव परीक्षण का असर 76
2.5 अन्य परिचालन आय - प्रतिभूति व्यापार पर लाभ/हानी
2.6 अर्निंग्स एट रिस्क (ईएआर) – पारंपरिक अंतराल विश्लेषण (टीजीए) 77
2.7 इक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीई) – अवधि अंतराल विश्लेषण (डीजीए) 77
2.8 एनबीएफ़सी की निधियों के श्रोत 89
2.9 एनबीएफ़सी में चलनिधि जोखिम 93
2.10 म्यूचुअल फंड की ओपन-एंडेड डेट योजनाओं का दबाव परीक्षण – सारांश निष्कर्ष – मार्च 2026 93
2.11 एमएफ मिडकैप और स्मॉलकैप योजनाओं के तनाव परीक्षण और तरलता विश्लेषण का सारांश 94
2.12 समाशोधन निगमों में तनाव परीक्षण विश्लेषण के आधार पर कोर एसजीएफ का न्यूनतम आवश्यक कॉर्पस 95
2.13 बैंक की विफलता के कारण संक्रमण संबंधी हानियां- मार्च 2026 102
2.14 एनबीएफसी की विफलता के कारण संक्रमण संबंधी हानियां- मार्च 2026 103
2.15 एचएफ़सी की विफलता के कारण संक्रमण संबंधी हानियां- मार्च 2026 103
2.16 जीवन बीमा – ऋण शोधन क्षमता 113
2.17 सामान्य बीमा - ऋण शोधन क्षमता 113
2.18 आघात परिदृश्य 115
2.19 ऋण शोधन क्षमता का जीवन बीमाकर्ता-वार वितरण 116
2.20 ऋण शोधन क्षमता का सामान्य बीमाकर्ता-वार वितरण 117

अध्याय III

3.1 आरबी-आईओएस, 2021 के तहत प्राप्त शिकायतों की श्रेणी 134
3.2 शिकायतों का प्रकार/श्रेणी
3.3 SmartODR.in पर विवादों की स्थिति 135
3.4 बीमा भरोसा पर शिकायत 135
3.5 बीमा ओम्बड्समेन में शिकायतें 136
3.6 जमाराशियों की कवरेज 136
3.7 बैंक समूहवार जमा सुरक्षा कवरेज 137
3.8 जमा बीमा प्रीमियम 137
3.9 जमा बीमा निधि और आरक्षित निधि अनुपात 137
3.10 कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की स्थिति 138
3.11 सीआईआरपी का क्षेत्र-वार वितरण 139
3.12 हितधारक-वार आरंभ की गई सीआईआरपी के परिणाम 139

चुनिंदा संक्षेपाक्षरों की सूची

एई	उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ
एएफ़एस	बिक्री के लिए उपलब्ध
एआई	कृत्रिम बुद्धिमत्ता
एआईएफ	वैकल्पिक निवेश निधि
एआईएफआई	अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान
एएलएम	आस्ति देयता प्रबंधन
एएमसी	आस्ति प्रबंधन कंपनियां
एएमएफआई	एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया
एपीवाई	अटल पेंशन योजना
एएसएम	उपलब्ध ऋण शोधन क्षमता मार्जिन
एयूसी	अभिरक्षा में संपत्ति
एयूएम	प्रबंधनाधीन आस्तियां
बीसीबीएस	बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति
बीआईएफआर	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड
बीपीएस	आधार अंक
बीएसआई	बैंकिंग स्थिरता संकेतक
सीएडी	चालू खाता घाटा
सीएपीई	चक्रीय समायोजित कीमत अर्जन
सीएएसए	चालू खाता और बचत खाता
सीसीआईएल	भारत के समासोधन निगम लिमिटेड
सीसीबी	पूंजी संरक्षण बफर
सीसीआईएल	भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड
सीसीपी	केंद्रीय प्रतिपक्षकार
सीसीआरआई	ऋण संकेंद्रण जोखिम सूचकांक
सीसी	समाशोधन निगम
सीडी	जमा प्रमाणपत्र
सीडी	कॉर्पोरेट ऋणी
सीईटी -1	कॉमन इक्विटी टियर-1
सीजीएस	केंद्रीय सरकार प्रतिभूति
सीआईसी	मूल निवेश कंपनियां
सीआईआरपी	कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया
सीकेवाईसीआर	सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री
सीएम	समाशोधन सदस्य (क्लियरिंग मेंबर्स)
सीओसी	ऋणदाताओं की समिति
मूल एसजीएफ	मूल निपटान गारंटी निधि
सीपी	वाणिज्यिक पत्र
सीपीआई	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीआरएआर	जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात
सीआरआर	आरक्षित नकदी निधि अनुपात
डीडीएम	लाभांश डिस्काउंट बिल
डीजीए	अवधि अंतराल विश्लेषण
डीआईसीजीसी	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
डीआईआई	घरेलू संस्थागत निवेशक
डीआईएफ	जमा बीमा निधि
डीपीडी	देय तिथि से अधिक
डीटीआई	आय पर ऋण
डीएसआर	कर्ज चुकौती अनुपात
ईएआर	जोखिम पर अर्जन
ईबीपीटी	लाभ और कर-पूर्व अर्जन
ईसीबी	बाह्य वाणिज्यिक उधार
ईसीएल	प्रत्याशित ऋण हानि
ईडी	कार्यपालक निदेशक
ईएमई	उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाएँ
ईपीएस	प्रति शेयर अर्जन
ईआरपी	इक्विटी जोखिम प्रीमियम
ईएसजी	पर्यावरणीय, सामाजिक और अभिशासन
ईटीएफ़	एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड
एफ़एटीएफ़	वित्तीय कार्रवाई कार्यबल
एफबी	विदेशी बैंक
एफडीआई	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश
एफएमई	निधि प्रबंधन संस्थाएं
एफ़ओएफ़	फ़ंड ऑफ फ़ंडस
एफपीआई	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक

एफ़पीआईस	विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों
एफएसबी	वित्तीय स्थिरता बोर्ड
एफएसडीसी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद
एफएसडीसी-एससी	वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उप-समिति
एफ़एसआर	वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट
एफएसएसआई	वित्तीय प्रणाली दबाव संकेतक
एफ़वीटीपीएल	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य
जी20	20 देशों का समूह
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीईएनआईयूएस एक्ट	अमेरिकी अधिनियम के लिए राष्ट्रीय नवाचार मार्गदर्शन और स्थापना
जीआईसी आरई	भारत का साधारण बीमा निगम
जी-सेक	सरकारी प्रतिभूतियाँ
एचएफसी	आवास वित्त कंपनियां
एचएफटी	ट्रेडिंग के लिए धारित
एचक्यूएलए	उच्च गुणवत्ता युक्त चलआस्तियां
एचटीएम	परिपक्वता तक धारित
आईएसी	बीमा सलाहकार सामिति
आईएआई	भारतीय बीमांकक संस्थान
आईबीबीआई	भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
आईसीएआई	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
आईसीआर	ब्याज व्याप्ति अनुपात
आईडी	बीमाकृत जमाराशियाँ
आईएफ़एससी	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र
आईएफएससीए	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण
आईएफ़आर	निवेश उतार चढ़ाव आरक्षित निधि
आईआईबीएक्स	इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज
आईआईएफ़	अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान
आईआईपी	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति
आईएम	सूचना ज्ञापन
आईएमएफ	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
इंड एएस	भारतीय लेखांकन मानक
आईएनआर	भारतीय रुपया
आईएनवीआईटी	अवसंरचना निवेश न्यास
आईओएससीओ	अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन
आईपीए	दिवाला पेशेवर संघ
आईपीओ	प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव
आईक्यूआर	इंटर क्वाटर रेंज
आईआरएसीपी	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानिकरण
आईआरडीएआई	भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
आईएसएसबी	अंतर्राष्ट्रीय संधारणीयता मानक बोर्ड
आईयू	सूचना उपयोगिता
जेईजी	संयुक्त विशेषज्ञ समूह
केएफएस	मुख्य तथ्य विवरणी
केएमपी	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक
केवाईसी	अपने ग्राहक को जानिए
एलबीएमए	लंदन बुलियन मार्केट एसोसिएशन
एलसीआर	चलनिधि कवरेज अनुपात
एलजीडी	चूक पर हानि
एलआर – सीआरएआर	चलनिधि अनुपात - जोखिम पर सशर्त मोचन
एलआर – आरएआर	चलनिधि अनुपात - जोखिम पर मोचन
एलटी	दीर्घावधि
एलटीवी	मूल्य से ऋण
एमडी	संशोधित अवधि
एमडीजी	संशोधित अवधि अंतराल
एमडी	मास्टर निदेश
एमएफ	म्यूचुअल फंड
एमआईआई	बाजार अवसंरचना संस्थान
एमएल	धन शोधन
एमपीसी	मौद्रिक नीति समिति

एमआरसी	न्यूनतम आवश्यक निधि
एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एमटीएम	बाजार भाव पर दर्शाना
एमवीई	इक्विटी का बाजार मूल्य
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
एनएवी	निवल आस्ति मूल्य
एनएबीएफआईडी	राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी
एनबीएफसी-एमएल	मध्यम स्तर की एनबीएफसी
एनबीएफसी-यूएल	उच्च स्तर की एनबीएफसी
एनबीएफआई	गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यस्थ
एनबीएसआई	गैर-बैंकिंग स्थिरता संकेतक
एनसीडीसी	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
एनडीटीएल	निवल मांग और मीयादी देयताएं
एनजीएफएस	वित्तीय प्रणाली को हरित बनाने के लिए नेटवर्क
एनजीएनएफ	गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियां
एनजीएस	गैर-सरकारी क्षेत्र
एनएचबी	राष्ट्रीय आवास बैंक
एनआईसी	राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण
एनआईआई	निवल ब्याज आय
एनआईएम	निवल ब्याज मार्जिन
एनएनपीए	निवल अनर्जक आस्तियां
एनओआई	निवल परिचालन आय
एनओपी -आईएनआर	रुपए सहित निवल मुक्त स्थिति
एनपीए	अनर्जक आस्तियां
एनपीएल	अनर्जक ऋण
एनपीएस	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली
एनएसडीएल	नेशनल सिक्युरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड
एनएसई आईएक्स	एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज
एनएसएफआर	निवल स्थिर निधीयन अनुपात
एनएसओ	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय
एनटीसी	ऋण के लिए नवीन
एनएसयूसीबी	गैर अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक
ओईसीडी	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन
ओएफ़सीबी	विदेशी मुद्रा उधारियाँ
ओआईएस	ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वैप
ओएमओ	खुला बाजार परिचालन
ओओआई	अन्य परिचालन आय
ओआरबीआईओ	भारतीय रिज़र्व बैंक ओम्बड्समैन कार्यालय
पी & जी	पेंशन और समान्य वार्षिकी और समूह
पी/ई	आय के प्रति मूल्य
पीएटी	कर पश्चात लाभ
पीसीआर	प्रावधान कवरेज अनुपात
पीडी	प्राथमिक व्यापारी
पीएफआरडीए	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
पीएमएल	धन शोधन निवारण
पीओपी	उपस्थिति बिन्दु
पीपीएम	निजी स्थान नियोजन ज्ञापन
पीएसबी	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
पीएसएल	प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र उधार
पीएसओ	भुगतान प्रणाली परिचालक
पीवीबी	निजी क्षेत्र के बैंक
क्यूसी	क्वांटम कम्प्यूटिंग
आरएसी	पुनर्बीमा सलाहकार समिति
आरबीसी	जोखिम आधारित पूंजी
आरबीआई	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरबी-आईओएस,2021	रिज़र्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021
आरबीपी	जोखिम आधारित प्रीमियम
आरईआईटी	भू-संपदा निवेश न्यास
आरईपीओ	पुनर्खरीद लेनदेन
आरई	विनियमित संस्थाएं
आरओए	आस्तियों पर प्रतिलाभ

आरओडी	चूककर्ताओं के अभिलेख
आरओई	इक्विटी पर प्रतिलाभ
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरएसए	दर संवेदनशील आस्तियां
आरएसएल	दर संवेदनशील देयताएँ
आरएसएम	अपेक्षित ऋण शोधन मार्जिन
आरडबल्यूए	जोखिम भारित आस्तियां
एसएएचआई	एकल स्वास्थ्य बीमाकर्ता
एससीबी	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
एसडी	मानक विचलन
एसडीआई	प्रतिभूतिकृत ऋण लिखत
एसडीएल	राज्य विकास ऋण
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
एसएफबी	लघु वित्त बैंक
एसजीएफ	निपटान गारंटी निधि
एसजीएस	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां
एसआईपी	सुनियोजित निवेश योजनाएँ
एसएलआर	सांविधिक चलनिधि अनुपात
एसएमए	विशेष उल्लेख खाते
एसएम आरईआईटी	लघु एवं मध्यम भू-संपदा निवेश न्यास
एसओसी	सुरक्षा परिचालन केंद्र
एसपीडी	एकल प्राथमिक डीलर
एसआरटी	कृतिम जोखिम अंतरण
एसएसई	सोशल स्टॉक एक्सचेंज
एसटी	अल्पकालिक
एसयूसीबी	अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक
एसडबल्यूएजीएटी -एफ़आई	एकल विंडो ऑटोमैटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस (स्वागत -एफ़आई)
टीएफ़	आतंकवादी वित्तपोषन
टीजीए	पारंपरिक अंतराल विश्लेषण
यूसीबी	शहरी सहकारी बैंक
यूसीसी	अनापेक्षित वाणिज्यिक सम्प्रेषण
यूएलआईपी	यूनिट संबद्ध बीमा योजना
यूएस	संयुक्त राज्य अमेरिका
यूएसडी	यूएस डॉलर
वीएआरएक्स	बहिर्जात चर के साथ वेक्टर ऑटोरिग्रेशन
वीआरआर	स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग
वीआईएक्स	अस्थिरता सूचकांक
ओडीटीई	ज़ीरो डे टु एक्सपयर

विहंगावलोकन

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफ़एसआर) एक छमाही प्रकाशन है, जिसमें वित्तीय क्षेत्र के सभी विनियामकों का योगदान होता है। यह रिपोर्ट वित्तीय स्थिरता और विकास समिति की उप -समिति द्वारा भारतीय वित्तीय प्रणाली[1] की स्थिरता के लिए मौजूदा और उभरते जोखिमों के सामूहिक आकलन को प्रस्तुत करती है।

वैश्विक व्यापक-वित्तीय जोखिम

निरंतर आघातों के बावजूद, वैश्विक वित्तीय प्रणाली ने अब तक काफी मजबूती दिखाई है; पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद शुरुआती उतार-चढ़ाव के बावजूद बाजार स्थिर बने रहे हैं। बाजार में सकारात्मकता को तेल वायदा की कीमतों में उम्मीद से कम बढ़ोतरी, मजबूत कॉर्पोरेट आय अर्जन , एआई-संचालित निवेश में तेजी और आसान वित्तीय स्थितियों का समर्थन मिला है।

इसके बावजूद, वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम ऊंचे बने हुए हैं। संघर्ष को खत्म करने के लिए अंतरिम शांति समझौते के बावजूद, आपूर्ति श्रृंखला को लेकर बनी अनिश्चितताएं वित्तीय स्थितियों को कठिन बना सकती हैं और महंगाई के दबाव को बढ़ा सकती हैं, जिससे मौद्रिक नीति के नजरिए का फिर से आकलन करना पड़ सकता है। साथ ही, ऊंचे सरकारी कर्ज, बॉन्ड बाजार की कमजोरियों, आस्तियों के ऊंचे मूल्यांकन और लीवरेज्ड गैर -बैंक वित्तीय मध्यस्थों (एनबीएफ़आई) की बढ़ती भूमिका से पैदा होने वाले जोखिम भविष्य के आघातों को और बढ़ा सकते हैं। नतीजतन, जहां बाजार मजबूत बने हुए हैं, वहीं ऊंचे जोखिमों और बदलते व्यापक-वित्तीय जोखिमों का मेल वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए चुनौतियां पैदा करता रहता है।

घरेलू व्यापक -आर्थिक परिदृश्य

हालांकि पश्चिम एशिया में चल रहे टकराव के बीच अंतरिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने से मुश्किलें कम हो रही हैं, फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली भू-राजनीतिक तनाव और उससे जुड़े आघातों के प्रति संवेदनशील बने हुए हैं। अगर आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटें सामान्य होने में देरी और इन्वेंट्री को फिर से पूरा करने की अतिरिक्त मांग के कारण तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो विनिमय दर में उतार-चढ़ाव बढ़ सकता है। वैश्विक इक्विटी बाज़ार में बड़ी गिरावट - खासकर अगर यह कॉर्पोरेट आय -अर्जन में बढ़ोतरी के नए आकलन और एआई से जुड़े शेयरों के ऊंचे मूल्यांकन की वजह से हो - तो इसका असर घरेलू बाज़ार पर भी पड़ सकता है।

भारत के व्यापक -आर्थिक आधार अपने कई समकक्षों और पिछले संकट के दौर की तुलना में मजबूत हैं, जो इन आघातों का सामना करने के लिए ज़रूरी सुरक्षा कवच प्रदान करते हैं। पर्याप्त पूँजी और चलनिधि बफर के साथ मजबूत बैंक और गैर-बैंक तुलन-पत्र पर आधारित एक मज़बूत और लचीली वित्तीय प्रणाली एक मजबूत आधार प्रदान करता है। इसलिए, अनिश्चित वैश्विक माहौल के बावजूद, बाहरी आघातों से प्रणाली में वित्तीय दबाव पैदा होने और वास्तविक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने की संभावना सीमित बनी हुई है। इसके अलावा, पश्चिम एशिया टकराव में लड़ाई रुकने और पूँजी अंतर्वाह को मजबूत करने के उद्देश्य से सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा हाल ही में उठाए गए नीतिगत कदमों के कारण जोखिमों का संतुलन अनुकूल हो गया है।

वित्तीय संस्थान : मजबूती और लचीलापन

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) मजबूत बने रहे। उन्हें मजबूत पूँजी और चलनिधि बफ़र, आस्ति गुणवत्ता में लगातार सुधार (जिसमें अनर्जक आस्ति अनुपात कई दशकों के निचले स्तर पर आ गए) और स्थिर लाभप्रदता का सहारा मिला। 2025-26 की दूसरी छमाही में ऋण और जमा वृद्धि में तेज़ी आई। व्यापक दबाव परीक्षण के नतीजे बताते हैं कि यह क्षेत्र

[1] इस रिपोर्ट में 10 जून, 2026 तक उपलब्ध जानकारी शामिल है, जब तक कि स्पष्ट तौर पर कुछ और न बताया गया हो।

संभावित आघातों का सामना करने के लिए अच्छी स्थिति में है। मुश्किल हालात में भी कुल पूँजी अनुपात विनियामकीय सीमा से काफी ऊपर रहने का अनुमान है।

प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) ने आस्ति गुणवत्ता में सुधार और पर्याप्त पूंजीकरण के ज़रिए अपने तुलन -पत्र की स्थिति को मजबूत करना जारी रखा, भले ही लाभ प्रदता में थोड़ी कमी आई। दबाव परीक्षण के नतीजों से पता चलता है कि कुल मिलाकर यह क्षेत्र मजबूत बना रहा, हालांकि गंभीर आघातों के दौरान कुछ बैंकों में कमज़ोरियां देखी गईं।

मज़बूत पूंजीकरण, बेहतर लाभ-प्रदता और अच्छी होती आस्ति गुणवत्ता की वजह से गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफ़सी) आर्थिक रूप से मज़बूत बनी रहीं। दबाव परीक्षण के नतीजों से पता चलता है कि मुश्किल हालात में भी इस क्षेत्र की कुल पूँजी स्थिति विनियामकीय ज़रूरतों से काफ़ी ऊपर बनी रहेगी, हालाँकि कुछ कंपनियों को बहुत ज़्यादा दबावपूर्ण स्थितियों में तनाव का सामना करना पड़ सकता है। म्यूचुअल फंड और समाशोधन गृह के दबाव परीक्षण से भी उनकी मज़बूती की पुष्टि हुई, जबकि बीमा क्षेत्र भी अच्छी स्थिति में रहा। हालाँकि, अलग-अलग कंपनियों और क्षेत्रों के बीच बढ़ती आपसी निर्भरता, जो गहरे वित्तीय एकीकरण का संकेत है, आघातों के प्रसार का एक अतिरिक्त ज़रिया बन सकती है और इसलिए इस पर कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है।

वित्तीय क्षेत्र में विनियामकीय पहलें

2026 में वैश्विक विनियामकीय प्राथमिकताएं मौजूदा नियमों को असरदार ढंग से लागू करने और मज़बूत बनाने पर केंद्रित रही हैं। बैंकिंग क्षेत्र में, नीति से जुड़ी कोशिशें बेसल III को बेहतर ढंग से लागू करने, परिचालन जोखिम प्रबंध और समाधान की तैयारी पर केंद्रित रही हैं, साथ ही पर्यवेक्षी ज़रूरतों को आसान बनाने की कोशिशें भी की गई हैं। एनबीएफ़आई क्षेत्र में, नीति बनाने वालों ने लेवरेज, आपस में जुड़ाव, रेपो मार्केट की गतिविधियों और प्राइवेट क्रेडिट की तेज़ी से बढ़ती संवृद्धि से पैदा होने वाली संरचनागत कमज़ोरियों पर ज़्यादा ध्यान दिया है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय मानक तय करने वाली संस्थाओं ने डिजिटल आस्तियों, जलवायु वित्त और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी काम आगे बढ़ाया है।

घरेलू विनियामकीय कोशिशें 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (कारोबार में आसानी) को बढ़ावा देने, ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने, वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने, क्रेडिट के प्रवाह को बेहतर बनाने, यूसीबी को मज़बूत करने और वित्तीय बाज़ार को मजबूत बनाने के उपायों पर केंद्रित रही हैं। इसके साथ ही, प्राधिकारी ऑफ़-साइट निगरानी, कमज़ोरियों का आकलन, शुरुआती चेतावनी के संकेतकों, थीम-आधारित समीक्षाओं और माइक्रो-डेटा विश्लेषण के ज़रिए अपने पर्यवेक्षी प्रणाली को मज़बूत कर रहे हैं। कुल मिलाकर, सोच-समझकर और हालात के हिसाब से बदलने वाले विनियामकीय और निगरानी वाली संस्थाओं के जोखिम -आधारित और भविष्य को ध्यान में रखकर किए गए आकलन के ज़रिए, प्राधिकारियों का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली की मज़बूती को बेहतर करना है।

अध्याय I

समष्टि वित्तीय जोखिम

पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद वैश्विक वित्तीय परिस्थितियाँ अधिक सख्त हो गईं। यद्यपि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर बढ़ते आशावाद के कारण वित्तीय बाजारों में सुधार हुआ है, फिर भी बॉण्ड बाजार की कमजोरियों, आस्तियों के बढ़े हुए मूल्यांकन तथा गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थों की बढ़ती भूमिका जैसे खास नाजुक बिंदु नए आघातों के प्रभाव को बढ़ा सकते हैं और वैश्विक वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं। इसके विपरीत, वैश्विक अनिश्चितताओं के निरंतर बने रहने के बावजूद, देश की वित्तीय स्थिरता से जुड़े जोखिम अभी भी नियंत्रण में हैं। मजबूत पूंजी एवं चलनिधि बफरों तथा सतत ऋण वृद्धि से समर्थित घरेलू बैंकिंग प्रणाली की सुदृढ़ता से आर्थिक गतिविधियों को निरंतर सहारा मिल रहा है। तथापि, बार-बार आने वाले बाह्य आघात वित्तीय परिस्थितियों को और सख्त कर सकते हैं, जिससे समष्टि आर्थिक परिदृश्य तथा घरेलू वित्तीय स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना बन सकती है।

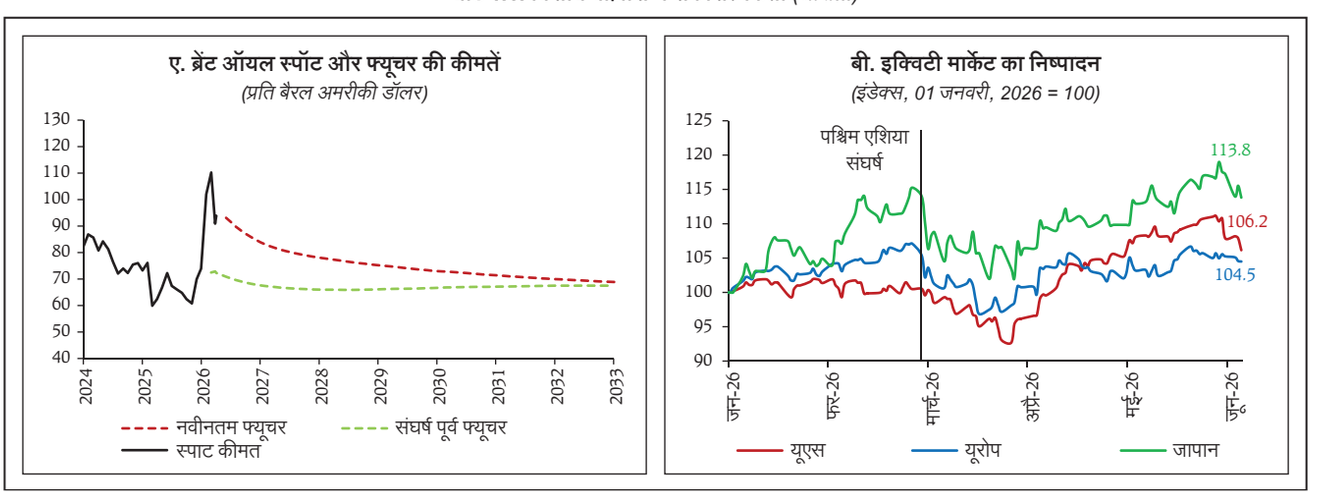
वैश्विक एवं घरेलू पृष्ठभूमि

1.1 वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट का यह संस्करण पश्चिम एशिया में हुए संघर्ष के चलते वैश्विक तथा घरेलू वित्तीय स्थिरता संबंधी जोखिमों का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। इस संघर्ष के कारण ऊर्जा तथा अन्य पण्यों (कमोडिटी) की कीमतों में तीव्र वृद्धि और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान उत्पन्न हुआ, जिससे वैश्विक एवं घरेलू दोनों अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष गंभीर चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं। यद्यपि अंतरिम शांति समझौते से परिदृश्य को लेकर अनिश्चितता में उल्लेखनीय कमी आई है, तथापि इसका वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि आपूर्ति श्रृंखलाओं का सामान्यीकरण किस सीमा तक और कितनी शीघ्रता से होता है।

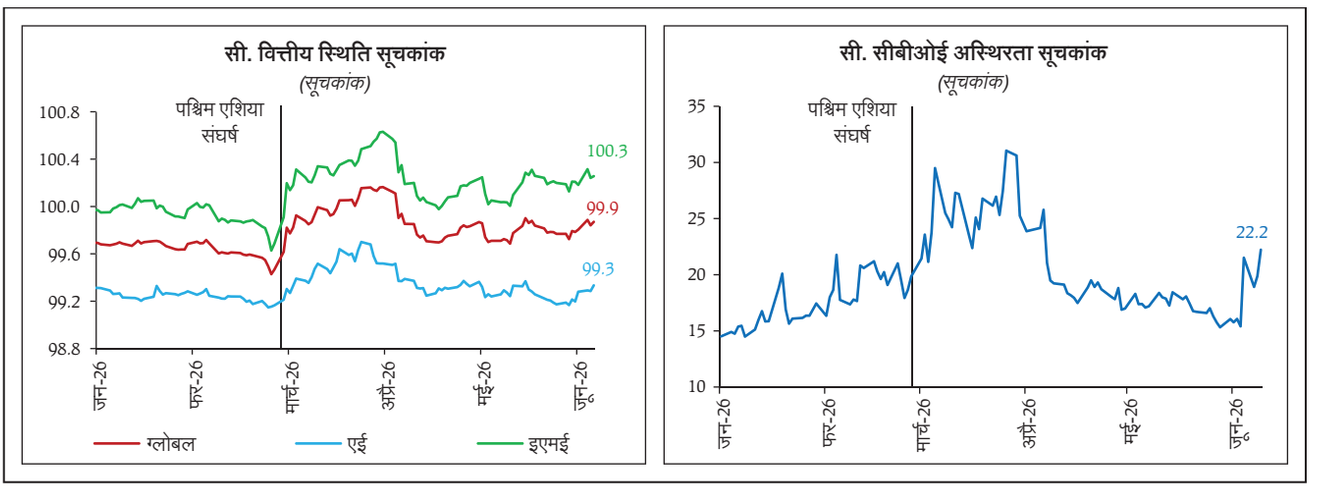
1.2 हाल के समय में लगातार आए एक के बाद एक झटकों के बावजूद वैश्विक वित्तीय प्रणाली ने उल्लेखनीय सुदृढ़ता दिखाई है। युद्ध के आरंभ में वित्तीय बाजारों में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिली थी, किंतु उसके बाद बाजार अपेक्षाकृत स्थिर और यथार्थपरक हो गया। कच्चे तेल के वायदा मूल्यों में अपेक्षा से कम वृद्धि, कंपनियों के मजबूत अर्जन (अर्निंग्स), कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रेरित उछाल तथा अनुकूल वित्तीय परिस्थितियों के संयुक्त प्रभाव ने बाजार में आशावाद को बनाए रखा है और अस्थिरता को नियंत्रित रखने में सहायता की है (चार्ट 1.1 ए, बी, सी और डी)।

1.3 तथापि, वैश्विक वित्तीय स्थिरता से जुड़े जोखिम अब भी उच्च स्तर पर बने हुए हैं। विभिन्न देशों द्वारा इन्वेंटरी के

चार्ट 1.1: वित्तीय बाज़ारों में सकारात्मकता *(जारी...)*



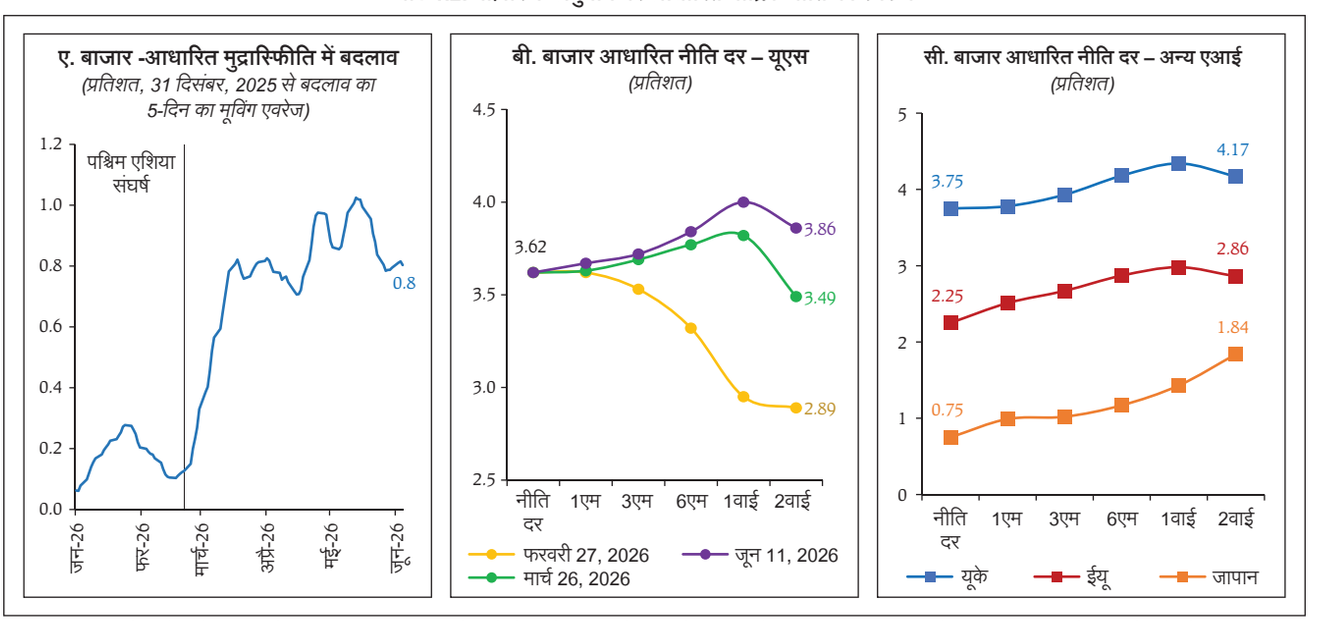
चार्ट 1.1: वित्तीय बाज़ारों में सकारात्मकता *(समाप्त...)*



Note: In chart (a), the latest futures curve is as on June 10, 2026; while pre-conflict futures curve is as on Feb 27, 2026.
Sources: Bloomberg; and Goldman Sachs.

पुनर्निर्माण के कारण, आपूर्ति श्रृंखलाओं के सामान्यीकरण की गति तेज होने के बावजूद ऊर्जा की कीमतें अपेक्षाकृत ऊँचे स्तर पर बनी रह सकती हैं। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में बाजार-आधारित मुद्रास्फीति अपेक्षाओं में वृद्धि, मुद्रास्फीति के बढ़ते जोखिम की ओर संकेत करती है। परिणामस्वरूप, बाजार की धारणा ब्याज दरों में कटौती की प्रत्याशा से हटकर ऐसी भावी मौद्रिक नीति की ओर जा रही है, जिसमें या तो कुछ अधिक अवधि तक दरों के यथास्थिति में रहने अथवा उनमें वृद्धि की गुंजाइश शामिल है (चार्ट 1.2 (ए), (बी) एवं (सी))। इससे वैश्विक वित्तीय परिस्थितियाँ और अधिक तंग हो सकती हैं। इसके साथ ही, बढ़ते सार्वजनिक ऋण, बॉण्ड बाजार की कमजोरियों, आस्तियों के उच्च मूल्यांकन तथा कृत्रिम

चार्ट 1.2: बाज़ार के अनुमान पर आधारित मौद्रिक नीति का स्वरूप



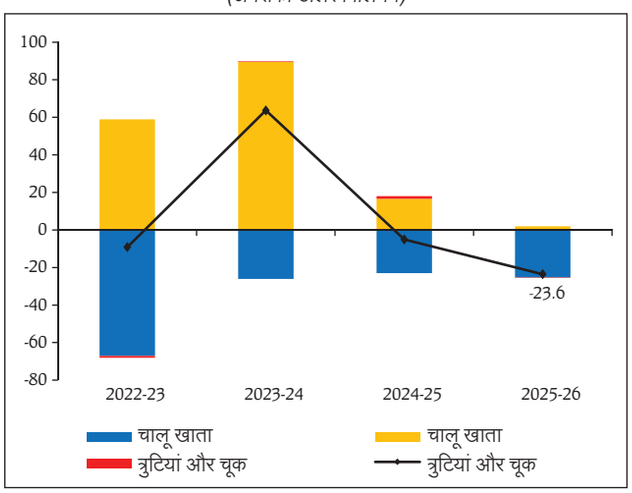
टिप्पणी: चार्ट (ए) में, मार्केट से पता चलने वाली महंगाई दर यूएस, यूके यूरोज़ोन और जापान के लिए दो साल की ब्रेक-ईवन महंगाई दर का औसत है। चार्ट (बी) और (सी) में, दरें ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) से ली गई हैं। डेटा 11 जून, 2026 का है।
स्रोत: ब्लूमबर्ग।

बुद्धिमत्ता में बड़े पैमाने पर निवेश के कारण उत्पन्न संकेंद्रित जोखिम से जुड़ी संवेदनशीलताएँ और अधिक स्पष्ट हो गई हैं। इसके अतिरिक्त, उधारी पर आधारित तथा कीमत संवेदी गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थों की बढ़ती उपस्थिति जोखिमों को और बढ़ाने का एक प्रमुख माध्यम बनी हुई है। इस प्रकार, नए आघातों से कमजोरियाँ उभर सकती हैं, जिससे वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा हो सकते हैं।

1.4 भारत के मजबूत समष्टि आर्थिक आधार बाहरी झटकों का सामना करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते हैं। फिर भी, कच्चे तेल तथा अन्य प्रमुख पण्यों के आयात पर अधिक निर्भरता के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था ऊर्जा कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बनी हुई है। वर्ष 2025-26 के दौरान चालू खाता घाटा प्रबंधनीय सीमा के भीतर रहा। हालांकि, समग्र भुगतान संतुलन (बीओपी) लगातार दूसरे वर्ष भी घाटे में रहा, जिसका मुख्य कारण पूंजी प्रवाह का कमजोर रहना था (चार्ट 1.3)।

चार्ट 1.3: भुगतान संतुलन

(अमरीकी डॉलर बिलियन)

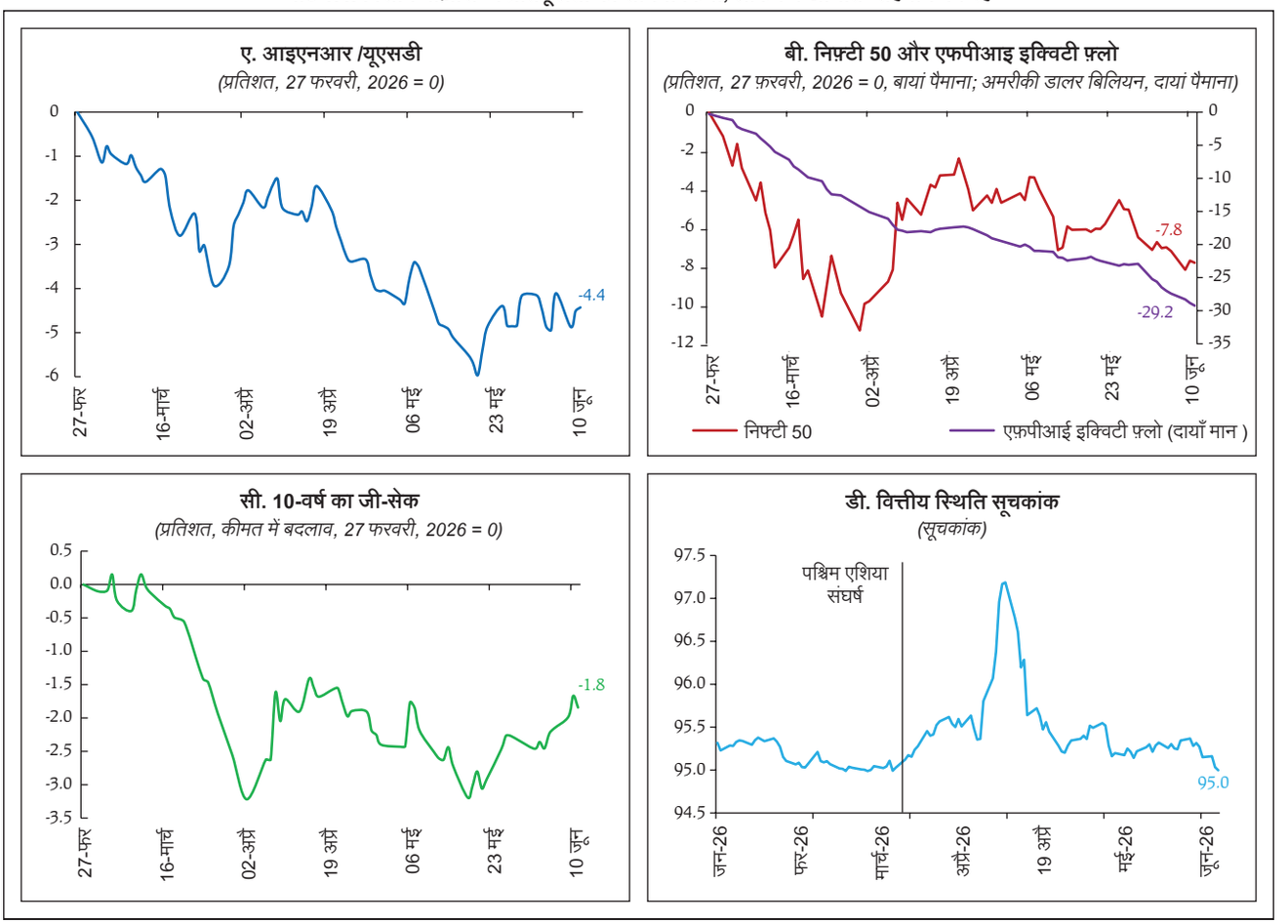


स्रोत: आरबीआई।

1.5 पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और उसके बाद वैश्विक अनिश्चितता में वृद्धि का भारत जैसी उभरती हुई बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) पर भी वित्तीय चैनल के माध्यम से प्रभाव पड़ा। पूंजी प्रवाह में कमी तथा आयातकों और निवेशकों द्वारा हेजिंग की बढ़ती मांग के कारण विनिमय दर पर लगातार मूल्यह्रास का दबाव बना रहा। निरंतर राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के बावजूद मुख्यतः भू-राजनीतिक तनाव और ऊर्जा कीमतों में वृद्धि के कारण सरकारी बॉन्ड यील्ड , विशेषकर दीर्घकालिक बॉन्ड यील्ड पर दबाव देखा गया। हालाँकि, पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक और सरकार द्वारा किए गए उपायों के बाद विनिमय दर तथा बॉन्ड यील्ड पर बना दबाव कम हुआ, जिससे समग्र वित्तीय परिस्थितियों में सुधार आया (चार्ट 1.4 ए, बी, सी और डी)।

1.6 उल्लेखनीय रूप से, सुदृढ़ समष्टि आर्थिक आधारभूत स्थितियों और एक स्वस्थ वित्तीय प्रणाली ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पश्चिम एशिया संकट के प्रभावों का सामना करने में सहयोग मिला (चार्ट 1.5 (ए) और (बी))। वैश्विक स्तर पर, भारत अभी भी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है, जिसका मुख्य आधार घरेलू मांग है, और मुद्रास्फीति भी लक्ष्य सीमा के भीतर बनी हुई है। बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों की बैलेंस शीट पर्याप्त पूंजी और चलनिधि बफर के साथ मजबूत बनी हुई है, जिससे वास्तविक अर्थव्यवस्था पर वित्तीय आघातों के असर का जोखिम कम हुआ है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय प्रणाली तनाव सूचकांक (एफएसएसआई) में कुछ वृद्धि होने के बावजूद, घरेलू वित्तीय प्रणाली में तनाव का स्तर पिछले संकटों की तुलना में अभी भी अपेक्षाकृत कम है (चार्ट 1.5 (सी))।

चार्ट 1.4: वित्तीय बाज़ारों ने प्रतिकूलता का सामना किया, लेकिन वे आघात -सहनीय बने रहे

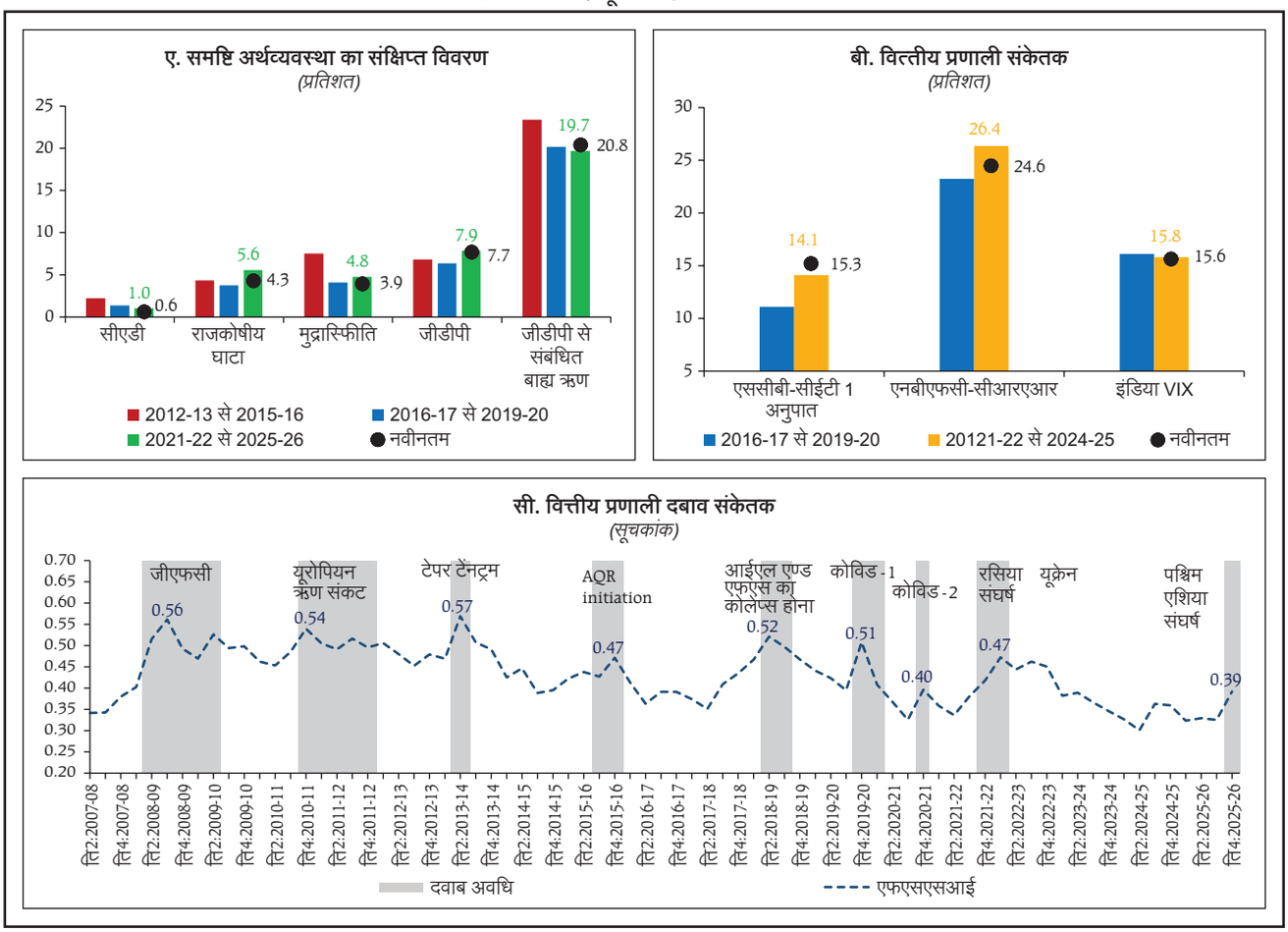


टिप्पणी: चार्ट (बी) में, एफपीआई इक्विटी फ़्लो 27 फ़रवरी, 2026 से अब तक का कुल दैनिक फ़्लो है। चार्ट (डी) में डेटा 10 जून, 2026 तक का है।
स्रोत: एलएसईजी वर्कस्पेस; गोल्डमैन सेस; और आरबीआई।

1.1 वैश्विक समष्टि वित्तीय भेद्यताएँ

1.7 वैश्विक वित्तीय प्रणाली को पश्चिम एशिया के संघर्ष से पैदा हुए झटकों का सामना करना पड़ रहा है, और यह ऐसे समय में हो रहा है जब कई तरह की भेद्यताओं के एक साथ उभरने की संभावना बढ़ गई है। हालाँकि, इस आघात से मुद्रास्फीतिकारी दबाव बढ़ सकते हैं और वित्तीय स्थितियां तंग हो सकती हैं, पर बाज़ार के मनोभावों (सेंटीमेंट्स) में बदलाव कई माध्यमों से वित्तीय बाज़ार में अस्थिरता पैदा कर सकता है, जिससे यह झटका और भी गंभीर हो सकता है। इसी संदर्भ में, यह भाग तीन मुख्य वैश्विक प्रवर्धन माध्यमों (एम्प्लीफिकेशन चैनलों) यथा, बॉन्ड बाज़ार की कमजोरियाँ, बढ़े हुए आस्ति मूल्यांकन एवं संकेंद्रित एक्सपोज़र , और एनबीएफआई से जुड़े जोखिमों का विश्लेषण करता है जो संभावित वित्तीय स्थिरता जोखिम पैदा कर सकते हैं।

चार्ट 1.5: भारत के मज़बूत समष्टि अर्थव्यवस्था का आधार



टिप्पणी: चार्ट (ए) में, महंगाई की नवीनतम वैल्यू मई 2026 की है; सीएडी और जीडीपी 2025-26 के लिए हैं; जीडीपी के मुकाबले विदेशी कर्ज मार्च 2026 तक का है और राजकोषीय घाटा 2026-27 के लिए है (बजट अनुमानों के आधार पर)। चार्ट (बी) में, महामारी वाले वर्ष 2020-21 को शामिल नहीं किया गया है। इसमें अपर लेयर और मिडिल लेयर एनबीएफसी को शामिल किया गया है। इंडिया VIX की नवीनतम वैल्यू 10 जून 2026 की है। शेष दो संकेतक मार्च 2026 के आखिर तक के हैं। चार्ट (सी) के लिए, विस्तृत पद्धति अनुबंध 1 में दिया गया है।

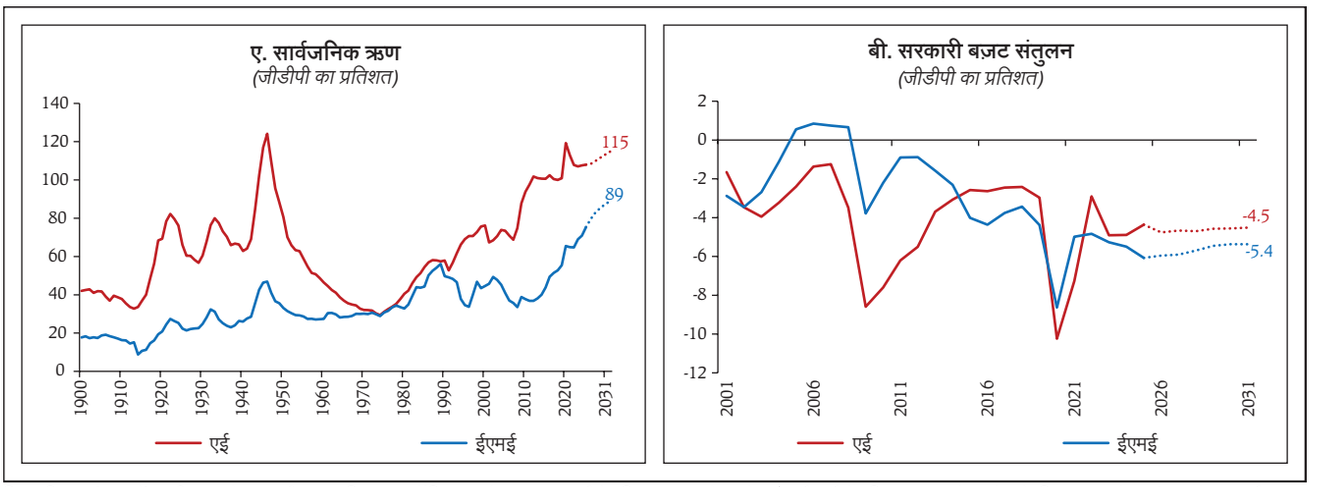
स्रोत: ब्लूमबर्ग; आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2026; राष्ट्रीय सांख्यिकी का कार्यालय; यूनियन बजट डॉक्यूमेंट्स; डीबीआईई; आरबीआई पर्यवेक्षी विवरण; और आरबीआई स्टाफ।

1.1.1 बॉण्ड बाज़ार की कमजोरियाँ

1.8 ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था वृद्धि में प्रतिकूलताओं और ऋण की अदायगी की बढ़ती लागत का सामना कर रही है, पहले से ही ऊँचे स्तर पर मौजूद सरकारी (सॉवरेन) ऋण में लगातार वृद्धि हो रही है। मौजूदा ऋण भार के अतिरिक्त, सरकारी घाटा और बढ़ सकता है, क्योंकि उच्चतर यील्ड में वृद्धि से ब्याज लागत बढ़ती है तथा ऊर्जा की ऊँची कीमतों के प्रभाव को कम करने के प्रयासों से उधार लेने की जरुरतें बढ़ सकती हैं (चार्ट 1.6 (ए) और (बी))।

1.9 पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद, कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सरकारी बॉण्ड यील्ड पिछले 20 वर्षों के अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गए हैं (चार्ट 1.7 (ए) और (बी))। सरकारी बॉण्ड यील्ड में यह वृद्धि कई कारणों से हो रही है, जिनमें पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी उच्चतर ऊर्जा कीमतों के कारण उत्पन्न मुद्रास्फीतिकारी दबाव, केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की अपेक्षाएँ, लगातार बने हुए राजकोषीय घाटे के कारण अधिक मात्रा में बॉण्ड जारी करने की आवश्यकता, तथा बढ़ती भू-राजनीतिक अनिश्चितता तथा केंद्रीय बैंकों द्वारा मात्रात्मक

चार्ट 1.6: वैश्विक सार्वजनिक ऋण बढ़ रहा है जबकि राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है



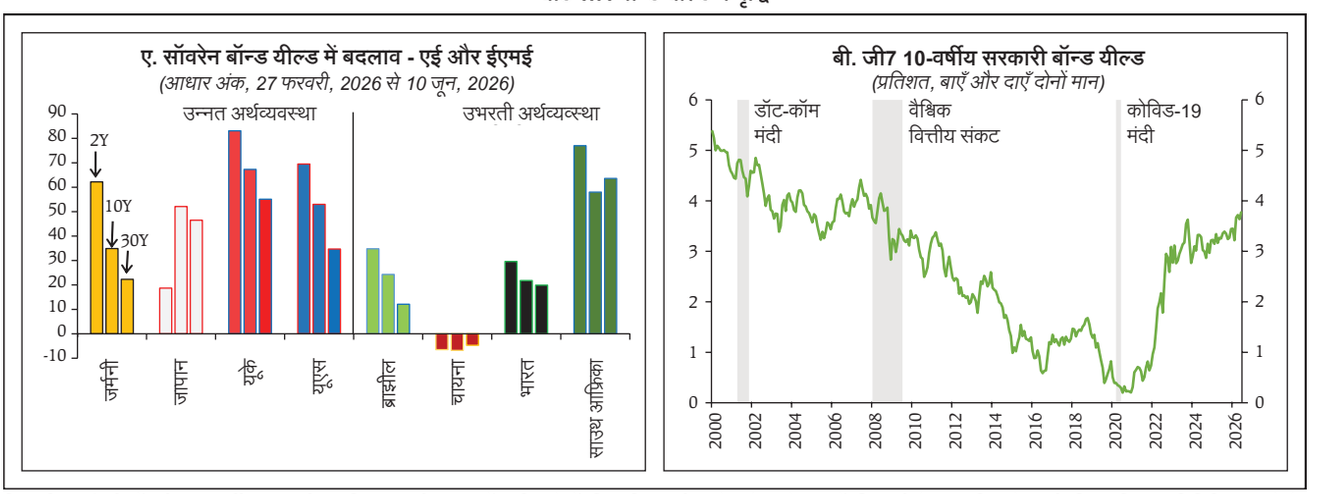
टिप्पणी: चार्ट (ए) में, नवीनतम डेटा आईएमएफ फिस्कल मॉनिटर अप्रैल 2026 (एई के लिए 1991 से आगे और ईएमई के लिए 1997 से आगे) से लिया गया है। पूर्व का डेटा आईएमएफ राजकोषीय मॉनिटर अक्टूबर 2020 पर आधारित है। देश के कवरेज, डेटा संशोधन और एकत्रीकरण पद्धति में अंतर के कारण मामूली अंतर हो सकते हैं। दोनों चार्ट में, बिंदीदार रेखाएँ पूर्वानुमान को दर्शाती हैं।

स्रोत: आईएमएफ राजकोषीय मॉनिटर अप्रैल 2026 और अक्टूबर 2020।

सख्ती अपनाए जाने के बीच निवेशकों द्वारा उच्चतर अवधि और मुद्रास्फीति प्रीमियम की माँग शामिल है।

1.10 वैश्विक ऋण स्तर में हो रही वृद्धि के बीच, रोलओवर जोखिम भी बढ़ रहा है, क्योंकि हाल के वर्षों में सरकारों ने अपने ऋण की परिपक्वता अवधि को काफी कम कर दिया है और ऐसा करने से पुराने ऋणों के पुनर्वित्तपोषण की आवश्यकता बढ़ गई है (चार्ट 1.8 (ए))। पिछले तीन वर्षों में, जी4 देशों की संप्रभु सरकारों[1] ने बढ़ते मीयादि प्रीमियम के कारण अपने नए ऋण निर्गम की औसत परिपक्वता अवधि में कमी की है जिसका दायरा 0.1 से 2.6 वर्ष तक का है। जबकि निवेश फंड, विदेशी निवेशक और हाउसहोल्ड्स जैसे कीमत -संवेदी निवेशक अब कम-से-कम आधा ऋण होल्ड करते हैं।[2]

चार्ट 1.7: बॉन्ड यील्ड में वृद्धि



टिप्पणी: चार्ट (बी) में, जी7 10-वर्षीय संप्रभु यील्ड की गणना जी7 समूह में शामिल देशों की व्यक्तिगत यील्ड के औसत के रूप में की जाती है। छायांकित क्षेत्र मंदी की अवधि का प्रतिनिधित्व करते हैं।

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

[1] जी4 देशों में अमेरिका, जर्मनी, जापान और यूनाइटेड किंग्डम शामिल हैं।

[2] अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2026), "वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट", अप्रैल।

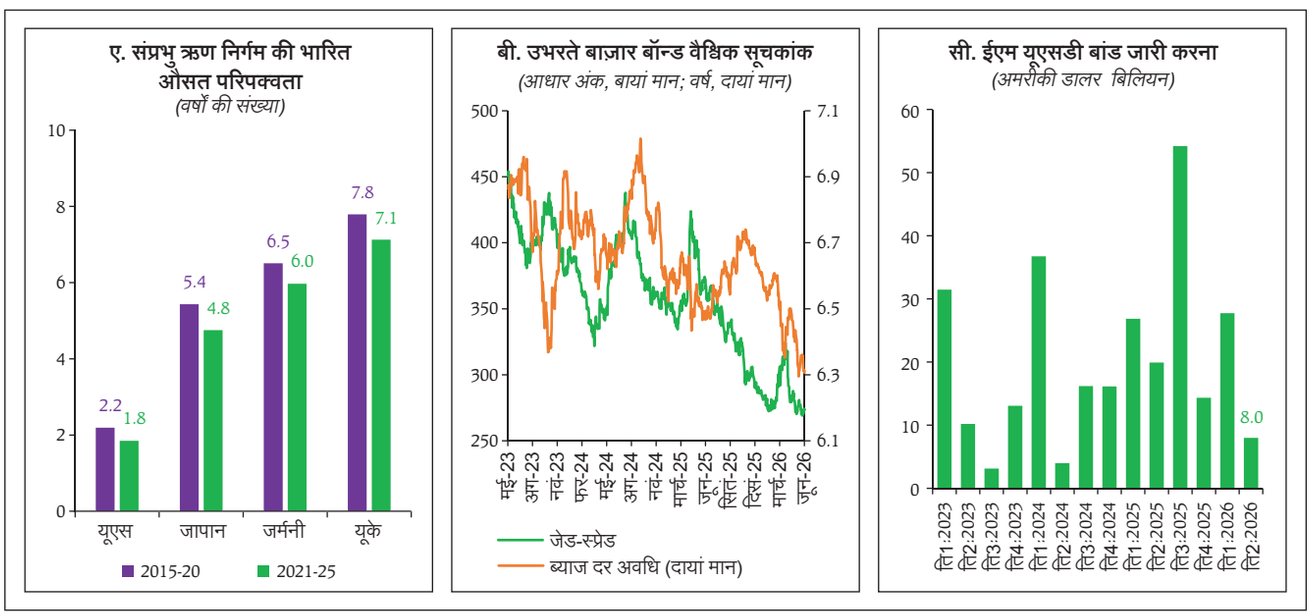
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के अनुसार, ओईसीडी देशों की रीफाइनेंसिंग की ज़रूरतें 2025 में 13.5 अमरीकी डालर ट्रिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गईं – जो कुल उधार का लगभग 80 प्रतिशत है और इनके और बढ़ने की उम्मीद है[3]। फिर भी, आर्थिक रूप से अनुशासित देशों द्वारा जारी डॉलर-मूल्यवर्गित ऋण के लिए निवेशकों में अच्छी रुचि बनी हुई है, जैसा कि अमरीकी ट्रेज़री पर स्प्रेड के कम होने से पता चलता है (चार्ट 1.8 बी और सी)।

1.11 ऐसे समय में जब बाजार सहभागी सरकारी बॉण्ड के सुरक्षित आस्ति स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं, सरकारी बॉण्ड पर मौद्रिकेतर प्रतिफल (कन्वीनियंस यील्ड)[4] कम हो रहा है और बॉण्ड बाजार में अस्थिरता बढ़ रही है। सरकारी बॉण्ड और बैंकों के बीच गहरे संबंध को देखते हुए, बॉण्ड मार्केट की कमज़ोरियाँ बैंकों की बैलेंस शीट तक तेज़ी से फैल सकती हैं। इसके अलावा, सरकारी बॉण्ड मार्केट में कीमत संवेदी ऋणाश्रित लीवरेज्ड निवेशकों (हेज फंड सहित) की मौजूदगी बढ़ रही है (चार्ट 1.9 ए)।[5] बड़े और ऋणाश्रित (लीवरेज्ड) हेज फंड सरकारी बॉण्ड आर्बिट्राज ट्रेड में शामिल हैं, जैसे कि कैश-फ्यूचर्स बेसिस और स्वैप स्प्रेड ट्रेड, जिसमें वे ज़्यादा लीवरेज का इस्तेमाल करते हैं (चार्ट 1.9 बी)। इसलिए, मार्केट में तनाव के समय, ये फंड तेज़ी से अपनी पोजीशन बंद (अनवाइंड) कर सकते हैं तथा अत्यल्प कीमत या भारी छूट वाली बिक्री(फायर सेल) और वृहत्तर बाजार पर प्रभाग का जोखिम बढ़ा सकते हैं।

1.1.2 बढ़ा हुआ आस्ति मूल्यांकन और संकेंद्रित एक्सपोज़र

1.12 ज़्यादातर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में आस्ति मूल्यांकन ऊँचा बना हुआ है, जबकि स्प्रेड कम हो रहे हैं

चार्ट 1.8: बॉन्ड बाजार के रुझान



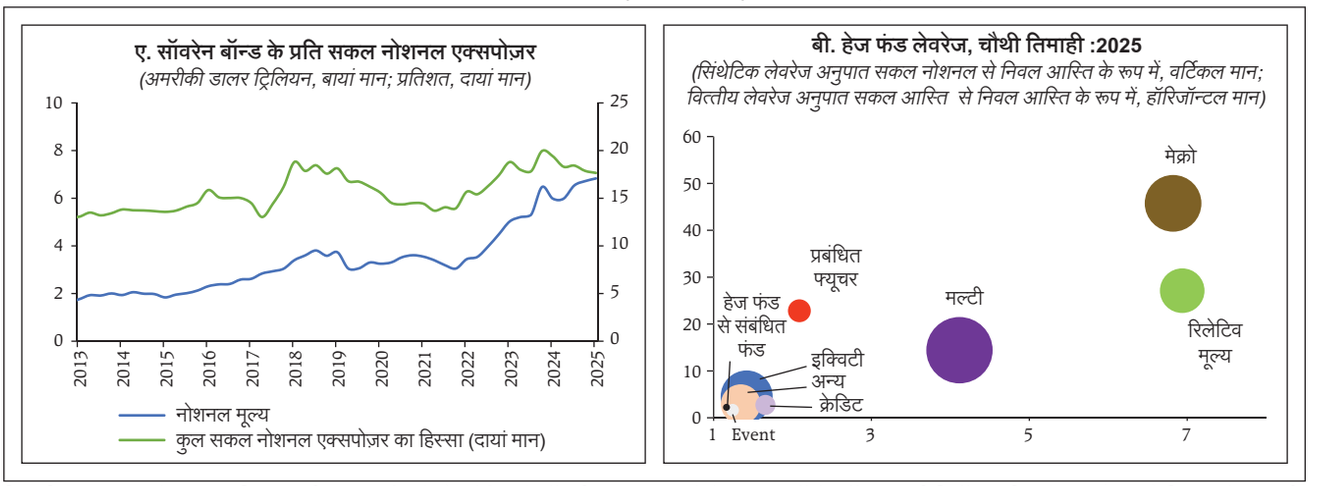
टिप्पणी: चार्ट (ए) में, भारित औसत परिपक्वता की गणना प्रत्येक निर्गम के लिए जारी की गई राशि के योग को परिपक्वता से गुणा करके, अवधि के दौरान जारी की गई कुल राशि से विभाजित करके की जाती है। चार्ट (सी) में, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, हंगरी, इंडोनेशिया, मैक्सिको, पेरू, फिलीपींस, पोलैंड, रोमानिया और दक्षिण अफ्रीका पर विचार किया गया देश हैं। 10 जून तक के आंकड़े 2026।
स्रोत: ब्लूमबर्ग; और जेपी मॉर्गन।

[3] ओईसीडी (2026), "ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2026", मार्च।

[4] 'कन्वीनियंस यील्ड' (सुविधा प्रतिफल) वह प्रीमियम है जो निवेशक सॉवरेन बॉन्ड की सुरक्षा और चलनिधि के लिए देने को तैयार रहते हैं; इससे सरकारों को कम दरों पर कर्ज लेने में मदद मिलती है।

[5] हेज फंड्स का इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स और सॉवरेन बॉन्ड में कुल नोशनल एक्सपोजर 2020 में $9 ट्रिलियन से कम था, जो 2025 में दोगुने से भी ज़्यादा बढ़कर $18 ट्रिलियन से अधिक हो गया। स्रोत: IMF, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, अप्रैल 2026।

चार्ट 1.9: उच्च लेवरेज के बीच सॉवरेन (सरकारी बॉन्ड) में हेज फंड का एक्सपोज़र बढ़ा

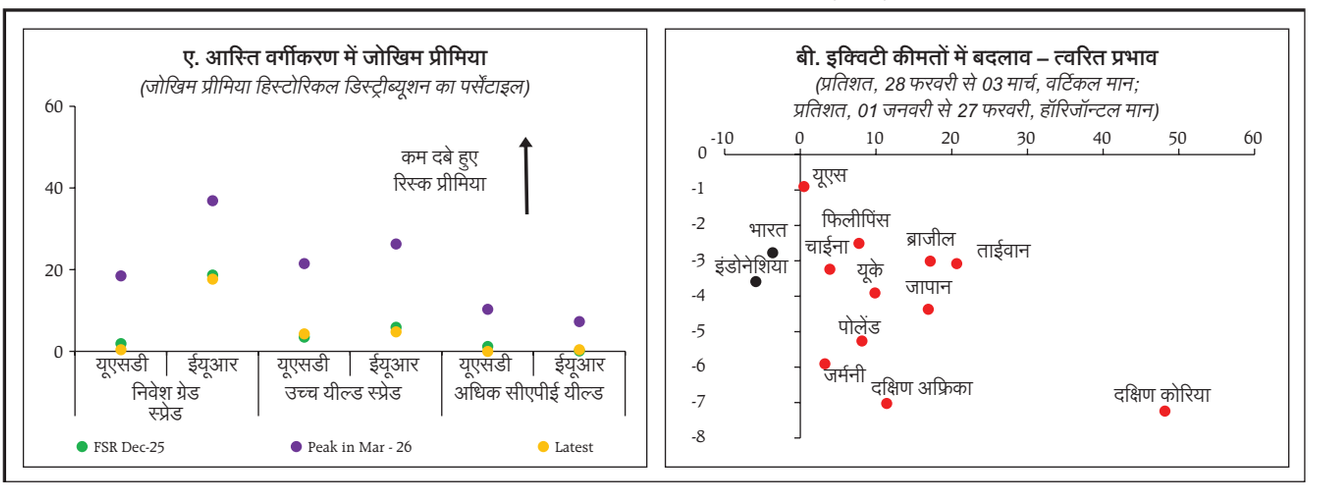


टिप्पणी: चार्ट (ए) उन हेज फंड्स की जानकारी पर आधारित है जो अमेरिका में फॉर्म पीएफ फाइल करते हैं। यह कुल सॉवरेन बॉन्ड (अमरीकी बॉन्ड सहित) में एक्सपोज़र को दिखाता है। चार्ट (बी) हेज फंड के प्रकार के आधार पर सिंथेटिक और फाइनेंशियल लेवरेज को दिखाता है। सर्कल का साइज़ कुल सकल नोशनल एक्सपोज़र के अनुपात में है।
स्रोत: ऑफिस ऑफ़ फाइनेंशियल रिसर्च; यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

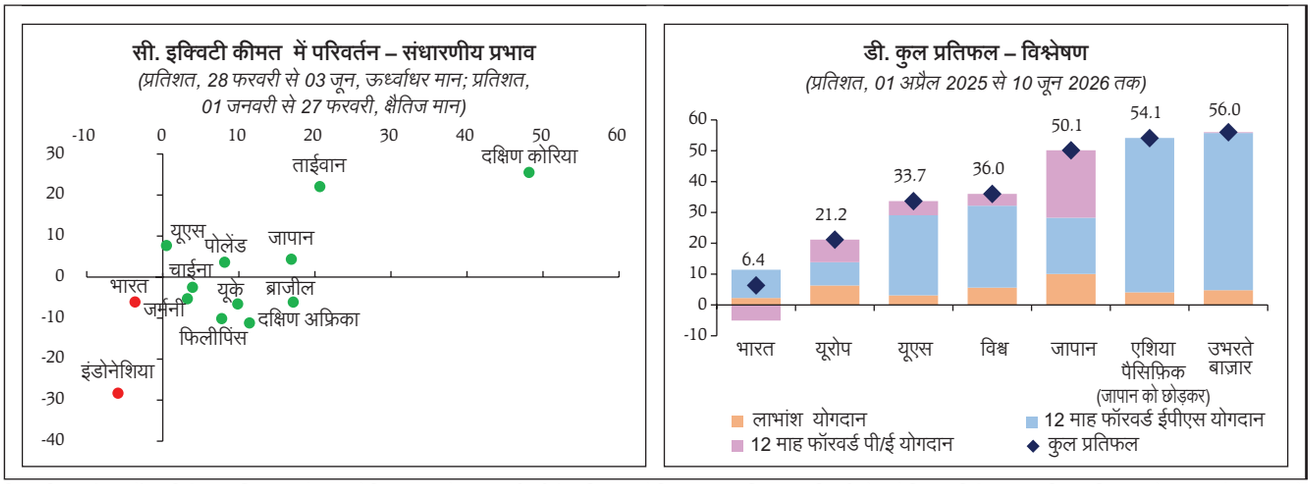
(चार्ट 1.10 ए)। हालाँकि, पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरू होने से शुरुआती तौर पर तेज़ प्रतिक्रियाएँ और सुधार देखने को मिले, लेकिन उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में इक्विटी बाजार और एआई संवेग को आगे बढ़ाने वाले बाजार ज़्यादातर उबर चुके हैं। हालाँकि, उदीयमान बाजार अर्थव्यवस्थाओं में ज़्यादा तेज़ सुधार देखा गया, जिसमें ऊर्जा आयातक देशों में कीमतों में तुलात्मक रूप से बड़ा समायोजन हुआ (चार्ट 1.10 बी और सी)। एआई की लंबी अवधि की संभावनाओं के बारे में उम्मीद और मज़बूत कॉर्पोरेट आय की उम्मीदों ने इक्विटी बाजार के ऊँचे मूल्यांकन को आधार मिला है, खासकर कोरिया और ताइवान में (चार्ट 1.10 डी)।

1.1.3 संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) में विभिन्न मानकों के आधार पर इक्विटी मूल्यांकन अपने ऐतिहासिक दायरे के ऊपरी स्तर पर बना हुआ है (चार्ट 1.11ए और 1.11बी)। इसी बीच, अमेरिकी इक्विटी बाज़ारों में दुनिया के अन्य देशों का सकल विदेशी निवेश उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया है। अमेरिकी (यूएस) इक्विटी में विदेशी निवेशकों की सकल हिस्सेदारी मार्च 2020 के 7.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर मार्च 2026 में 21 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई

चार्ट 1.10: वित्तीय बाज़ार की निरंतर सकारात्मकता *(जारी..)*



चार्ट 1.10: वित्तीय बाज़ार की निरंतर सकारात्मकता *(समाप्त..)*

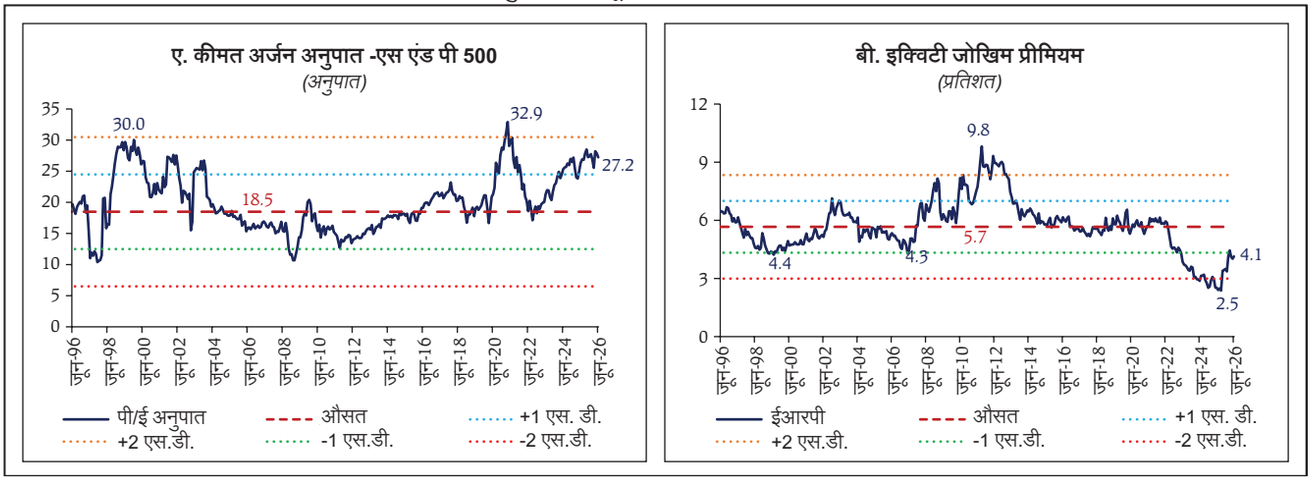


टिप्पणी: चार्ट (ए) में, अतिरिक्त चक्रीय रूप से समायोजित मूल्य-से-आय (सीएपीई) प्रतिफल जोखिम-मुक्त आस्ति पर इक्विटी से अपेक्षित अतिरिक्त वास्तविक प्रतिफल को मापता है। 2002 से क्रेडिट स्प्रेड (ऑप्शन-समायोजित) के लिए दैनिक डेटा के 3-दिवसीय आवर्ती औसत पर आधारित प्रतिशतक। अतिरिक्त चक्रीय रूप से समायोजित मूल्य-से-आय (सीएपीई) प्रतिफल के लिए, 2010 से एस एंड पी 500 और स्टॉक्स यूरोप 600 सूचकांकों के 3-दिवसीय आवर्ती औसत पर आधारित प्रतिशतक। 10 जून 2026 तक नवीनतम मूल्य। चार्ट (डी) एक मानक वित्तीय ढांचे पर आधारित है जिसमें एक विशिष्ट समय सीमा में इक्विटी सूचकांक के कुल प्रतिफल को गणितीय रूप से एक मानक एडिटिव आइडेंटिटी का उपयोग करके अलग-अलग हिस्सों में बांटा जाता है। इस आइडेंटिटी के अनुसार, कुल प्रतिशत प्रतिफल - लाभांश प्रतिफल, 12 माह फॉरवर्ड ईपीएस में प्रतिशत परिवर्तन और 12 माह फॉरवर्ड पी/ई गुणक में प्रतिशत परिवर्तन के योग के बराबर होता है।
स्रोत: ब्लूमबर्ग; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

है।[6] कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित प्रौद्योगिकियों वाले फर्मों के एक छोटे समूह में संकेंद्रण अधिक बना हुआ है जो उन अर्थव्यवस्थाओं में शेयर बाज़ार के प्रदर्शन को उत्तरोत्तर चालित कर रहा है, जो या तो एआई को अपनाने में अग्रणी हैं या उसकी आपूर्ति श्रृंखला में सहभागी हैं (चार्ट 1.11सी, 1.11डी और 1.11ई)।

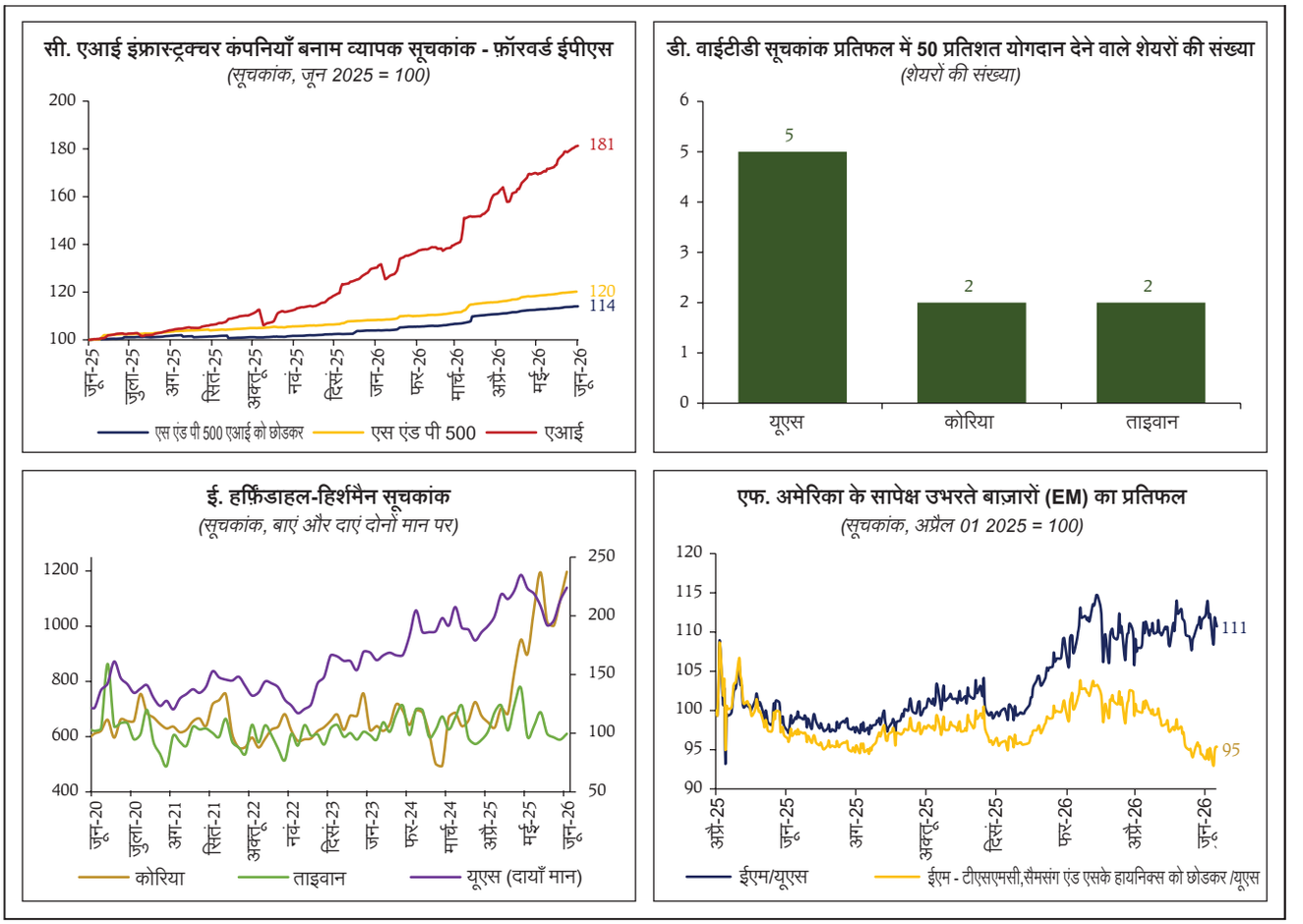
हाल के समय में कुछ उभरते बाज़ारों का बेहतर प्रदर्शन भी मुख्यतः एआई से जुड़ी कंपनियों के कारण रहा है, न कि व्यापक सुदृढ़ता के कारण (चार्ट 1.11एफ)। ये दोनों वित्तीय कमजोरी की स्रोत बनी हुई हैं, क्योंकि यदि इन फर्मों में औने-पौने दरों पर बिकवाली होती है, तो इससे अमेरिकी शेयर बाज़ार में व्यापक गिरावट आ सकती है और धन/संपत्ति प्रभावों (वेल्थ इफेक्ट्स) के माध्यम इसका असर अन्य देशों के वित्तीय बाज़ारों पर भी पड़ सकता है।

चार्ट 1.11: बढ़ा हुआ आस्ति मूल्यांकन और संकेंद्रित एक्सपोज़र *(जारी)*



[6] यूएस ट्रेजरी टीआईसी डेटा।

चार्ट 1.11: बढ़ा हुआ आस्ति मूल्यांकन और संकेंद्रित एक्सपोज़र *(समाप्त)*



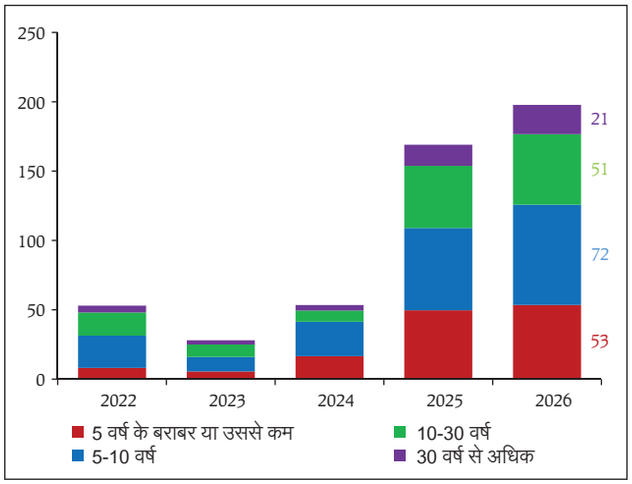
टिप्पणी: चार्ट (ए) और (बी) में, औसत और मानक विचलन पूर्ण अवधि के लिए हैं। चार्ट (सी) में, चार्ट को एआई कंपनियों के लिए ब्लूमबर्ग के स्वामित्व वाले समान-भारित सूचकांकों, एसएंडपी 500 एआई को छोडकर और एसएंडपी 500 का उपयोग करके बनाया गया है। चार्ट (डी) में, प्रत्येक देश के लिए, प्रतिनिधि इक्विटी सूचकांक पर विचार किया जा रहा है: यूएस - एसएंडपी 500, कोरिया - कोस्पी, और ताइवान - ताइएक्स। चार्ट इस वर्ष संबंधित सूचकांकों में प्रतिफल में कम से कम ~ 50 प्रतिशत का योगदान करने वाले शेयरों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अनुमान वर्ष की शुरुआत में प्रत्येक स्टॉक के भार को वर्ष-दर-तिथि प्रतिफल से गुणा करके लगाया जाता है। चार्ट (ई) में, प्रत्येक बाजार के लिए प्रतिनिधि व्यापक सूचकांकों के लिए एचएचआई सूचकांक की गणना की गई है, अर्थात, यूएस, दक्षिण कोरिया और ताइवान के लिए क्रमशः एसएंडपी 500,एमएससीआई कोरिया और एमएससीआई ताइवान। चार्ट (एफ) में, ईएम को ब्लूमबर्ग ईएम लार्ज एंड मिड-कैप सूचकांक द्वारा दर्शाया गया है, जबकि यूएस को ब्लूमबर्ग यूएस 500 सूचकांक द्वारा दर्शाया गया है।
स्रोत: ब्लूमबर्ग; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

1.14 एआई-संबंधित निवेश अब बॉण्ड बाजारों सहित पूंजी बाजारों के अन्य खंडों में हो रहे हैं। मुक्त नकदी प्रवाह में गिरावट के बीच, हाइपरस्केलर (बड़ी टेक कंपनियाँ) द्वारा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हेतु पूंजी व्यय में वृद्धि के साथ, उनके द्वारा इन निवेशों के वित्तपोषण के लिए पिछले दो वर्षों में ऋण निर्गम में काफी वृद्धि हुई है (चार्ट 1.12)। जैसे-जैसे व्यय और बढ़ेगा, ऋण वित्तपोषण में काफी वृद्धि होने की आशा है। इस प्रकार, एक एआई-संचालित आस्ति मूल्य सुधार इस चैनल के माध्यम से प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि बैंक, निजी क्रेडिट फर्मों और एआई बूम के लिए निधीयन करने वाले अन्य प्रमुख वित्तपोषण मध्यस्थों के साथ अपनी संबद्धता के कारण अप्रत्यक्ष रूप से जोखिम में आ सकते हैं।

1.15 कुछ उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) ने आस्ति मूल्यांकन में भी वृद्धि दर्ज की है। बेहतर मूल आर्थिक तत्वों और रेटिंग अपग्रेड ने पर्याप्त सीमापारीय पोर्टफोलियो प्रवाह को आकर्षित किया है, विशेष रूप से एनबीएफआई से। इन पूंजी प्रवाह का बड़ा हिस्सा उन्नत अर्थव्यवस्थाओं(एई) की तुलना में उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में उच्च प्रतिफल का लाभ उठाने के उद्देश्य से कैरी-ट्रेड (प्रतिफल संवाहक

चार्ट 1.12: एआई कंपनियों द्वारा बढ़ता ऋण वित्तपोषण

(बिलियन अमेरिकी डॉलर)



टिप्पणी: एआई कंपनियों के समूह में माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, ओरेकल, एंथ्रोपिक, ओपनएआई, मेटा अल्फाबेट, गूगल एलएलसी, एनवीआईडीआईए, एक्स.एआई, ब्रॉडकॉम, एप्पल, अमेज़ॉन, पैलांटिर, टेस्ला, इंटेल, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस और कोरवेव शामिल हैं। 10 जून 2026 तक 2026 के आंकड़े।
स्रोत: ब्लूमबर्ग।

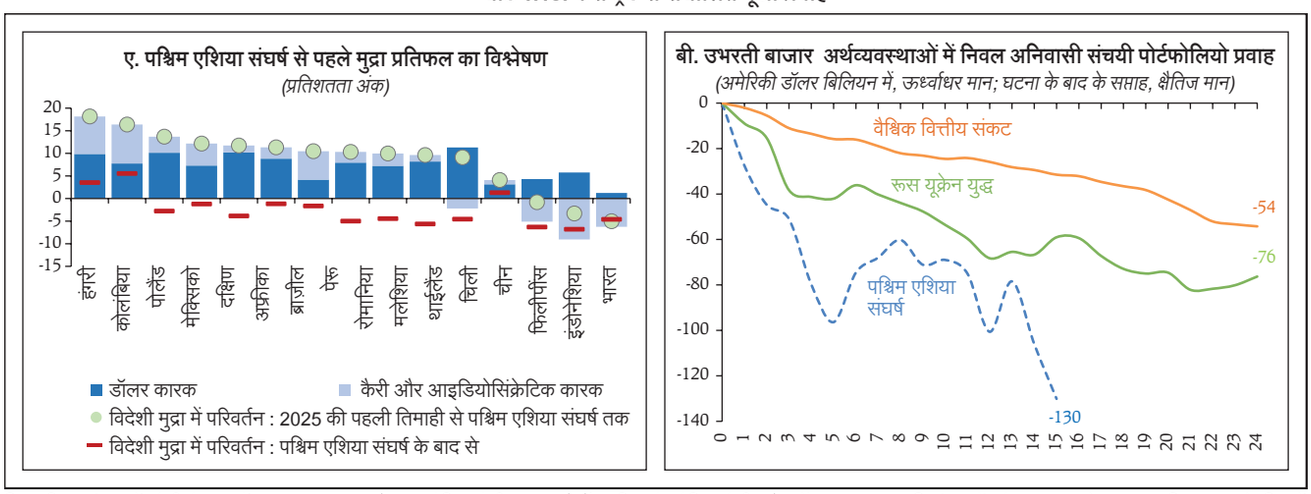
व्यापार) संचालित है (चार्ट 1.13 ए)। अपनी प्रचक्रीय प्रकृति को देखते हुए, ये प्रवाह दबाव की अवधि के दौरान अचानक उलट सकते हैं, क्योंकि गिरती जोखिम वहन क्षमता, निवेशक को मोचन के लिए ट्रिगर करती है। पश्चिम एशिया संघर्ष के दौरान, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में पिछले संकटों की तुलना में बड़े पूंजी बहिर्वाह दर्ज किए गए (चार्ट 1.13 बी)।

I.1.3 एनबीएफआई से जुड़े जोखिम

1.16 चूंकि एनबीएफआई क्षेत्र का विस्तार जारी है, जो बैंकिंग क्षेत्र की गति से दोगुनी गति से बढ़ रहा है, आस्ति वर्गों में उनके बढ़ते पदचिह्न, आघातों के विस्तार संबंधी जोखिम को बढ़ाते हैं और बाजार की उथल-पुथल को वित्तीय अस्थिरता में परिवर्तित करते हैं (चार्ट 1.14)। एनबीएफआई द्वारा अत्यधिक लीवरेज्ड और मात्रात्मक निवेश कार्यनीतियों में वित्तपोषण बाजारों, मूल बॉण्ड बाजारों और इक्विटी डेरिवेटिव बाजारों में अस्थिरता उत्पन्न करने की क्षमता है।

1.17 हेज फंड रेपो निधीयन और अल्प मार्जिन दोनों के माध्यम से लाभ का उपयोग करके कैश-फ्यूचर्स आधार और स्वैप-स्प्रेड ट्रेड करते हैं (चार्ट 1.15)। इससे ये ट्रेड निधीयन और चलनिधि, दोनों तरह के जोखिमों - रेपो उधार को रोलओवर करने में असमर्थता और मार्जिन कॉल को पूरा करने में विफलता के दायरे में आ जाते हैं। बार-बार, हेज फंडों ने दबाव की अवधि में तेजी से इन ट्रेडों को वापस ले लिया है, जिससे बाजार में उथल-पुथल मची है।[7]

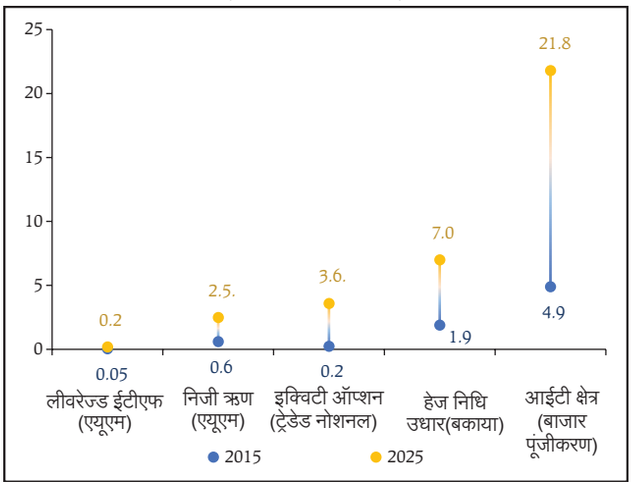
चार्ट 1.13: कैरी ट्रेड से संचालित पूंजी प्रवाह



टिप्पणी: चार्ट (ए) में, कैरी फैक्टर में ब्याज दर अंतर और एक वैश्विक कैरी कारक दोनों शामिल हैं। वैश्विक कैरी और डॉलर कारक का निर्माण वर्डेलहैन (2018) के अनुसार किया गया है, जिसमें उभरते बाजारों और नौ उन्नत अर्थव्यवस्था मुद्राओं के एक पोर्टफोलियो का उपयोग किया गया है। विश्लेषण 18 महीने के लिए आवर्ती रिग्रेशन पर आधारित है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद से विदेशी मुद्रा परिवर्तन को 27 फरवरी 2026 से 12 जून 2026 की अवधि के लिए माना गया है। चार्ट (बी) के लिए, 12 जून 2026 तक के आंकड़े।
स्रोत: आईएमएफ वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अप्रैल 2026; और अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान।

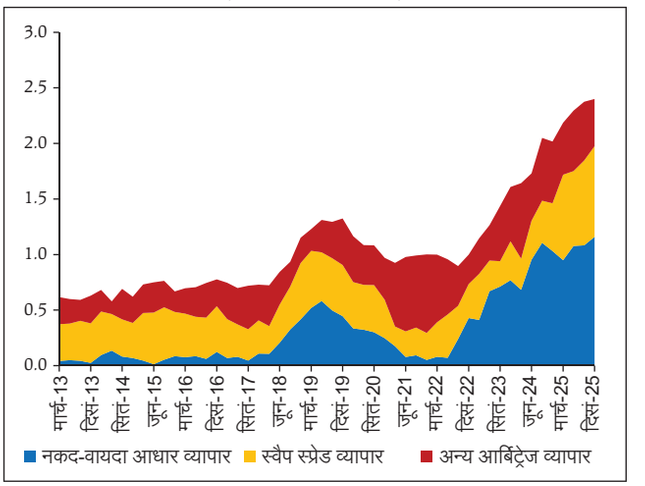
[7] 2020 की पहली तिमाही में, हेज फंड्स ने बेसिस ट्रेड्स के मोचन के दौरान लगभग 172 बिलियन डॉलर की ट्रेजरीज़ बेच दीं, जिससे प्रतिफल बढ़े और फेडरल रिज़र्व ने बड़े पैमाने पर खरीदारी फिर से शुरू की। इसी तरह अप्रैल 2025 में, बाजार में दबाव के बाद हेज फंड्स ने अपने अमेरिकी ट्रेजरी स्वैप-स्प्रेड पोजीशन में लगभग 80 बिलियन डॉलर की कमी की। स्रोत: आईएमएफ़ (2026), वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, अप्रैल।

चार्ट 1.14: वैश्विक एनबीएफआई के बढ़ते पदचिह्न
(बिलियन अमेरिकी डॉलर)



स्रोत: आईएमएफ़ वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अप्रैल 2026।

चार्ट 1.15: अमेरिकी ट्रेजरी बाजार में सापेक्ष मूल्य व्यापार
(बिलियन अमेरिकी डॉलर)



टिप्पणी: गणनाएँ एहलर्स और टोडोरोव (दिसंबर 2025) के आधार पर हैं।
स्रोत: वित्तीय अनुसंधान कार्यालय।

1.18 एनबीएफआई इक्विटी ऑप्शन बाजारों में बड़ी मात्रा में ऑप्शन ट्रेडिंग[8] के माध्यम से अस्थिरता को दबा रहे हैं, विशेष रूप से जीरो-डे-टू-एक्सपायरी (0डीटीई) ऑप्शन जैसे अल्पकालिक ऑप्शन में। चूंकि वे अपनी स्थितियों को हेज के लिए गतिशील कार्यनीतियों का उपयोग करते हैं, इसलिए ये ट्रेड बाजार की चाल को बढ़ाते हैं और अस्थिरता उत्पन्न करते हैं, विशेषतया दबाव की घटनाओं के दौरान। इस बीच, लीवरेज्ड ईटीएफ अपने एक्सपोजर के सापेक्ष इक्विटी बाजार की गतिविधियों पर एक बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं, और अपनी यांत्रिक पुनर्संतुलन प्रक्रिया के माध्यम से मूल्य में उतार-चढ़ाव को बढ़ा रहे हैं।

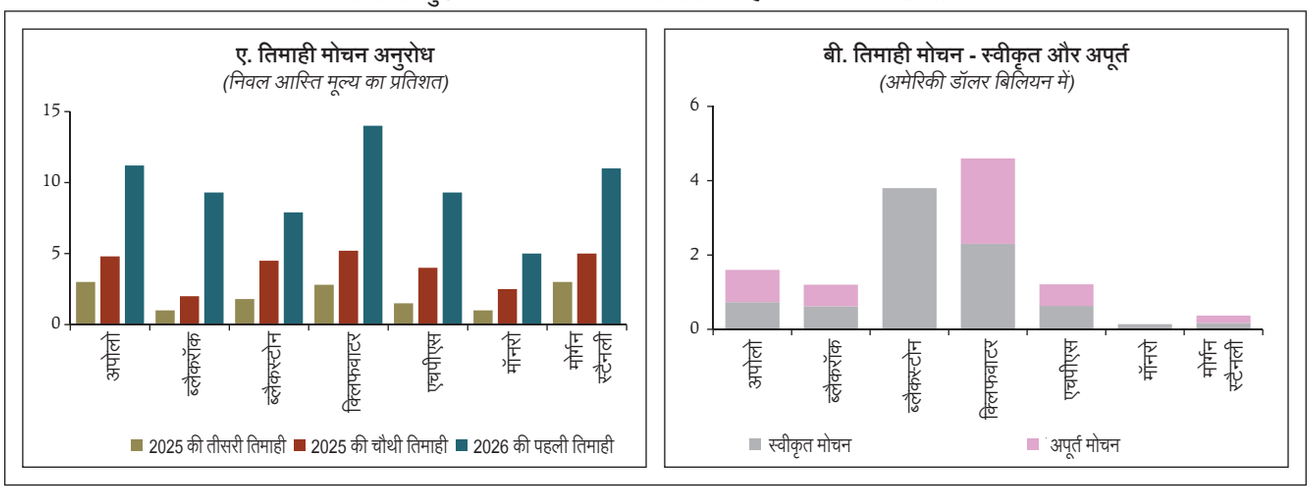
1.19 निजी ऋण, गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता का एक अन्य रूप, हाल के वर्षों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। विभिन्न अधिकार क्षेत्रों और डेटा संबंधी चुनौतियों के कारण निजी क्रेडिट बाजार के आकार के बारे में अनुमान अलग-अलग हैं - 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक। निजी ऋण पारितंत्र में परस्पर संबद्ध बैंकों और गैर-बैंक प्रतिभागियों का एक विविध समूह शामिल है। इन बाजारों में अस्पष्टता और अलग-अलग स्तर के लीवरेज वाली कई तरह की संस्थाओं के कारण इन संस्थाओं के बीच अंतर्संबंधों को पहचानना और आकलन करना कठिन है।[9] हाल के समय में, निजी ऋण में चूक और बढ़ते मोचन अनुरोधों (चार्ट 1.16 ए और बी) के साथ कुछ दोष रेखाएं उभरी हैं। जबकि वर्तमान दबाव से निजी ऋण में प्रणालीगत जोखिम की संभावना नहीं है, असुरक्षितताओं की पहचान करने और व्यापक वित्तीय प्रणाली पर प्रभाव को सीमित करने के लिए निरंतर निगरानी महत्वपूर्ण है।

1.20 गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता में तेजी से विस्तार आंशिक रूप से वित्तीय प्रणाली के मूल को संरक्षित करने के लिए बैंकों पर सख्त विनियमन का परिणाम है। इसके साथ ही, केंद्रीय बैंक मात्रात्मक सुलभता के मोचन से अपने तुलन-पत्र के आकार को सामान्यीकरण कर रहे हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके परिणामस्वरूप सीमित बाजार समर्थन और अधिक वित्तीय बाजार अस्थिरता हो सकती है। तुलन-पत्र के आकार को कम करने के लिए एक प्रस्तावित दृष्टिकोण बैंकों के चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) और निवल स्थिर निधीयन

[8] ऑप्शन व्यापार मूल रूप से अस्थिरता व्यापार हैं।

[9] एफ़एसबी (2026), "निजी ऋण में असुरक्षितताओं पर रिपोर्ट", मई।

चार्ट 1.16: खुदरा निवेशकों के निजी क्रेडिट फंड से बाहर निकलने संबंधी अवलोकन



Source: Company Filings.

अनुपात (एनएसएफआर) आवश्यकताओं को कम करना है, जिससे केंद्रीय बैंक आरक्षित निधियों की मांग कम हो जाती है[10]। इसके विपरीत, चूंकि एनबीएफआई अल्प विनियमित होते हैं, उनके कामकाज में पारदर्शिता कम होती है, मूल्य-संवेदनशील और अत्यधिक लीवरेज्ड होते हैं, और उनके पास केंद्रीय बैंक चलनिधि सुविधाओं तक पहुंच नहीं होती है, उनकी कार्रवाइयां दबाव के दौरान नुकसान को बढ़ा सकती हैं और अस्थिरता उत्पन्न कर सकती हैं। इस प्रकार, जैसे-जैसे केंद्रीय बैंक मात्रात्मक सुलभता का मोचन करते हैं, एनबीएफआई के बढ़ते प्रणालीगत महत्व और बैंकिंग क्षेत्र के साथ उनकी बढ़ती संबद्धता के बीच वित्तीय स्थिरता की सुरक्षा करना अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

I.2 घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियाँ

1.21 भारतीय अर्थव्यवस्था ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक उथल-पुथल के हालिया दौर में बाह्य दबाव के कई पहले के दौरों की तुलना में मजबूत समष्टि आर्थिक मूल तत्वों के साथ प्रवेश किया। जबकि भारत की आघातसहनीयता इन आघातों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण बफर प्रदान करती है, देश की आयातित ऊर्जा पर बड़ी निर्भरता को देखते हुए कुछ प्रभाव अपरिहार्य है।

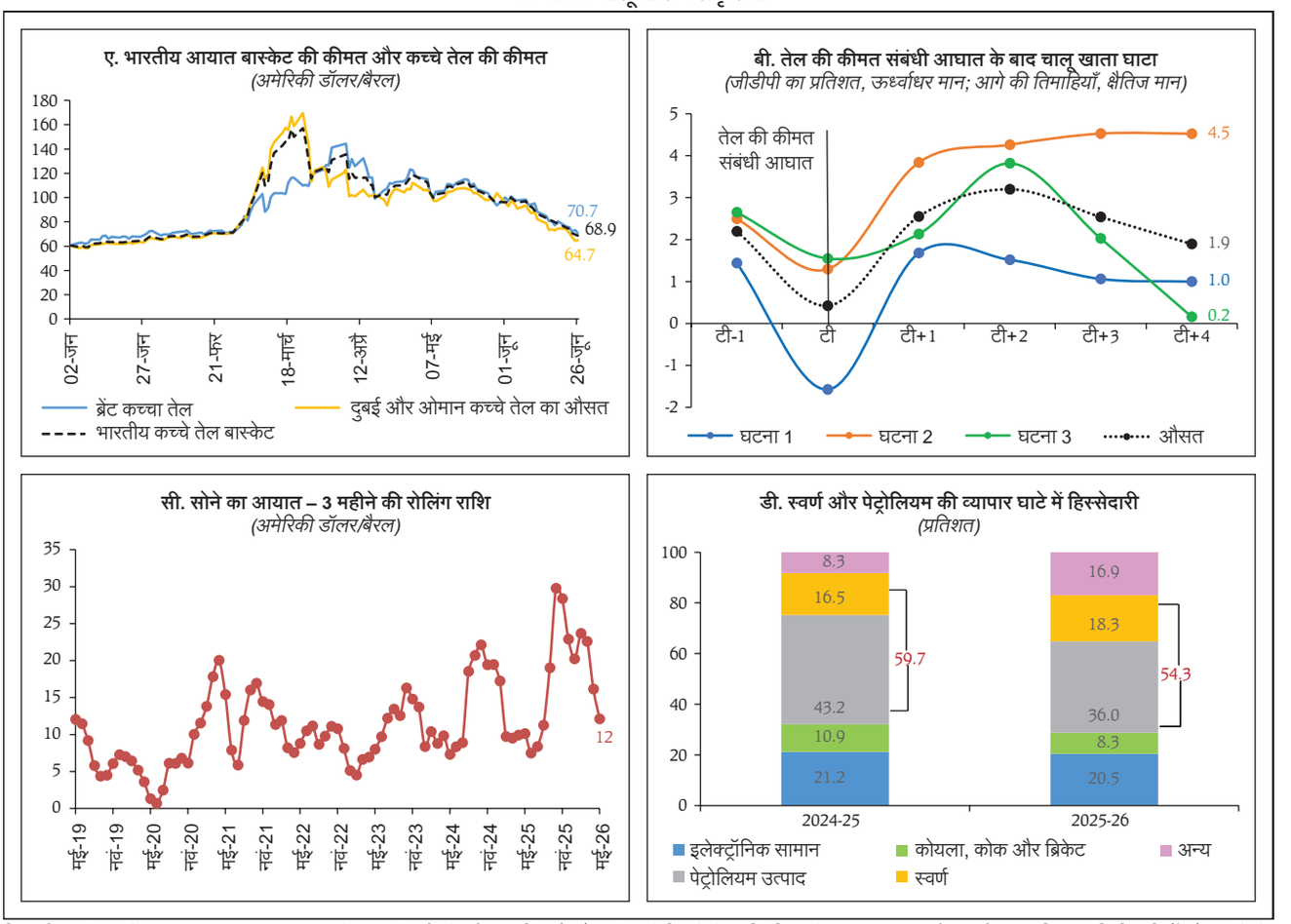
1.22 भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2025-26 में 7.7 प्रतिशत की मजबूत संवृद्धि दर्ज की (पिछले तीन वर्षों में 7.3 प्रतिशत की औसत संवृद्धि), जो कि मजबूत निजी खपत और निश्चित निवेश द्वारा समर्थित थी। अप्रैल-मई 2026 के अधिकांश उच्च-आवृत्ति संकेतकों ने आर्थिक गतिविधि में निरंतर आघात सहनीयता प्रकट की, जो दर्शाता है कि पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद 2026-27 की पहली तिमाही में संवृद्धि मजबूत रही है। फिर भी, तेल और अन्य वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतें और कमजोर वैश्विक संवृद्धि 2026-27 में भारत की घरेलू संवृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 2026-27 के लिए 6.6 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है। एमएसएमई और निर्यात क्षेत्रों को समर्थन सहित सरकार द्वारा उठाए गए कई उपायों से बाहरी आघातों के प्रभाव को कम करते हुए आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखने में मदद मिलने की आशा है। इसके अलावा, अंतरिम शांति समझौते ने इस संघर्ष को समाप्त करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं के सामान्यीकरण की नींव रखी है, जो संवृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न कर सकती है।

[10] एंडरसन, एलिसा जी., अलेसांद्रो बारबेरिनो, एंथनी एम. डियरक्स, और स्टीफन मिरान (2026). "ए यूजर्स गाइड टू रिड्यूसिंग दि फ़ेडरल रिज़र्व बैलेंस," वित्त और अर्थशास्त्र चर्चा श्रृंखला 2026-019. वाशिंगटन: फ़ेडरल रिज़र्व सिस्टम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, https://doi.org/10.17016/ FEDS.2026.019.

1.23 मुद्रास्फीति नियंत्रित और 4 प्रतिशत के लक्ष्य से नीचे बनी हुई है, तथापि हाल के महीनों में इसमें थोड़ी वृद्धि हुई है। हेडलाइन मुद्रास्फीति अप्रैल 2026 में 3.5 प्रतिशत से बढ़कर मई 2026 में 3.9 प्रतिशत हो गई, जो अन्य बातों के साथ-साथ तेल की कीमतों के प्रभाव विस्तार में वृद्धि को दर्शाती है। तथापि, संघर्ष जनित आपूर्ति आघात और अल नीनो के कारण अनुमानित कमजोर मानसून का संयोजन 2026-27 की तीसरी तिमाही में सहन स्तर के उच्च स्तर की ओर मुद्रास्फीति को बढ़ा सकता है और मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को और बिगाड़ सकता है। तदनुसार, एमपीसी ने अपने मुद्रास्फीति अनुमान को 2026-27 के लिए 4.6 प्रतिशत से ऊर्ध्वगामी संशोधित कर 5.1 प्रतिशत कर दिया।

1.24 कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई (चार्ट 1.17 ए), जिससे भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) बढ़ सकता है, जैसा कि पिछले एपिसोड के दौरान अनुभव किया गया है (चार्ट 1.17 बी)। तथापि, अंतरिम शांति समझौते पर हस्ताक्षर के बाद कच्चे तेल की कीमतों में काफी कमी आई है और इससे सीएडी पर दबाव कम होना चाहिए। स्वर्ण का आयात, जो चालू खाता शेष को प्रभावित करने वाला एक अन्य प्रमुख घटक है, 2025-26 में काफी बढ़ गया जो स्वर्ण की कीमत में भारी वृद्धि को दर्शाता है। तथापि, स्वर्ण के आयात में वृद्धि पिछले महीने की तुलना में मई 2026 में काफी धीमी हो गई (चार्ट 1.17 सी)। पेट्रोलियम और स्वर्ण मिलकर व्यापार घाटे के आधे से अधिक का योगदान करते हैं (चार्ट 1.17 डी), जो बाहरी आघातों के प्रति व्यापार संतुलन की असुरक्षितता को रेखांकित करता है। फिर भी, भारत का सीएडी पिछले तीन वर्षों में जीडीपी के 1 प्रतिशत से भी कम औसत के साथ मामूली बना हुआ है।

चार्ट 1.17: चालू खाते में प्रवृत्तियाँ

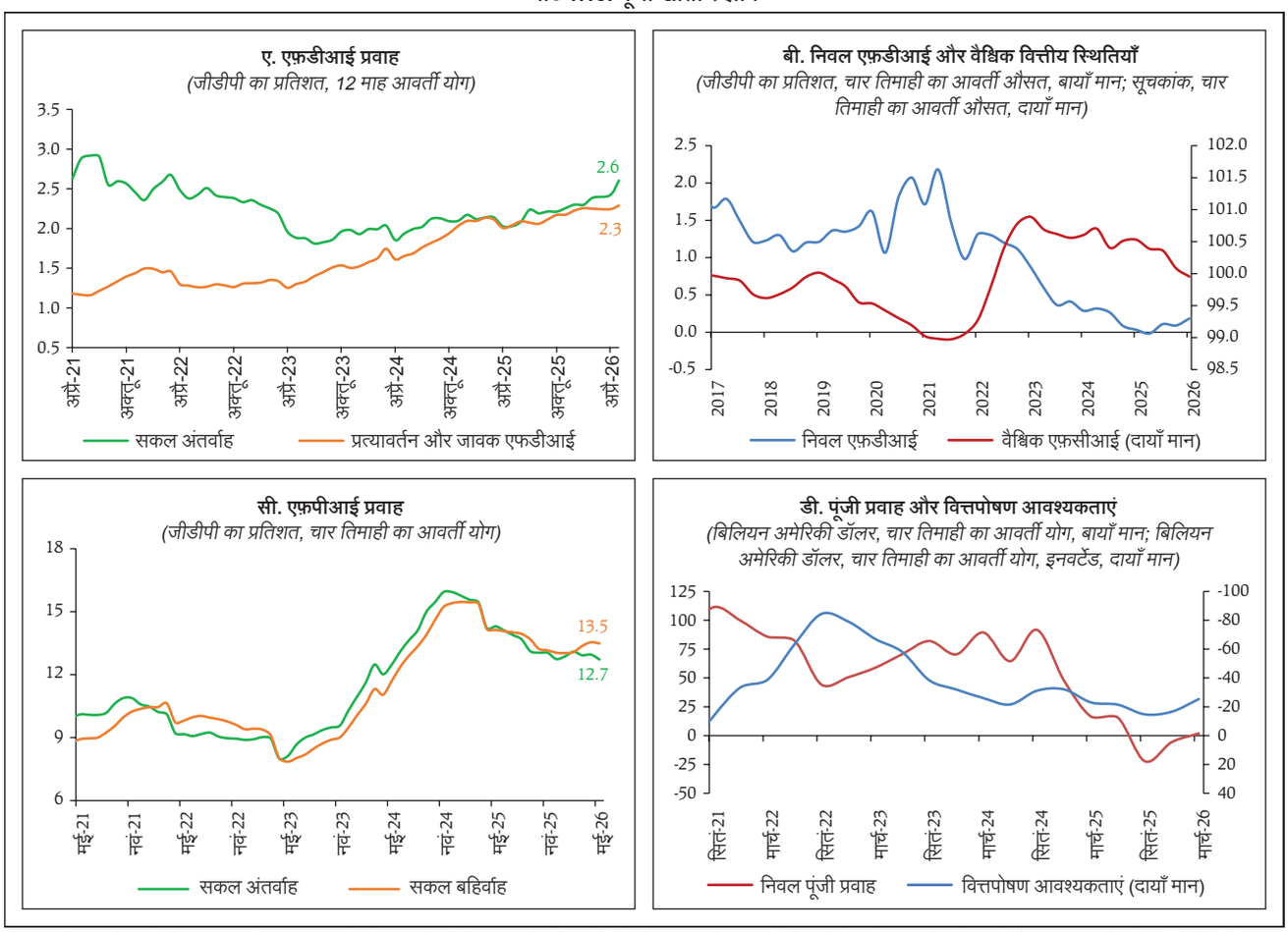


टिप्पणी: चार्ट (ए) में, 26 जून 2026 तक अद्यतन डेटा। चार्ट (बी) में, टी उस तिमाही को दर्शाता है जिसमें तेल की कीमत में आघात आया; टी+1, टी+2 आदि बाद की तिमाहियों को दर्शाते हैं। विचाराधीन घटनाएँ हैं: (i) मांग में वृद्धि (2007), (ii) अरब स्प्रिंग के कारण तेल की कीमत संबंधी आघात (2011), और (iii) रूस-यूक्रेन युद्ध ऊर्जा आघात (2022)।
स्रोत: डीबीआईई; ब्लूमबर्ग; एनएसओ; डीजीसीआई&एस; सीईआईसी; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

1.25 अंतर्वाह में कमी के कारण पूंजी खाता दबाव में रहा है। जबकि सकल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) मजबूत संवृद्धि संभावनाओं के कारण 2025-26 में मजबूत (95 बिलियन अमेरिकी डॉलर) था, निवल एफडीआई प्रवाह प्रत्यावर्तन और उच्च जावक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कारण मंद था (चार्ट 1.18 ए)। पिछले वर्ष अप्रैल में 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में अप्रैल 2026 में 7.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल प्रवाह के साथ निवल एफडीआई में बहाली के संकेत दिख रहे हैं। भारत का निवल एफडीआई वैश्विक वित्तीय स्थितियों के प्रति संवेदनशील है। तदनुसार, निवल एफडीआई में हालिया गिरावट, आंशिक रूप से, वैश्विक वित्तीय स्थितियों के सख्ती को प्रतिबिंबित करती है (चार्ट 1.18 बी)। इसके साथ ही, भारत में विदेशी पोर्टफोलियो प्रवाह 2025-26 में दबाव में रहा है, जो पश्चिम एशिया संघर्ष की शुरुआत के बाद निवेशक मनोभावों के बिगड़ने के कारण बढ़ गया (चार्ट 1.18 सी)। 2025-26 में निवल बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) अंतर्वाह भी कमजोर अंतर्वाह के कारण काफी कम हो गया। 2026-27 में गिरावट जारी है, अप्रैल 2025 की तुलना में अप्रैल 2026 में अंतर्वाह में गिरावट आई है, जो संभावित रूप से उच्च हेजिंग लागत को दर्शाती है (सारणी 1.1)। सरकार और रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित हालिया उपायों से पूंजी प्रवाह को बढ़ावा मिलने की आशा है। इसलिए, भले ही सीएडी बढ़े, मजबूत पूंजी प्रवाह से निधीयन संबंधी बाधाओं के कम होने की संभावना है (चार्ट 1.18 डी)।

1.26 पिछले दो वर्षों में समग्र बीओपी घाटे के बावजूद, भारत का बाह्य क्षेत्र कई मेट्रिक्स में आघात-सहनीय बना हुआ है। 19

चार्ट 1.18: पूंजी खाता रुझान



नोट: चार्ट (ए) और (सी) में, अनुपात की गणना उस वित्तीय वर्ष के संबंधित माह के लिए जीडीपी से 12-माह के आवर्ती योग को विभाजित करके की जाती है; 2026-27 के लिए, पिछले वित्तीय वर्ष के जीडीपी का उपयोग किया गया है। चार्ट (डी) में, चालू खाता घाटा वित्तपोषण आवश्यकता की राशि को दर्शाता है।
स्रोत: डीबीआईई; सीईआईसी; और गोल्डमैन सैक्स।

सारणी 1.1: बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) प्रवाह

(मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

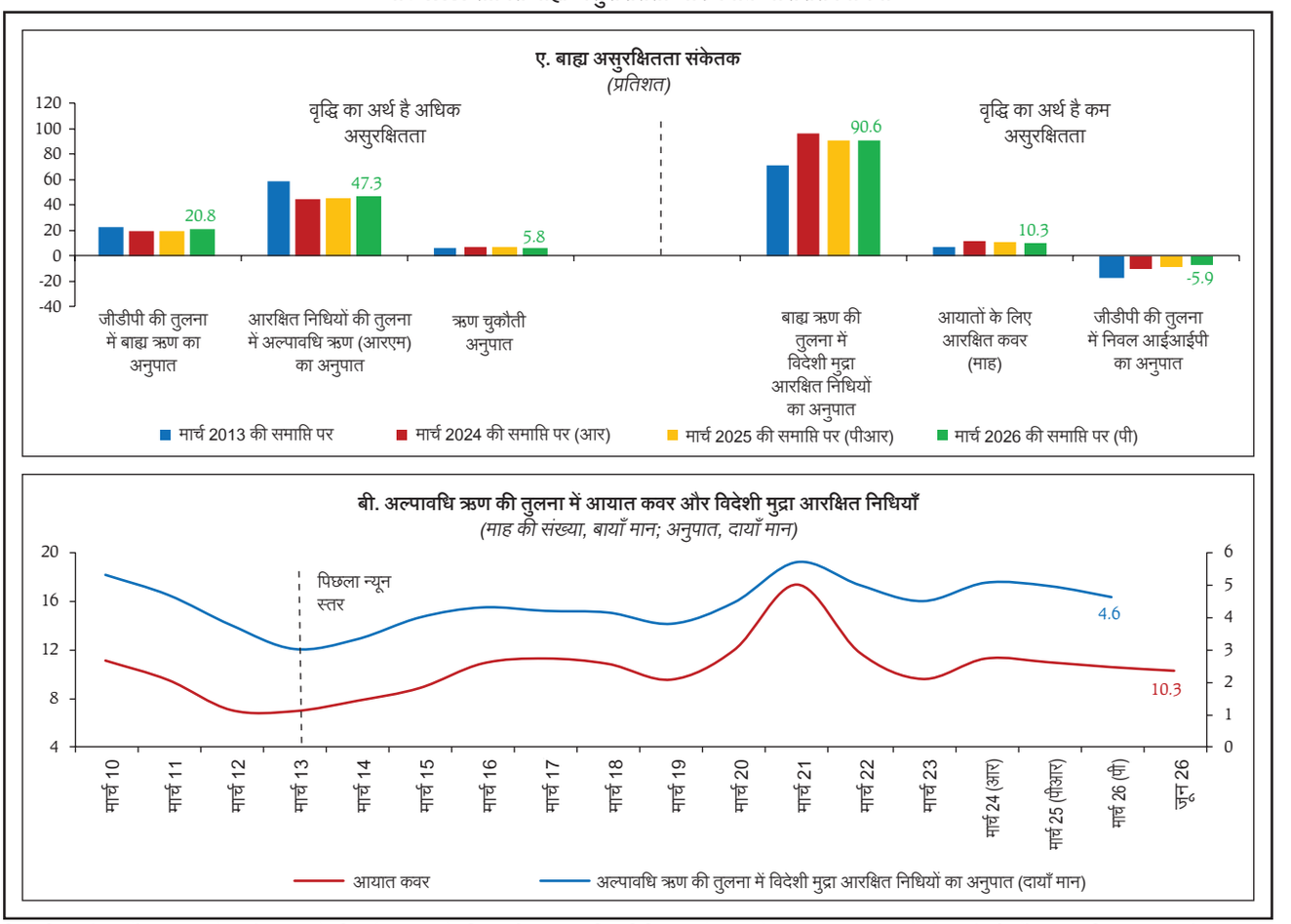
मद	2024-25	2025-26	अप्रै-25	अप्रै-26
(1) ईसीबी करार	**61,184**	**42,969**	**2,917**	**3,765**
जिसमें से, ईसीबी करार -गैर-एफ़डीआई	54,660	37,114	2,426	3,318
(2) ईसीबी अंतर्वाह	**54,969**	**42,557**	**5,079**	**2,694**
जिसमें से, ईसीबी अंतर्वाह -गैर-एफ़डीआई	48,018	35,655	4,543	2,167
(3) ईसीबी बहिर्वाह (मूलधन चुकौती)	**29,514**	**24,353**	**1,703**	**2,174**
जिसमें से, ईसीबी बहिर्वाह-गैर-एफ़डीआई	25,904	21,491	1,289	1,942
(4) निवल ईसीबी अंतर्वाह (2-3)	**25,455**	**18,204**	**3,376**	**520**
***(5)* निवल ईसीबी अंतर्वाह** *(₹ करोड़ में)*	**2,16,249**	**1,60,802**	**28,886**	**4,865**

स्रोत: आरबीआय।

जून 2026 को 672.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां 10 महीनों से अधिक के व्यापारिक माल आयात और बकाया बाह्य ऋण के 90.6 प्रतिशत कवर करती हैं; मार्च 2026 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद का 20.8 प्रतिशत पर बाह्य ऋण अपेक्षाकृत कम था; अवशिष्ट परिपक्वता आधार पर अल्पकालिक ऋण का हिस्सा मार्च 2026 के अंत में विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों का 47.3 प्रतिशत था; और निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी) में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया (चार्ट 1.19 ए और बी)।

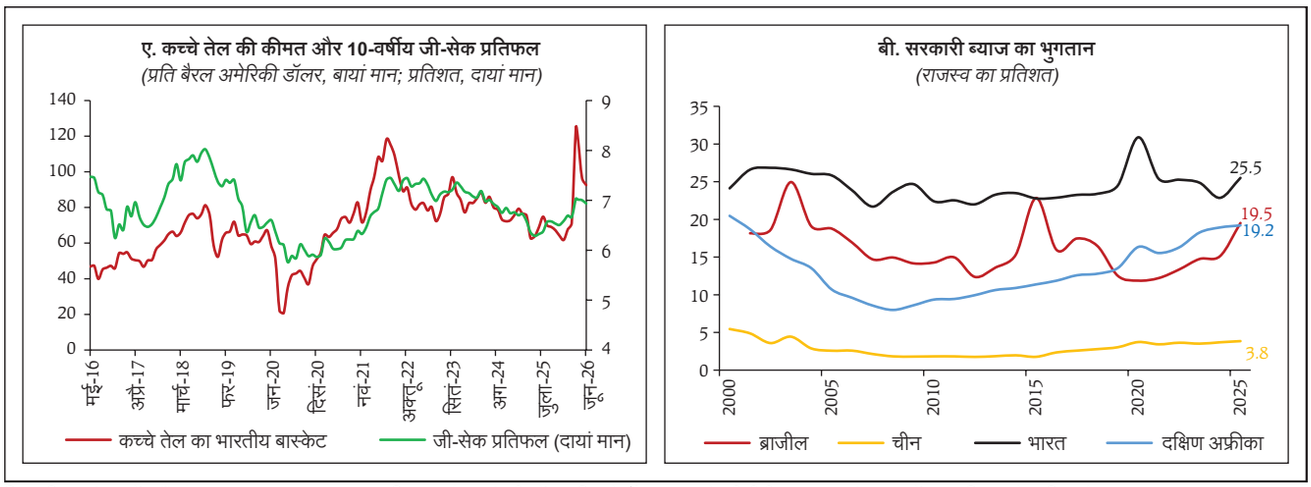
1.27 एक अन्य प्रमुख समष्टि चर है जो कुछ दबाव में आ सकता है, राजकोषीय घाटा। ऊर्जा और अन्य पण्य वस्तुओं

चार्ट 1.19: सीमित बाह्य असुरक्षितता और पर्याप्त आरक्षित निधियाँ



टिप्पणी: चार्ट (ए) में, 'आरएम' शेष परिपक्वता के लिए है। आयात के लिए नवीनतम आरक्षित निधि कवर के आंकड़े 19 जून 2026 तक के हैं। चार्ट (बी) में, अल्पावधि ऋण मूल परिपक्वता पर आधारित है। दोनों चार्टों में, बाह्य ऋण के लिए 'आर' संशोधित आंकड़ों के लिए, 'पीआर' आंशिक रूप से संशोधित आंकड़ों के लिए और 'पी' प्रारंभिक आंकड़ों के लिए है।
स्रोत: आरबीआई; और वित्त मंत्रालय।

चार्ट 1.20: तेल कीमत आघात से उत्पन्न राजकोषीय दबाव



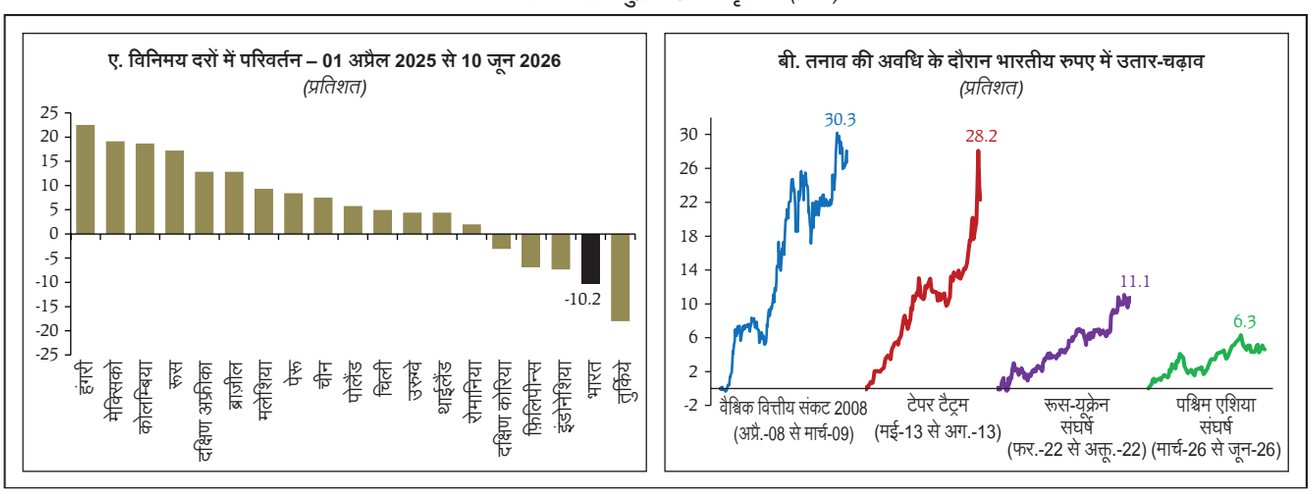
टिप्पणी: चार्ट (ए) में आँकड़े 10 जून 2026 तक अद्यतन किए गए हैं। चार्ट (बी) में चयनित देशों का ऋण-से-जीडीपी अनुपात वर्ष 2025 में 75 प्रतिशत से अधिक है।
स्रोत: आरबीआई; तथा आईएमएफ फिस्कल मॉनिटर, अप्रैल 2026।

की बढ़ी हुई कीमतें सरकारी राजकोष के संतुलन पर बुरा असर डाल सकती हैं। इसकी वजहें हैं - तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का पूरा असर ग्राहकों पर न पड़ना, उत्पाद शुल्क में कटौती और सब्सिडी पर ज़्यादा खर्च। दूसरी तरफ़, सोने और चांदी के आयात पर सीमा शुल्क बढ़ने से सरकारी राजकोष को कुछ राहत मिल सकती है। राजकोषीय स्थिति बिगड़ने से सरकारी बॉन्ड यील्ड बढ़ सकती है और पहले से ज़्यादा कर्ज चुकाने का बोझ और बढ़ सकता है (चार्ट 1.20 ए और बी)। हालांकि, हाल के उपायों के बाद एफ़पीआई ऋण प्रतिभूतियों में अंतर्वाह में आशा के अनुरूप सुधार और ऊर्जा की कीमतों में गिरावट से सरकारी बॉन्ड की मांग बढ़ेगी और यील्ड पर दबाव कम होगा।

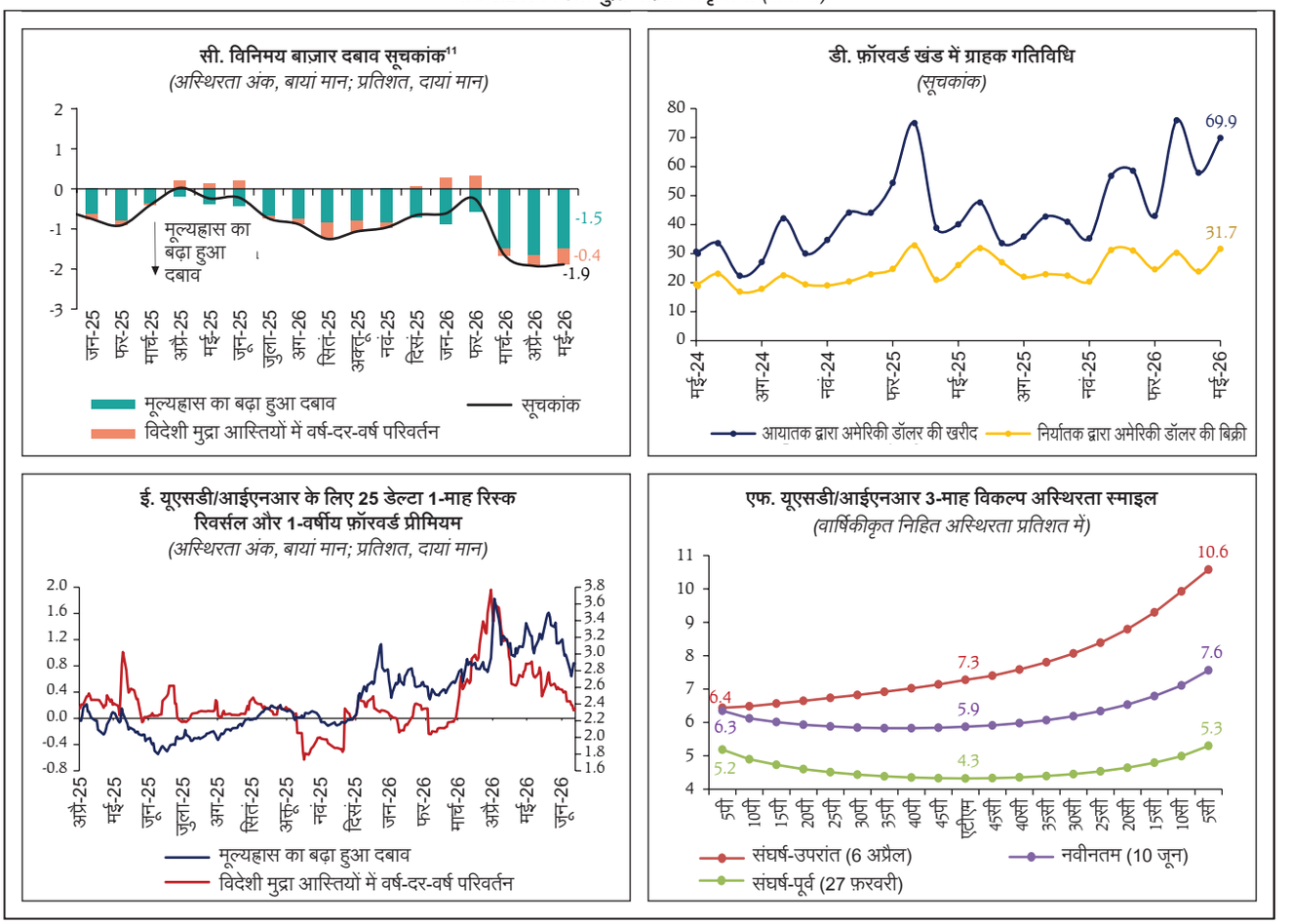
I.2.1 वित्तीय बाजार

1.28 पिछले कई महीनों से भारतीय रुपया व्यापार संबंधी बढ़ी हुई अनिश्चितता, पूंजी प्रवाह में कमजोरी तथा निवेशकों के कमजोर होते रुख के कारण निरंतर मूल्यह्रास के दबाव में रहा है (चार्ट 1.21ए और बी)। यद्यपि रुपये पर दबाव पश्चिम एशिया संघर्ष से पहले से मौजूद था, तथापि इस संघर्ष के प्रारंभ ने मूल्यह्रास के दबाव तथा विनिमय दर की अस्थिरता को और बढ़ा दिया, क्योंकि आयातकों की हेजिंग मांग निर्यातकों की आपूर्ति की तुलना में काफी अधिक हो गई थी (चार्ट 1.21सी एवं डी)। जबकि रुपये के प्रति नकारात्मक भावना में सुधार के संकेत दिखाई दे रहे हैं (चार्ट 1.21 ई), फिर भी मुद्रा डेरिवेटिवों के माध्यम से हेजिंग की लागत संघर्ष-पूर्व अवधि की तुलना

चार्ट 1.21: विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रवृत्तियाँ *(जारी)*



चार्ट 1.21: विदेशी मुद्रा बाज़ार प्रवृत्तियाँ *(समाप्त)*



टिप्पणी: चार्ट (सी) में विनिमय बाज़ार दबाव सूचकांक विनिमय दरों और विदेशी मुद्रा आस्तियों में मानकीकृत परिवर्तनों का उपयोग करके विनिमय दर पर निवल दबाव को मापता है। चार्ट (डी) में आँकड़े प्रत्येक माह के लिए समग्र मूल्य दर्शाते हैं। चार्ट (ई) में रिस्क रिवर्सल की गणना कॉल विकल्पों की निहित अस्थिरता से पुट विकल्पों की निहित अस्थिरता घटाकर की जाती है, जब दोनों का डेल्टा समान होता है। फ़ॉरवर्ड प्रीमियम वह प्रतिशत अंतर है जो किसी मुद्रा की फ़ॉरवर्ड विनिमय दर और स्पॉट विनिमय दर के बीच होता है, जिसकी गणना इस सूत्र से की जाती है: ((फ़ॉरवर्ड दर – स्पॉट दर) / स्पॉट दर) × 100। रिस्क रिवर्सल का सकारात्मक मान यह दर्शाता है कि कॉल विकल्प (यानी अमेरिकी डॉलर के बढ़ने की शर्त) पुट विकल्पों (यानी अमेरिकी डॉलर के गिरने की शर्त) से अधिक महंगे हैं। विभिन्न कारोबार इस प्रीमियम का उपयोग फ़ॉरवर्ड अनुबंध की लागत निर्धारित करने के लिए करते हैं, जिससे वे भविष्य की विनिमय दर को सुरक्षित कर सकते हैं। जब यह शून्य के निकट आता है, तो इसका अर्थ है कि अमेरिकी डॉलर के मज़बूत होने की आक्रामक बाज़ार अपेक्षा कमज़ोर हो रही है। चार्ट (एफ) में प्रदर्शित यूएसडी/आईएनआर विकल्प अस्थिरता स्माइल एक U-आकार का ग्राफ़ीय वक्र है, जो तब उत्पन्न होता है जब यूएसडी/आईएनआर विकल्प अनुबंधों की निहित अस्थिरता को विभिन्न स्ट्राइक कीमतों के विरुद्ध प्लॉट किया जाता है। ये स्ट्राइक कीमतें डेल्टा मनीनेस द्वारा ऑर्डर की जाती हैं, जिसमें आउट-ऑफ़-द-मनी पुट्स (5P से 45P), एट-द-मनी, और आउट-ऑफ़-द-मनी कॉल्स (45C से 5C) शामिल होते हैं, सभी एक ही समाप्ति तिथि के लिए।

स्रोत: ब्लूमबर्ग; एलएसईजी वर्कस्पेस; सीसीआईएल, आईएमएफ ग्लोबल फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, अप्रैल 2026; आरबीआई तथा आरबीआई स्टाफ़ अनुमान।

में अभी भी अधिक बनी हुई है (चार्ट 1.21 एफ)। पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक तथा सरकार द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों तथा कच्चे तेल की कीमतों में कमी से भारतीय रुपये के प्रति बाजार की धारणा में सुधार होने की उम्मीद है।

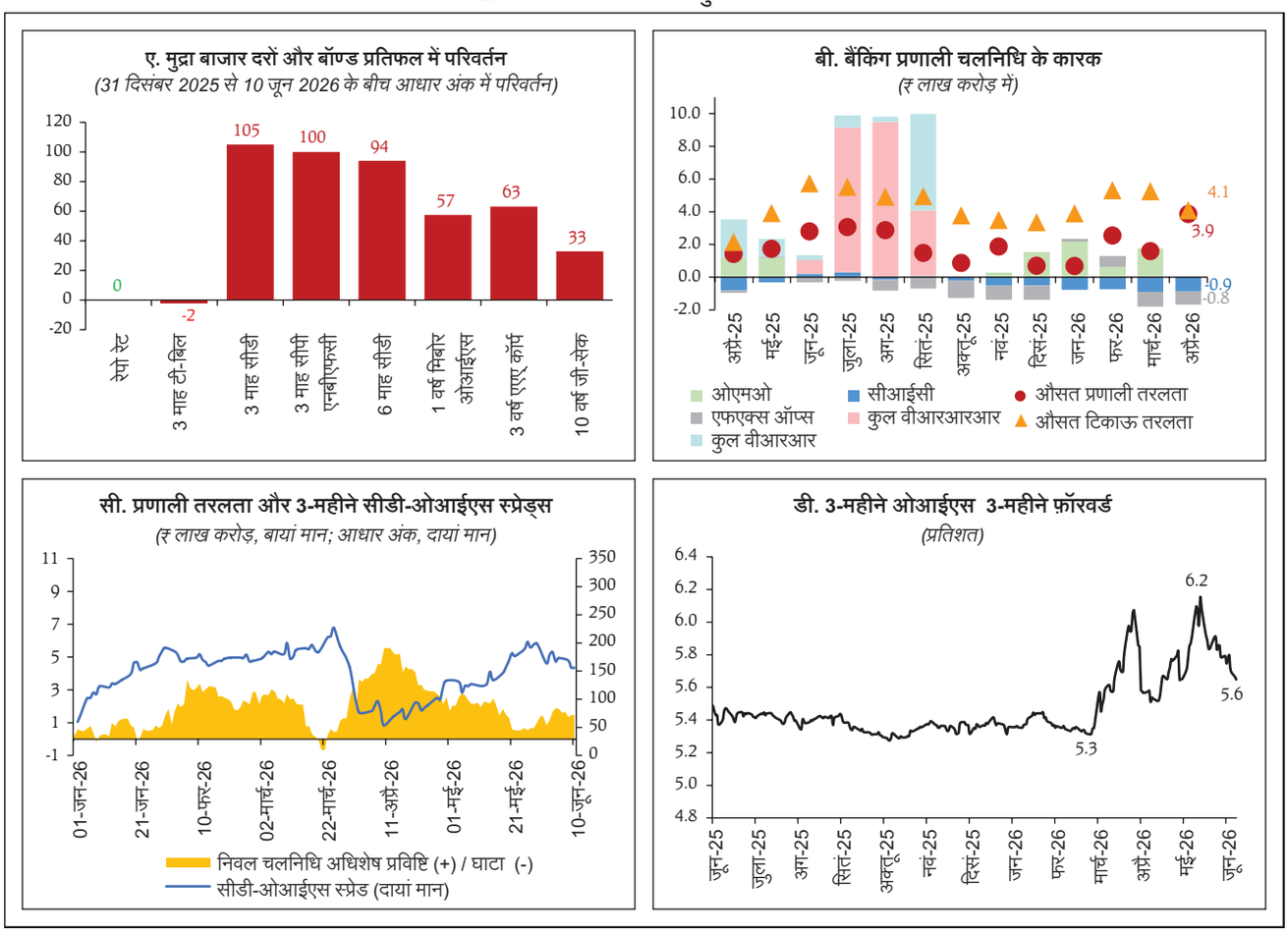
1.29 इस परिप्रेक्ष्य में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा किए जा रहे ऑनशोर-ऑफशोर आधारित कारोबारों से उत्पन्न अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए भी उपाय किए। सामान्यतः ऐसे अंतरपणन लेन-देन से विभिन्न बाजारों के बीच मूल्य विसंगतियों में कमी होने से बाजार

[11] ईएमपी इंडेक्स का उपयोग मुद्रा पर बाहरी दबावों को मापने के लिए किया जाता है और इसका निर्माण विनिमय दर के उतार-चढ़ाव और विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन के भारित औसत के रूप में किया जाता है। $EMP_t = \frac{1}{\sigma_{\Delta e_t}}\Delta e_t + \frac{1}{\sigma_{\Delta r_t}}\Delta r_t$ जहां समय Δe_t समय t पर अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष विनिमय दर में वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तन प्रतिशत है और Δr_t समय t-1 पर मौद्रिक आधार (एम3) के अंश के रूप में समय t पर विदेशी मुद्रा भंडार में वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत परिवर्तन है। $\sigma_{\Delta e_t}$ और $\sigma_{\Delta r_t}$ क्रमशः दो वेरियबल्स के ऐतिहासिक मानक विचलन हैं। अधिक जानकारी के लिए, आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक (अक्टूबर 2007, पृष्ठ संख्या 129-130) का परिशिष्ट 3.1 देखें। चूंकि विदेशी मुद्रा भंडार में मूल्यांकन लाभ शामिल किया जाता है, इसलिए विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में परिवर्तन मुद्रा हस्तक्षेप का अधिक सटीक अनुमान प्रदान करने के लिए लिया जाता है।

की दक्षता में सुधार होता है। हालांकि, ये लेन-देन भारतीय रुपये के निरंतर मूल्यह्रास पर आधारित सट्टेबाज़ी की स्थितियों में परिवर्तित हो गए, जिससे बाजार की स्थितियां अव्यवस्थित हो गईं। अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने तथा बाजार में अव्यवस्था को रोकने की घोषित नीति के अनुरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विनिमय दर की स्थिरता सुनिश्चित करने तथा बाजार की व्यवस्थित कार्यप्रणाली बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए। इनमें ऑनशोर डिलिवरेबल बाजार में भारतीय रुपये में नेट ओपन पोज़ीशन की सीमा को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के भीतर रखना भी शामिल था।[12]

1.30 मुद्रा बाजार का पर्याप्त बैंकिंग प्रणाली चलनिधि अधिशेष के समर्थन से सुव्यवस्थित ढंग से कार्य करना जारी रहा है। मौद्रिक नीति रेपो दर का संचरण मुद्रा बाजार के अल्पकालिक खंड में सुदृढ़ रहा है, जबकि दीर्घकालिक खंड तथा बॉण्ड बाजार में यह अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है (चार्ट 1.22 ए)। भारतीय रिज़र्व बैंक ने टिकाऊ चलनिधि उपलब्ध कराने के लिए कई उपाय किए, जिनमें खुले बाजार परिचालन (ओएमओ), विदेशी मुद्रा खरीद/बिक्री स्वैप नीलामियां तथा परिवर्ती दर रेपो नीलामियां शामिल हैं(चार्ट 1.22 बी)। इन उपायों के बावजूद, जमा प्रमाणपत्रों तथा समान परिपक्वता अवधि वाले ओवरनाइट इंडेक्स्ड स्वैप (ओआईएस) के बीच

चार्ट 1.22: मौद्रिक नीति प्रसारण में कुछ अवरोध बरकरार



टिप्पणी: चार्ट (बी) में (+) / (-) चिह्न क्रमशः बैंकिंग प्रणाली की चलनिधि में वृद्धि या कमी को दर्शाता है।
स्रोत: ब्लूमबर्ग; एलएसईजी वर्कस्पेस; एफबीआईएल; एफआईएमएमडीए; तथा आरबीआई।

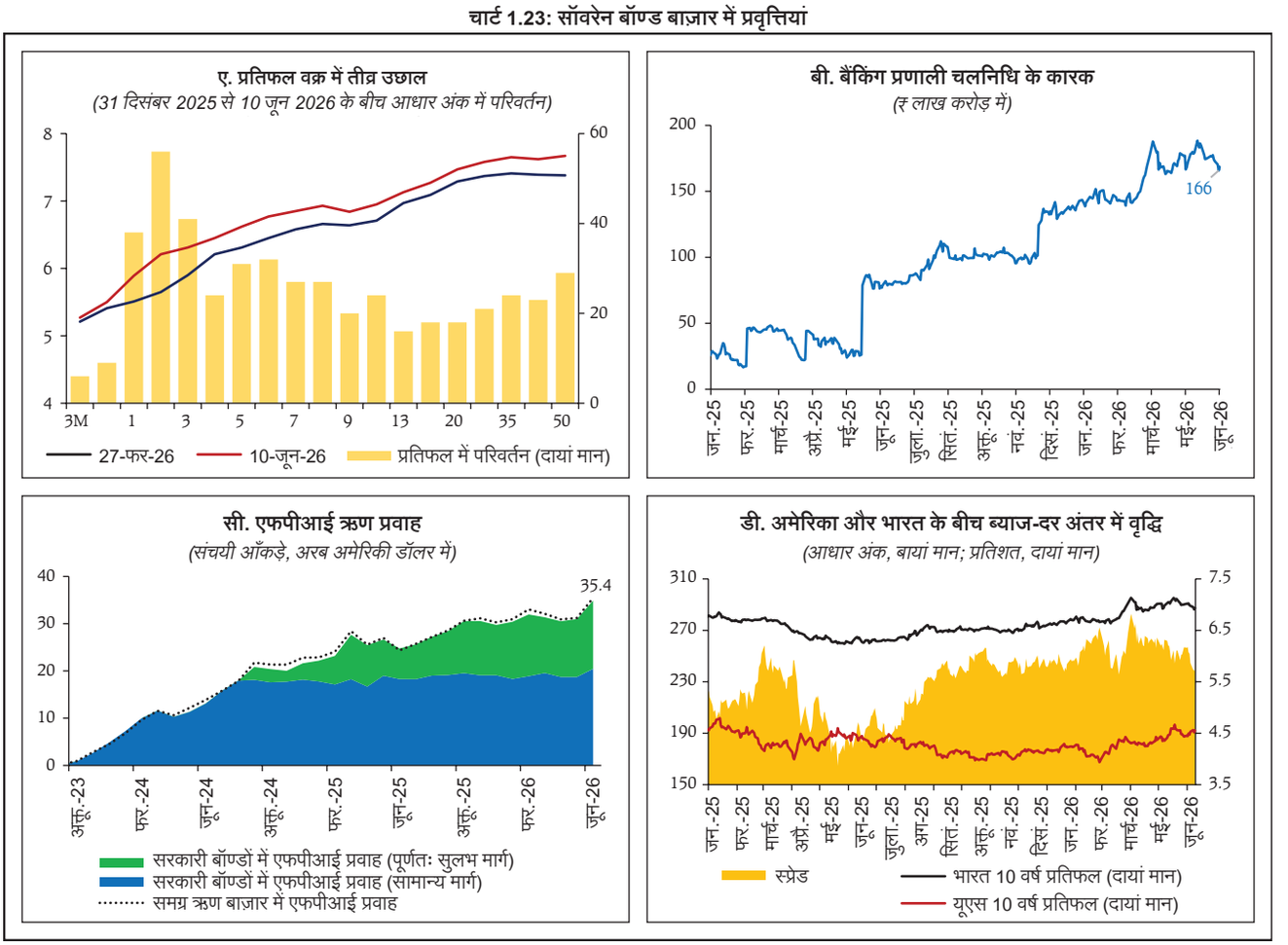
[12] एनओपी-आईएनआर सीमा की वजह से बैंकों की कुल तटवर्ती प्रदेय वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य में भविष्य में होने वाली वृद्धि को नियत अवधि के भीतर निर्धारित सीमाओं के अंदर लाने के लिए अधिक्रय की स्थिति को कम करना जरूरी हो गया है।

का का स्प्रेड जो कि मुद्रा बाजार में तनाव का मुख्य मान है- हाल की अवधि में बढ़ गया है (चार्ट 1.22 सी)। ओआईएस दरों ने पिछले कुछ महीनों में काफी अस्थिरता प्रदर्शित की है जो कि बदलती हुई चलनिधि परिस्थितियों तथा वर्धित अनिश्चितता को प्रतिबिंबित करती हैं- तीन माह के ओआईएस दर मई 2026 में बढ़ने के बाद जून 2026 में उल्लेखनीय रूप से घट गया (चार्ट 1.22 डी)। मौसमी नरमी की सामान्य प्रवृत्ति के विपरीत, वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में सीडी दरें ऊंचे स्तर पर बनी रहीं। इसका मुख्य कारण वित्तपोषण दबाव में वृद्धि था, क्योंकि ऋण वृद्धि जमा वृद्धि की तुलना में काफी अधिक रही। पूंजी प्रवाह को बढ़ाने के लिए हाल में की गई पहलों से निकट अवधि में पूंजी प्रवाह की स्थिति में सुधार होने तथा बैंकों में रुपये की तरलता बढ़ने की उम्मीद है, जिससे मुद्रा बाजार दरों पर दबाव कम हो सकता है।

1.31 पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के बाद से, सॉवरेन बॉण्ड यील्ड कर्व में, विशेष रूप से अल्पकालिक खंड में, तीव्र वृद्धि देखी गई है (चार्ट 1.23 ए)। परिणामस्वरूप, टर्म स्प्रेड का अंतर बढ़ गया है (चार्ट 1.23 बी)। इस बीच, भारतीय सरकारी बॉण्डों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) का निवेश प्रवाह स्थिर बना रहा, जिसका एक कारण अमेरिका और भारत के सॉवरेन यील्ड के बीच ब्याज दर अंतर का बढ़ना भी रहा (चार्ट 1.23 सी एवं डी)।

1.32 विकसित हो रही समष्टि आर्थिक गतिशीलता तथा बाह्य कारकों के अलावा, मांग और आपूर्ति की गतिशीलता भी केंद्र सरकार प्रतिभूतियों (जी-सेक) के प्रतिफलों को प्रभावित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हाल के वर्षों में राज्य सरकार प्रतिभूतियों (एसजीएस) के निर्गमों में तीव्र

चार्ट 1.23: सॉवरेन बॉण्ड बाज़ार में प्रवृत्तियां

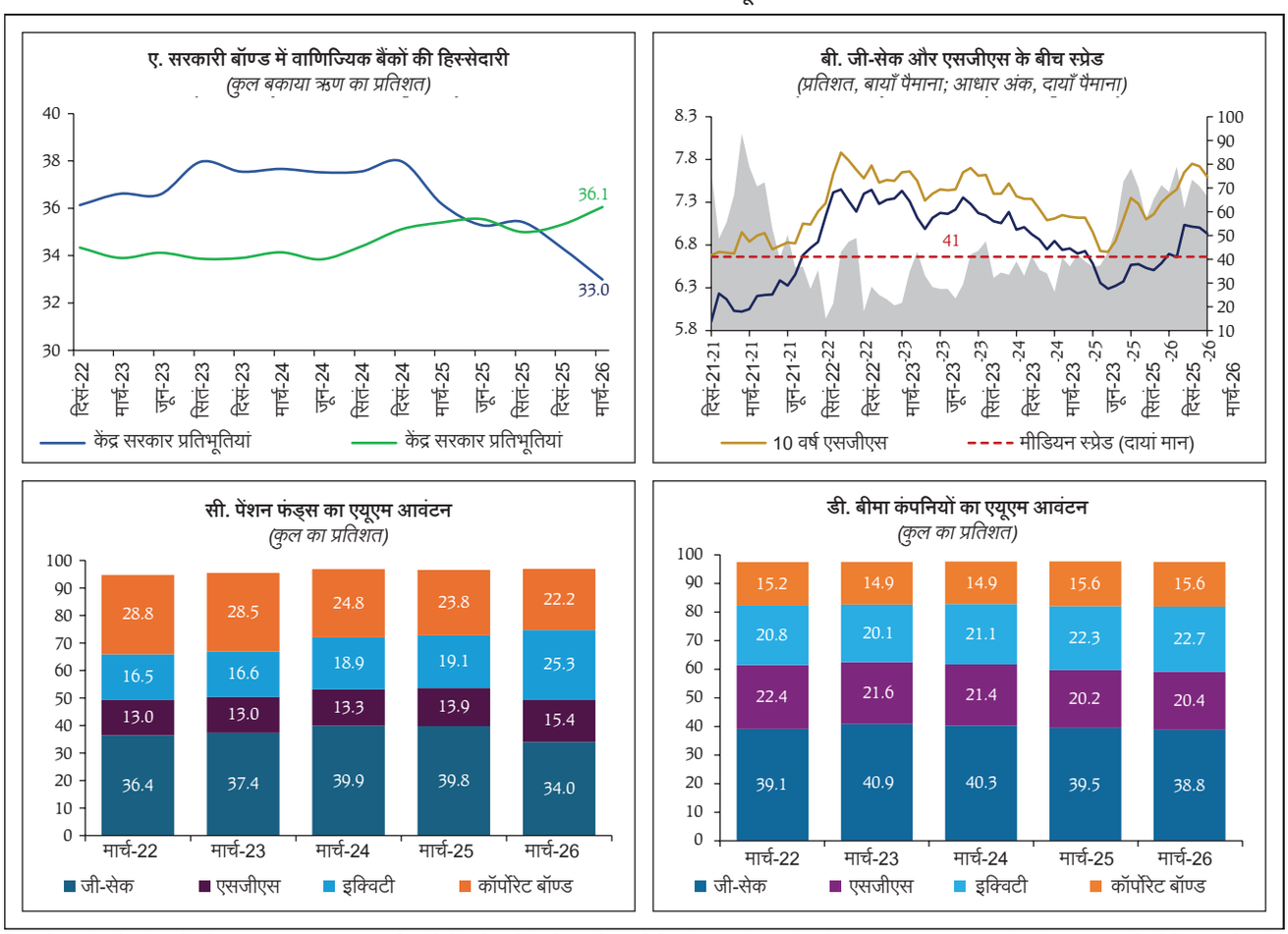


Note: In chart (a), semi-annual G-sec par yield curve is considered. In chart (c), data up to June 23, 2026.
Sources: Bloomberg; FBIL; and CCIL.

वृद्धि हुई है और उनकी अपेक्षाकृत अधिक प्रतिफल दरों के कारण बैंकों ने इन प्रतिभूतियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है (चार्ट 1.24 ए और बी)। वहीं दूसरी ओर, बीमा कंपनियों और पेंशन निधियों जैसे दीर्घकालिक संस्थागत निवेशकों ने धीरे-धीरे अपने निवेश पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा इक्विटी (शेयर बाजार) में निवेश कर अपने निवेश पोर्टफोलियों में विविधता लाई है (चार्ट 1.24 सी और डी)। इन घटनाक्रमों के वित्तीय स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकते हैं। एसजीएस में बैंकों का बढ़ता हुआ निवेश राज्य सरकारों के वित्त और बैंकों की बैलेंस शीटों के बीच संबंधों को और मजबूत कर सकता है, जिसके कारण उप-राष्ट्रीय स्तर पर राजकोषीय जोखिमों की कड़ी निगरानी आवश्यक हो जाती है। इसके अतिरिक्त, अधिक प्रतिफल वाली सरकारी प्रतिभूतियों के प्रति लगातार बढ़ती प्राथमिकता, सीमांत स्तर पर, बैंकों के अधिक संसाधनों को सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के योग्य निवेशों की ओर मोड़ सकती है। परिणामस्वरूप, निजी क्षेत्र के लिए उपलब्ध ऋण प्रवाह में कमी आ सकती है।

1.33 वर्ष 2025-26 में भारतीय प्रतिभूति बाजार से कुल संसाधन जुटाना मामूली रूप से घटकर ₹15.3 लाख करोड़ रह गया, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 2.3 प्रतिशत कम था। यह गिरावट बढ़ी हुई आर्थिक अनिश्चितता के माहौल में दर्ज की गई। इस कमी का मुख्य कारण ऋण जारी करने में 8.4 प्रतिशत की गिरावट थी। इसके विपरीत, इक्विटी के जारी किए जाने की स्थिति मजबूत बनी रही और इसमें 4.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। यह वृद्धि मुख्यतः रिकॉर्ड 366 प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) के कारण हुई, जिनके माध्यम से वर्ष 2025-26 में ₹1.9 लाख करोड़ जुटाए गए (सारणी 1.2)।

चार्ट 1.24: सरकारी बॉण्ड बाजार में मांग-आपूर्ति की गतिशीलता



टिप्पणी: चार्ट (सी)और (डी) में संतुलन आवंटन 'अन्य' आस्तियों में है, जिसमें वैकल्पिक निवेश निधि, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स आदि में निवेश शामिल है।
स्रोत: ब्लूमबर्ग; डीबीआईई; पीएफआरडीए और आईआरडीएआई।

सारणी 1.2: भारतीय प्रतिभूति बाजार में संसाधन जुटाना

(₹ लाख करोड़)

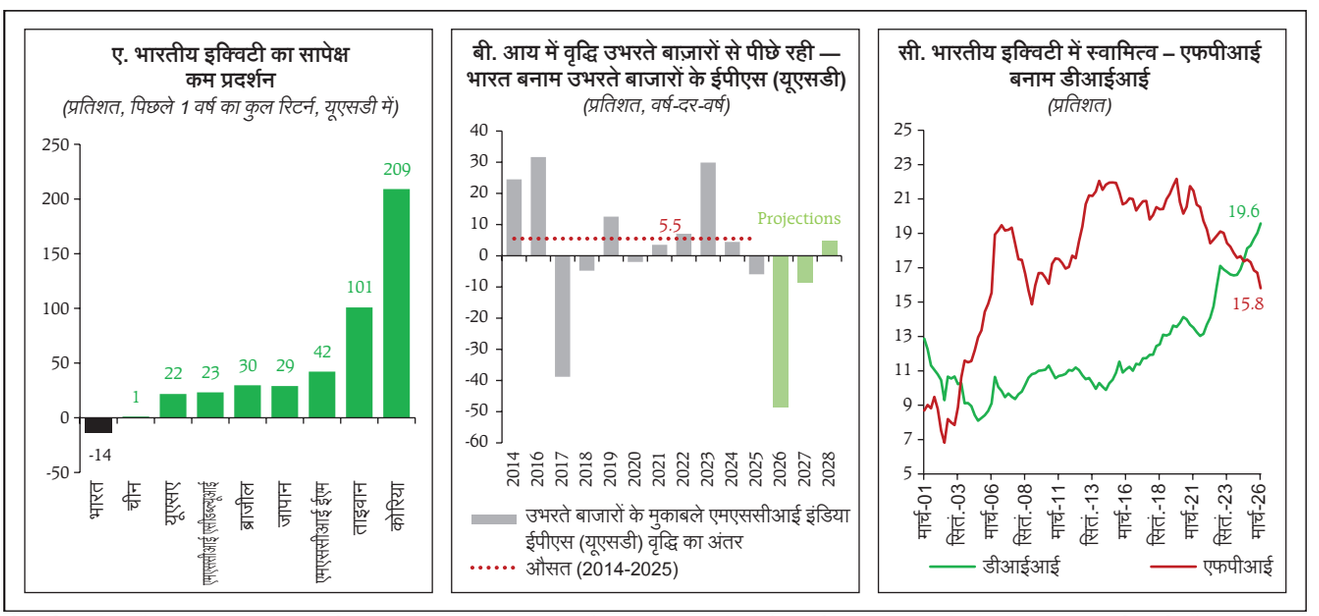
श्रेणी	2023-24	2024-25	2025-26
इक्विटी - सार्वजनिक	0.83	2.10	2.35
इक्विटी - निजी	1.14	2.20	2.16
ऋण - सार्वजनिक	0.19	0.08	0.11
ऋण - सूचीबद्ध आधार पर निजी	8.38	9.87	9.00
रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट	0.06	0.05	0.09
इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट	0.33	0.27	0.21
वैकल्पिक निवेश निधि	0.86	1.11	1.39
कुल	11.80	15.68	15.32

स्रोत: सेबी।

1.34 घरेलू इक्विटी बाजार, जो पिछले वर्ष से उभरते बाजारों के समकक्ष बाजारों की तुलना में पिछड़ रहा था, भारत की आपूर्ति-आघात के प्रति संवेदनशीलता तथा इसके परिणामस्वरूप कॉर्पोरेट आय वृद्धि में नरमी को लेकर चिंताओं के कारण नीचे आया (चार्ट 1.25 ए)। उभरते बाजारों की तुलना में भारत की आय-वृद्धि का अंतर अपने दीर्घकालिक औसत से नीचे आ गया है (चार्ट 1.25 बी)। भारतीय इक्विटी बाजार का अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की लंबे समय तक और बड़े पैमाने पर की गई बिकवाली के साथ देखा गया, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय इक्विटी में उनकी हिस्सेदारी दो दशकों के न्यूनतम स्तर पर पहुँच गई तथा घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) की हिस्सेदारी से भी कम हो गई (चार्ट 1.25 सी)।

1.35 वर्ष 2026 में एफपीआई द्वारा इक्विटी से 30.7 अरब अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह दर्ज किया गया[13], जो वर्ष 2025 में दर्ज 18.9 अरब अमेरिकी डॉलर के पूर्व रिकॉर्ड से भी अधिक है। यह पिछले लगभग ढाई दशकों का सर्वाधिक स्तर है (चार्ट 1.26 ए और बी)। उच्च इक्विटी मूल्यांकन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित निवेश अवसरों का अभाव तथा अपेक्षाकृत कम आय-वृद्धि ने निवेशकों के रुख को प्रभावित किया। इक्विटी खंड में एफपीआई की अभिरक्षाधीन आस्तियां (एयूसी) दिसंबर 2025 के लगभग ₹74.3 लाख करोड़ से घटकर मई 2026 में लगभग ₹67.7 लाख करोड़ रह गईं। इस अवधि में लगभग ₹6.6 लाख करोड़ की कमी मुख्यतः

चार्ट 1.25: भारतीय इक्विटी बाज़ार का प्रदर्शन और स्वामित्व



टिप्पणी: चार्ट (ए) में, 10 जून 2026 को समाप्त पिछले 1 वर्ष के कुल रिटर्न को ध्यान में रखा गया है। कुल रिटर्न में (i) पूंजीगत लाभ (प्राइस रिटर्न) और (ii)लाभांश प्राप्तियां, जिन्हें मूल सूचकांक में पुनर्निवेशित मान लिया गया है, शामिल हैं। एमएससीआई ईएम और एमएससीआई एसीडब्ल्यूआई को क्रमशः उभरते बाज़ारों और विश्व के प्रतिनिधि सूचकांक के रूप में लिया गया है। अलग-अलग देशों को उनके संबंधित एमएससीआई सूचकांकों द्वारा दर्शाया गया है। चार्ट (बी) में अनुमानित कमाई ब्लूमबर्ग से ली गई है। चार्ट (सी) में, डीआईआई का अर्थ है घरेलू संस्थागत निवेशक, जिसमें घरेलू म्यूचुअल फंड, बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां और अन्य संस्थागत गैर-प्रमोटर निवेशक शामिल हैं।

स्रोत: ब्लूमबर्ग, ब्लूमबर्ग कंसेंसस एस्टीमेट्स और सेबी।

[13] 12 जून, 2026 तक अद्यतन किए गए आंकड़े।

चार्ट 1.26: बढ़े हुए भू-राजनीतिक जोखिमों के बीच एफपीआई इक्विटी बहिर्वाह



टिप्पणी: चार्ट (ए) में डेटा 12 जून 2026 तक का है। चार्ट (सी) में दिसंबर-25 से मई-26 तक एफपीआई के एयूसी में परिवर्तन को बाज़ार प्रदर्शन (मूल्यांकन परिवर्तन) और प्रत्येक माह के प्रवाह में विभाजित किया गया है।

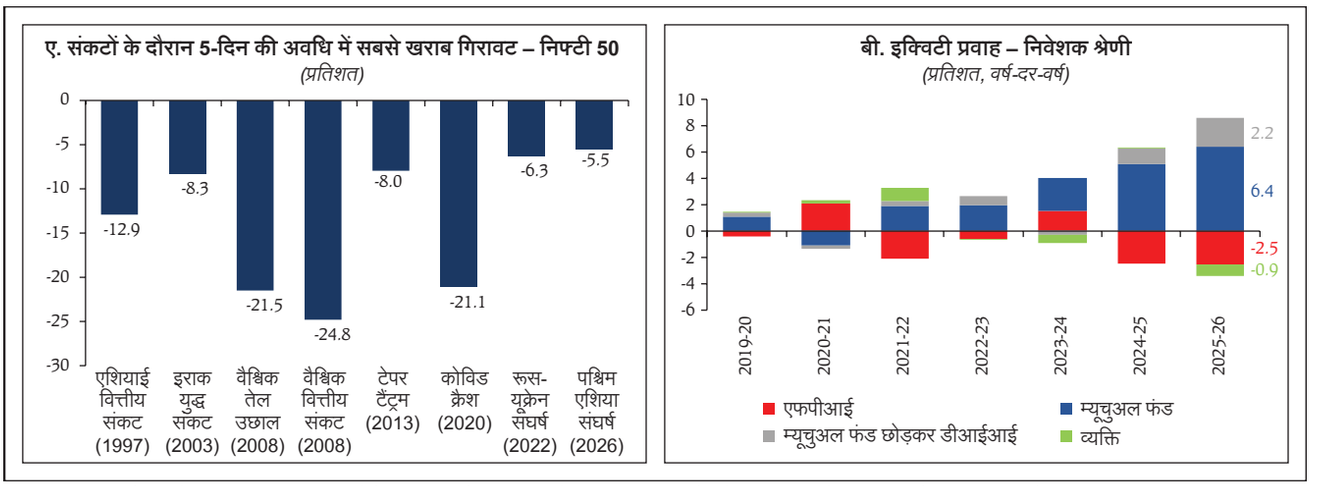
स्रोत: एनएसडीएल; ईपीएफआर और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

लगभग ₹4.3 लाख करोड़ के मूल्यांकन घाटे के कारण हुई, जबकि निवल बहिर्वाह ने कुल गिरावट में लगभग ₹2.3 लाख करोड़ का योगदान दिया (चार्ट 1.26 सी)। इसके अतिरिक्त, एफपीआई के पोर्टफोलियो आवंटन की प्रवृत्ति से संकेत मिलता है कि उभरते बाजार फंडों में भारत की हिस्सेदारी में भी कमी आई है (चार्ट 1.26 डी)।

1.36 इक्विटी बाजारों में तीव्र गिरावट के बावजूद उनकी आघातसहनीयता क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। विभिन्न संकट अवधियों के दौरान पाँच-दिवसीय अवधि में अधिकतम गिरावट के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्तमान प्रकरण में यह सबसे कम रही है (चार्ट 1.27 ए) । घरेलू संस्थागत निवेशकों, जैसे म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों के बढ़ते समर्थन ने घरेलू इक्विटी बाजार की स्थिरता और लचीलेपन को और मजबूत किया है (चार्ट 1.27 बी)।

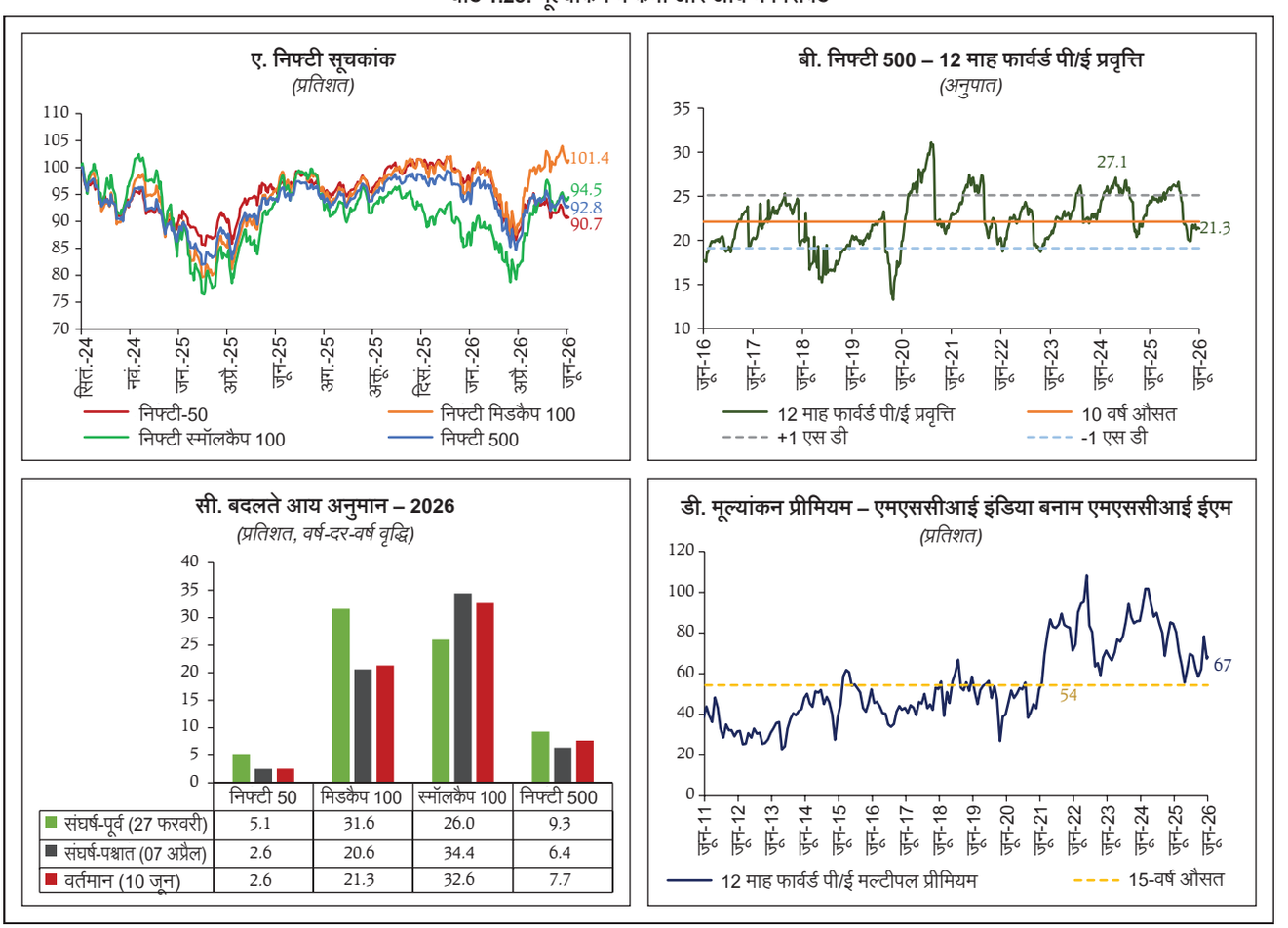
1.37 हाल में इक्विटी बाजारों में आई गिरावट के कारण पहले से ऊँचे मूल्यांकन स्तरों में कमी आई है और वे अपने ऐतिहासिक औसत के अधिक निकट पहुँच गए हैं (चार्ट 1.28 ए और बी) । इसके साथ ही, वर्ष 2026 के लिए आय के अनुमानों को संशोधित कर नीचे लाया गया है, हालांकि स्मॉल-कैप सूचकांक इसका अपवाद रहा है (चार्ट 1.28 सी)। फिर भी, भारतीय इक्विटी बाजार उभरते बाजारों के अन्य समकक्ष बाजारों की तुलना में प्रीमियम मूल्यांकन पर कारोबार करना जारी रखे हुए है (चार्ट 1.28 डी)।

चार्ट 1.27: संस्थागत मांग से समर्थित सुदृढ़ इक्विटी बाज़ार



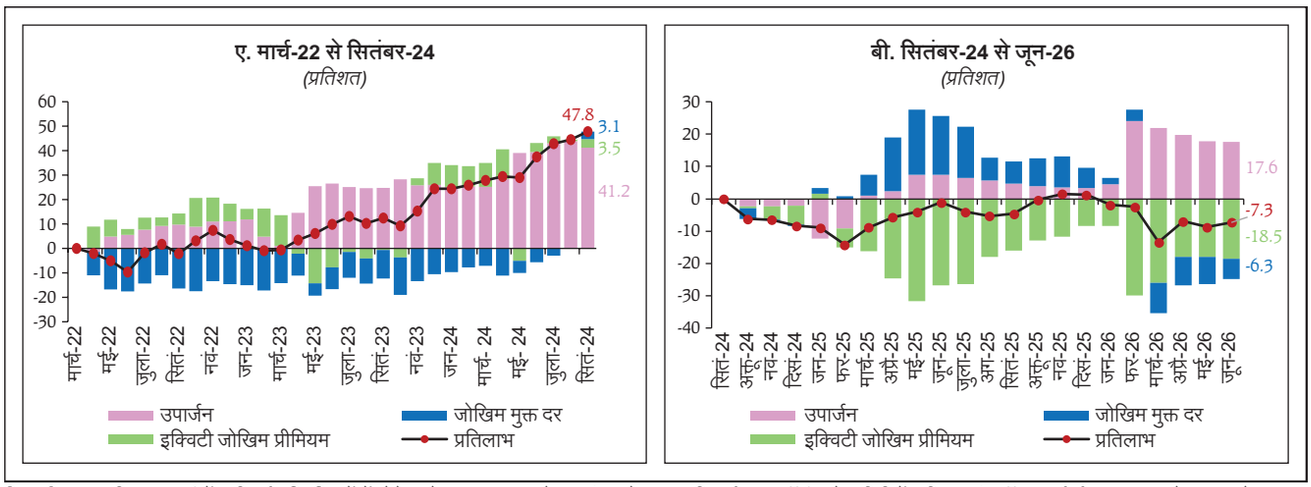
टिप्पणी: चार्ट (ए) में 'सबसे खराब' गिरावट का अर्थ है तेल मूल्य झटके की अवधि में 5-दिन की अवधि के दौरान सूचकांक के उच्चतम और न्यूनतम स्तर के बीच का अंतर।
स्रोत: एनएसई; एसएसडीएल; और बीएसई।

चार्ट 1.28: मूल्यांकन में कमी और आय में गिरावट



टिप्पणी: चार्ट (डी) में 15-वर्षीय औसत जनवरी-2011 से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए लिया गया है।
स्रोत: ब्लूमबर्ग।

चार्ट 1.29: निफ्टी 50 – प्रतिफल वियोजन



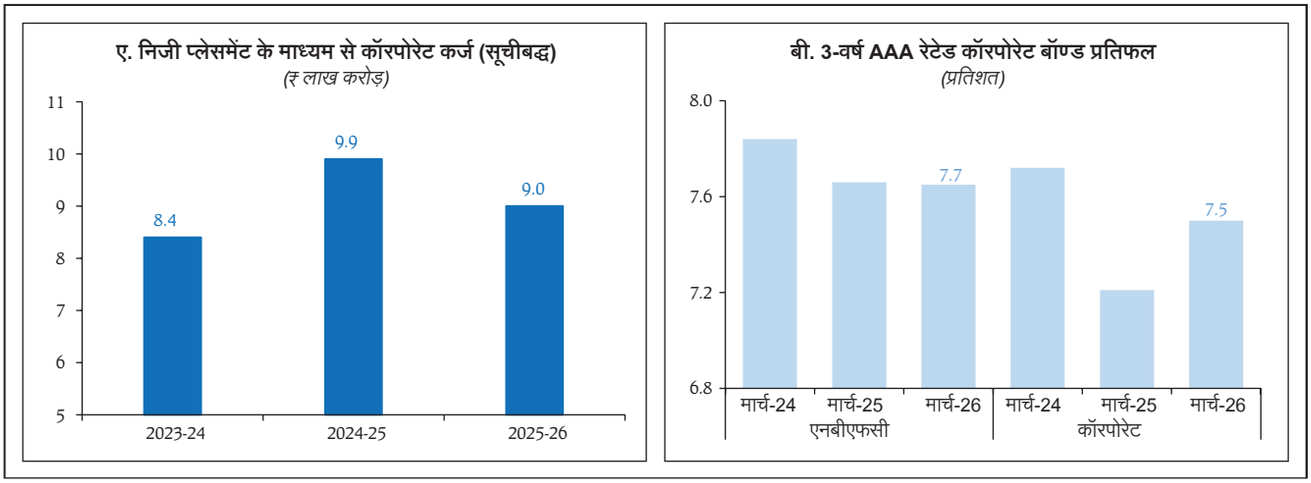
टिप्पणी: ऊपर दिए गए चार्ट में, इक्विटी की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को मूल्यांकन के एक बुनियादी टूल, गॉर्डन ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल (डीडीएम) का इस्तेमाल करके समझा गया है। डीडीएम फ्रेमवर्क वर्तमान बट्टागत मूल्य दृष्टिकोण का इस्तेमाल करके इक्विटी का मूल्य तय करता है और उपार्जन में बढ़ोत्तरी की उम्मीदें, जोखिम- मुक्त दर और इक्विटी जोखिम प्रीमियम (ईआरपी) सहित इक्विटी की कीमतों में बदलाव के कारकों को समझने में मदद करता है। चार्ट (बी) में आंकड़े 10 जून 2026 तक अद्यतीत किए गए हैं।
स्रोत: ब्लूमबर्ग; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

1.38 हाल की गिरावट ने निफ्टी 50 के प्रतिलाभ को कम कर दिया है और इक्विटी जोखिम प्रीमियम में कमी (चार्ट 1.29 ए) से पहले हुई बढ़त को खत्म कर दिया है, क्योंकि निवेशकों में जोखिम से बचने की प्रवृत्ति बढ़ने से जोखिम प्रीमियम बढ़ गए हैं (चार्ट 1.29 बी)।

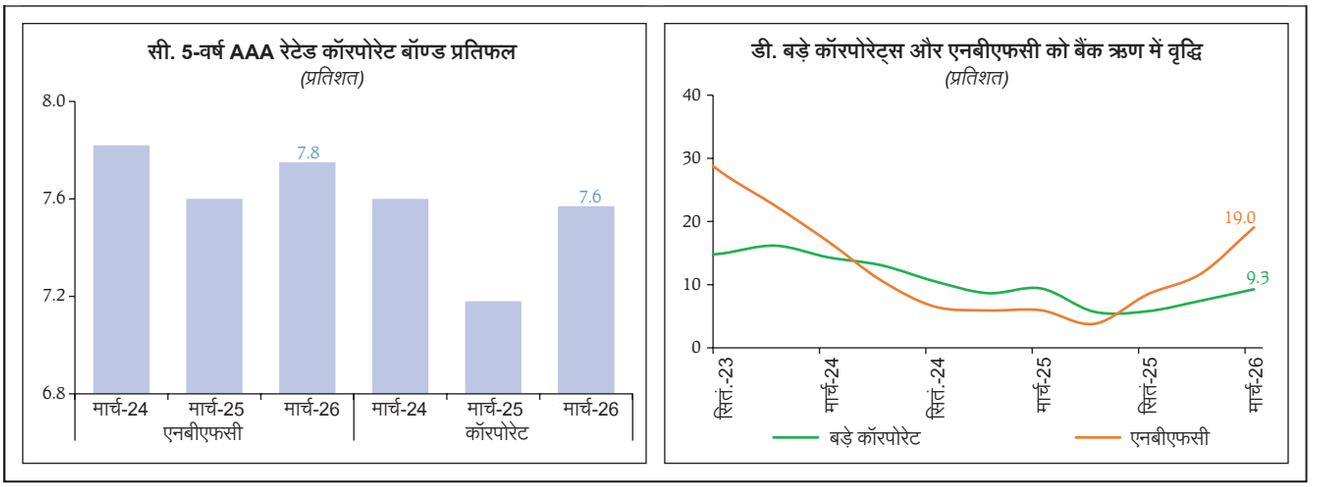
1.39 बॉण्ड प्रतिफल में आम बढ़ोतरी के बीच, 2025-26 में कॉरपोरेट बॉण्ड निर्गम में कमी आई, जैसा कि पिछले साल की तुलना में सूचीबद्ध निजी प्लेसमेंट रूट के ज़रिए जारी किए गए बॉण्ड से पता चलता है। नीतिगत दर के उधार संबंधी ब्याज दर पर सुदृढ़ संचरण के कारण, बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ने बैंक ऋण का ज़्यादा इस्तेमाल किया है (चार्ट 1.30 ए, बी, सी और डी)।

1.40 मार्च 2026 के आखिर तक बकाया कॉरपोरेट कर्ज बढ़कर ₹59.1 लाख करोड़ हो गया। हालांकि, हाल के वर्षों में लाभ के बावजूद, 2025–26 में औसत मासिक टर्नओवर 3.2 प्रतिशत पर कम बना रहा (चार्ट 1.31 ए)। नए जारी किए गए बॉण्ड में AAA-रेटिंग वाले उधारकर्ताओं की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आई है, जो अन्य रेटिंग श्रेणियों की ज़्यादा मांग को दिखाता है। इसके परिणामस्वरूप, 2022-23 में AA-रेटिंग से कम वाले बॉण्ड की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत थी, जो 2025–26 में बढ़कर 25 प्रतिशत हो गई (चार्ट 1.31 बी)। संसाधन जुटाने के लिए निजी प्लेसमेंट अधिमानित तरीका बना रहा, और केवल एनबीएफसी ही ऐसी संस्थाएं

चार्ट 1.30: प्रतिफल और बैंक ऋण में बढ़ोत्तरी के बीच कॉर्पोरेट बॉण्ड जारी करने में गिरावट *(जारी..)*



चार्ट 1.30: प्रतिफल और बैंक ऋण में बढ़ोत्तरी के बीच कॉर्पोरेट बॉण्ड जारी करने में गिरावट *(समाप्त)*



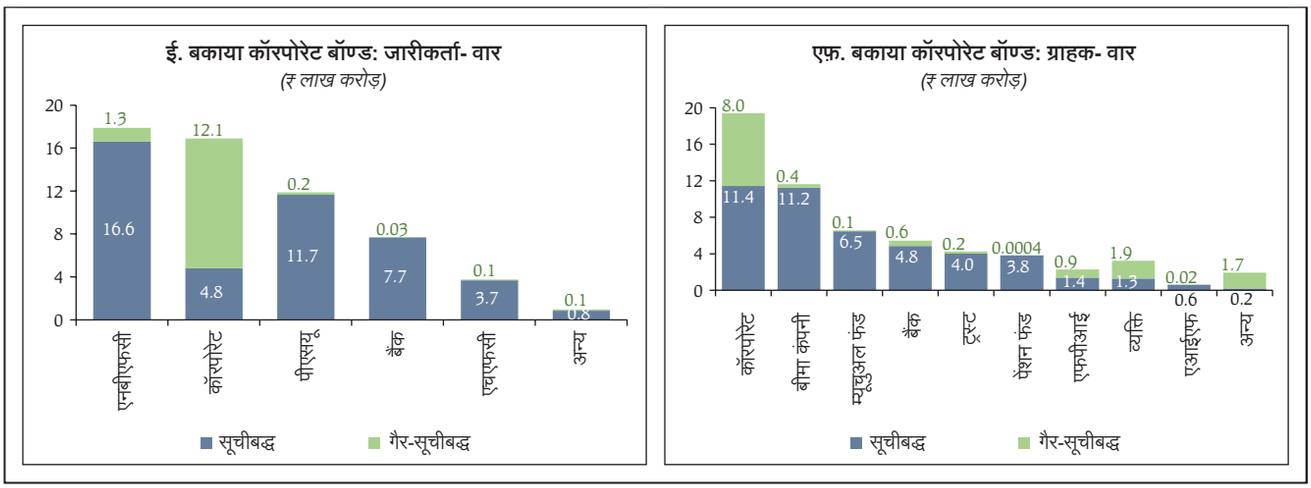
स्रोत: सेबी; एफ़आईएमएमडीए; और आरबीआई पर्यवेक्षी रिटर्न।

थीं जिन्होंने पब्लिक बॉण्ड जारी करने में उल्लेखनीय रुचि दिखाई (चार्ट 1.31 सी)। अस्थिर दर लिखत—जो प्राथमिक रूप से मुद्रा बाजार दरों, सरकारी प्रतिभूतियों और इक्विटी बेंचमार्क से जुड़े होते हैं—की हिस्सेदारी बढ़ी है (चार्ट 1.31 डी)। एनबीएफसी और गैर-वित्तीय कंपनियां मुख्य रूप से निधि जुटाने वाले बने रहे, जबकि सूचीबद्ध कॉरपोरेट बॉण्ड

चार्ट 1.31: कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार रुझान *(जारी)*



चार्ट 1.31: कॉरपोरेट बॉण्ड बाजार रुझान *(समाप्त)*



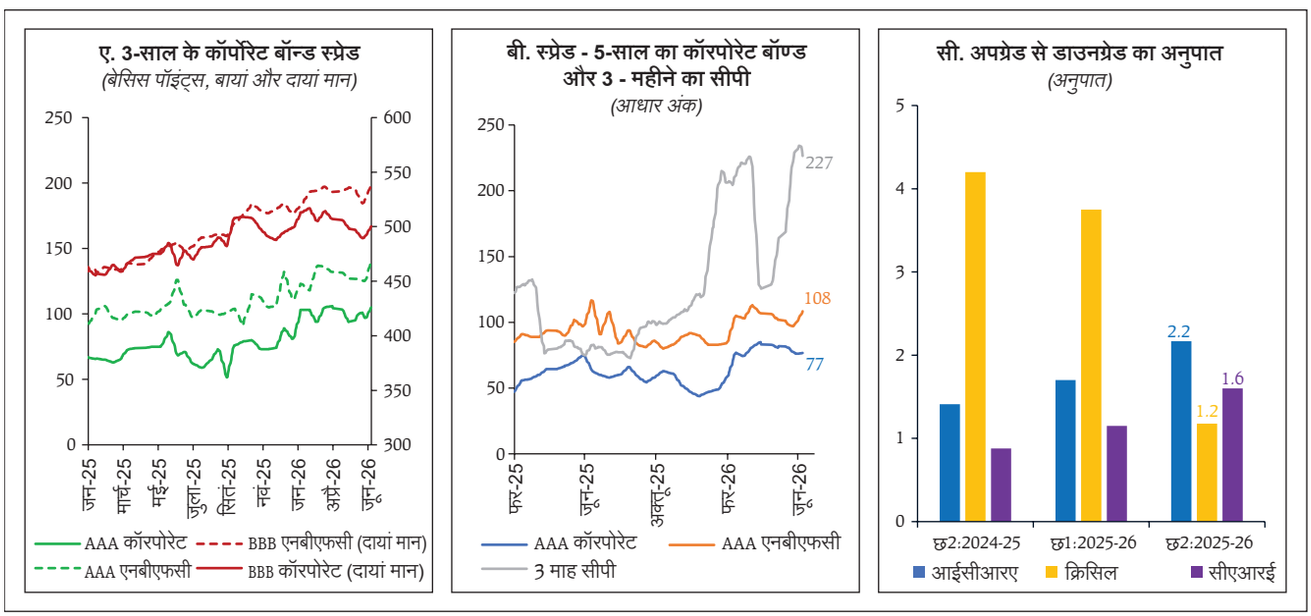
टिप्पणी: चार्ट (ए) में, औसत मासिक टर्नओवर कुल बकाया राशि का प्रतिशत है। चार्ट (बी) में, AA कैटेगरी से नीचे उन बॉन्ड को शामिल किया गया है जिनकी रेटिंग उपलब्ध नहीं है। चार्ट (सी) में केवल मुख्य कैटेगरी दिखाई गई हैं। डेटा 2025-26 की दूसरी छमाही से संबंधित है। चार्ट (ई) और (एफ़) में, एनबीएफ़सी: गैर -बैंकिंग वित्तीय कंपनी; पीएसयू : सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम; एचएफ़सी: हाउसिंग वित्त कंपनी; एफ़पीआई: फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर; एआईएफ़: अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। डेटा 31 मार्च, 2026 तक का है।

स्रोत: सेबी; प्राइम डेटाबेस; एनएसडीएल; सीएसडीएल; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

में कॉरपोरेट , बीमा कंपनियां और म्यूचुअल फंड मुख्य निवेशक रहे। इसके विपरीत, गैर-सूचीबद्ध बॉण्ड मुख्य रूप से कॉरपोरेट , व्यक्तियों और अन्य लोगों द्वारा धारित थे (चार्ट 1.31 ई और एफ)।

1.41 रेटिंग श्रेणियों और अवधि में कॉरपोरेट बॉण्ड स्प्रेड बढ़ गए हैं, जिसका मुख्य कारण ऋण जोखिम प्रीमियम में बढ़ोतरी है, जो ज़्यादा अनिश्चितता को दिखाता है (चार्ट 1.32 ए और बी)। फिर भी, ऋण अनुपात[14] कॉरपोरेट खंड

चार्ट 1.32: कॉरपोरेट बाण्ड स्प्रेड और रेटिंग

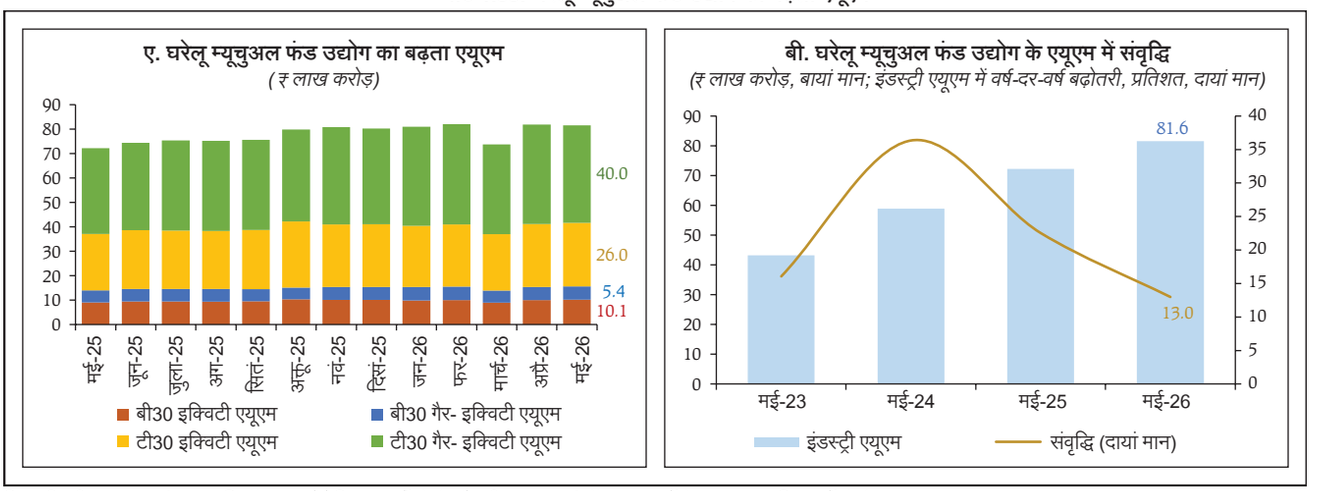


टिप्पणी: चार्ट (ए) और (बी) में 10-दिन का चल औसत और 10 जून 2026 तक के आंकड़े दिखाए गए हैं। चार्ट (बी) में, 3M CP स्प्रेड, 91-दिन के ट्रेज़री-बिल पर 3-महीने के वाणिज्यिक पत्र (एनबीएफसी) के स्प्रेड को संदर्भित करता है।

स्रोत: ब्लूमबर्ग; एलएसईजी वर्कस्पेस; सेबी; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

[14] यह एक अहम पैमाना है जिसका इस्तेमाल क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां कंपनियों की ऋण गुणवत्ता की रुझान को समझने के लिए करती हैं। 1.0 से ज़्यादा अनुपात का अर्थ है कि अपग्रेड डाउनग्रेड से अधिक है, जबकि 1.0 से कम अनुपात का अर्थ है कि अपग्रेड के मुकाबले डाउनग्रेड अधिक हुए हैं।

चार्ट 1.33: घरेलू म्यूचुअल फंड उद्योग का बढ़ता एयूएम



टिप्पणी: टी 30 का अर्थ भारत की टॉप 30 भौगोलिक जगहों से है और बी30 का अर्थ टॉप 30 शहरों के अलावा बाकी जगहों से है।
स्रोत: सेबी; एएमएफआई; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

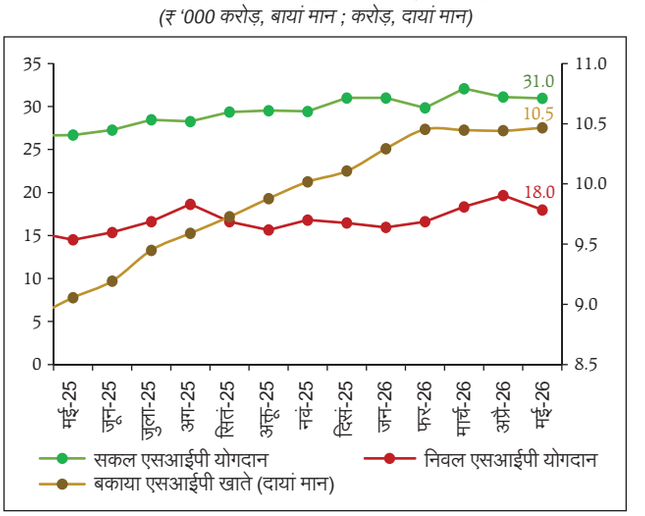
में बेहतर होते क्रेडिट माहौल की ओर इशारा करता है (चार्ट 1.32 c)।

1.42 मई 2026 के आखिर तक, घरेलू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की प्रबंधनाधीन आस्ति (एयूएम) बढ़कर ₹81.6 लाख करोड़ हो गई, जिसमें साल-दर-साल 13.0 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। फिर भी, एयूएम की बढ़ोतरी में काफी कमी आई है (चार्ट 1.33 ए और बी)। कुल एयूएम में से, ₹36.2 लाख करोड़ इक्विटी स्कीम में और ₹45.4 लाख करोड़ गैर-इक्विटी स्कीम में थे।[15]

1.43 मार्च 2026 में मासिक अंतर्वाह ₹32,086 करोड़ के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचने के साथ साल 2025-26 में सुनियोजित निवेश योजना (एसआईपी) में अंतर्वाह स्थिर रहा (चार्ट 1.34)। बकाया एसआईपी खातों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती रही, जो आम निवेशकों के लगातार खुदरा सहभागिता को दिखाता है। मई 2026 के आखिर तक, एसआईपी एयूएम ₹17.12 लाख करोड़ था, जो इक्विटी-उन्मुख स्कीम एयूएम का 47.3 प्रतिशत और कुल घरेलू म्यूचुअल फंड एयूएम का 20.9 प्रतिशत था।

1.44 2025-26 की दूसरी तिमाही के दौरान इक्विटी स्कीम में निवल अंतर्वाह 2025-26 की पहली तिमाही के मुकाबले मोटे तौर पर स्थिर रहा, जिसमें 0.2 प्रतिशत की मामूली कमी आई; जिसका मुख्य कारण सेक्टर/थीमैटिक फंड में कम अंतर्वाह था। इस दौरान इक्विटी-उन्मुख योजनाओं में अंतर्वाह मुख्य रूप से फ्लेक्सी-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप फंड के कारण हुआ (चार्ट 1.35 ए)। इसके विपरीत, ओपन-एंडेड डेट स्कीम में 2025-26 की दूसरी तिमाही के दौरान ₹1.8 लाख करोड़ का संचयी निवल बहिर्गमन (निवेश की निकासी) देखा गया, जबकि 2025-26 की पहली छमाही में ₹2.0 लाख

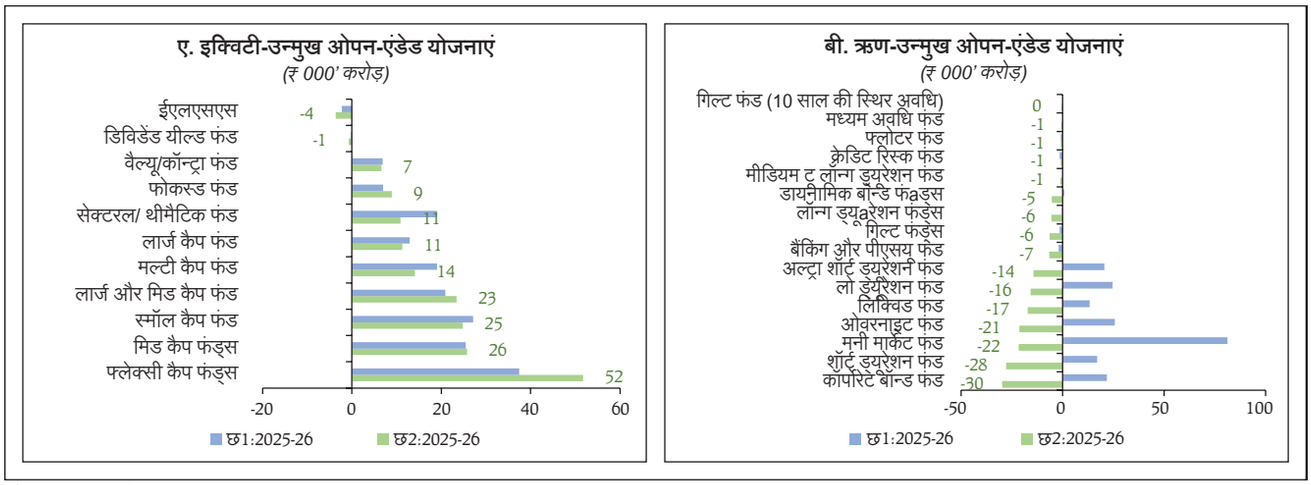
चार्ट 1.34: आघातसहनीय एसआईपी प्रवाह
(₹ '000 करोड़, बायां मान ; करोड़, दायां मान)



स्रोत: एएमएफआई।

[15] इक्विटी योजनाओं में सभी ग्रोथ/इक्विटी-उन्मुख योजनाएं शामिल हैं, जबकि गैर-इक्विटी योजनाओं में हाइब्रिड योजना, इनकम/डेट-उन्मुख योजना, समाधान-उन्मुख योजना और अन्य योजना शामिल हैं।

चार्ट 1.35: एमएफ योजनाओं में निवल अंतर्वाह

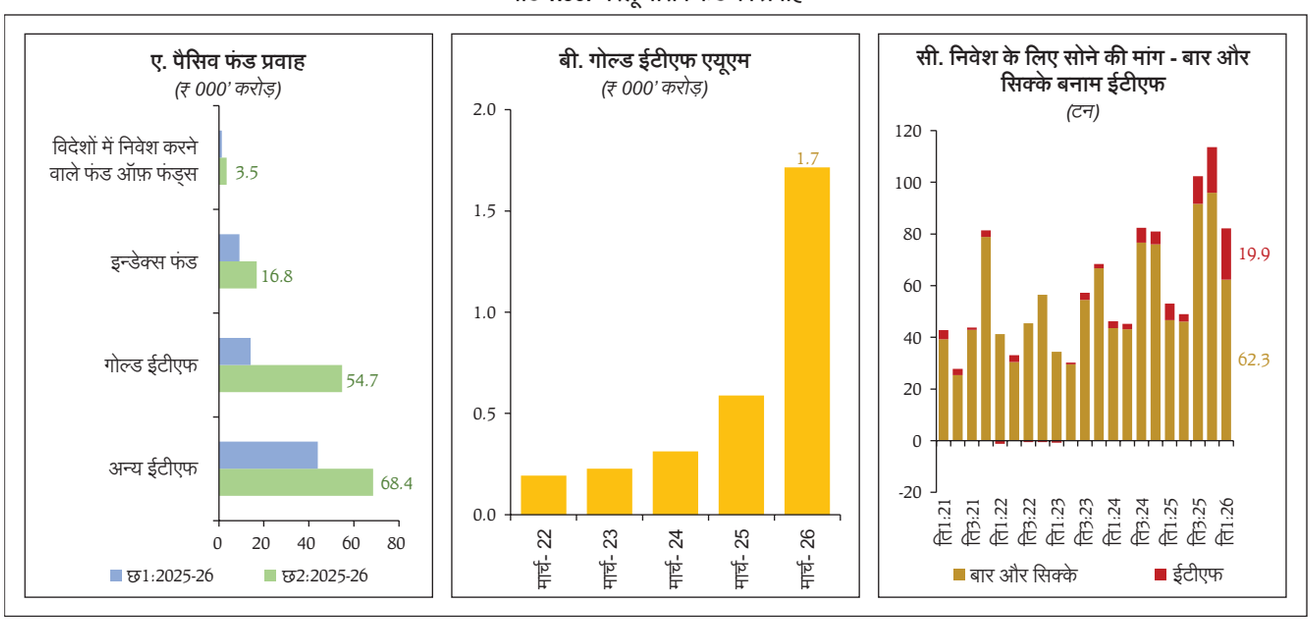


स्रोत: एएमएफआई।

करोड़ का निवल अंतर्वाह हुआ था (चार्ट 1.35 बी)। यह बदलाव कॉरपोरेट बॉण्ड फंड, अल्पकालिक फंड और मनी मार्केट फंड के मोचन (रिडेम्पशन) के साथ-साथ मार्च 2026 में तिमाही और साल के अंत में अग्रिम कर से जुड़े चलनिधि दबाव के कारण हुआ।

1.45 2025-26 की दूसरी छमाही में संचयी अंतर्वाह के दौरान 2025-26 की पहली छमाही के मुकाबले 109 प्रतिशत बढ़ जाने से पैसिव फंड में निवेश में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, जिसका मुख्य कारण गोल्ड ईटीएफ थे। इस अवधि के दौरान गोल्ड ईटीएफ में निवेश 286 प्रतिशत बढ़ गया[16] (चार्ट 1.36 ए)।

चार्ट 1.36: घरेलू पैसिव फंड का प्रवाह



स्रोत: एएमएफआई; और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल।

[16] हालाँकि, तब से गोल्ड ईटीएफ में मासिक निवल अंतर्वाह में गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है; जनवरी 2026 में ₹24,039 करोड़ के निवल अंतर्वाह से घटकर मई 2026 में ₹725 करोड़ का बहिर्गमन हुआ।

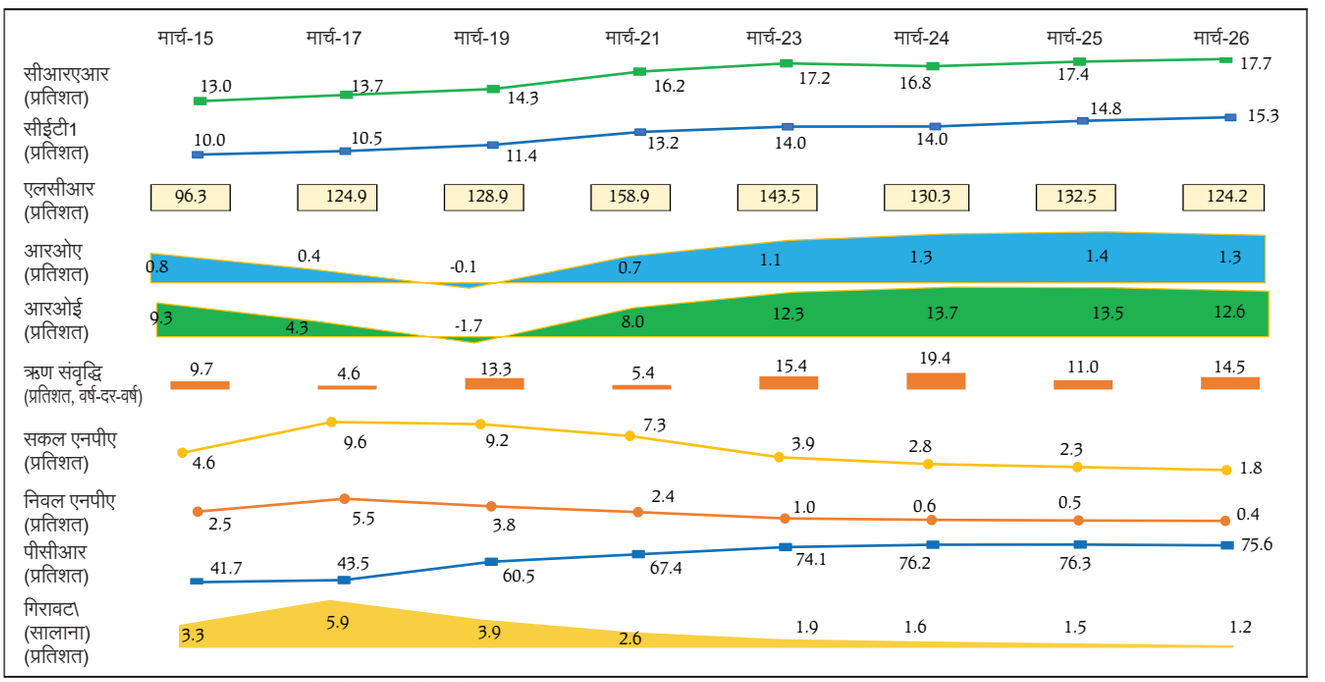
इसके परिणामस्वरूप, मार्च 2026 के अंत तक गोल्ड ईटीएफ का एयूएम तेज़ी से बढ़कर ₹1.7 लाख करोड़ हो गया, जिसमें साल-दर-साल लगभग 190 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह बढ़ोतरी मूल्यांकन में बढ़त और लगातार फंड अंतर्वाह, दोनों के कारण हुई (चार्ट 1.36 बी)। सोने में समग्र निवेश की मांग में गोल्ड ईटीएफ की हिस्सेदारी भी लगातार बढ़ी और 2026 की पहली तिमाही में कुल निवेश मांग का 24 प्रतिशत हो गई (चार्ट 1.36 सी)।

I.2.2 बैंकिंग प्रणाली

1.46 भारत की वित्तीय प्रणाली मुख्य रूप से बैंकों पर आधारित है, इसलिए समग्र वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से बैंकिंग क्षेत्र की आघातसहनीयता अत्यधिक ज़रूरी है। पिछले कुछ सालों में बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति लगातार बेहतर हुई है, जिससे वित्तीय स्थिरता मज़बूत हुई है। यह मुख्य पैमानों- जैसे पूंजिगत और चलनिधि बफ़र, लाभप्रदत्ता, आस्ति गुणवत्ता और ऋण-हानि प्रावधान में दिखता है (चार्ट 1.37)। ध्यान देने वाली बात है कि शुरुआती तनाव के कोई संकेत नहीं हैं क्योंकि एसएमए-2[17] खातों और ऋण लागत का अनुपात कम हो रहा है। बैंकों के तुलन पत्रों की कुल मज़बूती ऋण संवृद्धि की चालक है, खासकर नए ऋण की, जिसे क्रेडिट इम्पल्स से मापा जाता है (चार्ट 1.38 ए, बी और सी)।

1.47 भले ही बैंकिंग सिस्टम की आघातसहनीयता बनी हुई है, लेकिन निधियन मुख्य चुनौती बनकर उभर रहा है। बैंकों की देयता प्रोफ़ाइल कम लागत वाले चालू और बचत खातों (सीएएसए) से ज़्यादा लागत वाले मियादी जमा और सीडी की ओर बढ़ रही है, जिससे निधियों की सीमांत लागत बढ़ रही है (चार्ट 1.39 ए, बी और सी)। यह परिवर्तन बचत करने

चार्ट 1.37: मज़बूत वित्तीय स्थिति बैंकिंग सिस्टम को मज़बूत बनाती है

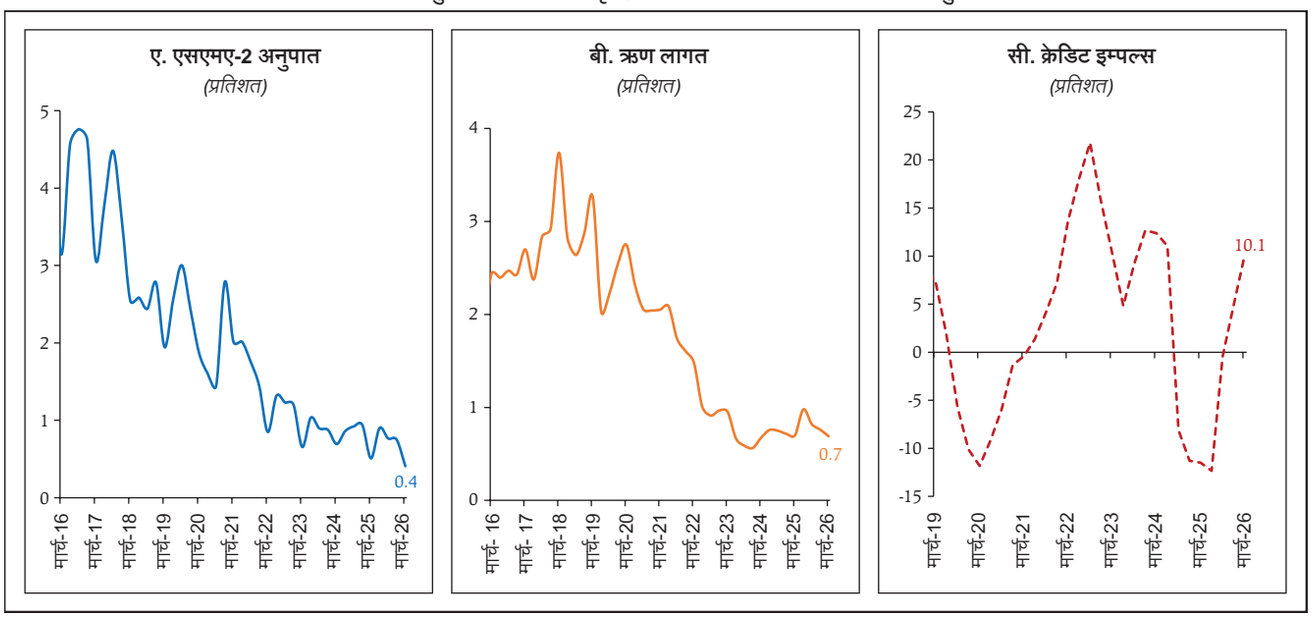


टिप्पणी: आंकड़े 11 जून 2026 तक (एसएफबी सहित एससीबी, सीआरएआर को छोड़कर) के घरेलू परिचालन पर आधारित है।
स्रोत: आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणी।

[17] विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) को इस तरह परिभाषित किया गया है: ए) परिक्रामी सुविधा वाले उधार (जैसे, नकदी ऋण/ ओवरड्राफ्ट) के लिए: अगर बकाया शेष लगातार 31-60 दिनों तक स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति (इनमें से जो भी कम हो) से ज़्यादा रहता है – तो एसएमए-1; 61-90 दिनों तक - एसएमए-2 बी) परिक्रामी सुविधा के अलावा अन्य उधार के लिए: यदि मूलधन या ब्याज का भुगतान या कोई अन्य राशि पूरी तरह या आंशिक रूप से 30 दिनों तक बकाया रहती है - तो एसएमए-0; 31-60 दिनों तक – एसएमए-1; 61-90 दिनों तक - एसएमए-2

[18] क्रेडिट इम्पल्स, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में जारी नए ऋण में बदलाव है। दरअसल, यह समय t और (t-1) तथा (t-1) और (t-2) के बीच ऋण की वृद्धि दर में बदलाव को समय (t-1) पर तिमाही जीडीपी के चार-अवधि वाले आवर्ती औसत के प्रतिशत के रूप में दिखाता है। असल में, यह समय t और (t-1) तथा (t-1) और (t-2) के बीच क्रेडिट की ग्रोथ रेट में आए बदलाव को, समय (t-1) पर तिमाही GDP के चार-अवधि वाले चल औसत के प्रतिशत के रूप में दिखाता है।

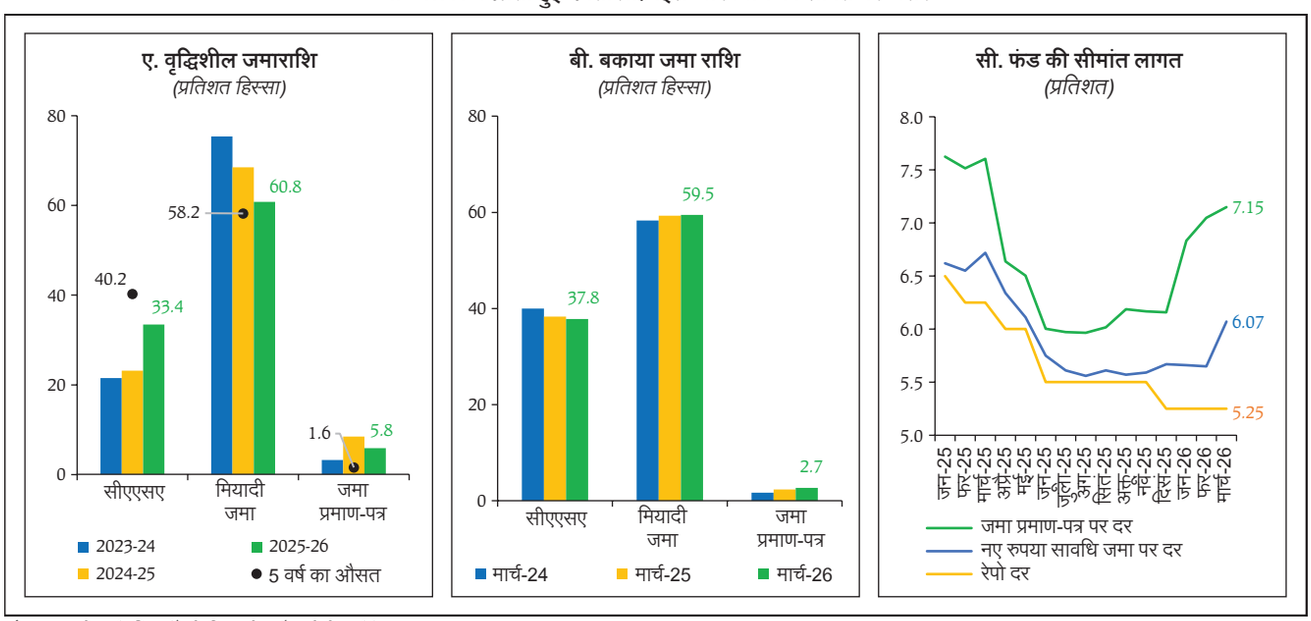
चार्ट 1.38: आस्ति गुणवत्ता और ऋण संवृद्धि का संचालन करने वाली ऋण लागत में सुधार लाना



टिप्पणी: चार्ट (बी) में, ऋण लागत = सालाना (जोखिम प्रावधान + बट्टे खाते डाले गए) / औसत सकल ऋण और अग्रिम।
स्रोत: एनएसओ; आरबीआई के पर्यवेक्षी विवरणी; और आरबीआई स्टाफ़ अनुमान।

वालों की निवेश प्राथमिकताओं में बदलाव को दिखाता है, जो ज़्यादा प्रतिलाभ देने वाले इक्विटी और म्यूचुअल फ़ंड की ओर बढ़ रहे हैं। इससे तेजी से पैसे निकाल लेने (रन ऑफ) की संभावना वाली बैंक जमाओं की संरचना में परिवर्तन हुआ है।[19]

चार्ट 1.39: बदलती हुई देयता प्रोफ़ाइल और निधि की लागत पर असर



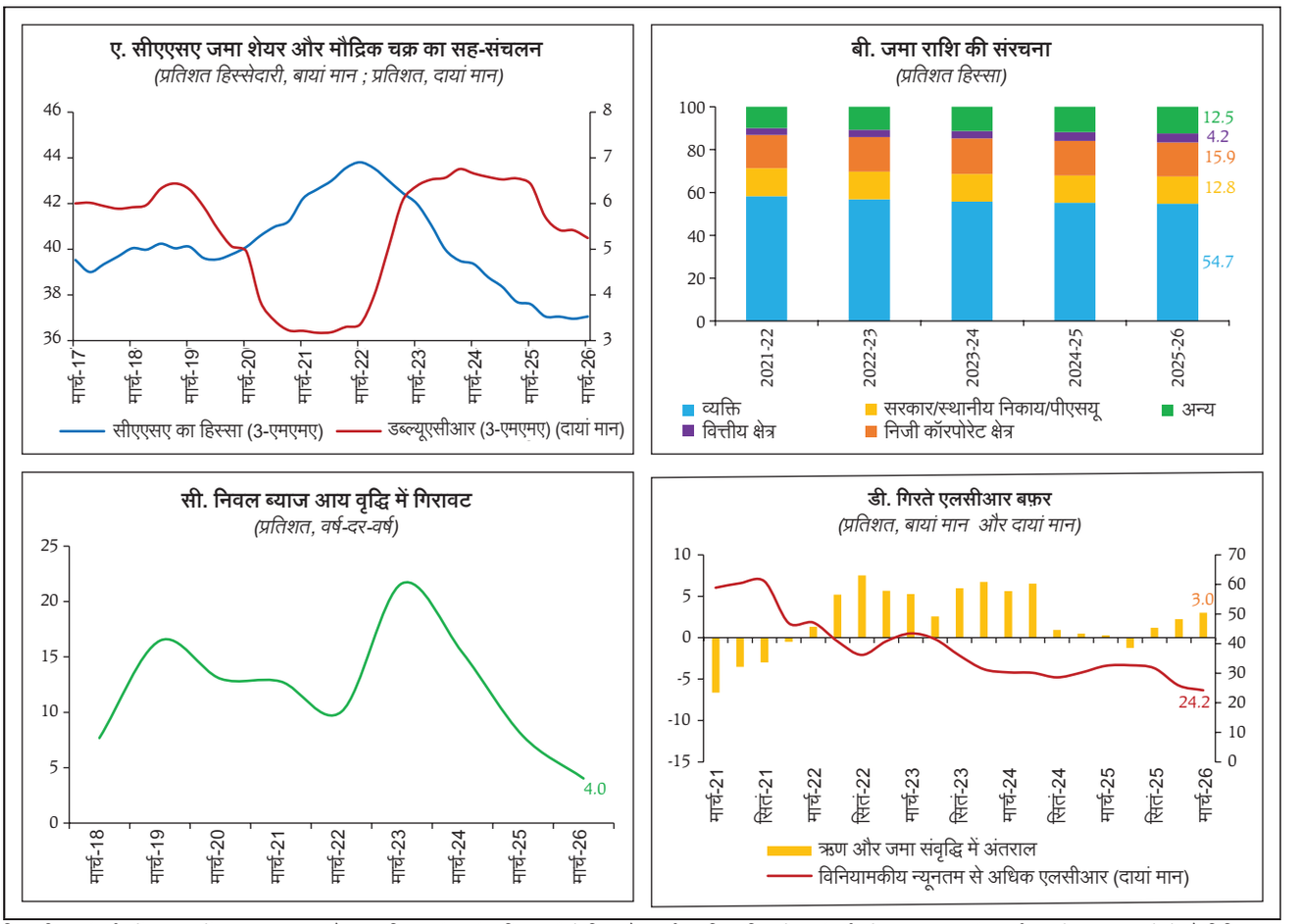
स्रोत: आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणी; और डीबीआईई।

[19] कम स्थिर थोक जमाओं पर लागू रन-ऑफ दरें स्थिर खुदरा जमा की तुलना में अधिक हैं, जिससे एलसीआर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाली चल/ तरल परिसंपत्तियों का स्तर बढ़ जाता है।

1.48 पिछले दौर की तुलना में, सीएएसए जमा की हिस्सेदारी और ब्याज दर चक्र के बीच विपरीत संबंध कमज़ोर होता दिख रहा है (चार्ट 1.40 ए)। जमा पर मिलने वाले 'कन्वीनियंस यील्ड'[20] में कमी आने से बैंकों के जमा फ्रैंचाइज़[21] पर असर पड़ रहा है (चार्ट 1.40 बी)। इससे उनकी लाभप्रदत्ता पर दबाव पड़ सकता है क्योंकि एक ओर ऋण की मांग भी मज़बूत बनी हुई है, वहीं परिवारों की बचत जमाएं प्राप्त करने के लिए होड़ लगी हुई है (चार्ट 1.40 सी)। यह बैंकों द्वारा ऋण वृद्धि के निधीयन के लिए अपने अतिरिक्त एसएलआर निवेश को कम करने में भी दिखता है, जिसके कारण एलसीआर बफ़र में कमी आ रही है (चार्ट 1.40 डी)। हालाँकि, पूँजीगत प्रवाह को बढ़ाने के लिए किए गए हालिया उपायों से बैंकों को कम लागत वाली रुपया चलनिधि मिलने में आसानी होगी, जिससे उन पर फ़ंडिंग का दबाव कम होने की उम्मीद है।

1.49 बैंक ज़्यादा प्रतिलाभ देने वाले क्षेत्र, जैसे कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और रिटेल में ऋण बढ़ा रहे हैं, जिससे उनके मार्जिन को बनाए रखने में मदद मिल रही है (चार्ट 1.41 a)। जिन बैंकों ने एमएसएमई और रिटेल ऋण में सोच-समझकर बढ़ोत्तरी की, उनके निवल ब्याज मार्जिन पर दबाव अपेक्षाकृत कम रहा, भले ही सीएएसए हिस्सेदारी में गिरावट आई। इससे पता चलता है कि इन क्षेत्रों से मिलने वाले ज़्यादा प्रतिलाभ ने निधियन की बढ़ती लागत की कुछ हद तक भरपाई कर दी (चार्ट 1.41 b)।

चार्ट 1.40: लाभप्रदता और तरलता पर घटती जमा फ्रेंचाइजी का प्रभाव

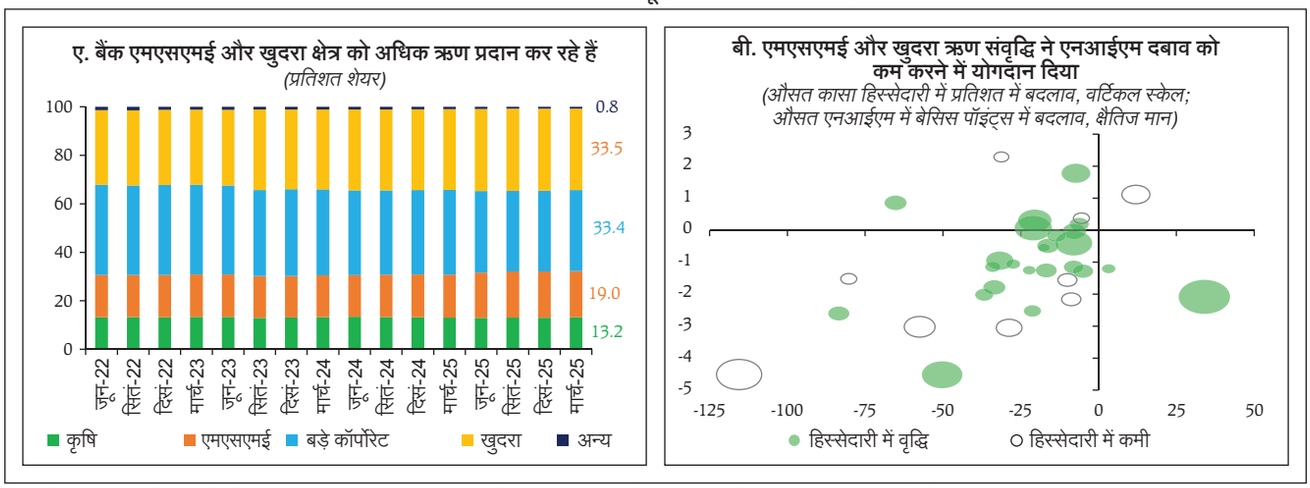


टिप्पणी: चार्ट (बी) में, 'अन्य' में एचयूएफ, ट्रस्ट, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, क्रेडिट सोसाइटी आदि शामिल हैं। चार्ट (डी) में, बफ़र का अर्थ एलसीआर के उस स्तर से है जो विनियामक न्यूनतम 100 प्रतिशत से अधिक है।
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी; और डीबीआईई।

[20] जमाराशि पर 'कन्वीनिएंस यील्ड' का अर्थ लोगों को मिलने वाले उन लाभ से है, जो ब्याज के अलावा मिलते हैं - जैसे सुविधा, सुरक्षा और तरलता। ये लाभ लोगों को बैंक जमा, खासकर चालू और बचत खाते में पैसे रखने से मिलते हैं। इसलिए, भले ही जमाराशि पर ब्याज दरें कम हों, फिर भी लोग इन फायदों की वजह से बैंकों में पैसे रखते हैं।

[21] डिपॉजिट फ्रैंचाइज़ी का अर्थ है समय के साथ ग्राहकों से स्थिर, कम लागत वाली जमा राशि प्राप्त करने और बनाए रखने की बैंक की क्षमता।

चार्ट 1.41: कासा शेयर में गिरावट के बावजूद बैंकों ने अपने मार्जिन दबाव को कम किया



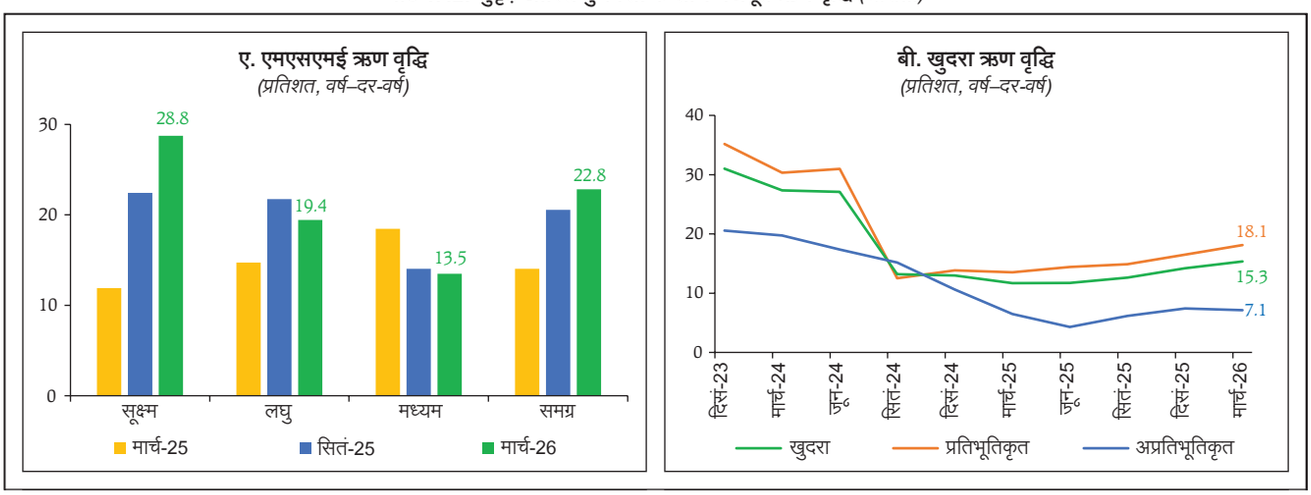
टिप्पणी: चार्ट (ए) में, हिस्सेदारी की गणना एससीबी के कुल गैर -खाद्य क्रेडिट के आधार पर की गई है। चार्ट (बी) में, हर बबल एक बैंक को दिखाता है। बबल का आकार मार्च 2025 और मार्च 2026 के बीच कुल अग्रिम में एमएसएमई और खुदरा अग्रिम की हिस्सेदारी में हुई बढ़ोतरी या कमी को दिखाता है। हरा बबल हिस्सेदारी में बढ़ोतरी को दिखाता है, जबकि खाली बबल हिस्सेदारी में कमी को दिखाता है।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी; और स्टाफ़ का अनुमान।

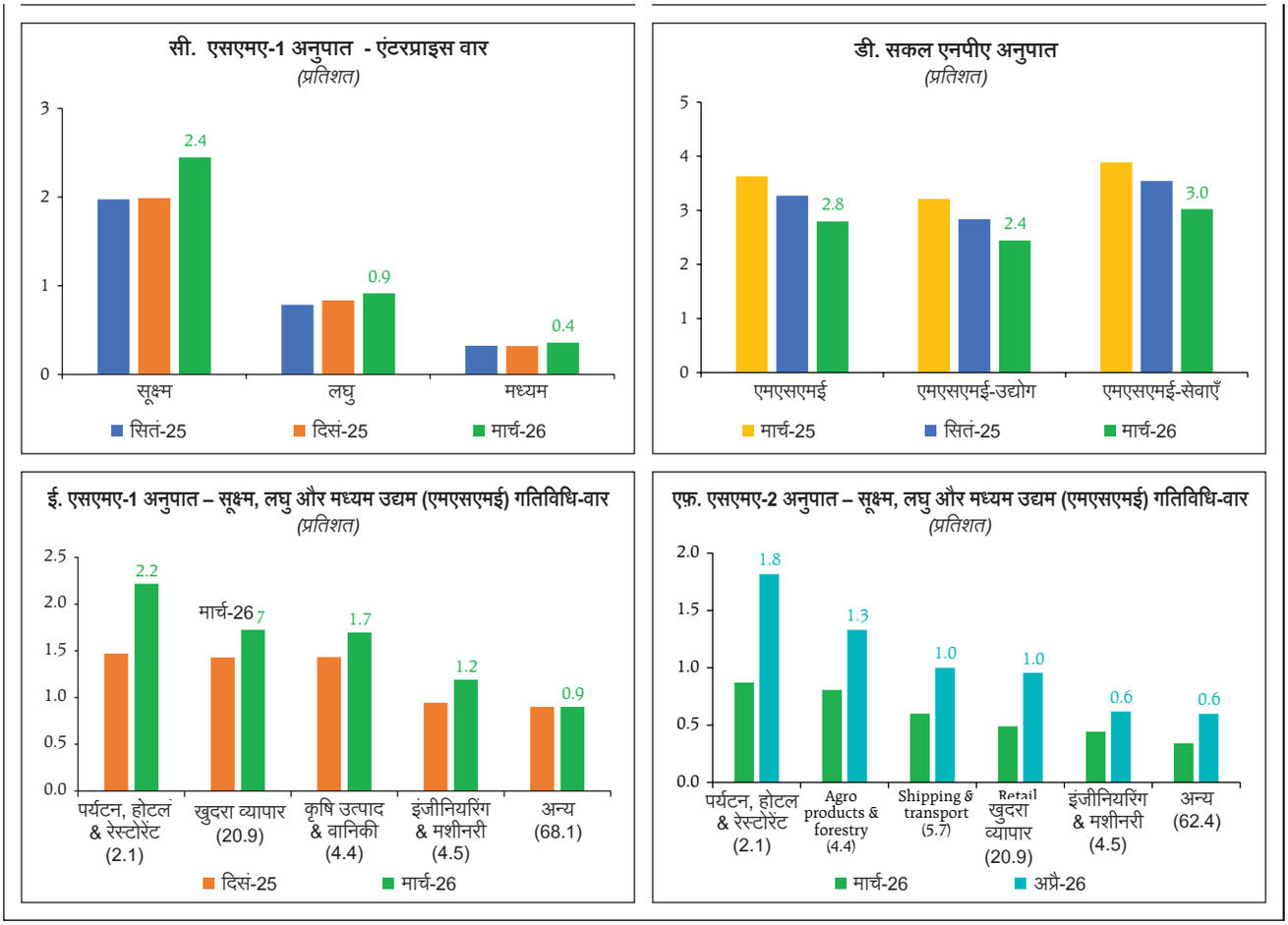
जिन बैंकों ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) तथा खुदरा ऋण में सार्थक वृद्धि की, उन पर शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पर अपेक्षाकृत कम दबाव पड़ा, भले ही चालू खाता और बचत खाता (सीएएसए) जमाओं का हिस्सा घटा हो। इससे संकेत मिलता है कि इन खंडों से प्राप्त ऊँचतर लाभ ने निधीयन लागत में वृद्धि की आंशिक रूप से पूर्ति की (चार्ट 1.41बी)।

1.50 एमएसएमई और खुदरा क्षेत्रों में औसत से अधिक ऋण वृद्धि के बावजूद, संपत्ति गुणवत्ता अभी भी अनुकूल बनी हुई है (चार्ट 1.42 ए और बी)। एमएसएमई खंड में, यद्यपि सूक्ष्म उद्यमों में कुछ प्रारंभिक तनाव दिखाई दे रहा है, समग्र सकल एनपीए अनुपात में सुधार हुआ है (चार्ट 1.42 सी और डी)। हालाँकि, वर्तमान में स्थिति नियंत्रित प्रतीत होती है, फिर भी यह खंड पश्चिम एशिया संघर्ष के प्रभाव के प्रति संवेदनशील बना हुआ है (चार्ट 1.42 ई और एफ)। खुदरा खंड में भी समान परिसंपत्ति गुणवत्ता प्रवृत्ति देखी गई है, जिसमें मार्च 2026 के अंत तक प्रतिभूतिगत और गैर-प्रतिभूतिगत खुदरा ऋणों के सकल एनपीए अनुपात क्रमशः 0.7 प्रतिशत और 1.7 प्रतिशत हैं। तथापि, इन क्षेत्रों में एक्सपोजर की बारीकी से निगरानी की आवश्यकता है, क्योंकि परिसंपत्ति की गुणवत्ता को लेकर जोखिम बढ़ सकते हैं, विशेष रूप से यदि पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण समग्र आर्थिक स्थितियां कमजोर होती हैं और उधारकर्ताओं की नकदी प्रवाह (कैश फ्लो) प्रभावित होती है।

चार्ट 1.42: सुदृढ़ आस्ति गुणवत्ता के साथ मजबूत ऋण वृद्धि *(जारी...)*



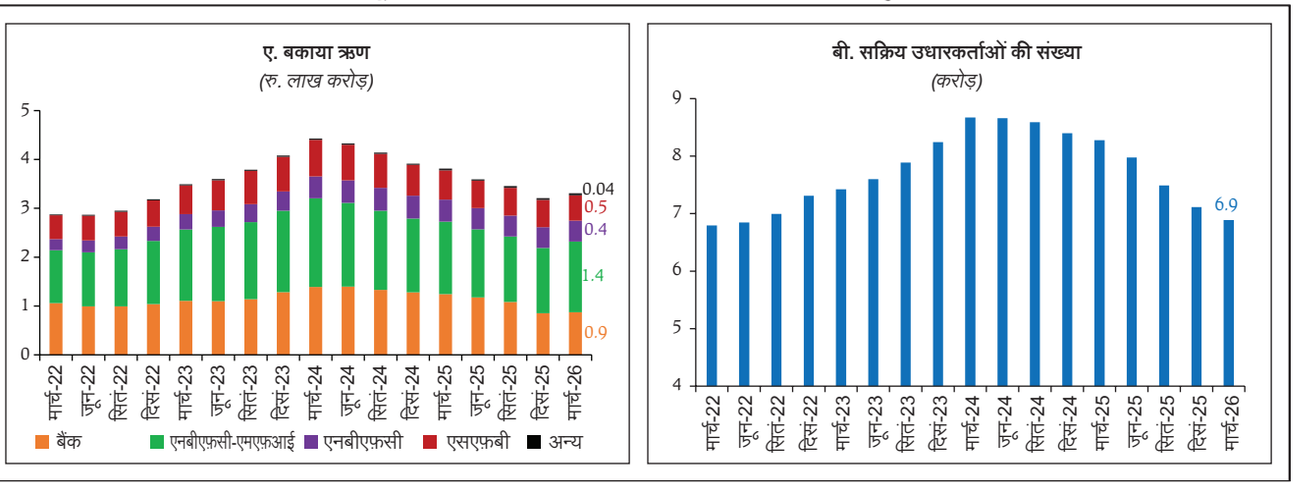
चार्ट 1.42: सुदृढ़ आस्ति गुणवत्ता के साथ मजबूत ऋण वृद्धि *(समाप्त)*



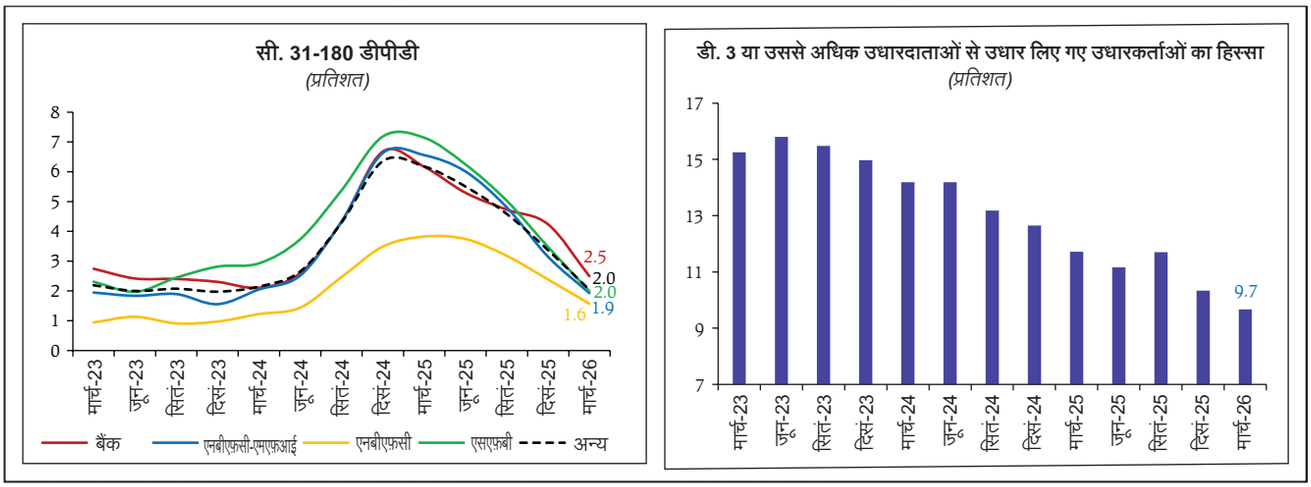
टिप्पणी: सीआरआईएफ हाईमार्क द्वारा अपने वाणिज्यिक ब्यूरो को प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) गतिविधियां। कोष्ठक में दिए गए आंकड़े एमएसएमई को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) और निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) द्वारा दिए गए कुल बकाया पोर्टफोलियो में गतिविधि-वार हिस्से को दर्शाती हैं।
स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षणीय रिटर्न; और सीआरआईएफ हाईमार्क।

1.51 लघुवित्त क्षेत्र को दिया गया ऋण सात तिमाहियों की गिरावट के बाद पहली बार बढ़ा, लेकिन उधारकर्ताओं की संख्या में कमी जारी रही, जो नवीनतम तिमाही में 22.7 लाख कम हो गई (चार्ट 1.43 ए और बी)। परिसंपत्ति की गुणवत्ता

चार्ट 1.43: सूक्ष्म वित्त क्षेत्र – सक्रिय उधारकर्ताओं में गिरावट के बीच ऋण में सुधार *(जारी...)*



चार्ट 1.43: सूक्ष्म वित्त क्षेत्र – सक्रिय उधारकर्ताओं में गिरावट के बीच ऋण में सुधार *(जारी...)*



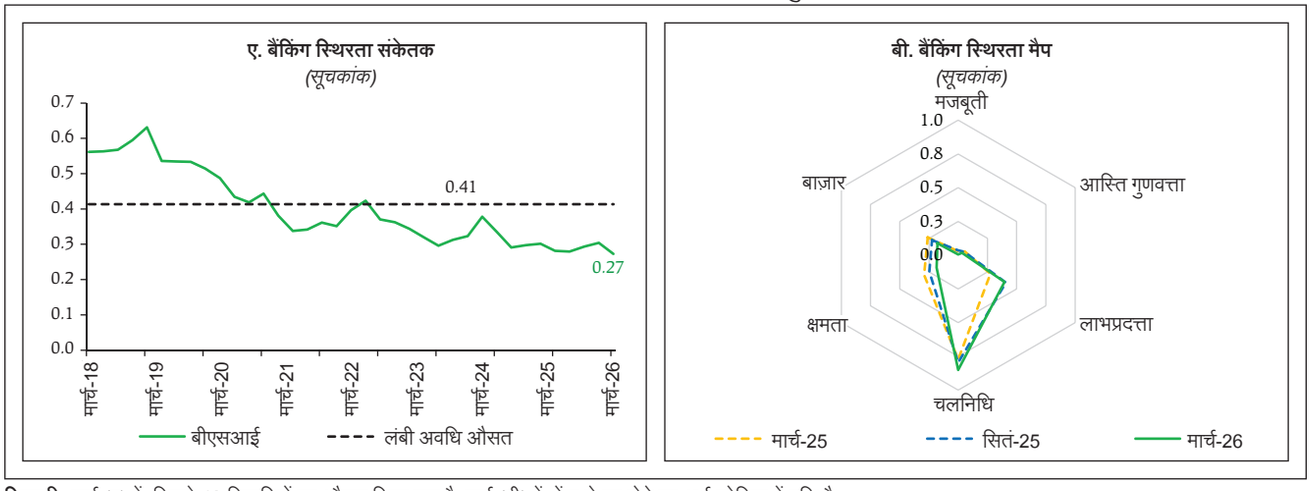
टिप्पणी: चार्ट (ए) और (बी) में, ऋणदाता की श्रेणी वही है जो वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण सूचना कंपनी को रिपोर्ट की गई है।
स्रोत: सीआरआईएफ हाई मार्क।

में सुधार जारी रहा, क्योंकि 31-180 दिन अतिदेय (डीपीडी) का हिस्सा पांचवीं लगातार तिमाही में घटा। साथ ही, तीन या अधिक ऋणदाताओं से ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं का हिस्सा मार्च 2026 में घटकर 9.7 प्रतिशत हो गया (चार्ट 1.43 सी और डी)।

1.52 साइबर जोखिम को वित्तीय प्रणाली की अतिसंवेदनशीलता के एक स्रोत के रूप में बढ़ती मान्यता मिल रही है, जिसमें वित्तीय अस्थिरता पैदा करने की क्षमता है। वैश्विक स्तर पर साइबर जोखिम द्वारा उत्पन्न प्रणालीगत खतरे को समझने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। इस संदर्भ में, एक चुनौतीपूर्ण परिदृश्य में साइबर खतरों के खिलाफ भारतीय वित्तीय संस्थानों की जागरूकता और तैयारियों का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण से यह पता चला कि जहां वित्तीय संस्थानों ने साइबर जोखिम प्रबंधन के मुख्य क्षेत्रों में मजबूत प्रथाएं स्थापित की हैं, एआई-सक्षम साइबर हमले निकट अवधि की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उभरे हैं (साइबर जोखिम और वित्तीय स्थिरता पर बॉक्स 1.1 देखें)।

1.53 बैंकिंग स्थिरता संकेतक (BSI) द्वारा दर्शाए गए अनुसार, बैंकिंग क्षेत्र में समग्र जोखिम कम हुआ है, जिसका समर्थन तरलता को छोड़कर सभी आयामों में सुधार द्वारा किया गया है (चार्ट 1.44 ए और बी देखें)।

चार्ट 1.44: बैंकिंग प्रणाली लचीली बनी हुई है



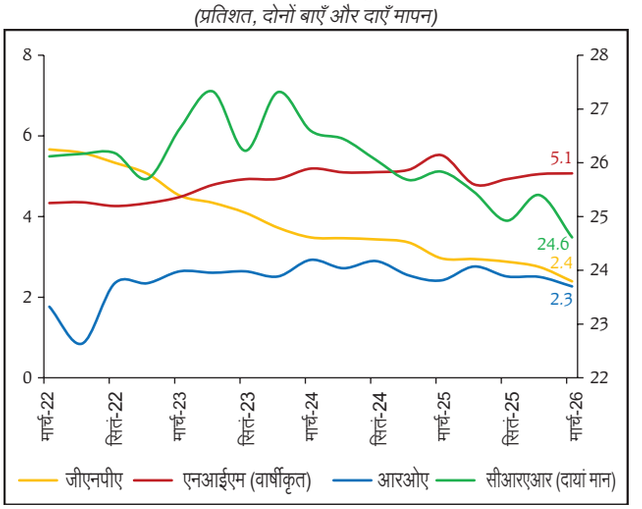
टिप्पणी: चार्ट (ए) में, पिछले 40 तिमाहियों का औसत लिया गया है। चार्ट (बी) में, केंद्र से दूर होने का अर्थ जोखिम में वृद्धि है।
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षण विवरणी; तथा स्टाफ गणना।

1.2.3 एनबीएफ़सी क्षेत्र

1.54 एनबीएफसी क्षेत्र[22] ने मजबूत पूंजीकरण, ठोस शुद्ध ब्याज मार्जिन, निरंतर लाभप्रदता और परिसंपत्ति हानि के घटते स्तर (चार्ट 1.45) के आधार पर लचीलापन प्रदर्शित करना जारी रखा। हालांकि कुल ऋण वृद्धि में नरमी आई है, लेकिन खुदरा क्षेत्र को ऋण देने में तेजी आई है, जो मुख्य रूप से स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो में तेज विस्तार से प्रेरित है, जो अब एनबीएफसी के खुदरा पोर्टफोलियो का 17.4 प्रतिशत है। मुख्य रूप से, क्रेडिट लागत का गिरना जारी रहा (चार्ट 1.46 ए, बी, सी और डी)।

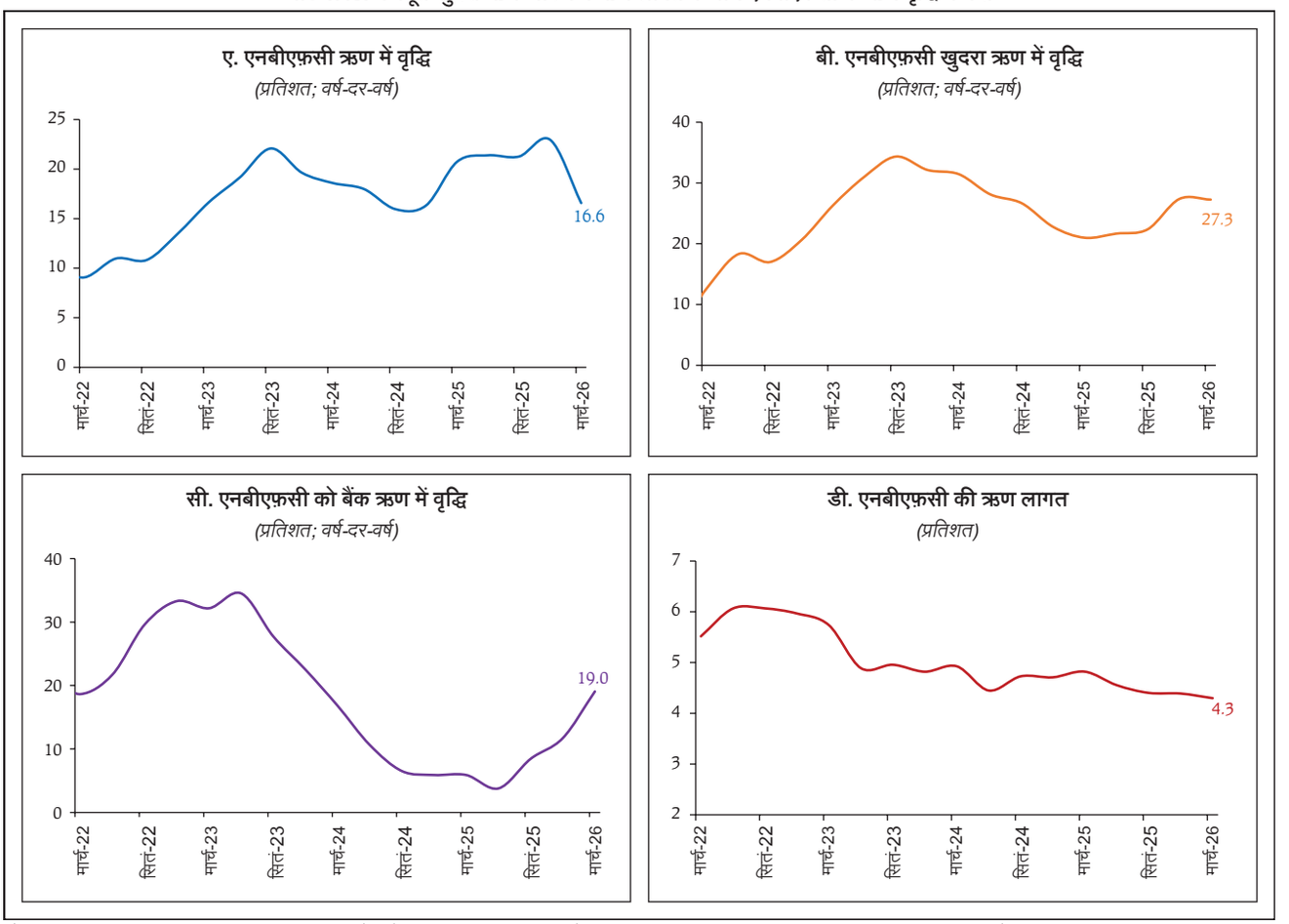
चार्ट 1.45: एनबीएफसी क्षेत्र – प्रमुख वित्तीय पैरामीटर

(प्रतिशत, दोनों बाएँ और दाएँ मापन)



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षण विवरणी।

चार्ट 1.46: मजबूत खुदरा ऋण और कम ऋण लागत के बीच एनबीएफसी के ऋण वृद्धि में मंदी



नोट: चार्ट (डी) में, ऋण लागत = (मानक आस्तियों और गैर-निष्पादित आस्तियों के लिए प्रावधान + वार्षिक बट्टे खाते लिखी गई राशि) / औसत सकल अग्रिम।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणी।

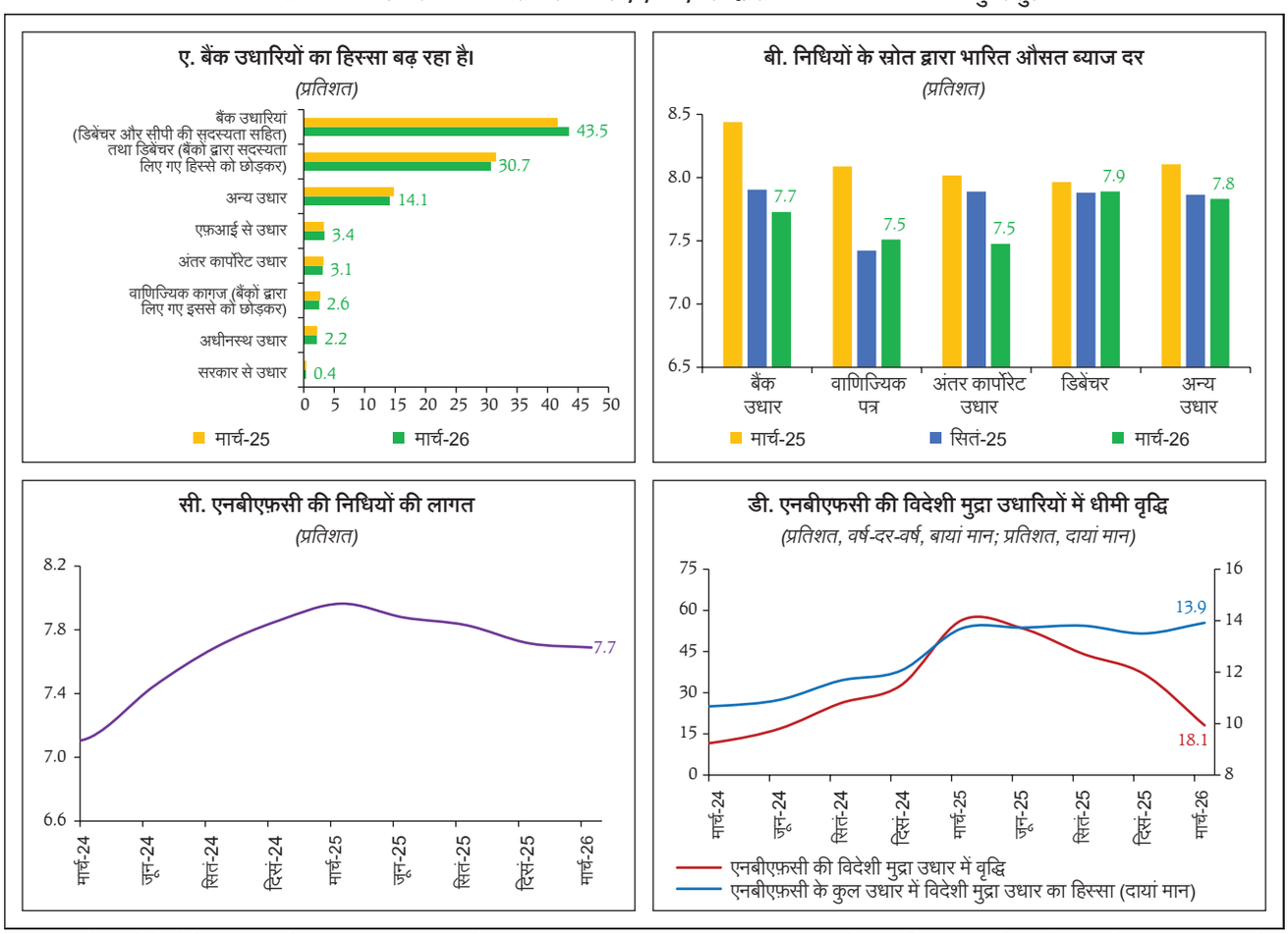
[22] इस खंड में किए गए विश्लेषण ऊपरी और मध्यम स्तर के एनबीएफसी पर आधारित हैं, लेकिन इसमें आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी), मुख्य निवेश कंपनियों (सीआईसी) और स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलरों (एसपीडी) को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन इसमें वर्तमान में समाधान के तहत एनबीएफसी शामिल हैं। यह विश्लेषण 18 मई, 2026 तक उपलब्ध अनंतिम डेटा पर आधारित है।

1.55 बैंकों द्वारा एनबीएफसी को ऋण में वृद्धि ने उनकी देयता प्रोफाइल को स्थिरता बढ़ाकर एवं लागत कम करके मजबूत किया है। नतीजतन, विदेशी मुद्रा उधार में वृद्धि में काफी कमी आई है, यहां तक कि रुपये के मूल्यह्रास और बढ़ती हेजिंग लागत ने इस तरह के उधारों को कम आकर्षक बना दिया है (चार्ट 1.47 ए, बी, सी और डी)।

1.56 परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार के संकेत दिख रहे हैं, जिसमें फिसलन अनुपात पहले के शिखर से कम हो गया है, विशेष रूप से मध्यम स्तर की एनबीएफसी (एनबीएफसी-एमएल) के बीच। हालांकि, ऊपरी परत के गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी-यूएल) के लिए स्लिपेज अपेक्षाकृत उच्च बने हुए हैं, हालांकि स्थिरीकरण के प्रारंभिक संकेत दिखाई दे रहे हैं (चार्ट 1.48 ए)। परिसंपत्ति गुणवत्ता में समग्र सुधार शुद्ध एनपीए अनुपात में गिरावट के रुझान से स्पष्ट है, जो 0.8 प्रतिशत के निचले स्तर पर पहुंच गया है (चार्ट 1.48 बी)।

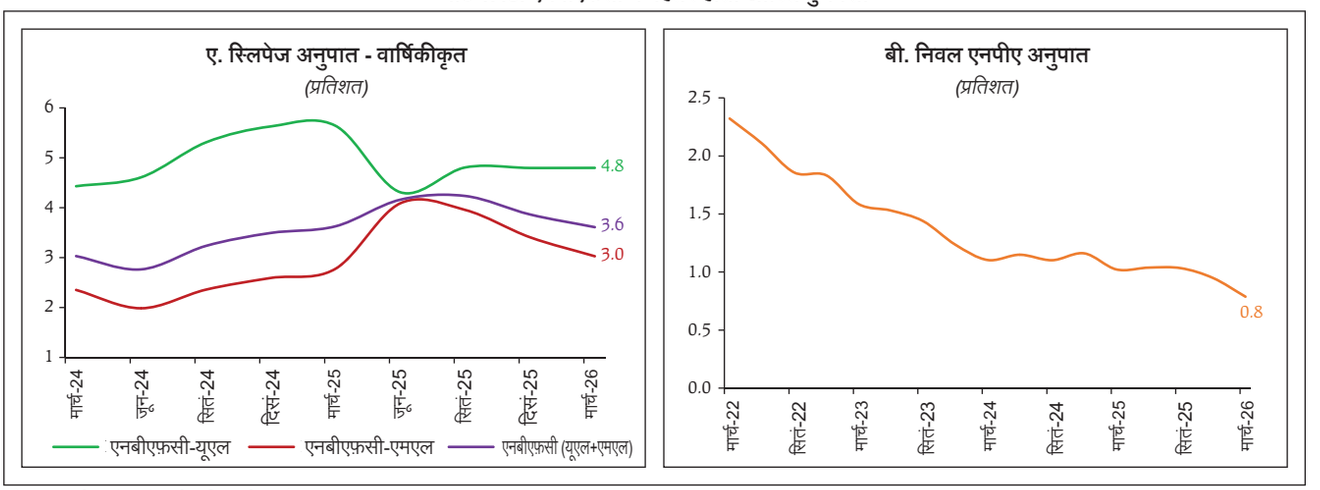
1.57 एनबीएफसी, वित्तीय समावेशन और रोजगार का समर्थन करते हुए एमएसएमई और माइक्रोफाइनेंस उद्यमों के वित्तपोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हालांकि एमएसएमई के लिए एनबीएफसी की ऋण वृद्धि थोड़ी कम हो गई है, लेकिन यह परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार के साथ मजबूत बनी हुई है (चार्ट 1.49 ए और बी)। इस बीच, माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र को संयुक्त एनबीएफसी और एनबीएफसी-एमएफआई ऋण - जो कुल ऋण का 56.7 प्रतिशत है - एच 2: 2025-26 में 5.9 प्रतिशत बढ़ गया (चार्ट 1.49 सी)। परिसंपत्ति गुणवत्ता मजबूत हुई, जिसमें 31-180 दिन अतिदेय का हिस्सा सितंबर 2025 में 4.4 प्रतिशत से घटकर मार्च 2026 में 1.8 प्रतिशत

चार्ट 1.47 निधीयन लागत को नियंत्रित करने के लिए एनबीएफसी द्वारा अपने निधीयन मिश्रण का पुनर्संतुलन।



नोट: चार्ट (सी) में, निधियों की लागत = वार्षिक ब्याज व्यय और अन्य वित्तपोषण लागत / (औसत कुल उधार + औसत जनता की जमाराशियाँ)। चार्ट (डी) में बॉन्ड और डिबेंचर के माध्यम से किए गए उधार शामिल हैं।
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षणीय विवरणी ; और स्टाफ गणना।

चार्ट 1.48: एनबीएफसी में बेहतर होती आस्ति गुणवत्ता

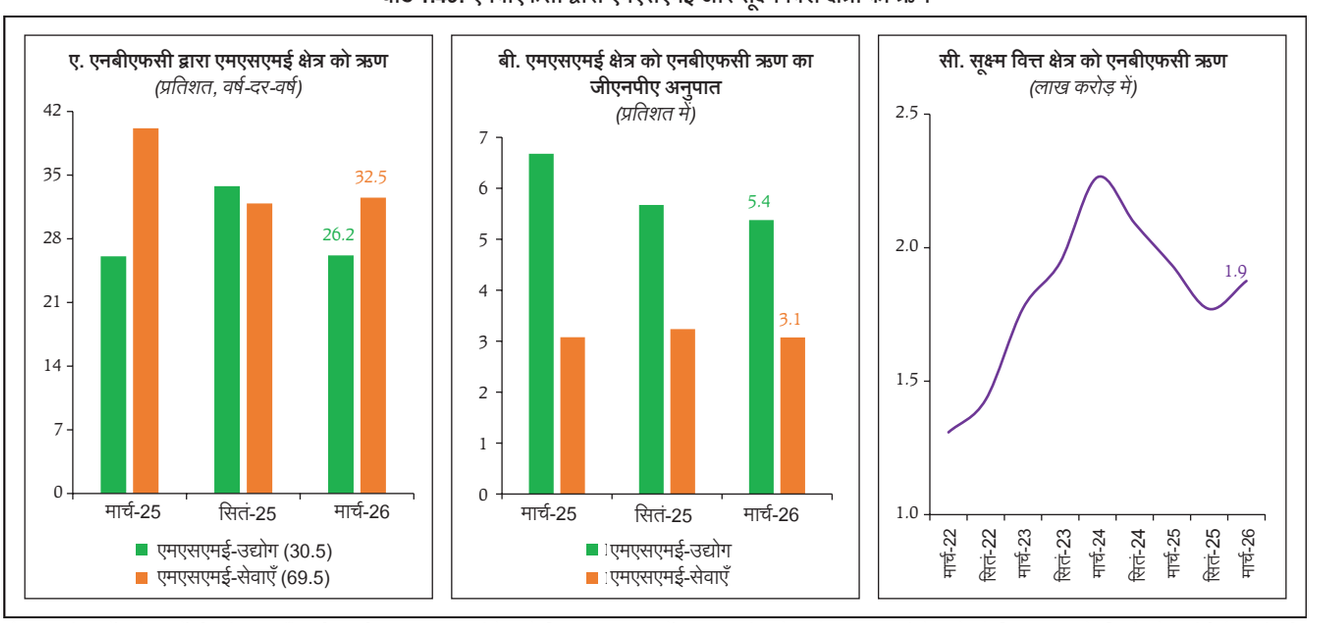


स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षणीय विवरणी ; और स्टाफ गणना

रह गया, जबकि एनबीएफसी-एमएफआई की साख लागत में कम प्रावधान और राइट-ऑफ के कारण कमी आई, हालांकि यह सितंबर 2023 में दर्ज 4.4 प्रतिशत की तुलना में अभी भी ऊंची बनी हुई है।

1.58 फिनटेक कंपनियों[23] ने छोटी रकम वाले व्यक्तिगत ऋण खंड (50,000 रुपये से कम) में अपनी स्थिति को मजबूत किया है, जहाँ मार्च 2026 तक उनका बाजार हिस्सा बढ़कर 56.8 प्रतिशत हो गया है। यह वृद्धि 41.6 प्रतिशत की मजबूत ऋण विस्तार दर द्वारा संचालित हुई है, जो समग्र खंड की 20.1 प्रतिशत की वृद्धि दर से काफी अधिक है। हालांकि, इस तीव्र विस्तार के साथ चूक दरों में वृद्धि (6.4 प्रतिशत) देखी

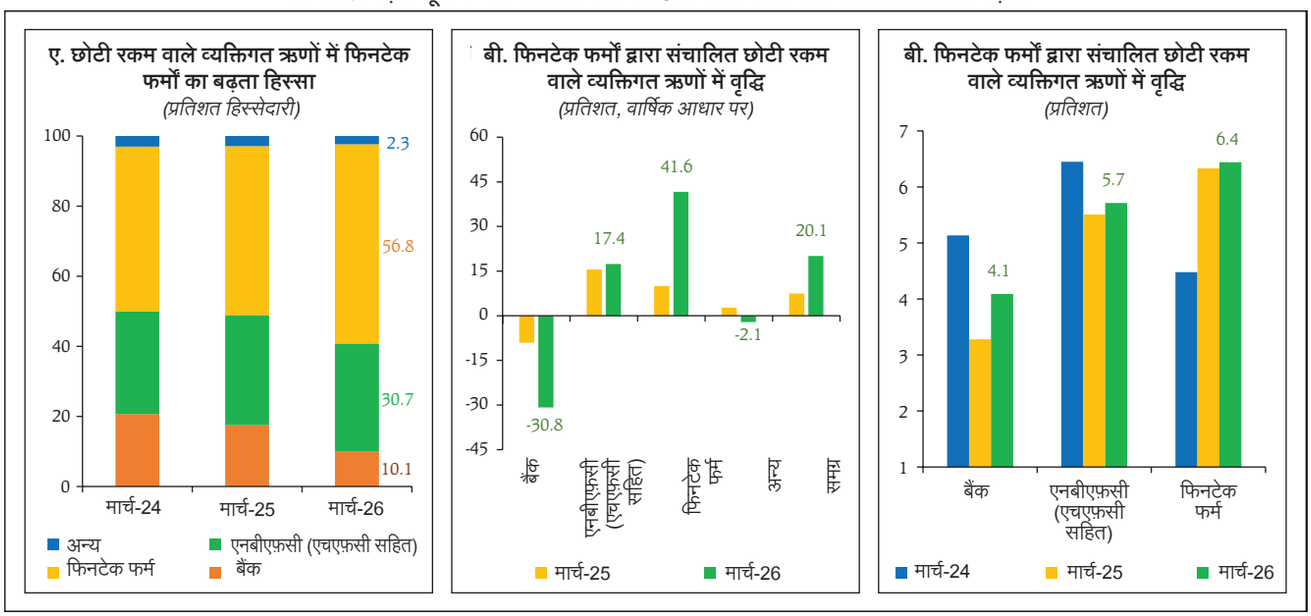
चार्ट 1.49: एनबीएफसी द्वारा एमएसएमई और सूक्ष्म वित्त क्षेत्रों को ऋण



नोट : चार्ट (ए) में, कोष्ठक में दी गई संख्याएँ एनबीएफसी द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को दिए गए कुल ऋण में एमएसएमई-उद्योग और एमएसएमई-सेवाओं को दिए गए ऋण के हिस्से को दर्शाती हैं। चार्ट (सी) में, सूक्ष्म वित्त क्षेत्र को एनबीएफसी और एनबीएफसी-एमएफआई से मिलकर कुल ऋण दिखाया गया है।
स्रोत: सीआरआईएफ हाई मार्क; और भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणी।

[23] एनबीएफसी को फिनटेक के रूप में वर्गीकृत करने की पद्धति ट्रांसयूनियन सिबिल के बाजार ज्ञान पर आधारित है कि उनके पास अपने ऋण देने वाले व्यवसाय के लिए एक डिजिटल प्रथम दृष्टिकोण है और/या वे फेस, यूएफएफ और आईएमएआई जैसे उद्योग निकायों के सदस्य हैं।

चार्ट 1.50: बढ़ती चूक के बीच फिनटेक कंपनियों द्वारा छोटी रकम वाले वैयक्तिक ऋणों को बढ़ावा



नोट : चार्ट (सी) में, चूक दरों को कुल बकाया ऋण शेष का 90 से 179 दिन अतीत देय (डीपीडी) वाले बकाया ऋण शेष का प्रतिशत के रूप में मापा गया है।

स्रोत: ट्रांसयूनियन सिबिल।

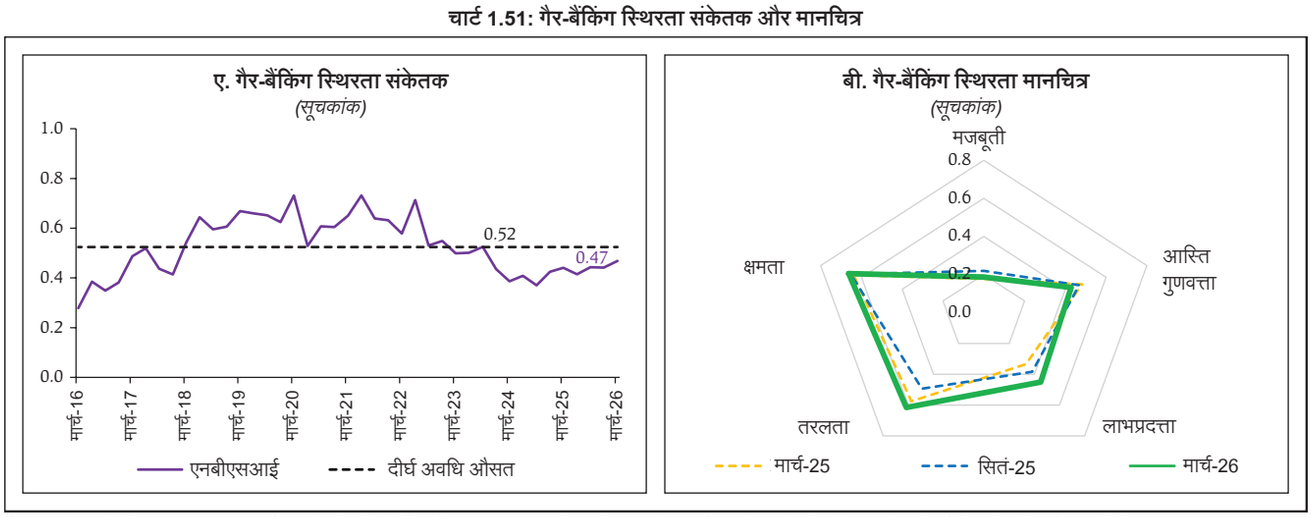
गई है, जो संभावित परिसंपत्ति गुणवत्ता जोखिमों का संकेत देती है (चार्ट 1.50 a, b और c)। बिना जमानत वाले ऋण उनके कुल ऋण पुस्तक का लगभग 70.5 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं, और इनमें से लगभग आधे ऋण 35 वर्ष से कम आयु के उधारकर्ताओं को दिए गए हैं[24]।

1.59 गैर-बैंकिंग स्थिरता संकेतक (एनबीएसआई) द्वारा इंगित किए गए एनबीएफसी क्षेत्र में समग्र जोखिम में मामूली वृद्धि देखी गई, जो लाभप्रदता और तरलता मेट्रिक्स में मामूली कमजोरी को दर्शाता है। हालांकि, एनबीएसआई अपने दीर्घकालिक औसत (चार्ट 1.51 ए और बी) से नीचे रहा।

1.2.4 कार्पोरेट क्षेत्र

1.60 वित्त संस्थाओं के साथ-साथ गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट क्षेत्र के मजबूत तुलनपत्र घरेलू वित्तीय स्थिरता का एक

चार्ट 1.51: गैर-बैंकिंग स्थिरता संकेतक और मानचित्र

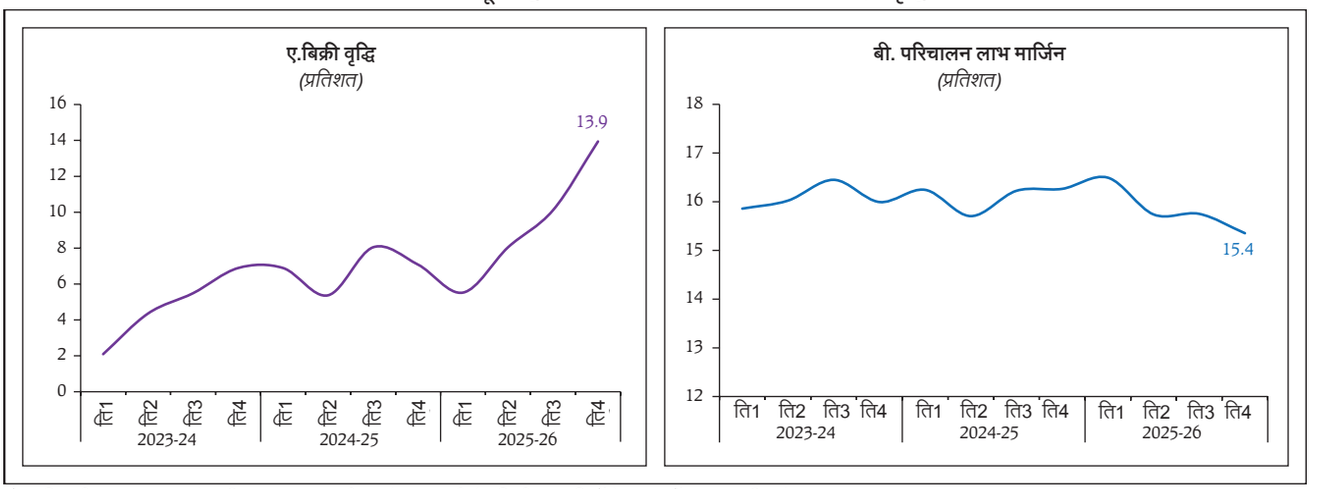


नोट: चार्ट (ए) में, निम्नतर मान सुधार को दर्शाता है। दीर्घावधि औसत मार्च 2016 से एनबीएसआई का औसत है। चार्ट (बी) में, मध्य से दूरी जोखिम में वृद्धि को दर्शाती है।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी; और स्टाफ गणना।

[24] सीआरआईएफ हाई मार्क द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार।

चार्ट 1.52: सूचीबद्ध निजी गैर-वित्तीय कंपनियों में नाममात्र बिक्री वृद्धि

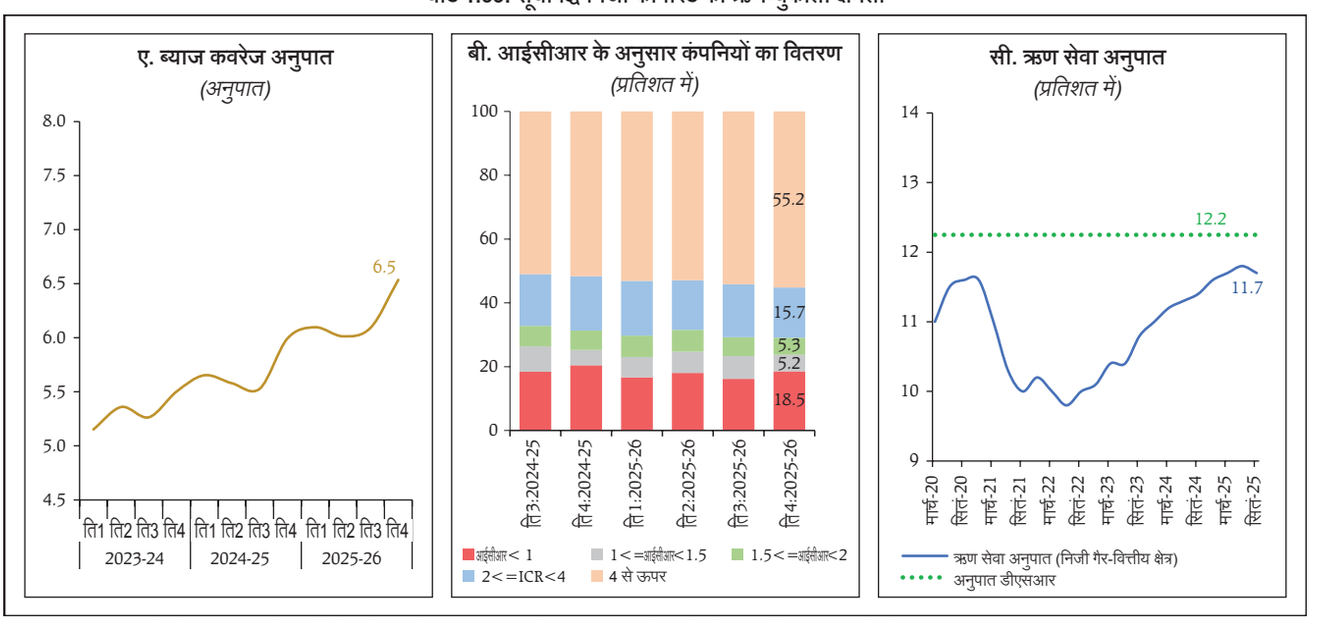


नोट: तिमाही 4 : 2025-26 के परिणाम 3,266 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों के आंकड़ों पर आधारित हैं।
स्रोत: कैपिटलाइन डेटाबेस; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

प्रमुख स्तंभ रहे हैं। निजी गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट क्षेत्र ने 2025-26 की चौथी तिमाही में उच्च बिक्री वृद्धि और स्थिर संचालन मार्जिन के समर्थन से मजबूत प्रदर्शन बनाए रखा (चार्ट 1.52 ए और बी)।

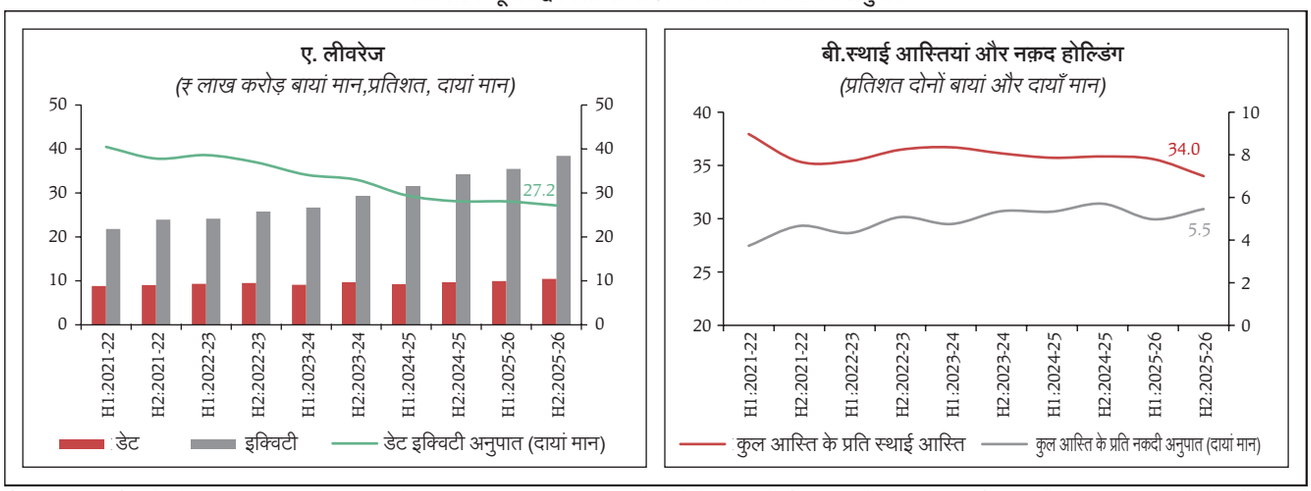
1.61 कॉर्पोरेट क्षेत्र की संवेदनशीलता का एक प्रमुख संकेतक, ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर) द्वारा मापी जाने वाली ऋण सेवा क्षमता, में सुधार जारी रहा है। ब्याज खर्चों के सापेक्ष सकल लाभ में मजबूत अनुक्रमिक वृद्धि द्वारा समर्थित, आईसीआर 2025-26 की चौथी तिमाही में बढ़कर 6.5 हो गया (चार्ट 1.53 ए)। कुल स्तर पर, तिमाही के दौरान कमजोर फर्मों (आईसीआर < 1) की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई

चार्ट 1.53: सूचीबद्ध निजी कार्पोरेट की ऋण-चुकौती क्षमता



नोट: चार्ट (ए) और (बी) में, 2025-26 की चौथी तिमाही के परिणाम 3,266 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ़) कंपनियों पर आधारित हैं।
स्रोत: कैपिटललाइन डेटाबेस; बीआईएस; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट 1.54 सूचीबद्ध निजी उत्पादक कंपनियों के चयनित अनुपात



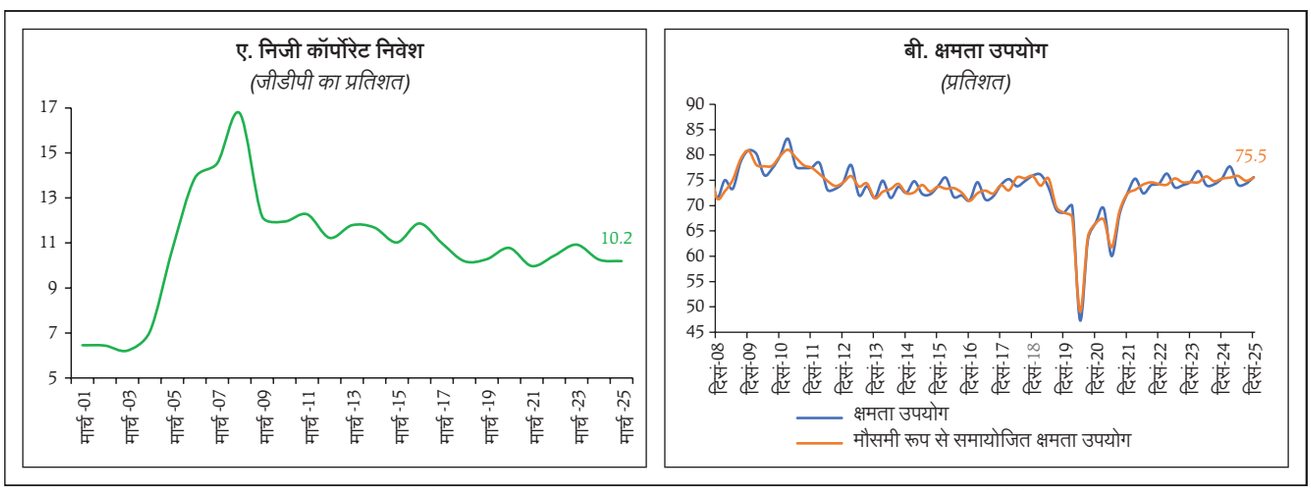
नोट : चार्ट (ए) और (बी) में, 2025-26 के दूसरी छमाही के लिए डेटा 2,336 सामान्य सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों पर आधारित है। लीवरेज को ऋण/इक्विटी *100 के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें ऋण = 'दीर्घकालिक उधार' और 'अल्पकालिक उधार' का योग; और इक्विटी = 'शेयर पूंजी' और 'आरक्षित और अधिशेष' का योग है।
स्रोत :केपिटालाइन और आरबीआई स्टाफ अनुमान

(चार्ट 1.53 बी), जबकि ऋण सेवा अनुपात दीर्घकालिक औसत (चार्ट 1.53 सी) से नीचे रहा।

1.62 सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों का बैलेंस शीट विश्लेषण [25] यह इंगित करता है कि कर्ज-इक्विटी अनुपात द्वारा मापे गए लीवरेज में, 2025–26 छमाही के दौरान गिरावट जारी रही (चार्ट 1.54 ए)। अचल संपत्ति की वृद्धि 2025-26 की पहली छमाही के 10.3 प्रतिशत से घटकर 2025-26 की दूसरी छमाही में 5.2 प्रतिशत हो गई, जिसका मुख्य कारण अलौह धातुओं, रसायनों सीमेंट और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, जिनकी कुल अचल आस्तियों में 34.1 फीसदी की हिस्सेदारी है, की कमजोर वृद्धि थी। इस अवधि के दौरान अचल संपत्ति-कुल संपत्ति अनुपात में गिरावट आई, जबकि कुल संपत्ति में नकद होल्डिंग की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई (चार्ट 1.54 बी)।

1.63 निजी कारपोरेट निवेश में मंदी बने रहने के कारण सकल घरेलू उत्पाद में कुल निवेश का हिस्सा कम हो गया है।

चार्ट 1.55 निजी कॉर्पोरेट निवेश और क्षमता उपयोग



टिप्पणी: चार्ट (ए) में, 2021-22 का डेटा 2011-12 जीडीपी आधार वर्ष का उपयोग करता है, जबकि उसके बाद के डेटा में 2022-23 जीडीपी आधार वर्ष का उपयोग किया गया है।:
Sources: NSO; and RBI.

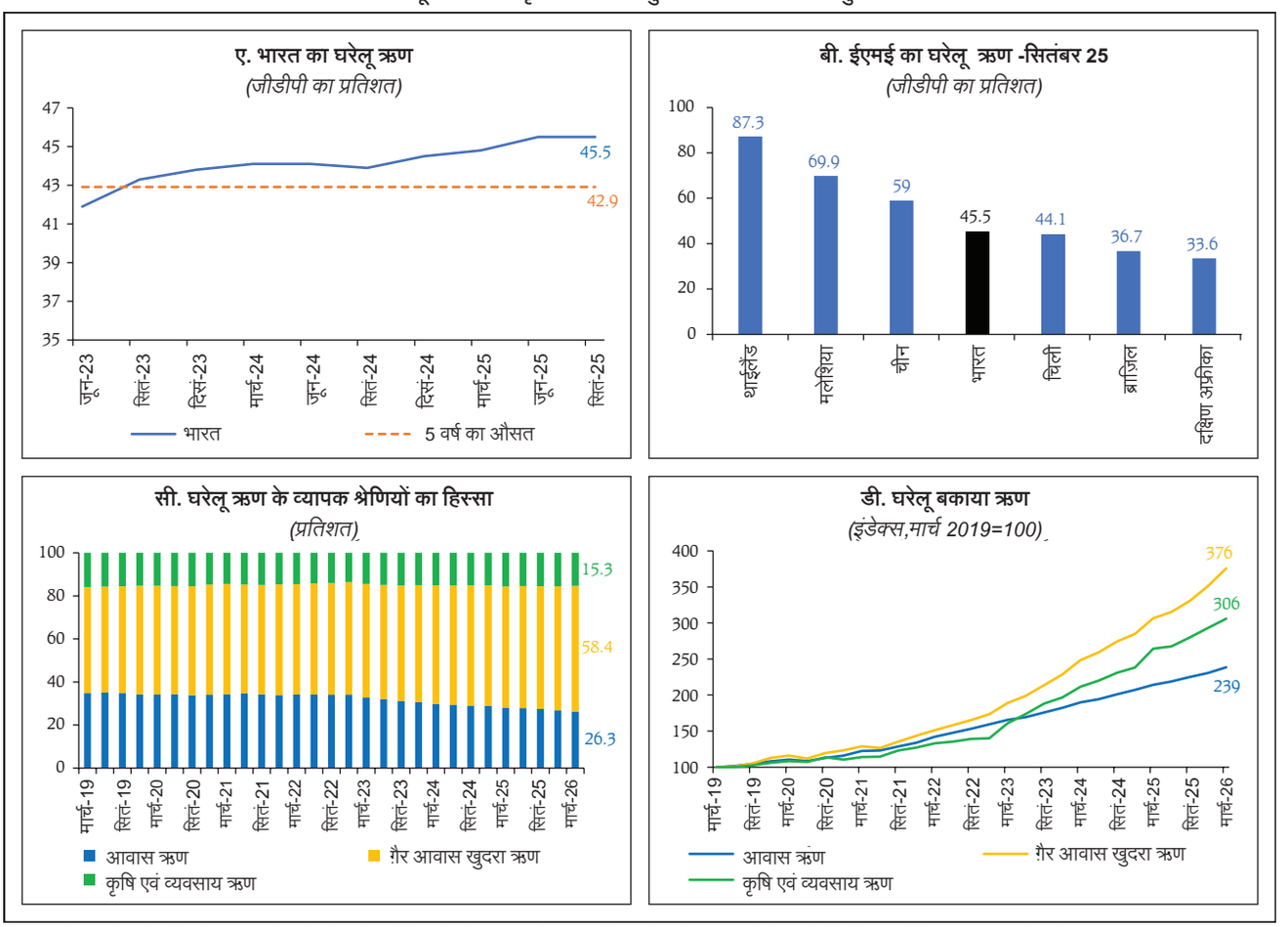
[25] अर्धवार्षिक बैलेंस शीट विश्लेषण 2336 सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों की संक्षिप्त बैलेंस शीट पर आधारित है।

हालांकि बैंकों और गैर-बैंकों से मजबूत ऋण प्रवाह से कॉर्पोरेट निवेश को निरंतर समर्थन मिल रहा है और क्षमता उपयोग अभी भी उच्च स्तर, अपने दीर्घकालिक औसत 74.0 प्रतिशत से ऊपर, (चार्ट 1.55 ए और बी) पर बना हुआ है। फिर भी, लगातार हो रहे बाहरी आपूर्ति आघातों के बीच फर्म कंपनियां अनिश्चित व्यवसाय वातावरण से निपटने का प्रयास कर रहे हैं।

B1.64 घरेलू क्षेत्र का कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, जो सितंबर 2025 के अंत तक जीडीपी के 45.5% तक पहुंच गया है (चार्ट 1.56 ए और बी)। यह वृद्धि मुख्य रूप से गैर-आवास खुदरा ऋणों के कारण है, जो मार्च 2026 तक कुल उधार का 58.4% है (चार्ट 1.56 सी)। समय के साथ आवास ऋण के अलावा कृषि एवं व्यावसायिक ऋण (चार्ट 1.56 डी) से आगे निकलते हुए उनकी हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि हुई है।

1.65 व्यापक श्रेणियों के संदर्भ में, अर्थात, उपभोग के उद्देश्यों हेतु[26], आस्ति सृजन[27], और उत्पादक प्रयोजनों[28] हेतु लिए गए ऋणों में से उपभोग के उद्देश्यों हेतु लिए गए ऋण कुल परिवार उधार का लगभग आधा हिस्सा है (चार्ट 1.57 ए)। उपभोग से जुड़े ऋण परिवार उधार की मुख्य धुरी बने रहे, जिसके बाद उत्पादन के उद्देश्य से लिए गए ऋण का स्थान है, जबकि

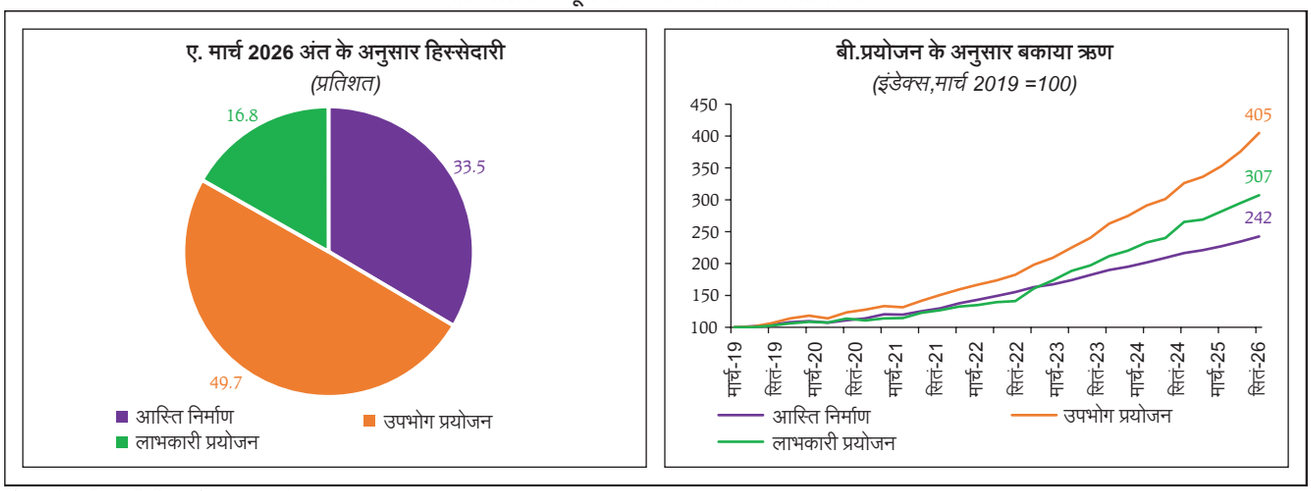
चार्ट 1.56: भारत का घरेलू ऋण अपेक्षाकृत कम है और मुख्य रूप से गैर-आवास खुदरा ऋणों द्वारा संचालित है



नोट: चार्ट (ए) और (बी) में, घरेलू ऋण परिवारों और परिवारों से जुड़े गैर-लाभकारी संस्थानों (एनपीआईएचएस) को बैंक और गैर-बैंक ऋणों से कुल ऋण दर्शाता है।
स्रोत : अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक डेटाबेस; और ट्रांसयूनियन सिबिल

[26] व्यक्तिगत ऋण, क्रेडिट कार्ड, टिकाऊ उपभोक्ता ऋण, अन्य व्यक्तिगत ऋण आदि शामिल हैं।
[27] आवास ऋण, वाहन ऋण और दोपहिया वाहन ऋण शामिल हैं।
[28] कृषि ऋण - व्यक्तिगत, व्यवसाय ऋण - व्यक्तिगत और शिक्षा ऋण शामिल हैं।

चार्ट 1.57: घरेलू उधार में उपभोग ऋण की अधिकता

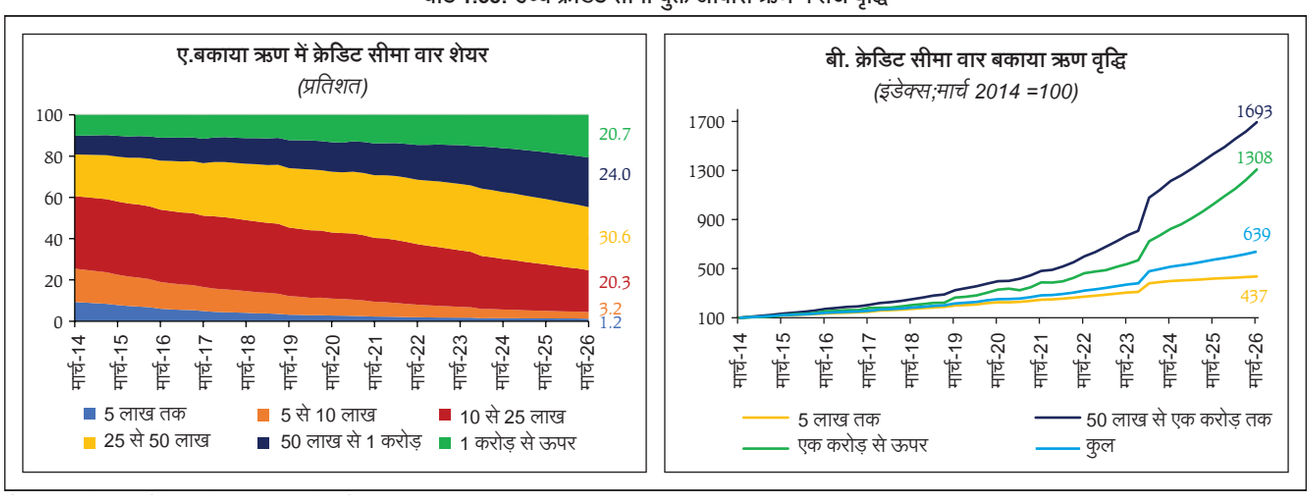


स्रोत: ट्रांसयूनियन सिबिल;और आरबीआई स्टाफ अनुमान

संपत्ति निर्माण के लिए लिए गए उधार की गति अपेक्षाकृत धीमी (चार्ट 1.57 बी) रही।

1.66 समय के साथ, बैंकों के आवास ऋण के पोर्टफोलियो में काफी बदलाव आया है। इससे पहले, 25 लाख रुपये से कम की ऋण सीमा (मार्च 2014 तक बकाया कुल आवास ऋण का 60.6 प्रतिशत) का वर्चस्व था, जो किफायती आवास पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है। हाल के वर्षों में, ऋण वितरण उच्च-मूल्य वाले खंडों की ओर बढ़ गया है, जिसमें ₹50 लाख और उससे अधिक की ऋण सीमा का हिस्सा अब बकाया ऋणों का 44.7 प्रतिशत है (चार्ट 1.58 ए और बी)। विशेष रूप से, बैंकों के गैर-निष्पादित आवास ऋण में कमी आई है और पूर्व-कोविड स्तर से गिरावट देखी गई है, जो मार्च 2019 के 1.2 प्रतिशत से घटकर मार्च 2026 में 0.5 प्रतिशत हो गई है।[29]

चार्ट 1.58: उच्च क्रेडिट सीमा युक्त आवास ऋण में तेज वृद्धि



नोट: ऋण सीमा अनुमोदित/ परिचालन ऋण सीमा है।
स्रोत: आरबीआई

[29] ट्रान्सयूनियन सिबिल द्वारा प्रदत्त डेटा के अनुसार।

सारणी 1.3: व्यक्तिगत ऋण - जोखिम श्रेणियों के लिए स्कोर माइग्रेशन

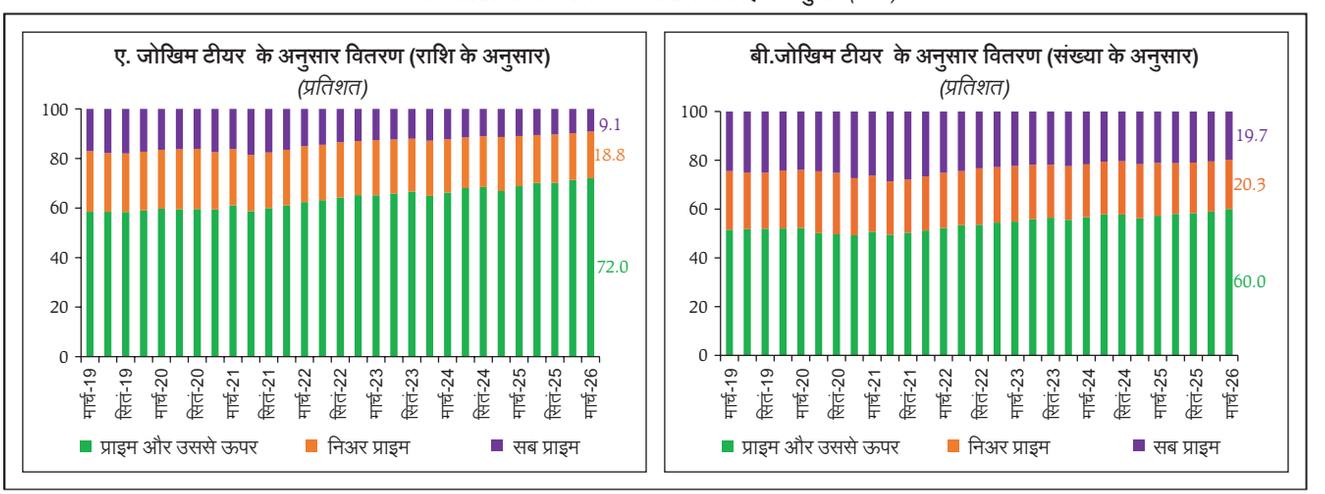
(प्रतिशत)

		सबप्राइम	निअर प्राइम	प्राइम	प्राइम प्लस	सुपर प्राइम	स्कोर टियर डाउनग्रेड	स्कोर टियर अपग्रेड
लाइव उधारकर्ता - स्कोर मूवमेंट (मार्च 2024 से मार्च 2025)								
		जोखिम टीयर मार्च 2025						
जोखिम टीयर मार्च 2024	सबप्राइम	79.0	13.8	5.6	1.4	0.3		21.0
	निअर प्राइम	22.2	31.9	33.7	11.5	0.8	22.2	45.9
	प्राइम	9.5	15.4	45.0	28.8	1.3	24.9	30.1
	प्राइम प्लस	4.3	8.7	24.4	57.3	5.3	37.4	5.3
	सुपर प्राइम	2.1	6.9	18.4	27.4	45.2	54.8	
लाइव उधारकर्ता - स्कोर मूवमेंट (मार्च 2025 से मार्च 2026)								
		जोखिम टीयर मार्च 2026						
जोखिम टीयर मार्च 2025	सबप्राइम	76.8	14.6	6.5	1.7	0.3		23.2
	निअर प्राइम	18.3	31.7	35.7	13.2	1.1	18.3	50.0
	प्राइम	7.3	13.9	46.9	30.6	1.4	21.2	31.9
	प्राइम प्लस	3.3	7.4	24.7	59.3	5.3	35.4	5.3
	सुपर प्राइम	1.6	5.9	17.8	27.3	47.3	52.7	

स्रोत: ट्रान्सयूनियन सिबिल;और आरबीआई स्टाफ अनुमान

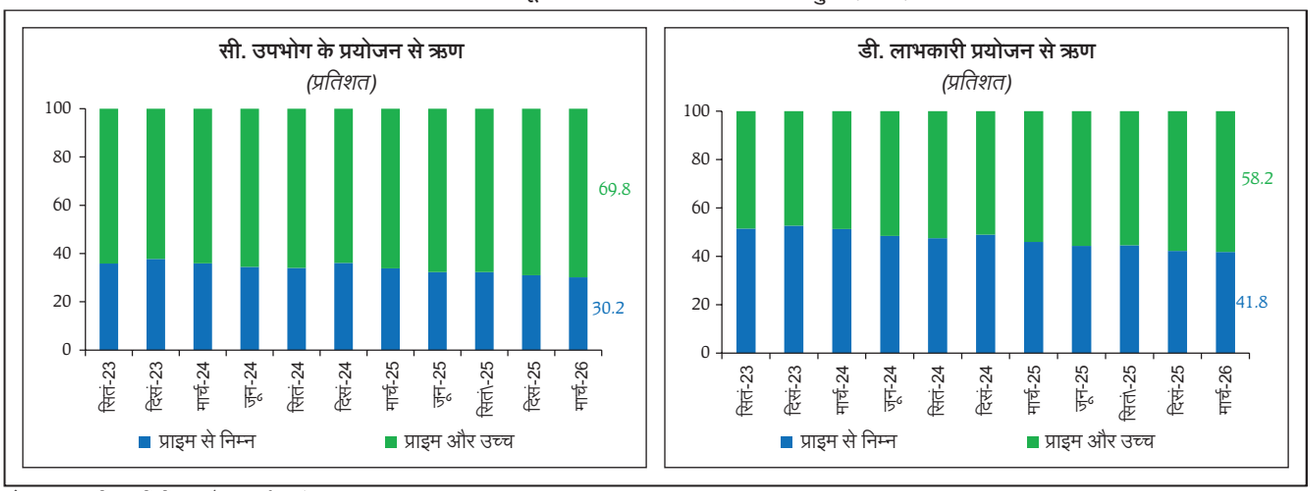
1.67 अरक्षित खुदरा ऋणों में से, व्यक्तिगत ऋण उपभोग से संबंधित ऋणों से अधिक थे। जोखिम टियर[30] माइग्रेशन मैट्रिक्स इंगित करता है कि प्राइम और उससे उच्चतर उधारकर्ताओं के एक बड़े हिस्से ने 2024-25 की तुलना में 2025-26 में अपनी जोखिम श्रेणियों को बनाए रखा। जबकि निकट-प्राइम और प्राइम उधारकर्ताओं में अधिक अपग्रेड देखा गया, प्राइम-प्लस और सुपर-प्राइम उधारकर्ताओं ने डाउनग्रेड में उच्च सहभागिता का अनुभव किया, हालांकि वे ज्यादातर प्राइम और उच्चतर श्रेणियों के भीतर बने रहे (सारणी 1.3)। इसके अतिरिक्त, दस एससीबी के आय-स्तर सर्वेक्षण से पता चलता है कि उधारकर्ता-पक्ष की कमजोरियां आय वर्ग और जोखिम श्रेणियों में परिसंपत्ति गुणवत्ता में व्यापक-आधारित सुधार के साथ निहित रहती हैं (उधारकर्ता आघात सहनीयता - आय स्तर विश्लेषण पर बॉक्स1.2 देखें)

चार्ट 1.59: परिवार उधार के जोखिम प्रोफाइल में सुधार *(जारी)*



[30] ट्रान्सयूनियन सिबिल स्कोर के आधार पर रिस्क टियर का बंटवारा इस प्रकार है: सब-प्राइम = 300–680; नियर-प्राइम = 681–730; प्राइम = 731–770; प्राइम प्लस = 771–790; सुपर प्राइम = 791–900।

चार्ट 1.59: घरेलू उधार का जोखिम प्रोफाइल बेहतर हुआ *(समाप्त)*



स्रोत: ट्रान्सयूनियन सिबिल; और आरबीआई स्टाफ अनुमान

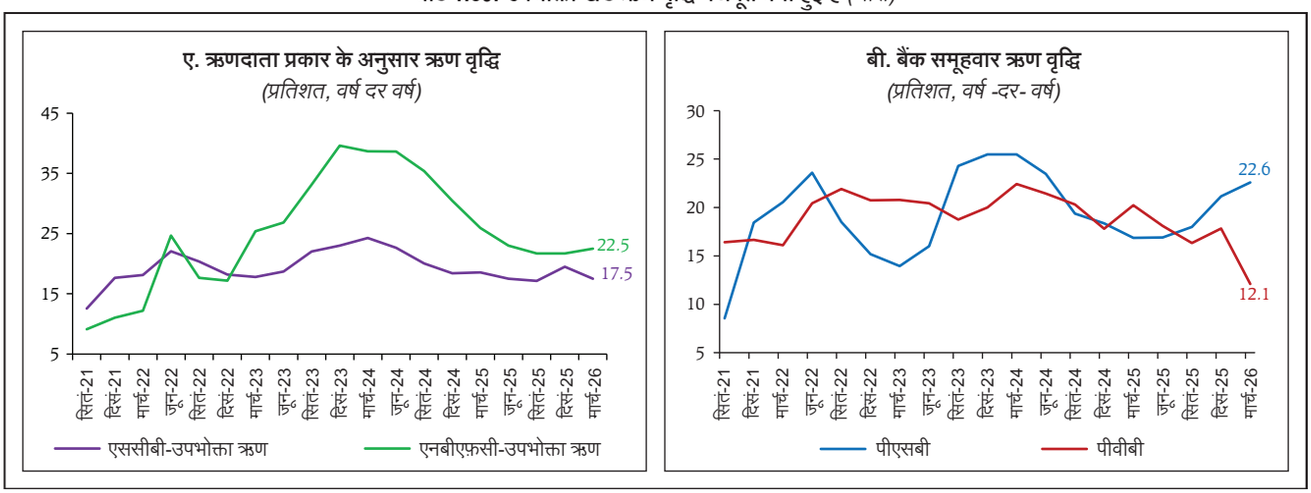
1.68 कुल मिलाकर, परिवार उधार में वृद्धि के बावजूद, उधारकर्ता प्रोफाइल में सुधार जारी रहा है। उच्च रेटिंग वाले उधारकर्ताओं (प्राइम और ऊपर) की हिस्सेदारी बकाया राशि और उधारकर्ताओं की संख्या (चार्ट 1.59 ए और बी) दोनों के संदर्भ में बढ़ी है। बकाया राशि और उधारकर्ताओं की संख्या दोनों के संदर्भ में उच्च-रेटेड उधारकर्ताओं (प्राइम और उससे ऊपर) की हिस्सेदारी बढ़ी है (चार्ट 1.59 ए और बी)। कुल बकाया ऋण में प्राइम और उससे ऊपर के उधारकर्ताओं की बढ़ती हिस्सेदारी के साथ यह सुधार उपभोग और उत्पादक ऋण दोनों में स्पष्ट है, (चार्ट 1.59 सी और डी)।

I.2.6 उपभोक्ता ऋण क्षेत्र

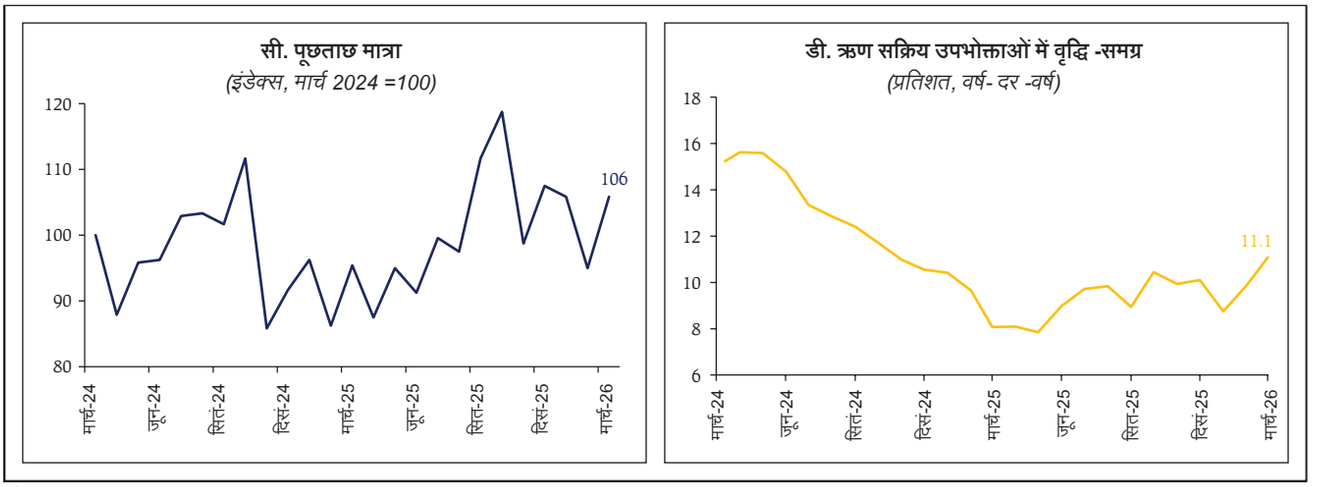
1.69 बैंकों और एनबीएफसी की ऋण वृद्धि में उपभोक्ता सेगमेंट एक प्रमुख कारक बना हुआ है, और यह समग्र अग्रिमों की तुलना में तेज गति से विस्तार कर रहा है।अनुसूचित वाणिज्य बैंकों में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में मजबूत विकास गति प्रदर्शित की (चार्ट 1.60 ए और बी)। पूछताछ की मात्रा (इनक्वायरी वॉल्युम) और ऋण-सक्रिय उपभोक्ताओं की वृद्धि दोनों मजबूत रही है (चार्ट 1.60 सी और डी)।

1.70 गैर-निष्पादित ऋणों में गिरावट से यह सिद्ध हुआ है कि ऋणदाता श्रेणी और ऋण उत्पाद के परिप्रेक्ष्य में उपभोक्ता ऋण खंड की आस्ति गुणवत्ता में सुधार जारी रहा है(चार्ट 1.61 ए और बी)। एसएमए -2 खातों से गिरावट में तेजी से कम हुई है जबकि ऋण उन्नयन धीमी गति से जारी रहा (चार्ट

चार्ट 1.60: उपभोक्ता खंड ऋण वृद्धि मजबूत बनी हुई है *(जारी)*

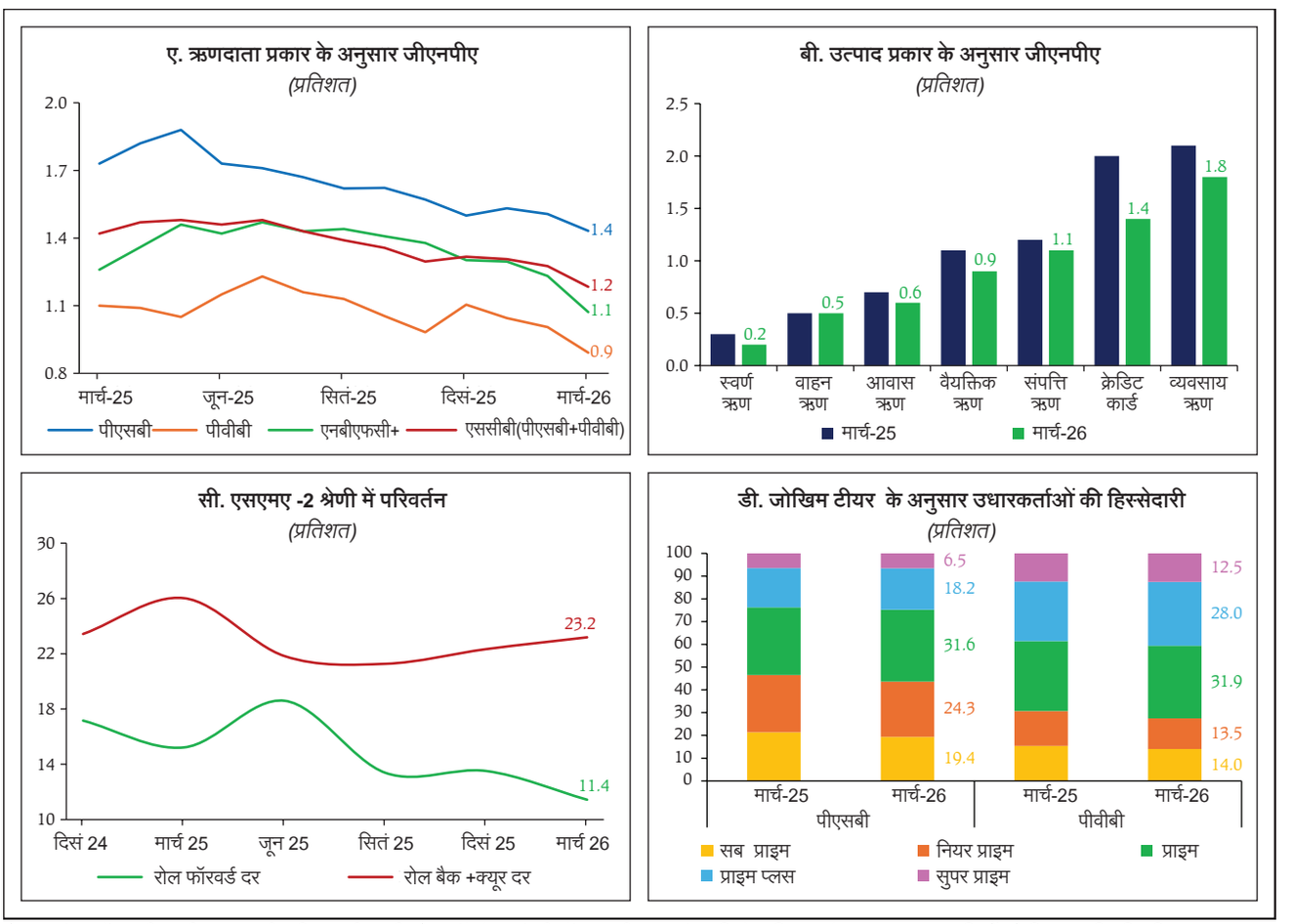


चार्ट 1.60: उपभोक्ता खंड ऋण वृद्धि मजबूत बनी हुई है *(समाप्त)*



स्रोत: ट्रांसयूनियन सिबिल

चार्ट 1.61: उपभोक्ता खंड ऋण की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हो रहा है



नोट: चार्ट (ए) में, एनबीएफसी+ एचएफसी सहित एनबीएफसी को दर्शाते है। चार्ट (बी) में, एलएपी का अर्थ संपत्ति के प्रति ऋण है; व्यवसाय ऋण व्यक्तियों को दिए गए प्रतिभूति रहित व्यवसाय ऋण हैं। चार्ट (सी) में, रोल फॉरवर्ड दर वर्तमान महीने में एसएमए-2 श्रेणी (61-90 डीपीडी) से प्रतिशत परिवर्तन (राशि में) है, जो अगले महीने (त्रैमासिक रूप से एकत्रित) में एनपीए श्रेणी (90+डीपीडी) में चला गया है। रोलबैक + क्यूर दर वर्तमान महीने में एसएमए-2 श्रेणी में प्रतिशत परिवर्तन (राशि में) है, जो अगले महीने (त्रैमासिक रूप से एकत्रित) में एसएमए-1/एसएमए-0/0 डीपीडी में वापस चला गया है। स्वर्ण ऋण में कृषि स्वर्ण ऋण शामिल हैं और सोने के आभूषण, गहने और सिक्कों की संपार्श्विक प्रतिभूति के एवज में दिए जाने वाले ऋण हैं।

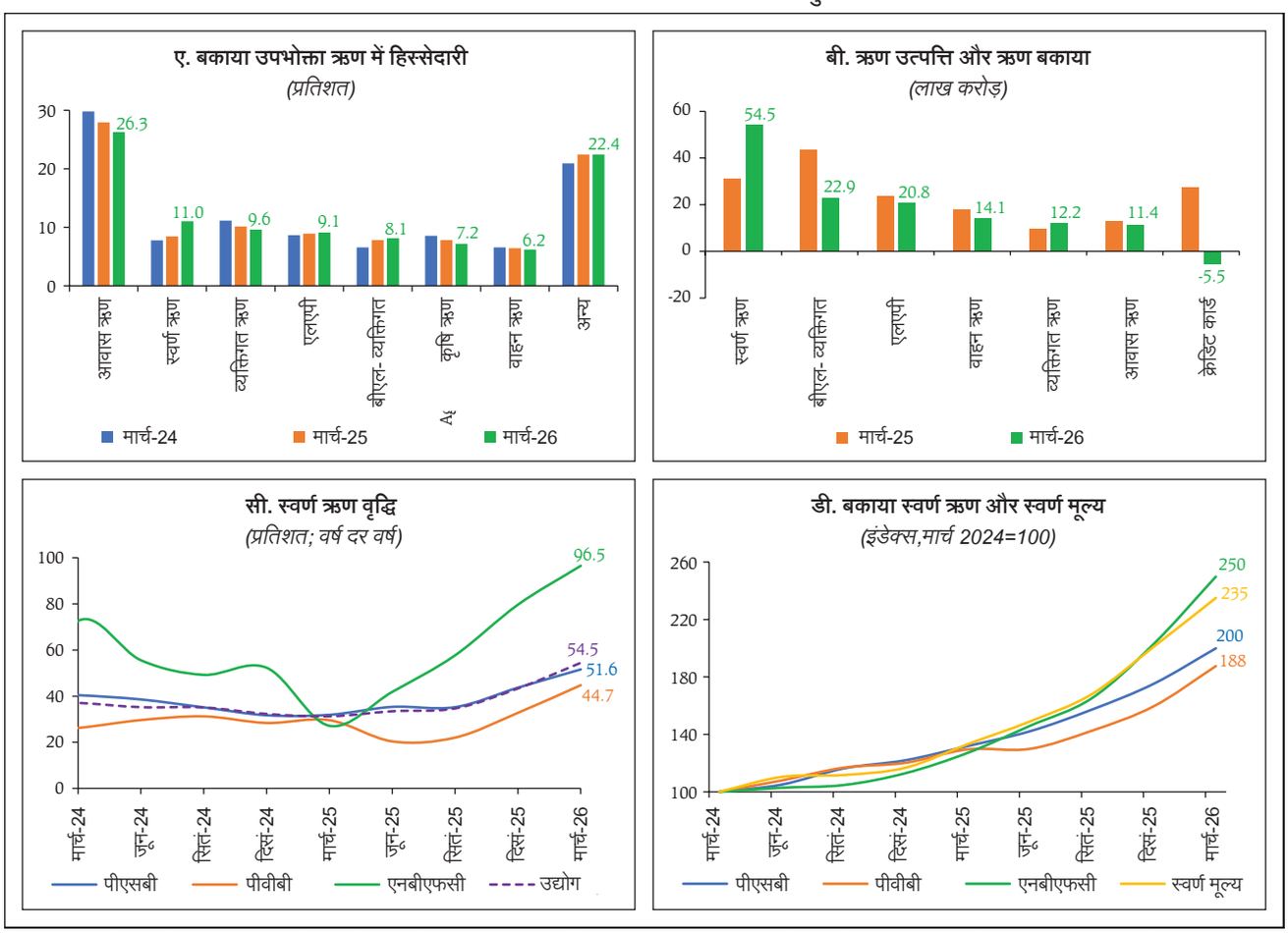
Source: TransUnion CIBIL.

1.61 सी)। इसके अलावा, प्राइम और उससे अधिक रेटिंग वाले उधारकर्ताओं का उच्च अनुपात इस सेगमेंट की ऋण संभावना को और मजबूत करता है (चार्ट 1.61 डी)।

1.71 स्वर्ण ऋण गैर-आवास खुदरा ऋणों के भीतर सबसे बड़े खंड के रूप में उभरा है, जो मार्च 2024 के बाद से 42.4 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़ रहा है – जो इसी अवधि के दौरान समग्र गैर-आवास खुदरा ऋण (23.0 प्रतिशत की सीएजीआर) की गति से लगभग दोगुना है(चार्ट 1.62 ए और बी)। बैंकों और एनबीएफसी दोनों ने 2025-26 में अपने स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो का काफी विस्तार किया है, जिसने आवास ऋण सहित अन्य खुदरा ऋण श्रेणियों में वृद्धि को पीछे छोड़ दिया है। सोने की कीमतों में तेज वृद्धि द्वारा इस रुझान को समर्थन मिला है(चार्ट 1.62 सी और डी) ।

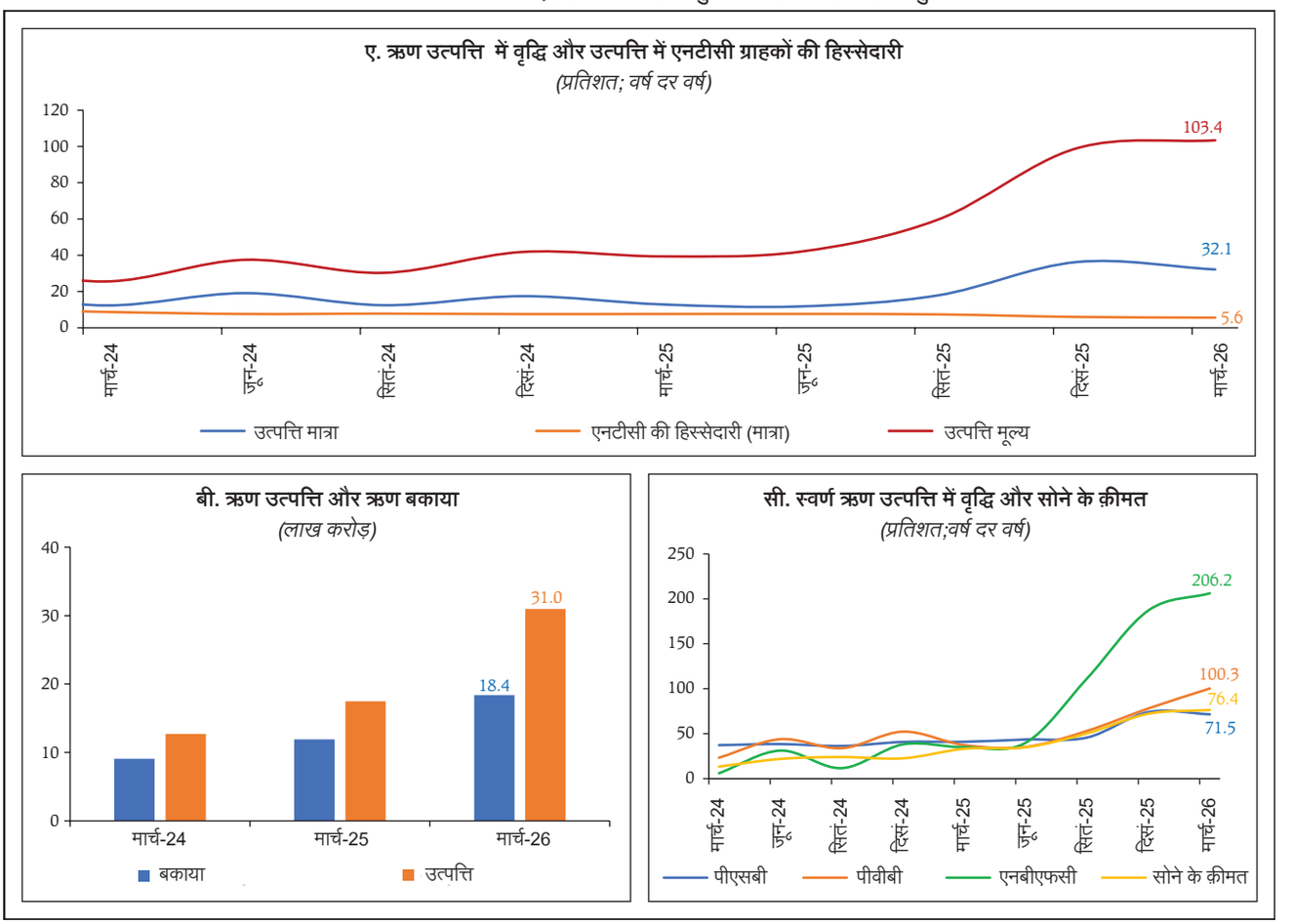
1.72 नए उधार और बकाया ऋण (चार्ट 1.63 ए और बी) के बीच के अंतर से संकेत मिलता है कि स्वर्ण ऋण में हालिया वृद्धि मुख्य रूप से मौजूदा उधारकर्ताओं द्वारा संचालित है, जो अधिक ऋण प्राप्त करने के लिए और मौजूदा ऋण के रोल ओवर के लिए सोने की उच्च कीमतों का उपयोग कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से एनबीएफसी ऋण उत्पत्ति में देखी जा रही है, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में काफी अधिक तेजी से बढ़ गयी है। (चार्ट 1.63 सी)।

चार्ट 1.62: उपभोक्ता खंड ऋण में स्वर्ण ऋण प्रमुख



नोट: चार्ट (ए) और (बी) में, एलएपी का अर्थ है संपत्ति के एवज़ में ऋण; बीएल का अर्थ है व्यावसायिक ऋण। चार्ट (सी) और (डी) के लिए, स्वर्ण ऋण में कृषि स्वर्ण ऋण शामिल हैं। चार्ट (डी) में, मुंबई में सोने की मासिक औसत कीमत (रुपये प्रति 10 ग्राम) पर विचार किया गया है।
स्रोत: ट्रांसयूनियन सिबिल; आरबीआई; और स्टाफ अनुमान

चार्ट 1.63: स्वर्ण ऋण में बढ़ते लीवरेज के साथ पुनः ऋण लेने वाले ग्राहक प्रमुख



नोट: उत्पत्ति मात्रा का अर्थ है नए ऋण खातों की संख्या और उत्पत्ति मूल्य का अर्थ है अवधि के दौरान प्रारंभ किए गए नए ऋणों की राशि। एनटीसी का अर्थ है न्यू टू क्रेडिट। चार्ट (बी) में, उत्पत्ति वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किए गए ऋणों से संबंधित है।

स्रोत: ट्रांसयूनियन सिबिल; आरबीआई पर्यवेक्षीय रिटर्न ; और स्टाफ अनुमान।

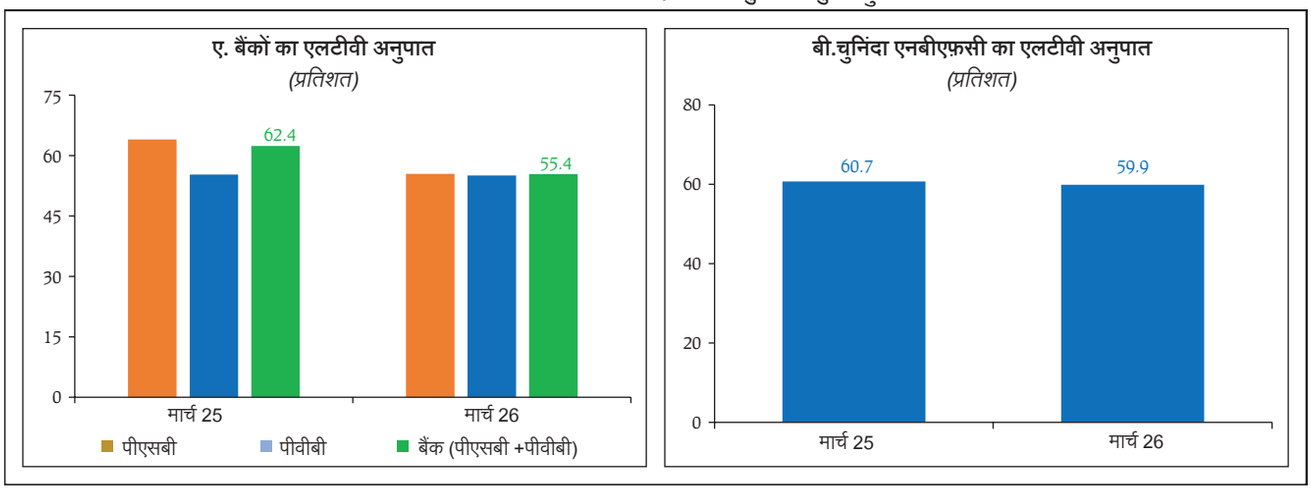
1.73 उधार लिए[31] गए स्वर्ण ऋण की राशि के आधार पर, स्वर्ण ऋण 75 प्रतिशत से 85 प्रतिशत के बीच मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) कैप के अधीन हैं। गौरतलब है कि, सोने की कीमतों में बढ़ोतरी के समर्थन के साथ स्वर्ण ऋण में मजबूत वृद्धि के बावजूद बैंकों और एनबीएफसी के एलटीवी अनुपात में गिरावट आई है। इसने संपार्श्विक बफर को मजबूत किया है और ऋणदाताओं को सोने की कीमतों में अप्रत्याशित गिरावट के प्रति एक विस्तृत कुशन प्रदान किया है।

1.74 उधारकर्ता जिनका व्यक्तिगत ऋण और स्वर्ण ऋण दोनों हैं, ऐसे उधारकर्ताओं के संबंध में सोने के ऋण में तेजी से वृद्धि होने के साथ-साथ व्यक्तिगत ऋणों की बकाया राशि की वृद्धि में कमी आई है। यह प्रवृत्ति विशेष रूप से सब-प्राइम उधारकर्ताओं के बीच दिखाई देती है ,जिनके व्यक्तिगत ऋण शेष और ऋण खातों में गिरावट आई है (चार्ट 1.65 ए, बी, सी और डी)

1.75 कुल मिलाकर, आस्तिह्रास का जोखिम नियंत्रण में है, और एलटीवी अनुपात द्वारा एक सुविधाजनक कुशन प्राप्त हो रहा है, वहीं सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव के बीच स्वर्ण कोलेटरल पर ऋण में शीघ्र वृद्धि में सतर्क और सावधान रहना महत्वपूर्ण है। सोने की कीमतों में लंबे समय तक उतार-चढ़ाव बने रहने से कोलेटरल सुरक्षा कमजोर हो सकती है, उधारकर्ता का तनाव बढ़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप अधिक चूक हो सकती है।

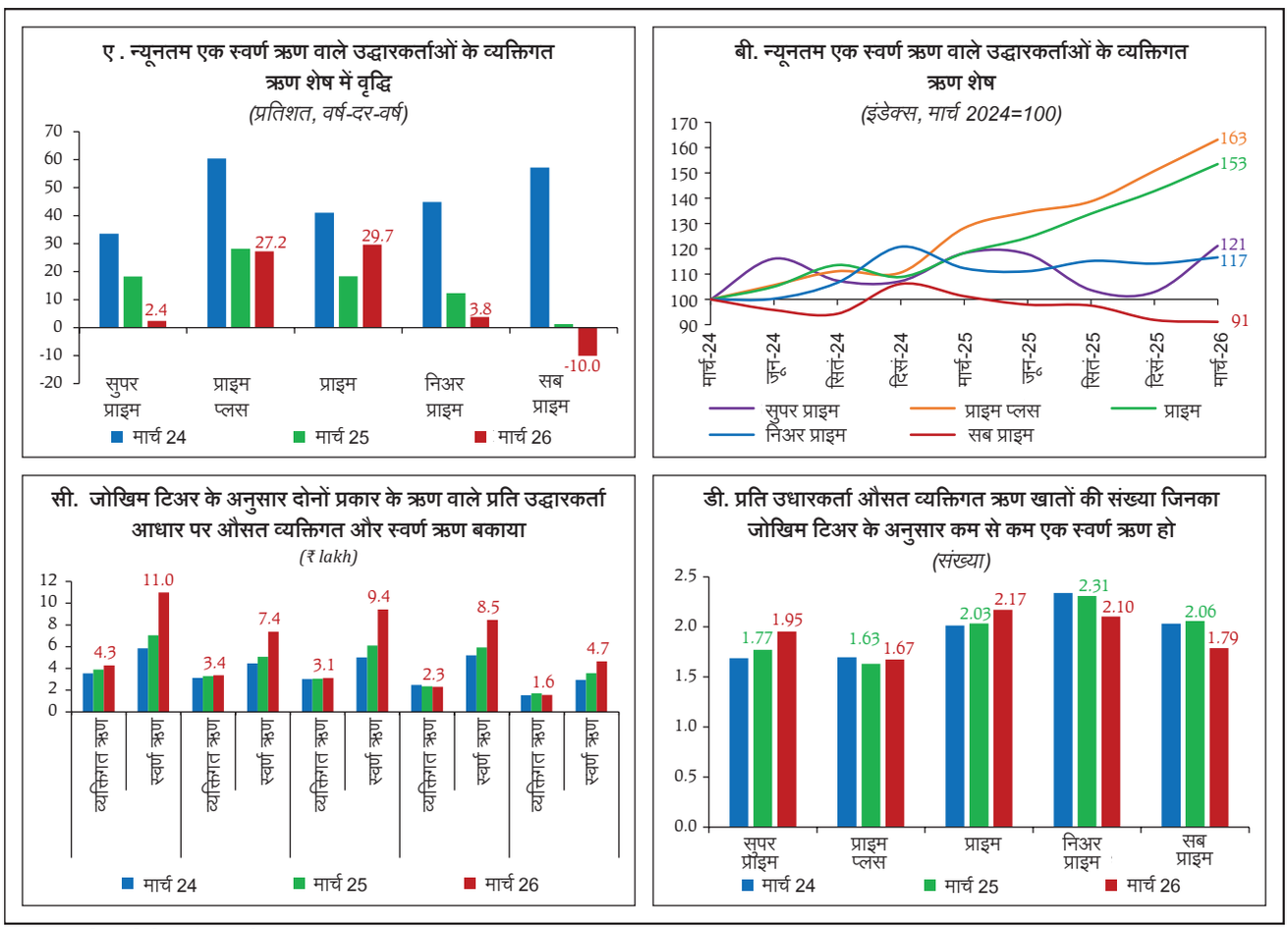
[31] भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – क्रेडिट सुविधाएँ) निर्देश, 2025 (01 अप्रैल, 2026 तक अद्यतन)।

चार्ट 1.64: बैंकों और गैर-बैंकों के एलटीवी अनुपात में सुधार हुआ है



नोट: चार्ट बी में, डेटा चुनिंदा एनबीएफसी के एलटीवी अनुपात से संबंधित है, जिनके स्वर्ण के एवज़ में ऋण उनके आस्ति पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा हिस्सा निर्मित करते हैं। 31 मार्च 2026 के अनुसार इन चुनिंदा एनबीएफसी के स्वर्ण ऋण पोर्टफोलियो का हिस्सा एनबीएफसी के कुल स्वर्ण ऋण बकाया का 75 प्रतिशत था।
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी; और चुनिंदा एनबीएफसी द्वारा प्रस्तुत सूचनाएं।

चार्ट 1.65: जोखिम वाले उधारकर्ता श्रेणियों में बढ़ते स्वर्ण ऋण और घटते व्यक्तिगत ऋण शेष



स्रोत: ट्रांसयूनियन सिबिल;और आरबीआई स्टाफ अनुमान

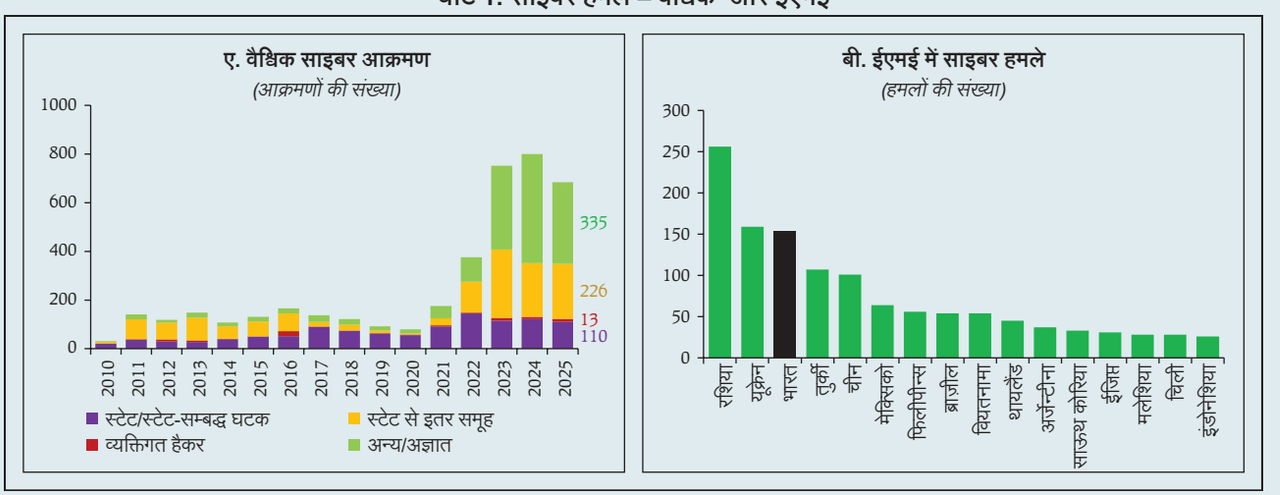
बॉक्स 1.1: साइबर जोखिम और वित्तीय स्थिरता

तेजी से डिजिटल हो रही और परस्पर रूप से जुड़ी वित्तीय प्रणाली में साइबर जोखिम एक प्रमुख वित्तीय स्थिरता संबंधी चिंता बन गया है। साइबर घटनाएं सेवा व्यवधान, डेटा हानि और भुगतान प्रणाली में अड़चन के माध्यम से महत्वपूर्ण वित्तीय बुनियादी ढांचे को बाधित कर सकती हैं, साथ ही वित्तीय प्रणाली में जनता के विश्वास को भी कम कर सकती हैं। हाल के वर्षों में डिजिटल वित्तीय सेवाओं को तेजी से अपनाने से दुर्भावनापूर्ण पक्षों के लिए हमले के दायरे का विस्तार हुआ है, जिससे 2020 के बाद से साइबर हमलों में वैश्विक वृद्धि हुई है। भारत इन जोखिमों का शिकार बना हुआ है, जहां अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में साइबर हमले होते हैं (चार्ट 1 ए और बी)।

डिजिटलाइज़ेशन में वृद्धि और बढ़ते साइबर खतरों की पृष्ठभूमि में, साइबर जोखिम तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए, प्रमुख भारतीय बैंकों और एनबीएफसी का एक सर्वेक्षण किया गया था [32]। 79% प्रत्यर्थियों ने रिपोर्ट किया कि उनके ग्राहक लेनदेन का तीन-चौथाई से अधिक अब डिजिटल रूप से होता है। अधिकांश संस्थानों को लगता है कि उनका साइबर जोखिम नियंत्रण में है जबकि 98% ने अपने वर्तमान जोखिम स्तर को बहुत कम से मध्यम स्तर तक माना है (चार्ट 2ए), जो उनकी मौजूदा जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की प्रभावशीलता में मजबूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। यह मूल्यांकन परिचालन परिणामों के अनुरूप है, क्योंकि संस्थानों ने 2025-26 के दौरान महत्वपूर्ण ग्राहक सेवाओं में न्यूनतम व्यवधान की सूचना दी, और जो घटनाएं हुईं उन्हें 24 घंटों के भीतर काफी हद तक नियंत्रित किया गया। लगभग एक-तिहाई प्रत्यर्थियों ने एक साल पहले की तुलना में साइबर जोखिम में मध्यम या महत्वपूर्ण वृद्धि की सूचना दी, जो एक चुनौतीपूर्ण खतरे के माहौल (चार्ट 2 बी) के कारण बढ़ती अनिश्चितता पर प्रकाश डालता है।

साइबर खतरों के उभरते परिदृश्य में तकनीकी और साइबर सुरक्षा क्षमताओं में निरंतर निवेश की आवश्यकता है। सर्वेक्षण के अनुसार, 81 प्रतिशत प्रत्यर्थियों ने 2025-26 के दौरान राजस्व के 5 प्रतिशत से भी कम आईटी व्यय की सूचना दी। तथापि, रिपोर्ट की गई सूचना प्रौद्योगिकी

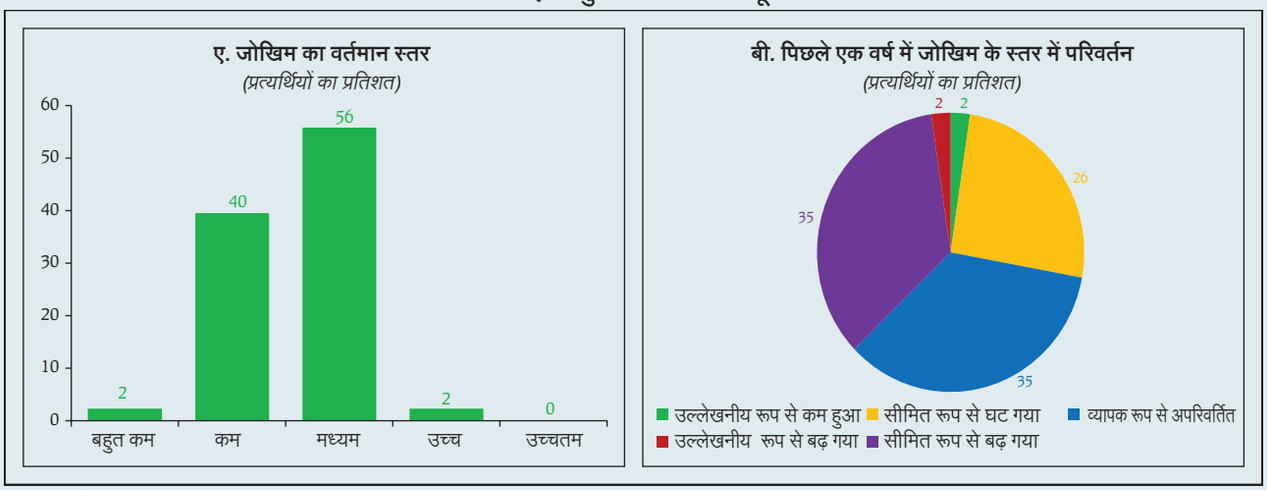
चार्ट 1: साइबर हमले – वैश्विक और ईएमई



टिप्पणी: चार्ट (ए) में, "स्टेट/स्टेट-संबद्ध घटक" का अर्थ राष्ट्र-राज्य घटकों या गैर-राज्य घटकों द्वारा किए गए हमले हैं जिनके लिए स्टेट संबद्धता इंगित की गई है। चार्ट (बी) में, जनवरी 2000 और मई 2026 के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किए गए मूर्त साइबर हमलों पर आधारित डेटा।
स्रोत: साइबर घटनाओं की यूरोपीय रिपोज़टरी; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[32] एससीबी और 10 ऊपरी स्तर एनबीएफ़सी में सर्वे किया गया।

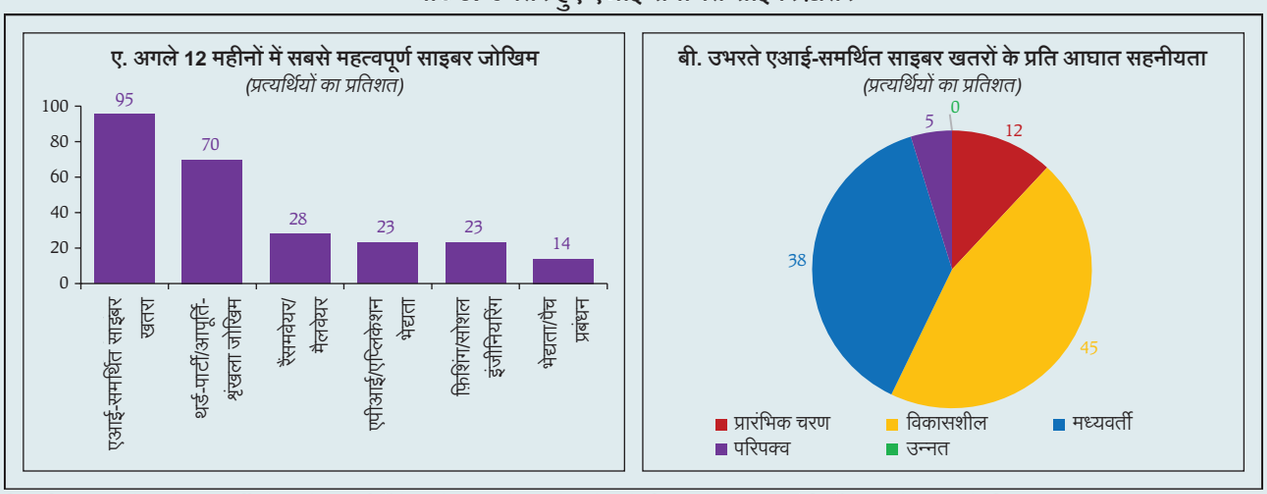
चार्ट 2: साइबर सुरक्षा जोखिम का मूल्यांकन



स्रोत: आरबीआई सर्वेक्षण परिणाम।

व्यय अनुपात में संस्थागत अंतर हो सकता है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ व्यापार मॉडल, समूह-स्तर की प्रौद्योगिकी व्यवस्थाएं, प्रौद्योगिकी संसाधन जुटाना/आउटसोर्सिंग मॉडल, और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी निवेशों का समय निर्धारण आदि शामिल है। बहरहाल, मानव पूंजी और साइबर सुरक्षा बुनियादी ढांचे में बढ़ते निवेश साइबर खतरों से निपटने के लिए हमारी तैयारी में प्रगति के संकेत दे रहे हैं। मार्च 2025 और मार्च 2026 के बीच, लगभग 67 प्रतिशत प्रत्यर्थियों ने आईटी और साइबर सुरक्षा स्टाफिंग में वृद्धि रिपोर्ट की। इसके अलावा, पिछले तीन वित्त वर्षों में 71 प्रतिशत प्रत्यर्थियों ने आईटी व्यय के हिस्से के रूप में साइबर सुरक्षा व्यय में वृद्धि दर्ज की है। इस संबंध में, साइबर सुरक्षा सहित समग्र आईटी बजट से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क एक महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में कार्य कर सकते हैं। एआई-सक्षम साइबर खतरे आने वाले 12 महीनों के लिए प्रमुख कथित जोखिम बन गए हैं(चार्ट 3 ए)। एआई में तेजी से प्रगति साइबर घटनाओं की जटिलता, गति और पैमाने को बढ़ा सकती है। सर्वेक्षण प्रतिक्रियाएं यह इंगित करती

चार्ट 3: उभरते हुए एआई समर्थित साइबर ख़तरे



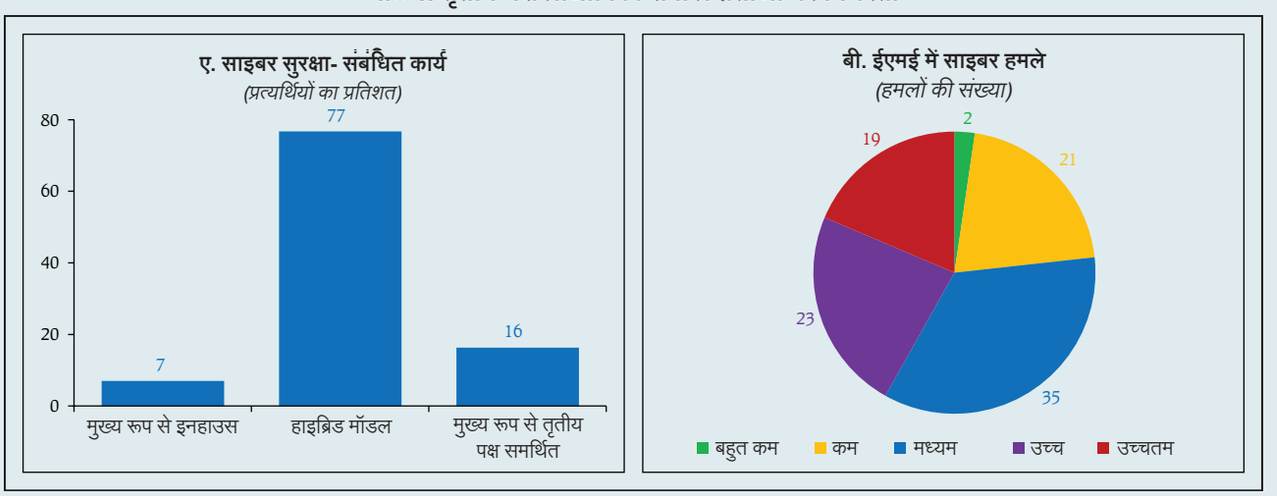
टिप्पणी: चार्ट (ए) में, प्रत्येक प्रत्यर्थी को अगले 12 महीनों में अपने संगठन के सामने आने वाले तीन सबसे महत्वपूर्ण जोखिमों का उल्लेख करने के लिए कहा गया था।
स्रोत: आरबीआई सर्वेक्षण परिणाम।

हैं कि एआई-समर्थित खतरा प्रबंधन तैयारी उनके मौजूदा साइबर जोखिम प्रबंधन ढांचे के भीतर औपचारिकता और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर हैं। अधिकांश प्रत्यर्थियों ने अपने आप को 'विकासशील' या 'मध्यवर्ती' चरण में वर्गीकृत किया है जबकि एक छोटे हिस्से ने 'परिपक्व' चरण रिपोर्ट किया (चार्ट 3 बी)। यह एआई-सक्षम साइबर खतरों के एक विकसित जोखिम क्षेत्र के संदर्भ में देखा जा सकता है, जहां संस्थाओं के मौजूदा साइबर सुरक्षा नियंत्रण ढांचे पर निर्भर करते हुए जोखिम-आधारित सन्नद्धता उपायों को लगातार मजबूत करने की अपेक्षा की जाएगी। इसलिए, विनियामक मार्गदर्शन के तहत खतरे की निगरानी, पता लगाना, प्रतिक्रिया, कर्मचारी जागरूकता, घटना तैयारी और आघात सहनीयता क्षमताओं को लगातार मजबूत करना महत्वपूर्ण बना रहेगा। इस संबंध में, वित्तीय क्षेत्र में विनियामक सामंजस्य अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।

सर्वेक्षण में तृतीय पक्ष निर्भरता और आपूर्ति श्रृंखला जोखिम को दूसरा सबसे महत्वपूर्ण साइबर जोखिम माना गया। 93 प्रतिशत प्रत्यर्थियों ने सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) निगरानी, क्लाउड सुरक्षा, घटना प्रतिक्रिया, खतरा आसूचना, भेद्यता (वलनेरबिलिटी) आकलन आदि जैसे साइबर सुरक्षा से संबंधित कार्यों के लिए बाहरी विक्रेताओं पर आंशिक या काफी हद तक निर्भर हैं।(चार्ट 4 ए)। इसके अलावा, तीन-चौथाई प्रत्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए तीसरे पक्ष की प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं पर परिचालन निर्भरता मध्यम से बहुत अधिक तक है (चार्ट 4 बी)। आउटसोर्सिंग पर बढ़ती निर्भरता आपूर्ति श्रृंखला जोखिम उत्पन्न करती है, खासकर जहां सीमित संख्या में सेवा प्रदाता एक साथ कई वित्तीय संस्थानों की सहायता करते हैं। ऐसे किसी भी प्रदाता को प्रभावित करने वाली एक बड़ी साइबर घटना विनियमित संस्थाओं में तेजी से फैल सकती है, परिचालनगत व्यवधानों को बढ़ा सकती है और वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकती है।

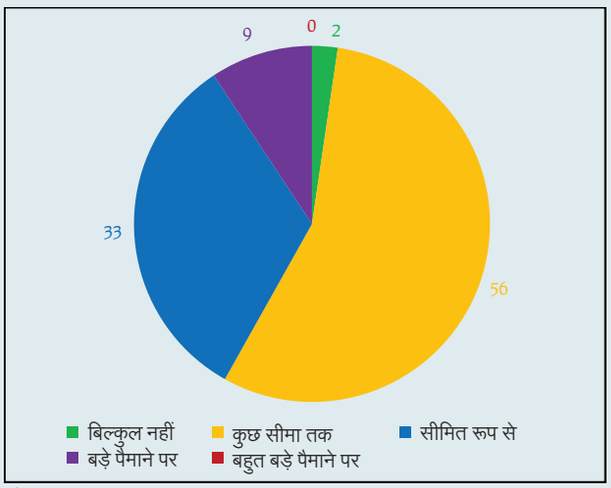
तृतीय पक्ष जोखिमों से निकटता से जुड़ी चुनौतियाँ प्रौद्योगिकी अप्रचलन और पैच प्रबंधन से संबंधित हैं। सर्वेक्षण के निष्कर्ष इंगित करते हैं कि भारतीय वित्तीय संस्थान प्रौद्योगिकी जीवन-चक्र जोखिमों का प्रबंधन सक्रिय रूप से कर रहे हैं। प्रमुख जोखिम श्रेणियों में, जिसमें असमर्थित या एंड-ऑफ-लाइफ सिस्टम, प्रमुख उन्नयन की प्रतीक्षा कर रहे सिस्टम और विक्रेता सुरक्षा पैच प्राप्त करने में असमर्थ सिस्टम शामिल हैं, 93 प्रतिशत प्रत्यर्थियों ने अपनी महत्वपूर्ण सेवाओं और अनुप्रयोगों में या तो कोई जोखिम न होने या कम जोखिम की सूचना दी। यह परिचालनगत आघात सहनीयता के लिए एक मजबूत आधार को दर्शाता है, हालांकि नई कमजोरियों के तेजी से उभरने को देखते हुए

चार्ट 4: तृतीय-पक्ष प्रौद्योगिकी सेवा प्रदाताओं पर निर्भरता



स्रोत:आरबीआई सर्वेक्षण परिणाम।

चार्ट 5: भू-राजनीतिक अनिश्चितता और साइबर हमलों की संभावना
(प्रत्यर्थियों का प्रतिशत)



स्रोत: आरबीआई सर्वेक्षण परिणाम।

निरंतर सतर्कता आवश्यक बनी हुई है। भू-राजनीतिक तनाव साइबर जोखिम संबंधी चिंताओं को बढ़ा सकते हैं और खतरों की बदलती गतिविधियों के खिलाफ सतर्कता की आवश्यकता को मजबूत कर सकते हैं। इस चिंता को दर्शाते हुए, सर्वेक्षित संस्थानों में से 42 प्रतिशत ने बताया कि भू-राजनीतिक अनिश्चितता ने साइबर हमलों की संभावना को बढ़ा दिया है (चार्ट 5)।

कुल मिलाकर, सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि वित्तीय संस्थानों ने साइबर जोखिम प्रबंधन के प्रमुख क्षेत्रों, विशेष रूप से महत्वपूर्ण सूचना प्रणालियों के भेद्यता मूल्यांकन और प्रवेश परीक्षण में मजबूत प्रथाओं को स्थापित किया है। महत्वपूर्ण साइबर घटनाओं की विनियामक रिपोर्टिंग और बोर्ड-स्तरीय रिपोर्टिंग से संबंधित प्रक्रियाएं भी परिपक्व हो गई हैं। तथापि, यह देखते हुए कि मानव व्यवहार साइबर हमलों के लिए सबसे अधिक शोषित प्रवेश बिंदुओं में से एक है, कर्मचारियों के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता और प्रशिक्षण ऐसे क्षेत्र बने हुए हैं जिन्हें और मजबूत करने की आवश्यकता है। इसी तरह, घटना प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करने, डिजिटल साक्ष्य को संरक्षित करने और परिष्कृत साइबर हमलों की स्थिति में विनियामक और कानून प्रवर्तन अन्वेषण की सुविधा के लिए फोरेंसिक तैयारियों में भी सुधार की आवश्यकता है।

बॉक्स 1.2 उधारकर्ता आघात सहनीयता - आय स्तर विश्लेषण

समष्टिविवेकपूर्ण नीति का एक प्रमुख उद्देश्य प्रतिकूल घटनाओं के प्रति उधारकर्ताओं में आघात सहनीयता का निर्माण करना है। कई देशों में, उधारकर्ता-आधारित उपकरण जैसे मूल्य की तुलना में ऋण (एलटीवी) और/या आय के प्रति ऋण (डीटीआई) अनुपात का उपयोग उधारकर्ता-पक्ष की कमजोरियां निर्मित होने से रोकने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों में प्रतिभूति रहित व्यक्तिगत ऋणों की मांग बढ़ रही है और अतीत में, इस खंड ने इतनी तेजी से विकास किया है कि विनियामकों को मामलों को नियंत्रित रखने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा था।हालांकि इन उपायों के बाद ऋण वृद्धि में मंदी आई है, लेकिन ऐसे ऋणों की प्रतिभूति रहित प्रकृति उधारकर्ता भेद्यता का स्रोत बनी हुई है।

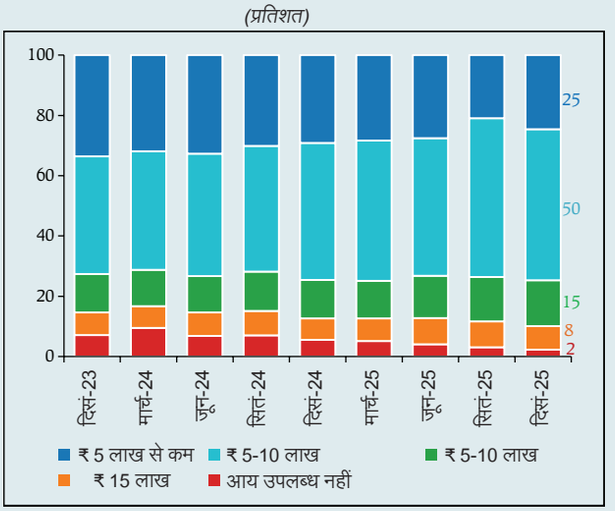
इस पृष्ठभूमि में, ऐसे सेगमेंट से अप्रत्याभूत व्यक्तिगत ऋण (पीएल) उद्भव और नई गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) पर विस्तृत आय-स्तर के आंकड़े एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण किए गए थे[33]। सर्वेक्षण 2023-24 की तीसरी तिमाही से 2025-26 की तीसरी तिमाही तक नौ तिमाहियों की अवधि में किया गया, जिसमें पांच आय बकेट शामिल हैं- ₹5 लाख से कम, ₹5–10 लाख, ₹10–15 लाख, >= ₹15 लाख, आय-उपलब्ध नहीं—और छह ऋण जोखिम टिअर[34]। सर्वेक्षण द्वारा आय समूहों और रेटिंग श्रेणियों के संबंध में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई जो ऋण उद्भव और ऋण क्षतियों पर वर्चस्व रखते हैं।

नीचे दिए गए चार्ट्स से पता चलता है कि आय वितरण के मामले में, अधिकांश ऋण ₹5 लाख से कम या ₹5–10 लाख के बीच कमाने वाले लोगों को दिए जा रहे हैं। इसी तरह, ऋण जोखिम के मामले में, प्राइम या प्राइम-प्लस रेटिंग वाले उधारकर्ता बड़े पैमाने पर हैं जो ऋण उद्भव का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा हैं (चार्ट 1 और 2)। विशेष रूप से, 5 लाख रुपये से कम के खंड की हिस्सेदारी में गिरावट का रुझान दिख रहा है। इसके अलावा, 2025-26 की तीसरी तिमाही के लिए जोखिम स्तरों और आय स्तरों का विघटन 10 लाख रुपये से कम आय वाले समूह (कोहोर्ट) में और प्राइम और प्राइम प्लस जोखिम टियरों में जोखिम का संकेन्द्रण दर्शाता है (सारणी1)।

ऋण उद्गम की तरह, ऋण हानियां भी 10 लाख रुपये से कम आय वाले समूह (कोहोर्ट) में केंद्रित हैं(चार्ट 3)। फिर

चार्ट 1: आय के आधार पर वैयक्तिक ऋण जारी किया जाना

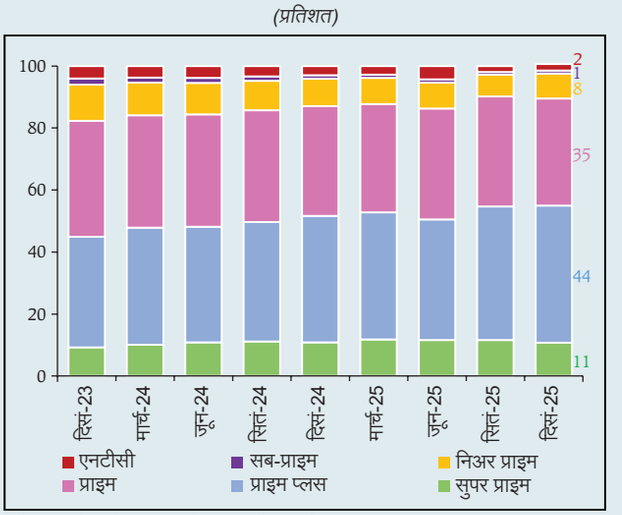
(प्रतिशत)



स्रोत: आरबीआई सर्वेक्षण परिणाम।

चार्ट 1: आय के आधार पर वैयक्तिक ऋण जारी किया जाना

(प्रतिशत)



स्रोत:आरबीआई सर्वेक्षण परिणाम ;और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[33] ति3:2025-26 में कुल वैयक्तिक ऋण का 89% हिस्सा रखने वाले 10 बड़े एससीबी (पीएसबी और पीवीबी) ने इस सर्वे में हिस्सा लिया।

[34] ट्रान्सयूनियन सिबिल द्वारा बताए गए छह जोखिम टियर (जोखिम के स्तर) ये हैं – सब-प्राइम, नियर प्राइम, प्राइम, प्राइम प्लस, सुपर प्राइम और न्यू टू क्रेडिट (टीटीसी)।

[35] इसे ऐसे ऋण खातों के तौर पर मापा गया जो तिमाही की शुरुआत में 'मानक' थे और तिमाही के आखिर में ' गैर निष्पादित' श्रेणी में आ गए।

सारणी 1: जारी पीएल का विभाजन – 2025 -26 की तीसरी तिमाही के लिए जोखिम टिअर और आय स्तर

(प्रतिशत शेयर)

	सुपर प्राइम	प्राइम प्लस	प्राइम	निअर प्राइम	सब प्राइम	न्यू टू क्रेडिट (एनटीसी)
<₹5 लाख	2	10	9	2	0	1
₹5 से 10 लाख	5	24	17	4	0	1
₹10-15 लाख	2	7	5	1	0	0
□ ₹ 15 लाख	2	3	3	0	0	0
आय उपलब्ध नहीं	0	1	1	0	0	0

स्रोत: आरबीआई सर्वेक्षण प्रतिक्रियाएं; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

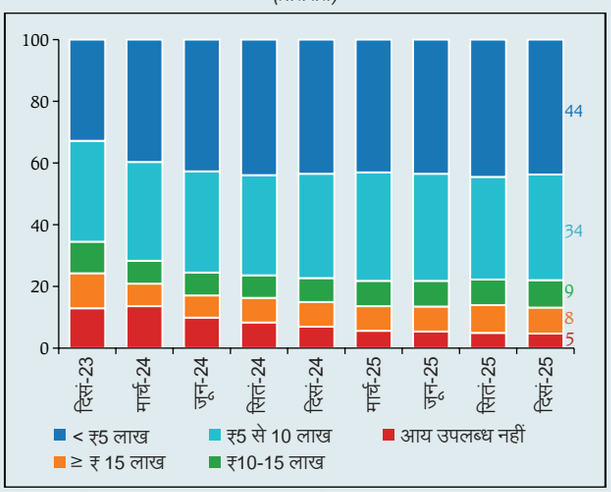
भी, चूक की घटनाएं नियंत्रण में हैं और सभी रेटिंग श्रेणियों में कम हैं, जिसमें सब-प्राइम और नियर प्राइम सेगमेंट में सबसे अधिक सुधार दिखाई दे रहा है। फिर भी, चूक अंतर्निहित हैं और सभी रेटिंग श्रेणियों में गिरावट दिख रही है, जिसमें सब-प्राइम और नियर- प्राइम खंडों में सुधार सबसे अधिक दिखाई देता है (सारणी 2)।

आय कोहॉर्ट और जोखिम-टियर को सम्मिलित करते हुए किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि 5-10 लाख रुपये की आय बकेट में प्राइम-प्लस उधारकर्ता व्यक्तिगत ऋण उद्भव में वृद्धि में प्राथमिक योगदानकर्ता थे, जबकि सब-प्राइम और न्यू-टू-क्रेडिट (एनटीसी) उधारकर्ताओं ने अपेक्षाकृत कम वृद्धि दर्ज की। आस्ति गुणवत्ता में व्यापक रूप से सुधार हुआ है, सभी जोखिम-स्तरों में नए एनपीए में गिरावट आई है। उद्भव के रुझानों के अनुरूप, ₹5-10 लाख आय वर्ग में प्राइम-प्लस उधारकर्ताओं ने भी नए एनपीए में सबसे अधिक वृद्धि हेतु योगदान दिया (चार्ट 4ए और बी)।

बैंक-स्तरीय विविधता का अध्ययन करने के लिए, वायलिन प्लॉट[36] का निर्माण किया गया था जो सभी आय बकेट और जोखिम टियरों में सर्वेक्षण अधीन सभी बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए वर्ष - दर- वर्ष विकास दरों का पूर्ण वितरण दर्शाता है। प्लॉट कतिपय बैंकों के संबंध में जोखिम टियरों और आय बकेट में विचलन के साथ समग्र रूप से उद्भव गुणवत्ता में सुधार दिखाता है (चार्ट 5ए और बी)।

चार्ट 3: आय के अनुसार नए एनपीए

(प्रतिशत)



स्रोत: आरबीआई सर्वेक्षण परिणाम ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सारणी 2: सम्पूर्ण जोखिम श्रेणी में एक वर्ष की चूक दर

(प्रतिशत)

	Dec-24	Mar-25	Jun-25	Sep-25	Dec-25
सुपर प्राइम	0.16	0.12	0.14	0.12	0.11
प्राइम प्लस	0.27	0.26	0.28	0.24	0.22
प्राइम	0.58	0.51	0.51	0.43	0.41
निअर प्राइम	0.78	0.77	0.86	0.60	0.55
सब प्राइम	1.85	2.86	3.58	2.05	1.01
न्यू टू क्रेडिट (एनटीसी)	0.42	0.41	0.48	0.33	0.35
समग्र	0.51	0.49	0.56	0.41	0.35

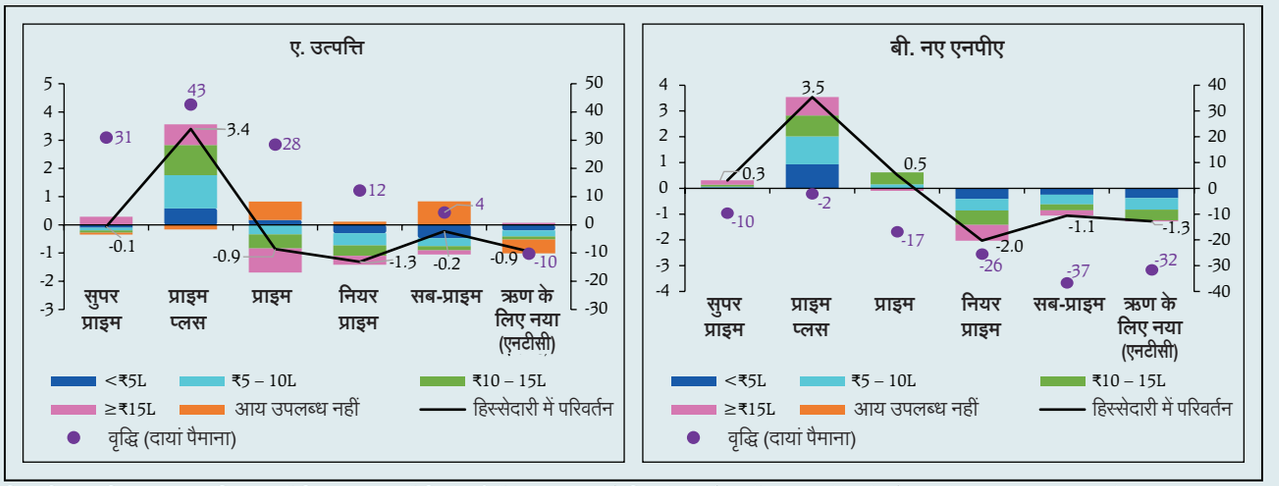
टिप्पणी: यहां विचार में लिए गए जोखिम स्तर-वार एक वर्ष की चूक दर, दी गई अवधि में व्यक्तिगत ऋण उद्गमों का अनुपात है जो वितरण के एक वर्ष बाद चूकयुक्त हो गए।

स्रोत: आरबीआई सर्वेक्षण परिणाम ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[36] किसी भी पॉइंट पर वायलिन की चौड़ाई उस ग्रोथ लेवल पर बैंक-टियर सेल ऑब्ज़र्वेशन की डेंसिटी को दिखाती है — चौड़ा हिस्सा बताता है कि उस वैल्यू के आस-पास ज़्यादा सेल जमा हैं। यह एनालिसिस के लिहाज़ से ज़रूरी है क्योंकि एक जैसी मीडियन ग्रोथ वाले दो सेगमेंट के रिस्क प्रोफ़ाइल बहुत अलग हो सकते हैं: एक जिसमें सभी सेल मीडियन के आस-पास कसकर जुड़े होते हैं, और दूसरा जिसमें कुछ तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं जबकि कुछ तेज़ी से घट रहे होते हैं। इस तरह वायलिन सिंगल नंबर (मीडियन) समरी के पीछे के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाता है और हमें इनकम बकेट और रिस्क-टियर के आधार पर बैंक के व्यवहार का अंदाज़ा लगाने में मदद करता है।

चार्ट 4: 'उत्पत्ति (ओरिजिनेशन्स) और अर्नजक आस्तियों (एनपीए) में सापेक्ष हिस्सेदारी में परिवर्तन – जोखिम स्तर और आय स्तर

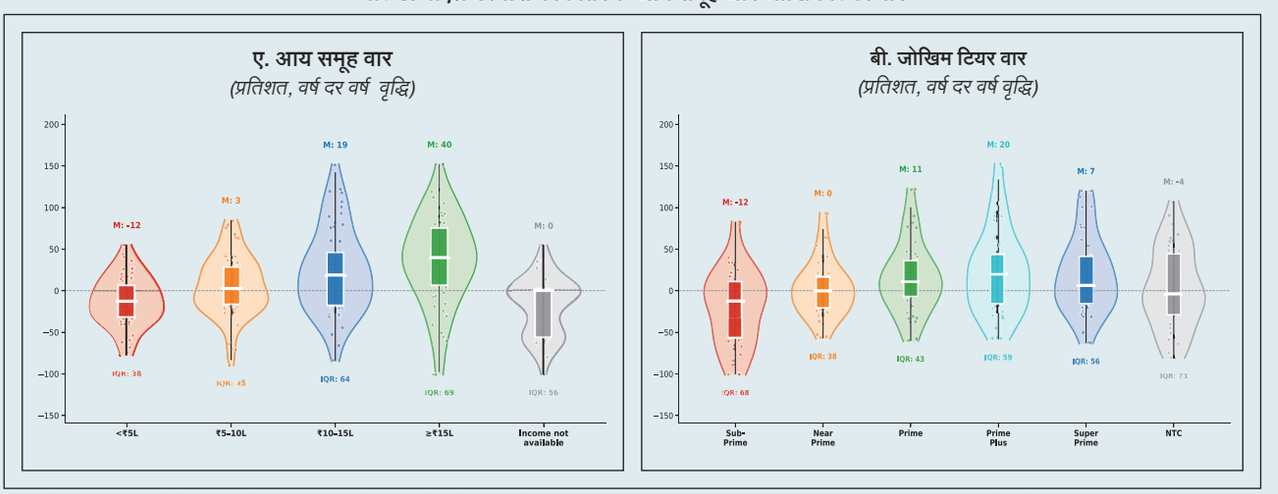
(प्रतिशत, हिस्सेदारी में परिवर्तन, बायां पैमाना; प्रतिशत, वर्ष दर वर्ष वृद्धि, दायां पैमाना)



टिप्पणी: बार ति3:2024-25 की तुलना में ति3:2025-26 में हिस्सेदारी में आए बदलाव को दिखाते हैं और इन्हें हर आय ब्रैकेट के योगदान के आधार पर बांटा गया है।
स्रोत: आरबीआई सर्वे प्रतिक्रिया और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

दूसरी ओर, आस्ति मूल्यह्रास के मामले में, सभी आय और जोखिम आधारित बकेट में मीडियन वैल्यू नेगेटिव रही है, जिससे यह पुष्टि होती है कि नए एनपीए की बढ़ोतरी में कमी आ रही है। हालाँकि, नीचे दिए गए लंबे वायलन ₹5 लाख से कम (IQR37: 56) और ₹5–10 लाख (IQR: 47) अलग-अलग खंड़ों में बैंकों के बीच काफी अंतर दिखता है। कुल मिलाकर, भले ही आस्ति की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है, फिर भी अलग-अलग टियर के कुछ बैंकों में अभी भी दबाव बना हुआ है (चार्ट 6 ए और बी)।

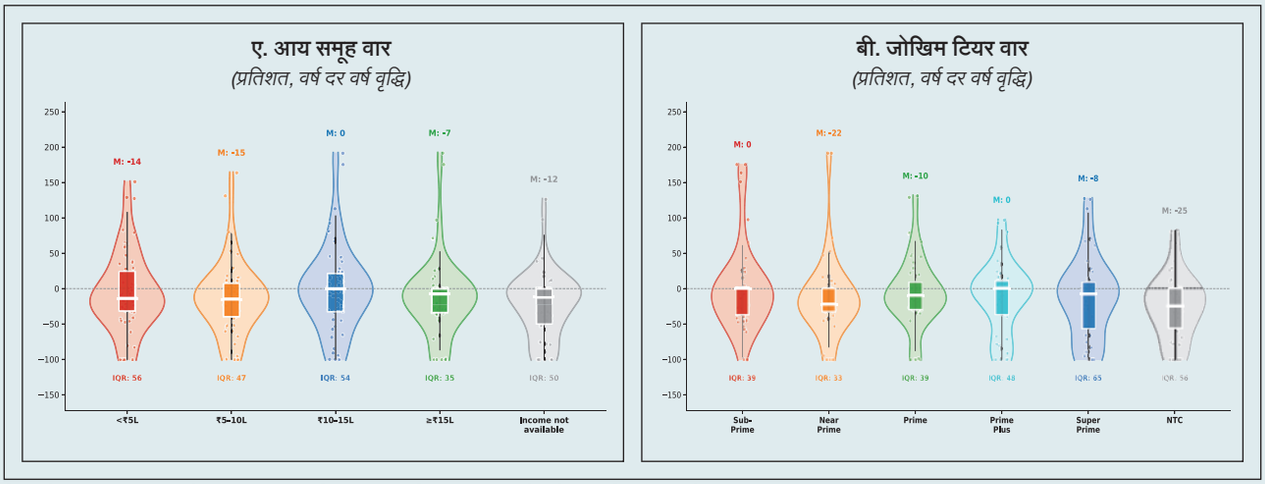
चार्ट 5: पीएल उत्पत्ति का वितरण- आय समूह और जोखिम टियर वार



टिप्पणी: हर डॉट एक विशिष्ट बैंक की वर्ष-दर- वर्ष वृद्धि × जोखिम टियर कॉम्बिनेशन (आय समूह वारचार्ट) या बैंक × आय समूह कॉम्बिनेशन (जोखिम टियर वार चार्ट) दर दिखाता है; हर वायलिन में क्रमशः 60 और 50 तक अवलोकन शामिल हैं। वैल्यूज़ को [2nd–98th] परसेंटाइल पर विंसोराइज़ किया गया है।
स्रोत: आरबीआई सर्वे प्रतिक्रिया और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[37] आईक्यूआर (इंटरक्वार्टाइल रेंज) डिस्ट्रिब्यूशन के 75वें और 25वें परसेंटाइल के बीच का अंतर है; चौड़ाई आईक्यूआर ग्रुप में बैंक के गतिविधि में ज़्यादा प्रसार को दिखाता है।

चार्ट 6: पीएल नए एनपीए का वितरण – आय बकेट और जोखिम टियर के अनुसार



टिप्पणी: ये वैल्यूज़ नए एनपीए में वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर हैं। वायलिन संरचना उसी तरीके से की गई है जैसी चार्ट 5 में है।
स्रोत: आरबीआई सर्वे प्रतिक्रिया और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

कुल मिलाकर, बैंकों ने वैयक्तिक ऋण वृद्धि को बेहतर आय प्रोफ़ाइल और ऋण गुणवत्ता वाले उधारकर्ताओं की ओर मोड़ा है, जिसमें ₹5–10 लाख की आय वाले लोग ऋण लेने वालों के मुख्य वर्ग के तौर पर उभरे हैं। इसके विपरीत, ₹5 लाख से कम कीमत वाले खंड की हिस्सेदारी में भारी गिरावट देखी गई है। आस्ति गुणवत्ता में आम तौर पर सुधार हुआ है, जो आय और जोखिम की सभी श्रेणियों में नए एनपीए के कम होने से दिखाई देता है। तथापि, कम आय वाले खंड में नए एनपीए का हिस्सा, नए लोन देने में उनके योगदान के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। कुल मिलाकर स्थिति सकारात्मक है, लेकिन अलग-अलग बैंकों और उधार लेने वालों के समूहों के हिसाब से निष्पादन अलग-अलग है।

अध्याय II

वित्तीय संस्थाएं: सुदृढ़ता और लचीलापन

भारतीय बैंकिंग सेक्टर, पर्याप्त पूंजी और चलनिधि बफ़र के साथ मज़बूत बना रहा और आस्ति गुणवत्ता में भी लगातार सुधार हुआ। मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट के नतीजों से पता चला कि मुश्किल हालात में भी एससीबी का कुल पूंजी स्तर नियामक न्यूनतम से ऊपर बना रहेगा। एनबीएफसी सेक्टर भी मज़बूत बना रहा; इसमें आस्ति गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ अच्छे पूंजी और लाभप्रदता अनुपात भी देखे गए। अलग-अलग तरह की वित्तीय संस्थाओं के बीच बकाया द्विपक्षीय एक्सपोज़र के मामले में आपसी जुड़ाव लगातार बढ़ता रहा।

परिचय

2.1 चुनौतीपूर्ण विश्व परिदृश्य के बावजूद भारतीय वित्तीय सेक्टर मज़बूत बना रहा। बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने अपनी बैलेंस शीट को मज़बूत करना जारी रखा; इसमें उन्हें अच्छे पुंजी अनुपात और सुविधादायक चलनिधि बफ़र से मदद मिली, साथ ही अर्नजक आस्तियों के अनुपात भी कई दशकों के निचले स्तर पर रहे। एनबीएफसी की ओर से क्रेडिट विस्तार की रफ़्तार धीमी हुई, खासकर उद्योग और सेवा क्षेत्र में, जबकि आस्ति गुणवत्ता में और सुधार हुआ। दवाब परीक्षणों के नतीजों ने इस बात की पुष्टि की कि ये संस्थान मुश्किल हालात में भी नुकसान झेलने और कुल मिलाकर नियामक न्यूनतम से काफी ऊपर पूंजी अनुपात बनाए रखने में सक्षम हैं। वित्तीय क्षेत्र के अन्य खंड, जैसे आस्ति प्रबंधन कंपनियां, समाशोधन निगम और बीमा क्षेत्र भी मजबूत बने रहे।

2.2 यह अध्याय घरेलू वित्तीय क्षेत्र के नवीनतम रुझानों और वित्तीय प्रणाली की मज़बूती का आकलन करने के लिए किए गए दबाव परीक्षण पर शैलीगत तथ्य और विश्लेषण प्रस्तुत करता है। खंड II.1 विभिन्न मापदंडों के माध्यम से भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार करता है, जैसे कि व्यापार मिश्रण; आस्ति गुणवत्ता; बड़े उधारकर्ताओं की एकाग्रता; पूंजी पर्याप्तता; आय और लाभप्रदता। एससीबी के लचीलेपन का मूल्यांकन करने के लिए मैक्रो दबाव परीक्षण और संवेदनशीलता विश्लेषण भी किए जाते हैं। खंड II.2 और II.3 क्रमशः शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) और एनबीएफसी के वित्तीय मापदंडों की जांच करते हैं, जिसमें इस संस्थाओं के दबाव परिक्षण भी शामिल है। खंड II.4, II.5 और II.6 में क्रमशः बीमा क्षेत्र, म्यूचुअल फंड और समाशोधन निगमों की सुदृढ़ता का परीक्षण किया जाता है। खंड II.6 में प्रतिकूल परिदृश्यों के तहत संक्रामक विश्लेषण के साथ भारतीय वित्तीय प्रणाली की नेटवर्क संरचना और कनेक्टिविटी के विस्तृत विश्लेषण किया जाता है।

II.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी)[1 2 3]

2.3 एससीबी (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों) की समेकित बैलेंस शीट मजबूत बनी रही; इसमें आस्ति गुणवत्ता और पूंजी अनुपात में लगातार सुधार हुआ और चलनिधि बफर भी सुविधाजनल स्तर पर रहे। 2025-26 के दौरान वर्ष की दूसरी छमाही में एससीबी ऋण और जामराशि में वृद्धि हुई। नेट

[1] विश्लेषण मुख्य रूप से भारतीय रिज़र्व बैंक के पर्यवेक्षी विवरणी पर आधारित हैं, जो बड़े उधारकर्ताओं के डेटा के मामले को छोड़कर केवल अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के घरेलू परिचालन को कवर करते हैं, जो बैंकों के वैश्विक परिचालन पर आधारित हैं। इस कार्य के लिए, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक और विदेशी बैंक और लघु वित्त बैंक शामिल हैं।

[2] विश्लेषण 11 जून 2026 तक उपलब्ध अनंतिम डेटा पर आधारित हैं।

[3] वैयक्तिक ऋण व्यक्तियों को दिए जाने वाले ऋणों को संदर्भित करते हैं और इसमें (ए) उपभोक्ता ऋण (बी) शिक्षा ऋण (सी) अचल संपत्तियों (जैसे आवास, आदि) के निर्माण/संवर्द्धन के लिए दिए गए ऋण और (डी) वित्तीय परिसंपत्तियों (शेयर, डिबेंचर, आदि) में निवेश के लिए दिए गए ऋण शामिल हैं।

इंटरेस्ट मार्जिन (NIMs) मोटे तौर पर स्थिर रहे। मार्च 2026 में अन्य ऑपरेटिंग इनकम में बढ़ोतरी की गति कुछ कम रहने से प्रावधान और टैक्स से पहले की आय (EBPT) में बढ़ोतरी की रफ़्तार धीमी पड़ गई (सारणी 2.1)।

II.1.1 जमाराशियां और ऋण

2.4 2025-26 के दौरान एससीबी (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) की कुल जमा राशि में वर्ष-दर-वर्ष 11.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। निजी क्षेत्रों के बैंकों (पीवीबी) और विदेशी बैंकों (एफबी) में जमा राशि जुटाने में तेज़ी देखी गई (चार्ट 2.1 ए) । सावधी जमा में बढ़ोतरी, चालू और बचत खाता जमाराशि की तुलना में ज़्यादा बनी रही, जिससे पता चलता है कि लोग ब्याज देने वाले सावधि जमाराशि को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं (चार्ट 2.1 बी)।

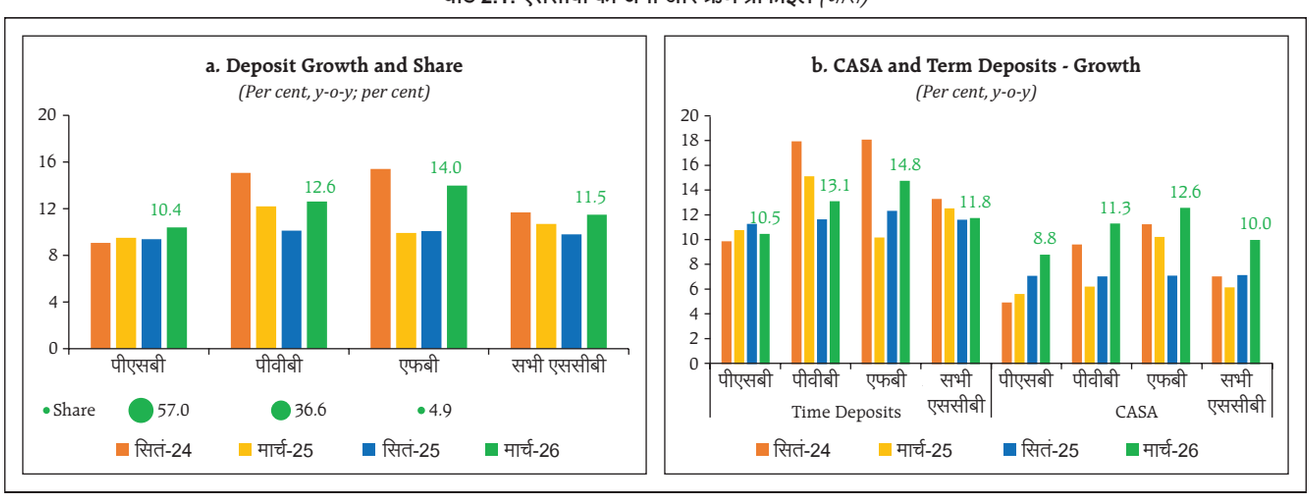
2.5 2025-26 के दौरान एससीबी (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों) की ऋण वृद्धि वर्ष- दर- वर्ष आधार पर बढ़कर 14.5 प्रतिशत हो गई, जिसमें पीएसबी (सरकारी क्षेत्र के बैंक) का प्रदर्शन पीवीबी (निजी क्षेत्र के बैंक) से बेहतर बना रहा (चार्ट 2.1 सी)। प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में, पिछले वर्ष की तुलना में सेवा क्षेत्र और व्यक्तिगत ऋण के लिए दिए गए ऋण की हिस्सेदारी बढ़ी, जबकि उद्योग को दिए गए ऋण की हिस्सेदारी में कमी आई (चार्ट 2.1 डी)। मार्च 2026 में सभी चार प्रमुख क्षेत्रों में ऋण वृद्धि में बढ़ोतरी हुई, जो ऋण मांग में व्यापक मज़बूती का संकेत है (चार्ट 2.1 इ)। कुल ऋण वृद्धि के विश्लेषण से

सारणी 2.1: हेल्थ ट्रैकर – अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी)

			उत्तम ⟶ बुरा			
	(प्रतिशत)	*10-वर्षीय माध्यिका*	31-मार्च-23	31-मार्च-24	31-मार्च-25	31-मार्च-26
ऋण और जमा	ऋण वृद्धि	*11.0*	15.4	19.4	11.0	14.5
	जमाराशि वृद्धि	*10.1*	10.1	13.8	10.7	11.5
आस्ति गुणवत्ता और प्रोविज़निंग	जीएनपीए अनुपात	*7.3*	3.9	2.8	2.3	1.8
	एनएनपीए अनुपात	*2.4*	1.0	0.6	0.5	0.4
	स्लिपेज अनुपात	*2.8*	1.9	1.6	1.5	1.2
	पीसीआर	*67.4*	74.1	76.2	76.3	75.6
चलनिधि	एलसीआर	*130.3*	143.5	130.3	132.5	124.2
	एनएसएफआर	*126.4*	128.8	126.9	126.4	122.1
अर्जन	एनआईआई वृद्धि	*10.1*	21.6	15.4	7.9	4.0
	ओओआई वृद्धि	*7.9*	7.7	17.9	18.0	14.5
	इबीपीटी वृद्धि	*12.3*	16.1	12.3	14.9	7.9
	पीएटी वृद्धि	*16.8*	39.7	31.5	16.8	7.2
लाभप्रदता	एनआईएम	*3.3*	3.7	3.7	3.5	3.3
	आरओए	*0.7*	1.1	1.3	1.4	1.3
	आरओई	*8.0*	12.3	13.7	13.5	12.6
कैपिटल	सीईटी1 अनुपात	*13.2*	14.0	14.0	14.8	15.3
	सीआरएआर	*16.2*	17.2	16.8	17.4	17.7

टिप्पणी: यह टेबल पिछले 10 वर्षों के डेटा के आधार पर सेक्टर की सेहत की तुलनात्मक जानकारी देता है। सही स्थिति दिखाने के लिए रंगों का इस्तेमाल किया गया है; इसमें 10 साल के मिनिमम/मैक्सिमम (इंडिकेटर के आधार पर) को सबसे अच्छा/सबसे खराब माना गया है। एलसीआर और एनएसएफआर (मिनिमम 100 और मिडपॉइंट 120) को छोड़कर, मिडपॉइंट 50वां परसेंटाइल है। सीईटी1 अनुपात और सीआरआर के लिए, न्यूनतम रेगुलेटरी कैपिटल को सबसे खराब माना गया है। पीएटी वृद्धि: निम्नतम और अधिकतम को क्रमशः (-)100 और 100 माना गया है।
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां और स्टाफ गणनाए।

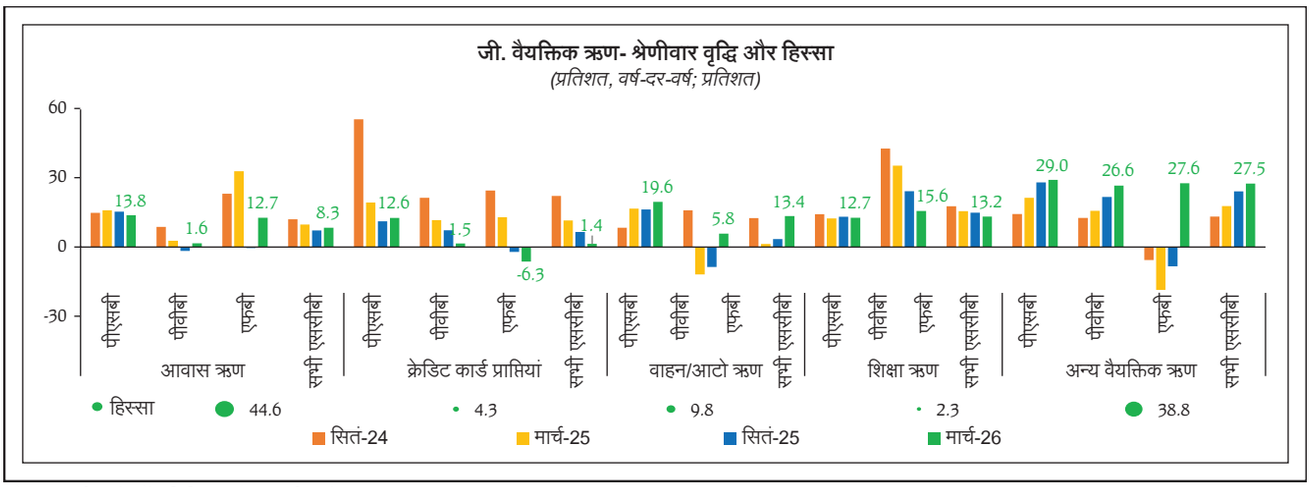
चार्ट 2.1: एससीबी की जमा और ऋण प्रोफाइल *(जारी)*



चार्ट 2.1: एससीबी की जमा और ऋण प्रोफाइल *(जारी)*



चार्ट 2.1: एससीबी की जमा और ऋण प्रोफाइल *(समाप्त)*



स्रोत: आरबीआई सर्वे प्रतिक्रिया और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

पता चलता है कि वैयक्तिक ऋण और सेवा ऋण में वृद्धि जारी रही , ये एससीबी (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों) में कुल ऋण वृद्धि के मुख्य कारक रहे हैं (चार्ट 2.1 एफ)। व्यक्तिगत ऋण खंड में, सभी बैंक ग्रुप्स ने 'अन्य व्यक्तिगत ऋण' श्रेणी में ज़बरदस्त बढ़ोतरी दर्ज करना जारी रखा (चार्ट 2.1 जी)।

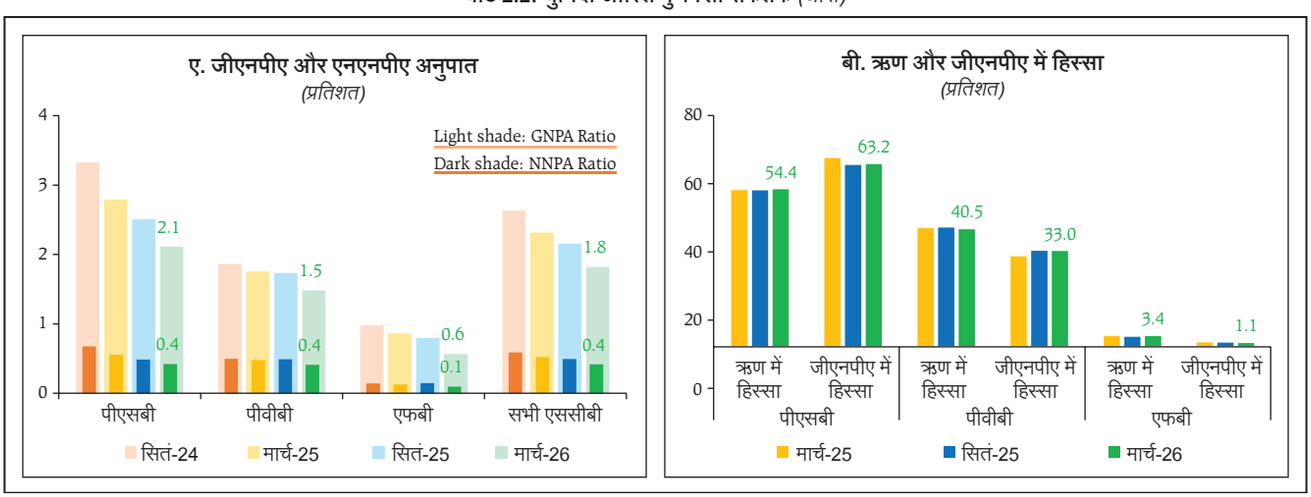
II.1.2 आस्ति गुणवत्ता

2.6 मार्च 2026 में आगे एससीबी की आस्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार दर्ज किया गया और उनका जीएनपीए अनुपात कई दशकों के सबसे निचले स्तर 1.8 प्रतिशत पर आ गया। । सभी बैंक समूहों में आस्ति गुणवत्ता में सुधार व्यापक स्तर पर देखा गया (चार्ट 2.2 ए और बी)।

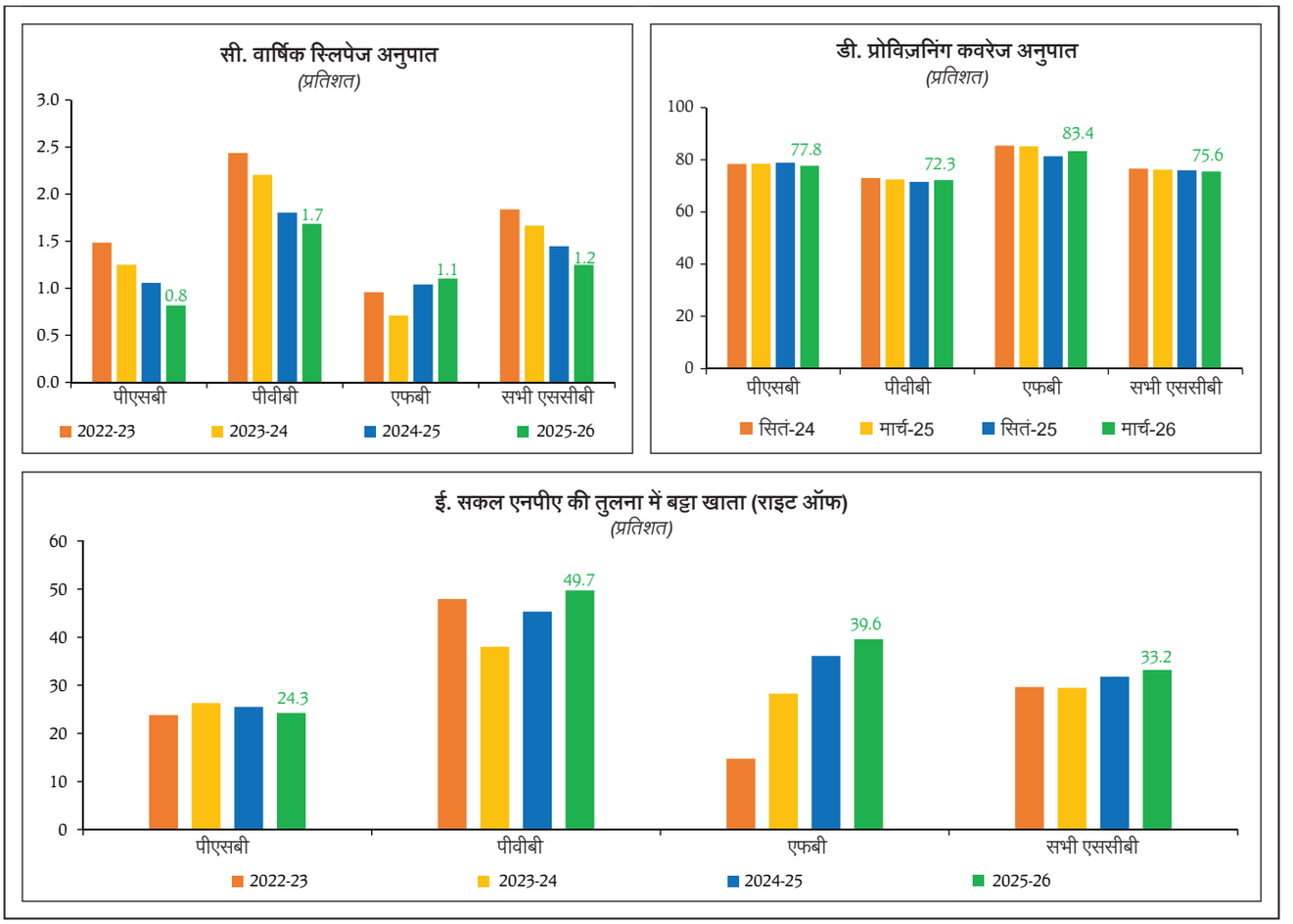
2.7 पिछले चार वित्तीय वर्षों में वार्षिक स्लिपेज अनुपात धीरे-धीरे कम होकर 2025-26 में 1.2 प्रतिशत हो गया। इसकी मुख्य वजह पीएसबी और पीवीबी में कमजोर आस्तियों में की नई बढ़ोतरी में कमी होना था (चार्ट 2.2 सी)।

2.8 एससीबी का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) मोटे तौर पर 75.6 प्रतिशत पर स्थिर रहा, जो कि बैलेंस

चार्ट 2.2: चुनिंदा आस्ति गुणवत्ता संकेतक *(जारी)*



चार्ट 2.2: चुनिंदा आस्ति गुणवत्ता संकेतक *(जारी)*



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी रिटर्न और स्टाफ गणना।

शीट प्रबंधन में लगातार सावधानी बरतने का संकेत देता है (चार्ट 2.2 डी) । हालाँकि, पीवीबी और एफबी के मामले में खासकर, 2025-26 के दौरान सकल अनर्जक आस्तियां (GNPA) के मुकाबले राइट-ऑफ का स्तर ऊँचा बना रहा, (चार्ट 2.2 ई) ।

II.1.3 क्षेत्रवार आस्ति गुणवत्ता

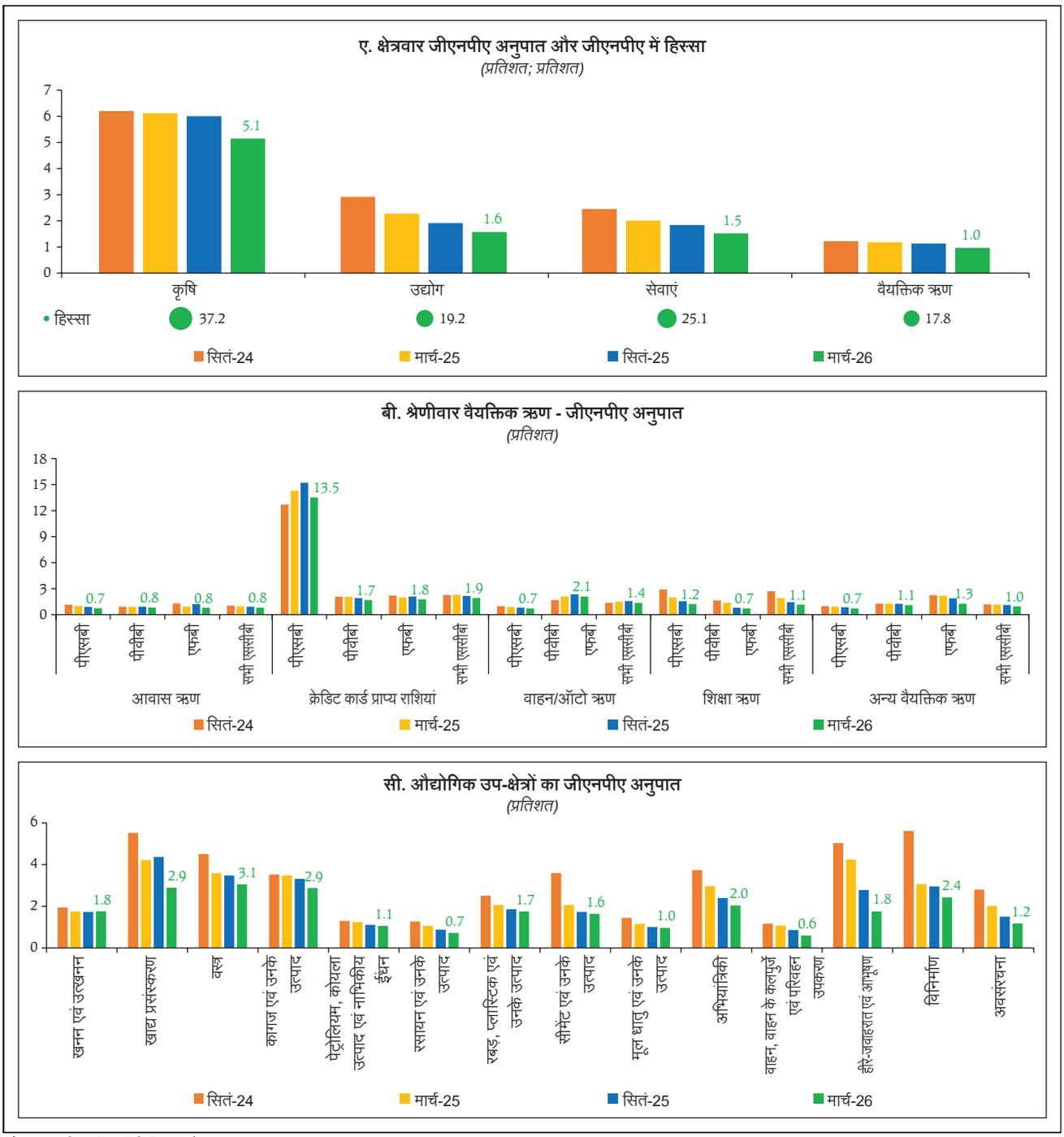
2.9 सभी व्यापक आर्थिक क्षेत्रों में ऋण गुणवत्ता में सुधार हुआ। सुधार के बावजूद, कृषि क्षेत्र में जीएनपीए अनुपात सबसे ज़्यादा 5.1 प्रतिशत रहा और मार्च 2026 में एससीबी के कुल जीएनपीए में इसकी हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा 37.2 प्रतिशत थी (चार्ट 2.3 ए)। औद्योगिक क्षेत्र के उप क्षेत्रों और वैयक्तिक ऋण श्रेणी के भीतर, सभी खंड़ों में आस्ति गुणवत्ता में आम तौर पर सुधार हुआ (चार्ट 2.3 बी और सी)।

II.1.4 बड़े उधारकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता[4]

2.10 मार्च 2026 की समाप्ति के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के सकल अग्रिमों में बड़े उधारकर्ताओं की

[4] एक बड़े उधारकर्ता को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका कुल निधि-आधारित और गैर-निधि -आधारित जोखिम ₹5 करोड़ और उससे अधिक है। यह विश्लेषण एससीबी के वैश्विक परिचालन पर आधारित है।

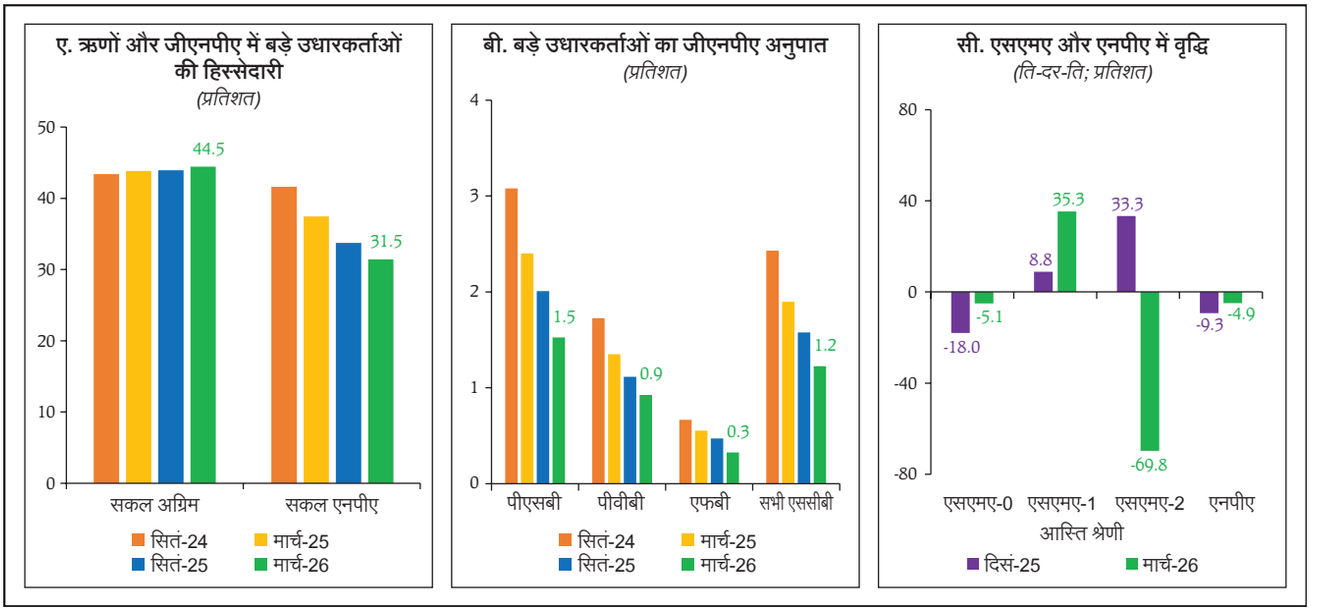
चार्ट 2.3: क्षेत्रवार आस्ति गुणवत्ता संकेतक



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी रिटर्न और स्टाफ गणना।

हिस्सेदारी 44.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, हालांकि कुल जीएनपीए में उनके हिस्सेदारी में गिरावट आई (चार्ट 2.4 ए) । बैंक समूहों में बड़े उधारकर्ताओं की आस्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है, और कुल जीएनपीए अनुपात सितंबर 2024 के अंत के 2.4 प्रतिशत से घटकर मार्च 2026 के अंत में 1.2 प्रतिशत हो गया है (चार्ट 2.4 बी)। मार्च 2026

चार्ट 2.4: बड़े उधारकर्ताओं के लिए चुनिंदा आस्ति गुणवत्ता संकेतक



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ गणन।

में SMA-0 और SMA-2[5] ऋण में संकुचन हुआ, जबकि मार्च 2026 में SMA-1 ऋण की मात्रा में बढ़ोतरी हुई (चार्ट 2.4 सी)।

II.1.5 आय और लाभप्रदता

2.11 जैसे-जैसे 2025-26 के दौरान बैंकिंग प्रणाली में मौद्रिक नीति में ढील का असर धीरे-धीरे प्रसारित होता गया, अलग-अलग बैंक समूह ने निधि की लागत और आस्ति पर मिलने वाले प्रतिफल (यील्ड) काफी हद तक एक साथ कम किए, इससे इस अवधि में नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIMs) में कोई खास बदलाव नहीं आया (चार्ट 2.5 ए, बी और सी)। इसके बावजूद, ज़्यादा ऋण मात्रा के कारण, मार्च 2026 में एससीबी की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) में वार्षिक आधार पर 4.0 प्रतिशत का मामूली सुधार दर्ज किया गया (चार्ट 2.5 डी)।

2.12 हालांकि अन्य परिचालन आय में बढ़ोतरी, 14.5 प्रतिशत पर मज़बूत बनी रही, लेकिन मार्च 2026 को खत्म होने वाली तिमाही में इसकी रफ़्तार कुछ धीमी पड़ गई, जिससे ईबीपीटी की बढ़ोतरी में कमी आई (चार्ट 2.5 डी)। लगातार ऋण विस्तार, स्थिर ब्याज मार्जिन और अन्य परिचालन आय में मज़बूत बढ़ोतरी की वजह से, एससीबी का टैक्स के बाद का लाभ (पीएटी) 2025-26 में बढ़कर ₹4,05,268 करोड़ हो गया, जो एक वर्ष पहले ₹3,78,163 करोड़ था (चार्ट 2.5 ई)।

2.13 लाभप्रदता संकेतक, अर्थात आरओई और आरओए , प्रणाली स्तर पर व्यापक रूप में स्थिर रहे। हालाँकि, बैंक समूह में समग्र स्थिति के बावजूद कुछ अंतर देखा गया। 2025-26 की दूसरी छमाही के दौरान पीएसबी के दोनों अनुपात में मामूली सुधार हुआ, जबकि एफबी के लाभप्रदता अनुपात में कुछ कमी देखी गई (चार्ट 2.5 एफ और जी) ।

[5] विशेष उल्लेख खाता (SMA) को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :

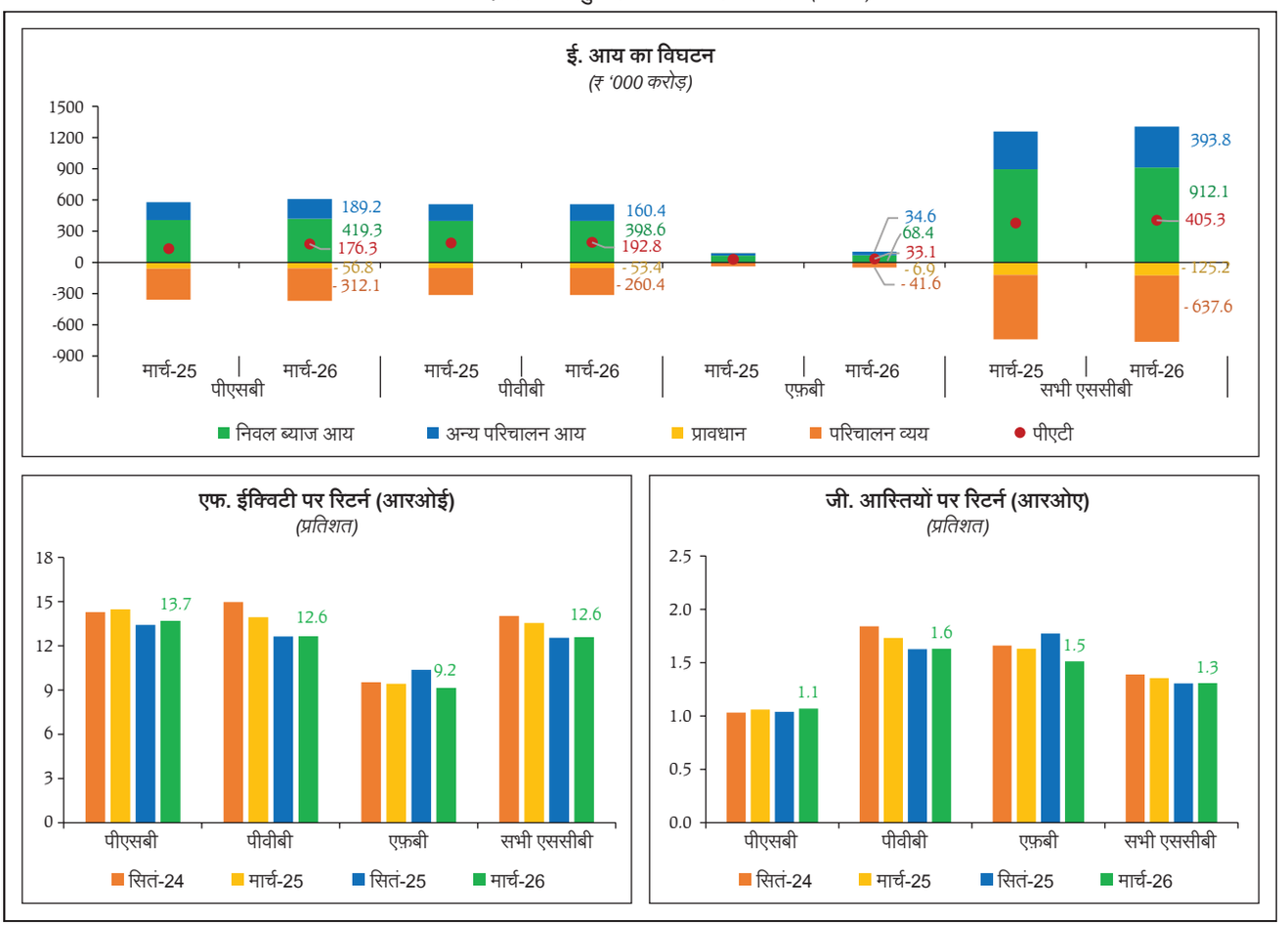
ए) कैश क्रेडिट/ओवरड्राफ्ट जैसी परिक्रामी सुविधाओं की प्रकृति के ऋणों के लिए : यदि बकाया राशि स्वीकृत सीमा या आहरण शक्ति, जो भी कम हो, से 31-60 दिनों की अवधि के लिए लगातार अधिक रहती है - एसएमए-1; 61-90 दिन - एसएमए -2 ।

बी) परिक्रामी सुविधाओं के अलावा अन्य ऋणों के लिए : यदि मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से अतिदेय रहती है, 30 दिनों तक बकाया रहती है – एसएमए-0; 31-60 दिन – एसएमए-1; 61-90 दिन – एसएमए-2 ।

चार्ट 2.5: एससीबी के चुनिंदा कार्यनिष्पादन संकेतक *(जारी)*



चार्ट 2.5: एससीबी के चुनिंदा कार्यनिष्पादन संकेतक *(समाप्ति)*



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ गणना।

II.I.6 पूंजी पर्याप्तता

2.14 एससीबी ने अपने कैपिटल बफ़र को फिर से भरा और मार्च 2026 के अंत तक कैपिटल टू रिस्क-वेटेड एसेट्स रेश्यो (CRAR) और कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1) रेश्यो में कई दशकों का सबसे ऊंचा स्तर दर्ज किया, जो क्रमशः 17.7 प्रतिशत और 15.3 प्रतिशत था (चार्ट 2.6 ए)। मार्च 2026 में पीएसबी और पीवीबी, दोनों ने ज़्यादा सीआरएआर रिपोर्ट किया। मार्च 2026 में सीआरएआर में हुई बढ़ोतरी की वजह इस अवधि में रिस्क-वेटेड एसेट्स (आरडब्ल्यूए) में हुई वृद्धि की तुलना में पूंजी में अधिक वृद्धि होना है (चार्ट 2.6 बी)।

2.15 पूंजी की बदलती संरचना से पता चलता है कि कुल पूंजी में बढ़ोतरी लगभग पूरी तरह से सीईटी1 पूंजी (जो कुल पूंजी का 86 प्रतिशत है) के कारण हुई है, जिससे उच्च-गुणवत्ता वाली पूंजी का बढ़ता स्टॉक बैंकिंग प्रणाली में दिखता है (चार्ट 2.6 सी)। ऋण के कुल विस्तार के बीच, क्रेडिट रिस्क-वेटेड एसेट्स (जो कुल आरडब्ल्यूए का लगभग 86 प्रतिशत हैं) में बढ़ोतरी, 2025-26 के दौरान तीन वर्ष में पहली बार कुल क्रेडिट ग्रोथ से कम रही (चार्ट 2.6 डी)। यह कम जोखिम-भार वाले क्रेडिट एक्सपोज़र की ओर एक व्यापक बदलाव और नई ऋण-वितरण (इंक्रीमेंटल लेंडिंग) के जोखिम प्रोफ़ाइल में सुधार का संकेत देता है।

2.16 मार्च 2026 के अंत तक कुल टियर I लेवरेज अनुपात मामूली रूप से बढ़कर 8.2 प्रतिशत हो गया (चार्ट 2.6 ई)।

चार्ट 2.6: पूंजी पर्याप्तता



टिप्पणी: SCBs in all panels of chart 2.6 exclude SFBs.
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी और स्टाफ गणना।

II.I.7 चलनिधि

2.17 कुल मिलाकर, एससीबी का चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)[6] और नेट स्टेबल फंडिंग रेश्यो (एनएसएफआर)[7] क्रमशः 124.2 प्रतिशत और 122.1 प्रतिशत हो गया, हालांकि सभी बैंक समूहों ने अपने चलनिधि बफ़र को संबंधित नियामक न्यूनतम स्तरों से काफी ऊपर बनाए रखा (चार्ट 2.7 ए और बी)।

II.1.8 लचीलापन – मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट

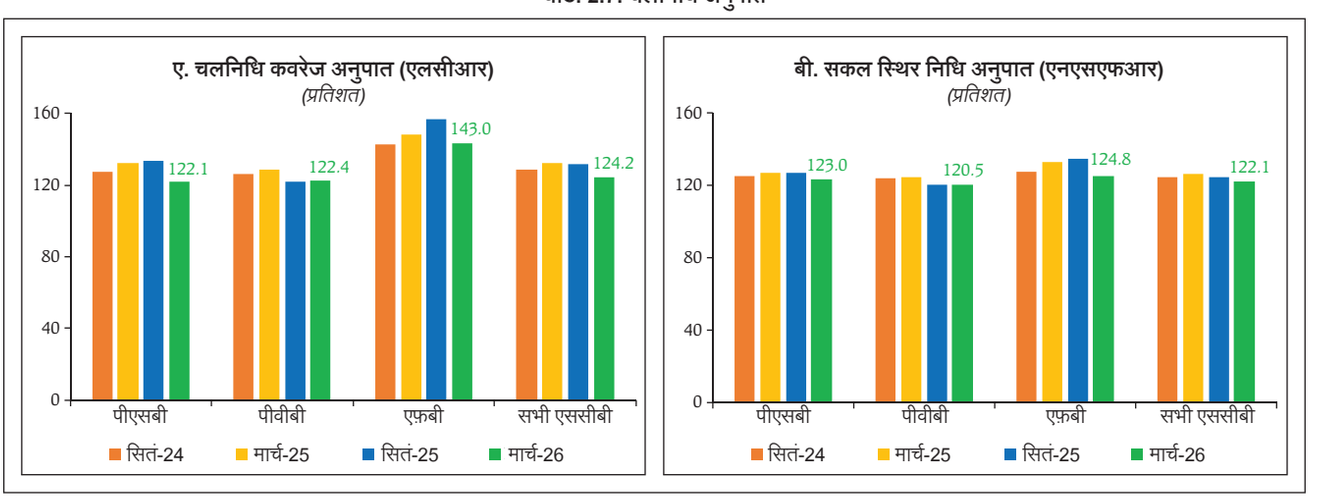
2.18 मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट, विपरीत मैक्रो-इकोनॉमिक वातावरण से निकलने वाले झटकों को झेलने की एससीबी (अनुसूचित वाणिज्य बैंक) की क्षमता का आकलन करता है। यह दो वर्ष की अवधि के लिए एक आधारभूत और दो प्रतिकूल मैक्रो परिदृश्यों के तहत बैंकों के पूंजी अनुपात का आकलन करने का प्रयास करते हैं। जहां आधारभूत परिदृश्य व्यापक आर्थिक चर के पूर्वानुमानित मूल्यों से लिया गया था, वहीं दो प्रतिकूल परिदृश्य काल्पनिक रूप से कड़े दबाव परिदृश्यों[8] (चार्ट 2.8)।

(i) प्रतिकूल स्थिति 1: इस परिदृश्य में माना गया है कि भू-राजनीतिक जोखिम और बढ़ेंगे, ऊर्जा की कीमतें और एक्सचेंज रेट पर दबाव भी बढ़ेगा जिससे घरेलू महंगाई बढ़ेगी और विकास दर धीमी होगी, जिसके परिणामस्वरूप 2027-28 में स्थिति में धीरे-धीरे सुधार होगा।

(ii) प्रतिकूल स्थिति 2: इस परिदृश्य में माना गया है कि 2027-28 के लंबे समय तक चलने वाले और ज़्यादा बड़े पैमाने पर भू-राजनीतिक टकराव होंगे, जिससे दोनों वर्षों में घरेलू महंगाई और विकास दर पर बुरा असर पड़ेगा।

2.19 मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट के परिणामों से पता चलता है कि एससीबी मैक्रो-इकोनॉमिक झटकों का सामना करने में सक्षम हैं। बेसलाइन परिदृश्य के तहत, चयनित 46 बैंकों का कुल CET1 कैपिटल रेश्यो मार्च 2026 में 15.2 प्रतिशत से घटकर मार्च 2028 तक 13.9 प्रतिशत होने का अनुमान है। प्रतिकूल स्थिति 1 और 2 में क्रमश: यह घटकर 11.6 प्रतिशत और 11.4 प्रतिशत हो सकता है। इसके

चार्ट: 2.7: चलनिधि अनुपात



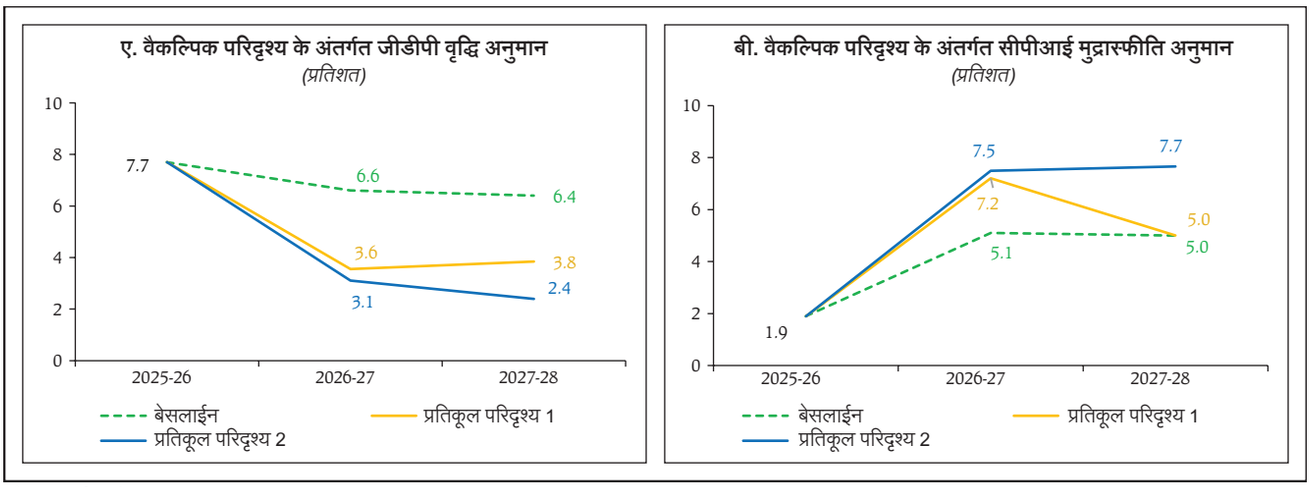
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणी और आरबीआई स्टाफ गणना।

[6] लनिधि कवरेज अनुपात को हाई-क्वालिटी लिक्विड एसेट्स (HQLA) के स्टॉक और अगले 30 कैलेंडर दिनों में कुल नेट कैश आउटफ़्लो के अनुपात के तौर पर परिभाषित किया जाता है।

[7] नेट स्टेबल फंडिंग रेश्यो को उपलब्ध स्टेबल फंडिंग और ज़रूरी स्टेबल फंडिंग के अनुपात के तौर पर परिभाषित किया जाता है।

[8] प्रतिकूल परिदृश्य को 'वेक्टर ऑटोरेग्रेशन विद एक्सोजेनस वेरिएबल्स' (VARX) मॉडल का उपयोग करके सिमुलेशन करने से प्राप्त किया जाता है।

चार्ट 2.8: समष्टि परिदृश्य अनुमान



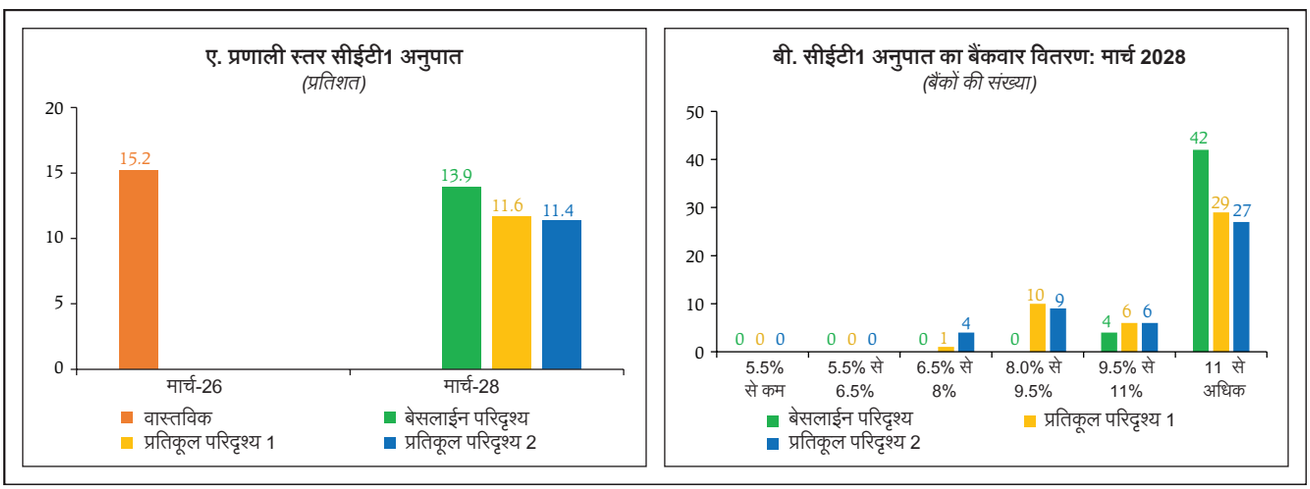
स्रोत: आरबीआई स्टाफ गणना।

बावजूद, सभी बैंक हर स्थिति में 5.5 प्रतिशत के न्यूनतम CET1 पूंजी अनुपात की आवश्यकता को पूरा करते रहेंगे (चार्ट 2.9)।

2.20 बेसलाइन परिदृश्य के तहत, 46 प्रमुख एससीबी का कुल सीआरएआर मार्च 2026 में 17.5 प्रतिशत से घटकर मार्च 2028 तक 15.6 प्रतिशत हो सकता है। प्रतिकूल स्थिति 1 और 2 के तहत, यह क्रमशः 13.3 प्रतिशत और 13.0 प्रतिशत तक गिर सकता है (चार्ट 2.10 ए)। बैंक के स्तर पर, बेसलाइन स्थिति में कोई भी बैंक 9 प्रतिशत की न्यूनतम सीआरएआर आवश्यकता का उल्लंघन नहीं करेगा, जबकि विपरीत स्थिति 1 और 2 में क्रमशः एक और दो बैंक इस आवश्यकता से नीचे जा सकते हैं (चार्ट 2.10 बी)।

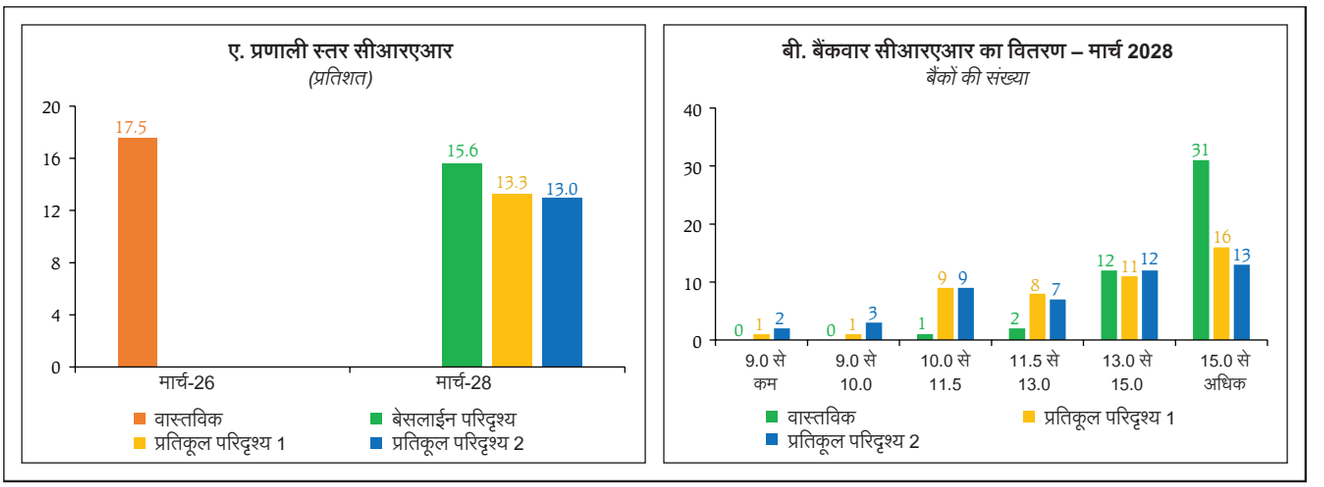
2.21 चुनिंदा 46 एससीबी का कुल जीएनपीए अनुपात मार्च 2026 में 1.8 प्रतिशत से बढ़कर बेसलाइन परिदृश्य के तहत मार्च 2028 में 1.9 प्रतिशत हो सकता है। प्रतिकूल स्थिति 1 और 2 के तहत यह क्रमशः 3.8 प्रतिशत और 4.1 प्रतिशत तक बढ़ सकता है (चार्ट 2.11)।

चार्ट 2.9: सीईटी1 अनुपात का प्रोजेक्शन



टिप्पणी: 46 चुनिन्दा बैंकों के सिस्टम के लिए।
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी रिटर्न और स्टाफ गणना।

चार्ट 2.10: सीआरएआर प्रोजेक्शन

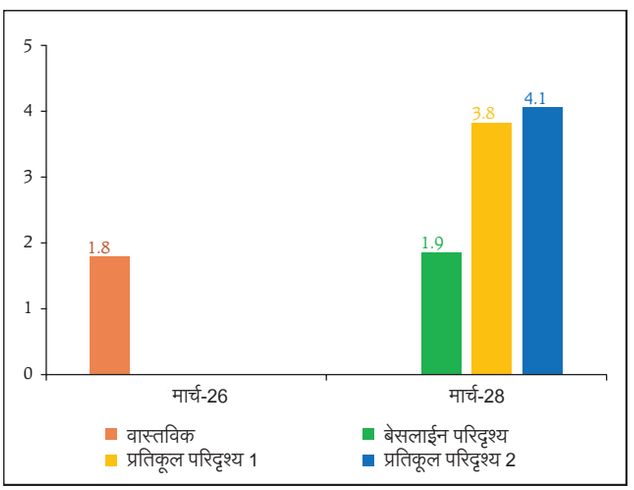


टिप्पणी: 46 चुनिन्दा बैंकों के सिस्टम के लिए।
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी रिटर्न और स्टाफ गणना।

II.1.9 संवेदनशीलता विश्लेषण[9]

2.22 संवेदनशीलता विश्लेषण में[10], जीएनपीए अनुपात, ब्याज दर इत्यादि जैसे अलग-अलग कारकों पर एक समय में एक, आघात (shocks) दिए जाते हैं। यह उप-खंड मार्च 2026 के आखिर के डेटा के आधार पर, विभिन्न दबाव परिदृश्यों के तहत क्रेडिट, ब्याज दर,चलनिधि जोखिम इत्यादि के लिए एससीबी की कमजोरियों का आकलन करने के लिए टॉप-डाउन संवेदनशीलता विश्लेषण के परिणाम प्रस्तुत करता है।

चार्ट 2.11 : जीएनपीए अनुपात का प्रोजेक्शन
प्रतिशत



टिप्पणी: 46 चुनिन्दा बैंकों के सिस्टम के लिए।
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी रिटर्न और स्टाफ गणना।

ए. ऋण जोखिम

2.23 ऋण जोखिम के मामले में एससीबी की क्षमता का आकलन दो अनुमानित दबाव स्थितियों के तहत किया गया - (i) मार्च 2026 तक कुल जीएनपीए अनुपात के स्तर में एक स्टैंडर्ड डेविएशन (एसडी[11] [शॉक 1] की वृद्धि और (ii) दो एसडी [शॉक 2] की वृद्धि।

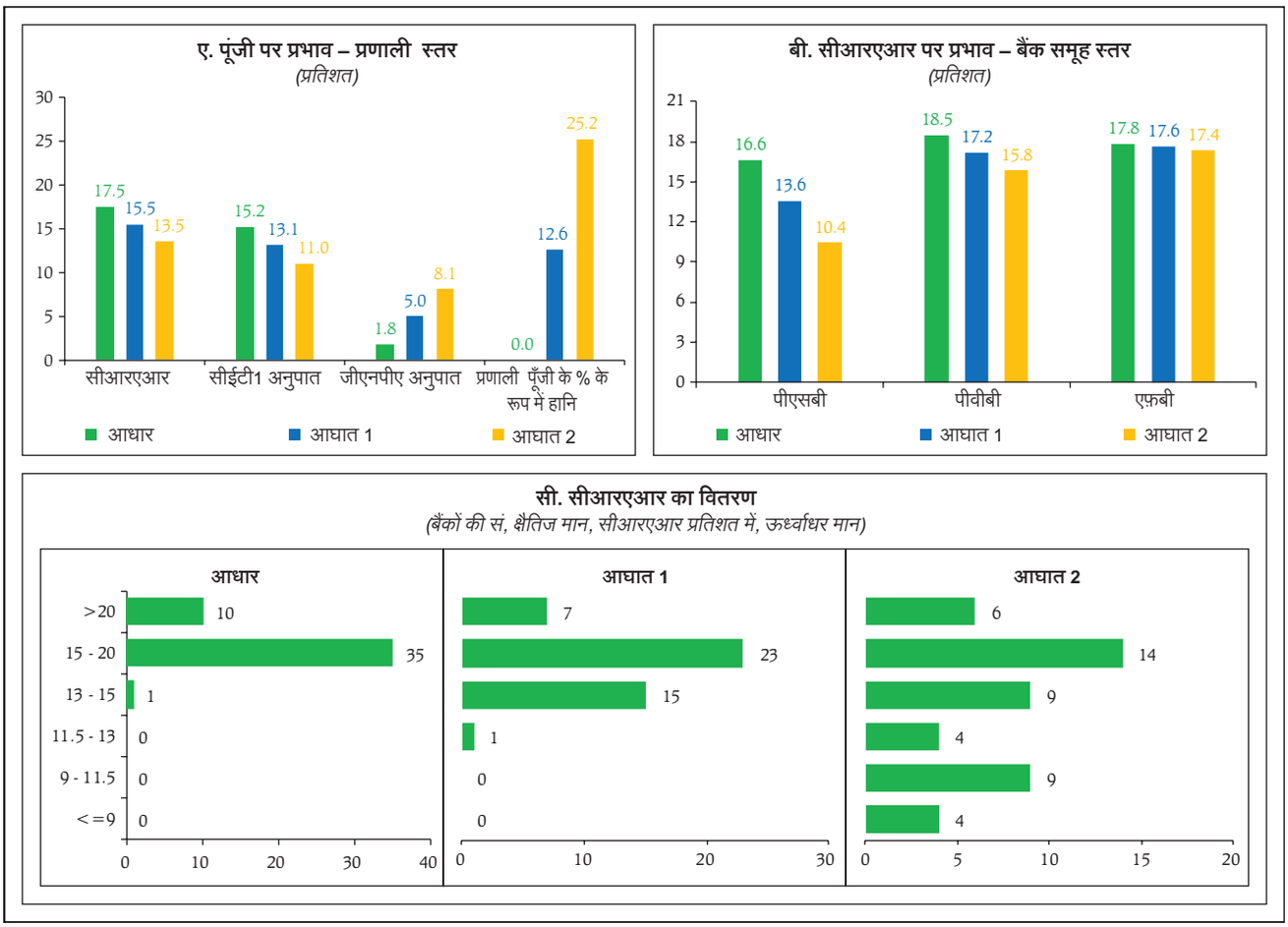
2.24 ज़्यादा गंभीर आघात वाले परिदृश्य में, अर्थात 'शॉक 2' में, जहाँ चुनिंदा 46 एससीबी का कुल जीएनपीए अनुपात बढ़कर 8.1 प्रतिशत होने का अनुमान है, सीआरएआर और सीईटी1 पूंजी अनुपात में क्रमशः 400 बीपीएस और 420 बीपीएस की कमी आएगी (चार्ट 2.12 ए)। हालांकि, दोनों पूंजी अनुपात संबंधित नियामक न्यूनतम स्तरों से काफी ऊपर बने रहेंगे। इसके परिणामस्वरूप प्रणाली स्तर पर पूंजी में 25.2 प्रतिशत की कमी आ सकती है। रिवर्स दबाव परीक्षण के परिणामों से पता चलता है कि प्रणाली-स्तर सीआरएआर और सीईटी1 पूंजी अनुपात को उनके नियामक न्यूनतम स्तर से नीचे लाने के लिए, सकल जीएनपीए अनुपात में क्रमशः 4.4 एसडी और 5.9 एसडी के आघातों की ज़रूरत होगी।

[9] विस्तृत कार्यप्रणाली के लिए अनुलग्नक-1 देखें।

[10] एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण नमूने के तौर पर बैंकिंग क्षेत्र की कुल आस्तियों के 99 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार 46 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए किया जाता है। विभिन्न काल्पनिक परिदृश्यों के तहत डिजाइन किए गए झटके परम है, लेकिन प्रश्नसनीय हैं।

[11] जीएनपीए अनुपात के एसडी की गणना पिछले 10 वर्षों के त्रैमासिक डेटा का उपयोग करके की जाती है।

चार्ट 2.12: ऋण जोखिम – आघात और परिणाम



टिप्पणी: चुनिंदा 46 एससीबी की प्रणाली के लिए। आघात 1 और आघात 2 के तहत जीएनपीए अनुपात पर क्रमशः 1 एसडी और 2 एसडी के आघात लागू हैं।
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी रिटर्न; औरआरबीआई स्टाफ अनुमान।

2.25 बैंक समूह स्तर पर, दबाव परीक्षणों से संकेत मिला कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की पूंजी में निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) और विदेशी बैंकों (एफबी) की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक क्षरण हुआ (चार्ट 2.12 बी) । बैंक स्तर पर, एससीबी की कुल आस्तियों में 12 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले चार बैंक आघात 2 के तहत सीआरएआर के विनियामकीय न्यूनतम स्तर का उल्लंघन करेंगे (चार्ट 2.12 सी)।

बी. ऋण संकेंद्रण जोखिम

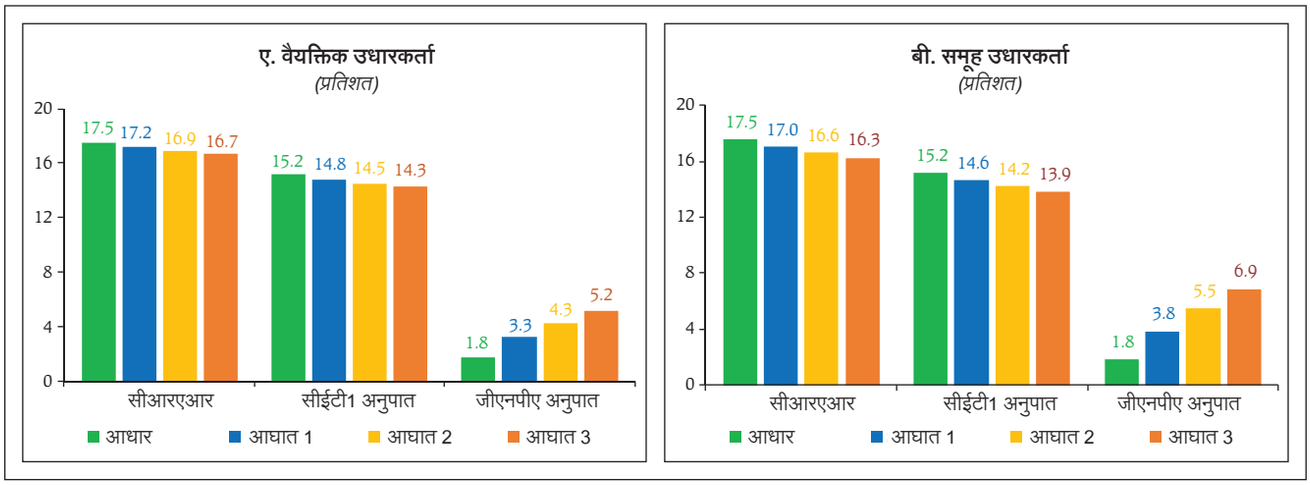
2.26 बैंकों के ऋण संकेंद्रण पर किए गए दबाव परीक्षणों से पता चला कि संबंधित बैंकों के शीर्ष तीन वैयक्तिक उधारकर्ताओं के चूक करने की चरम स्थिति में, प्रणाली स्तर पर जीएनपीए अनुपात 340 आधार अंक बढ़ जाएगा, और परिणामस्वरूप सीआरएआर और सीईटी1 अनुपात क्रमशः 80 और 90 आधार अंक घट जाएंगे (चार्ट 2.13 ए)। इसी प्रकार, यदि शीर्ष तीन समूह उधारकर्ता चूक करते हैं, तो जीएनपीए अनुपात 510 आधार अंक बढ़ जाएगा, और सीआरएआर एवं सीईटी1 अनुपात क्रमशः 120 और 130 आधार अंक घट जाएंगे (चार्ट 2.13 बी)। हालांकि, ऐसी चरम स्थितियों में भी, सभी बैंक अपने पूंजी अनुपात को संबंधित न्यूनतम विनियामक स्तर से ऊपर बनाए रखने में सक्षम होंगे।

2.27 शीर्ष उधारकर्ताओं के प्रणाली-व्यापी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, शीर्ष सौ उधारकर्ताओं का संकेंद्रण, जिसे सीआर-100 अनुपात[12] द्वारा मापा जाता है, मार्च 2026 में और बढ़

[12] सीआर -100 अनुपात, एससीबी के कुल बकाया ऋण में शीर्ष 100 उधारकर्ताओं के बकाया ऋण का अनुपात है।

चार्ट 2.13: ऋण संकेंद्रण जोखिम- उधारकर्ता एक्स्पोज़र

(प्रतिशत में प्रणालीगत अनुपात)



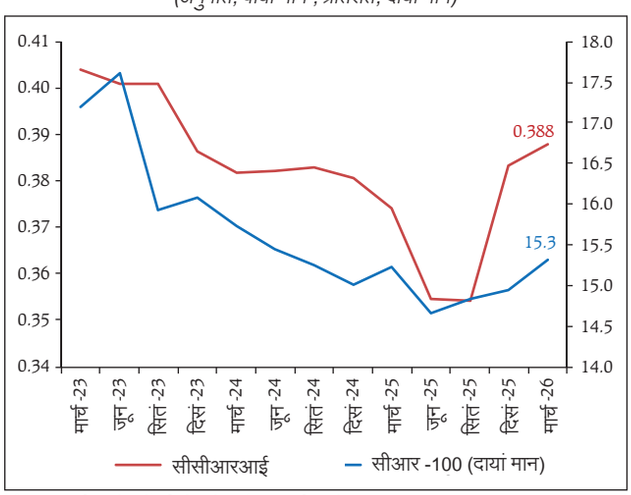
टिप्पणी: चुनिंदा46 एससीबी के प्रणाली के लिए। आघात 1, 2 और 3 के तहत क्रमशः उच्च 1, 2 और 3 वैयक्तिक उधारकर्ताओं/समूह उधारकर्ताओं द्वारा भुगतान की प्रतिबद्धताओं को पूरा न कर पाने (चूक) की स्थिति मानी गई है।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी रिटर्न; और आरबीआई स्टाफ़ अनुमान।

गया, जिससे सितंबर 2025 तक देखे गए घटते रुझान की दिशा बदल गई। पिछली दो तिमाहियों में ऋण संकेंद्रण जोखिम सूचकांक (सीसीआरआई)[13] में भी वृद्धि हुई, जो शीर्ष 100 उधारकर्ताओं के भीतर संकेंद्रण जोखिम में वृद्धि को दर्शाता है (चार्ट 2.14)।

चार्ट 2.14: उच्च 100 उधारकर्ताओं से जुड़ा ऋण संकेंद्रण जोखिम

(अनुपात, बायां मान ; प्रतिशत, दायां मान)



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी रिटर्न ; और आरबीआई स्टाफ़ अनुमान।

सी. क्षेत्रीय ऋण जोखिम

2.28 एससीबी के क्षेत्रीय ऋण जोखिम का आकलन दो काल्पनिक दबाव परिदृश्यों के तहत किया गया — (i) मार्च 2026 तक संबंधित क्षेत्रों के जीएनपीए अनुपात में एक एसडी[14] [आघात 1] और (ii) दो एसडी [आघात 2] की वृद्धि। दबाव परीक्षणों के परिणाम एससीबी की समग्र पूंजी पर ऐसे आघातों के केवल मामूली प्रभाव को दर्शाते हैं, जो क्षेत्र-विशिष्ट ऋण जोखिम के प्रति बैंकिंग प्रणाली की लचीलेपन को रेखांकित करता है (सारणी 2.2)।

घ. ब्याज दर जोखिम[15 16]

2.29 आकलन के तहत 46 एससीबी के नमूने के लिए, उचित मूल्य के अधीन निवेशों का बाजार मूल्य मार्च 2026 में बढ़कर ₹24.1 लाख करोड़ के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो सितंबर 2025 में ₹22.8 लाख करोड़ था (चार्ट 2.15)। इसी अवधि में, समग्र उचित-मूल्यांकित पोर्टफोलियो में पीएसबी और पीवीबी की हिस्सेदारी घट गई, जबकि एफबी की हिस्सेदारी बढ़ गई।

[13] सीसीआरआई एक इंडेक्स (0 से 1 के बीच) है जो सभी एससीबी की कुल पूंजी पर उच्च 100 उधारकर्ताओं के असर को मापता है।

[14] जीएनपीए अनुपात का एसडी पिछले 10 वर्षों के तिमाही डेटा का इस्तेमाल करके निकाला जाता है।

[15] पिछले समय के डेटा और मौजूदा डेटा में एक जैसापन और तुलना करने में दिक्कत हो सकती है क्योंकि पुराने डेटा को नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से दोबारा तैयार नहीं किया गया है।

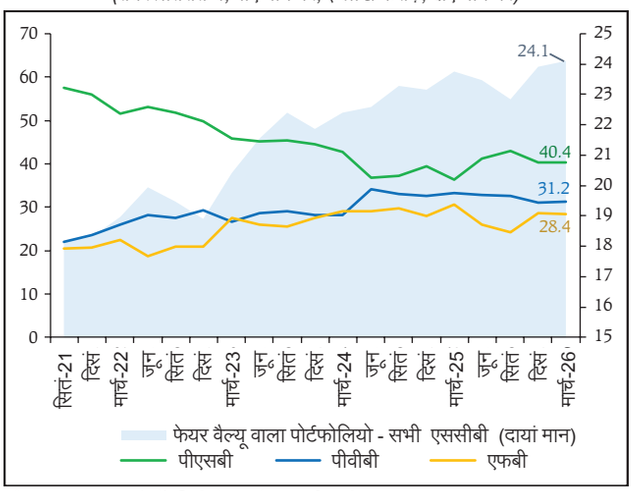
[16] इस हिस्से में एनालिसिस सिर्फ़ एससीबी के घरेलू कामकाज से भारत में किए गए निवेश तक ही सीमित है। इसमें सिर्फ़ एचटीएम, एएफ़एस और एफ़वीटीपीएल (एचएफ़टी सहित) पोर्टफोलियो के लिए ब्याज दर से जुड़े लिखत और "सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश" के लिए ब्याज और बिना ब्याज वाले निवेश, दोनों को ही शामिल किया गया है।

सारणी 2.2: संवेदनशीलता विश्लेषण – उद्योग उप क्षेत्र स्तर
(आधार अंक , उच्च 10 सबसे संवेदनशील उप क्षेत्र के लिए घटते क्रम में)

उद्योग	सीआरएआर में गिरावट (आधार अंक)	
	1 एसडी आघात	2 एसडी आघात
आधार धातु और धातु उत्पाद	9	18
अवसंरचना - ऊर्जा	6	12
सभी इंजीनियरिंग	3	7
अवसंरचना - ट्रांसपोर्ट	3	6
टेक्सटाइल्स	2	4
निर्माण	1	3
गाड़ियाँ, गाड़ियों के पार्ट्स और ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट	1	3
फूड प्रोसेसिंग	1	2
रसायन	1	2
रत्न और आभूषण	1	2

टिप्पणी: चुनिंदा 46 एससीबी (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों) के प्रणाली के लिए।
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी रिटर्न; औरआरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट 2.15: एएफ़एस और एफ़वीटीपीएल (एचएफ़टी सहित) पोर्टफोलियो और बैंक-समूहों का हिस्सा।
(शेयर प्रतिशत में, बाएं मान पर; ₹ लाख करोड़, दाएं मान पर)



स्रोत: अलग-अलग बैंकों की रिपोर्ट; और आरबीआई स्टाफ़ अनुमा।

2.30 एससीबी के एएफएस पोर्टफोलियो की संवेदनशीलता (पीवी01[17]) मार्च 2026 में समग्र स्तर पर मामूली रूप से बढ़ी, जो मुख्यतः एफबी के पीवी01 में वृद्धि से प्रेरित थी (सारणी 2.3)। जबकि पीएसबी और पीवीबी दोनों ने अपने एएफएस पोर्टफोलियो की संशोधित अवधि (मॉडिफाइड ड्यूरेशन) को घटाया है, समग्र एएफएस पोर्टफोलियो मूल्य में सितंबर 2025 की तुलना में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यद्यपि पीएसबी और पीवीबी दोनों ने अपने एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो के पीवी01 को घटाया है, एफबी द्वारा तीव्र वृद्धि के कारण मार्च 2026 में एससीबी के पीवी01 में वृद्धि हुई। पीएसबी और एफबी ने अपनी संशोधित परिपक्वता अवधि बढ़ाई है, जबकि पीवीबी ने इसे घटाया है। हालांकि, पीएसबी के लिए एफवीटीपीएल पोर्टफोलियो मूल्य में 13.0 प्रतिशत की समग्र गिरावट ने संशोधित अवधि में वृद्धि के बावजूद उनके पीवी 01 को घटाया है।

सारणी 2.3: एएफएस एवं एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो का पीवी01
(₹ करोड़)

	एएफएस पोर्टफोलियो		एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो	
	सित-25	मार्च -26	सित-25	मार्च -26
पीएसबी	246.4	248.0	85.7	84.7
पीवीबी	95.5	70.9	86.9	73.0
एफबी	18.9	44.1	232.2	314.1
सभी एससीबी	**360.8**	**363.0**	**404.8**	**471.9**

स्रोत: अलग-अलग बैंकों की रिपोर्ट; और आरबीआई स्टाफ़ अनुमान।

2.31 प्रतिफल वक्र में 250 आधार अंकों की समानांतर ऊपरी शिफ्ट के दबाव परिदृश्य में, उचित-मूल्यांकित पोर्टफोलियो और ब्याज दर व्युत्पन्न (डेरिवेटिव) पोर्टफोलियो पर प्रभाव से प्रणाली स्तर पर सीआरएआर और सीईटी1 अनुपात क्रमशः 99 और 100 आधार अंक घट जाएंगे (सारणी 2.4)। बैंक स्तर पर, दो विदेशी बैंकों का सीआरएआर 9 प्रतिशत के नियामक न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाएगा।

2.32 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही में सभी बैंक समूहों को प्रतिभूति व्यापार में हानि हुई। पीएसबी और पीवीबी के लिए, प्रतिभूति व्यापार से लाभ पिछली तीन तिमाहियों में लगातार घटता गया, और मार्च 2026 में यह नकारात्मक हो गया (सारणी 2.5)। दूसरी ओर, एफबी ने लगातार चार तिमाहियों तक कारोबार में हानि दर्ज की है।

2.33 एचटीएम पोर्टफोलियो में, पीएसबी और पीवीबी दोनों ने राज्य सरकार प्रतिभूतियों (एसजीएस) में अपनी हिस्सेदारी

[17] पीवी01, ब्याज दर में एक आधार अंक के बदलाव के प्रति पोर्टफोलियो के अंतिम वैल्यू की संवेदशीलता का माप है।

सारणी 2.4: ब्याज दर जोखिम – बैंक-ग्रुप्स पर दबाव परीक्षण का प्रभाव

(आघात : आईएनआर यील्ड कर्व में 250 आधार अंक का समानान्तर ऊपर की ओर बदलाव)

	पीएसबी		पीवीबी		एफ़बी		सभी एससीबी	
	एएफ़एस	एफ़वीटीपीएल (एचएफ़टी सहित)	एएफ़एस	एफ़वीटीपीएल (एचएफ़टी सहित)	एएफ़एस	एफ़वीटीपीएल (एचएफ़टी सहित)	एएफ़एस	एफ़वीटीपीएल (एचएफ़टी सहित)
संशोधित अवधि (वर्ष)	3.2	4.1	1.5	2.6	1.4	8.3	2.4	5.4
कुल निवेश में हिस्सा (प्रतिशत)	18.4	5.0	17.8	10.7	38.6	47.6	20.3	11.4
फेयर वैल्यू वाले पोर्टफोलियो (एएफ़एस + एफ़वीटीपीएल) का पीवी01	332.7		144.0		358.1		834.8	
ट्रेडिंग के लिए रखे गए ब्याज दर डेरिवेटिव्स का पीवी01	1.3		2.6		53.1		57.0	
हेज[18] के तौर पर रखे गए ब्याज दर डेरिवेटिव्स का पीवी01	0.0		39.6		10.5		50.2	
आईएनआर यील्ड कर्व में 250 बीपीएस के समानान्तर ऊपर की ओर बदलाव का प्रभाव								
सीआरएआर में कमी (बीपीएस)	85		28		588		99	
सीईटी1 में कमी (बीपीएस)	86		28		593		100	

टिप्पणी: कुल निवेश का हिस्सा एसोसिएट्स, सब्सिडियरीज और जेवी में निवेश को छोड़कर गणना किया गया है।

स्रोत: अलग-अलग बैंकों की जानकारी; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सारणी 2.5: अन्य परिचालन आय – प्रतिभूतियों के कारोबार पर लाभ/(हानि)

(₹ करोड़)

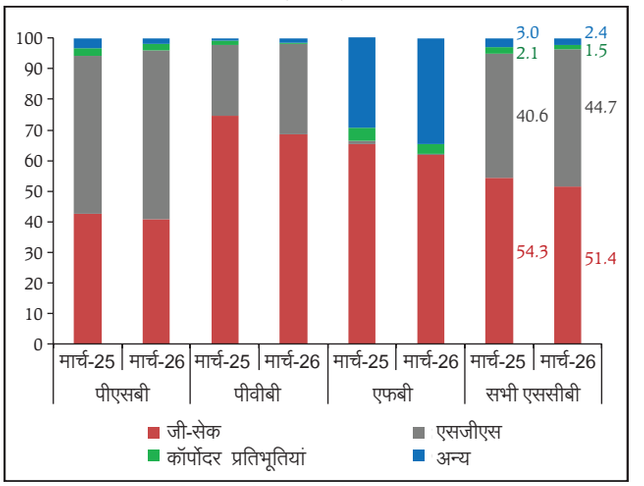
	ति4: 2024-25	ति1: 2025-26	ति2: 2025-26	ति3: 2025-26	ति4: 2025-26
पीएसबी	12,245 (16.1)	15,026 (20.3)	12,076 (16.4)	10,124 (13.1)	-158 (-0.2)
पीवीबी	2,761 (3.7)	15,320 (17.4)	3,493 (4.5)	2,460 (3.2)	-280 (-0.4)
एफबी	2,927 (22.7)	-340 (-2.0)	-2,586 (-16.8)	-1,413 (-11.6)	-9,597 (-63.2)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े अन्य परिचालन आय (ओओआई) को दर्शाते हैं - यानी निवल परिचालन आय के प्रतिशत के रूप में प्रतिभूति ट्रेडिंग से हुआ लाभ/(हानि)।

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी रिटर्न; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट 2.16: एचटीएम पोर्टफोलियो – संरचना

(प्रतिशत)



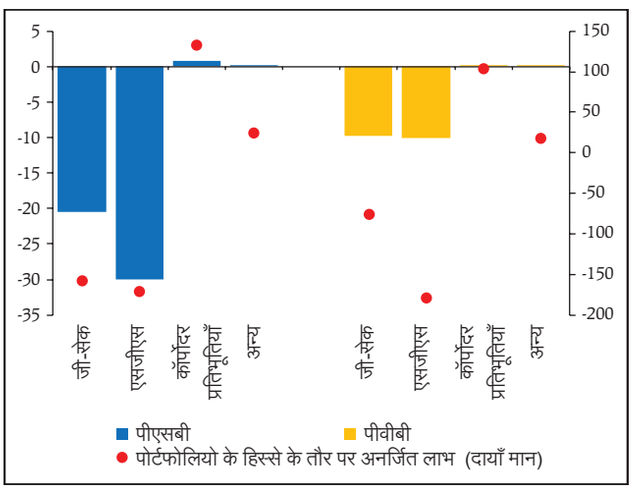
स्रोत: अलग-अलग बैंकों की जानकारी; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

बढ़ाना जारी रखा, जबकि केंद्र सरकार प्रतिभूतियों (जी-सेक) और अन्य एचटीएम-पात्र प्रतिभूतियों में अपनी हिस्सेदारी घटाई। एफबी ने अपने एचटीएम पोर्टफोलियो में अन्य प्रतिभूतियों की हिस्सेदारी बढ़ाना जारी रखा (चार्ट 2.16)। मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान, एचटीएम बही में जी-सेक और एसजीएस दोनों हिस्सेदारियों में अवास्तविक हानि देखी गई (चार्ट 2.17)।

2.34 यदि प्रतिफल वक्र में 250 आधार अंकों की समानांतर ऊपरी शिफ्ट का आघात लगाया जाए, तो बैंकों के एचटीएम

चार्ट 2.17: एचटीएम पोर्टफोलियो – 31 मार्च, 2026 तक अनर्जित लाभ/ हानि

(राशि ₹ '000 करोड़ में, बायाँ मान ; आधार अंक , दायाँ मान)



स्रोत: अलग-अलग बैंकों की जानकारी; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[18] सकारात्मक वैल्यू का मतलब है प्रभावी ब्याज दर एक्सपोज़र में कमी।

पोर्टफोलियो पर एमटीएम प्रभाव से एचटीएम बही में अतिरिक्त अवास्तविक हानि, एचटीएम पोर्टफोलियो आकार (बही वैल्यू) के 10.5 प्रतिशत के बराबर होगी।

2.35 पारंपरिक अंतराल विश्लेषण (टीजीए[19]) का उपयोग करते हुए बैंकों के ब्याज दर जोखिम के आकलन में, दर-संवेदनशील वैश्विक आस्तियों, देयताओं और तुलन-पत्र से इतर मदों के लिए, यह अनुमान लगाया गया है कि 200 आधार अंकों की ब्याज दर वृद्धि पर, पीएसबी और पीवीबी के लिए जोखिम में आय (ईएआर) निवल ब्याज आय (एनआईआई) का क्रमशः 14.7 प्रतिशत और 14.1 प्रतिशत होगी (सारणी 2.6)। एफबी और एसएफबी के लिए प्रभाव कम होगा। ब्याज दर वृद्धि का आय पर प्रभाव पीएसबी, पीवीबी और एफबी के लिए सकारात्मक होगा क्योंकि बैंक समूह स्तर पर उनका संचयी अंतराल[20] सकारात्मक था। एसएफबी के मामले में, प्रभाव नकारात्मक होगा क्योंकि मार्च 2026 का उनका संचयी अंतराल नकारात्मक था।

2.36 जोखिम-संवेदनशील वैश्विक आस्तियों, देयताओं और तुलन-पत्र से इतर मदों के कालावधि अंतराल विश्लेषण (डीजीए[21]) के अनुसार, पीवीबी, एफबी और एसएफबी के लिए इक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीई) ब्याज दर में ऊपरी (निचली) दिशा में परिवर्तन से घटेगा (बढ़ेगा), जबकि पीएसबी पर प्रभाव सकारात्मक होगा (सारणी 2.7)। एसएफबी का एमवीई ब्याज दर वृद्धि से विशेष रूप से प्रभावित होगा।

सारणी 2.6: जोखिम आय (एआर) – पारंपरिक गैप विश्लेषण (टीजीए)

(प्रतिशत)

बैंक समूह	निवल ब्याज आय (एनआईआई) के प्रतिशत के तौर पर जोखिम वाली आय (एक वर्ष तक)	
	100 बीपीएस की बढ़ोतरी	200 बीपीएस की बढ़ोतरी
पीएसबी	7.4 (6.5)	14.7 (13.1)
पीवीबी	7.0 (5.7)	14.1 (11.5)
एफबी	2.0 (1.4)	4.1 (2.8)
एसएफ़बी	-0.5 (-0.6)	-1.0 (-1.2)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सितंबर 2025 के समान मान दर्शाते हैं।
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी रिटर्न; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सारणी 2.7: इक्विटी की बाज़ार वैल्यू (एमवीई) – ड्यूरेशन गैप एनालिसिस (डीजीए)

(प्रतिशत)

बैंक समूह	इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी का बाज़ार वैल्यू (एमवीई)	
	100 बीपीएस की बढ़ोतरी	200 बीपीएस की बढ़ोतरी
पीएसबी	1.6 (0.8)	3.1 (1.7)
पीवीबी	-0.5 (-1.3)	-0.9 (-2.7)
एफबी	-1.5 (-2.6)	-3.0 (-5.1)
एसएफ़बी	-6.2 (-6.7)	-12.5 (-13.3)

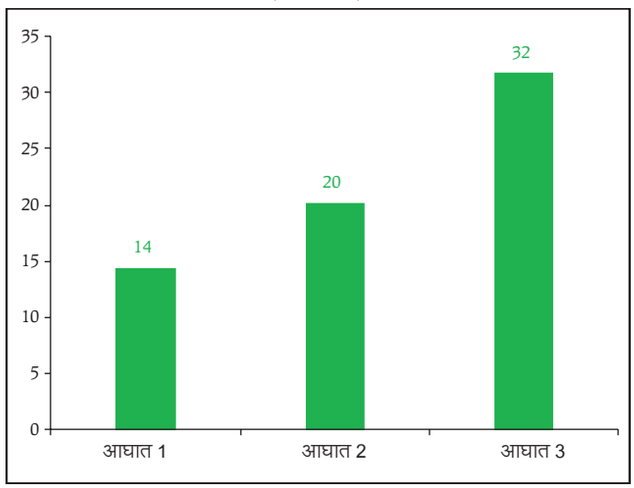
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सितंबर 2025 तक की वैल्यू दिखाते हैं।
स्रोत: आरबीआई के पर्यवेक्षी रिटर्न; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

ई. इक्विटी मूल्य जोखिम

2.37 चूंकि विनियामकीय दिशानिर्देशों के कारण बैंकों का पूंजी बाजार में प्रत्यक्ष एक्सपोजर सीमित है, इक्विटी बाजार मूल्यों में संभावित महत्वपूर्ण गिरावट का बैंकों के सीआरएआर पर प्रभाव मामूली रहने की उम्मीद है। दबाव परीक्षण के परिणाम दर्शाते हैं कि इक्विटी कीमतों में क्रमशः 25, 35 और 55 प्रतिशत की गिरावट वाले परिदृश्यों में, प्रणाली-स्तरीय सीआरएआर क्रमशः 14, 20 और 32 आधार अंक घट जाएगा (चार्ट 2.18)।

चार्ट 2.18: इक्विटी मूल्य जोखिम – प्रणाली स्तर पर सीआरएआर में गिरावट

(आधार अंक)



टिप्पणी: चुनिंदा 46 एससीबी की प्रणाली के लिए। आघात 1, 2 और 3 के तहत इक्विटी की कीमतों में क्रमशः 25, 35 और 55 प्रतिशत की गिरावट मानी गई है।
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी रिटर्न; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[19] 04 नवंबर, 2010 के "बैंकों के आस्ति देयता प्रबंधन ढाँचा - ब्याज दर जोखिम पर दिशानिर्देश" परिपत्र के संदर्भ में।

[20] गैप का मतलब है रेट-सेंसिटिव एसेट्स (आरएसए) में से रेट-सेंसिटिव लायबिलिटीज (आरएसएल) को घटाना। अग्रिम,एचटीएमनिवेश, स्वैप/फॉरेक्स स्वैप और रिवर्स रेपोआरएसए में मुख्य योगदानकर्ता हैं, जबकि जमा, स्वैप/फॉरेक्स स्वैप और रेपो आरएसएल के तहत मुख्य तत्व हैं।

[21] डीजीए में सभी आरएसए और आरएसएल को शेष परिपक्वता/री-प्राइसिंग तारीखों के अनुसार अलग-अलग समय-सीमाओं में बांटना और मॉडिफाइड ड्यूरेशन गैप (एमडीजी) की गणना करना शामिल है।

एफ़. चलनिधि जोखिम

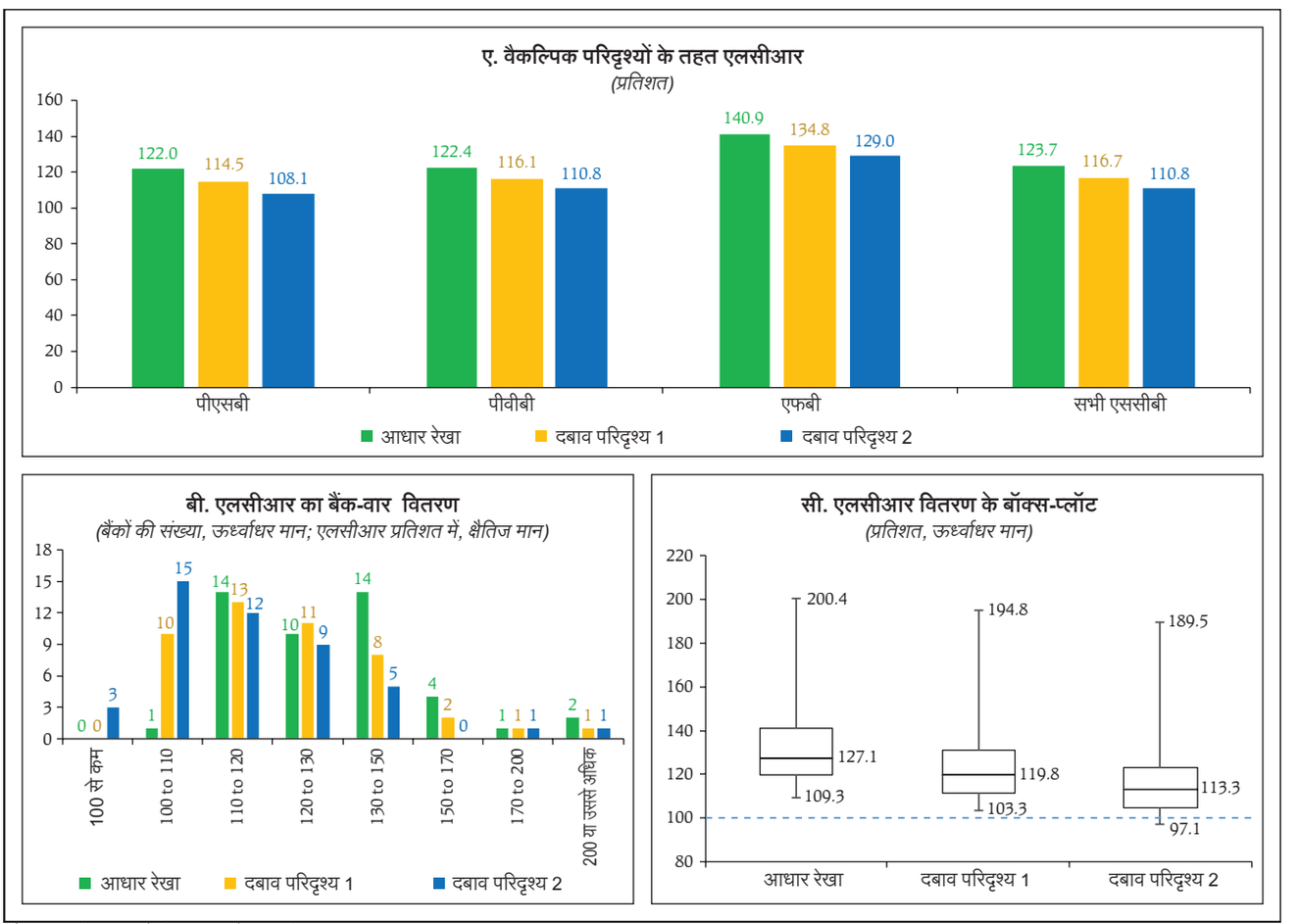
2.38 चलनिधि दबाव परीक्षण, जमा पर संभावित निकासी दबाव (रन) और प्रतिबद्ध ऋण एवं चलनिधि सुविधाओं के अप्रयुक्त हिस्सों की बढ़ी हुई मांग के बैंकों की चल निधि स्थिति पर प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करता है। दबाव परीक्षण के लिए आधार परिदृश्य[22] आरबीआई के एलसीआर संगणना[23] दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक नकदी प्रवाह घटक पर भार लागू करता है। दोनों दबाव परिदृश्य कुछ नकदी बहिर्प्रवाह घटकों पर अधिक रन-ऑफ दरें लागू करके तैयार किए गए हैं।

2.39 परिणामों से पता चला कि चुनिंदा एससीबी का समग्र एलसीआर आधार परिदृश्य में 123.7 प्रतिशत से घटकर दबाव परिदृश्य 1 में 116.7 प्रतिशत और दबाव परिदृश्य 2 में और घटकर 110.8 प्रतिशत हो जाएगा (चार्ट 2.19 ए)। व्यक्तिगत रूप से, अधिक गंभीर दबाव परिदृश्य 2 के तहत, तीन बैंक नियामक न्यूनतम एलसीआर को पूरा करने में विफल रहेंगे (चार्ट 2.19 बी और सी)। बैंक समूहों में, पीएसबी के लिए प्रभाव सबसे अधिक है (दबाव परिदृश्य 2 के तहत 13.9 प्रतिशत अंकों की गिरावट)।

II.1.10 लघु वित्त बैंकों की संवेदनशीलता विश्लेषण — ऋण जोखिम

2.40 एसएफबी का ऋण जोखिम संवेदनशीलता विश्लेषण एससीबी के समान दो दबाव परिदृश्यों के तहत अलग से किया गया है। जीएनपीए अनुपात में दो एसडी वृद्धि के गंभीर दबाव

चार्ट 2.19: एलसीआर - आधारित चल निधि दबाव परीक्षण



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी रिटर्न; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

[22] इन स्थितियों का वर्णन अनुबंध 1 में किया गया है।

[23] "चलनिधि मानक पर बेसल III ढाँचा - लिक्विडिटी कवरेज रेश्यो (एलसीआर), लिक्विडिटी रिस्क मॉनिटरिंग टूल्स और एलसीआर प्रकटीकरण मानक " पर आरबीआई के दिनांक 09 जून, 2014, को जारी परिपत्र सं आरबीआई /2013-14/635 डीबीओडी बीपी बीसी सं120/21.04.098/2013-14 ।

परिदृश्य में, एसएफबी का समग्र जीएनपीए अनुपात 380 आधार अंक बढ़ जाएगा, जिससे सीआरएआर और सीईटी1 अनुपात क्रमशः 170 और 180 आधार अंक घट जाएंगे। क्षेत्र के समग्र लचीलेपन के बावजूद, एक बैंक विनियामक न्यूनतम सीआरएआर आवश्यकता का उल्लंघन करेगा (चार्ट 2.20 ए और बी)।

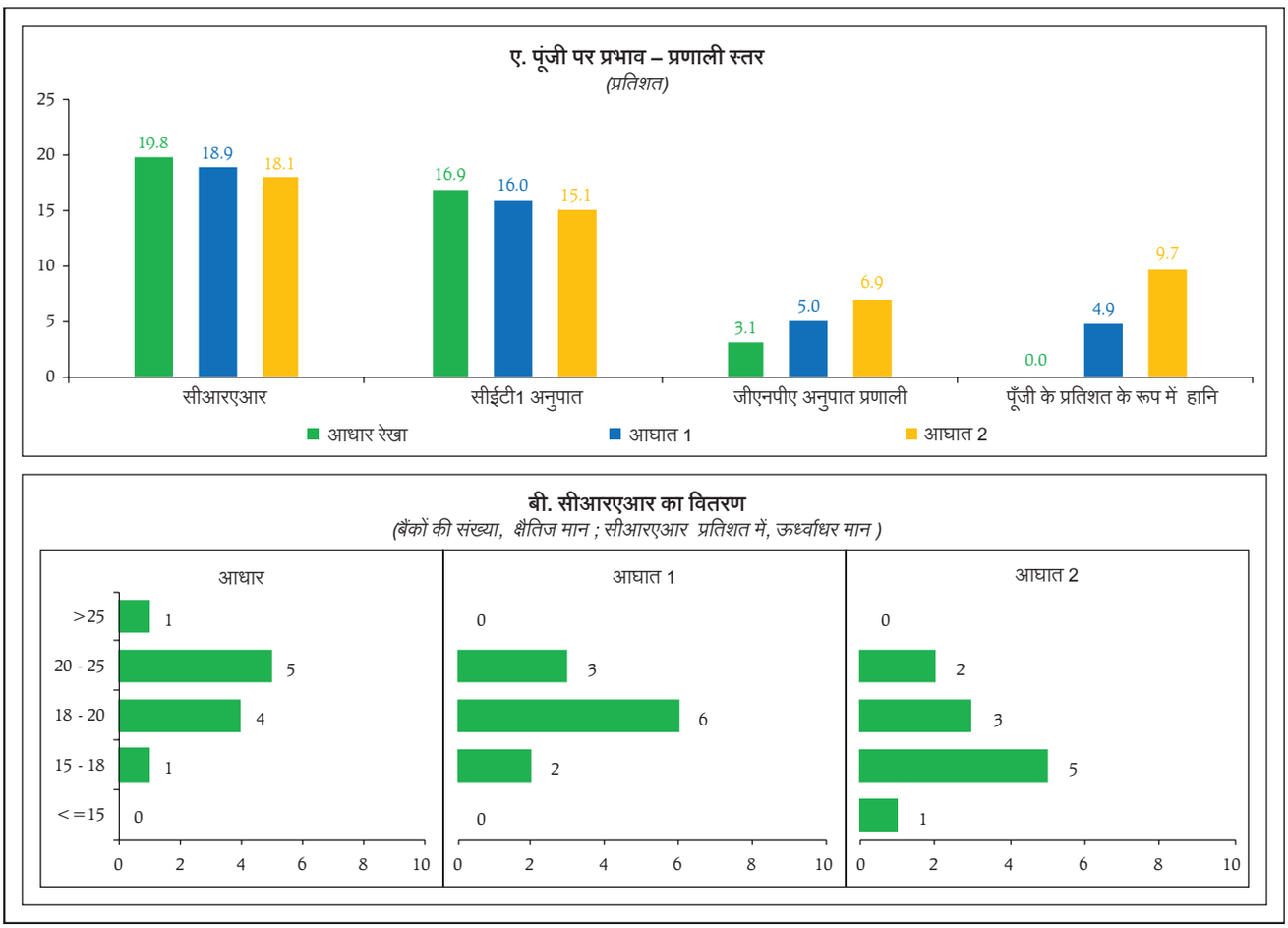
II.1.11 डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर आधार -दबाव परीक्षण

2.41 चयनित बैंकों[24] द्वारा मार्च 2026 तक के अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर चार अलग-अलग आघातों — अर्थात ब्याज दरों और विदेशी मुद्रा दरों पर आधारित दो-दो आघातों — के अधीन आधार दबाव परीक्षणों (संवेदनशीलता विश्लेषण) की एक श्रृंखला आयोजित की गई।

2.42 अधिकांश एफबी ने मार्च 2026 में सीईटी1 पूंजी के अनुपात के रूप में बाजार भाव पर दर्शाने वाली (एमटीएम) निवल सकारात्मक मार्क-टू-मार्केट स्थिति (लाभ-हानि खाते में प्रभावित) बनाए रखी। इसके विपरीत, पीएसबी और पीवीबी के लिए एमटीएम प्रभाव काफी हद तक सीमित रहा (चार्ट 2.21)।

2.43 दबाव परीक्षण के परिणामों से पता चला कि निवल एमटीएम स्थिति में परिवर्तन के रूप में मापा गया ब्याज दर आघातों का प्रभाव, सितंबर 2025 की तुलना में मार्च 2026

चार्ट 2.20: एसएफ़बी के लिए ऋण जोखिम – आघात और नतीजे

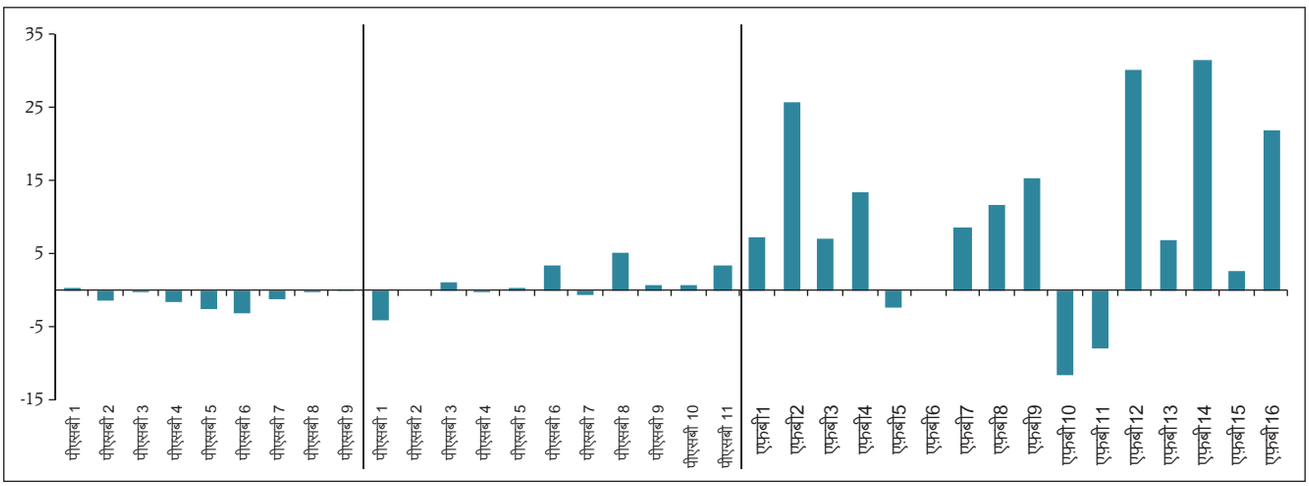


टिप्पणी: 11 एसएफ़बी की प्रणाली के लिए। आघात 1, जीएनपीए अनुपात पर 1 एसडी का आघात है। आघात 2, जीएनपीए अनुपात पर 2 एसडी का आघात है।
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी रिटर्न; और आरबीआई स्टाफ़ अनुमान।

[24] डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर दबाव परीक्षण 36 बैंकों के एक सैंपल द्वारा किए जाते हैं, जिनमें सक्रिय अधिकृत डीलर और ब्याज दर स्वैप प्रति पक्षकार शामिल हैं। परीक्षण स्थितियों का विवरण अनुबंध 1 में दिया गया है।

चार्ट 2.21: कुल डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो का निवल एमटीएम (लाभ और हानि में गणना करने योग्य)

(सीईटी1 पूँजी का प्रतिशत)



टिप्पणी: पीएसबी:- पब्लिक सेक्टर बैंक, पीवीबी:- प्राइवेट सेक्टर बैंक, एफ़बी:- विदेशी बैंक।
स्रोत: अलग-अलग बैंकों द्वारा दी गई जानकारी; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

में थोड़ा अधिक होते हुए भी, दोनों ब्याज दर आघातों के लिए लाभ-हानि प्रभाव के संदर्भ में सममित है (चार्ट 2.22)। रुपया विनिमय दर के संदर्भ में आघातों के लिए, भुगतान प्रोफाइल अधिक असममित हो गई है, जिसमें मूल्यवृद्धि से संभावित हानियां काफी बढ़ रही हैं, जो दीर्घ यूएसडी स्थितियों के संचय का संकेत देती हैं।

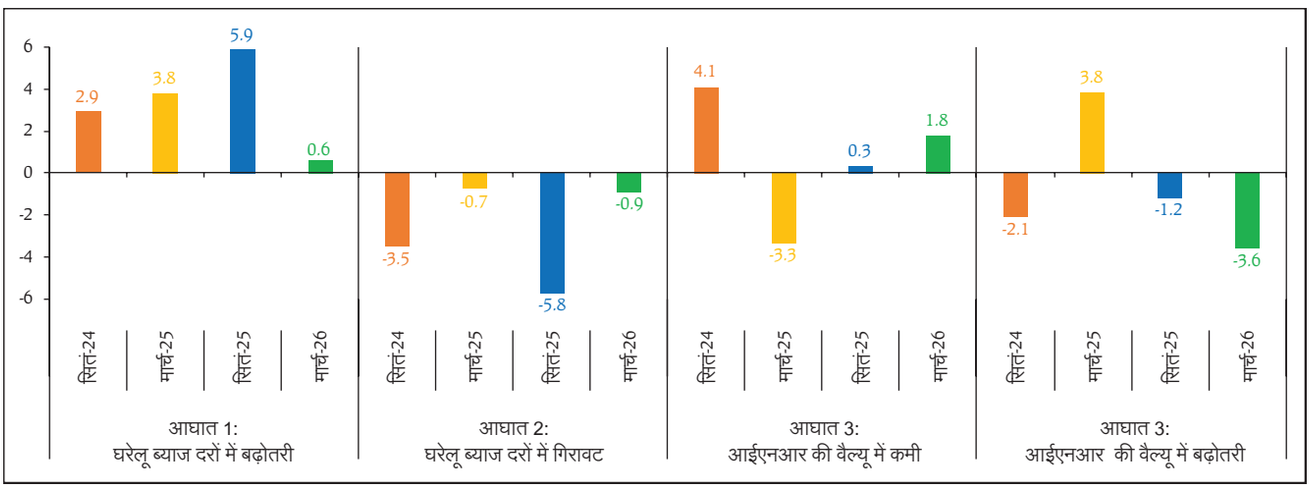
2.44 डेरिवेटिव पोर्टफोलियो से आय, जिसमें निवल एमटीएम स्थितियों में परिवर्तन और वसूल की गई आय शामिल है, मार्च 2026 के दौरान एफबी के लिए तेजी से बढ़ी है। पीएसबी और पीवीबी के संबंध में, निवल परिचालन आय (एनओआई) में डेरिवेटिव पोर्टफोलियो से आय का योगदान अपेक्षाकृत सीमित है (चार्ट 2.23)।

II.1.12 ऋण, बाजार और चल निधि जोखिम पर आधार दबाव परीक्षण

2.45 एक आधार दबाव परीक्षण (संवेदनशीलता विश्लेषण) मार्च 2026 के अंत की स्थिति के अनुसार 37 चयनित बैंकों की तुलन पत्र पर किया गया। परिणामों ने विभिन्न प्रकार और

चार्ट 2.22: चुनिंदा बैंकों के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर आघातों का एमटीएम प्रभाव

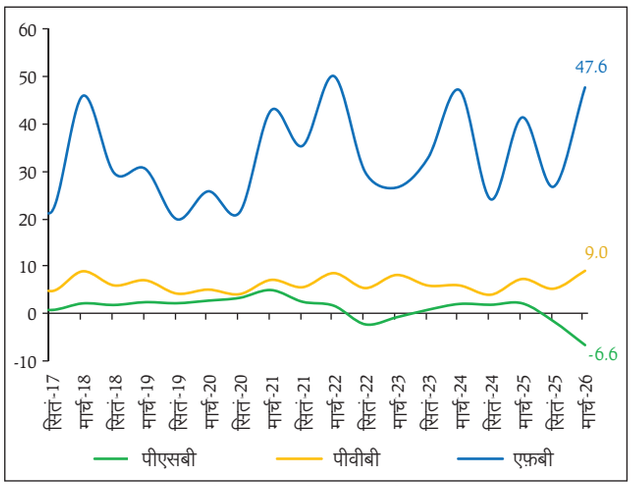
(आघात लगने पर निवल एमटीएम स्थिति में बदलाव, आधार रेखा के मुकाबले कुल पूँजी के प्रतिशत के तौर पर)



टिप्पणी: आघात लगने के कारण निवल एमटीएम में बदलाव आधार रेखा के सापेक्ष है।
स्रोत: अलग-अलग बैंकों की रिपोर्ट; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट 2.23: डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो से आय

(निवल परिचालन आय का प्रतिशत)



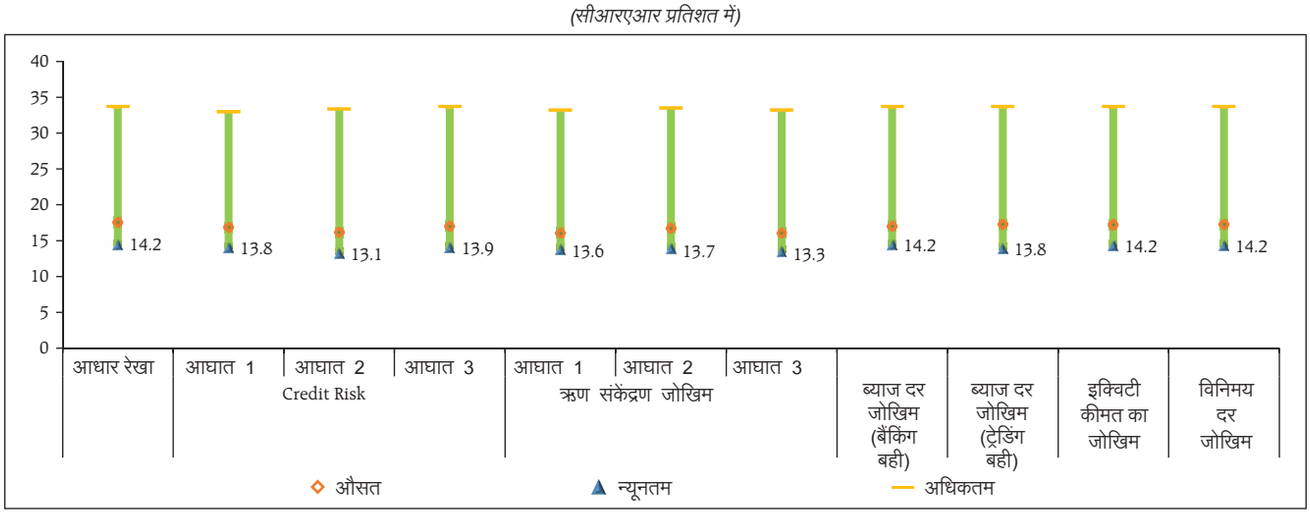
स्रोत: अलग-अलग बैंकों द्वारा दी गई जानकारी; और आरबीआईस्टाफ अनुमान।

मात्रा के आघातों के प्रति इन बैंकों की सुदृढ़ता की पुष्टि की। सभी नमूना बैंक विभिन्न परिदृश्यों के तहत सीआरएआर (सीआरएआर) की नियामक न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होंगे (चार्ट 2.24)।

2.46 चलनिधि जोखिम के लिए आधार दबाव परीक्षण से पता चला कि सभी नमूना बैंकों के चलनिधि आस्ति अनुपात[25] वैकल्पिक परिदृश्यों के तहत सकारात्मक बने रहेंगे, जो जमाराशियों की अचानक और अप्रत्याशित निकासी से उत्पन्न चलनिधि दबाव झेलने के लिए उनकी उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियों की पर्याप्तता को दर्शाता है। लगातार पांच दिनों तक तीन प्रतिशत जमा निकासी के परिदृश्य के तहत, चयनित बैंकों का औसत चलनिधि आस्ति अनुपात 21.4 प्रतिशत से घटकर 11.0 प्रतिशत हो जाएगा (चार्ट 2.25)।

चार्ट 2.24: ऋण और बाज़ार जोखिम

(सीआरएआर प्रतिशत में)



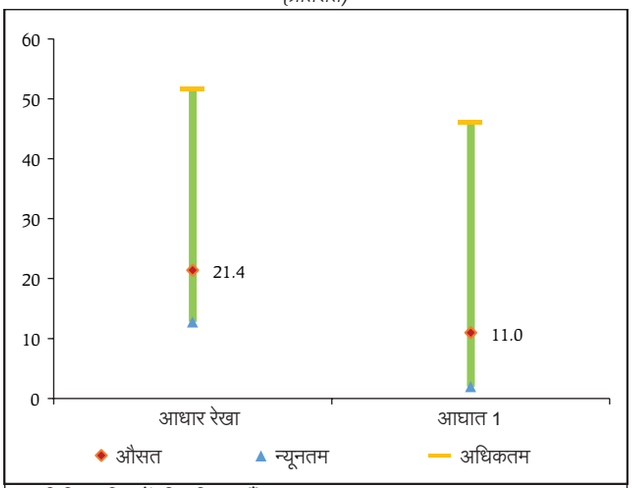
ऋण जोखिम : सकल ऋण	आघात 1	एनपीए में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी
	आघात 2	कॉर्पोदर बही के लिए सभी उधारकर्ताओं की रेटिंग में एक स्तर की एकसमान गिरावट
	आघात 3	उच्च 5 सेक्टर/उद्योग में से प्रत्येक में एनपीए में 5 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी
ऋण जोखिम : संकेंद्रण	आघात 1	उच्च तीन वैयक्तिक उधारकर्ताअवमानक श्रेणी में चूक करते हैं
	आघात 2	सबसे बड़ा समूह अवमानक श्रेणी में चूक से जुड़ा है।
	आघात 3	उच्च पांच उद्योग /सेक्टर में से प्रत्येक का सबसे बड़ा उधारकर्ता अवमानक श्रेणी में चूक करते हैं।
ब्याज दर जोखिम – बैंकिंग बही	आघात	आईएनआर यील्ड कर्व में 2.5 प्रतिशत अंक की समानांतर ऊपर की ओर शिफ्ट
ब्याज दर जोखिम – ट्रेडिंग बही	आघात	आईएनआर यील्ड कर्व में 2.5 प्रतिशत अंक की समानांतर ऊपर की ओर शिफ्ट
इक्विटी मूल्य जोखिम	आघात	इक्विटी मूल्य इंडेक्स में 40 प्रतिशत की गिरावट
विनिमय दर जोखिम	आघात	अन्य सभी करेंसी के मुकाबले आईएनआर की वैल्यू में 20 प्रतिशत की गिरावट

स्रोत: वैयक्तिक बैंकों की जानकारी; और आरबीआईस्टाफ अनुमान।

[25] Liquid Assets Ratio = $\frac{Liquid\ Assets}{Total\ Assets} \times 100$

चार्ट 2.25: चल निधि जोखिम – चल निधि आस्ति अनुपात

(प्रतिशत)



चल निधि आस्तियों की परिभाषाएँ	
चल निधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) दिशानिर्देशों के अनुसार उच्च गुणवत्ता चल निधि आस्तियां (एचक्यूएलए)।	
चलनिधि आघात	
आघात 1	5 दिनों के भीतर (हर दिन) 3 प्रतिशत जमा निकासी

स्रोत: वैयक्तिक बैंकों की जानकारी; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

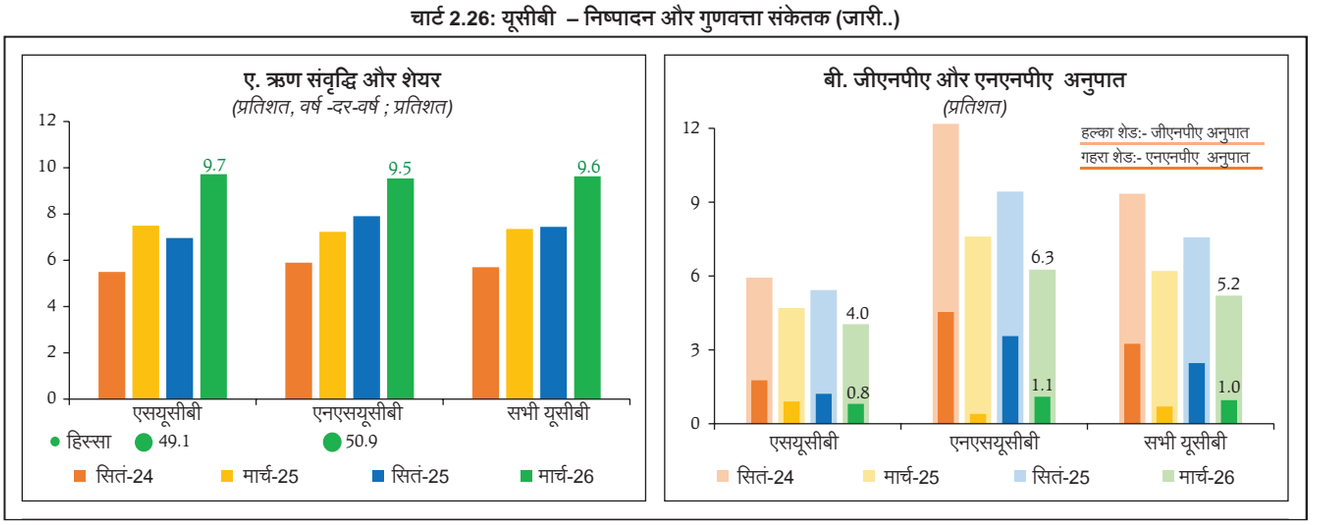
II.2 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक[26]

2.47 मार्च 2026 में प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी)[27] द्वारा दिए गए ऋण में 9.6 प्रतिशत की मजबूत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जिसे अनुसूचित यूसीबी (एसयूसीबी) और गैर-अनुसूचित यूसीबी (एनएसयूसीबी) दोनों में सुधार हुआ (चार्ट 2.26 ए)।

2.48 यूसीबी की आय संरचना में मार्च 2026 में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक निवल ब्याज आय (एनआईआई) और अन्य परिचालन आय परिलक्षित हुई (चार्ट 2.26 ग)। एनआईआई में मार्च 2026 में 2.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जो मुख्य रूप से एनएसयूसीबी में अधिक वृद्धि से प्रेरित थी (चार्ट 2.26 घ)। समग्र स्तर पर, एनआईएम में पिछली छमाही की तुलना में मार्च 2026 में मामूली सुधार हुआ; हालांकि, यह एक वर्ष पहले दर्ज किए गए स्तर से नीचे ही रहा (चार्ट 2.26 ङ)। लाभप्रदता संकेतकों में नरमी आई, जिसमें आरओए और आरओई क्रमशः मार्च 2026 में घटकर 0.6 प्रतिशत और 6.3 प्रतिशत रह गए (चार्ट 2.26 च और 2.24 जी)। यूसीबी के विभिन्न स्तरों[28] में, लाभप्रदता अनुपातों में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट देखी गई (चार्ट 2.26 आई)।

2.49 सितंबर 2025 की तुलना में मार्च 2026 में यूसीबी के जीएनपीए और एनएनपीए अनुपातों में उल्लेखनीय गिरावट आई (चार्ट 2.26 ख)। यह सुधार एसयूसीबी और एनएसयूसीबी दोनों में देखा गया। बड़े उधारकर्ताओं में भी जीएनपीए अनुपात में इसी प्रकार का रुझान देखा गया, जिनकी यूसीबी के ऋण पोर्टफोलियो में 22.7 प्रतिशत हिस्सेदारी थी (चार्ट 2.26 झ)। पीसीआर में भी मार्च 2025 और सितंबर 2025 दोनों की तुलना में मार्च 2026 में सुधार हुआ, जो मुख्य रूप से

चार्ट 2.26: यूसीबी – निष्पादन और गुणवत्ता संकेतक (जारी..)

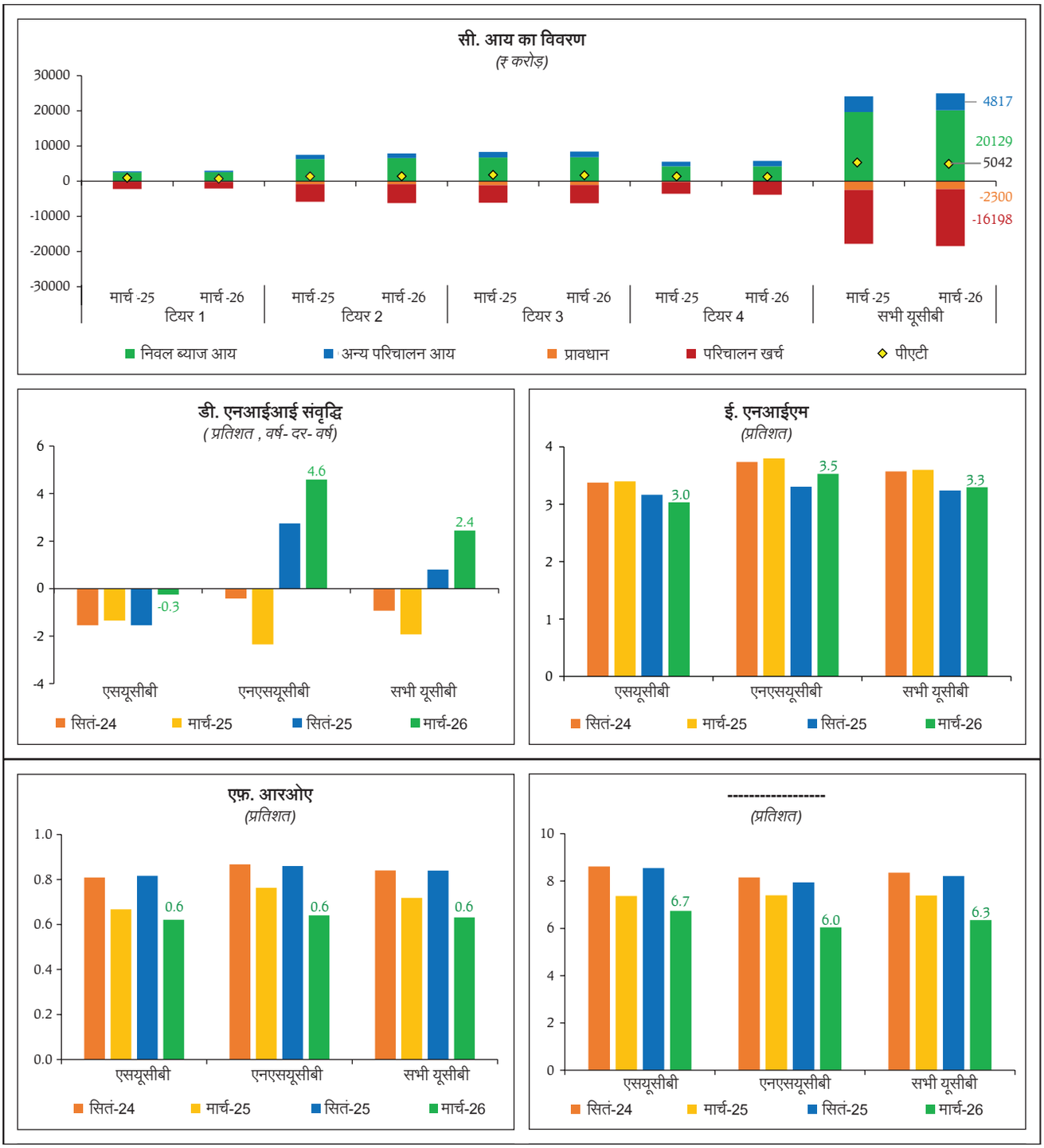


[26] डेटा अनंतिम है और आरबीआई के पर्यवेक्षी रिटर्न के माध्यम से यूसीबी द्वारा जमा किए गए डेटा पर आधारित है।

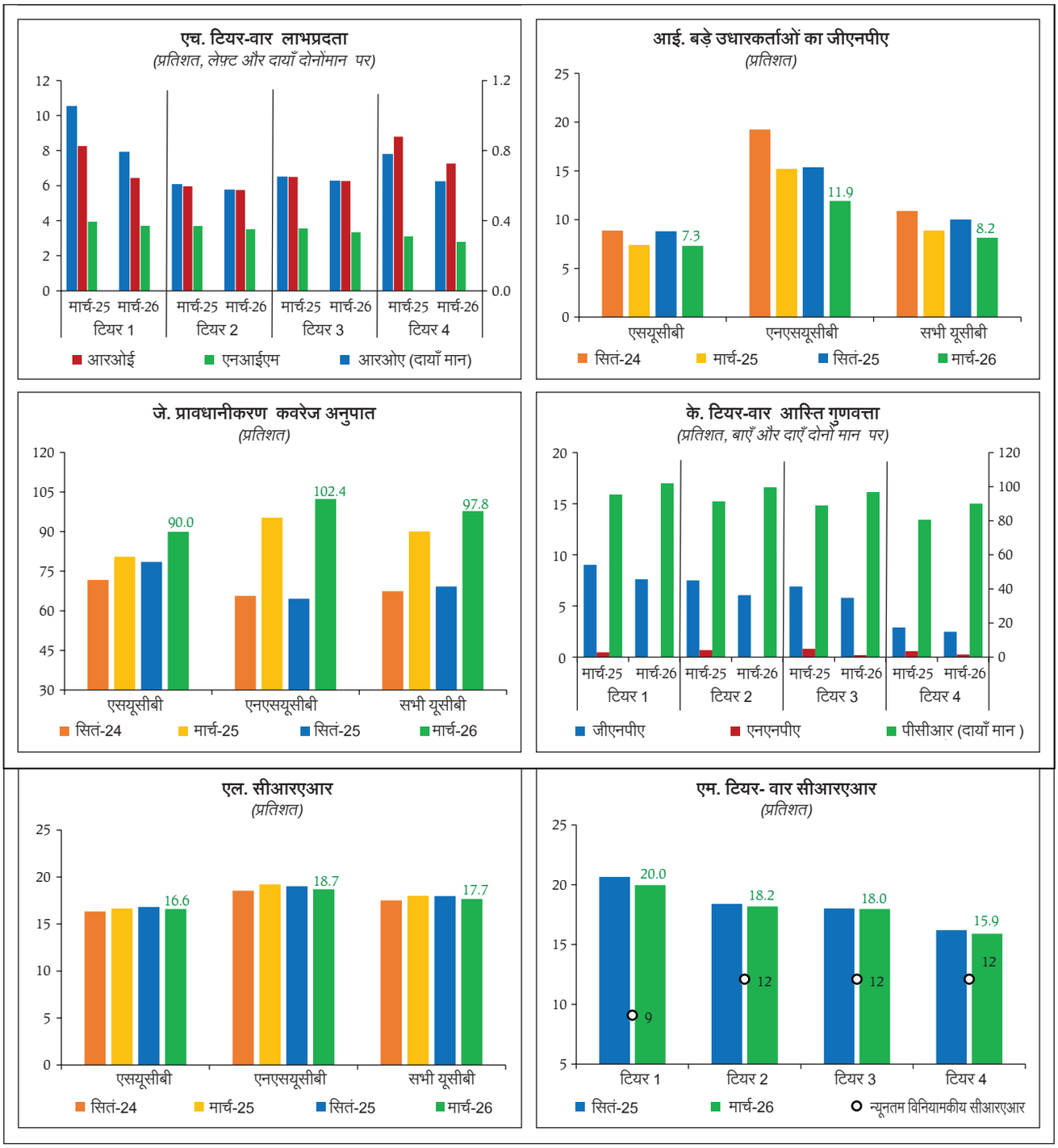
[27] 1,328 यूसीबी के सामान्य सैंपल पर आधारित, जिसमें सभी यूसीबी द्वारा दिए गए कुल ऋण का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा शामिल है।

[28] भारतीय रिज़र्व बैंक (शहरी सहकारी बैंक - लाइसेंसिंग, शेड्यूलिंग और विनियामक वर्गीकरण) दिशानिर्देश, 2025 (परिपत्र आरबीआई/बैविवि/2025-26/269 दिनांक 04 दिसंबर, 2025)।

चार्ट 2.26: यूसीबी – निष्पादन और गुणवत्ता संकेतक *(जारी..)*



चार्ट 2.26: यूसीबी – निष्पादन और गुणवत्ता संकेतक *(जारी.)*



स्रोत: वैयक्तिक बैंकों की जानकारी; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

एनएसयूसीबी द्वारा संचालित था (चार्ट 2.26 ट)। यूसीबी के सभी स्तरों में परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ, तथा मार्च 2026 में पिछले वर्ष की तुलना में पीसीआर में वृद्धि हुई (चार्ट 2.26 के)।

2.50 यूसीबी की पूंजी पर्याप्तता स्थिति मजबूत बनी रही, मार्च 2026 में सीआरएआर 17.7 प्रतिशत पर स्थिर रहा। यूसीबी के विभिन्न स्तरों में सीआरएआर नियामक न्यूनतम आवश्यकता से ऊपर बना रहा, हालांकि सितंबर 2025

की तुलना में इसमें मामूली गिरावट आई (चार्ट 2.26 ल और एम)।

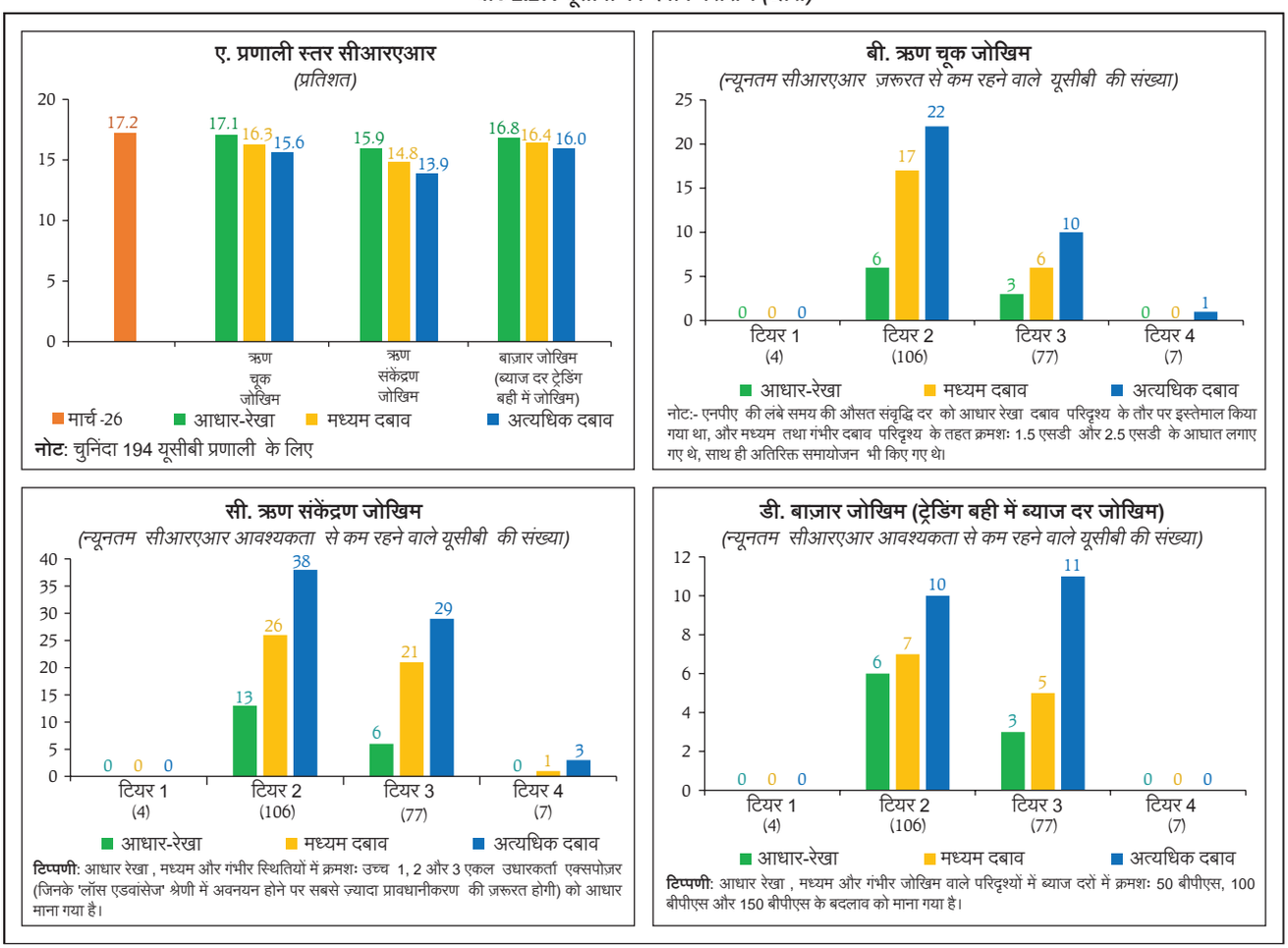
II.2.1 दबाव परीक्षण

2.51 चयनित यूसीबी के एक समूह[29] पर दबाव परीक्षण किए गए ताकि मार्च 2026 के अंत तक उनकी रिपोर्ट की गई वित्तीय स्थिति के आधार पर ऋण जोखिम (चूक जोखिम और संकेंद्रण जोखिम), बाजार जोखिम (ट्रेडिंग बही और बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम) और चलनिधि जोखिम का आकलन किया जा सके।

2.52 ऋण चूक जोखिम, ऋण संकेंद्रण जोखिम और ब्याज दर जोखिम (ट्रेडिंग बुक) के गंभीर दबाव परिदृश्यों के तहत, चयनित यूसीबी का समेकित सीआरएआर पूर्व-आघात स्तर 17.2 प्रतिशत से घटकर क्रमशः 15.6 प्रतिशत, 13.9 प्रतिशत और 16.0 प्रतिशत हो जाएगा (चार्ट 2.27 ए)। बैंकिंग बही में गंभीर ब्याज दर आघातों से समेकित एनआईआई में 8.0 प्रतिशत की कमी आएगी। चलनिधि दबाव परीक्षण के तहत, 1-28 दिनों की समय अवधि में समेकित संचयी चलनिधि बेमेल तीनों दबाव परिदृश्यों के तहत सकारात्मक रहा।

2.53 ऋण जोखिम के लिए गंभीर दबाव परिदृश्य का सीआरएआर[30] पर प्रभाव टियर 4 श्रेणी के अंतर्गत एक

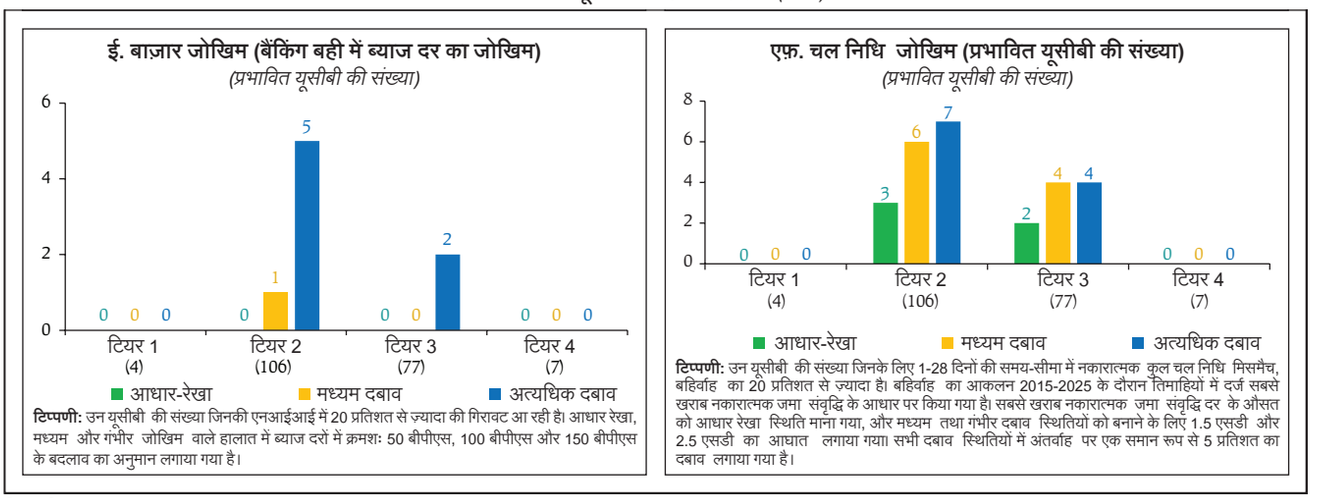
चार्ट 2.27: यूसीबी का दबाव परीक्षण *(जारी)*



[29] दबाव परीक्षण, 500 करोड़ रुपये से ज़्यादा आस्ति आकार वाले चुनिंदा 194 यूसीबी की मार्च 2026 की वित्तीय स्थिति के आधार पर किया जाता है। इसमें रिज़र्व बैंक के 'ऑल-इनक्लूसिव डायरेक्शंस' (एआईडी) के तहत आने वाले बैंक शामिल नहीं हैं। ये 194 यूसीबी मिलकर यूसीबी क्षेत्र के कुल आस्ति का लगभग 71 प्रतिशत हिस्सा कवर करते हैं। दबाव परीक्षण के लिए इस्तेमाल किया गया विस्तृत तरीका अनुबंध 1 में दिया गया है।

[30] 31 मार्च 2026 तक, टियर 1 यूसीबी के लिए न्यूनतम विनियामक सीआरएआर 9 प्रतिशत है और टियर 2, टियर 3 और टियर 4 में आने वाले यूसीबी के लिए यह 12 प्रतिशत है।

चार्ट 2.27: यूसीबी का दबाव परीक्षण *(जारी)*



टिप्पणी: Figures in brackets represent the sample size of the Tier.
स्रोत: RBI Supervisory Returns; and RBI Staff Estimates.

यूसीबी के लिए महत्वपूर्ण होगा। टियर 2 और टियर 3 यूसीबी के मामले में, गंभीर दबाव परिदृश्यों के तहत ऋण जोखिम और ऋण संकेंद्रण जोखिम का प्रभाव महत्वपूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त, ऋण संकेंद्रण जोखिम के गंभीर दबाव परिदृश्य के तहत तीन टियर 4 यूसीबी पूंजी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाएंगे (चार्ट 2.27 ए और सी)।

2.54 टियर 1 और टियर 4 में से कोई भी यूसीबी अपने ट्रेडिंग बही पर लागू ब्याज दर आघात परिदृश्यों के तहत सीआरएआर पर नियामक सीमाओं का उल्लंघन नहीं करेगा, न ही अपनी बैंकिंग बही में एनआईआई में 20 प्रतिशत से अधिक की गिरावट का अनुभव करेगा (चार्ट 2.27 घ)। ब्याज दर जोखिम (ट्रेडिंग बुक) के गंभीर दबाव परिदृश्य के तहत, 10 टियर 2 और 11 टियर 3 यूसीबी नियामक न्यूनतम सीआरएआर को पूरा नहीं कर पाएंगे। टियर 2 और 3 के कुछ यूसीबी को गंभीर दबाव परिदृश्य के तहत 1-28 दिनों की समय अवधि में 20 प्रतिशत से अधिक के नकारात्मक चलनिधि बेमेल का सामना करना पड़ेगा (चार्ट 2.27 ङ और च)।

II.3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)[31]

2.55 एनबीएफसी (ऊपरी और मध्य स्तर) की समेकित ऋण वृद्धि मार्च 2026 में घटकर 16.6 प्रतिशत वार्षिक रह गई (चार्ट 2.28 ए)। गतिविधि-आधारित श्रेणियों में, एनबीएफसी-आईसीसी और एनबीएफसी-आईएफसी दोनों के लिए ऋण वृद्धि में नरमी आई। इसके विपरीत, एनबीएफसी-एमएफआई की ऋण वृद्धि सकारात्मक हो गई और मार्च 2026 में बढ़कर 14.5 प्रतिशत वार्षिक हो गई (चार्ट 2.28 बी)। क्षेत्रवार, एनबीएफसी की ऋण वृद्धि कृषि और खुदरा ऋण खंडों में तेज हुई, जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्रों में धीमी हुई (चार्ट 2.28 सी)। खुदरा ऋणों में, वृद्धि मुख्य रूप से स्वर्ण ऋण और अन्य खुदरा ऋणों से प्रेरित थी, जबकि वाहन/ऑटो ऋणों में मंदी देखी गई (चार्ट 2.28 ई)

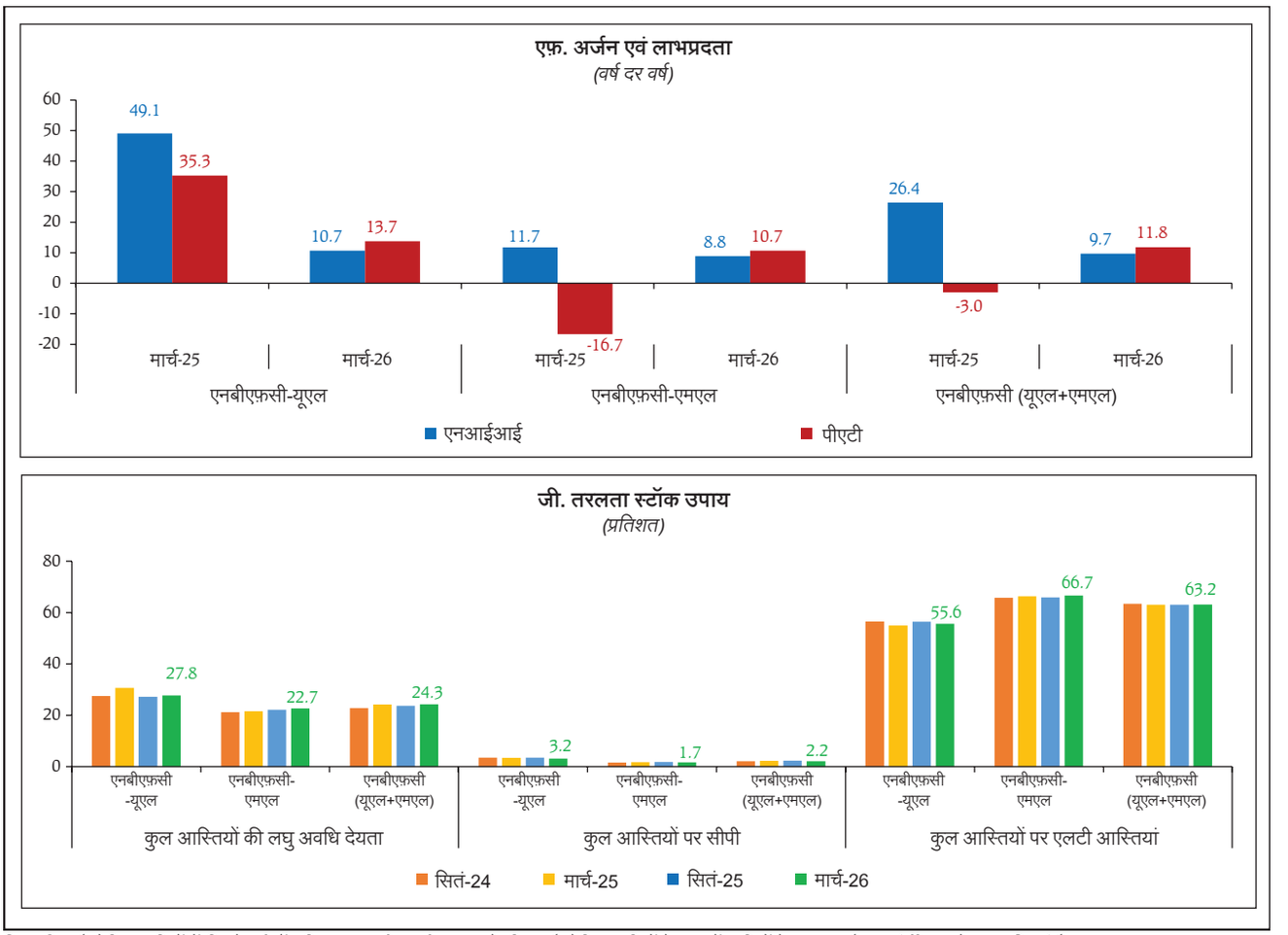
2.56 एनबीएफसी की एनआईआई वृद्धि मार्च 2026 में वार्षिक आधार पर 9.7 प्रतिशत बढ़ी (चार्ट 2.28 एफ़)। लाभप्रदता में भी सुधार हुआ, जो 11.8 प्रतिशत की पीएटी वृद्धि में परिलक्षित हुआ। एनआईआई और पीएटी में वृद्धि ऊपरी स्तर एनबीएफसी के मामले में अधिक थी।

[31] इस भाग में किया गया विश्लेषण, ऊपरी स्तर, मध्य स्तर की एनबीएफ़सी (सीआईसी, एचएफ़सी और एसपीडी को छोड़कर) के लिए उपलब्ध अनंतिम डेटा पर आधारित है, लेकिन इसमें 18 मई, 2026 तक समाधान के तहत चल रही कंपनियाँ शामिल हैं। पिछले समय के डेटा के साथ निरंतरता और तुलना सीमित हो सकती है क्योंकि एनबीएफ़सी डेटा को स्केल-आधारित विनियमन के आधार पर फिर से वर्गीकृत किया गया है। पुराने डेटा को फिर से तैयार करने के लिए मर्जर और पुनर्वर्गीकरण के प्रभाव (अगर कोई हो) पर विचार नहीं किया गया है।

चार्ट 2.28: एनबीएफ़सी – मुख्य वित्तीय मानक *(जारी..)*



चार्ट 2.28: एनबीएफ़सी – मुख्य वित्तीय मापदंड *(समाप्त)*



टिप्पणी: औद्योगिक अग्रिमों में हिस्सेदारी में वृद्धि कुछ एनबीएफसी-एमएल के लिए औद्योगिक अग्रिमों के रूप में अग्रिमों के सुधार और पुनर्वर्गीकरण के बाद की गई है।
स्रोत: आरबीआई के पर्यवेक्षी रिटर्न; आरबीआई का स्टाफ अनुमान।

2.57 सभी प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में एनबीएफसी की आस्ति गुणवत्ता में सुधार जारी रहा (चार्ट 2.28 डी)। खुदरा ऋणों के तहत, जीएनपीए अनुपात में आवास और शिक्षा ऋण खंडों में मामूली वृद्धि दर्ज की (चार्ट 2.28 ई)।

2.58 चलनिधि के मोर्चे पर, कुल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में अल्पकालिक देनदारियों में मामूली वृद्धि हुई (चार्ट 2.28 जी)।

2.59 एनबीएफसी के एक सामान्य सेट[32] के लिए, एनबीएफसी-यूएल द्वारा ऋण में वृद्धि मोटे तौर पर 19.8 प्रतिशत पर स्थिर रही। एनबीएफसी-एमएल ने ऋण वृद्धि में सितंबर 2025 में 12.6% से मार्च 2026 में 14.4% की बढ़ोतरी देखी (चार्ट 2.29 ए और बी)।

2.60 प्रमुख क्षेत्रों में, एनबीएफसी-यूएल द्वारा दिया गया ऋण खुदरा (62.2 प्रतिशत) और सेवा क्षेत्रों (25.5 प्रतिशत) में केंद्रित था; जबकि, मार्च 2026 तक इन खंडों में ऋण वृद्धि धीमी हो गई (चार्ट 2.29 सी)। एनबीएफसी-एमएल के मामले में, ऋण पोर्टफोलियो ज्यादातर औद्योगिक क्षेत्र की ओर केंद्रित था, जो कुल ऋण का 61.7 प्रतिशत थी। इस खंड में ऋण वृद्धि भी काफी धीमी हो गई (चार्ट 2.29 डी)।

[32] एक तिमाही के लिए, सामान्य सेट उस तिमाही में एनबीएफसी के साथ एक साल पहले समान तिमाही में एनबीएफसी पर आधारित है।

2.61 ऊपरी और मध्य स्तर दोनों एनबीएफसी के लिए जीएनपीए अनुपात में लगातार गिरावट के साथ आस्ति की गुणवत्ता में सुधार हुआ (चार्ट 2.29 ई और एफ)। एनबीएफसी-एमएल ने एनबीएफसी-यूएल की तुलना में बहुत अधिक पीसीआर बनाए रखना जारी रखा। क्षेत्रीय स्तर पर, जीएनपीए में प्रमुख हिस्सेदारी वाले क्षेत्रों में आस्ति की गुणवत्ता में मार्च 2026 में सुधार हुआ (चार्ट 2.29 जी एवं एच)।

2.62 मार्च 2026 में गिरावट देखने के बावजूद प्रमुख लाभप्रदता अनुपात और विनियामक पूंजी अनुपात अच्छे रहे (चार्ट 2.29 आई,जे,के और आई)

2.63 हालांकि कुल मिलाकर एनबीएफ़सी के लिए निधियन का पैटर्न एक साल पहले जैसा ही रहा, पिछले वर्ष की तुलना में मार्च 2026 में एनबीएफ़सी-यूएल और एनबीएफ़सी-एमएल दोनों के लिए बैंक उधारी पर निर्भरता बढ़ी (सारणी 2.8)। डिबेंचर और सीपी एनबीएफ़सी-यूएल और एनबीएफ़सी-एमएल दोनों के लिए उधारी का अन्य बड़े स्रोत बने। इसके अलावा, मार्च 2026 में जमानती उधारी का एनबीएफ़सी-यूल का हिस्सा और गैर-जमानती उधारी का एनबीएफ़सी-एमएल का हिस्सा दोनों बढ़े, बाद में वृद्धि अधिक स्पष्ट है।

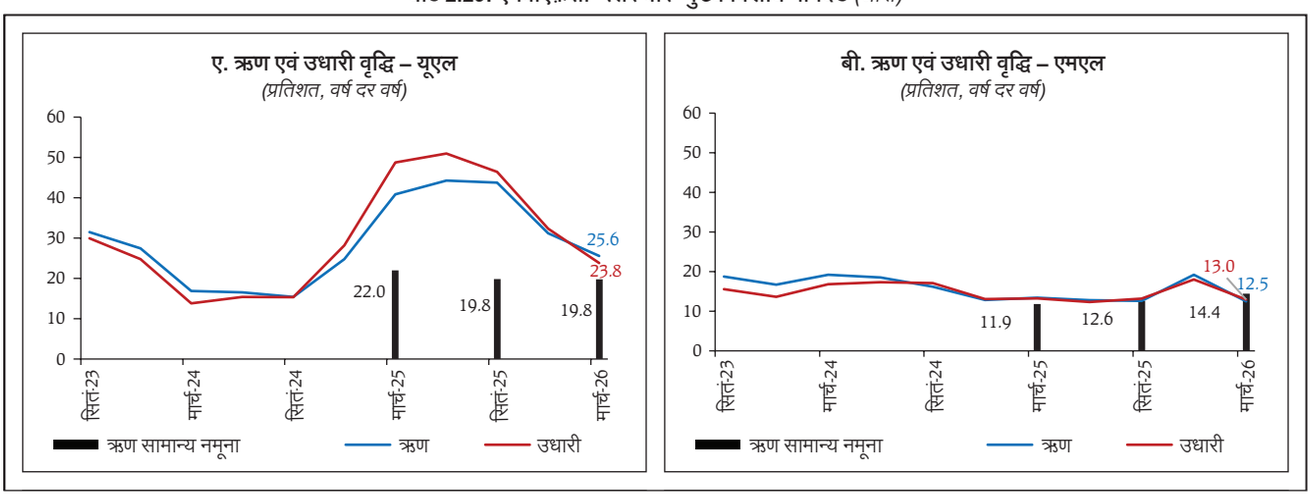
सारणी 2.8: एनबीएफसी की निधियों के स्रोत

(प्रतिशत)

मद विवरण	एनबीएफ़सी-यूएल		एनबीएफ़सी-एमएल		एनबीएफ़सी (यूएल+एमएल)	
	मार्च-25	मार्च-26	मार्च-25	मार्च-26	मार्च-25	मार्च- 26
I. शेयर पूंजी, रिजर्व और अधिशेष	18.6	19.4	24.5	22.4	22.8	21.5
II. कुल उधार	71.1	70.8	67.5	69.5	68.5	65.9
जिनमें से: *(i)* संरक्षित	61.6	62.4	30.9	30.8	39.9	40.8
(ii) असंरक्षित	9.5	8.4	36.5	38.7	28.7	29.1
(1) बैंकों से	33.8	34.5	26.4	28.5	28.6	30.4
(a) उधारी (संरक्षित + असंरक्षित)	29.9	30.6	24.0	26.3	25.7	27.6
(b) सब्सक्राइब किए गए डिबेंचर	3.2	3.2	2.1	2.0	2.4	2.4
(c) सब्सक्राइब किए गए सीपी	0.8	0.6	0.2	0.2	0.4	0.4
(2) डिबेंचर को छोड़कर II(1) (बी)	16.3	16.2	23.8	23.9	21.6	21.5
(3) सीपी को छोड़कर II(1) (सी)	2.6	2.6	1.6	1.4	1.9	1.8
III. जनता की जमा राशियाँ	6.0	5.3	0.5	0.5	2.1	2.0
IV. प्रावधान	2.8	3.0	2.9	2.6	2.9	2.7
V. अन्य देयताएँ	1.6	1.5	4.6	4.9	3.7	3.8
कुल	100	100	100	100	100	100

स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी रिटर्न और स्टाफ गणना।

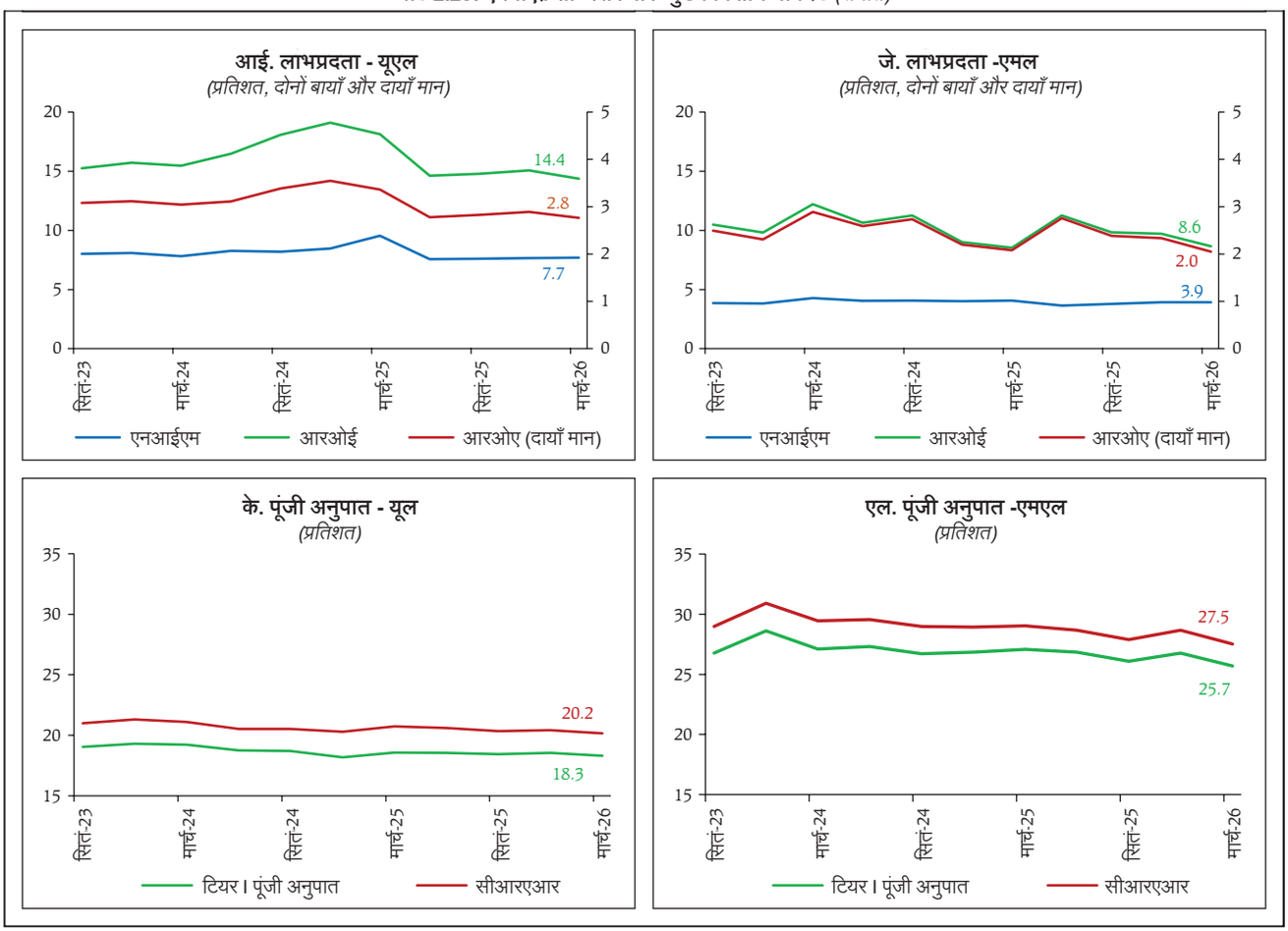
चार्ट 2.29: एनबीएफ़सी- स्तर वार- मुख्य वित्तीय मापदंड *(जारी)*



चार्ट 2.29: एनबीएफ़सी- स्तर वार- मुख्य वित्तीय मापदंड *(जारी)*



चार्ट 2.29: एनबीएफ़सी- स्तर वार- मुख्य वित्तीय मापदंड *(समाप्त)*



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी रिटर्न और स्टाफ गणना।

II.3.1. दबाव परीक्षण[33] - ऋण जोखिम

2.64 ऋण जोखिम आघातों के प्रति एनबीएफसी क्षेत्र के सहनीयता का आकलन करने के लिए आधार और दो दबाव मानदंड के अंतर्गत एक साल के दौरान प्रणाली स्तर पर दबाव परीक्षण 174 एनबीएफसी[34] के नमूने पर किए गए। जबकि आधारभूत परिदृश्य हमेशा की तरह व्यापार की मान्यताओं पर आधारित था, मध्यम और गंभीर जोखिम परिदृश्य क्रमशः 1 एसडी और 2 एसडी आघातों को जीएनपीए अनुपात में लागू करके प्राप्त किए गए थे।

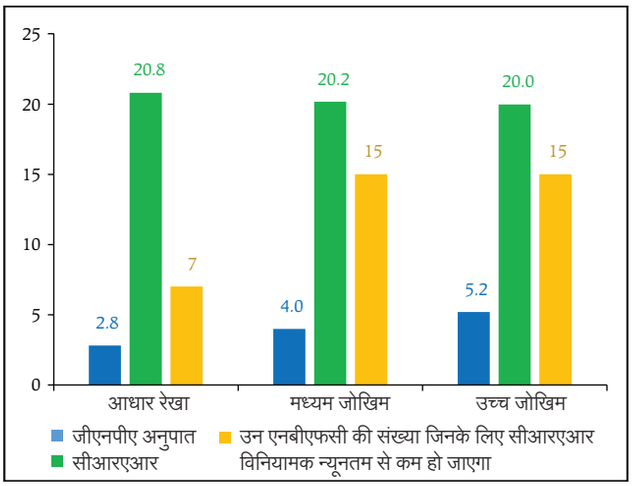
2.65. आधार रेखा परिदृश्य के तहत, नमूना एनबीएफ़सी का प्रणाली स्तर जीएनपीए अनुपात मार्च 2026 में 2.4% से मार्च 2027 में 2.8% प्रतिशत होने का अनुमान है। परिणामस्वरूप, उनका सकल सीआरएआर उक्त अवधि के दौरान 22.3% से 20.8% तक गिरने का अनुमान है (चार्ट 2.30)। आधार रेखा परिदृश्य के तहत, 7 एनबीएफ़सी 15 प्रतिशत के न्यूनतम विनियामक पूंजी आवश्यकता का उल्लंघन कर सकते हैं। मध्यम और उच्च जोखिम परिदृश्यों के तहत, आय हानि और अतिरिक्त प्रावधान आवश्यकताओं से सकल सीआरएआर और कम होकर क्रमशः 60 बीपीएस और 80 बीपीएस हो जाएगा, और 15 एनबीएफ़सी विनियामक न्यूनतम सीआरएआर को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे।

[33] एनबीएफ़सी के दबाव परीक्षण के लिए प्रयोग में लायी गयी विस्तृत विधि अनुलग्नक 1 में उपलब्ध कराई गई है।

[34] नमूने में मार्च 2026 तक रु. 34.45 लाख करोड़ रुपये के कुल अग्रिमों के साथ 174 एनबीएफ़सी (11 ऊपरी स्तर और 163 मध्य स्तर) शामिल थे, जो गैर-सरकारी एनबीएफ़सी के कुल अग्रिमों का लगभग 95 प्रतिशत है। तनाव परीक्षणों के नमूने में सरकारी एनबीएफ़सी, वर्तमान में समाधान के अधीन कंपनियां, स्टैंड-एलोन प्राथमिक डीलर और निवेश केंद्रित कंपनियां शामिल नहीं हैं।

चार्ट 2.30: एनबीएफसी में ऋण जोखिम – प्रणाली स्तर

(जीएनपीए आनुपात और सीआरए हेतु प्रतिशत, एनबीएफ़सी की संख्या के लिए गणना)



टिप्पणी: आधार रेखा परिदृश्य एक वर्ष आगे तक सामान्य परिस्थितियों में कारोबार जारी रहने की धारणाओं पर आधारित है, जबकि मध्यम जोखिम और उच्च जोखिम परिदृश्य एक वर्ष की अवधि में जीएनपीए अनुपात में क्रमशः 1 एसडी और 2 एसडी की वृद्धि को मानते हैं।
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी रिटर्न और स्टाफ गणना।

II.3.2 दबाव परीक्षण[35] – संकेन्द्रण जोखिम

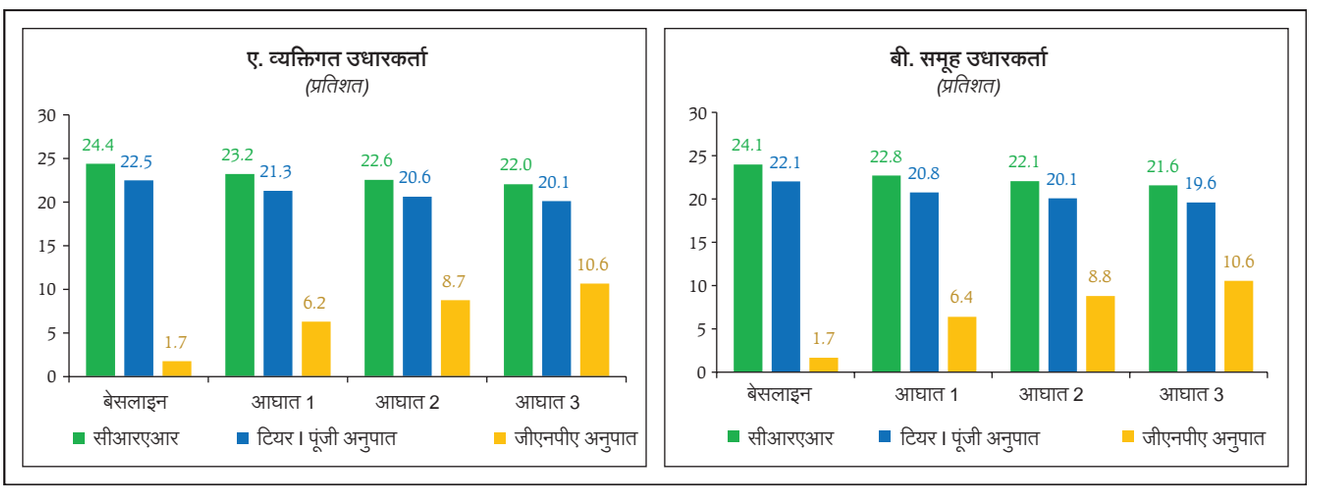
2.66 एनबीएफसी के ऋण संकेन्द्रण पर दबाव परीक्षण से पता चलता है कि संबंधित एनबीएफसी के सबसे बड़े तीन व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के डिफाल्ट[36] करने के अत्यधिक विकट परिदृश्य में, प्रणाली स्तर सीआरएआर में 230 बीपीएस की गिरावट आएगी (चार्ट 2.31 ए) और आठ एनबीएफसी को सीआरएआर में विनियामकीय न्यूनतम 15 प्रतिशत से नीचे गिरावट की स्थिति का सामना करना पड़ेगा।

2.67 सबसे खराब स्थिति में मानक श्रेणी के तीन समूह के उधारकर्ता चुकौती[37] करने में विफल हो जाते हैं, तो प्रणालीगत स्तरीय सीआरएआर 240 बीपीएस तक गिर जाएगा और आठ एनबीएफसी में सीआरएआर विनियामकीय न्यूनतम 15 प्रतिशत से नीचे आ जाएगा (चार्ट 2.31 बी)।

II.3.3 दबाव परीक्षण[38] [39] - चलनिधि जोखिम

2.68 चलनिधि असंतुलन पर आवक नकदी प्रवाह में कमी के साथ नकदी बहिर्वाह में वृद्धि के प्रभाव का अनुमान लगाकर एनबीएफसी क्षेत्र की चलनिधि आघातों के प्रति सहनीयता का आकलन किया गया है । परिणाम एनबीएफ़सी की वे संख्या को दर्शाते हैं जो अगले एक वर्ष में 20 प्रतिशत से अधिक का

चार्ट 2.31: क्रेडिट संकेंद्रण जोखिम-एक्सपोजर



टिप्पणी: 215 ऊपरी और मध्य स्तर एनबीएफ़सी की प्रणाली के लिए।
भुगतान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए शीर्ष 1,2 और 3 व्यक्तिगत उधारकर्ताओं की चूक को क्रमशः आघात 1, 2 और 3 के तहत माना जाता है।
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी रिटर्न; और कर्मचारियों का अनुमान।

टिप्पणी: 138 ऊपरी और मध्य परत एनबीएफ़सी की प्रणाली के लिए।
भुगतान प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए शीर्ष 1,2 और 3 समूह के उधारकर्ताओं की चूक को क्रमशः आघात 1,2 और 3 के तहत माना जाता है।
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी रिटर्न; और कर्मचारियों का अनुमान।

[35] एनबीएफ़सी के तनाव परीक्षणों के लिए उपयोग की जाने वाली विस्तृत पद्धति अनुलग्नक 1 में दी गई है।

[36] चूक के मामले में यह मान लिया जाता है कि मानक श्रेणी में व्यक्तिगत उधारकर्ता उप-मानक श्रेणी में चला गया है।

[37] चूक के मामले में यह मान लिया जाता है कि मानक श्रेणी में समूह उधारकर्ता उप-मानक श्रेणी में चला गया है।

[38] एनबीएफ़सी के तनाव परीक्षणों के लिए उपयोग की जाने वाली विस्तृत पद्धति अनुलग्नक 1 में दी गई है।

[39] 275 एनबीएफ़सी (ऊपरी स्तर में 11 और मध्य स्तर में 264) के नमूने पर चलनिधि जोखिम के आधार पर दबाव परीक्षण किया गया था। नमूने की कुल आस्तियों का आकार 42.52 लाख करोड़ रुपए था, जो इस क्षेत्र में गैर-सरकारी, गैर-सीआईसी एनबीएफ़सी की कुल आस्तियों का लगभग 99 प्रतिशत था।

नकारात्मक संचयी चलनिधि असंतुलन का सामना कर सकते हैं (सारणी 2.9)।

II.4 म्यूचुअल फंड के लिए दबाव परीक्षण[40]

2.69 म्यूचुअल फंड के दबाव परीक्षण के परिणाम से पता चलता है कि मार्च 2026 में, रु.3.18 लाख करोड़ के कुल प्रबंधनाधीन आस्तियां (एयूएम) वाली 44 निरंतर स्वरूप (ओपेन-एंडेड) ऋण योजनाओं ने एएमएफ़आई या एएमसी द्वारा तय सीमा का उल्लंघन किया है (सारणी 2.10)। इस संदर्भ में, सभी एमएफ़ ने या तो इसका उल्लंघन को ठीक कर लिया है या इसके लिए सुधार के कदम की शुरुआत के बारे में रिपोर्ट किया है और यह अपेक्षा की जाती है कि निर्धारित समय-सीमा में उक्त को पूरा कर लिया जाए।

2.70 निरंतर स्वरूप (ओपेन-एंडेड) ऋण योजनाओं के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन के रूप में, मार्च 2026 के अंत में ओपेन-एंडेड ऋण योजनाओं की 13 श्रेणियों के लिए शीर्ष 10 एएमसी (एयूएम पर आधारित) द्वारा दो चलनिधि अनुपात – जोखिम पर मोचन (एलआर-आरएआर42) और जोखिम पर सशर्त मोचन (एलआर-सीआरएआर) पर गणना की गई। दोनों अनुपात अधिकांश एमएफ़ के लिए संबंधित प्रारम्भिक सीमा से काफी अधिक थे। अनुपातों का प्रारम्भिक सीमाओं को उल्लंघन करने के कुछ मामले संबंधित एएमसी द्वारा समय से संबोधित किया गया (चार्ट2.32)।

सारणी 2.9 : एनबीएफ़सी में चलनिधि जोखिम

(Per cent)

अगले एक वर्ष में बहिर्वाह के प्रतिशत के रूप में संचयी असंतुलन	ऋणात्मक असंतुलन वाली एनबीएफ़सी की संख्या		
	बेसलाइन	मध्यम	उच्च
50 प्रतिशत से अधिक	1 (0.06)	1 (0.06)	1 (0.07)
20 से 50 प्रतिशत के बीच	1 (0.77)	4 (1.62)	5 (1.83)
20 प्रतिशत तक	4 (1.06)	21 (11.50)	35 (17.69)

नोट : बेसलाइन परिदृश्य अगले एक वर्ष में अनुमानित बहिर्वाह और अंतर्वाह पर आधारित है: माध्यम जोखिम परिदृश्य अंतर्वाह में 5 प्रतिशत की कमी और बहिर्वाह में 5 प्रतिशत की वृद्धि दिखाता है जबकि उच्च जोखिम परिदृश्य अंतर्वाह में 10 प्रतिशत की कमी और बहिर्वाह में 10 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। कोष्ठक में दिये गए आंकड़े नमूने के आस्ति आकार में प्रतिशत हिस्सेदारी को दर्शाते हैं।
स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी रिटर्न; और कर्मचारियों का अनुमान।

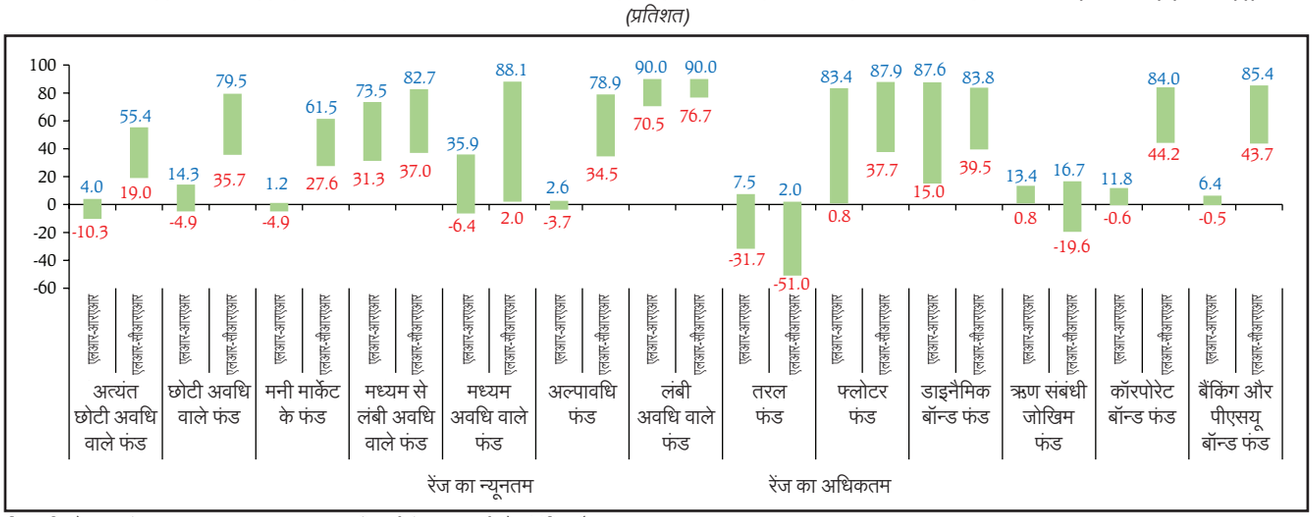
सारणी 2.10: म्यूचुअल फंड की ओपेन-एंडेड डेट योजनाओं का दबाव परीक्षण-सारांश निष्कर्ष – मार्च 2026

	प्रारम्भिक सीमा का उल्लंघन	प्रारम्भिक सीमा के उल्लंघन की सं.	कुल
एएमसी की सं.	28	14	42
योजनाओं की सं	44*	282	326
एयूएम (रु.लाख करोड़)	3.18	13.07	16.25

नोट : निर्धारित सीमा से अधिक ब्याज दर जोखिम, ऋण जोखिम और चलनिधि जोखिम की संख्या क्रमशः 22, 22 और 07 है, जबकि किसी भी निर्धारित प्रारंभिक सीमाओं का उल्लंघन करने वाली अनूठी योजनाओं की कुल संख्या 44 है।
स्रोत : सेबी।

चार्ट 2.32: एएमसी द्वारा एएमएफ़आई निर्धारित सीमाओं से अधिक बनाए गए एलआर-आरएआर और एलआर-सीआरएआर की रेंज (अधिशेष (+)/घाटा (-))

(प्रतिशत)



टिप्पणी: डेटा मार्च 31, 2026 तक एयूएम पर आधारित शीर्ष 10 एएमसी से संबंधित है।
स्रोत: AMFI and सेबी।

[40] म्यूचुअल फंडों के तनाव परीक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली विस्तृत पद्धति अनुलग्नक 1 में दी गई है।

[41] किसी दिये गए विश्वास अंतराल पर संभावित बहिर्वाह का प्रतिनिधित्व करता है।

[42] दिये गए कॉन्फ़िडेंस इंटरवल पर टेल के व्यवहार को दिखाता है।

2.71. मिडकैप और स्मालकैप इक्विटी योजनाओं के दबाव परीक्षण के परिणाम और चलनिधि विश्लेषण से पता चलता है कि अप्रैल 2026 में शीर्ष 5 योजनाओं (एयूएम के संदर्भ में) के लिए पोर्टफोलियो का 25 प्रतिशत परिसमापन करने के दिनों की संख्या मिडकैप योजनाओं के लिए 5 से 23 दिन और स्मालकैप योजनाओं के लिए 7 से 33 दिन थी (सारणी 2.11)।

II.5 समाशोधन निगमों पर दबाव परीक्षण का विश्लेषण[43]

2.72. कोर निपटान गारंटी निधि (कोर एसजीएफ़) के खंड-वार न्यूनतम अपेक्षित कॉर्पस (एमआरसी) का निर्धारण करने के लिए समाशोधन निगमों (सीसी) में दबाव का परीक्षण किया गया। दिसंबर 2025 से मार्च 2026 की अवधि के लिए दबाव परीक्षण के विश्लेषण से पता चला कि अधिकतर क्षेत्रों के लिए असल एमआरसी की आवश्यकता वही रही, सिवाय इक्विटी डेरिवेटिव्स खंड के, जिसमें समाशोधन निगम 2 के लिए आवश्यकता बढ़ गई और कमोडिटी डेरिवेटिव्स खंड के, जिसमें इस समय के दौरान समाशोधन निगम 3 की आवश्यकता बढ़ गई (सारणी 2.12)।

II.6 वित्तीय नेटवर्क और संक्रमण विश्लेषण

2.73. वित्तीय संस्थाओं के बीच अंतरसंबंध निधियन संबंध, चलनिधि असंतुलन और परिपक्वता में परिवर्तन, भुगतान और निपटान प्रक्रिया और जोखिम अंतरण पद्धति से उत्पन्न होते हैं। वित्तीय प्रणाली को एक नेटवर्क के तौर पर देखा जा सकता है, जहां वित्तीय संस्थाएं नोड के तौर पर काम करती हैं और उनके बीच द्विपक्षीय एक्सपोजर इन नोड को जोड़ने वाले लिंक का काम करती है। ये लिंक एक-दूसरे को उधार, निवेश या जमा के रूप में हो सकते हैं, जो धन, चलनिधि, निवेश और जोखिम विविधीकरण के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि ये लिंक संसाधन आवंटन मे सुधार और जोखिम विविधीकरण द्वारा वित्तीय प्रणाली की दक्षता और सहनीयता को बढाता है, वे संकट में जोखिम संचरण और प्रवर्धन के माध्यम बन सकते हैं। इन नेटवर्कों के माध्यम से जोखिमों के प्रसार में बारीकियों को समझना प्रणालीगत जोखिमों के आकलन और वित्तीय एवं समस्त आर्थिक स्थिरता की सुरक्षा के लिए उचित नीति प्रतिक्रियाएं तैयार करने के लिए उपयोगी है।

सारणी 2.11: एमएफ़ मिडकैप और स्मालकैप इक्विटी योजनाओं के दबाव परीक्षण और तरलता विश्लेषण का सारांश

योजना / माह		मिडकैप योजनाएं					स्मालकैप योजनाएं				
		दिसं-25	जन 26	फर-26	मार्च-26	अप्रै 26	दिसं-25	जन 26	फर -26	मार्च-26	अप्रै 26
पोर्टफोलियों का 25 प्रतिशत परिसमापन के लिए दिनों की संख्या- एयूएम के संबंध में शीर्ष 5 योजनाओं के लिए सीमा		5 to 21	5 to 27	4 to 28	4 to 25	5 to 23	11 to 44	12 to 51	12 to 43	13 to 38	7 to 33
संकेन्द्रण-आस्ति पक्ष (धारित एयूएम प्रतिशत में)	लार्जकैप	12.9	13.2	13.6	13.3	13.4	8.5	8.6	8.4	8.2	8.0
	मिडकैप	69.0	68.8	69.2	69.1	69.5	12.7	12.3	12.1	12.0	12.7
	स्मालकैप	12.9	14.1	13.5	13.4	13.4	73.5	73.9	73.6	73.6	73.5
	नकद	5.1	3.9	3.6	4.2	3.7	5.4	5.2	5.9	6.0	5.8

स्रोत : एएमएफ़आई।

[43] दबाव परीक्षणों की विस्तृत पद्धति अनुलग्नक 1 में दी गई है।

सारणी 2.12 : समाशोधन निगमों में दबाव परीक्षण विश्लेषण के आधार पर कोर एसजीएफ़ का न्यूनतम आवश्यक कार्पस

(करोड़ में)

हिस्सा	दिसं-25	जन-26	फर-26	मार्च-26	दिसं-25	जन-26	फर-26	मार्च-26
समाशोधन निगम 1	**औसत दबाव परीक्षण हानि**				**वास्तविक एमआरसी आवश्यकता**			
इक्विटी नगद खंड	106	86	92	105	388	388	388	388
इक्विटी डेरिवेटिव खंड	9,243	8,871	7,196	5,918	10,500	10,500	10,500	10,500
मुद्रा डेरिवेटिव खंड	90	89	78	125	161	161	161	161
ऋण का खंड	-	-	-	-	4	4	4	4
त्रि-दलीय रेपो खंड	-	-	-	-	17	17	17	17
कोमोडिटी डेरिवेटिव खंड	9	8	5	8	15	15	15	15
कुल	**9,448**	**9,055**	**7,371**	**6,156**	**11,085**	**11,085**	**11,085**	**11,085**
समाशोधन निगम 2	**औसत दबाव परीक्षण हानि**				**वास्तविक एमआरसी आवश्यकता**			
इक्विटी नगद खंड	69	72	42	68	194	194	194	194
इक्विटी डेरिवेटिव खंड	715	707	712	618	723	733	733	733
मुद्रा डेरिवेटिव खंड	0	1	1	9	10	10	10	10
ऋण का खंड	0	0	0	0	0	0	0	0
त्रि-दलीय रेपो खंड	0	0	0	0	0	0	0	0
कोमोडिटी डेरिवेटिव खंड	0	0	0	0	14	14	14	14
कुल	**784**	**780**	**755**	**694**	**942**	**951**	**951**	**951**
समाशोधन निगम 3	**औसत दबाव परीक्षण हानि**				**वास्तविक एमआरसी आवश्यकता**			
कोमोडिटी डेरिवेटिव खंड	749	1,046	1,248	804	990	990	990	1,046
समाशोधन निगम 4	**Average Stress Test Loss**				**Actual MRC Requirement**			
कोमोडिटी डेरिवेटिव खंड	49	36	48	55	124	124	124	124

नोट : एक माह M के लिए गणना की गई औसत दबाव परीक्षण हानि, M+2 माह से एमआरसी के रूप में लागू होती है। सेबी ने 27 मार्च 2025 के पत्र के माध्यम से समाशोधन निगम 1 और 2 को करेंसी डेरिवेटिव खंड के न्यूनतम आवश्यक कार्पस (एमआरसी) को रीसेट करने और बाद में इक्विटी डेरिवेटिव खंड के कोर एसजीएफ़ में निधियों को अंतरित करने की अनुमति दी है। तदनुसार, करेंसी डेरिवेटिव खंड के कोर एसजीएफ़ के लिए मई 2024 से देखे गए उच्चतम दबाव हानियों के आधार पर रीसेट किया है, जो रु. 10 करोड़ की न्यूनतम सीमा के अधीन है। इसलिए, करेंसी डेरिवेटिव खंड में कम वॉल्यूम के कारण मई 2025 से समाशोधन निगम 1 के लिए करेंसी डेरिवेटिव खंड के लिए एमआरसी वैल्यू में कमी आई है।
स्रोत : समाशोधन निगम।

II.6.1 वित्तीय प्रणाली नेटवर्क[44]

2.74 नेटवर्क विश्लेषण में 280 वित्तीय संस्थाएं[45] आती है। 280 संस्थाओं का कुल बकाया द्विपक्षीय एक्सपोजर[46] मार्च 2026 में वर्ष -दर-वर्ष 20.1 प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़ा। इसमें से, नेटवर्क में एससीबी का सबसे बड़ा हिस्सा (45.5 प्रतिशत) बना रहा, उसके बाद एनबीएफ़सी (18.5 प्रतिशत) और एआईएफ़आई (13.7 प्रतिशत) का स्थान रहा (चार्ट 2.33 ए और बी)।

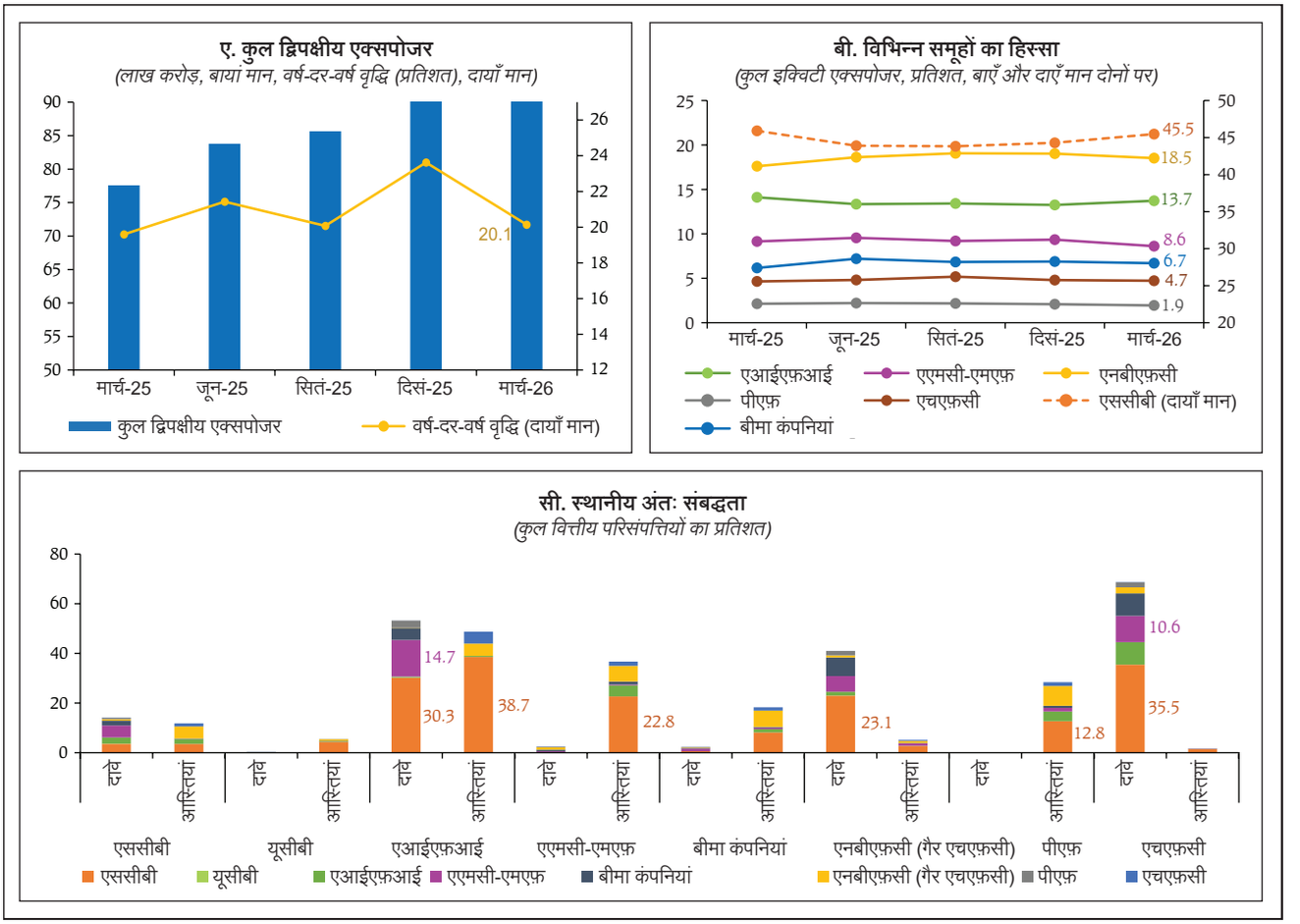
2.75 एनबीएफ़सी, एचएफ़सी, एआईएफ़आई और एएमसी-एमएफ़ के साथ एससीबी की अंतरसंबद्धता मजबूत बनी

[44] विश्लेषण में उपयोग किए गए नेटवर्क मॉडल को प्रोफेसर शेरी मार्कोस (एसेक्स विस्वविद्यालय) और डॉ. सिमोन जियानसांटे (बाथ यूनिवर्सिटी) ने वित्तीय स्थिर विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के सहयोग से विकसित किया है।

[45] निम्न 8 श्रेणियों में विश्लेषण के तहत संस्थाओं की संख्या 280 है- [88 एससीबी, 33 अनुसूचित यूसीबी (एसयूसीबी); 31 एएमसी-एमएफ़ (म्यूचुअल फंड उद्योग के एयूएम के लगभग 99 प्रतिशत को कवर करते हुए); 51 एनबीएफ़सी (एनबीएफ़सी की कुल आस्तियों के लगभग 80 प्रतिशत को कवर करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण जमा लेने वाली और जमा न लेने वाली दोनों कंपनियां); 36 बीमा कंपनियां (क्षेत्र की लगभग 98 प्रतिशत को कवर करती है); 26 एचएफ़सी (कुल एचएफ़सी परिसंपत्तियों के लगभग 94 प्रतिशत को कवर करती है); 10 पीएफ़ और 5 एआईएफ़आई (नाबार्ड, एक्जिम, एनएचबी,सिडबी और एनएबीएफ़आईडी)]

[46] द्विपक्षीय एक्सपोजर में एक ही समूह की संस्थाओं के बीच एक्सपोजर शामिल है। एक्सपोजर 31 मार्च 2026 तक की बकाया स्थिति है, और मोटे तौर पर फंड -आधारित (जैसे मुद्रा बाजार लिखत, जमा, ऋण और अग्रिम, दीर्घकालिक ऋण लिखत और इक्विटी निवेश) और गैर-फंड आधारित एक्सपोजर (जैसे लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी और डेरिवेटिव इन्स्ट्रुमेंट (सीसीआईएल द्वारा गारंटीकृत निपटान को छोड़कर) में विभाजित है।

चार्ट 2.33: वित्तीय प्रणाली में संस्थाओं के बीच द्विपक्षीय एक्सपोजर



टिप्पणी: एक ही समूह के संस्थाओं के बीच एक्सपोजर शामिल है।
स्रोत: विभिन्न विनियामकों के पर्यवेक्षी रिटर्न; और आरबीआई स्टाफ गणना।

रही। इन समूहों में, एआईएफ़आई अपने तुलन पत्र के दोनों परिसंपत्तियों और देनदरियों के माध्यम से एससीबी से बहुत निकटता से जुड़े हुए है (चार्ट 2.33 सी)।

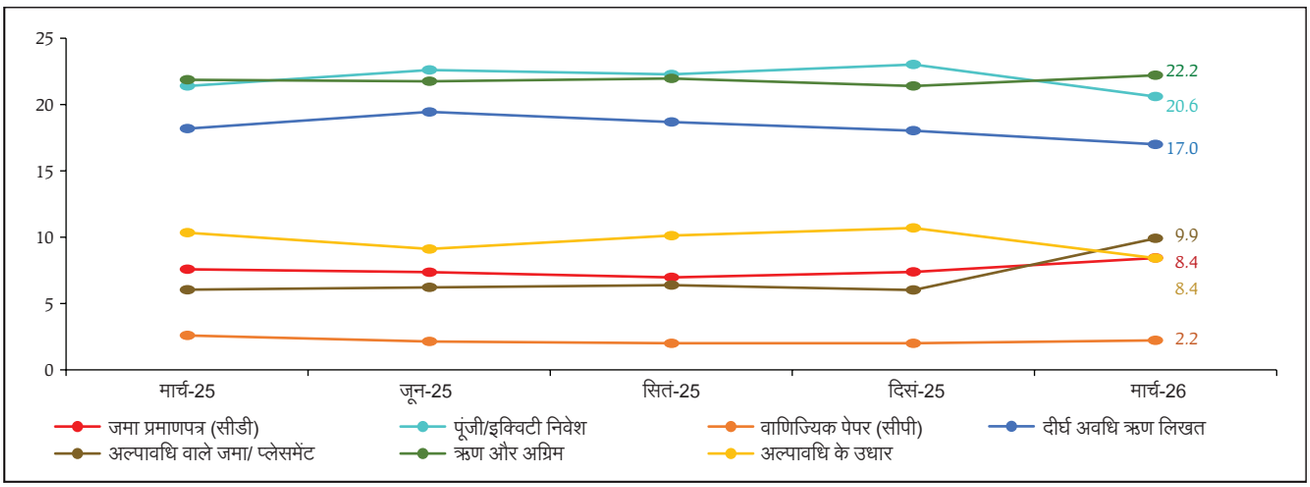
2.76 ऋण और अग्रिम, पूंजी /इक्विटी निवेश और दीर्घकालिक (एलटी) ऋण लिखत वित्तीय नेटवर्क में द्विपक्षीय एक्सपोजर में प्रमुख लिखत बने रहे (चार्ट 2.34)। मार्च 2026 के अंत तक कुल द्विपक्षीय एक्सपोजर में लगभग 59.8 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दीर्घकालिक अवधि (एलटी) निधियन हावी रही। हालांकि, 2025-26 के दौरान निधियन ढांचे में कुछ परिवर्तन हुए हैं, जिसमें लघु अवधि (एसटी) जमाओं के हिस्से बढ़े हैं, जबकि इक्विटी निवेशों, एलटी ऋण लिखत और एसटी ऋणों की हिस्सेदारी में मामूली वृद्धि हुई है।

2.77 अंतर- क्षेत्रीय एक्सपोजर[47] के संदर्भ में, एएमसी-एमएफ़, बीमा कंपनियां और पीएसबी प्रणाली में सबसे बड़े फंड प्रदाता बने रहे, एनबीएफ़सी, पीवीबी और एचएफ़सी फंड के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता थे। बैंक समूहों में, पीएसबी, यूसीबी औए एफ़बी की शुद्ध प्राप्य स्थिति रही जबकि पीवीबी और एसएफ़बी की निवल देय की स्थिति बनी रही (चार्ट 2.35)।

2.78 मार्च 2025 की तुलना में मार्च 2026 में विभिन्न समूहों की निवल प्राप्य और निवल देय स्थिति में वृद्धि हुई

[47] अंतर-क्षेत्रीय एक्सपोजर में वित्तीय प्रणाली में एक ही क्षेत्र की संस्थाओं के बीच लेनदेन शामिल नहीं है।

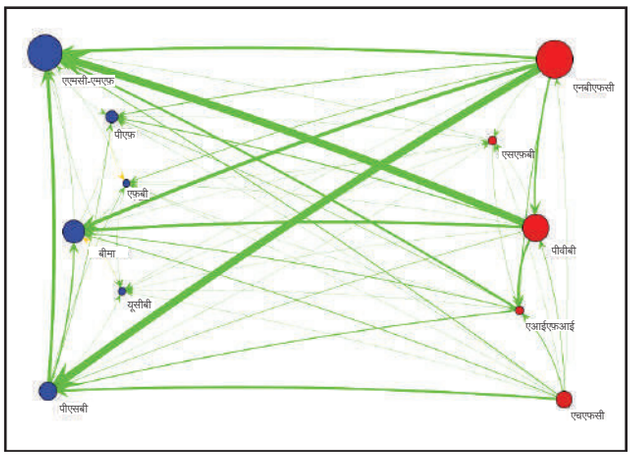
चार्ट 2.34: वित्तीय प्रणाली में संस्थाओं के बीच लिखत-वार एक्सपोजर
(प्रतिशत)



टिप्पणी: एक ही समूह के संस्थाओं के बीच एक्सपोजर शामिल है।
स्रोत: विभिन्न विनियामकों के पर्यवेक्षी रिटर्न; और आरबीआई स्टाफ गणना।

है (चार्ट 2.36 ए)। मार्च 2025 और मार्च 2026 के बीच एनबीएफ़सी और निजी बैंकों द्वारा निवल उधारी और बढ़ गई है, जो अंतर-संस्था निधियन में बढ़ोतरी दर्शाते हैं, साथ ही साथ एएमसी-एमएफ़ और बीमा कंपनियों की भी निवल

चार्ट 2.35: वित्तीय प्रणाली में नेटवर्क प्लॉट – मार्च 2026



टिप्पणी: बुलबुले का आकार प्रणाली (कुल प्राप्य- कुल देय) में प्रत्येक समूह के वित्तीय फुटप्रिंट को दिखाता है, जैसा कि उनके द्विपक्षीय एक्सपोजर मैट्रिक्स से गणना की गई है। यह नोट करें कि इसमें एक ही समूह की संस्थाओं के बीच लेन-देन शामिल नहीं है। लाल घेरे शुद्ध देय (शुद्ध अदाकर्ता) संस्था है और नीले वाले शुद्ध प्राप्य संस्था (शुद्ध प्राप्तकर्ता) हैं। तीर की चौड़ाई वित्तीय मूल्य/ अंतःसंबंध की मात्रा को दर्शाती है।
स्रोत: विभिन्न विनियामकों के पर्यवेक्षी रिटर्न; और आरबीआई स्टाफ गणना।

प्राप्य स्थिति में विस्तार हुआ है। समय के साथ सकल वित्तीय प्रणाली के जोखिम में शेयरों के संदर्भ में, वित्तीय प्रणाली में शुद्ध प्राप्य/देय राशि कुछ प्रमुख क्षेत्रों में केंद्रित रही, जिसमें एएमसी-एमएफ, बीमा कंपनियां, पीएसबी और पीएफ निधियों के शुद्ध प्रदाता बने रहे, जबकि एनबीएफसी, निजी बैंक और एचएफसी सबसे बड़े शुद्ध उधारकर्ता बने रहे (चार्ट 2.36 बी), हालांकि श्रेणियों में कुल सकल जोखिम सितंबर 2018 में रु. 32.45 लाख करोड़ से बढ़कर मार्च 2026 में रु. 93.2 लाख करोड़ हो गया।

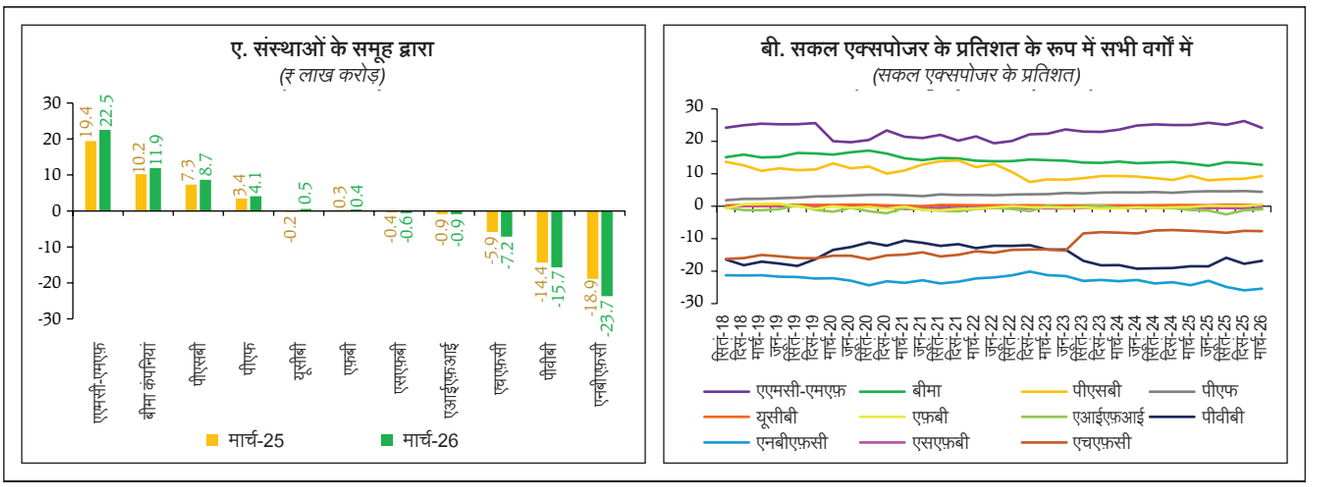
ए. अंतर-बैंक बाज़ार

2.79 बैंकिंग प्रणाली की कुल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में अंतर-बैंक एक्सपोजर पिछली दो तिमाहियों में मामूली बढ़ोतरी हुई और 3.4 प्रतिशत पर रहा। यह बढ़ोतरी मुख्यतः फंड आधारित एक्सपोजर[48] से बढ़ी, जबकि इस अवधि में गैर- फंड आधारित एक्सपोजर[49] मुख्यता स्थिर रहे (चार्ट 2.37 ए)।

[48] निधिआधारित एक्सपोजर में अल्पकालिक एक्सपोजर (सात श्रेणियों में डेटा को कवर करते हुए – रेपो (गैर-केंद्रीय रूप से समाशोधित); कॉल मनी; वाणिज्यिक पत्र; जमा प्रमाण पत्र, अल्पकालिक ऋण, अल्पकालिक जमा और अन्य अल्पकालिक एक्सपोजर) और दीर्घकालिक एक्सपोजर (पाँच श्रेणियों में डेटा को कवर करते हुए- इक्विटी, दीर्घकालिक ऋण, दीर्घकालिक कर्ज, दीर्घकालिक जमा और अन्य दीर्घकालिक देनदारियां)।

[49] गैर-निधि आधारित एक्सपोजर में शामिल है- बकाया बैंक गारंटी, बकाया ऋण पत्र और डेरिवेटिव बाज़ार में घनात्मक मार्क-टू-मार्केट स्थिति (उन एक्सपोजर को छोड़कर जिनके लिए सीसीआईएल द्वारा गारंटी दी जाती है)।

चार्ट 2.36: निवल प्राप्य (+)/देय(-)



टिप्पणी: समान समूह के संस्थाओं के लेन-देन शामिल नहीं है।
स्रोत: विभिन्न विनियामकों के पर्यवेक्षी रिटर्न; और आरबीआई स्टाफ गणना।

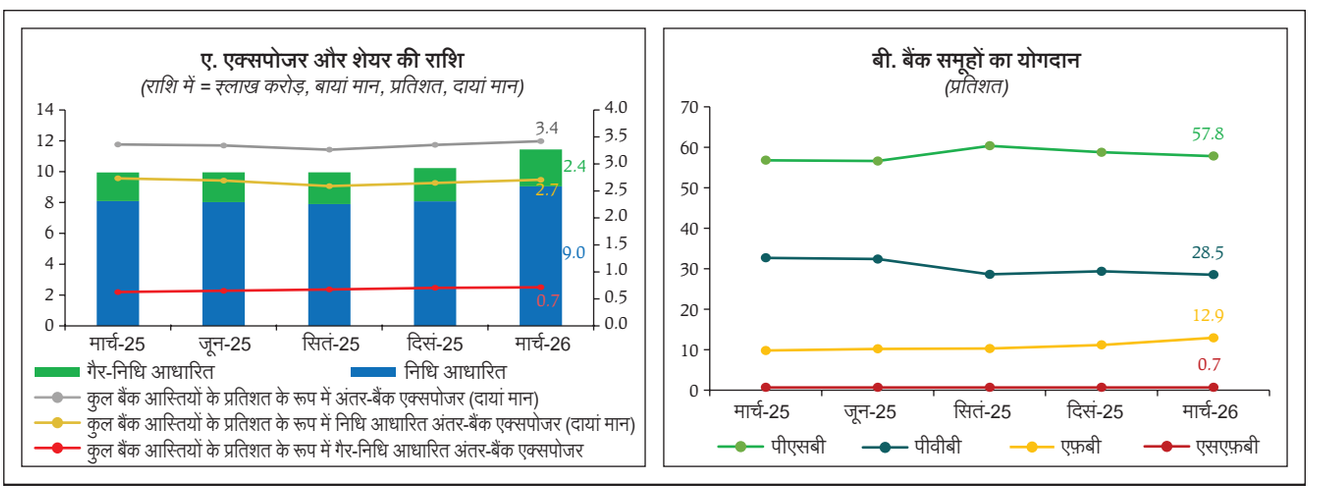
2.80 मार्च 2026 को समाप्त तिमाही के दौरान अंतर-बैंक बाज़ार में पीएसबी का कुल 57.8 प्रतिशत होकर अंतर-बैंक बाज़ार में प्रभुत्व जारी रहा, हाल के तिमाही में एफ़बी के हिस्से में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखी गई (चार्ट 2.37बी)।

2.81 2025-26 के दौरान अल्पकालिक अंतर-बैंक निधियन की संरचना में मामूली बदलाव आया, जिसमें एसटी जमा की हिस्सेदारी में वृद्धि और सीडी में तदनुरूप गिरावट देखी गई। एसटी जमा अल्पकालिक निधियन का प्रमुख स्रोत बना रहा, जबकि एसटी ऋण लगातार दूसरे सबसे बड़े घटक बने रहे। दीर्घकालिक अंतर-बैंक निधियन की संरचना पर एलटी ऋण और एलटी ऋण लिखतों का प्रभुत्व जारी रहा, जो एक साथ एलटी फंड का एक बड़ा हिस्सा था (चार्ट 2.38 ए और बी)।

बी. अंतर बैंक बाजार : नेटवर्क संरचना और कनेक्टिविटी

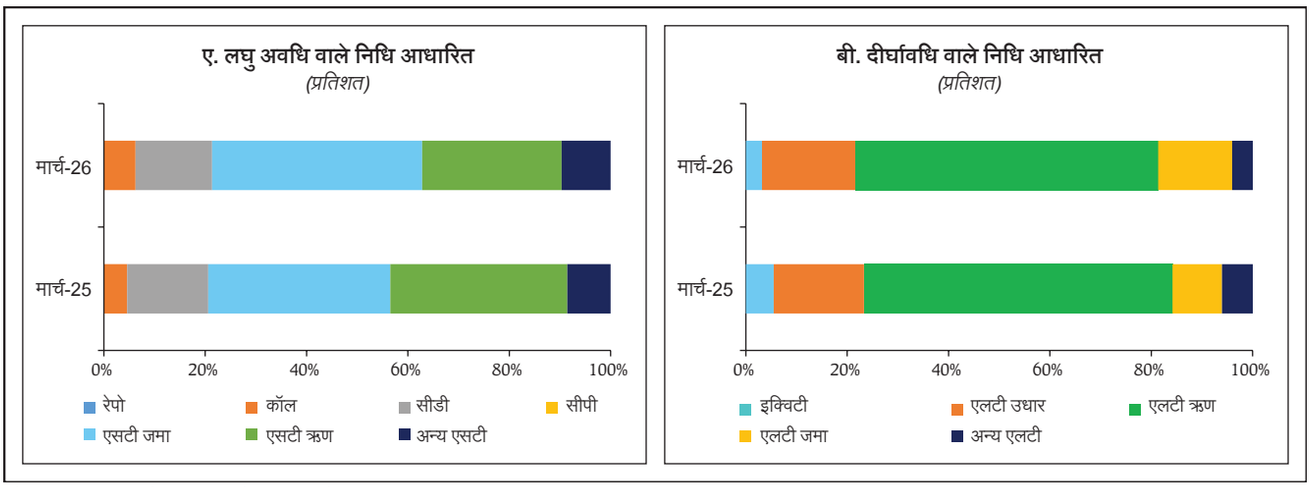
2.82 बैंकिंग नेटवर्क (एससीबी और एसयूसीबी) के अंतर्गत अंतर सहबद्धता विषम रही, जिसमें केवल कुछ एससीबी (कोर और मिड नेटवर्क में देखें) के पास अधिकांश लिंक थे, जैसा कि विशिष्ट कोर-परिधि नेटवर्क संरचना द्वारा परिलक्षित होता

चार्ट 2.37: अंतर-बैंक बाज़ार



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी रिटर्न; और कर्मचारियों का अनुमान।

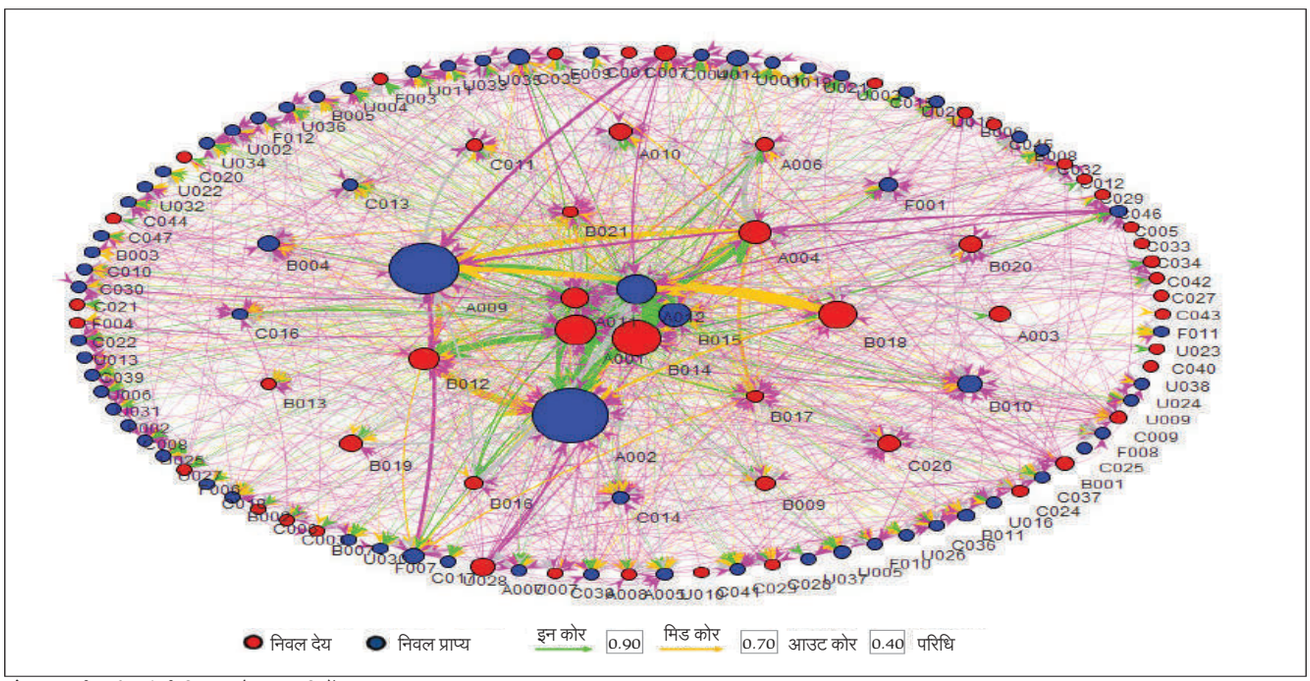
चार्ट 2.38: निधि आधारित अंतर बैंक बाज़ार की संरचना



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी रिटर्न; और कर्मचारियों का अनुमान।

है[50] [51]। मार्च 2026 तक, पाँच बैंक सबसे भीतरी कोर में थे और सात बैंक मिड-कोर सर्कल में थे जिसमें पीएसबी और पीवीबी शामिल थे। बैंकिंग नेटवर्क के परिधि मुख्यतया एफ़बी, यूसीबी और एसएफ़बी द्वारा अधिकृत हैं (चार्ट 2.39)।

चार्ट 2.39: भारतीय बैंकिंग प्रणाली (एससीबी+एसयूसीबी) का नेटवर्क ढांचा -मार्च 2026



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी रिटर्न; और कर्मचारियों का अनुमान।

[50] बैंकिंग प्रणाली के नेटवर्क का आरेखीय प्रतिनिधित्व एक स्तरीय संरचना का है, जिसमें विभिन्न बैंकों के पास नेटवर्क में दूसरों के साथ कनेक्टिविटी की अलग-अलग डिग्री या स्तर होते हैं। सबसे अधिक जुड़े हुए बैंक सबसे आंतरिक कोर (नेटवर्क आरेख के केंद्र में) में है। बैंकों को तब मध्य-कोर, बाहरी-कोर और परिधि (आरेख के केंद्र के चारों ओर संकेंद्रित वृत्त) में रखा जाता है, जो उनके सापेक्ष कनेक्टिविटी के स्तर पर आधारित होता है। टियर्ड नेटवर्क आरेख में लिंक की रंग कोडिंग नेटवर्क में विभिन्न स्तरों से उधार का प्रतिनिधित्व करती है (उदाहरण के लिए, हरे रंग के लिंक आंतरिक कोर में बैंकों से उधार का प्रतिनिधित्व करते हैं)। प्रत्येक बैंक एक बैंक का प्रतिनिधित्व करती है और उन्हें सिस्टम में अन्य सभी बैंकों की तुलना में उनकी निवल स्थिति के अनुसार भारित किया जाता है। प्रत्येक बैंक को जोड़ने वाली लाइनों को बकाया एक्सपोजर के आधार पर भारित किया जाता है।

[51] इस विश्लेषण के लिए 77 एससीबी, 11 एसएफ़बी और 33 एसयूसीबी पर विचार किया गया था।

2.83 कनेक्टविटी अनुपात[52] बैंकों के (एससीबी और एसयूसीबी) मध्य अंतः संबंध की डिग्री के रूप में परिभाषित और मार्च 2026 के अंत तक क्लस्टर गुणांक[53] के हिसाब से स्थानीय परस्पर संबद्धता भी कुछ कम हो गई (चार्ट 2.40)।

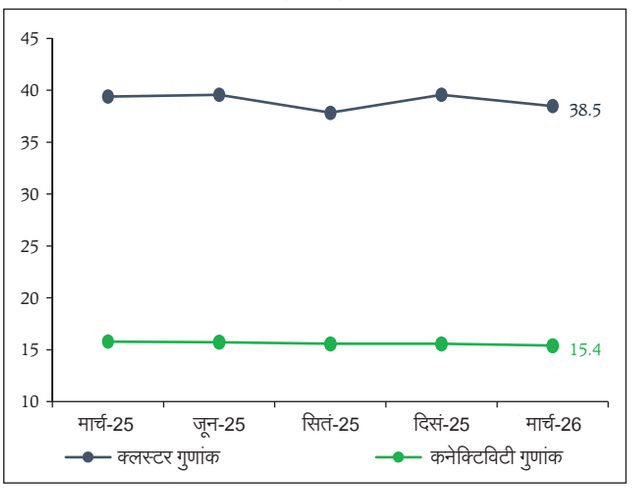
सी. एएमसी-एमएफ़ का एक्सपोजर

2.84 सबसे बड़े फंड प्रदाता, एएमसी-एमएफ़ की सकल प्राप्तियां सितंबर 2025 में रु. 23.27 लाख करोड़ से बढ़कर मार्च 2026 में रु. 23.95 लाख करोड़ हो गई (जैसा कि दिसंबर 2025 एफ़एसआर में रिपोर्ट किया गया है), जबकि उनके सकल देय राशि 1.46 करोड़ रुपए थी। एससीबी (मुख्य रूप से पीवीबी) एएमसी-एमएफ़ से धन के प्रमुख प्राप्तकर्ता बने रहे, इसके बाद एनबीएफ़सी,एआईएफ़आई और एचएफ़सी का स्थान रहा (चार्ट 2.41)।

डी. बीमा कंपनियों का एक्सपोजर

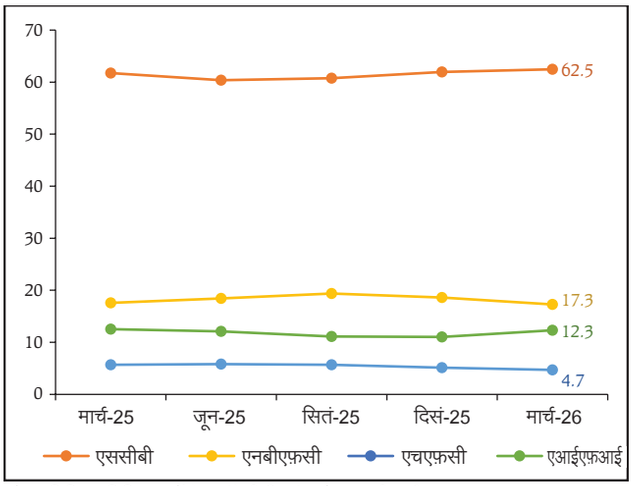
2.85 रु. 1.56 लाख करोड़ की सकल देयताओं और रु. 13.44 लाख करोड़ के सकल प्राप्तियों के साथ, मार्च 2026 के अंत में बीमा कंपनियां वित्तीय प्रणाली के लिए धन की दूसरी सबसे बड़ी निवल प्रदाता थी। एससीबी (मुख्यतया पीवीबी) उनके फंड के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता थे, इसके बाद एनबीएफ़सी और एचएफ़सी थे (चार्ट 2.42)।

चार्ट 2.40: बैंकिंग प्रणाली (एससीबी) के कनेक्टिविटी सांख्यिकी
(प्रतिशत)



स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी रिटर्न; और कर्मचारियों का अनुमान।

चार्ट 2.41: वित्तीय प्रणाली से एएमसी-एमएफ़ को सकल प्राप्य – शीर्ष 4 उधार समूहों का हिस्सा
(प्रतिशत)

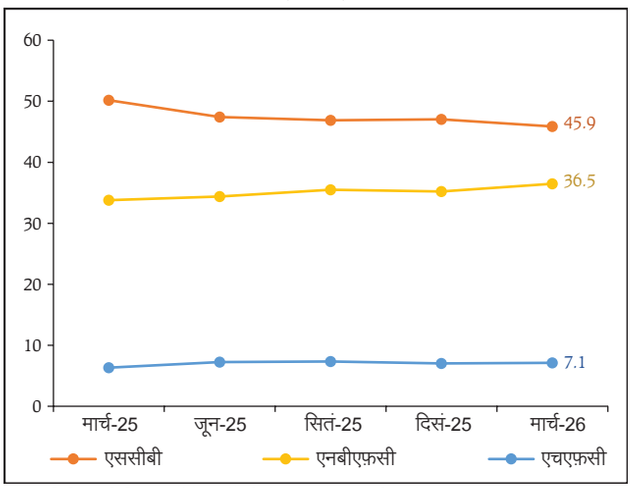


स्रोत: विभिन्न विनियामकों के पर्यवेक्षी रिटर्न; और आरबीआई स्टाफ गणना।

ई. एनबीएफ़सी में एक्सपोजर (गैर-एचएफ़सी)

2.86 मार्च 2026 के अंत तक सकल प्राप्तियों के मुक़ाबले रु. 26.57 लाख करोड़ के सकल देय की तुलना में रु. 2.88 लाख करोड़ की सकल प्राप्तियों के साथ एनबीएफ़सी

चार्ट 2.42: वित्तीय प्रणाली से बीमा कंपनियों को सकल प्राप्य – शीर्ष 3 उधार समूहों का हिस्सा
(प्रतिशत)

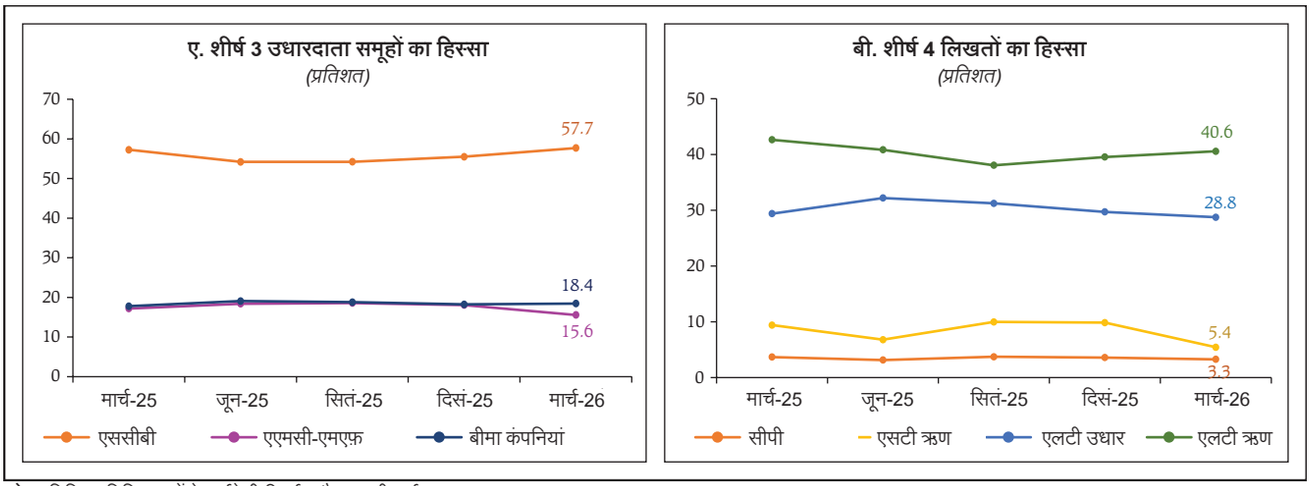


स्रोत: विभिन्न विनियामकों के पर्यवेक्षी रिटर्न; और आरबीआई स्टाफ गणना।

[52] कनेक्टिविटी अनुपात एक पूर्ण नेटवर्क में सभी संभावित लिंक के सापेक्ष नोड्स के बीच लिंक की वास्तविक संख्या को मापता है।

[53] क्लस्टर गुणांक: नेटवर्क में क्लस्टरिंग मापता है कि प्रत्येक नोड कैसे परस्पर जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से, इस बात की संभावना बढ़ जानी चाहिए कि नोड के दो पड़ोसी (वित्तीय नेटवर्क के मामले में बैंकों के समकक्ष) भी स्वयं पड़ोसी है। नेटवर्क के लिए एक उच्च क्लस्टर गुणांक सिस्टम में प्रचलित उच्च स्थानीय अंतर्संबंध से मेल खाता है।

चार्ट 2.43: वित्तीय प्रणाली से एनबीएफ़सी को सकल देय



स्रोत: विभिन्न विनियामकों के पर्यवेक्षी रिटर्न; और आरबीआई स्टाफ गणना।

(गैर-एचएफ़सी) वित्तीय प्रणाली से धन के सबसे बड़े निवल उधारकर्ता थे। उनके आधे से अधिक फंड एससीबी से प्राप्त होते रहे, इसके बाद बीमा कंपनियां और एएमसी-एमएफ़ का स्थान रहा (चार्ट 2.43 ए) एलटी लोन और एलटी ऋण एनबीएफ़सी (गैर-एचएफ़सी) के लिए वित्त पोषण का पसंदीदा तरीका बना रहा (चार्ट 2.43 बी)।

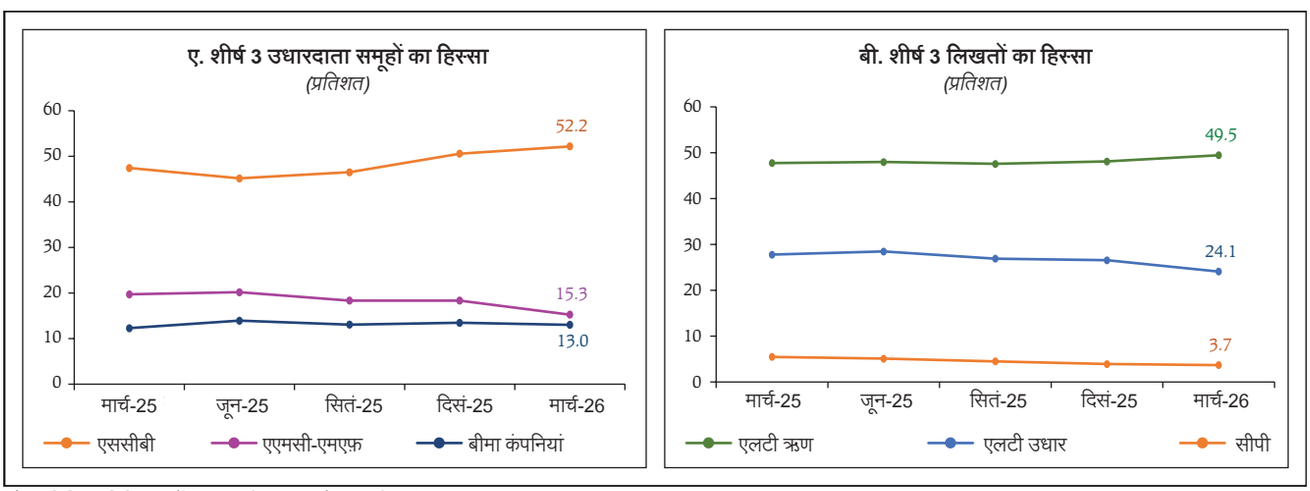
एफ़. एचएफ़सी में एक्सपोजर

2.87 एचएफ़सी, तीसरे सबसे बड़े निवल उधारकर्ता के पास मार्च 2026 में रु.0.19 लाख करोड़ की सकल प्राप्तियों के सापेक्ष रु.7.35 लाख करोड़ की सकला देयताएँ थी। एससीबी, एएमसी-एमएफ़ और बीमा कंपनियों द्वारा बढ़े हिस्से के साथ फंड का सबसे बड़ा प्रदाता बना रहा। एचएफ़सी के धन का लगभग 73.6 प्रतिशत एलटी ऋण और एलटी ऋण लिखतों के माध्यम से प्राप्त किया गया था (चार्ट 2.44 ए और बी)।

जी. एआईएफ़आई का एक्सपोजर

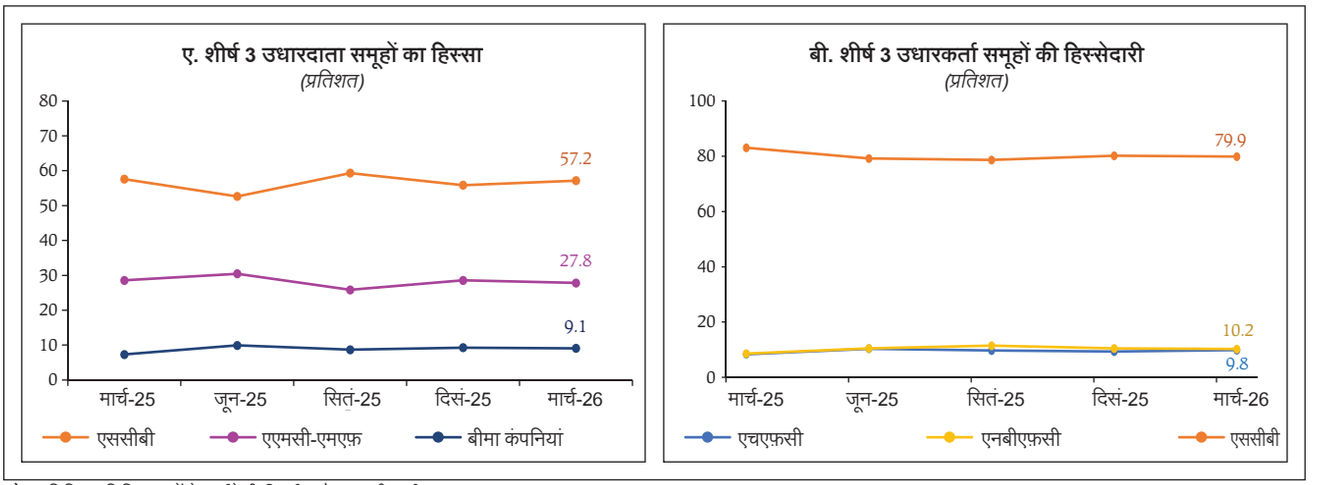
2.88 क्रमशः रु. 10.61 लाख करोड़ और रु. 9.71 लाख करोड़ वाले सकल देयताओं और प्राप्तियों के साथ एआईएफ़आई वित्तीय प्रणाली में सक्रिय उधारकर्ता और ऋणदाता दोनों थे और मार्च 2026 में लगभग रु. 0.9 लाख करोड़ निवल देय था। जबकि एआईएफ़आई ने मुख्य रूप से

चार्ट 2.44: वित्तीय प्रणाली को एचएफ़सी का सकल देय



स्रोत: विभिन्न विनियामकों के पर्यवेक्षी रिटर्न; और आरबीआई स्टाफ गणना।

चार्ट 2.45: वित्तीय प्रणाली को एआईएफ़आई का सकल देय और प्राप्य



स्रोत: विभिन्न विनियामकों के पर्यवेक्षी रिटर्न; और आरबीआई स्टाफ गणना।

एससीबी, एएमसी-एमएफ़ और बीमा कंपनियों से धन जुटाया , उन्होंने मुख्य रूप से एससीबी को उधार दिया (मार्च 2026 में 79.9 प्रतिशत) (चार्ट 2.45 ए और बी)।

II. 6.2 संक्रमण विश्लेषण[54]

2.89 संक्रमण विश्लेषण विभिन्न वित्तीय संस्थानों के प्रणालीगत महत्व का अनुमान लगाने के लिए नेटवर्क प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है। ऋणशोधन क्षमता और/या चलनिधि संबंधी हानियों के कारण बैंक की विफलता से बैंकिंग प्रणाली के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली पर भी संक्रामक प्रभाव पड़ेगा। बैंक की विफलता उसकी प्रारंभिक पूंजी और चलनिधि की स्थिति के साथ-साथ शेष बैंकिंग प्रणाली के साथ उसके अंतः संबद्धता की संख्या, प्रकृति (चाहे वह उधारदाता हो या उधारकर्ता) और परिमाण पर निर्भर करेगी।

ए. संयुक्त ऋणशोधन क्षमता[55]- बैंक विफलता के कारण अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पर चलनिधि[56] संक्रमण प्रभाव

2.90 मार्च 2026 के अंत में बैंकिंग नेटवर्क का संक्रमण विश्लेषण इंगित करता है कि यदि संक्रमण की हानि का कारण बनने की अधिकतम क्षमता वाला बैंक विफल हो जाता है, तो इससे एससीबी की कुल टियर I पूंजी के 2.2 प्रतिशत (सितंबर 2025 में 2.3 प्रतिशत की तुलना में) की ऋण शोधन क्षमता हानि और बैंकिंग प्रणाली के कुल एचक्यूएलए के 0.7 प्रतिशत (सितंबर 2025 में 0.4 प्रतिशत की तुलना में) की चलनिधि हानि होगी (सारणी 2.13)।

2.91 इसके अलावा, एक ही समय में प्रभावशाली और कमजोर बैंकों की पहचान के लिए विकसित प्रभाव और भेद्यता मेट्रिक्स के संदर्भ में, मार्च 2026 तक दो बैंकों को प्रभावशाली और कमजोर दोनों पाया गया।

सारणी 2.13 : बैंक की विफलता के कारण संक्रमण संबंधी हानियां-मार्च 2026

बैंक का नाम	Solvency Losses as a percentage of Tier I Capital of the Banking System	Liquidity Losses as a percentage of HQLA	Number of Banks Defaulting due to Solvency	Number of Banks Defaulting due to Liquidity
बैंक 1	2.2	0.7	0	1
बैंक 2	2.0	0.3	0	0
बैंक 3	1.8	0.1	0	0
बैंक 4	1.7	0.3	0	0
बैंक 5	1.4	0.0	0	0

नोट : बैंकिंग प्रणाली को हुई ऋण-शोधन क्षमता संबंधी हानियों के आधार पर शीर्ष पाँच 'ट्रिगर बैंकों' का चयन किया गया है।
स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां; और स्टाफ अनुमान।

[54] संक्रमण विश्लेषण में, संस्थाओं के बीच इक्विटी एक्सपोजर से द्विपक्षीय एक्सपोजर को बाहर निकाल दिया जाता है।

[55] ऋणशोधन क्षमता विश्लेषण में, एक या अधिक उधारकर्ता बैंकों की काल्पनिक विफलता के कारण डॉमिनो इफेक्ट से बैंकिंग प्रणाली को होने वाले कुल नुकसान का आकलन किया जाता है। संक्रमण विश्लेषण के लिए विफलता मानदंड के रूप में टियर 1 पूंजी का 7 प्रतिशत से नीचे गिरना माना गया है।

[56] चलनिधि संक्रमण विश्लेषण में, किसी बैंक को तब विफल माना जाता है जब उसकी चल आस्तियां किसी बड़े निवल ऋणदाता की काल्पनिक विफलता के कारण उत्पन्न चलनिधि संकट से निपटने के लिए पर्याप्त न हो। चल आस्तियों का मापन इस प्रकार किया जाता है: एनडीटीएल का 18 प्रतिशत + अतिरिक्त एसएलआर+अतिरिक्त सीआरआर।

बी. एनबीएफ़सी/एचएफ़सी की विफलता के कारण एससीबी पर ऋण-शोधन क्षमता संक्रमण का प्रभाव

2.92 बैंकों से काफी अधिक मात्रा में निधियन प्राप्त करने वाले एनबीएफ़सी (गैर-एचएफ़सी) और एचएफ़सी वित्तीय प्रणाली के सबसे बड़े उधारकर्ता हैं। अतएव उक्त में से किसी भी एनबीएफ़सी या एचएफ़सी की विफलता से उनके उधारदाताओं को ऋण-शोधन-क्षमता आघात पहुंचेगा, जिसका संक्रमण से प्रसार हो सकता है।

2.93 मार्च 2026 के अंत तक बैंकिंग प्रणाली को ऋण-शोधन क्षमता हानि पहुंचाने की सबसे अधिक क्षमता रखने वाली एनबीएफ़सी की परिकल्पित विफलता के कारण बैंकिंग प्रणाली की टियर 1 पूंजी 3.1 प्रतिशत (सितंबर 2025 में 3.0 प्रतिशत) कम हो जाएगी और ऐसी शीर्ष एचएफ़सी की परिकल्पित विफलता से बैंकिंग प्रणाली की टियर 1 पूंजी 3.6 प्रतिशत (सितंबर 2025 में 3.6 प्रतिशत) कम हो जाएगी (सारणी 2.14 और 2.15)। हालांकि, दोनों ही मामलों में, इससे किसी भी बैंक को विनियामकीय न्यूनतम पूंजी बनाए रखने में कमी नहीं आएगी और संक्रमण का कोई प्रभाव नही होगा।

सारणी 2.14 : एनबीएफ़सी की विफलता के कारण संक्रमण संबंधी हानियां-मार्च 2026

नाम	बैंकिंग प्रणाली की टियर 1 पूंजी के प्रतिशत के रूप में ऋण-शोधन क्षमता के कारण हानि	ऋण-शोधन क्षमता के कारण चूक करने वाले बैंक की संख्या
एनबीएफ़सी 1	3.1	0
एनबीएफ़सी 2	2.9	0
एनबीएफ़सी 3	2.5	0
एनबीएफ़सी 4	2.1	0
एनबीएफ़सी 5	1.8	0

नोट: केवल निजी एनबीएफसी पर विचार किया जाता है। बैंकिंग प्रणाली को हुई ऋण-शोधन क्षमता संबंधी हानियों के आधार पर शीर्ष पाँच 'ट्रिगर एनबीएफ़सी' का चयन किया गया है।
स्रोत: आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सारणी 2.15: एचएफ़सी विफलता के कारण संक्रमण संबंधी हानियां-मार्च 2026

नाम	बैंकिंग प्रणाली की टियर 1 पूंजी के प्रतिशत के रूप में ऋण-शोधन क्षमता के कारण हानि	ऋण-शोधन क्षमता के कारण चूक करने वाले बैंक की संख्या
एचएफ़सी 1	3.6	0
एचएफ़सी2	1.7	0
एचएफ़सी 3	1.2	0
एचएफ़सी4	1.0	0
एचएफ़सी5	0.6	0

नोट : बैंकिंग प्रणाली को हुई ऋण-शोधन क्षमता संबंधी हानियों के आधार पर शीर्ष पाँच 'ट्रिगर एचएफ़सी' का चयन किया गया है।
स्रोत : आरबीआई पर्यवेक्षी विवरणियां; और स्टाफ अनुमान।

सी. एससीबी पर समष्टि आर्थिक आघातों के बाद ऋण-शोधन क्षमता संक्रमण का प्रभाव

2.94 समष्टि दबाव परीक्षण[57] के तहत माने गए परिकल्पित दबाव परिदृश्यों के अनुप्रयोग से समग्र स्तर पर पूंजीगत हानि क्रमशः बेसलाइन, प्रतिकूल परिदृश्य 1 और प्रतिकूल परिदृश्य 2 के तहत टियर 1 पूंजी के 8.3 प्रतिशत, 22.7 प्रतिशत और 23.7 प्रतिशत पर रही। प्रतिकूल परिदृश्य 2, कोई बैंक 7 प्रतिशत की न्यूनतम टियर 1 पूंजी अनुपात बनाए को रखने में सक्षम नहीं होगा। परिणामस्वरूप, संक्रमण के कारण बैंकिंग तंत्र को टियर 1 पूँजी के 0.23 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त अधिदेयता हानि उठानी पड़ेगी (समष्टिगत आघातों के कारण पूँजी की प्रारंभिक हानि के अतिरिक्त); तथापि, इसके फलस्वरूप कोई और बैंक विफल नहीं होगा। (चार्ट 2.46 ए और बी)।

II.7 बीमा क्षेत्र

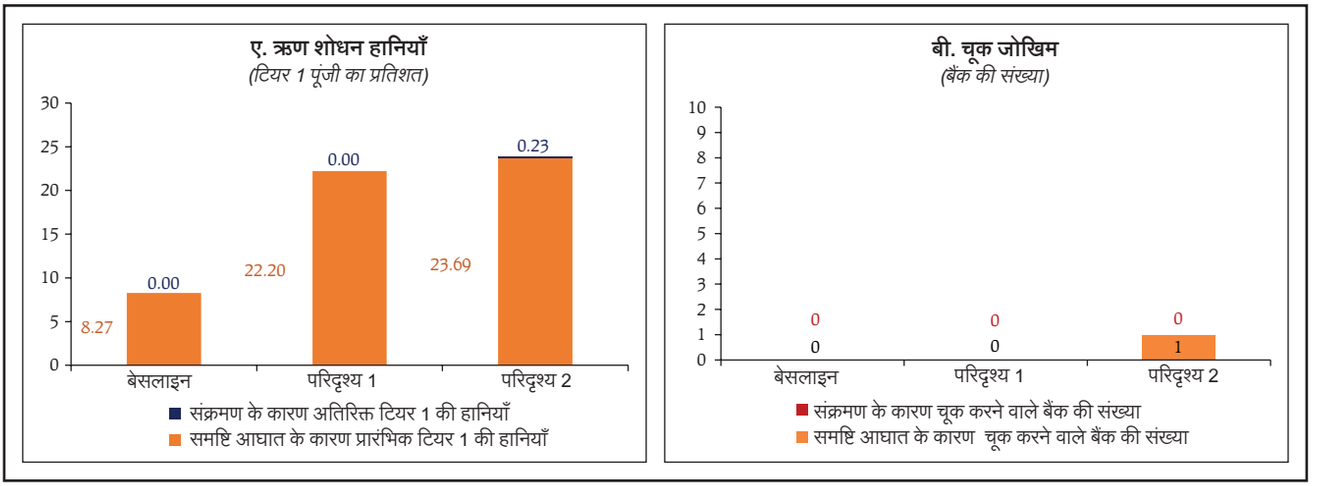
2.95 भारत का बीमा क्षेत्र अपने विशाल आकार, निवेश के प्रभाव और घरेलू पूंजी बाजारों के साथ परस्पर जुड़ाव के कारण व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बना हुआ है।

[57] कंटैजियन एनालिसिस (संक्रमण विश्लेषण) में मैक्रो-स्ट्रेस टेस्ट के नतीजों का इस्तेमाल किया गया और ये अनुमान लगाए गए:

(ए) व्यापक परिदृश्य के तहत अनुमानित हानि (जिसे मार्च 2026 के वास्तविक मूल्य के सापेक्ष मार्च 2028 में अनुमानित टियर I कैपिटल में कमी के तौर पर प्रतिशत में गणना किया गया) को मार्च 2026 की पूंजी स्थिति पर लागू किया गया। इसमें यह माना गया कि मार्च 2026 और मार्च 2028, दोनों के लिए तुलन पत्र संरचना आनुपातिक रूप से एक जैसी है।

(बी) यह माना गया कि वित्तीय संस्थाओं के बीच आपसी एक्सपोज़र (लेन-देन का जोखिम) मार्च 2026 और मार्च 2028 के लिए एक जैसा है।

चार्ट 2.46: समष्टि आर्थिक आघातों का संक्रामक प्रभाव (ऋण -शोधन संक्रामक)



स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणियां एवं स्टाफ द्वारा गणनाएं।

II.7.1 आकार और संरचना

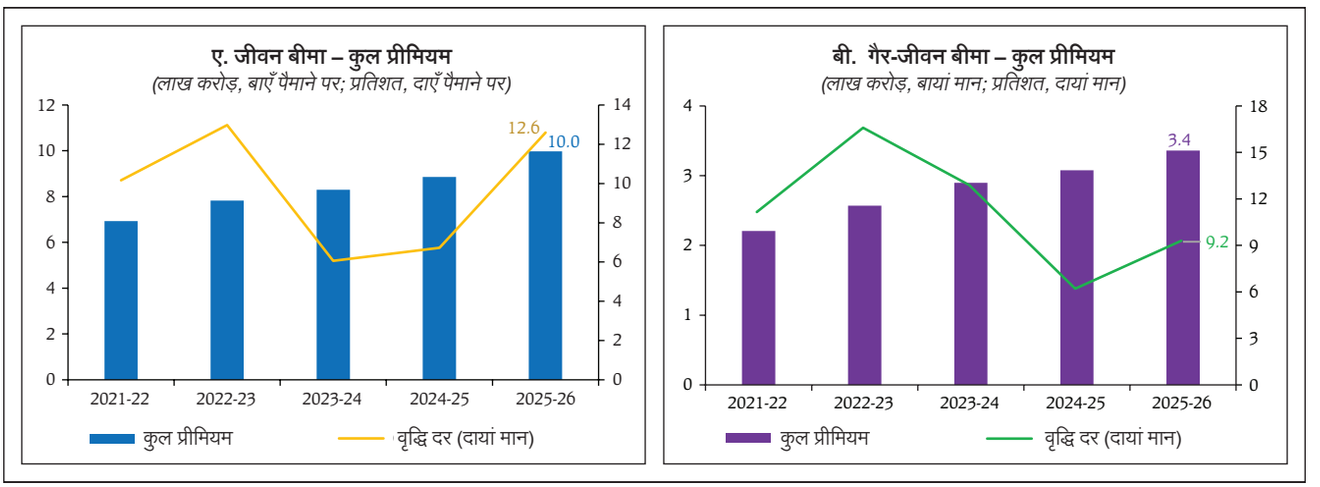
II.7.1.1 प्रीमियम प्रोफ़ाइल

2.96 31 मार्च 2026 तक कुल प्रीमियम आय ₹ 13.3 लाख करोड़ तक पहुंच गई, जो 2024-25 की तुलना में 11.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करती है । 2021-22 से 2025-26 तक का सीएजीआर 9.9 प्रतिशत रहा। जीवन बीमा प्रीमियम ₹ 10 लाख करोड़ रहा, जबकि सामान्य बीमा प्रीमियम ₹ 3.4 लाख करोड़ तक पहुंच गया (चार्ट 2.47 ए और बी)। प्रीमियम आधार में निरंतर विस्तार से परिचालन संबंधी आघातों को सहन करने और दीर्घकालिक पॉलिसीधारक दायित्वों को पूरा करने के क्षेत्र की क्षमता सुदृढ़ होती है, लेकिन इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी दिवालियापन या चलनिधि आघात का प्रणालीगत महत्व भी बढ़ जाता है।

II.7.1.2 बाज़ार हिस्सेदारी

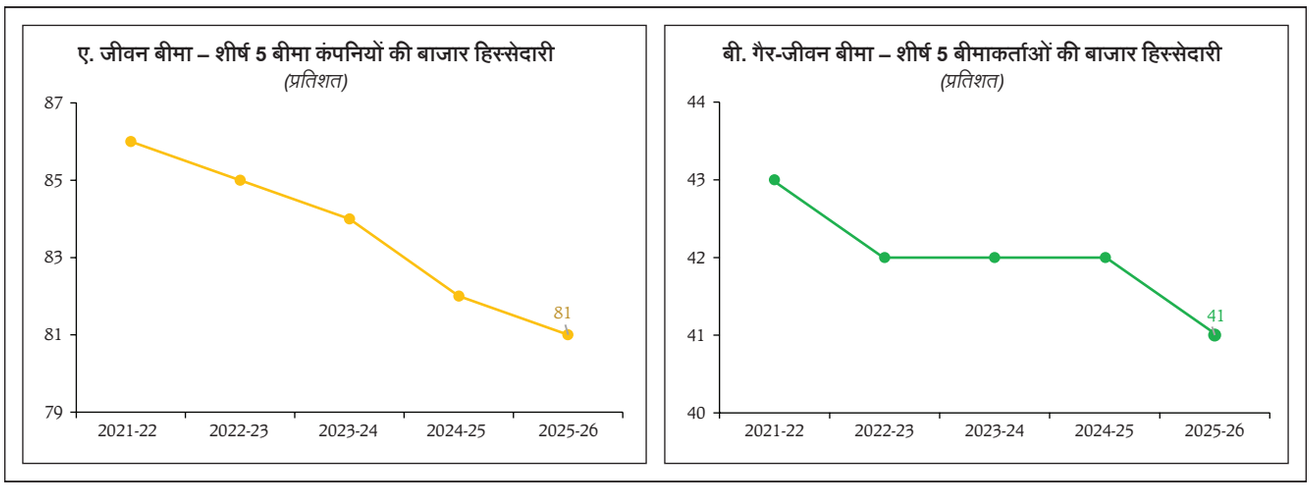
2.97 जीवन बीमा खंड अत्यधिक केंद्रित है, जिसमें 2025-26 (चार्ट 2.48 ए) में कुल प्रीमियम का 81 प्रतिशत शीर्ष पांच बीमाकर्ता के पास है। सामान्य बीमा क्षेत्र तुलनात्मक रूप से अधिक विविध है, जिसमें शीर्ष पांच बीमाकर्ता 2025-26 में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम का 41 प्रतिशत हैं, जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धी वितरण का संकेत देते हैं (चार्ट 2.48 बी)।

चार्ट 2.47 कुल प्रीमियम



नोट : 2025-26 के लिए डाटा अनंतिम है।
स्रोत : आईआरडीएआई

चार्ट 2.48: बीमा क्षेत्र



नोट : 2025-26 के लिए डाटा अनंतिम है।
स्त्रोत : आईआरडीएआई।

II.7.1.3 प्रबंधनाधीन आस्तियां(एयूएम)

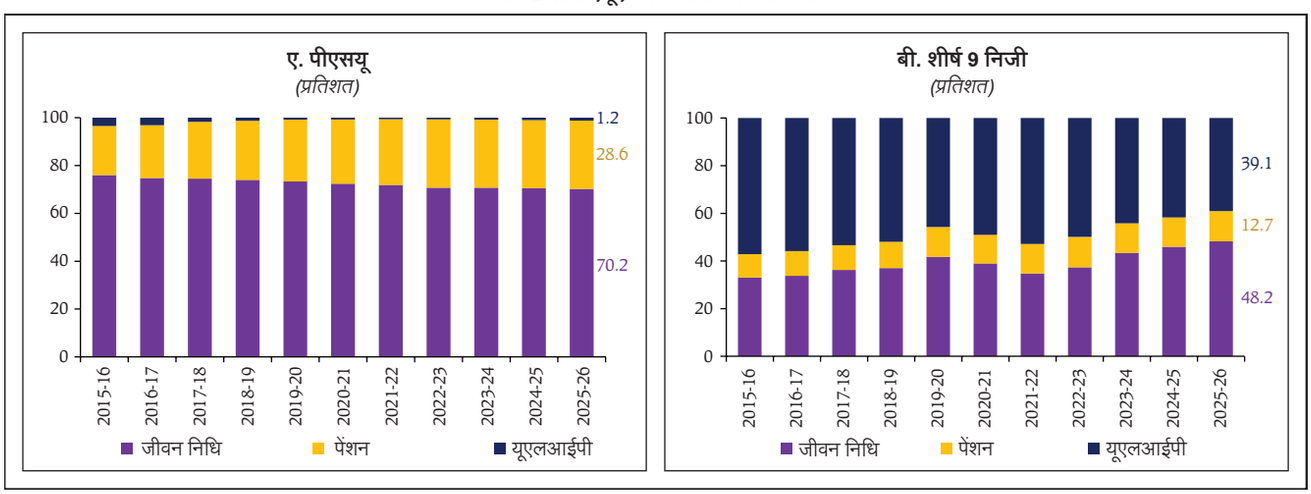
II.7.1.3.1 जीवन बीमा उद्योग

ए. एयूएम का गठन निधि वार

2.98 जीवन बीमा क्षेत्र के एयूएम में जीवन निधि, पेंशन और सामान्य वार्षिकी और समूह (पी एंड जी) निधि और यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (यूएलआईपी) निधि शामिल हैं। पीएसयू जीवन बीमाकर्ताओं के विपरीत, शीर्ष नौ निजी जीवन बीमाकर्ता में अधिक विविध निधि संरचना प्रदर्शित होती है, जिसमें यूएलआईपी फंड का काफी बड़ा अनुपात कुल एयूएम में है, यह निजी बीमाकर्ताओं के बाजार -संबन्धित प्रॉडक्ट पर अधिक जोर देता है (चार्ट 2.49 ए और बी)।

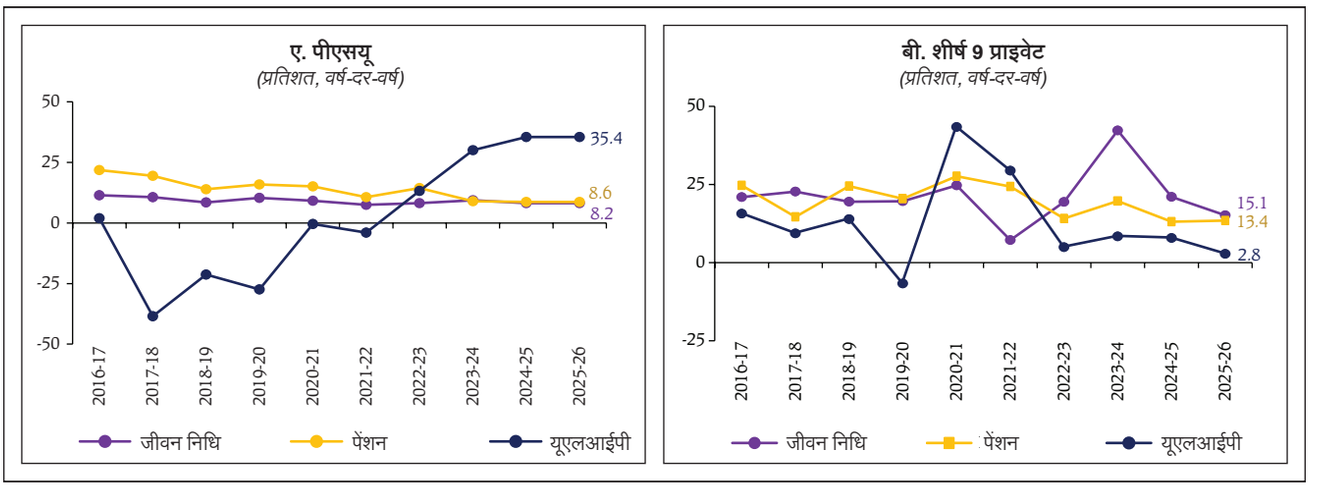
2.99 विभिन्न निधियों के एयूएम में वृद्धि पीएसयू और निजी बीमाकर्ताओं के लिए भिन्न होती है। पीएसयू बीमाकर्ता का जीवन निधि, सरकारी बांडों द्वारा समर्थित, बॉन्ड बाजार में ठहराव उत्पन्न करता है , लेकिन ब्याज दर जोखिम को भी केंद्रित करता है। निजी बीमाकर्ताओं के पोर्टफोलियो बड़े मात्रा में यूएलआईपी पोर्टफोलियो में परिवर्तन बाजार के जोखिम को पॉलिसीधारकों पर स्थानांतरित करते हैं, फिर भी इक्विटी मंदी के दौरान बड़े पैमाने पर आहरण , जैसे कि 2019-20 में हुआ था, तरलता में तनाव उत्पन्न कर सकता है (चार्ट 2.50 ए और बी)।

चार्ट 2.49 : एयूएम की निधि -वार संरचना



स्त्रोत : आईआरडीएआई।

चार्ट 2.50 : निधि वार वृद्धि दर



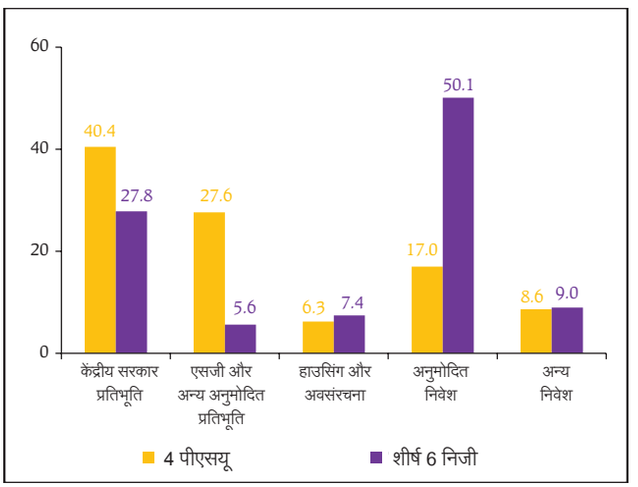
स्त्रोत : आईआरडीएआई।

बी. एयूएम का गठन - निवेश वार

2.100 जीवन बीमाकर्ताओं के पोर्टफोलियो मुख्य रूप से सरकारी प्रतिभूतियों में निवेशित हैं, जो उनकी दीर्घ देयता प्रोफाइल को दर्शाते हैं। पीएसयू बीमाकर्ता सॉवरेन आस्तियां में अधिक निवेश आबंटित करते हैं , वहीं निजी बीमाकर्ता आवास, बुनियादी ढांचे और अन्य अनुमोदित निवेशों में अपेक्षाकृत अधिक विविध पोर्टफोलियो अनुरक्षित करते हैं। इन अंतरों के बावजूद, पिछले दशक में दोनों खंडों का निवेश मिश्रण मोटे तौर पर स्थिर रहा है (चार्ट 2.51)।

चार्ट 2.51 : जीवन - निवेश वर्गवार संरचना

(प्रतिशत)



नोट : 2016-17 से 2024-25 तक के लिए औसत साझा।
स्त्रोत : आईआरडीएआई।

II.7.1.3.2 सामान्य बीमा उद्योग

2.101 सामान्य बीमाकर्ताओं के पोर्टफोलियो लघु - देनदारियों द्वारा प्रभावित होते हैं, जो अवधि -मिलान के ऊपर तरलता और आय को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन यह सीमा अनुकूलन को सीमित करता है और दरों में गिरावट के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाता है। इनकी होल्डिंग्स में सरकारी प्रतिभूतियाँ का वर्चस्व है , हालांकि जीवन बीमा निधि की तुलना से इसकी हिस्सेदारी कम है , इसमें आवास, बुनियादी ढांचे और अनुमोदित निवेशों में सार्थक आवंटन किए गए हैं, संप्रभुता में संकेद्रण अभी भी पोर्टफोलियो को प्रतिफल में वृद्धि के दौरान बाजार – दर- बाजार के समय नुकसान के लिए उजागर करती है। पीएसयू बीमाकर्ता के पास निजी समकक्षों की तुलना में सरकारी प्रतिभूतियाँ अधिक है जिससे वे ब्याज दर परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और परिसंपत्तियों की ओर पुनर्स्थापित करने के लिए कम लचीलापन रखते हैं। दोनों खंडों का निवेश मिश्रण मोटे तौर पर स्थिर रहा है (चार्ट 2.52)।

II.7.2 वित्तीय सुदृढ़ता

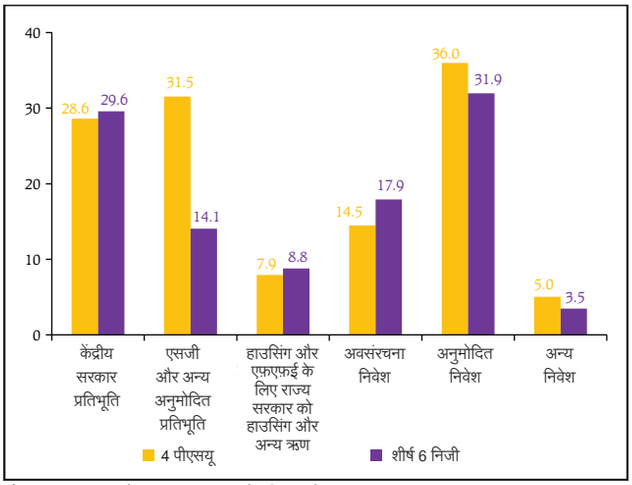
II.7.2.1 दावा

II.7.2.1.1 जीवन बीमा उद्योग

2.102 जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा भुगतान किया गया कुल लाभ 2021-22 में लगभग ₹ 5 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-

चार्ट 2.52 गैर -जीवन - निवेश वर्गवार संरचना

(प्रतिशत)



नोट : 2016-17 से 2024-25 तक के लिए औसत साझा।
स्रोत : आईआरडीएआई।

26 में ₹ 7.3 लाख करोड़ हो गया, जो 2024-25 से 16.1 प्रतिशत की तुलना में अधिक है (चार्ट 2.53 ए)। इस वृद्धि का पैमाना मोटे तौर पर प्रीमियम वृद्धि के अनुरूप है, लेकिन पे-आउट की संरचना एक संरचनात्मक चिंता का संकेत देती है (चार्ट 2.53 बी)।

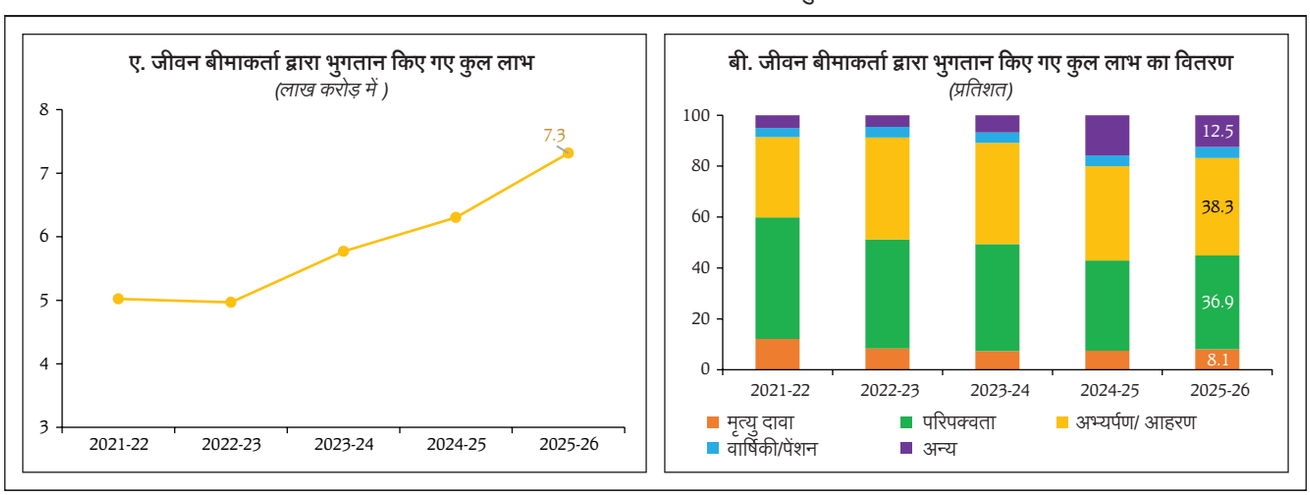
2.103 अभ्यर्पण (सरेंडर) और आहरण में तेजी से वृद्धि आई है , जो 2025-26 में कुल भुगतान का लगभग 38.3 प्रतिशत है, जो परिपक्वता लाभ से अतिरिक्त 36.9 प्रतिशत था। मृत्यु पर दावे सामान्य होकर लगभग 8.1 प्रतिशत हो गए हैं। अभ्यर्पण (सरेंडर) और परिपक्वता (मैच्योरिटी) पे आउट्स के बीच निकट समानता इंगित करती है कि पॉलिसीधारक अधिक मात्रा में समय से पूर्व पॉलिसियों से निकासी कर रहे हैं। इस बदलाव का आस्ति -देयता प्रबंधन (एएलएम) पर सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पूर्ण निकासी से जीवन बीमा निवेश रणनीतियों को रेखांकित करने वाली लंबी अवधि की धारनाएं बाधित होती है और समय से पूर्व आस्ति परिसमापन मजबूर की जा सकती है। लगातार बढ़ी हुई अभ्यर्पण (सरेंडर) दरें, पॉलिसीधारक में असंतोष, प्रॉडक्ट की गलत बिक्री, या वैकल्पिक वित्तीय साधनों से प्रतिस्पर्धी दबाव का भी संकेत देती हैं।

II.7.2.1.2 सामान्य बीमा उद्योग

2.104 सामान्य बीमा खंड में निवल दावे 2021-22 में ₹ 1.4 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹ 2.1 लाख करोड़ हो गए, जो 5 वर्षों में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि है (चार्ट 2.54 ए)। यह नुकसान की घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति और गंभीरता को दर्शाता है, विशेष रूप से स्वास्थ्य और मोटर लाइनों में, जो 2025-26 में निवल दावों के 95.3 प्रतिशत का गठन करते हैं । (चार्ट 2.54 बी)।

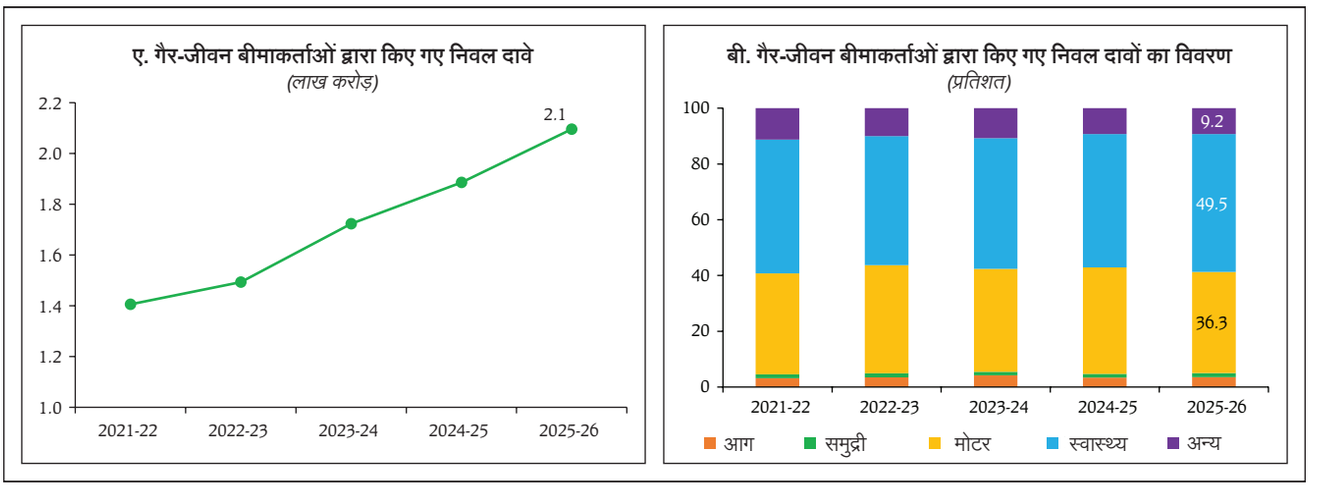
2.105 स्वास्थ्य बीमा दावों में कुल निवल दावों का 55 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है, जो चिकित्सा मुद्रास्फीति, अस्पताल में भर्ती होने की बढ़ती दर और कवरेज के विस्तार से प्रेरित है। मोटर से संबन्धित दावा 40.3 फीसदी है। इनमें दावों

चार्ट 2.53 जीवन बीमाकर्ता द्वारा अदा किए गए कुल लाभ



नोट: 2025-26 के लिए डाटा अनंतिम है।
स्रोत: आईआरडीएआई।

चार्ट 2.54 : गैर-जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा किए गए निवल दावे



नोट : 2025-26 के लिए डाटा अनंतिम है।
स्रोत: आईआरडीएआई।

का एकाग्रता दो खंड सहसंबद्ध और संरचनात्मक रूप से बढ़ते नुकसान का जोखिम पैदा करते हैं जो पर्याप्तता और अंडरराइटिंग मार्जिन को आरक्षित करने पर दबाव डाल सकते हैं, अगर लगातार पुन: कैलिब्रेट नहीं किया जाता है।

II.7.2.2 व्यय

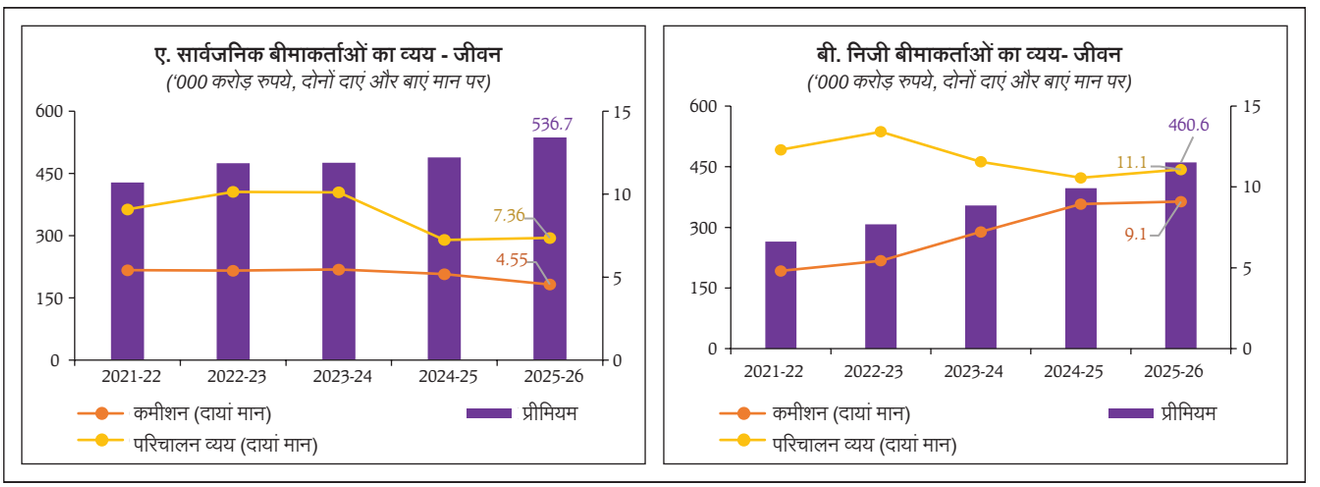
II.7.2.2.1 जीवन बीमा उद्योग

2.106 सार्वजनिक और निजी जीवन बीमाकर्ताओं के बीच लागत संरचना में अंतर स्पष्ट है। निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने 2021-22 से कमीशन अनुपात में लगभग दोगुना की वृद्धि देखी है, साथ ही स्थिर परिचालन व्यय अनुपात (चार्ट 2.55 ए और बी) भी देखा है। वितरण लागत में यह वृद्धि निजी क्षेत्र की प्रीमियम वृद्धि से काफी अधिक है, निवल मार्जिन को कम करती है और अधिग्रहण-लागत- मिससेल्लिंग के जोखिम को बढ़ाती है।

II.7.2.2.2 सामान्य बीमा उद्योग

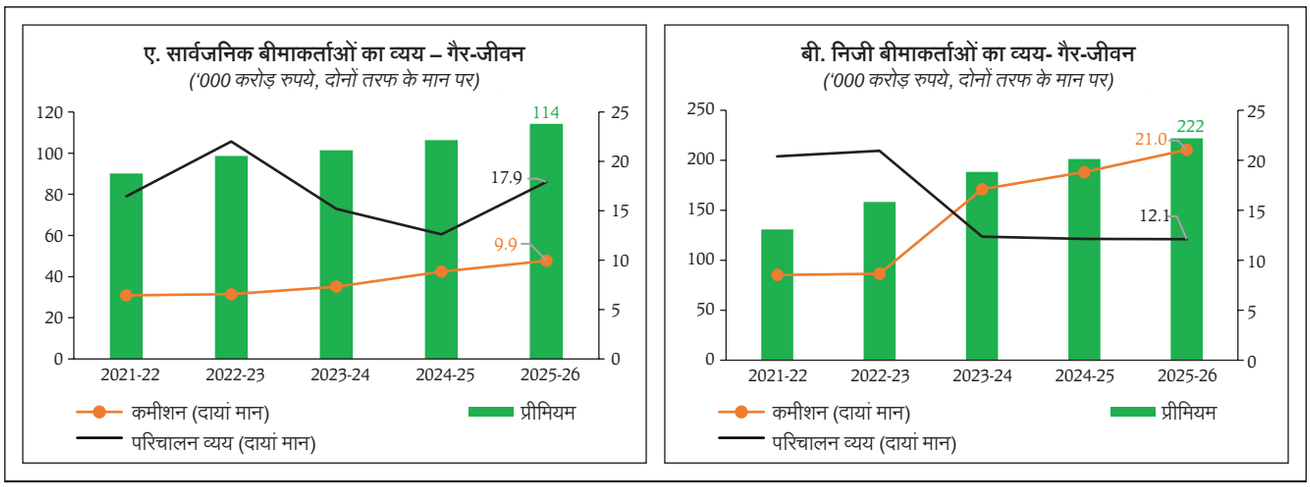
2.107 सामान्य बीमा खंड में, सार्वजनिक बीमा कंपनियां स्थिर लेकिन उत्थित व्यय आधार दर्शाती है। 2024-25 में मॉडरेट करने के बाद परिचालनात्मक व्यय 2025-26 में फिर से तेजी से बढ़ गया. पिछले 5 वर्षों में सार्वजनिक बीमाकर्ताओं के लिए कमीशन अनुपात में मामूली वृद्धि हुई है (चार्ट 2.56 ए)। वहीं, निजी बीमा कंपनियों का कमीशन व्यय अनुपात तीव्र गति से बढ़ा है, जिसने भौतिक रूप से प्रीमियम वृद्धि

चार्ट 2.55 : व्यय – जीवन बीमाकर्ता



नोट: 2025-26 के लिए डाटा अनंतिम है। परिचालन व्यय अनुपात में कमीशन व्यय शामिल नहीं है।
स्रोत: आईआरडीएआई

चार्ट 2.56 व्यय – गैर-जीवन बीमाकर्ता



Note: Data for 2025-26 is provisional.
Sources: IRDAI.

(चार्ट 2.56 बी) को भी पीछे छोड़ दिया है। सार्वजनिक और निजी दोनों बीमाकर्ताओं के लिए वितरण की यह उच्च लागत अंडरराइटिंग मार्जिन पर एक संरचनात्मक ड्रैग के रूप में कार्य करती है, जो पहले से ही अधिकांश क्षेत्र में नकारात्मक हैं।

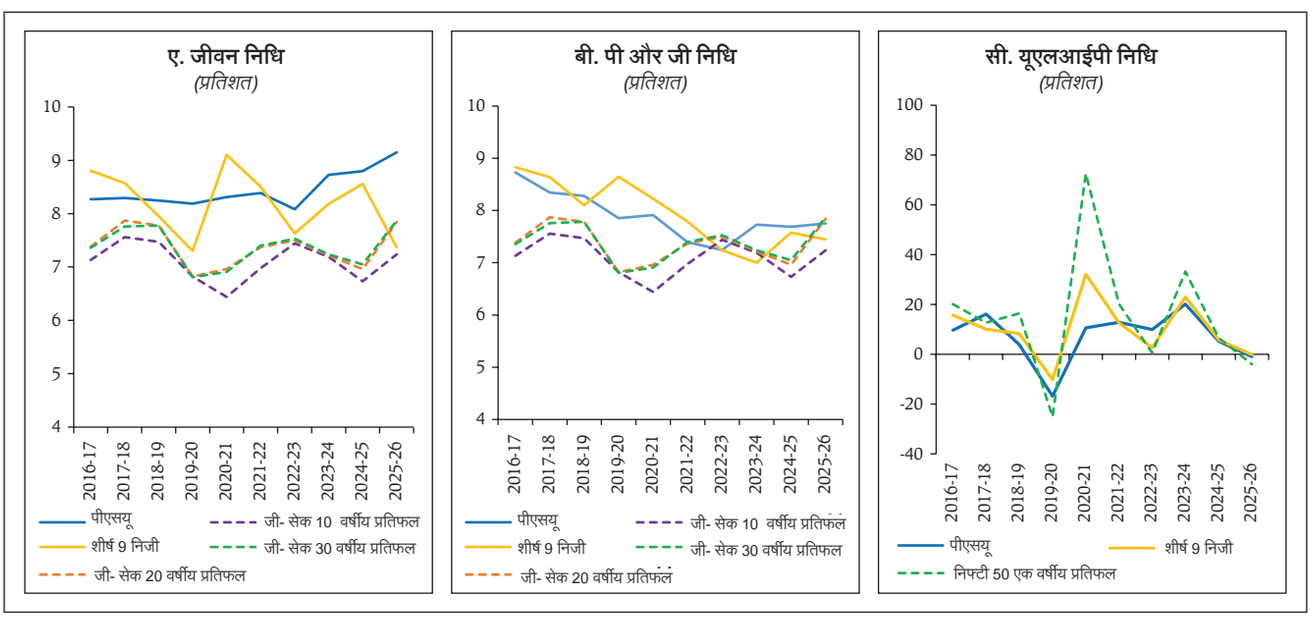
II.7.2.3 सकल प्रतिफल

II.7.2.3.1 जीवन बीमा उद्योग

2.108 पीएसयू बीमाकर्ता के जीवन निधि ने बढ़ती प्रवृत्ति दर्शायी है, जबकि शीर्ष नौ निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने 10-वर्ष की अवधि में अस्थिर प्रवृत्ति प्रदर्शित की है (चार्ट 2.57 ए)। दोनों श्रेणियों के लिए पी एंड जी फंड के प्रतिफल ने इस अवधि में व्यापक रूप से गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित की है (चार्ट 2.57 बी)। यह वार्षिकी और पेंशन दायित्वों के लिए संरचनात्मक पुनर्निवेश जोखिम का संकेत देता है, जो भारत की बढ़ती जनसंख्या के लिए विशेष रूप से संवेदनशील मुद्दा है, जिसे इस क्षेत्र में दीर्घावधि गारंटीकृत देनदारियों की आवश्यकता है।

2.109 यूएलआईपी प्रतिफल अत्यधिक अस्थिरता प्रदर्शित करती है, जो यूलिप निवेश की इक्विटी-उन्मुख प्रकृति के

चार्ट 2.57: शीर्ष 10 जीवन बीमाकर्ता के लिए निधि वार सकल प्रतिफल



Sources: IRDAI; and FBIL.

अनुरूप है (चार्ट 2.57 सी)। यूलिप की उच्च अस्थिरता, हालांकि अंतर्निहित पॉलिसीधारक जोखिम को दर्शाती है, इस फंड खंड की मार्क-टू-मार्केट संवेदनशीलता और बीमा क्षेत्र के समग्र रिटर्न मेट्रिक्स में निकट-अवधि की अस्थिरता उत्पन्न करने की इसकी क्षमता को भी उजागर करती है।

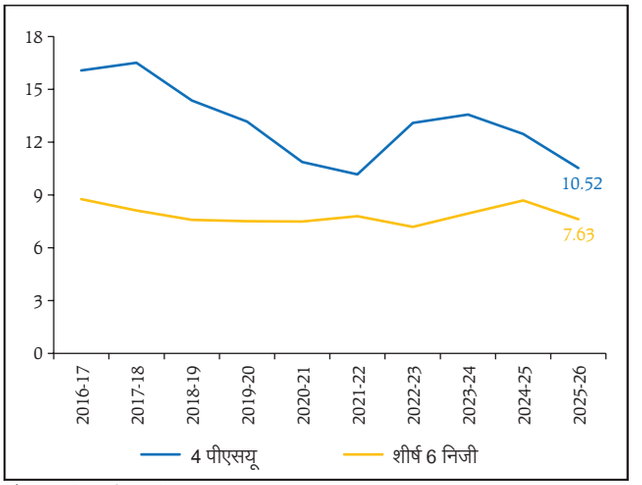
2.110 पार प्रॉडक्ट यिएल्ड ने जीवन निधि प्रतिफल को मोटे तौर पर ट्रैक किया है, जो 2021-22 से 2025-26 के दौरान संकीर्ण बैंड 8.0 से 8.8 प्रतिशत के तहत परिवर्तित हुआ। गैर-पार प्रॉडक्ट में गारंटीकृत रिटर्न दायित्व होते हैं, जिसके लिए बीमाकर्ताओं को निधि से कम से कम गारंटीकृत दर अर्जित करने की आवश्यकता है। दो बीमाकर्ताओं ने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है, जिससे मजबूत निवेश स्थिति का ज्ञान होता है। यूएलआईपी यील्ड पॉलिसीधारकों को मिलने वाले कुल मार्क-टू-मार्केट रिटर्न को दर्शाती है। 2025-26 में यील्ड में तेज गिरावट दर्ज की गई, जिसमें औसत क्षेत्रीय निधि प्रतिफल लगभग 1.4 प्रतिशत रहा, और केवल दो बीमाकर्ता औसत निधि प्रतिफल से ऊपर रहे। चूंकि पॉलिसीधारक यूएलआईपी के तहत निवेश जोखिम वहन करते हैं, इसलिए बीमाकर्ताओं की बैलेंस शीट पृथक रही , लेकिन निरंतर नकारात्मक एनएवी प्रदर्शन भौतिक रूप से अभ्यर्पण (सरेंडर) जोखिम को बढ़ाता है।

II.7.2.3.2 सामान्य बीमा उद्योग

2.111 शीर्ष 10 सामान्य बीमाकर्ताओं के सकल निवेश के प्रतिफल का रुझान पिछले एक दशक में मोटे तौर पर नीचे की ओर रहा, हालांकि लघु अवधि पोर्टफोलियो का अर्थ है कि जीवन खंड की तुलना में आस्तियां का पुनर्मूल्यांकन तीव्रता से होता है, जो दरों में वृद्धि होने पर त्वरित लाभ प्रदान करता है (चार्ट 2.58)। निवेश आय सामान्य बीमाकर्ताओं की लाभप्रदता के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जहां संयुक्त अनुपात उत्थित बना हुआ है। इसलिए, निरंतर प्रतिफल का संकुचन, हामीदारी अंकन की अपेक्षाओं को बढ़ाता है, जो क्षेत्र के वित्तीय स्थिति पर प्रभाव डालता है। सामान्य बीमाकर्ताओं के निवेश के प्रतिफल की ट्रेजक्ट्री ब्याज दर चक्रों, पोर्टफोलियो रिपोजिशनिंग और दावों की लागत मुद्रास्फीति के अंत: क्रिया को दर्शाता है, जो निकट-से-मध्यम अवधि के वित्तीय परिणामों को भौतिक रूप से आकार देता है।

चार्ट 2.58 : शीर्ष 10 गैर जीवन बीमाकर्ता के लिए सकल प्रतिफल

(प्रतिशत)



स्रोत: आईआरडीएआई।

II.7.2.4 इक्विटी शेयर कैपिटल

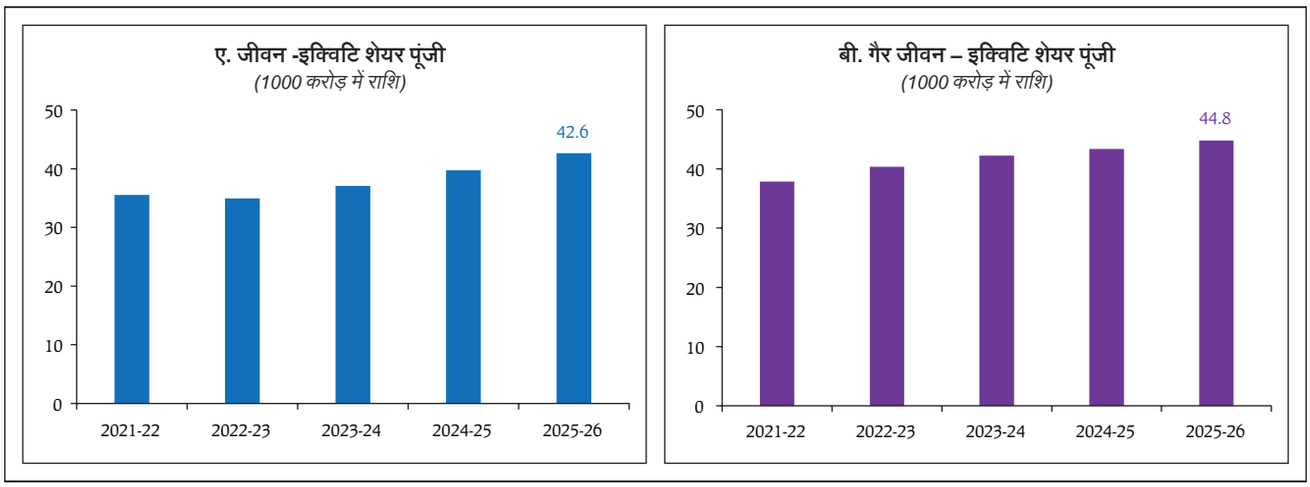
II.7.2.4.1 जीवन बीमा उद्योग

2.112 जीवन बीमा क्षेत्र की इक्विटी पूंजी 2021-22 में लगभग ₹ 35,547 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹ 42,627 करोड़ (चार्ट 2.59 ए) हो गयी । कोर इक्विटी पूंजी का स्थिर संचय सॉल्वेंसी बफर को अनुरक्षित करते हुए हुए क्षेत्र की क्षमता को निधि की वृद्धि को दर्शाता है।

II.7.2.4.2 सामान्य बीमा उद्योग

2.113 सामान्य बीमा क्षेत्र की इक्विटी पूंजी 2021-22 में लगभग 37,855 करोड़ रुपये से अधिक रैखिक और आक्रामक रूप से विस्तारित होकर 2025-26 में 44,824 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है (चार्ट 2.59 बी)। यह निरंतर पूंजी निवेश लगातार अंडरराइटिंग नुकसान को अवशोषित करने और प्रीमियम वृद्धि का समर्थन करने की संरचनात्मक आवश्यकता को दर्शाता है। जबकि निरंतर प्रमोटर समर्थन सकारात्मक स्थिरता का संकेत देता है, अंतर्निहित ड्राइवर इंगित करते हैं कि लाभदायक विस्तारण की तुलना में आवर्ती परिचालनात्मक घाटा को प्लग करने के लिए पूंजी को रक्षात्मक रूप से तैनात किया जा रहा है।

चार्ट 2.59 : जीवन और गैर -जीवन बीमाकर्ता का इक्विटि शेयर पूंजी



नोट: 2025-26 के लिए डाटा अनंतिम है।
स्रोत: आईआरडीएआई।

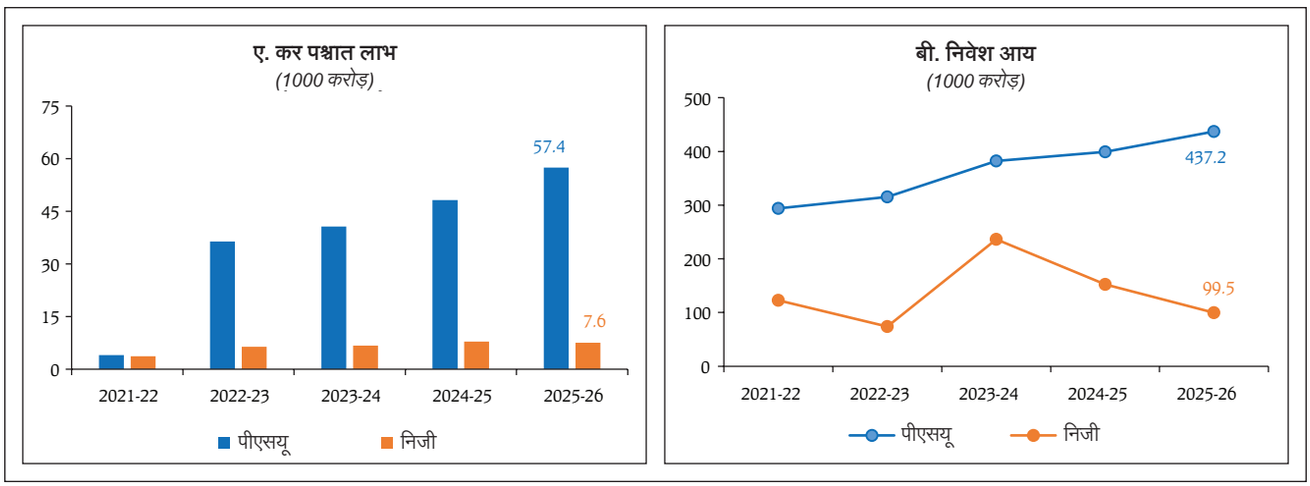
II.7.2.5 लाभप्रदता

II.7.2.5.1 जीवन बीमा उद्योग

2.114 सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के बीच निवेश आय पैटर्न में उल्लेखनीय अंतर देखा गया है। जीवन बीमाकर्ताओं की लाभप्रदता का प्राथमिक चालक निवेश आय बनी हुई है। पीएसयू बीमाकर्ता की निवेश आय 2021-22 में लगभग ₹ 2.9 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-26 में लगभग ₹ 4.4 लाख करोड़ हो गई है, जो इसका विस्तृत, संप्रभु-से प्रेरित आस्ति आधार को दर्शाती है। इसके विपरीत, निजी बीमा कंपनियों की निवेश आय काफी अधिक अस्थिर रही है।

2.115 पीएसयू बीमाकर्ताओं का पीएटी 2025-26 में बढ़कर '57,419 करोड़ हो गया. निजी क्षेत्र का पीएटी 2025-26 में '7,576 करोड़ पर संकुचित रहा है, जो उच्च अधिग्रहण लागत और आय की अस्थिरता से लगातार सीमा को दर्शाता है . 2025-26 में कुल जीवन क्षेत्र का पीएटी लगभग ₹ 65,000 करोड़ है (चार्ट 2.60 ए और बी)।

चार्ट 2.60 : जीवन -बीमाकर्ता की लाभप्रदता



नोट: 2025-26 के लिए डाटा अनंतिम है।
स्रोत: आईआरडीएआई।

II.7.2.5.2 सामान्य बीमा उद्योग

2.116 2025-26 में पीएसयू हामीदारी का घाटा बढ़ा है। 2025-26 में एकल स्वास्थ्य बीमाकर्ता (एसएएचआई) और निजी बीमाकर्ता ने भी महत्वपूर्ण हामीदारी नुकसान रिपोर्ट किया (चार्ट 2.61 ए)। निवेश आय पूरे खंड में तकनीकी नुकसान को सब्सिडी देना जारी रखती है, निजी बीमाकर्ताओं ने निवेश आय में वृद्धि की दिखाई है (चार्ट 2.61 बी)। यद्यपि, प्राथमिक लाभ स्थिरीकरण के रूप में गैर- हामीदारी आय पर यह संरचनात्मक निर्भरता प्रणालीगत संवेदनशीलता है। निवेश प्रतिफल में कोई भी संकुचन या पूंजी बाजार में सुधार सीधे तौर पर क्षेत्र की आय-क्षमता बफर को नष्ट कर सकता है, जो अंतर्निहित हामीदारी प्रदर्शन की अपर्याप्तता को उजागर कर सकेगा(चार्ट 2.61 सी)।

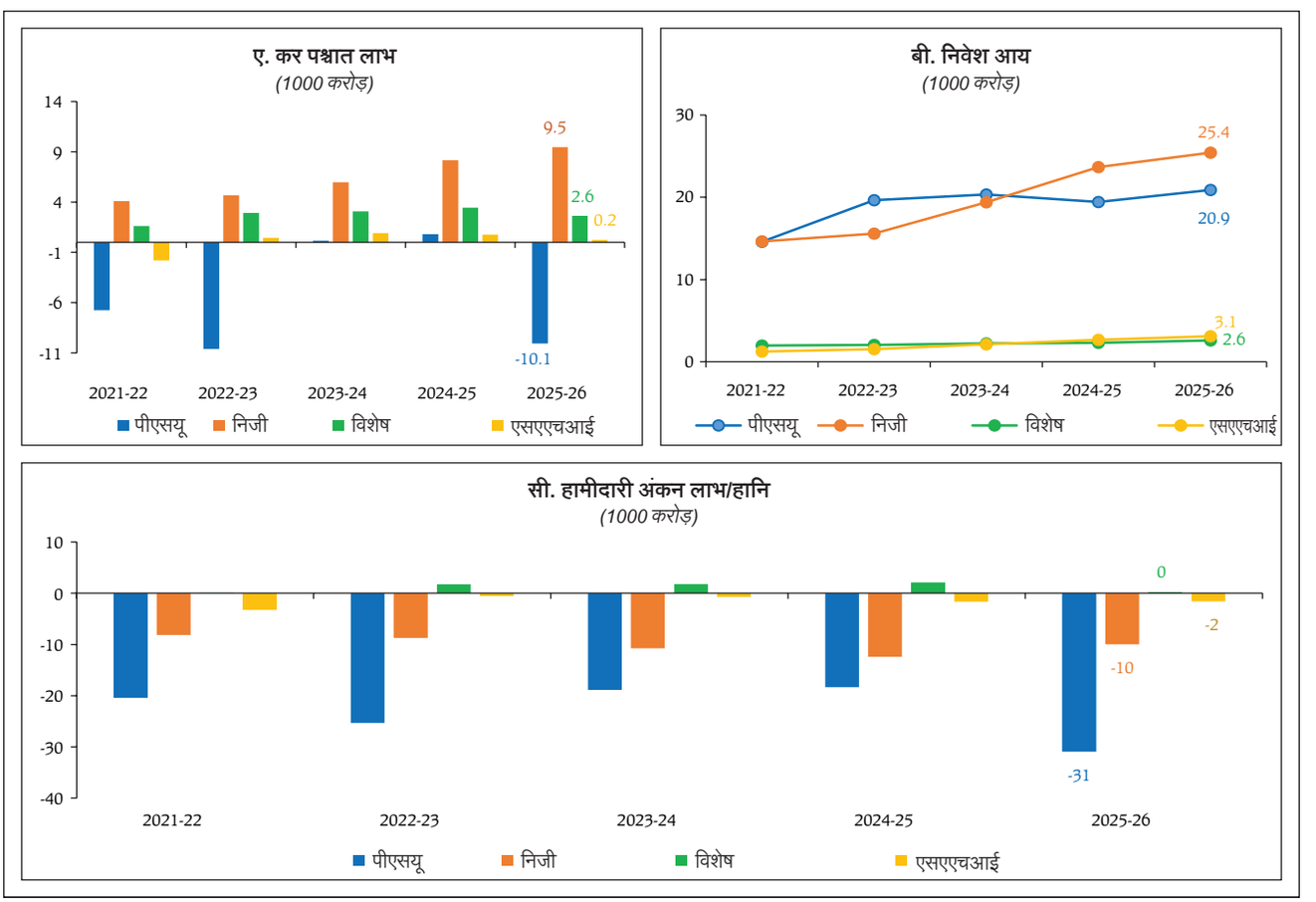
II.7.2.6 ऋण -शोधन क्षमता

II.7.2.6.1 जीवन बीमा उद्योग

2.117 2025-26 में सभी बीमाकर्ताओं के लिए जीवन बीमा क्षेत्र का ऋण- शोधन अनुपालन अनुरूप बना हुआ है, जिसमें कोई भी बीमाकर्ता 150 प्रतिशत की नियामक न्यूनतम से नीचे नहीं है। (तालिका 2.16) हालांकि, ऋण शोधन अनुपात का वितरण अनुपालन सीमा के भीतर उल्लेखनीय गिरावट की प्रवृत्ति का संकेत देता है।

2.118 उच्च ऋण शोधन क्षमता बैंड से निम्न अनुपालन श्रेणी की ओर बीमाकर्ताओं का प्रगतिशील स्थानांतरण देखा जाता है। न्यूनतम से कुछ अधिक बफर के साथ कार्य करने वाले बड़ी संख्या में बीमाकर्ता संरचनात्मक रूप से एक साथ तनाव के प्रति अधिक संवेदनशील हैं, विशेष रूप से प्रतिकूल ब्याज दर या इक्विटी बाजार परिदृश्यों के तहत।

चार्ट 2.61: गैर - जीवन -बीमाकर्ता की लाभप्रदता



नोट: 2025-26 के लिए डाटा अनंतिम है।
स्त्रोत: आईआरडीएआई।

सारणी 2.16 : जीवन बीमा निगम – ऋण शोधन क्षमता

ऋण शोधन क्षमता के साथ जीवन बीमाकर्ताओं की संख्या	ति4: 2024-25	ति1: 2025-26	ति2: 2025-26	ति3: 2025-26	ति4: 2025-26
>225	9	10	7	6	3
>=200 to <225	5	3	6	8	2
>=175 to <200	8	10	9	9	15
>=150 to <175	3	2	3	2	5
<150	0	0	0	0	0

स्त्रोत: 2025 -26 के लिए डाटा अनंतिम है।
नोट: 2025-26 के लिए डाटा अनंतिम है।

सारणी 2.17 : गैर-जीवन बीमा निगम – ऋण शोधन क्षमता

ऋण शोधन क्षमता के साथ जीवन बीमाकर्ताओं की संख्या	ति4: 2024-25	ति1: 2025-26	ति2: 2025-26	ति3: 2025-26	ति4: 2025-26
>225	10	11	11	11	10
>=200 to <225	6	7	8	8	3
>=175 to <200	8	8	7	4	10
>=150 to <175	7	5	5	8	8
<150	3	3	3	3	3

स्त्रोत: 2025 -26 के लिए डाटा अनंतिम है।
नोट: 2025-26 के लिए डाटा अनंतिम है।

II.7.2.6.2 सामान्य बीमा उद्योग

2.119 सामान्य बीमा ऋण शोधन क्षमता अधिक मिश्रित और संरचनात्मक रूप से अधिक चिंताजनक चित्र दर्शाता है। तीन बीमाकर्ता लगातार सभी पांच तिमाहियों 2024 -25 से 2025-26 तक में 150 प्रतिशत नियामक न्यूनतम से नीचे रहे हैं , लगातार गैर-अनुपालन जो प्रत्यक्ष वित्तीय स्थिरता चिंता का प्रतिनिधित्व करता है (तालिका 2.17)।

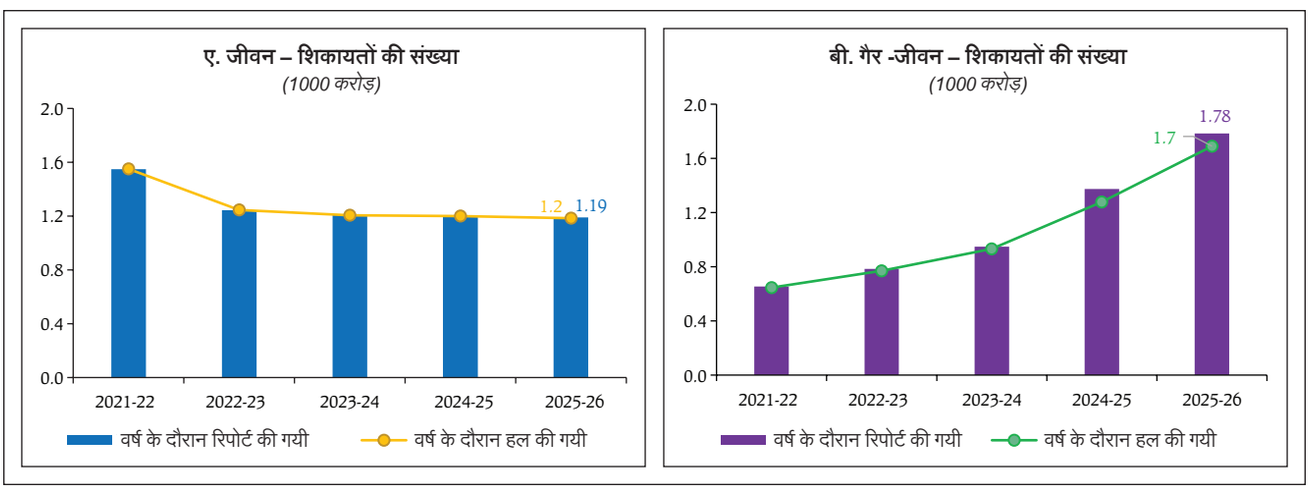
2.120 सामान्य बीमा खंड का ऋण - शोधन अनुपात जीवन खंड की तुलना में अधिक त्रैमासिक अस्थिरता दर्शाता है। यह अस्थिरता, लगातार अनुपालन संस्थाओं की संरचनात्मक उपस्थिति और उच्च हामीदारी घाटे के साथ मिलकर, सामान्य बीमा क्षेत्र को व्यापक बीमा व्यवस्था के तहत पूंजी जोखिम के निकट अवधि संकेंद्रण के रूप में व्यवस्थित करता है।

II.7.2.7 शिकायत का विश्लेषण

II.7.2.7.1 जीवन बीमा उद्योग

2.121 जीवन बीमा उद्योग क्षेत्र में शिकायत के अनुभव में संरचनात्मक सुधार दर्शाया गया है। 2021-22 में 1.5 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त होने के पश्चात, 2025-26 में शिकायतें घटकर 1.2 लाख हो गईं (चार्ट 2.62 ए)। यह सुधार प्रवृत्ति बेहतर बाजार आचरण, बेहतर प्रॉडक्ट उपयुक्तता और बिक्री के पश्चात सेवा के लिए अधिक प्रभाव का सुझाव देता है। स्थिरता के दृष्टिकोण से, शिकायत की मात्रा में गिरावट आचरण से संबंधित प्रतिष्ठा संबंधित जोखिम को कम कर सकती है और समय के साथ निरंतरता में सुधार का समर्थन कर सकती है।

चार्ट 2.62 : जीवन और जीवन -बीमा बीमाकर्ता की संरचना



नोट: 2025-26 के लिए डाटा अनंतिम है।
स्त्रोत: आईआरडीएआई।

II.7.2.7.2 सामान्य बीमा उद्योग

2.122 सामान्य बीमा उद्योग विषम तस्वीर दर्शाता है। 2025-26 (चार्ट 2.62) में शिकायतें लगभग तीन गुना बढ़कर 1.78 लाख हो गई हैं। शिकायतों में तीव्र और निरंतर वृद्धि दावों के प्रबंधन, सेवा गुणवत्ता और उत्पाद के संचार में प्रणालीगत कमियों को दर्शाती है। इस पैमाने के अनसुलझे आचरण जोखिम से पॉलिसीधारक का विश्वास कम हो सकता है, नवीनीकरण दर कम हो सकती है और अंततः यह वित्तीय स्थिरता की चिंता बन सकती है यदि यह बड़े पैमाने पर पॉलिसी से बाहर निकलने का कारण बनता है।

II.7.3 परिदृश्य विश्लेषण

II.7.3.1 पॉलिसीधारकों की निधि बनाम शेयरधारकों की निधि

2.123 ऋण शोधन मार्जिन, जिसे अपेक्षित ऋण शोधन मार्जिन (आरएसएम) पर उपलब्ध ऋण शोधन मार्जिन (एएसएम) की अधिकता के रूप में परिभाषित किया गया है, बीमाकर्ता वित्तीय सुदृढ़ता का प्राथमिक माप है। बीमाकर्ताओं के एएसएम को 'पॉलिसीधारकों के फंड में अधिकता' और 'शेयरधारकों के फंड में अधिकता' के बीच विभाजित किया गया है, जो ऋण शोधन क्षमता का बफर कहाँ स्थित है, इसपर विस्तृत दृश्य उपलब्ध करवाता है।

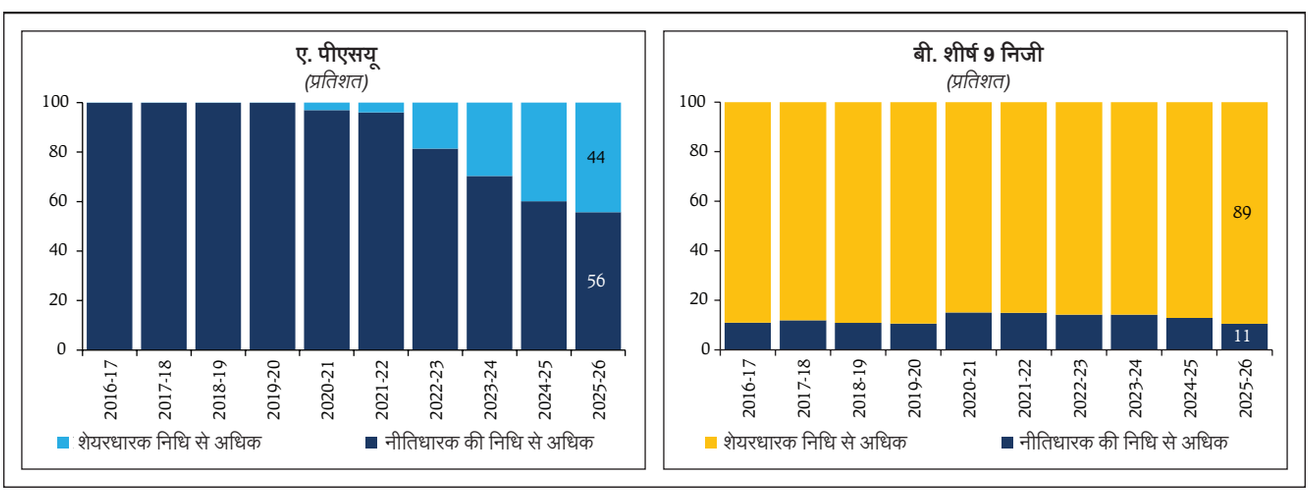
II.7.3.1.1 जीवन बीमा उद्योग

2.124 पीएसयू बीमाकर्ता के एएसएम के शेयरधारकों की निधि का घटक व्यापक उद्योग अभ्यास के साथ संरेखित करते हुए, 2022-23 से उत्तरोत्तर बढ़ा है (चार्ट 2.63 ए)। शीर्ष नौ निजी बीमाकर्ताओं के लिए, एएसएम संरचना स्थिर बनी हुई है, जिसमें शेयरधारकों के निधि का संरचनात्मक रूप से उच्च हिस्सा है, जो गैर-भागीदारी और यूनिट-लिंक्ड व्यवसाय के उनके अधिक अनुपात को दर्शाता है (चार्ट 2.63 बी)।

II.7.3.1.2 सामान्य बीमा उद्योग

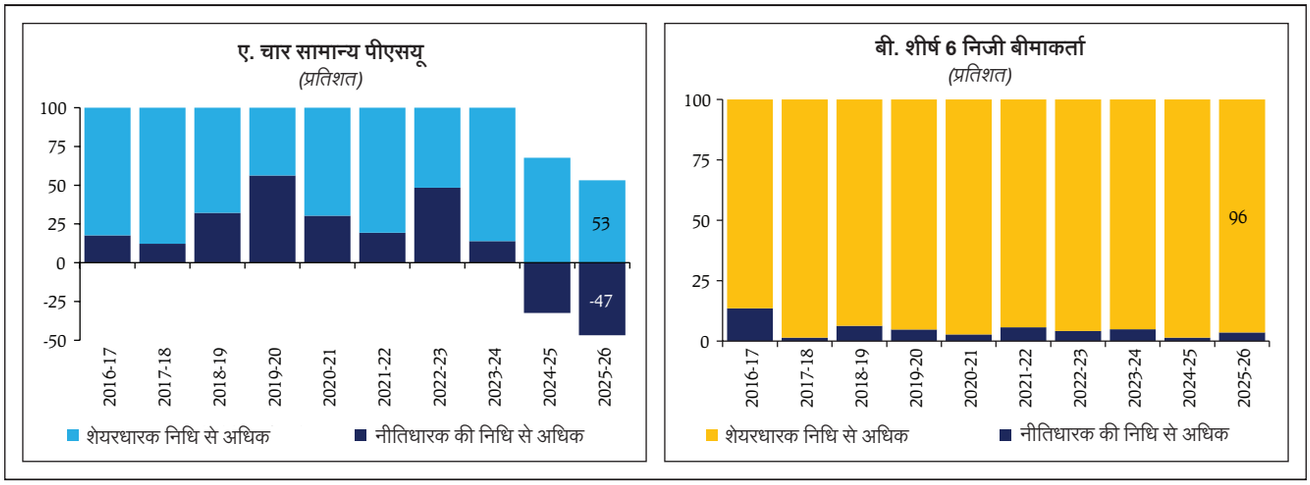
2.125 चार सामान्य पीएसयू के लिए, 'पॉलिसीधारकों के निधि में अधिशेष' ने 2024-25 और 2025-26 के लिए एएसएम में नकारात्मक योगदान दिया है (चार्ट 2.64 ए)। शीर्ष 6 निजी सामान्य बीमाकर्ताओं के लिए, एएसएम संरचना स्थिर है (चार्ट 2.64 बी)। 4 सामान्य पीएसयू के एएसएम में पॉलिसीधारकों के निधि का नकारात्मक योगदान वित्तीय स्थिरता का संकेत है। यह संरचनात्मक संवेदनशीलता सार्वजनिक क्षेत्र के सामान्य बीमाकर्ताओं के एएसएम को शेयरधारक पूंजी के प्रवाह और निवेश आय पर निर्भर करती है, जो दोनों बाहरी कारकों के अधीन हैं। यदि यह प्रवृत्ति बनी रहती है, तो पीएसयू सामान्य बीमाकर्ताओं की पूंजी पर्याप्तता सरकारी पूंजी समर्थन निर्णयों

चार्ट 2.63 : शीर्ष 10 जीवन बीमाकर्ताओं के एएसएम का गठन



Sources: IRDAI.

चार्ट 2.64: शीर्ष 10 सामान्य बीमाकर्ता के एएसएम की संरचना



Sources: IRDAI.

के प्रति उत्तरोत्तर अधिक संवेदनशील होगी , जो महत्वपूर्ण आकस्मिक राजकोषीय जोखिम है।

II.7.3.2 परिदृश्य विश्लेषण – ऋण -शोधन मार्जिन का आघात सहनीयता

2.126 प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन और सामान्य बीमाकर्ताओं की ऋण शोधन क्षमता की स्थिति के आघात सहनीयता का आकलन करने के लिए, एएसएम और आरएसएम के समुचित आघात को मिलाकर उपरोक्त पांच आघात परिदृश्यों का निर्माण किया गया था। ये परिदृश्य हल्के से लेकर गंभीर आघात तक हैं: पूंजी बफर का प्रत्यक्ष तौर पर कम होना, आरएसएम की तुलना में एएसएम पर असमान संकुचन और जोखिम के उच्च एक्सपोजर के कारण आरएसएम में वृद्धि। विनियामक ऋण- शोधन क्षमता सीमा का आरएसएम के 1.5 गुना के रूप में परिदृश्यों में बीमाकर्ता के आघात सहनीयता का मूल्यांकन करने के लिए बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है। ये आघात परिदृश्य, जबकि एएसएम और आरएसएम के लिए अमूर्त आघातों के रूप में निर्मित हैं, ऊपर वर्णित मैक्रोइकॉनॉमिक ट्रांसमिशन चैनलों पर आधारित हैं। हल्का (एस1) और मध्यम (एस2) परिदृश्य अल्प-चक्र व्यवधानों के अनुरूप हैं, जैसे कि क्षणिक ब्याज दर अस्थिरता या मध्यम इक्विटी बाजार सुधार, जहां गणितीय अनुरक्षित सीमित पुनर्मूल्यांकन दबाव का सामना करते हैं और निवेश पोर्टफोलियो नुकसान सीमित रहता है। गंभीर परिदृश्य (S3) मोटे तौर पर महत्वपूर्ण मैक्रोइकॉनॉमिक मंदी या तीव्र लेकिन पुनर्प्राप्त करने योग्य बाजार विस्थापन से जुड़ी स्थितियों को दर्शाता है, जिसमें कम होती परिसंपत्ति गुणवत्ता, बढ़ते दावों के प्रावधान और उच्च पुनर्निवेश जोखिम एक साथ दिवालियापन समीकरण के दोनों पक्षों पर दबाव डालते हैं। मार्जिन स्क्वीज़ परिदृश्य (एस4) ऐसे वातावरण का प्रतिनिधि है जिसमें भू-राजनीतिक आघात निश्चित आय और इक्विटी पोर्टफोलियो पर बाज़ार –दर –बाज़ार नुकसान को ट्रिगर करते हैं, जिसमें स्वीकार्य परिसंपत्तियों को संकुचित करते हैं। मार्जिन को समायोजित करने की आवश्यकता से अधिक तेजी से। आरएसएम स्पाइक परिदृश्य (एस5) नियामक रिज़र्व मजबूती (तालिका 2.18) की स्थितियों को दर्शाता है।

सारणी 2.18 : आघात परिदृश्य

(per cent)

परिदृश्य	एएसएम आघात	आरएसएम आघात	विवरण
S1 हल्का	-5.00	+5.00	Mild direct solvency stress
S2 मध्यम	-10.00	+10.00	Moderate direct solvency stress
S3 गंभीर	-15.00	+15.00	Severe direct solvency stress
S4 मार्जिन स्क्वीज़	-20.00	+10.00	ASM falls faster than RSM rises
S5 आर एस एम स्पाइक	-10.00	+20.00	Required margin shock dominates

Source: IRDAI.

II.7.3.2.1 जीवन बीमा उद्योग

2.127 शीर्ष 10 जीवन बीमाकर्ताओं के परिदृश्य विश्लेषण के परिणाम से पता चलता है कि तनाव की तीव्रता बढ़ने के साथ-साथ क्षेत्र-व्यापी ऋण -शोधन के अनुपालन में लगातार गिरावट आ रही है (चार्ट 2.65 ए और बी)। सबसे हल्के परिदृश्य (एस1) के तहत, सभी 10 बीमाकर्ता 1. 5 गुण सीमा से ऊपर ऋण- शोधन का अनुपात बनाए रखते हैं, जिससे पता चलता है कि अधिकांश बीमाकर्ता हल्के तनाव (तालिका 2.19) के तहत विनियामक अपेक्षाओं से अधिक पूंजी बफर अनुरक्षित रखते हैं। हालांकि, जैसे-जैसे आघात की गंभीरता बढ़ती है, अनुपालन तेजी से संकुचित हो जाता है, मध्यम परिदृश्य (एस2) के तहत 8 बीमाकर्ताओं तक कम होता है, और गंभीर (एस3) और मार्जिन स्क्वीज़ (एस4) परिदृश्य के तहत प्रत्येक में केवल 4 बीमाकर्ताओं तक कम होता है। आरएसएम स्पाइक परिदृश्य (एस5) के परिणामस्वरूप केवल 4 बीमाकर्ता सीमा से ऊपर रहते हैं।

2.128 ये निष्कर्ष क्षेत्र के ऋण -शोधन परिदृश्य में द्विभाजन को रेखांकित करते हैं। जबकि अधिकांश बीमाकर्ता हल्के से मध्यम तनाव को अवशोषित करने के लिए पर्याप्त रूप से पूंजीकृत हैं, संस्थाओं का उपसमूह विनियामक तल से

Table 2.19: Life Insurer-wise Distribution of Solvency

Scenario	Number of Insurers above 1.5x
S1 Mild	10
S2 Moderate	8
S3 Severe	4
S4 Margin Squeeze	4
S5 RSM Spike	4

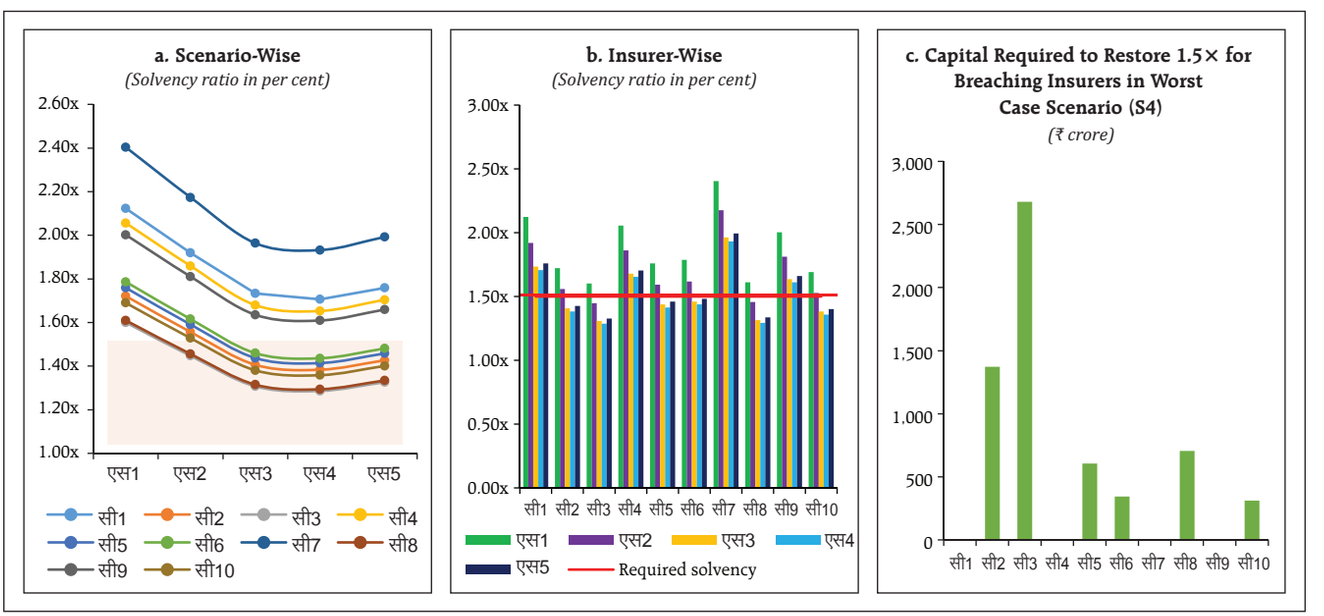
Source: IRDAI.

ऊपर सीमित बफर प्रदर्शित करते हैं, जिससे वे अधिक गंभीर प्रतिस्थापन के प्रति अधिक संवेदनशील हैं (चार्ट 2.65 सी)। ऋण -शोधन वितरण के ट्रेल में तनाव प्रभाव का संकेद्रन करीबी पर्यवेक्षी ध्यान की गारंटी देती है, विशेष रूप से क्योंकि बाजार की अस्थिरता, दावों का अनुभव और ब्याज दर की गतिविधियां एक साथ एएसएम को संकुचित कर सकती हैं और आरएसएम को बढ़ा सकती हैं, जो व्यापक रूप से एस4 या एस5 परिदृश्यों के अनुरूप स्थितियों को दोहरा सकती है।

II.7.3.2.2 सामान्य बीमा उद्योग

2.129 शीर्ष 10 सामान्य बीमाकर्ताओं के लिए परिदृश्य विश्लेषण के परिणाम बताते हैं कि जीवन बीमा खंड की तुलना में क्षेत्र सुदृढ़ पूंजी बफर प्रदर्शित करता है, जिसमें प्रत्येक स्तर के तनाव पर 1.5 गुना सीमा से ऊपर अनुपालन बनाए रखने

Chart 2.65: Scenario Analysis for ASM of Top 10 Life Insurers



Sources: IRDAI.

एस2

वाले बीमाकर्ताओं की संख्या कम है (चार्ट 2.66 ए)। हल्के परिदृश्य (एस1) के तहत, शीर्ष 10 सामान्य बीमाकर्ताओं में से 7 नियामक सीमा से ऊपर बने हुए हैं, जो यह दर्शाता है कि मध्यम आघात के तहत अधिकांश क्षेत्र पर्याप्त रूप से पूंजीकृत है, हल्के प्रतिकूल परिस्थितियों के तहत सार्थक अनुपात सीमित सीमा के साथ संचालित होता है (चार्ट 2.66 बी)। जैसे-जैसे तनाव की तीव्रता बढ़ती है, अनुपालन उत्तरोत्तर संकुचित होता जाता है, मध्यम परिदृश्य (एस2) के तहत 6 बीमाकर्ताओं और गंभीर परिदृश्य (एस3) के तहत 4 तक कम होता है (तालिका 2.20)। मार्जिन स्क्वीज़ परिदृश्य (एस4), केवल 3 बीमाकर्ताओं को सीमा में बनाए रखने के परिणाम देता है, पूंजी की विशेष भेद्यता को रेखांकित करता है - सामान्य बीमा संस्थाओं के उन परिदृश्यों के प्रति जहां अंडरराइटिंग नुकसान और आरक्षित सुदृढ़ता एक साथ उपलब्ध मार्जिन को कम करते हैं। आरएसएम स्पाइक परिदृश्य (एस 5), 5 अनुपालन बीमाकर्ताओं के साथ, उजागर करता है कि आवश्यक पूंजी में वृद्धि उच्च जोखिम के एक्स्पोज़र से प्रेरित है, यह ऋण शोधन बफर के प्रत्यक्ष कम के रूप में अस्थिर हो सकता है।

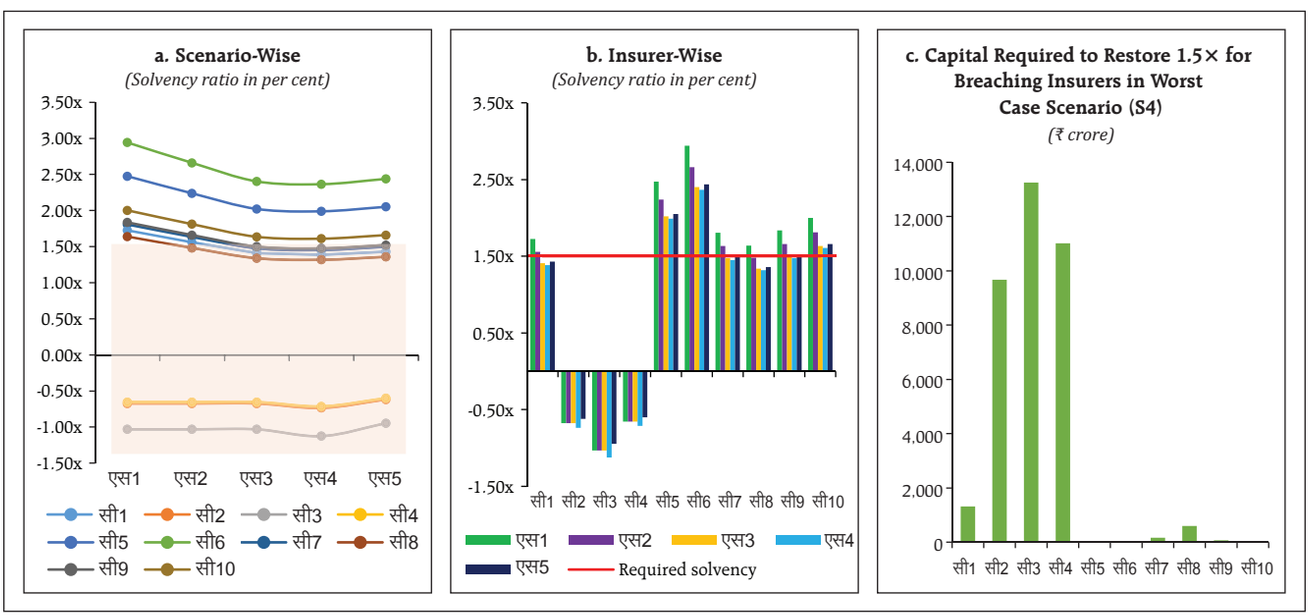
Table 2.20: General Insurer-wise Distribution of Solvency

Scenario	Number of Insurers above 1.5x
S1 Mild	7
S2 Moderate	6
S3 Severe	4
S4 Margin Squeeze	3
S5 RSM Spike	5

Source: IRDAI.

2.130 कुल मिलाकर, ये निष्कर्ष क्षेत्र-स्तरीय ऋण -शोधन वितरण की ओर इशारा करते हैं जिसमें सामान्य बीमाकर्ताओं का एक उपसमूह, विशेष रूप से उच्च संयुक्त अनुपात या संकेंद्रित अंडरराइटिंग एक्सपोजर एस 2 से अधिक तनाव की स्थिति में विनियामक उल्लंघन के लिए सार्थक रूप से उजागर होते हैं (चार्ट 2.66 सी)। सामान्य बीमा उद्योग की अपेक्षाकृत कम आस्ति -देयता अवधि और वार्षिक अंडरराइटिंग परिणामों के प्रति अधिक संवेदनशीलता प्रतिकूल विकास के साथ गति को बढ़ाती है जो ऋण - शोधन गिरावट में बदल सकती है, सक्रिय पूंजी प्रबंधन और नियामक न्यूनतम के करीब काम करने वाली संस्थाओं के साथ निरंतर पर्यवेक्षी जुड़ाव की आवश्यकता को भी पुष्ट करती है।

Chart 2.66: Scenario Analysis for ASM of Top 10 General Insurers



Sources: IRDAI.

एस2

II.7.3.3 विनियामकीय न्यूनतम ऋण शोधन क्षमता से अधिक का पूंजी बफर

II.7.3.3.1 शीर्ष 10 जीवन बीमाकर्ता

2.131 विनियामकीय न्यूनतम ऋण शोधन क्षमता से अधिक का पूंजी बफर उस अतिरिक्त पूंजीगत गुंजाइश को मापता है जिसे बीमाकर्ता आवश्यक ऋण शोधन क्षमता मार्जिन (आरएसएम) सीमा के 1.5 बार/गुना से अधिक बनाए रखते हैं। यह मीट्रिक क्षेत्र की सुदृढ़ता पर भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो न केवल यह दर्शाता है कि क्या कोई बीमाकर्ता अनुपालन कर रहा है, बल्कि यह भी बताता है कि विनियामकीय सीमा का उल्लंघन करने से पहले वह अतिरिक्त आघात को किस हद तक झेल सकता है।

2.132 पीएसयू बीमाकर्ता के लिए, 1.5 गुना ऋण शोधन क्षमता के लिए पूंजी बफर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक है और 2.0 गुना ऋण शोधन क्षमता के लिए पचास हजार करोड़ रुपये से अधिक है। शीर्ष 9 निजी जीवन बीमाकर्ताओं के लिए, बफर वितरण का विश्लेषण एक ध्रुवीकृत पूंजी परिदृश्य को दर्शाता है। अधिकांश बीमाकर्ता 1.5 गुना की निर्धारित सीमा से काफी अधिक ऋण शोधन क्षमता अनुपात बनाए रखते हैं। हालाँकि, 2.0 गुना ऋण शोधन क्षमता के लिए, बीमाकर्ताओं का एक समूह अपेक्षाकृत कम बफ़र के साथ काम करता है, जिसके कारण उनके पास अप्रत्याशित झटकों को झेलने के लिए अत्यंत सीमित गुंजाइश होते हैं। (चार्ट 2.67).

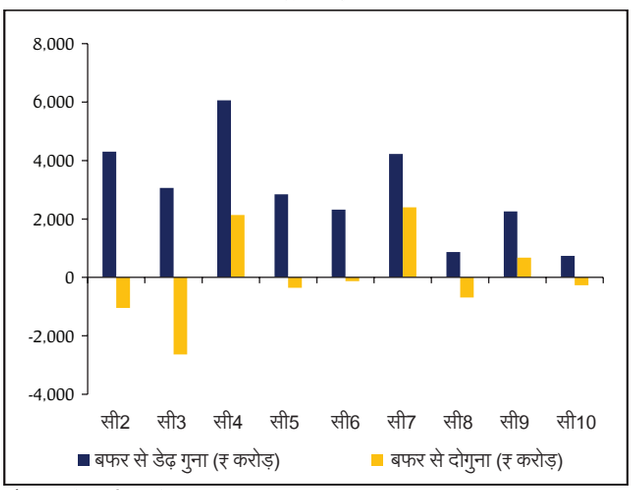
II.7.3.3.2 शीर्ष 10 सामान्य बीमाकर्ता

2.133 शीर्ष 10 सामान्य बीमाकर्ताओं के लिए विनियामकीय न्यूनतम ऋण शोधन क्षमता से अधिक का पूंजी बफर, प्रत्येक बीमाकर्ता के लिए वास्तविक ऋण शोधन क्षमता अनुपात और अनिवार्य 1.5गुना आरएसएम सीमा के बीच के अतिरिक्त अंतर को दर्शाता है। जीवन बीमा क्षेत्र की तुलना में, जहाँ दीर्घकालिक तथा अपेक्षाकृत पूर्वानुमेय प्रकृति के कारण ऋण शोधन क्षमता बफर संरचनात्मक रूप से अधिक स्थिर रहता है, वहीं सामान्य बीमा क्षेत्र में ऋण शोधन क्षमता बफर वर्ष-दर-वर्ष अधिक उतार-चढ़ाव का सामना करता है। इसका प्रमुख कारण दावों के परिणामों का प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल हानि-संबंधी घटनाक्रम तथा हामीदारी चक्र में होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रति अधिक संवेदनशील होना है। तद्नुसार, सामान्य अर्थों में विनियामकीय न्यूनतम के लिए पर्याप्त बफर बनाए रखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है (चार्ट 2.68)।

2.134 शीर्ष 10 सामान्य बीमाकर्ताओं में पूंजी बफर वितरण का विश्लेषण एक विषम तस्वीर दिखाता है। कई अच्छी-पूंजीकृत निजी सामान्य बीमाकर्ता 1.5गुना सीमा से काफी अधिक ऋण शोधन क्षमता अनुपात बनाए रखते हैं। हालांकि, बीमाकर्ताओं का एक समूह ऐसा भी जो काफी कम पूंजी के साथ काम करता है।

चार्ट 2.67: शीर्ष 9 निजी जीवन बीमाकर्ताओं के लिए विनियामक न्यूनतम सॉल्वेंसी से ऊपर पूंजी बफर

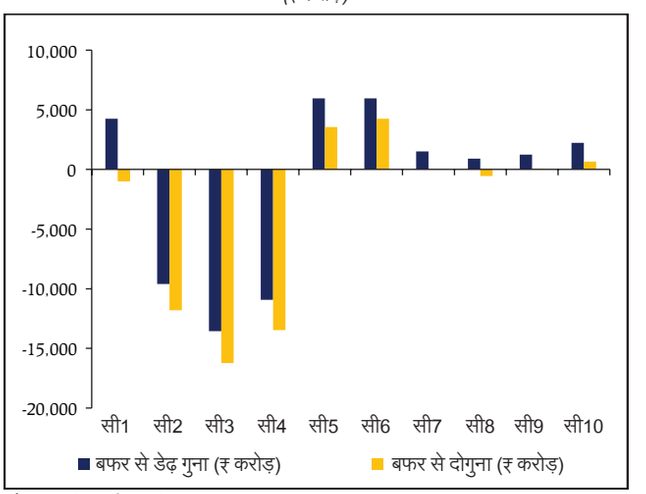
(₹ करोड़)



स्रोत: आईआरडीएआई।

चार्ट 2.68: शीर्ष 10 सामान्य बीमाकर्ताओं के लिए विनियामक न्यूनतम सॉल्वेंसी से ऊपर पूंजी बफर

(₹ करोड़)



स्रोत: आईआरडीएआई।

2.135 सामान्य क्षेत्र में पूंजी बफर का विषम वितरण, जिसमें बीमाकर्ताओं का एक समूह काफी कम पूंजी के साथ काम कर रहा है, बीमा क्षेत्र में सबसे तीव्र निकट-अवधि की वित्तीय स्थिरता संबंधी चिंता को दर्शाते हैं। जीवन क्षेत्र के विपरीत, जहां दीर्घकालिक देयताएँ क्रमिक पूंजी पुनर्निर्माण का सहूलियत देती हैं, सामान्य ऋण शोधन क्षमता बफर एक ही प्रतिकूल अंडरराइटिंग वर्ष में तेजी से समाप्त हो सकते हैं, इसका कारण प्राकृतिक आपदाएँ, महामारी जैसी घटनाएँ अथवा न्यायालयों द्वारा दिए जाने वाले मुआवज़े में अचानक वृद्धि जैसी परिस्थितियाँ हैं, जो इस प्रकार के जोखिम को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। कुछ सामान्य बीमा संस्थाओं में कम पूंजीगत सुरक्षा, उच्च संयुक्त दावा अनुपात तथा निवेश प्रतिफल में गिरावट का संयोजन ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है, जिसमें मध्यम स्तर का समष्टि-आर्थिक एवं वित्तीय आघात एक साथ अनेक बीमा कंपनियों पर ऋण शोधन क्षमता संबंधी दबाव पैदा कर सकता है, जिससे पूरे वित्तीय तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। इस जोखिम को कम करने का प्रमुख उपाय सुदृढ़ पूंजी नियोजन है, जिसमें जोखिमग्रस्त संस्थाओं द्वारा अग्र सक्रिय तरीके अतिरिक्त पूंजी जुटाना शामिल है।

II.7.4 बीमा क्षेत्र में तनाव के उभरते क्षेत्र

2.136 यद्यपि बीमा क्षेत्र में समग्र रूप से सुदृढ़ एवं आघात-सहनीय बना हुआ है, तथापि वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से इसके समक्ष कुछ अंतर्निहित संरचनात्मक दबाव विद्यमान हैं। प्रीमियम में निरंतर वृद्धि ने इस क्षेत्र की आघातों का सामना करने की क्षमता को सुदृढ़ किया है। हालांकि, जीवन बीमा क्षेत्र में पॉलिसियों के समर्पण की उच्च प्रवृत्ति पॉलिसियों की निरंतरता में कमजोरी का संकेत देती है तथा आस्ति-देयता प्रबंधन में अनिश्चितता उत्पन्न करती है। सामान्य बीमा क्षेत्र में दावों की बढ़ती संख्या तथा स्वास्थ्य और मोटर बीमा खंडों में दावों के संकेंद्रण ने अंडरराइटिंग प्रदर्शन पर दबाव बढ़ा दिया है, जिसके परिणामस्वरूप लाभप्रदता को स्थिर बनाए रखने के लिए निवेश आय पर निर्भरता और अधिक बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त, विशेषकर निजी क्षेत्र की जीवन एवं सामान्य बीमा कंपनियों में संवितरण संबंधी लागत में वृद्धि भी लाभप्रदता एवं परिचालन दक्षता पर अतिरिक्त दबाव डाल रही है। इसके अतिरिक्त, विशेषकर निजी क्षेत्र की जीवन एवं सामान्य बीमा कंपनियों में वितरण लागत में निरंतर वृद्धि पॉलिसीधारकों को मिलने वाले मूल्य को प्रभावित कर रही है तथा लाभ मार्जिन को संकुचित कर रही है। इसके अलावा, सामान्य बीमा क्षेत्र में पॉलिसीधारकों की शिकायतों में बढ़ोतरी सेवा की गुणवत्ता में विद्यमान कमियों का संकेत देती है।

2.137 बीमा कंपनियों के ऋण शोधन क्षमता बफर का धीरे-धीरे कम होना तथा तीन सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों का पूंजी निवेश पर निरंतर निर्भर रहना, उनकी पूंजीगत सुदृढ़ता को और मजबूत बनाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। साथ ही, निवेश पोर्टफोलियो का बड़ा हिस्सा सोवरेन प्रतिभूतियों में केंद्रित होने से बीमा कंपनियाँ ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के जोखिम के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं तथा उनके निवेश पोर्टफोलियो के प्रबंधन में लचीलापन सीमित हो जाता है। साथ ही, यदि यील्ड पर दबाव लंबे समय तक बना रहता है, तो विशेषकर जीवन बीमा क्षेत्र की दीर्घावधि देयताओं के संदर्भ में पुनर्निवेश संबंधी चुनौतियाँ और बढ़ सकती हैं।

2.138 इन दबावों का समाधान करने के लिए अंडरराइटिंग अनुशासन को सुदृढ़ करना, पूंजीगत बफर को मजबूत बनाना, वितरण संबंधी प्रोत्साहनों को नीतिगत निरंतरता के साथ बेहतर ढंग से संरेखित करना तथा पॉलिसीधारकों के लिए परिणामों में सुधार लाना आवश्यक होगा। इससे बीमा क्षेत्र की दीर्घकालिक सुदृढ़ता को और मजबूत करने तथा व्यापक एवं समावेशी बीमा विकास को सतत बनाए रखने में सहायता मिलेगी। इन प्रयासों को 'सबका बीमा, सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) अधिनियम, 2025' के अंतर्गत परिकल्पित संरचनात्मक एवं परिचालन संबंधी सुधारों का भी सहयोग प्राप्त होगा।

2.139 इन पारंपरिक दबावों के अतिरिक्त, जलवायु परिवर्तन, साइबर खतरे तथा भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं जैसी उभरते जोखिम बीमा क्षेत्र के जोखिम प्रोफाइल को नया आयाम दे रही है।

2.140 समग्र रूप से देखें तो ये जोखिम इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि बीमा क्षेत्र की कमजोरियां/कमीयां अब केवल अंडरराइटिंग निष्पादन तक ही केवल सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि जलवायु संबंधी जोखिमों, प्रौद्योगिकी संबंधी जोखिमों, बाज़ार संबंधी जोखिमों, भू-राजनीतिक जोखिमों तथा परिचालन संबंधी जोखिमों से भी उत्पन्न हो रही हैं।

अध्याय III

वित्तीय क्षेत्र में विनियामकीय पहल

वैश्विक वित्तीय प्रणाली भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही है। इस परिप्रेक्ष्य में, विश्वभर के विनियामक बासेल मानकों के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन, सिंथेटिक जोखिम अंतरण, रेपो तथा निजी ऋण बाज़ारों के माध्यम से बैंकों एवं गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के बीच बढ़ती परस्पर संबद्धता की निगरानी, टोकनाइज़ेशन से संबंधित विकासक्रमों का विश्लेषण, पर्यवेक्षी परिचालनगत ढाँचे का विकास तथा जलवायु संबंधी जोखिमों को समष्टि-वित्तीय निगरानी ढाँचों में समाहित करने के माध्यम से वित्तीय प्रणाली की प्रणालीगत सुदृढ़ता को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।घरेलू स्तर पर भी विनियामक इन वैश्विक प्रयासों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। इस दिशा में वे नियामकीय ढाँचों में आवश्यक संशोधनों, ग्राहकों एवं निवेशकों के सुरक्षा को बढ़ाने तथा कारोबार करने में सुगमता के लिए सुधार पर विशेष बल दे रहे हैं।

परिचय

3.1 वैश्विक अनिश्चितताओं तथा व्यापार प्रवाह , ऊर्जा बाज़ारों एवं पूंजीगत गतिविधियों पर पड़ने वाले प्रभावों के बीच, विश्वभर के विनियामक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाज़ारों में वित्तीय प्रणालियों की सुरक्षा एवं वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय कर रहे हैं। दिसंबर 2025 से , वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करने, विनियामकीय ढाँचों को सुव्यवस्थित करने तथा सभी संस्थाओं में जोखिम प्रबंधन प्रणालियों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण विनियामकीय पहलें कार्यान्वित की गई हैं।

3.2 इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए , यह अध्याय वित्तीय प्रणाली की सुदृढ़ता को बढ़ाने के उद्देश्य से दोनों वैश्विक एवं घरेलू स्तर पर हाल ही में की गई प्रमुख विनियामकीय तथा समीक्षा-संबंधी पहल की समीक्षा करता है।

III.1 वैश्विक विनियामकीय गतिविधियां

III.1.1 बैंकिंग

3.3 बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने बासेल III निगरानी रिपोर्ट[1] जारी की, जिसमें बासेल III के निगरानी संबंधी कार्य पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट यह बताता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े सक्रिय बैंकों के लिए जोखिम-आधारित पूंजी तथा लीवरेज अनुपात स्थिर बने हुए हैं, जबकि चलनिधि संकेतकों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। निगरानी कार्य यह इंगित करता है कि समूह/ ग्रुप-1 बैंकों का औसत चलनिधि कवरेज अनुपात थोड़ा बढ़ा है। वैश्विक स्तर पर, बैंकों की पूंजी व्यवस्था में "आउटपुट फ्लोर" के चरणबद्ध कार्यान्वयन में निरंतर प्रगति हो रही है। यह बैंकों के लिए एक सुरक्षा उपाय है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक पूंजी रखने के लिए आंतरिक रूप से विकसित मॉडलों से प्राप्त जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के उपयोग से अत्यधिक कम पूंजी आवश्यकताओं को निर्धारित न कर सकें। पूर्ण रूप से चरणबद्ध अंतिम बासेल III ढाँचे के अनुसार, जनवरी 2028 तक इसे 72.5 प्रतिशत के स्तर तक पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित है।[2]

3.4 इससे संबंधित गतिविधि में, बीसीबीएस ने परिचालन जोखिम के मानकीकृत दृष्टिकोण (Standardised Approach) से संबंधित एक अंतिम तकनीकी संशोधन[3] जारी किया, जिसमें हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया को भी शामिल किया गया है। इस संशोधन में परिचालन संबंधी जोखिम हेतु पूंजीगत आवश्यकताओं की गणना में प्रयुक्त व्यावसायिक संकेतकों के कुछ पहलुओं को स्पष्ट किया गया है। इस संशोधन को बेसल समिति के सदस्य देशों द्वारा आगामी तीन वर्षों के भीतर लागू किए जाने की अपेक्षा की गई है।[5]

3.5 बीसीबीएस ने सिंथेटिक जोखिम अंतरण[6] पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें बैंकों द्वारा क्रेडिट जोखिम के अंतरण तथा

1 बीसीबीएस (2026), "बासेल III निगरानी रिपोर्ट", मार्च ।

2 आउटपुट फ्लोर 50 प्रतिशत (2023) से चरणबद्ध तरीके से बढ़ गया है, जो हर साल 01 जनवरी की स्थिति के अनुसार 5 प्रतिशत बढ़ रहा है।

3 बीसीबीएस (2026), "तकनीकी संशोधन और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को अंतिम रूप देना", मार्च।

4 संशोधन मूल रूप से जून 2025 में परामर्श के लिए प्रकाशित किया गया था।

5 अलग से, समिति ने एक परामर्शी दस्तावेज के साथ बैंकों और पर्यवेक्षकों के लिए दिशानिर्देशों और ठोस प्रथाओं को कवर करते हुए अपनी वेबसाइट का एक समेकित खंड लॉन्च किया।

6 बीसीबीएस (2026), "सिंथेटिक जोखिम स्थानांतरण", फरवरी।

पूंजी आवश्यकताओं के प्रबंधन के लिए क्रेडिट-संबद्ध नोट्स और ऋण चूक स्वैप्स जैसे वित्तीय लिखतों के बढ़ते उपयोग की समीक्षा की गई है। रिपोर्ट में ऐसे वित्तीय लिखतों पर प्रभावी पर्यवेक्षी निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सिंथेटिक जोखिम अंतरण के माध्यम से बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के बीच बढ़ती परस्पर संबद्धता को देखते हुए, वित्तीय स्थिरता संबंधी जोखिमों की समयबद्ध निगरानी एवं उनके प्रभावी समाधान के लिए बैंकों तथा के पर्यवेक्षकों के बीच घनिष्ठ सहयोग एवं समन्वय की आवश्यकता भी रेखांकित की गई है।

3.6 वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ने बैंकों, बीमाकर्ताओं और वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे के लिए समाधान ढांचे को अपडेट करते हुए और परिचालन योजना, समाधान मूल्यांकन और संकट प्रबंधन व्यवस्था में प्रगति पर प्रकाश डालते हुए अपनी संकल्प रिपोर्ट प्रकाशित की[7]। एफएसबी ने वसूली और समाधान योजना की आवश्यकताओं के अधीन बीमाकर्ताओं के दायरे पर मार्गदर्शन को अंतिम रूप दिया। मार्गदर्शन दस्तावेज[8] ने अधिकारियों को यह निर्धारित करने में मदद करने के लिए छह मानदंड निर्धारित किए हैं कि कौन से बीमाकर्ताओं को ऐसी आवश्यकताओं के अधीन होना चाहिए।

3.7 एफएसबी की वार्षिक रिपोर्ट [9] में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कार्यान्वयन निगरानी की कार्यनीतिक समीक्षा का उद्देश्य जी20 वित्तीय सुधार कार्यान्वयन में देखी गई मंदी के मूल कारणों की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जिससे वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में नियामक सुधारों के कार्यान्वयन के महत्व पर प्रकाश डाला जा सके।

III.1.2 गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता (एनबीएफआई)

3.8 एफएसबी ने एनबीएफआई की आघातसहनीयता को मज़बूत बनाने के एक हिस्से के रूप में सरकारी बॉन्ड-समर्थित रेपो बाजारों में कमजोरियों पर एक रिपोर्ट[10] प्रकाशित की। सरकारी बॉन्ड-समर्थित रेपो बाजारों ने सॉवरेन बॉन्ड बाजार की चलनिधि और अल्पकालिक वित्त पोषण में सहयोग पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, ये लिखतें ने एनबीएफआई से संबंधित बाजार के तनाव के हालिया एपिसोड के केंद्र में भी रहे हैं। तदनुसार, उक्त रिपोर्ट में तीन प्रमुख कमजोरियों की पहचान की गई है: (ए) रेपो-वित्त पोषित स्थितियों के माध्यम से बिल्ड-अप लिवरेज़; (बी)आस्ति-देयता बेमेल के एपिसोड में मांग-आपूर्ति असंतुलन; और (सी) रेपो बाजार में उच्च नियंत्रण/संकेंद्रण। एफएसबी ने अधिकारियों से रेपो बाजारों की बाजार की कार्यप्रणाली की मुख्य भूमिका को संरक्षित करते हुए डेटा अंतराल को कम करने, निगरानी को मजबूत करने और लिवरेज और चलनिधि की कमजोरियों को दूर करने का आह्वान किया है।

3.9 वैश्विक स्तर पर निजी ऋण में तीव्र वृद्धि को देखते हुए, एफएसबी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की[11] जिसमें चार मुख्य कमजोरियों पर प्रकाश डाला गया: (ए) बैंकों और निजी ऋण निधियों के बीच अंतर्संबंधों का गहरा होना; (बी) उधारकर्ता ऋण गुणवत्ता संबंधी चिंताएं और द्विपक्षीय आधार पर बातचीत किए गए ऋणों में मूल्यांकन अस्पष्टता; (सी) कंसंट्रेशन, लिवरेज़, और चलनिधि के मुद्दे - विशेष रूप से जहां लिवरेज़ अपारदर्शी, बहुस्तरीय संरचनाओं की उपस्थिति में परिलक्षित होता है; और (डी) डेटा में लगातार अंतराल जो प्रभावी निरीक्षण को बाधित करते हैं। हालांकि निजी क्रेडिट फंडों के लिए प्रत्यक्ष बैंक एक्सपोजर वैश्विक स्तर पर कम रहे, एफएसबी ने नोट किया कि वित्तपोषण, जोखिम हस्तांतरण और संपार्श्विक ऋण दायित्वों (सीएलओ) के माध्यम से अप्रत्यक्ष और जटिल संबंधों को करीब से जांच किए जाने की आवश्यकता है।

3.10 एफएसबी के 2026[12] कार्य कार्यक्रम के अनुसार, एनबीएफआई के लिए नियामक डिजाइन कार्यान्वयन निगरानी, कमजोरियों के मूल्यांकन और नीति मूल्यांकन की ओर बढ़ रहा है। गैर-बैंक डेटा टास्क फोर्स[13] का काम - विशेष रूप से संप्रभु

7 एफएसबी (2026), "योजनाओं से अभ्यास तक: संकल्प का संचालन करना", जनवरी।
8 एफएसबी (2026), "प्रमुख विशेषताओं में वसूली और समाधान योजना आवश्यकताओं के अधीन बीमाकर्ताओं का दायरा", अप्रैल।
9 एफएसबी (2026), "वार्षिक रिपोर्ट" (मार्च)।
10 एफएसबी (2026), "सरकारी बॉन्ड-समर्थित रेपो बाजारों की कमजोरियां", फरवरी।
11 एफएसबी (2026), "निजी ऋण में कमजोरियों पर रिपोर्ट", मई।
12 एफएसबी (2026), "2026 के लिए कार्यक्रम", फरवरी।
13 एफएसबी (2025), "गैर-बैंक डेटा टास्क फोर्स (एनडीटीएफ)", जुलाई।

बांड बाजारों में लीवरेज्ड ट्रेडिंग रणनीतियों पर अपने नैदानिक परीक्षण मामले के माध्यम से - संप्रभु बॉन्ड नकद-वायदा आधार ट्रेडों में डेटा के अंतराल को संबोधित करने पर सीधे ध्यान केंद्रित करता है। यह पहल लीवरेज, तरलता जोखिम और अंतर्संबंध को कैपचर करने के लिए एक व्यापक, प्रणालीगत प्रयास का हिस्सा है जो पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से परे है।

III.1.3 वित्तीय बाज़ार

3.11 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) ने ओटीसी कमोडिटी डेरिवेटिव बाजारों[15] से संबंधित अच्छी प्रथाओं पर एक परामर्श रिपोर्ट प्रकाशित की[14]। यह परामर्श विशेष रूप से सिद्धांत 12, 15 और 16 के तहत सूचना, हस्तक्षेप शक्तियों और बाजार व्यवधान प्रतिक्रिया तंत्र तक विनियामक अधिगम्यता को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य अत्यधिक अटकलों का पता लगाने के लिए अधिकारियों की क्षमता में सुधार करना है, ओटीसी कमोडिटी डेरिवेटिव बाजारों में जोखिमों के निर्माण की निगरानी करना और अव्यवस्थित बाजार स्थितियों के लिए अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया **देना है।**

3.12 केंद्रीय समकक्षों (सीसीपी) जोखिम प्रबंधन प्रथाओं पर बाजार सहभागियों को स्पष्ट जानकारी की आवश्यकता से उपजी, सीपीएमआई-आईओएससीओ ने सीसीपी[16] से संबंधित अद्यतन मार्गदर्शन पर परामर्श प्रकाशित किया, जो प्रारंभिक मार्जिन प्रस्तावों, सार्वजनिक मात्रात्मक प्रकटीकरण और वित्तीय बाजार बुनियादी ढांचे के सिद्धांतों से संबंधित मार्गदर्शन पर केंद्रित था। आईओएससीओ ने कारोबारी दिन के दौरान बाजार की नकदी के विकास और इक्विटी बाजारों में विस्तारित व्यापारिक घंटों के संबंध में परामर्श पत्र/रिपोर्टें[17] भी प्रकाशित की हैं। इन प्रकाशनों ने व्यापारिक व्यवहार में संरचनात्मक परिवर्तनों की जांच की, जिसमें बाजार बंद होने के आसपास चलनिधि का बढ़ता संक्रेंदण, दिन के अंत की नीलामी, बंद होने के बाद के सत्र और लंबे समय तक व्यापारिक घंटों के प्रस्ताव शामिल हैं।

3.13 आईओएससीओ ने गैर-जीएएपी इन चिंताओं का जवाब देते हुए कि वैकल्पिक प्रदर्शन उपायों का बढ़ता उपयोग जारीकर्ताओं के बीच तुलनीयता को प्रभावित कर सकता है और पर्याप्त प्रकटन के अभाव में निवेशकों की समझ को कमजोर कर सकता है वित्तीय उपायों पर अपने स्टेटमेंट[18] को और अपडेट किया।

III.1.4 विकेंद्रीकृत वित्त और डिजिटल संपत्ति

3.14 पारंपरिक वित्तीय बाजारों, भुगतान प्रणालियों और सुरक्षित-आस्ति बाजारों के साथ अपने बढ़ते संबंधों को देखते हुए स्टेबलकॉइन ने विनियामक का ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। दिसंबर 2025 के एफ़एसआर ने उल्लेख किया था कि स्टेबलकॉइन जारीकर्ता पारंपरिक आरक्षित आस्तियों के महत्वपूर्ण धारक बन रहे थे - एक प्रवृत्ति जो करीबी निगरानी की गारंटी देती है। तब से, अंतर्राष्ट्रीय नीति संबंधी कार्य ने बाजार के कामकाज, मौद्रिक संप्रभुता, बैंक वित्त पोषण और सीमा पार भुगतान के लिए स्टेबलकॉइन के निहितार्थ पर तेजी से ध्यान केंद्रित किया है।

3.15 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ़) की वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (जीएफ़एसआर), 2026 में विश्लेषण, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी स्टेबल क्वाइन प्रवाह के तेजी से विस्तार की ओर इशारा करता है। स्टेबलकॉइन प्रवाह व्यापक क्रिप्टो आस्ति बाजार गतिविधि से निकटता से जुड़ा हुआ है, जबकि प्रेषण और व्यापार प्रवाह के साथ एक संबंध भी प्रदर्शित करता है। इसके अलावा, कमजोर संस्थागत और राजनीतिक स्थिरता और अल्पकालिक डॉलर-मूल्यवर्ग की आस्तियों तक सीमित पहुंच वाली अर्थव्यवस्थाओं में स्टेबलकॉइन की मांग अक्सर मजबूत रही है, जो विदेशी लेनदेन को सुविधाजनक बनाने और डॉलर एक्सपोजर प्रदान करने में उनकी संभावित

14 आईओएससीओ (2026), "ओवर-द-काउंटर कमोडिटी डेरिवेटिव बाजारों से संबंधित अच्छी प्रथाओं पर परामर्श रिपोर्ट", मार्च।

15 इस रिपोर्ट से पहले कमोडिटी डेरिवेटिव सिद्धांतों की पिछली समीक्षा की गई थी, जिसमें ओटीसी डेटा संग्रह, पदों के एकत्रीकरण, बड़े एक्सपोजर की निगरानी और बाजार तनाव की अवधि के दौरान समय पर विनियामक हस्तक्षेप में निरंतर अंतराल की पहचान की गई थी।

16 सीपीएमआई (2026), "प्रारंभिक मार्जिन प्रस्तावों को लागू करने के लिए अद्यतन मार्गदर्शन और सार्वजनिक प्रकटीकरण पर परामर्श", मई।

17 आईओएससीओ (2026), "इक्विटी बाजारों के लिए ट्रेडिंग दिवस के दौरान बाजार तरलता के विकास पर रिपोर्ट और इक्विटी स्थानों के लिए विस्तारित ट्रेडिंग घंटों पर", मई।

18 आईओएससीओ (2026), "गैर-जीएएपी वित्तीय उपायों पर वक्तव्य", मार्च।

भूमिका के साथ-साथ मुद्रा प्रतिस्थापन और वित्तीय स्थिरता से संबंधित चिंताओं को उजागर करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जीनियस अधिनियम, यूरोपीय संघ का एमआईसीए ढांचा और यूनाइटेड किंगडम की विकसित स्टेबलकॉइन व्यवस्था जैसे क्षेत्राधिकार संबंधी विकास स्पष्ट विनियामक परिधि की दिशा में महत्वपूर्ण कदम को दर्शाते हैं।

3.16 वर्ष 2026[19] के लिए आईओएससीओ के कार्यक्रम ने क्रिप्टो और डिजिटल आस्ति आकलन के लिए एक औपचारिक पद्धति को अंतिम रूप देने और क्षेत्राधिकार[20] में लगातार कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए नियमित विषयगत समीक्षा शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। आईओएससीओ का लक्ष्य टोकनाइजेशन और अन्य वित्तीय प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों में विकास की निगरानी जारी रखना है, जबकि एआई से संबंधित शासन और वित्तीय बाजार प्रकटीकरण पर अलग से पर्यवेक्षी मार्गदर्शन प्रदान करना है। वर्ष 2025-26 के लिए बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के बेसल कमेटी कार्य कार्यक्रम और रणनीतिक प्राथमिकताओं ने भी वित्त के डिजिटलीकरण को फोकस के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में माना है, जिसमें क्रिप्टो आस्ति बाजार के विकास की निरंतर निगरानी और क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए इसके विवेकपूर्ण मानक और प्रकटीकरण ढांचे का कार्यान्वयन शामिल है। इसके अतिरिक्त, 2026 के लिए एफएसबी के कार्य कार्यक्रम ने महत्वपूर्ण सीमा पार जोखिमों सहित डिजिटल परिसंपत्तियों में सीमा पार मुद्दों की निगरानी पर जोर दिया है।

III.1.5 जलवायु वित्त

3.17 आईएमएफ ने वित्तीय विनियमन और पर्यवेक्षण में जलवायु संबंधी जोखिमों के एकीकरण का विश्लेषण करते हुए एक तकनीकी नोट और मैनुअल प्रकाशित किया[21]. इस दस्तावेज़ में बीसीबी, एनजीएफएस, आईएसएसबी और एफएसबी सहित वैश्विक मानक-निर्धारण निकायों द्वारा की गई प्रगति का आकलन किया गया है, और संशोधित बासेल कोर सिद्धांतों, बीसीबीएस स्तंभ 3 जलवायु प्रकटीकरण ढांचे, जलवायु-जोखिम शासन अपेक्षाओं, परिदृश्य विश्लेषण और पर्यवेक्षी समीक्षा प्रक्रियाओं में जलवायु संबंधी जोखिमों को एकीकृत करके पर्यवेक्षी अपेक्षाओं पर प्रकाश डाला गया है। उक्त दस्तावेज़ ने यह निष्कर्ष निकाला कि जलवायु जोखिमों को एक अलग नीतिगत उद्देश्य के बजाय विवेकपूर्ण ढांचे के भीतर मुख्यधारा के वित्तीय जोखिमों के रूप में माना जाना चाहिए।

III.1.6 कृत्रिम बुद्धिमत्ता

3.18 एफएसबी के 2026 कार्यक्रम में, एआई को एक समर्पित कार्यधारा दी गई है। एफएसबी का उद्देश्य वैश्विक मानक-निर्धारण निकायों के समन्वय में वित्तीय संस्थानों द्वारा एआई को अपनाने, उपयोग और नवाचार के लिए ठोस प्रथाओं को विकसित करने पर काम करना है।[22]

3.19 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) ने एक एआई पर्यवेक्षी टूलकिट[23] प्रकाशित किया जिसे प्रतिभूति नियामकों को विनियमित संस्थाओं द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग की देखरेख करने में मदद पंहुचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। टूलकिट फोकस के चार मुख्य क्षेत्रों में आयोजित व्यावहारिक पर्यवेक्षी दृष्टिकोण प्रदान करता है: (i) गवर्नेंस और जोखिम प्रबंधन; (ii) तृतीय-पक्ष और आउटसोर्सिंग जोखिम प्रबंधन; (iii) प्रकटन; और (iv) रिकॉर्डकीपिंग और रिपोर्टिंग। यह प्रकाशन अंतरराष्ट्रीय विनियामक फोकस में उच्च-स्तरीय एआई सिद्धांतों से परिचालन पर्यवेक्षी प्रथाओं के विकास के लिए एक निश्चित बदलाव का प्रतीक है।

3.20 ओईसीडी ने एक व्यापक रिपोर्ट जारी की[24] जिसमें यह बताया गया है कि कि वित्तीय पर्यवेक्षक बैंकिंग, बीमा और पूंजी बाजारों में एआई को कैसे अपना रहे हैं । । रिपोर्ट में मॉडल सत्यापन, डेटा गवर्नेंस, आम एआई प्रदाताओं से उत्पन्न होने

19 आईओएससीओ (2026), "2026 के लिए कार्यक्रम", फरवरी।

20 जैसा कि दिसंबर 2025 के एफ़एसआर में उल्लेख किया गया है, आईओएससीओ ने अक्टूबर 2025 में क्रिप्टो और डिजिटल परिसंपत्ति बाजारों के लिए उनकी सिफारिशों के कार्यान्वयन का आकलन करते हुए एक विषयगत समीक्षा की।

21 आईएमएफ (2026), "जलवायु जोखिम: वित्तीय नियामकों और पर्यवेक्षकों की भूमिका", फरवरी।

22 यह एआई से संबंधित कमजोरियों पर अक्टूबर 2025 की निगरानी रिपोर्ट पर आधारित है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समन्वित नीति मार्गदर्शन की ओर एक कदम का संकेत देता है।

23 आईओएससीओ (2026), "पूंजी बाजारों में एआई के उपयोग के लिए पर्यवेक्षी टूलकिट", मई।

24 ओईसीडी (2026) "वित्त में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का पर्यवेक्षण", जनवरी।

वाले कंसेंट्रेशन जोखिम और पर्यवेक्षी क्षमताओं को मजबूत करने की आवश्यकता से संबंधित उभरती पर्यवेक्षी चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है।

3.21 सामूहिक रूप से, ये पहल एआई से संबंधित जोखिमों को समझने से नियामक फोकस में बदलाव का संकेत देती हैं, जो सामान्य एआई मॉडल, सेवा प्रदाताओं और डेटा बुनियादी ढांचे पर बढ़ती निर्भरता से उत्पन्न होने वाली संभावित कमजोरियों को दूर करने में सक्षम परिचालन पर्यवेक्षी ढांचे को विकसित करने की दिशा में हैं।

III.2 घरेलू नियामकों/ प्राधिकारियों की पहल

3.22 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, वित्तीय विनियामकों ने भारतीय वित्तीय प्रणाली की आघातसहनीयता में सुधार के लिए कई पहलें की हैं (प्रमुख उपाय अनुलग्नक 2 में सूचीबद्ध हैं)।

III.2.1 संबंधित पक्षों को ऋण देने के निर्देश

3.23 प्रतिपक्षों को ऋण देना जो विनियमित संस्थाओं (आरई) से संबंधित या जुड़े हुए हैं, या तो स्वामित्व हिस्सेदारी के माध्यम से या ऋण देने के निर्णयों को नियंत्रित करने और प्रभावित करने की उनकी क्षमता के माध्यम से, बैंक और अन्य हितधारकों के हितों के साथ संघर्ष की चिंताएं बढ़ाते हैं। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने 05 जनवरी 2026 को एक सिद्धांत-आधारित संबंधित-पक्ष ऋण निर्देश जारी किया ।

III.2.2 भारत में निक्षेप बीमा के लिए जोखिम आधारित प्रीमियम फ्रेमवर्क

3.24 रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से डीआईसीजीसी ने निक्षेप बीमा और ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) अधिनियम, 1961 की धारा 15(1) के तहत निक्षेप बीमा के लिए एक जोखिम-आधारित प्रीमियम (आरबीपी) ढांचा पेश किया है, जो बीमित बैंकों की श्रेणियों में अलग-अलग प्रीमियम दरों की अनुमति देता है। इस ढांचे में टियर-1 बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक) और टियर-2 बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, ग्रामीण सहकारी बैंकों और शहरी सहकारी बैंक) के लिए दो-स्तरीय जोखिम मूल्यांकन पद्धति अपनाई गई है।

3.25 आरबीपी फ्रेमवर्क निक्षेप बीमा प्रीमियम को बीमित संस्थानों के अंतर्निहित जोखिम प्रोफाइल के साथ अधिक निकटता से जोड़ता है, जिससे मजबूत गवर्नेंस और विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन बढ़ता है। फ्रेमवर्क में एक विंटेज डिस्काउंट मैकेनिज्म भी शामिल है, जो बीमा दावा भुगतान के बिना डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड (डीआईएफ) में योगदान के निरंतर रिकॉर्ड वाले बैंकों को मान्यता देता है। परिणामतः, बेहतर प्रबंधित बैंक प्रति वर्ष मूल्यांकन योग्य जमाराशियों के प्रति 100 रुपये पर 12 पैसे के मौजूदा एक समान प्रीमियम की तुलना में कम प्रीमियम दरों का भुगतान करने के पात्र होंगे। बीमित बैंकों की प्रीमियम दरों को उनके जोखिम और डीआईसीजीसी से भुगतान किए बिना डीआईएफ में दीर्घकालिक योगदान से जोड़कर, ढांचा वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देता है और बेहतर रेटिंग वाले बैंकों पर प्रीमियम के दबाव को काफी कम करता है।

III.2.3 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

3.26 स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) के तहत निवेश सीमाओं की उपलब्धता के बारे में पूर्वानुमेयता सुनिश्चित करने और व्यापार करने में आसानी को और बढ़ाने के लिए, 01 अप्रैल 2026 से सामान्य मार्ग के लिए संबंधित निवेश सीमा के तहत टी-बिल, राज्य सरकार की प्रतिभूतियों और कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों सहित केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में वीआरआर निवेश पर विचार करने का निर्णय लिया गया; और उन एफपीआई को अनुमति देने के लिए जिन्होंने वीआरआर के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रतिधारण अवधि से अधिक समय तक प्रतिधारण अवधि का लाभ उठाया है, न्यूनतम प्रतिधारण अवधि की समाप्ति के बाद अपने पोर्टफोलियो को आंशिक रूप से या पूरी तरह से समाप्त करने के लिए होगा ।

3.27 इसके बाद, सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए 5 जून 2026 से एफपीआई निवेश ढांचे को और सरल बनाया गया। पूरी तरह से सुलभ मार्ग (एफएआर) के तहत निर्दिष्ट प्रतिभूतियों के सूट का विस्तार 15 वर्ष, 30 वर्ष और 40 वर्ष की अवधि में सरकारी प्रतिभूतियों के सभी नए निर्गमों को शामिल करने और 5, 7, 10, 15, 30 और 40 वर्षों की एफएआर-पात्र अवधि में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड

के सभी नए निर्गमों को शामिल करने के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त, एफपीआई के लिए सामान्य मार्ग के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए अल्पावधि निवेश सीमा, सुरक्षा-वार सीमा और संकेंद्रण सीमा का अनुपालन करने की आवश्यकता को वापस ले लिया गया था। निवेश सीमा की अलग-अलग उप-श्रेणियों, अर्थात् 'सामान्य' और 'दीर्घकालिक' को भी केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए एकल निवेश सीमा में मिला दिया गया था।

III.2.4 विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खातों (बैंकों) जमाराशियों के लिए स्वैप सुविधा

3.28 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एडी श्रेणी-I बैंकों के लिए 30 सितंबर, 2026 तक जुटाई गई जमा राशि के लिए तीन से पांच साल की अवधि और 16 अक्टूबर, 2026 तक एक साल की लॉक-इन अवधि के साथ नए एफ़सीएनआर (बी) जमा (नवीनीकरण सहित) पर अमेरिकी डॉलर-रुपया विदेशी मुद्रा स्वैप सुविधा शुरू की। यह सुविधा बैंकों को वित्तीय बाजार परिचालन विभाग के माध्यम से सप्ताह में केवल एक बार समान दरों पर योग्य जमा की यूएसडी में अदला-बदली करने की अनुमति देती है। बैंकों को आईएसडीए करारों और विशिष्ट क्रेडिट सुविधा निर्देशों से छूट के बावजूद अलग-अलग रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए, मूल्य निर्धारण सीमा का पालन करना चाहिए, और एक अनुपालन घोषणा प्रस्तुत करनी चाहिए। यद्यपि आरबीआई के साथ संबंधित स्वैप को रद्द नहीं किया जा सकता है, जमा की अवधि से पहले एक वर्ष के बाद आहरण की अनुमति है।

III.2.5 विदेशी वाणिज्यिक उधारों और विदेशी मुद्रा उधारों के लिए स्वैप सुविधा

3.29 भारतीय रिज़र्व बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा लिए गए पात्र बाहरी वाणिज्यिक ऋणों और एडी श्रेणी -I बैंकों द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों (ओएफसीबी) के लिए एक यूएस डॉलर-रुपया फॉरेक्स स्वैप सुविधा शुरू की है। यह सुविधा उन ऋणों के लिए है जिनकी अवधि तीन साल या उससे अधिक है, जो 31 दिसंबर, 2026 तक के लिए हैं और यह 15 जनवरी, 2027 तक लागू रहेगी।. यह सुविधा बैंकों को अधिकतम पांच साल की अवधि के लिए 1.5 प्रतिशत सालाना चक्रवृद्धि वार्षिक प्रीमियम पर पिछले सप्ताह की अंतर्वाह मात्रा तक केवल अमेरिकी डॉलर में अंतर्वाह की स्वैप करने की अनुमति देती है। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे वित्तीय बाजार परिचालन विभाग को अनुपालन घोषणा प्रस्तुत करें, लेकिन उन्हें आईएसडीए समझौतों को निष्पादित करने से छूट दी गई है। स्वैप में स्पॉट आधार पर एफबीआईएल रेफरेंस दर पर आरबीआई को यूएसडी बेचना और प्रीमियम के साथ मैच्योरिटी पर उन्हें फिर से खरीदना शामिल है।

III.2.6 अधिकृत डीलरों की ओपेन स्थिति

3.30 विदेशी मुद्रा बाजार में अनुचित अस्थिरता को रोकने और व्यवस्थित बाजार स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए, 27 मार्च 2026 को, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अधिकृत डीलरों को 10 अप्रैल 2026 से प्रभावी प्रत्येक व्यावसायिक दिन के अंत में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के भीतर ऑनशोर डिलिवरी योग्य बाजार में भारतीय रुपये (एनओपी-आईएनआर) से जुड़ी अपनी निवल ओपेन स्थिति बनाए रखने के लिए अनिवार्य किया।

3.31 8 जून 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा **'एफ़सीएनआर (बी) डिपॉजिट के लिए स्वैप सुविधा' और 'बाहरी वाणिज्यिक उधार और विदेशी विदेशी मुद्रा उधार के लिए स्वैप सुविधा'** की शुरुआत के अनुसार 27 मार्च 2026 को अधिकृत डीलरों की एनओपी-आईएनआर स्थिति पर निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अधिकृत डीलर श्रेणी-I बैंकों को इन सुविधाओं के तहत उठाए गए एफ़सीएनआर (बी) जमा, बाहरी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी), और विदेशी विदेशी मुद्रा उधार (ओएफ़सीबी) से उत्पन्न होने वाली स्वैप स्थितियों को बाहर रखने की अनुमति दी गई थी।

3.32 इसके बाद, 23 जून 2026 को, रिज़र्व बैंक ने 27 मार्च 2026 को जारी अधिकृत डीलरों की एनओपी-आईएनआर स्थिति पर निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए और नेट ओवरनाइट ओपन पोजीशन की गणना के लिए अधिकृत डीलर श्रेणी-I बैंकों को उपरोक्त सुविधाओं के तहत उठाए गए एफसीएनआर (बी) जमा, ईसीबी और ओएफसीबी से संबंधित हेज लेनदेन से उत्पन्न होने वाली स्थितियों को बाहर रखने की अनुमति दी।

III.2.7 वित्तीय बाजारों में विशिष्ट पहचानकर्ता – निदेश

3.33 रिज़र्व बैंक ने ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन के लिए विशिष्ट लेनदेन पहचानकर्ता पर निदेश जारी किए। यूटीआई ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन के लिए सौंपा गया एक विशिष्ट पहचानकर्ता है और नीति निर्माताओं को ओटीसी डेरिवेटिव बाजार का व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए ओटीसी डेरिवेटिव लेनदेन की रिपोर्टिंग के लिए विश्व स्तर पर पहचाने गए प्रमुख डेटा तत्वों में से एक के रूप में कल्पना की जाती है। रिज़र्व बैंक के इस कदम से वित्तीय डेटा की गुणवत्ता और सटीकता में सुधार होने की उम्मीद है और इकाई-स्तर और लेन-देन स्तर का पता लगाने और निगरानी के माध्यम से प्रणालीगत जोखिम निगरानी को मजबूत किया जा सकता है। इन अनुदेशों को बाद में वित्तीय बाजारों में विशिष्ट पहचानकर्ताओं पर मास्टर निदेश में समेकित किया गया था, जिसमें दो वैश्विक पहचानकर्ताओं - विधिक एंटीटी पहचानकर्ता (एलईआई) और यूनिक लेनदेन पहचानकर्ता (यूटीआई) के उपयोग पर सभी मौजूदा परिपत्रों को एक ही ढांचे में समेकित किया गया था।

III.2.8 भारतीय रिज़र्व बैंक (नकदी आरक्षित अनुपात और सांविधिक चलनिधि अनुपात) दूसरा संशोधन निदेश, 2026

3.34 भारत में विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए रिज़र्व बैंक के उपायों के एक भाग के रूप में, 8 जून, 2026 और 30 सितंबर, 2026 के बीच बैंकों द्वारा जुटाई गई न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि और अधिकतम पांच वर्ष की अवधि (परिपक्वता पर नवीनीकृत जमा राशियों सहित) को नकदी आरक्षित अनुपात (सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) के रखरखाव से छूट दी गई है। 1 जुलाई, 2026 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से (अर्थात्, 15 जून, 2026 तक एनडीटीएल गणना के आधार पर) और उसके बाद के पखवाड़े से। इसके अतिरिक्त, 19 जून, 2026 और 30 सितंबर, 2026 के बीच बैंकों द्वारा जुटाए गए तीन साल या उससे अधिक की अवधि (परिपक्वता पर नवीनीकृत जमा सहित) की नई अनिवासी (बाहरी) रुपया (एनआरई) सावधि जमा को भी 16 जुलाई, 2026 से शुरू होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से सीआरआर और एसएलआर के रखरखाव से छूट दी गई है (अर्थात्, 30 जून तक एनडीटीएल गणना के आधार पर, 2026) और उसके बाद के पखवाड़े। आरक्षित निधि के रखरखाव पर छूट मूल जमा राशि के लिए तब तक उपलब्ध है जब तक कि जमाराशियां बैंक बही-खातों में नहीं रखी जाती हैं।

III.2.9 जोखिम निगरानी तथा अंतर-बैंक कारोबार

3.35 विदेशी मुद्रा बाजार में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को देखते हुए, 01 अप्रैल 2026 को भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारियों को निवासी और गैर-निवासी उपयोगकर्ताओं को भारतीय रुपया वाले गैर-डेलीवरेबल्स व्युत्पन्नी संविदाओं की पेशकश करने से प्रतिबंधित कर दिया था। प्राधिकृत व्यापारियों को भारतीय रुपया वाले उन सभी विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं को पुनः बुक करने की उपयोगकर्ता को अनुमति देने से भी प्रतिबंधित किया गया था जिन्हें अनुदेशों के जारी होने की तिथि के बाद रद्द कर दिया गया था, चाहे वे डेलीवरेबल्स हों या गैर-डेलीवरेबल्स। इसके अलावा, प्राधिकृत व्यापारियों को अपने संबंधित पक्षकारों के साथ भारतीय रुपया वाले विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा करने से प्रतिबंधित किया गया था। भारतीय रुपया वाले गैर-डेलीवरेबल्स व्युत्पन्नी संविदाओं की पेशकश करने तथा भारतीय रुपया वाले विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं को रद्द करने व पुनः बुक करने पर लगे प्रतिबंधों को 20 अप्रैल 2026 को वापस ले लिया गया था। इसके अतिरिक्त, विद्यमान विनियामकीय ढाँचा के अंतर्गत, प्राधिकृत व्यापारियों को मौजूदा संविदाओं को रद्द करने और आगे बढ़ाने के साथ-साथ गैर-संबंधित गैर-निवासी उपयोगकर्ताओं के साथ बैक-टू-बैक लेनदेन के लिए अपने संबंधित पक्षकारों के साथ भारतीय रुपया वाले विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदा करने की अनुमति दी गई।

III.2.10 प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों द्वारा संबंधित पक्षकारों के लेनदेन की रिपोर्टिंग – निदेश

3.36 विदेशी मुद्रा बाजार में अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अनुदेश जारी कर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को उनके संबंधित पक्षकारों द्वारा वैश्विक स्तर पर किए गए भारतीय रुपया वाले विदेशी मुद्रा व्युत्पन्नी संविदाओं की रिपोर्ट भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड को करना

अनिवार्य किया गया है। ये रिपोर्टिंग अपेक्षाएं विभिन्न चरणों में 1 जुलाई 2027 से लागू होंगी।

III.2.11 वाणिज्यिक बैंकों के लिए आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान और आय निर्धारण पर निदेश

3.37 रिज़र्व बैंक ने क्रेडिट जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को और मजबूत बनाने, विनियमित संस्थाओं के बीच तुलनात्मकता में सुधार लाने और विनियामकीय ढांचे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत वित्तीय रिपोर्टिंग सिद्धांतों के और अधिक समीप लाने के उद्देश्य से आस्ति वर्गीकरण, प्रावधान और आय निर्धारण पर 01 अप्रैल 2027 से प्रभावी निदेश जारी किए हैं। ये निदेश मौजूदा आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) मानदंडों को निरस्त करते हैं और एक भविष्योन्मुखी प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) ढांचा पेश करते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, तीन-स्तरीय प्रावधान का दृष्टिकोण और प्रभावी ब्याज दर पद्धति के आधार पर आय निर्धारण शामिल है।

III.2.12 पर्यवेक्षी अनुदेशों का समेकन

3.38 पिछले वर्ष, रिज़र्व बैंक ने 'ज्यों का त्यों' के आधार पर विनियामकीय अनुदेशों का व्यापक समेकन कार्य पूरा किया था[25]। इस वर्ष, पर्यवेक्षी अनुदेशों के लिए ऐसा ही कार्य किया गया है। तदनुसार, नौ कार्यात्मक क्षेत्रों पर मौजूद पर्यवेक्षी निदेशों को समेकित करते हुए 64 'मास्टर निर्देशों' के प्रारूप सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए आरबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित किए गए हैं।

III.2.13 'निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि' पर संशोधन निदेश '

3.39 भारतीय रिज़र्व बैंक ने विभिन्न बैंक श्रेणियों के लिए निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफ़आर) पर अनुदेशों की व्यापक समीक्षा की और उनमें संशोधन किए। इन संशोधनों के साथ, आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) तथा स्थानीय क्षेत्र के बैंकों (एलएबी) के लिए आईएफ़आर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है क्योंकि इन बैंकों पर अलग से बाजार जोखिम पूंजी प्रभार लागू होते हैं और निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन पर संशोधित मानदंड लागू होते हैं। इन श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले बैंकों को अब अपने मौजूदा आईएफआर शेष को निर्दिष्ट टियर 1 पूंजी घटकों में स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई है, जिससे उनके टियर 1 पूंजी अनुपात मजबूत होने की उम्मीद है। अन्य बैंक श्रेणियों के लिए, आईएफआर की गणना पर विनियामकीय स्पष्टता बेहतर करने और सभी बैंक श्रेणियों में सामंजस्यपूर्ण अनुदेश सुनिश्चित करने हेतु नियमों में संशोधन किए गए हैं।

III.2.14 भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक- क्रेडिट जोखिम के लिए पूंजी प्रभार – मानकीकृत दृष्टिकोण) निदेश, 2026 (27 अप्रैल 2026 को जारी)

3.40 यह निदेश क्रेडिट जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना के मौजूदा मानकीकृत दृष्टिकोण ढांचे को संशोधित करता है, जिसका उद्देश्य इसकी मजबूती, सूक्ष्मता और जोखिम संवेदनशीलता को बढ़ाना है। बासेल III के मानकों पर आधारित ये संशोधित निदेश, वैश्विक संकट के पश्चात के सुधारों के एक प्रमुख तत्व को लागू करते हैं जिसे भारतीय परिप्रेक्ष्य के लिए समुचित रूप में तैयार किया गया है। मौजूदा मानदंडों की तुलना में मुख्य बदलावों में शामिल हैं: (i) क्रेडिट जोखिमों के जोखिम भार के लिए अधिक सूक्ष्म और जोखिम-संवेदनशील प्रावधान; (ii) प्रतिपक्षकार बैंकों पर दावों के लिए बाहरी क्रेडिट रेटिंग आधारित दृष्टिकोण; (iii) गैर-श्रेणीकृत एमएसएमई का अपेक्षाकृत कमतर जोखिम भार के लिए अधिक कवरेज; (iv) विनियामकीय खुदरा श्रेणी के अंतर्गत 'ट्रांजेक्टर्स '[26] को शामिल करना; (v) गैर-बाजार तुलन-पत्रेत्तर जोखिमों के लिए क्रेडिट रूपांतरण कारकों (सीसीएफ) को ऐसे जोखिमों से जुड़ी

25 25 इस कार्य में 9,000 से अधिक मौजूदा विनियामकीय परिपत्रों/दिशानिर्देशों को 238 कार्य-वार मास्टर निदेशों (एमडी) में समेकित किया जाना शामिल था, जो विनियमित संस्थाओं की प्रत्येक श्रेणी विशेष के लिए थे।

26 'ट्रांजेक्टर्स' से तात्पर्य क्रेडिट कार्ड और चार्ज कार्ड जैसी सुविधाओं के संदर्भ में उन देनदारों से है जहाँ पिछले 12 महीनों के लिए प्रत्येक निर्धारित पुनर्भुगतान तिथि पर (तीन दिनों की अनुग्रह अवधि सहित) शेष राशि का पूर्ण भुगतान कर दिया गया है।

वास्तविक जोखिम क्षमता के अनुरूप बनाना; (vi) घरेलू और विदेशी कॉरपोरेट्स के लिए जोखिम भार का एकीकरण; 'निधियों में इक्विटी निवेश' के लिए विशिष्ट व्यवहार; और (vii) क्रेडिट श्रेणीकरण एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट की गई श्रेणी की संप्रेक्षित चूक दर के आधार पर कॉरपोरेट एक्सपोज़र के लिए जोखिम भार में समायोजन। ये संशोधित अनुदेश 1 अप्रैल 2027 से प्रभावी होंगे।

III.2.15 वित्तीय क्षेत्र में क्वांटम प्रौद्योगिकी

3.41 क्वांटम कंप्यूटिंग (क्यूसी) क्वांटम यांत्रिकी के सुपरपोजिशन, 'क्वांटम उलझाव' और 'क्वांटम व्यतिकरण' जैसे सिद्धांतों के सहारे ऐसी गणना करती है जिन्हें पारंपरिक कंप्यूटरों के लिए संभालना बहुत जटिल होता है। क्यूसी अभूतपूर्व गति से जटिल गणना करने की अपनी क्षमता के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र के कई हिस्सों में संभावित लाभ प्रदान करता है, जैसे कि जोखिम प्रबंधन, पोर्टफोलियो अनुकूलन, समष्टि आर्थिक प्रतिमानन, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी आदि। हालांकि, क्यूसी वित्तीय क्षेत्र के लिए व्यावहारिक चुनौतियां भी उत्पन्न करता है, विशेष रूप से क्रिप्टोग्राफी के क्षेत्र में। आधुनिक वित्तीय प्रणालियाँ वित्तीय डिजिटल संचार को सुरक्षित करने के लिए मुख्य रूप से एसिमिट्रिक एन्क्रिप्शन जैसे रिवेस्ट-शमीर-एडलमैन (आरएसए) और इलिप्टिक-कर्व क्रिप्टोग्राफी (ईसीसी) पर निर्भर करती हैं। एक पर्याप्त रूप से उन्नत क्वांटम कंप्यूटर, जिसे क्रिप्टोग्राफिक रूप से प्रासंगिक क्वांटम कंप्यूटर (सीआरक्यूसी) कहा जाता है, में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले इन एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम को भेदने की क्षमता होती है।

3.42 वित्तीय क्षेत्र के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी के अवसरों, जोखिमों, तैयारियों और विनियामकीय ढांचों की पर्याप्तता का आकलन करने तथा एक क्वांटम-सुरक्षित भारतीय वित्तीय प्रणाली बनाने हेतु रोडमैप की सिफारिश करने के लिए, आरबीआई ने 'क्वांटम सुरक्षित एवं अनुकूली वित्तीय परिवेश' (क्यू-एसएएफई) हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

III.2.16 के वाईसी निर्देश, 2025 में संशोधन

3.43 ऐसी विनियमित संस्थाएं जिन्होंने 'केंद्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री' (सीकेवाईसीआर) पर अपने ग्राहकों के केवाईसी अभिलेख अपलोड/अपडेट किए हैं और उनके सापेक्ष वे विनियमित संस्थाएं जिन्होंने सीकेवाईसीआर से ऐसे रिकॉर्ड डाउनलोड किए हैं, उनकी जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने हेतु केवाईसी निदेश, 2025 में संशोधन किए गए थे। वह विनियमित संस्था जिसने सीकेवाईसीआर पर ग्राहक के केवाईसी रिकॉर्ड अंतिम बार अपलोड/अपडेट की है, ग्राहक की पहचान और/या पते को सत्यापित करने के लिए जिम्मेदार होगी। तदनुसार, सीकेवाईसीआर से उस रिकॉर्ड डाउनलोड करने और उन पर भरोसा करने वाली किसी भी विनियमित संस्था को ग्राहक की पहचान और/या पते की प्रामाणिकता को पुनः सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते सीकेवाईसीआर से डाउनलोड किए गए केवाईसी रिकॉर्ड अद्यतन हों और पीएमएल अधिनियम, 2002 / पीएमएल नियम, 2005 के अनुपालन में हों। सीकेवाईसीआर से डाउनलोड किए गए केवाईसी रिकॉर्ड पर भरोसा करने वाली विनियमित संस्था ग्राहक की पहचान और/या पते के सत्यापन को छोड़कर, सीडीडी प्रक्रिया और निदेशों के प्रावधानों के सभी पहलुओं के लिए जिम्मेदार बनी रहेगी।

III.2.17 प्रौद्योगिकी-सक्षम केवाईसी: ग्राहक सुविधा और जोखिम प्रबंधन में संतुलन

3.44 आधार ई-केवाईसी प्रमाणीकरण और आधार ऑफलाइन सत्यापन, डिजिलॉकर, वीडियो केवाईसी और केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) में जारी दस्तावेजों सहित समकक्ष ई-दस्तावेजों जैसे पहचान के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधानों की शुरुआत के साथ पिछले डेढ़ दशक में अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रियाओं में एक बड़ा बदलाव आया है।

3.45 हालांकि प्रौद्योगिकी केवाईसी प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने में मदद करती है, मनी लॉन्ड्रिंग (एमएल) और आतंकवादी वित्तपोषण (टीएफ) से उत्पन्न जोखिमों को नई

27 पर्यवेक्षण एक ऐसी अवस्था को दर्शाता है जहाँ एक क्यूबिट आंशिक रूप से 'शून्य' और आंशिक रूप से 'एक' की स्थिति में होता है, और इसलिए वह एक ही समय में दोनों अवस्थाओं में मौजूद रहता है। दो क्यूबिट्स ' क्वांटम उलझाव' की स्थिति में हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वे एक साझा क्वांटम अवस्था में जुड़े होते हैं। क्वांटम व्यतिकरण क्वांटम अवस्थाओं की वह क्षमता है जिसके तहत वे या तो एक-दूसरे के प्रभाव को बढ़ा सकती हैं (रचनात्मक इंटरफेरेंस) या एक-दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर सकती हैं (विनाशकारी इंटरफेरेंस) ।

प्रौद्योगिकियों और उत्पादों की शुरूआत से पहले पहचाना और उनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) की सिफारिशों के अनुसार, वित्तीय संस्थानों को नए उत्पादों के विकास और नई व्यावसायिक पद्धतियों के संबंध में उत्पन्न होने वाले धन शोधन अथवा आतंकवादी वित्तपोषण जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करना अपेक्षित है, जिसमें नए सुपुर्दगी तंत्र शामिल हैं और नए और पहले से मौजूद दोनों उत्पादों के लिए नई या विकासशील प्रौद्योगिकियों का उपयोग शामिल है।

3.46 तदनुसार, आरबीआई केवाईसी निर्देश विनियमित संस्थाओं को नए उत्पादों के विकास और नए वितरण तंत्र सहित नई व्यावसायिक प्रथाओं के संबंध में उत्पन्न होने वाले एमएल/टीएफ जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करने और नए और मौजूदा दोनों उत्पादों के लिए नई या विकासशील प्रौद्योगिकियों के उपयोग को अनिवार्य करते हैं। इस तरह का जोखिम मूल्यांकन अभ्यास सालाना किया जाएगा और अभ्यास के परिणाम को विनियमित इकाई के बोर्ड के सामने रखा जाएगा।

III.2.18 वित्तीय क्षेत्र साइबर सुरक्षा कार्यनीति- अद्यतन प्रगति

3.47 अगस्त 2025 में एफ़एसडीसी द्वारा अनिवार्य वित्तीय क्षेत्र साइबर सुरक्षा रणनीति (एफ़एससीएसएस) पर अंतर-मंत्रालयी समूह ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड कंप्यूटिंग और क्वांटम प्रौद्योगिकियों जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए वित्तीय क्षेत्र जोखिम प्रबंधन ढांचे में नियामक सामंजस्य और एकीकृत साइबर सुरक्षा मानकों; तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन को मजबूत करना; उपभोक्ता संरक्षण और सहायक कानूनी वास्तुकला को बढ़ाना; साइबर ऑडिट, घटना रिपोर्टिंग और सूचना-साझाकरण तंत्र में सुधार; और क्रॉस-सेक्टर निर्भरता और परस्पर जुड़े महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे से उत्पन्न होने वाले साइबर जोखिमों से निपटान को कवर करते हुए अपने घटक कार्यधाराओं में अपना विचार-विमर्श जारी रखा है। एफएससीएसएस दस्तावेज का मसौदा तैयार होने के अंतिम चरण में है। इसको अपनाए जाने पर, रणनीति शासन ढांचे, जवाबदेही संरचनाओं और कार्यान्वयन की समयसीमा स्थापित करेगी, जिसके भीतर प्रत्येक वित्तीय क्षेत्र नियामक अपने क्रॉस-रेगुलेटरी साइबर सुरक्षा दायित्वों का संचालन करेगा।

III.2.19 एफपीआई और एफवीसीआई के लिए विश्वसनीय विदेशी निवेशकों के लिए एकल पटल स्वचालित और सामान्यीकृत पहुंच (स्वागत-एफआई) फ्रेमवर्क

3.48 सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और विदेशी उद्यम पूंजी निवेशक (एफवीसीआई) के लिए स्वागत-एफआई ढांचे के तहत दो परिपत्र जारी किए, जिसमें निर्बाध एफपीआई-एफवीसीआई पंजीकरण, कुछ निवेश और योगदान सीमा से छूट, 10 साल के पंजीकरण/केवाईसी वैधता और एकीकृत डिपॉजिटरी-आधारित लेखांकन और निवेश अनुभव सहित महत्वपूर्ण छूट दी गई है। इन छूटों का लाभ निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले मौजूदा और नए एफपीआई और एफवीसीआई द्वारा उठाया जा सकता है। यह ढांचा नियामक जटिलता को कम करेगा और निवेशक-अनुकूल गंतव्य के रूप में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा।

III.2.20 बाजार अवसंरचना संस्थानों (एमआईआई) के गवर्नेंस को मजबूत करना

3.49 भारतीय प्रतिभूति बाजार तेजी से विकास के बीच गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए, सेबी ने एमआईआई को अपने गवर्निंग बोर्ड में प्रथमतः महत्वपूर्ण संचालन के लिए और दूसरा विनियामक, अनुपालन, जोखिम प्रबंधन और निवेशक शिकायतों के लिए दो समर्पित कार्यकारी निदेशक (ईडी) नियुक्त करने का आदेश दिया है। संबंधित सांविधिक समितियों को एमडी की उपस्थिति के बिना संबंधित वर्टिकल के ईडी के साथ अलग-अलग त्रैमासिक बैठकें आयोजित करनी चाहिए और ईडी को अपने संबंधित कार्यक्षेत्रों पर सीधे गवर्निंग बोर्ड को रिपोर्ट करना चाहिए।

III.2.21 री-केवाईसी करते समय एनआरआई के लिए भारत में जियो-टैगिंग की अपेक्षाओं में छूट

3.50 धन शोधन रोकथाम (पीएमएल) नियम, 2005 के अनुसार, भारत में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थिति को अनिवार्य किए बिना, डिजिटल केवाईसी के दौरान केवल ग्राहकों के अक्षांश और देशांतर को कैप्चर करना आवश्यक था। इसलिए, सेबी ने इस ढांचे की समीक्षा की और एनआरआई के लिए री-केवाईसी के लिए भारत में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता में ढील दी। यह छूट एनआरआई को निर्बाध तरीके से डिजिटल रूप से री-केवाईसी पूरा करने में सक्षम बनाती है। यह छूट एनआरआई को निर्बाध तरीके से डिजिटल रूप से री-केवाईसी पूरा करने में सक्षम बनाती है।

III.2.22 निवेश करने में आसानी – भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण और अभौतिकीकरण के लिए विशेष पटल

3.51 सेबी ने भौतिक शेयर प्रमाण पत्र रखने वाले निवेशकों की मदद करने के लिए एकबारगी विशेष पटल की शुरुआत की, जिनके हस्तांतरण अनुरोधों को पहले संसाधित नहीं किया गया था ताकि भौतिक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण विलेख को फिर से दर्ज किया जा सके। वर्ष 2019 में भौतिक स्थानान्तरण बंद होने के बाद दस्तावेजीकरण संबंधी मुद्दों के कारण ऐसे कई मामले अटके हुए थे। सेबी ने अब 05 फरवरी 2026 से 04 फरवरी 2027 तक के एक वर्ष की अवधि के लिए खोले गए एक विशेष पटल के दौरान पुराने स्थानांतरण के अनुरोधों (जहां दस्तावेज 1 अप्रैल 2019 से पहले निष्पादित किए गए थे) को फिर से जमा करने या नए सिरे से जमा करने की अनुमति दी है। इस पहल का उद्देश्य लंबित पुराने मामलों को समाधान करना, निवेशकों के लिए निवेश में आसानी प्रदान करना और उनके द्वारा खरीदी गई प्रतिभूतियों में उनके अधिकारों को सुरक्षित करना है।

III.2.23 सेबी (मर्चेंट बैंकर) विनियम, 1992 में संशोधन

3.52 अन्य बातों के साथ-साथ इन संशोधनों में मर्चेंट बैंकरों का वर्गीकरण, निवल मूल्य और तरल निवल मूल्य अपेक्षाओं, न्यूनतम राजस्व मानदंड, प्रमुख कर्मचारियों और अनुपालन अधिकारियों के लिए अनिवार्य प्रमाणन अपेक्षाएं, पृथक व्यावसायिक इकाइयों (एसबीयू) के माध्यम से कार्यकलापों का पृथक्करण, मुख्य कार्यकलापों की आउटसोर्सिंग पर प्रतिबंध और हितों के टकराव से बचने के लिए उन्नत प्रावधान किए गए हैं।

3.53 मर्चेंट बैंकरों के लिए विनियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए, सेबी का उद्देश्य प्रभावी संघर्ष प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय/परिचालन क्षमताओं, अनुपालन और निवेशक सुरक्षा को बढ़ाना है। पृथक/अलग बिजनेस यूनिट्स (एसबीयू) की शुरुआत का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना और मर्चेंट बैंकर की विभिन्न व्यावसायिक लाइनों से सेबी-विनियमित गतिविधियों के लिए जोखिम संक्रमण को रोकना है।

III.2.24 गूगल प्ले स्टोर पर सेबी के साथ पंजीकृत ब्रोकरों के स्टॉक ट्रेडिंग ऐप के लिए सत्यापित लेबल

3.54 धोखाधड़ी वाले ट्रेडिंग ऐप्स का प्रसार खुदरा निवेशकों के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है, जिसमें स्कैमर्स वास्तविक ऐप्स का प्रतिरूपण करते हैं। सेबी ने गूगल के सहयोग से भारत में सभी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप के लिए गूगल प्ले पर अपनी तरह का पहला "सत्यापित" बैज लागू करने की पहल की है, जो सेबी के साथ पंजीकृत संस्थाओं द्वारा पेश किए जाते हैं। सेबी ने गूगल के सहयोग से भारत में सेबी के साथ पंजीकृत संस्थाओं द्वारा पेश किए जाने वाले सभी स्टॉक ट्रेडिंग ऐप के लिए गूगल प्ले पर अपनी तरह का पहला "सत्यापित" बैज लागू करने की पहल की है।

III.2.25 प्रोजेक्ट सुदर्शन-एआई-संचालित धोखाधड़ी का पता लगाना

3.55 बढ़ते फिनफ्लुएंसर के कदाचार और डिजिटल धोखाधड़ी का मुकाबला करने के लिए, सेबी ने प्रोजेक्ट सुदर्शन (एंटी-फ्रॉड के लिए रीयल-टाइम स्कैनर के माध्यम से अनधिकृत डिजिटल गतिविधि की निगरानी) का संचालन किया, जो एक एआई-संचालित रेगटेक प्लेटफॉर्म है जो सोशल मीडिया की सक्रिय, वास्तविक समय आधारित निगरानी को सक्षम बनाता है। ऑडियो, विजुअल और प्रासंगिक संकेतों (क्षेत्रीय भाषाओं सहित) का विश्लेषण करने के लिए उन्नत मल्टीमॉडल एआई का उपयोग करते हुए, सिस्टम जोखिम स्कोरिंग और अलर्ट जनरेशन को स्वचालित करता है। यह गारंटीकृत रिटर्न दावे, धोखाधड़ी वाले प्रमाणन, इकाई प्रतिरूपण और अपंजीकृत निवेश सलाह, निगरानी को मैनुअल रूप से स्वचालित में स्थानांतरित करने जैसी भ्रामक प्रथाओं का पता लगाने के लिए प्लेटफार्मों पर सार्वजनिक सामग्री को लगातार स्कैन करता है।

III.2.26 किसी अन्य वित्तीय क्षेत्र के नियामक के क्षेत्राधिकार में आने वाले वित्तीय साधनों की रेटिंग करते समय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सीआरए) पर दायित्व

3.56 सेबी ने सीआरए (क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों) के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बदलाव किया है, ताकि वे दूसरे फाइनेंशियल सेक्टर रेग्यूलेटर (एफ़एसआर) के दायरे में आने वाले फाइनेंशियल प्रोडक्ट और इंस्ट्रूमेंट की रेटिंग कर सकें, भले ही संबंधित एफ़एसआर ने उनके लिए कोई खास रेटिंग गाइडलाइन जारी न की हो। नियामक स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए, सीआरए को प्रकटीकरण के लिए अलग-अलग शिकायत

निवारण ईमेल आईडी और वेबसाइट अनुभाग बनाए रखकर गैर-सेबी गतिविधियों को अलग करना चाहिए। रेटिंग रिपोर्ट और विपणन सामग्री को लागू विनियामक का स्पष्ट रूप से खुलासा करना चाहिए और यह बताना चाहिए कि सेबी का निवेशक संरक्षण ढांचा उन विशिष्ट उपकरणों पर लागू नहीं होता है। सेबी की न्यूनतम निवल मूल्य आवश्यकताओं को अप्रभावित रहना चाहिए; अन्य एफएसआर से किसी भी अतिरिक्त पूंजी आवश्यकताओं को स्वतंत्र रूप से पूरा किया जाना चाहिए। यह ढांचा निवेशकों की पारदर्शिता को बढ़ाता है और क्षेत्राधिकार ओवरलैप को रोकता है।

III.2.27 बीमा क्षेत्र में भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी एएस) का कार्यान्वयन

3.57 आईआरडीएआई ने आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त और निवेश कार्य) (संशोधन) विनियम, 2026 को अधिसूचित किया, जो भारतीय लेखा मानकों के तहत वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए रूपरेखा बनाया गया है। विनियम दो साल की समानांतर रिपोर्टिंग अवधि प्रदान करते हैं जिसमें बीमाकर्ताओं को भारतीय लेखा मानकों और आईजीएएपी-आधारित जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित कार्य योजना और मासिक प्रगति रिपोर्टिंग के अधीन उन बीमाकर्ताओं के लिए एक साल की सहनशीलता उपलब्ध है जो भारतीय लेखा मानकों को पूरी तरह से अपनाने में असमर्थ है। कार्यान्वयन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, आईआरडीएआई, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई), भारतीय बीमांकक संस्थान (आईएआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक संयुक्त विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है। कार्यान्वयन पर भी एक परिपत्र जारी किया गया था, जिसमें प्रमुख परिचालन, लेखा और नियामक पहलुओं को स्पष्ट किया गया था, साथ ही पूरे क्षेत्र में लगातार अपनाने का समर्थन करने के लिए क्षमता निर्माण के उपाय भी किए गए थे।

III.2.28 आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस) विनियम, 2024 के तहत जारी मास्टर परिपत्र में संशोधन

3.58 आईआरडीएआई ने बीमा कंपनियों में प्रमुख प्रबंधन व्यक्तियों (केएमपी) के परिवर्तनीय वेतन का निर्धारण करने के लिए प्रदर्शन मापदंडों को संशोधित करते हुए एक परिपत्र जारी किया, जिसका उद्देश्य ग्राहक विश्वास, पारदर्शिता, जवाबदेही और पॉलिसीधारक हितों के साथ प्रोत्साहनों के संरेखण को मजबूत करना है। संशोधित ढांचे के तहत, केएमपी निष्पादन मूल्यांकन का 50 प्रतिशत आईआरडीएआई द्वारा अनिवार्य मापदंडों पर आधारित होना चाहिए, जिसमें वित्तीय सुदृढ़ता, उत्पाद निष्पादन, दावों की जवाबदेही, शिकायत निवारण, भारतीय लेखा मानकों (आईएनडी एएस) का कार्यान्वयन और ग्राहक बातचीत और वितरण चैनलों में डार्क पैटर्न को समाप्त करना शामिल है। शेष 50 प्रतिशत का निर्धारण बीमाकर्ता की नामांकन पारिश्रमिक समिति/बोर्ड द्वारा व्यवसाय विशिष्ट उद्देश्यों के आधार पर किया जा सकता है।

3.59 यह ढांचा ग्राहक-केंद्रित परिणामों, जिसमें ग्राहक की संतुष्टि, समय पर दावे और शिकायत का समाधान, बार-बार आने वाली शिकायतों और सेवा विफलताओं में कमी, पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रियाएं और उत्पाद निष्पादन संकेतक शामिल हैं, पर अधिक बल देता है । यह अधिक विस्तृत प्रकटीकरण के माध्यम से दावों से निपटने और शिकायत प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास करता है। बीमाकर्ताओं को अपनी वेबसाइट पर पिछले तीन वर्षों के लिए संबंधित जानकारी के साथ केएमपी पारिश्रमिक की गणना के लिए अपनाए गए मापदंडों का खुलासा आसानी से सुलभ और समझने योग्य प्रारूप में करना होता है।

III.2.29 पॉलिसीधारकों के लिए शिक्षा और संरक्षण कोष की स्थापना

3.60 सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) अधिनियम, 2025 (एसबीएसआर अधिनियम) ने पॉलिसीधारकों की शिक्षा और संरक्षण निधि (पीईपीएफ़) के गठन को अनिवार्य कर दिया है। तदनुसार, आईआरडीएआई ने ₹800 करोड़ के प्रारंभिक योगदान के साथ फंड का गठन किया। निधि पर अर्जित राशि का उपयोग पॉलिसीधारकों की शिक्षा और सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाएगा।

3.61 पीईपीएफ कोष का निर्माण प्राधिकारी अर्थात्, केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदान, बीमाकर्ताओं और अन्य संस्थानों से स्वैच्छिक दान और दंड से आवर्ती प्रवाह सहित

प्रवाह के माध्यम से किया जाएगा। आईआरडीएआई द्वारा इसे दिया जाएगा और उपयोग किया जाएगा ।

III.2.30 वार्षिक शुल्क के भुगतान और पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने के लिए संक्रमणकालीन व्यवस्था (मध्यस्थ)

3.62 सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) अधिनियम, 2025 (एसबीएसआर अधिनियम) ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी में संशोधन किया है, ताकि बीमा मध्यस्थों के लिए तीन साल की पंजीकरण वैधता अवधि को वार्षिक शुल्क के भुगतान के अधीन एक स्थायी पंजीकरण ढांचे के साथ बदल दिया जा सके। परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए 5 फरवरी 2026 और 30 जून 2026 के बीच नए पंजीकरण या पंजीकरण के नवीनीकरण की मंजूरी देने के लिए बीमा मध्यस्थों के लिए एक अंतरिम व्यवस्था शुरू की गई है।

III.2.31 सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान मोटर थर्ड पार्टी (एमटीपी) बीमा संबंधी अभियान (11-17 जनवरी 2026)

3.63 आईआरडीएआई ने सामान्य बीमाकर्ताओं (विशेष बीमाकर्ताओं के अलावा) को सड़क सुरक्षा सप्ताह (11-17 जनवरी 2026) के दौरान मोटर थर्ड पार्टी (एमटीपी) बीमा जागरूकता पर एक केंद्रित 31 जनवरी 2026 तक जारी रहने वाले अभियान चलाने का निर्देश दिया। इस पहल का उद्देश्य एमटीपी बीमा की अनिवार्य प्रकृति और लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, उच्च स्तर के गैर-बीमाकृत वाहनों (50 प्रतिशत से अधिक) का निपटान करना और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना था। बीमाकर्ताओं को सलाह दी गई कि वे पॉलिसी खरीद और नवीनीकरण को सरल बनाएं, डिजिटल और प्रत्यक्ष चैनलों के माध्यम से जागरूकता गतिविधियां शुरू करें और गैर-बीमाकृत वाहनों को कम करने पर इसके प्रभाव की निगरानी रखते हुए राज्य बीमा योजना के तहत राज्य सरकारों के सहयोग से पहल जारी रखें।

III.2.32 स्वास्थ्य बीमा परिदृश्य में प्रणालीगत मुद्दों को हल करने के उपाय

3.64 पॉलिसीधारक की बढ़ती शिकायतों को दूर करने, विश्वास में सुधार करने और स्वास्थ्य बीमा पारिस्थितिकी तंत्र में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए, आईआरडीएआई, सीआईआई के सहयोग से, स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के बीच एक संरचित जुड़ाव की सुविधा प्रदान कर रहा है। इस पहल के एक भाग के रूप में, उद्योग के प्रमुख मुद्दों की जांच करने और दावा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा प्रदाता जुड़ाव, धोखाधड़ी शमन, मानकीकरण, पारदर्शिता और पॉलिसीधारक अनुभव से संबंधित कार्रवाई योग्य समाधानों की सिफारिश करने के लिए 10 विषयगत समूहों का गठन करने पर सहमति व्यक्त की गई है।

3.65 मार्च से दिसंबर 2026 तक चलने वाली पहल के पहले चरण के तहत, प्रणालीगत मुद्दों की जांच करने और विशिष्ट समाधानों और कार्यनीतियों की सिफारिश करने के लिए बीमाकर्ताओं, अस्पतालों, अस्पताल संघों, सामान्य बीमा परिषद, डायग्नोस्टिक केंद्रों और शिक्षाविदों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए पांच समूहों का गठन किया गया है। कार्यान्वयन को बढ़ावा देने, प्रमुख मुद्दों पर मार्गदर्शन और अभिसरण प्रदान करने के लिए एक संयुक्त समन्वय समिति के माध्यम से उनकी प्रगति और सिफारिशों की मासिक समीक्षा की जा रही है।

III.2.33 बीमाकर्ताओं के निवेश के लिए विनियामक विकास

3.66 आईआरडीएआई ने बीमाकर्ताओं को एआईएफ के श्रेणी I और II में निवेश करने की अनुमति दी, हालांकि, बीमाकर्ताओं को भारत के बाहर एक्सपोजर वाले एआईएफ में निवेश करने की अनुमति नहीं दी गयी थी। एआईएफ में और निवेश को प्रोत्साहित करने और निवेश यील्ड में सुधार करने के लिए, आईआरडीएआई ने बीमाकर्ताओं को "एक्सक्यूज़ राईट्स" के साथ भारत के बाहर एक्सपोजर वाले एआईएफ में निवेश करने की अनुमति दी और ऐसे एआईएफ द्वारा भारत के बाहर बीमाकर्ताओं के निवेश की आय का निवेश नहीं किया जा रहा है। बीमाकर्ताओं को ऐसे एआईएफ में निवेश करते समय परिचालन संबंधी नियंत्रण की आवश्यकता होती है।

III.2.34 इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में संलग्न पब्लिक लिमिटेड स्पेशल पर्पज व्हीकल्स (एसपीवी) में निवेश

3.67 दिसंबर 2025 में एक परामर्श पत्र जारी किया गया था, जिसमें परिचालन परियोजनाओं और स्थिर नकदी प्रवाह के साथ पब्लिक लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एसपीवी द्वारा जारी कर्ज लिखतों के लिए निवेश मानदंडों को सरल बनाने के प्रस्ताव पर हितधारकों की टिप्पणियां मांगी गई थीं। इस प्रस्ताव का उद्देश्य मूल कंपनी की गारंटी और निवल मूल्य से संबंधित मौजूदा आवश्यकताओं को दूर करना है, जो इस शर्त के अधीन है कि निर्गम प्राप्तियों का उपयोग मौजूदा एसपीवी ऋण को पुनर्वित्त करने के लिए किया जाए, ऋणदाता द्वारा पुनर्वित्त ऋण को मानक के रूप में वर्गीकृत किया जाए और जारी किए गए ऋण की क्रेडिट रेटिंग कम-से-कम एए हो।

III.2.35 आईएफएससीए (निधि प्रबंधन) (संशोधन) विनियमन 2026

3.68 यह संशोधन कार्यानुभव आवश्यकताओं के संबंध में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंडों में नरमी लाता है तथा मौजूदा पात्रता मानदंडों के अलावा, कम कार्यानुभव आवश्यकता के साथ एक प्रमाणन-आधारित वैकल्पिक पात्रता मानदंड प्रस्तुत किया गया है।

3.69 निजी स्थानन ज्ञापन (पीपीएम) की वैधता के एकमुश्त विस्तार के प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है और निधि प्रबंधन संस्थाओं (एफएमई) को अब उद्यम पूंजी योजनाओं एवं प्रतिबंधित योजनाओं, प्रत्येक के लिए छह महीने के एकाधिक विस्तार का लाभ उठाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, ऐसी असीमित अवधि वाली (ओपन-एंडेड) योजनाओं में निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए विशिष्ट प्रावधान शुरू किए गए हैं जिन्होंने 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ निवेश करना शुरू कर दिया है, लेकिन 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की न्यूनतम निधि प्राप्त नहीं कर पाये। एफएमई को 24 महीने की परिवर्तन अवधि (माइग्रेशन विंडो) प्रदान की गई है, जिन्हें अपने मौजूदा संरक्षकों से माइग्रेट करने के लिए आईएफएससी-आधारित एक संरक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता है।

III.3 अन्य घटनाक्रम

III.3.1 उभरते फ्रंटियर एआई मॉडलों का विकास

3.70 भारत में, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र के भीतर, उभरते फ्रंटियर एआई मॉडलों की चर्चा और विश्लेषण, साइबर सुरक्षा परिदृश्य को नया आकार दे रहे हैं तथा सूचना प्रौद्योगिकी और परिचालन प्रौद्योगिकी (आईटी और ओटी) प्रणालियों की सुदृढ़ता के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रहे हैं।

3.71 वित्तीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमलों के बढ़ते स्वचालन के कारण, ऐसे मॉडलों के संभावित जोखिम मुख्य रूप से वित्तीय संस्थाओं के लिए परिचालन जोखिम हैं, जिससे सेवा में व्यवधान, वित्तीय हानि, प्रतिष्ठा संबंधी क्षति, डेटा उल्लंघन, गोपनीय वित्तीय जानकारी का संभावित दुरुपयोग और ग्राहक विश्वास में कमी आ सकती है। इसके अलावा, इससे प्रणालीगत जोखिम भी उत्पन्न हो सकता है, जिसमें असुरक्षाएँ साझा होती हैं और प्रौद्योगिकी संकेंद्रण जोखिम होता है, विशेषकर जहां कुछ ही सेवा प्रदाता हों या साझा इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भरता हो।

3.72 ये घटनाक्रम भारतीय वित्तीय क्षेत्र में साइबर सुदृढ़ता, एआई अभिशासन और तृतीय पक्ष के जोखिम प्रबंधन के लिए व्यापक ढांचे की अति-आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। एफएसडीसी द्वारा निर्देशित अंतर-मंत्रालयी समूह द्वारा तैयार की जा रही वित्तीय क्षेत्र साइबर सुरक्षा रणनीति (एफएससीएसएस) एक ऐसी नीतिगत व्यवस्था प्रदान करती है, जिसके माध्यम से इन अनिवार्यताओं को कार्रवाई योग्य और अलग-अलग विनियामकीय संस्थाओं पर लागू होने वाले मानकों में बदला जा सके। वित्तीय विनियामकों, साइबर सुरक्षा एजेंसियों (CERT-In, एनसीआईआईपीसी), एवं प्रौद्योगिकी निगरानीकर्ता निकायों के बीच घनिष्ठ समन्वय यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा कि एफएससीएसएस, पूर्व-स्थापित और उभरते प्रौद्योगिकी जोखिमों, दोनों को दूर करे, जिनमें फ्रंटियर एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और तृतीय-पक्ष संकेंद्रण से उत्पन्न होने वाले जोखिम शामिल हैं।

III.3.2 ग्राहक संरक्षण

3.73 पिछली दो तिमाहियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ओमबड्समैन (ओआरबीआईओ) के कार्यालयों द्वारा प्राप्त

शिकायतों की संख्या से संकेत मिलता है कि अधिकांश शिकायतें ऋण/अग्रिम और क्रेडिट कार्ड से संबंधित हैं, जो 2025-26 की तीसरी और चौथी तिमाहियों के दौरान प्राप्त शिकायतों का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा हैं (सारणी 3.1)।

3.74 भारतीय प्रतिभूति बाजारों के संबंध में, जनवरी-मार्च 2026 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या में पिछली तिमाही की तुलना में 5.8 प्रतिशत की कमी आई है। तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या में से 54.6 प्रतिशत शिकायतें स्टॉक ब्रोकरों एवं रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंटों से संबंधित थीं (सारणी 3.2)।

3.75 सेबी ने जुलाई 2023 में भारतीय प्रतिभूति बाजार में विवादों के ऑनलाइन समाधान पर एक परिपत्र जारी किया, जिसके तहत एमआईआई को अपने पैनल में शामिल ओडीआर संस्थाओं के परामर्श से, भारतीय प्रतिभूति बाजार में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए ऑनलाइन समाधान/सुलह और ऑनलाइन मध्यस्थता का उपयोग करने के लिए एक सामान्य ऑनलाइन विवाद समाधान पोर्टल स्थापित करने

सारणी 3.1: आरबी-आईओएस, 2021 के तहत प्राप्त शिकायतों की श्रेणी

क्रम सं.	शिकायत के आधार	अक्तू-दिसं 2025		जन-मार्च 2026	
		संख्या	*हिस्सा (प्रतिशत)*	संख्या	*हिस्सा (प्रतिशत)*
1	ऋण और अग्रिम	29,512	32.0%	34,972	32.0%
2	क्रेडिट कार्ड	17,413	18.9%	20,190	18.5%
3	मोबाइल/ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग	13,820	15.0%	17,977	16.4%
4	जमा खाते खोलना/संचालन	14,713	15.9%	17,640	16.1%
5	अन्य उत्पाद और सेवाएं*	9,551	10.3%	11,488	10.5%
6	एटीएम/सीडीएम/डेबिट कार्ड	4,347	4.7%	4,416	4.0%
7	विप्रेषण और लिखतों का संग्रह	1,416	1.5%	1,074	1.0%
8	पैरा-बैंकिंग	856	0.9%	871	0.8%
9	पेंशन से संबंधित	563	0.6%	600	0.5%
10	नोट और सिक्के	176	0.2%	165	0.2%
कुल		**92,367**	**100.0%**	**1,09,393**	**100.0%**

टिप्पणी: * इसमें बैंक गारंटी/साख पत्र, ग्राहक गोपनीयता, परिसर और कर्मचारी, शिकायत निवारण आदि शामिल हैं।
स्रोत: आरबीआई।

सारणी 3.2: शिकायतों के प्रकार/श्रेणी

क्रम सं.	श्रेणी	अक्तू-दिसं 2025	जन-मार्च 2026
1	स्टॉक ब्रोकर	4,939	5,321
2	रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट	3,234	2,972
3	सूचीबद्ध कंपनी- इक्विटी इश्यू (लाभांश/अंतरण/ट्रांसमिशन/डुप्लिकेट शेयर/बोनस शेयर आदि)	3,075	2,942
4	म्यूचुअल फंड	1,076	744
5	अनुसंधान विश्लेषक	670	641
6	डिपॉजिटरी प्रतिभागी	649	605
7	सूचीबद्ध कंपनी- आईपीओ/प्रीलिस्टिंग/ऑफर डॉक्यूमेंट (डिबेंचर एवं बॉन्ड)	585	260
8	सूचीबद्ध कंपनी-आईपीओ/प्रीलिस्टिंग/ऑफर डॉक्यूमेंट (शेयर)	405	254
9	सूचकांक	335	311
10	डिपॉजिटरी	221	210
11	निवेश सलाहकार	216	241
12	निर्गम के लिए बैंकर	173	107
13	सूचीबद्ध कंपनी- ऋण निर्गम (ब्याज/मोचन/अंतरण/ट्रांसमिशन आदि)	95	86
14	केवाईसी पंजीकरण एजेंसी	65	53
15	पोर्टफोलियो मैनेजर	63	33
16	सूचीबद्ध कंपनी- प्रतिभूतियों को सूची से हटाने की प्रक्रिया (डीलिस्टिंग)	60	43
17	मर्चेंट बैंकर	52	91
18	डिबेंचर न्यासी (ट्रस्टी)	51	95
19	श्रेणी 2 वैकल्पिक निवेश निधि	38	24
20	समाशोधन निगम (क्लियरिंग कॉर्पोरेशन)	23	43
21	एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग	18	34
22	सूचीबद्ध कंपनी- प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद	17	10
23	श्रेणी 3 वैकल्पिक निवेश निधि	14	11
24	जोखिम पूंजी निधि	13	9
25	क्रेडिट रेटिंग एजेंसी	11	9
26	भू-संपदा निवेश न्यास (आरईआईटी)	-	9
27	लघु और मध्यम भू-संपदा निवेश न्यास (एसएम आरईआईटी)	10	13
28	शेयर आधारित कर्मचारी लाभ	6	8
29	अवसंरचना निवेश न्यास (InvIT)	6	4
30	श्रेणी 1 वैकल्पिक निवेश निधि	5	8
31	सामूहिक निवेश योजना	1	-
32	तिजोरी प्रबंधक	-	1
33	प्रतिभूतीकृत कर्ज लिखत (एसडीआई)	1	1
कुल योग		**16,127**	**15,193**

स्रोत: सेबी।

और संचालित करने की आवश्यकता है। 2025-26 की दूसरी छमाही के लिए पोर्टल पर विवादों की स्थिति सारणी में दी गई है (सारणी 3.3)।

3.76 2025-26 के दौरान, 'बीमा भरोसा' पर 2,97,468 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 1,19,027 जीवन बीमा कारोबार से संबंधित थीं और 1,78,441 स्वास्थ्य कारोबार सहित सामान्य बीमा कारोबार से संबंधित थीं। जीवन बीमा कारोबार के तहत दर्ज की गई कुल शिकायतों में से लगभग 46 प्रतिशत अनुचित कारोबार प्रथाओं और उत्तरजीविता दावों से संबंधित थीं। मृत्यु पश्चात देय दावों के निपटान न करने की शिकायतें, पॉलिसी सर्विसिंग और प्रस्ताव फॉर्म से संबंधित मुद्दों की शिकायतें क्रमश: 6 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 5 प्रतिशत थीं। गैर-जीवन बीमा खंड के तहत, अधिकांश शिकायतें दावों (69 प्रतिशत) से संबंधित थीं। 2025-26 की दूसरी छमाही के लिए 'बीमा भरोसा' में शिकायतों की स्थिति सारणी में दी गई है (सारणी 3.4)।

3.77 वर्ष 2025-26 के दौरान, 2024-25 की तुलना में पूरे भारत में बीमा ओमबड्समैन द्वारा प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या में 11.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई (कृपया सारणी 3.5 देखें)। इन शिकायतों में से, दोनों वर्षों में प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या में से दावों के आंशिक निराकरण या पूर्ण अस्वीकृति से संबंधित शिकायतें लगभग 72 प्रतिशत थीं, इसके बाद बीमाकर्ताओं द्वारा पॉलिसी के नियमों और शर्तों की गलत बयानी से संबंधित शिकायतें हैं (सारणी 3.5)।

सारणी 3.3: SmartODR.in पर विवादों की स्थिति

(₹ करोड़)

अवधि	विवादों की प्रारंभिक स्थिति/ शेष		प्राप्त शिकायतें		सुलझाई गईं शिकायतें		तिमाही के अंत में बकाया स्थिति	
	संख्या	मूल्य (₹ करोड़)	संख्या	मूल्य (₹ करोड़)	संख्या	मूल्य (₹ करोड़)	संख्या	मूल्य (₹ करोड़)
अक्टू-दिसं 2025	570	63.82	1,040	68.79	944	40.58	666	92.03
जन-मार्च 2026	666	92.03	1,441	194.29	1,229	104.99	878	181.33

टिप्पणी: उपर्युक्त डेटा सभी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस (एमआईआई) से जुड़ी निवल शिकायतों से संबंधित है।
स्रोत: सेबी।

3.78 "दावों की अस्वीकृति" के तहत वर्गीकृत शिकायतें मुख्य रूप से स्वास्थ्य बीमा खंड से संबंधित हैं, इसके बाद सामान्य बीमा से संबंधित हैं। जीवन बीमा, पॉलिसी के नियमों और शर्तों की गलत बयानी से संबंधित शिकायतों का सबसे बड़ा हिस्सा है, जबकि स्वास्थ्य बीमा खंड दूसरे स्थान पर है।

III.3.3 प्रवर्तन

3.79 रिज़र्व बैंक ने 99 विनियमित संस्थाओं-आरई (5 पीएसबी, 7 पीवीबी, एक पीबी, एक विदेशी बैंक, एक आरआरबी, 56 सहकारी बैंक, 21 एनबीएफसी, 3 एचएफसी और 4 पीएसओ) के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई की तथा दिसंबर 2025 से मई 2026 तक रिज़र्व बैंक द्वारा जारी सांविधिक प्रावधानों और/या निदेशों का अननुपालन/उल्लंघन करने के लिए कुल ₹8.96 करोड़ का जुर्माना लगाया।

सारणी 3.4: बीमा भरोसा में शिकायतें

	2024-25			2025-26		
बीमाकर्ता	**वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गईं**	**वर्ष के दौरान जिन पर कार्रवाई की गई**	**वर्ष के अंत में लंबित**	**वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गईं**	**वर्ष के दौरान जिन पर कार्रवाई की गई**	**वर्ष के अंत में लंबित**
जीवन बीमाकर्ता						
सार्वजनिक क्षेत्र	74,104	74,104	0	59,313	59,311	2
निजी क्षेत्र	46,325	45,771	554	59,714	59,118	596
कुल	**1,20,429**	**1,19,875**	**554**	**1,19,027**	**1,18,429**	**598**
सामान्य और स्वास्थ्य बीमाकर्ता						
सार्वजनिक क्षेत्र	38,924	30,723	8,201	40,839	33,153	7,686
निजी क्षेत्र	98,437	97,032	1,405	1,37,602	1,35,914	1,688
कुल	**1,37,361**	**1,27,755**	**9,606**	**1,78,441**	**1,69,067**	**9,374**
कुल योग	**2,57,790**	**2,47,630**	**10,160**	**2,97,468**	**2,87,496**	**9,972**

स्रोत: आईआरडीएआई।

सारणी 3.5: बीमा ओमबड्समैन के पास प्रस्तुत शिकायतें

क्रम सं.	शिकायतों के आधार	2025-26		2024-25	
		संख्या	हिस्सा *(प्रतिशत)*	संख्या	हिस्सा *(प्रतिशत)*
1	दावों के निपटान में देरी	822	1.7	771	1.8
2	दावों का कोई भी आंशिक निराकरण या पूर्ण अस्वीकृति	35,186	72.9	31,383	72.2
3	भुगतान किए गए या देय प्रीमियम के संबंध में कोई विवाद	1,330	2.8	2,106	4.8
4	किसी भी समय नीति के नियमों और शर्तों की गलत बयानी	9,142	18.9	7,585	17.5
5	बीमाकर्ताओं और उनके वितरण चैनल के खिलाफ पॉलिसी सर्विसिंग से संबंधित शिकायतें	1,358	2.8	1,293	3.0
6	Others	457	0.9	311	0.7
अन्य		**48,295**	**100**	**43,449**	**100**

स्रोत: आईआरडीएआई।

3.80 अक्टूबर 2025-मार्च 2026 के दौरान, सेबी अधिनियम, 1992 की धारा 11 के तहत 281 संस्थाओं के विरुद्ध निषेधी निदेश जारी किए गए थे। इसके अलावा, सेबी (मध्यस्थ संस्थाएं) विनियमन, 2008 के अंतर्गत दो मध्यस्थ संस्थाओं के पंजीकरण को रद्द करना, तीन मध्यस्थ संस्थाओं को निलंबित करना और तीन मध्यस्थ संस्थाओं के विरुद्ध चेतावनी जारी करना शामिल है। 74 संस्थाओं के खिलाफ कुल 36 अभियोजन मामले दर्ज किए गए थे। इस अवधि के दौरान, न्यायनिर्णयन कार्यवाहियों के तहत 340 संस्थाओं पर 17.4 करोड़ की राशि का जुर्माना लगाया गया।

3.81 जनवरी 2026 से जून 2026 की अवधि के दौरान, आईआरडीएआई ने दो विनियमित संस्थाओं के खिलाफ विनियामक कार्रवाई शुरू की, जिसमें एक जीवन बीमाकर्ता और एक कॉरपोरेट एजेंट शामिल है। आईआरडीएआई ने जीवन बीमाकर्ता को एक परामर्शिका जारी की और लागू विनियामक प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कॉरपोरेट एजेंट पर ₹1 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया।

III.3.4 जमा बीमा

3.82 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) भारत में कार्यरत सभी बैंकों के जमाकर्ताओं को बीमा कवर प्रदान करता है। 31 मार्च 2026 तक, डीआईसीजीसी के साथ पंजीकृत बैंकों की संख्या 1,950 थी, जिनमें 124 वाणिज्यिक बैंक (11 लघु वित्त बैंक, 6 भुगतान बैंक, 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 2 स्थानीय क्षेत्र बैंक सहित) और 1,826 सहकारी बैंक शामिल थे।

3.83 ₹5 लाख की वर्तमान जमा बीमा सीमा के साथ, 31 मार्च 2026 तक जमा खातों की कुल संख्या (301.4 करोड़) का 97.4 प्रतिशत हिस्सा पूरी तरह से बीमाकृत था और सभी निर्धारणीय जमाराशियों (₹275 लाख करोड़) के कुल मूल्य का 39.7 प्रतिशत अंश बीमाकृत था (सारणी 3.6)।

3.84 बीमाकृत जमा अनुपात (यानी, बीमाकृत जमा और निर्धारणीय जमाराशियों का अनुपात) सहकारी बैंकों (60.1 प्रतिशत) के लिए सर्वाधिक और उसके बाद वाणिज्यिक बैंकों

सारणी 3.6: जमाराशियों का कवरेज
(राशि ₹ करोड़ में और खातों की संख्या करोड़ में)

क्र. सं.	मद	की स्थिति में			प्रतिशत भिन्नता (व-द-व)	
		31 मार्च 2025	30 सितं 2025	31 मार्च 2026	31 मार्च 2025	31 मार्च 2026
		(एफ)	(एफ)	(पी)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पंजीकृत बैंकों की संख्या	1,982	1,957	1,950		
2	खातों की कुल संख्या	293.8	298.9	301.4	1.4	2.6
3	पूर्णतः संरक्षित खातों की संख्या	286.6	291.4	293.5	1.2	2.4
4	**(3)/(2) का प्रतिशत**	**97.6**	**97.5**	**97.4**		
5	कुल निर्धारणीय जमाराशियाँ	2,41,06,042	2,53,09,786	2,75,43,642	10.3	14.3
6	बीमित जमाराशियाँ	1,00,12,065	1,04,09,023	1,09,33,948	6.4	9.2
7	**(6)/(5) का प्रतिशत**	**41.5**	**41.1**	**39.7**		

टिप्पणी: एफ-अंतिम, पी-अनंतिम।
स्रोत: डीआईसीजीसी।

सारणी 3.7: बैंक समूह-वार जमाराशि संरक्षण कवरेज
(31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार)

बैंक समूह	30 सितंबर 2025 तक				31 मार्च 2026 तक*			
	बीमाकृत बैंक *(संख्या)*	बीमाकृत जमाराशियाँ *(₹ करोड़)*	निर्धारणीय जमाराशियाँ *(₹ करोड़)*	आईडीआर *(आईडी/एडी, प्रतिशत)*	बीमाकृत बैंक *(संख्या)*	बीमाकृत जमाराशियाँ *(₹ करोड़)*	निर्धारणीय जमाराशियाँ *(₹ करोड़)*	आईडीआर *(आईडी/एडी, प्रतिशत)*
I. वाणिज्यिक बैंक	**124**	**96,41,292**	**2,40,45,871**	**40.1**	**124**	**1,01,12,746**	**2,61,77,935**	**38.6**
(i) पीएसबी	12	62,02,745	1,33,65,458	46.4	12	64,80,763	1,45,13,352	44.7
(ii) पीवीबी	21	27,00,832	84,74,341	31.9	21	28,42,849	93,05,345	30.6
(iii) एफबी	44	51,686	12,02,752	4.3	44	50,911	12,67,912	4.0
(iv) एसएफबी	11	1,15,177	2,88,121	40.0	11	1,22,636	3,21,553	38.1
(v) पीबी	6	29,465	29,676	99.3	6	37,724	37,904	99.5
(vi) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	28	5,40,334	6,84,048	79.0	28	5,76,753	7,30,286	79.0
(vii) एलएबी	2	1,051	1,475	71.3	2	1,110	1,581	70.2
II. सहकारी बैंक	**1,833**	**7,67,731**	**12,63,915**	**60.7**	**1,826**	**8,21,202**	**13,65,707**	**60.1**
(i) यूसीबी	1,447	3,80,874	5,93,328	64.2	1,440	3,97,657	6,35,789	62.5
(ii) एसटीसीबी	34	65,323	1,60,969	40.6	34	71,330	1,69,856	42.0
(iii) डीसीसीबी	352	3,21,535	5,09,618	63.1	352	3,52,214	5,60,062	62.9
कुल (I+II)	**1,957**	**1,04,09,023**	**2,53,09,786**	**41.1**	**1,950**	**1,09,33,948**	**2,75,43,642**	**39.7**

टिप्पणियाँ: 1. आईडीआर: बीमाकृत जमा अनुपात की गणना बीमाकृत जमाराशियों की तुलना में निर्धारणीय जमाराशियों के रूप में की जाती है।
2. संभव है कि निर्धारणीय जमाराशि के लिए बीमाकृत जमाराशि अनुपात, पूर्णांकन के कारण संगत नहीं हो।
3. *अनंतिम।

स्रोत: डीआईसीजीसी।

(38.6 प्रतिशत) के लिए अधिक था (सारणी 3.7)। वाणिज्यिक बैंकों के भीतर, पीवीबी की तुलना में पीएसबी का बीमाकृत जमा अनुपात अधिक था।

3.85 डीआईसीजीसी द्वारा प्राप्त जमा बीमा प्रीमियम 2025-26 की दूसरी छमाही के दौरान 14.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर ₹15,565 करोड़ हो गया, जिसमें से वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी 95.1 प्रतिशत थी (सारणी 3.8)।

3.86 डीआईसीजीसी के साथ जमा बीमा निधि (डीआईएफ) मुख्य रूप से बीमाकृत बैंकों द्वारा चुकाए गए प्रीमियम, निवेश आय और निपटाए गए दावों से हुई वसूली (आयकर घटाकर) से बनती है। डीआईएफ ने 31 मार्च 2026 तक 14.4 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की और यह ₹2.62 लाख करोड़ तक पहुंच गई। आरक्षित निधि अनुपात (यानी, बीमाकृत जमाराशियों के प्रति डीआईएफ का अनुपात) एक वर्ष पहले के 2.29 प्रतिशत से बढ़कर 2.39 प्रतिशत हो गया (सारणी 3.9)।

सारणी 3.8: जमा बीमा प्रीमियम

(₹ करोड़)

अवधि	वाणिज्यिक बैंक	सहकारी बैंक	कुल
2024-25			
पहली छमाही	12,419	707	13,127
दूसरी छमाही	12,932	704	13,637
कुल	**25,352**	**1,412**	**26,764**
2025-26			
पहली छमाही	13,633	749	14,382
दूसरी छमाही	14,807	758	15,565
कुल	**28,440**	**1,507**	**29,947**

टिप्पणी: संभव है कि पूर्णांकन के कारण घटक मदों का योग कुल के बराबर न हो।
स्रोत: डीआईसीजीसी।

III.3.5 कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया

3.87 1 दिसंबर 2016 से कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के प्रावधान लागू होने के बाद से, 31 मार्च 2026 तक 8,987 सीआईआरपी शुरू किए गए हैं (सारणी 3.10)। उनमें से 7,102 मामले पूरे हो चुके हैं – 1,419 समाधान योजनाओं के माध्यम से; 1,388 अपील/समीक्षा/निपटान के माध्यम से; धारा 12ए के तहत 1,292 मामलों को वापस ले

सारणी 3.9: जमा बीमा निधि और आरक्षित निधि अनुपात

(₹ करोड़)

की स्थिति में	जमा बीमा निधि (डीआईएफ)	बीमाकृत जमाराशियाँ (आईडी)	आरक्षित निधि अनुपात (डीआईएफ/आईडी) (प्रतिशत)
31 मार्च 2025	2,28,933	1,00,12,065	2.29
30 सितं 2025	2,46,292	1,04,09,023	2.37
31 मार्च 2026	2,61,823	1,09,33,948	2.39

स्रोत: डीआईसीजीसी।

सारणी 3.10: कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया की स्थिति
(31 मार्च 2026 तक)

वर्ष/तिमाही	अवधि की शुरुआत में सीआईआरपी	स्वीकृत	द्वारा बंद करना				अवधि के अंत में सीआईआरपी
			अपील/समीक्षा/ निपटान	धारा 12ए के तहत वापस लिया जाना	समाधान योजना का अनुमोदन	परिसमापन की शुरुआत	
2016 - 17	0	37	1	0	0	0	36
2017 - 18	36	707	96	0	18	91	538
2018 - 19	538	1157	162	97	74	305	1057
2019 - 20	1057	1992	350	221	131	537	1810
2020 - 21	1810	537	92	168	119	348	1620
2021 - 22	1620	892	130	203	141	339	1699
2022 - 23	1699	1262	195	231	186	405	1944
2023 - 24	1944	1004	164	168	258	441	1917
2024 - 25	1917	734	122	89	259	291	1890
अप्रै-जून 2025	1890	188	15	29	63	75	1896
जुला-सितं 2025	1896	164	31	32	47	73	1877
अक्टू-दिसं 2025	1877	170	18	34	87	50	1858
जन-मार्च 2026	1858	143	12	20	36	48	1885
कुल	**NA**	**8987**	**1388**	**1292**	**1419**	**3003**	**1885**

टिप्पणी: ये सीआईआरपी 8403 सीडी के संबंध में हैं।
इसमें 1 सीडी शामिल नहीं है, जो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) से सीधे समाधान के लिए चली गई है।
स्रोत: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)।

लिया गया; और 3,003 को परिसमापन के लिए भेजा गया है। कुल 1,885 सीआईआरपी प्रक्रियाधीन हैं। सीआईआरपी के तहत कॉरपोरेट देनदारों (सीडी) का क्षेत्रवार वितरण (सारणी 3.11) में प्रस्तुत किया गया है।

3.88 हितधारक-वार शुरू किए गए सीआईआरपी के 31 मार्च 2026 तक के परिणाम सारणी 3.12 में प्रस्तुत किए गए हैं। ओसी द्वारा शुरू किए गए सीआईआरपी में से बंद किए गए लगभग 51 प्रतिशत अपील, समीक्षा या वापसी के चलते बंद कर दिए गए थे (सारणी 3.12)। अपील, समीक्षा या वापस लेने के कारण बंद हुए सभी मामलों में, इस तरह के मामलों की हिस्सेदारी 66 प्रतिशत से अधिक थी।

3.89 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) का प्राथमिक उद्देश्य संकट में कॉरपोरेट देनदारों (सीडी) का बचाव करना है। संहिता ने मार्च 2026 तक 4,099 सीडी (समाधान योजनाओं के माध्यम से 1,419, अपील या समीक्षा या निपटान के माध्यम से 1,388 और वापसी के माध्यम से 1,292) को बचाया है। इसने परिसमापन के लिए 3,003 सीडी को संदर्भित किया है। संचयी रूप से, मार्च 2026 तक लेनदारों ने समाधान योजनाओं के तहत ₹4.32 लाख करोड़ प्राप्त किए हैं। लेनदारों को परिसमापन पर प्राप्य मूल्य का 166.8 प्रतिशत और उचित मूल्य का 94.56 प्रतिशत (1,298 मामलों के आधार पर, जहां उचित मूल्य का अनुमान लगाया गया है) प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, इस प्राप्ति में सीआईआरपी लागत और भविष्य की कई संभावित उपलब्धियां शामिल नहीं हैं।

3.90 जिन सीआईआरपी (1,391 में से 585 जिनके लिए डेटा उपलब्ध हैं) ने समाधान योजनाओं का लाभ उठाया, उनमें से लगभग 42 प्रतिशत पहले बीआईएफआर के साथ थे और/या निष्क्रिय थे। इन सीडी में, दावेदारों को उनके स्वीकृत दावों का 17.49 प्रतिशत और परिसमापन मूल्य का 174.03 प्रतिशत हिस्सा मिला है।

3.91 मार्च 2026 के अंत तक, परिसमापन में समाप्त होने वाले कुल सीआईआरपी 3003 थे, जिनमें से 1692 मामलों में अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं। इन 1692 सीडी पर कुल मिलाकर ₹4.85 लाख करोड़ के दावे बकाया थे, लेकिन उनकी आस्तियों का मूल्य ₹0.21 लाख करोड़ था। इन कंपनियों के परिसमापन से, परिसमापन पर प्राप्य मूल्य की तुलना में 86.34 प्रतिशत की प्राप्ति हुई।

सारणी 3.11: सीआईआरपी का क्षेत्रवार वितरण

(31 मार्च 2026 तक)

क्षेत्र	सीआईआरपी की संख्या						
	स्वीकृत	बंद					मौजूदा/ प्रक्रियाधीन
		अपील/ समीक्षा/ निपटान	धारा 12ए के तहत वापस लिया जाना	समाधान योजना का अनुमोदन	परिसमापन की शुरुआत	कुल	
विनिर्माण	**3293**	**455**	**480**	**614**	**1205**	**2754**	**539**
खाद्य, पेय पदार्थ एवं तंबाकू उत्पाद	440	53	63	75	165	356	84
रसायन एवं रासायनिक उत्पाद	362	57	71	65	111	304	58
विद्युत मशीनरी एवं उपकरण	227	29	30	33	105	197	30
विनिर्मित धातु उत्पाद	175	26	28	31	54	139	36
मशीनरी एवं उपकरण	355	64	61	49	123	297	58
वस्त्र, चमड़ा एवं पोशाक उत्पाद	557	65	83	78	242	468	89
लकड़ी, रबर, प्लास्टिक एवं कागज उत्पाद	384	49	59	82	135	325	59
मूल धातु	531	68	47	144	197	456	75
अन्य	262	44	38	57	73	212	50
स्थावर संपदा, किराया और व्यावसायिक गतिविधियाँ	**1961**	**365**	**315**	**248**	**557**	**1485**	**476**
स्थावर संपदा गतिविधियाँ	562	119	88	83	89	379	183
कंप्यूटर और संबंधित गतिविधियाँ	254	36	47	26	96	205	49
अनुसंधान और विकास	13	2	4	2	2	10	3
अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ	1132	208	176	137	370	891	241
निर्माण	**1103**	**213**	**184**	**171**	**239**	**807**	**296**
थोक और खुदरा व्यापार	**893**	**121**	**87**	**102**	**397**	**707**	**186**
होटल और रेस्तरां	**179**	**37**	**30**	**33**	**44**	**144**	**35**
विद्युत एवं अन्य	**240**	**31**	**25**	**54**	**96**	**206**	**34**
परिवहन, भंडारण और संचार	**250**	**29**	**30**	**26**	**105**	**190**	**60**
अन्य	**1068**	**137**	**141**	**171**	**360**	**809**	**259**
कुल	**8987**	**1388**	**1292**	**1419**	**3003**	**7102**	**1885**

टिप्पणी: यह वितरण कॉरपोरेट देनदारों के सीआईएन और राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी 2004) के अनुसार है।

स्रोत: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)।

सारणी 3.12: हितधारक-वार आरंभ किए गए सीआईआरपी के परिणाम

(31 मार्च 2026 तक)

परिणाम	विवरण		सीआईआरपी द्वारा शुरू किए गए			
		वित्तीय ऋणदाता	परिचालन ऋणदाता	कॉरपोरेट देनदार	वित्तीय सेवा प्रदाता	कुल
सीआईआरपी की स्थिति	अपील/समीक्षा/निपटान द्वारा समापन	454	920	14	0	1388
	धारा 12ए के तहत वापस लेते हुए समापन	410	871	11	0	1292
	समाधान योजना के अनुमोदन द्वारा समापन	884	438	93	4	1419
	परिसमापन प्रारंभ होने से समापन	1424	1251	328	0	3003
	मौजूदा/प्रक्रियाधीन	1143	629	112	1	1885
	कुल	**4315**	**4109**	**558**	**5**	**8987**
समाधान योजनाएँ प्रदान करने वाले सीआईआरपी	परिसमापन मूल्य के प्रतिशत के रूप में ऋणदाताओं द्वारा वसूली	177.96	149.42	146.83	134.94	166.85
	ऋणदाताओं द्वारा उनके दावों के प्रतिशत के रूप में वसूली	30.61	24.82	17.99	41.41	30.56
	सीआईआरपी को बंद करने में लगने वाला औसत समय (दिन)	751	756	629	677	744
परिसमापन प्रदान करने वाले सीआईआरपी	दावों के प्रतिशत के रूप में परिसमापन मूल्य	5.37	8.32	7.46	-	6.02
	सीआईआरपी को बंद करने में लगने वाला औसत समय (दिन)	540	541	453	-	531

टिप्पणी: एफफआईएसपी = वित्तीय सेवा प्रदाता। "वित्तीय सेवा प्रदाता" का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो वित्तीय क्षेत्र के विनियामक द्वारा जारी प्राधिकरण या दिए गए पंजीकरण के संदर्भ में (बैंकों के अलावा) वित्तीय सेवाएँ प्रदान करता है।

स्रोत: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)।

3.92 यह संहिता विभिन्न प्रक्रियाओं को यथाशीघ्र पूरा करने का प्रयास करती है। मार्च 2026 के अंत तक जिन 1,419 सीआईआरपी में समाधान योजनाएं तैयार हुईं, उन्हें पूरा होने में औसतन 621 दिन (एए द्वारा छोड़े गए समय को हटाने के बाद) का समय लगा, जबकि परिसमापन मूल्य के 1.3 प्रतिशत और समाधान मूल्य के 0.80 प्रतिशत की औसत लागत व्यय हुई। इसी तरह, जो 3,003 सीआईआरपी परिसमापन के आदेश में परिणत हुए, उन्हें पूरा होने में औसतन 531 दिन का समय लगा। इसके अलावा, 1,692 परिसमापन प्रक्रियाएं, जिन्हें अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करके बंद कर दिया गया था, को बंद होने में औसतन 691 दिन लगे। इसी तरह, 2,022 स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रियाएं, जिन्हें अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करके बंद कर दिया गया था, को बंद होने में औसतन 394 दिन का समय लगा।

III.3.6 अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) के घटनाक्रम

3.93 आईएफएससी में सभी वित्तीय गतिविधियों के लिए एकीकृत विनियामक, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) ने वर्ष 2021 से 30 से अधिक विनियमों और 15 से अधिक रूपरेखाओं (फ्रेमवर्क) को अधिसूचित किया है। आईएफएससीए द्वारा किए गए पंजीकरण/प्राधिकारों की संख्या अक्टूबर 2020 के 94 से बढ़कर 31 मार्च 2026 तक 1150 हो गई है।

3.94 गिफ्ट आईएफएससी में बैंकिंग पारिस्थिकी तंत्र में 37 बैंकों की शाखाएं [आईएफएससी बैंकिंग इकाइयां (आईबीयू)] शामिल हैं, जिनमें 20 विदेशी बैंक और 17 घरेलू बैंक शामिल हैं जो बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, आईएफएससी में 2 बैंकों - एसबीआई और फर्स्टरैंड बैंक के वैश्विक प्रशासनिक कार्यालय (जीएओ) कार्यरत हैं। कुल बैंकिंग आस्तियाँ, सितंबर 2020 के 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर मार्च 2026 में 111 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई हैं, जबकि इसी अवधि के दौरान संचयी बैंकिंग लेनदेन 53 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 1,826.85 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गए हैं। आईबीयू के साथ कुल 21,449 खुदरा जमा खाते खोले गए हैं, जिनमें कुल 1.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर जमा हैं।

3.95 31 मार्च 2026 तक, बीमा पारिस्थिकी तंत्र में 22 विदेशी और 14 घरेलू फर्मों के 36 आईएफएससी बीमा कार्यालय (आईआईओ) एवं 34 आईएफएससी बीमा मध्यस्थ कार्यालय (आईआईआईओ) शामिल थे। आईआईओ द्वारा बुक किया गया कुल सकल लिखित प्रीमियम (जीडब्ल्यूपी) वित्त वर्ष 2024-25 के 162 मिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 648 मिलियन अमेरिकी डॉलर (40 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रत्यक्ष और 608 मिलियन अमेरिकी डॉलर पुनर्बीमा) हो गया।

3.96 निधि प्रबंधन पारिस्थिकी तंत्र में पर्याप्त वृद्धि देखी गई। 31 मार्च 2026 तक, 217 निधि प्रबंधन संस्थाएं (एफएमई) पंजीकृत की गई हैं, जिन्होंने 19.7 बिलियन यूएस डॉलर के संचयी निवेश के साथ 360 निधियाँ (एआईएफ और खुदरा योजनाओं सहित) प्रारंभ की हैं। एफएमई की संख्या मार्च 2025 के 162 से बढ़कर मार्च 2026 में 217 हो गई है, जो 34.0 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि को दर्शाती है। इसी प्रकार, इसी अवधि के दौरान निधियों की संख्या 229 से बढ़कर 360 हो गई है, जो 57.2 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि को दर्शाता है। इस बीच, संचयी निवेश मार्च 2025 में 8.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर मार्च 2026 में 19.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो 144.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

3.97 यह गति गिफ्ट आईएफएससी में पूंजी बाजार पारिस्थिकी तंत्र में परिलक्षित हुई। मार्च 2026 में गिफ्ट आईएफएससी एक्सचेंजों पर मासिक कारोबार 130.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा तथा मार्च 2026 में एनएसई IX पर निफ्टी डेरिवेटिव संविदाओं का औसत दैनिक कारोबार 5.90 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2026 तक आईएफएससी एक्सचेंजों पर कुल 77 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कर्ज प्रतिभूतियां सूचीबद्ध की गई हैं, जिनमें 17.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ईएसजी लेबल वाले कर्ज भी शामिल हैं।

3.98 इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (आईआईबीएक्स) बुलियन ट्रेडिंग के लिए एक प्रमुख प्लेटफॉर्म के रूप में उभरा है। 31 मार्च 2026 तक, आईआईबीएक्स के माध्यम से 102.33 टन स्वर्ण (8.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर) और 1,147.98 टन चांदी (927 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर) का लेनदेन और आयात किया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त तीन वॉल्ट प्रबंधकों ने चेन्नई में गिफ्ट

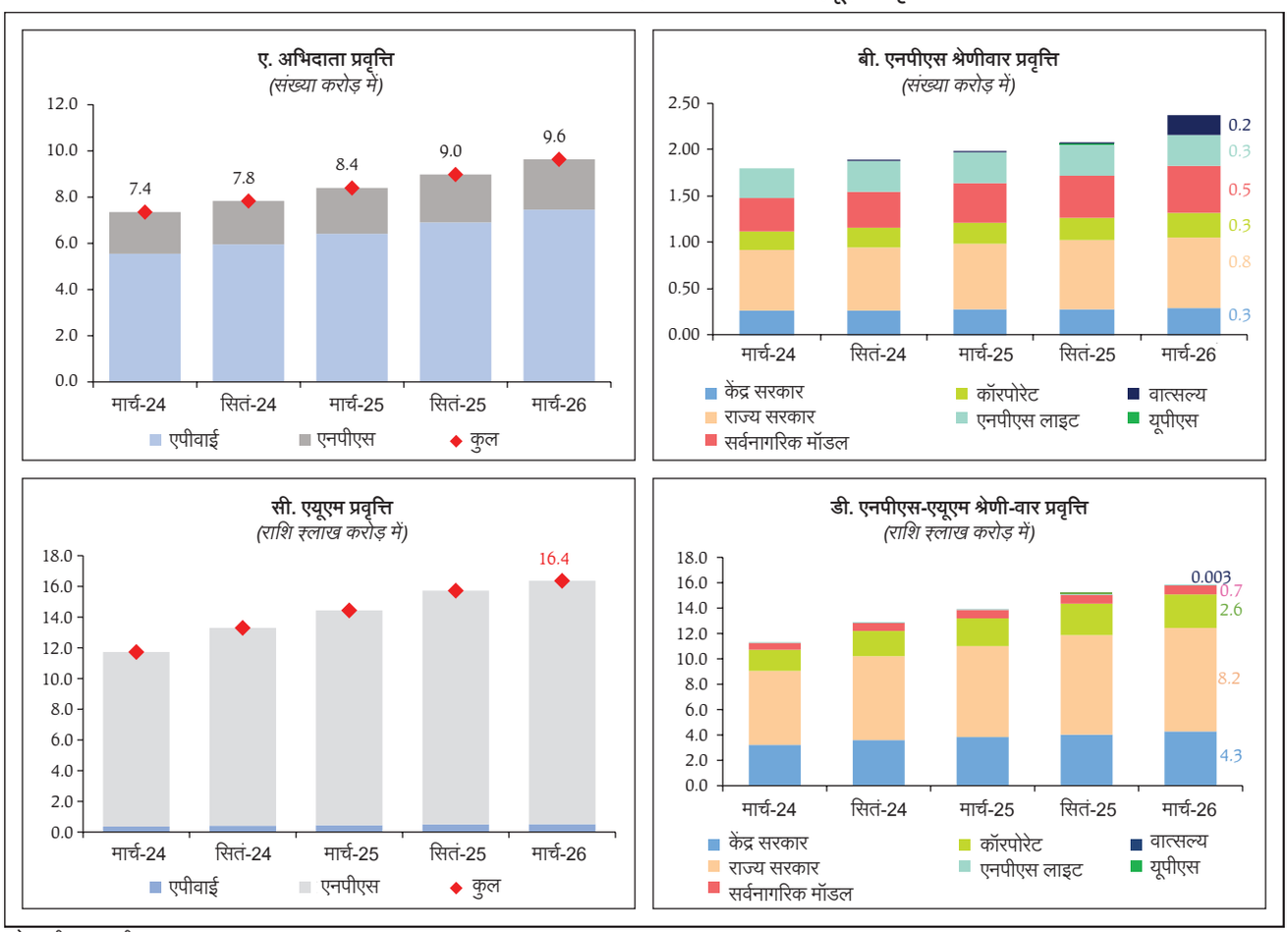
आईएफएससी और विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजे) में स्वर्ण के लिए लगभग 151 टन और चांदी के लिए लगभग 930 टन की भंडारण क्षमता के साथ वॉल्ट स्थापित किए हैं। गिफ्ट-आईएफएससी में पंजीकृत विमान पट्टे पर देने वाली संस्थाएं 35 थीं, जिन्होंने कुल 373 आस्तियों [विमान - 203, इंजन - 84, विमान सहायक बिजली इकाइयों (एपीयू) - 85 और विमानन सिमुलेशन प्रशिक्षण उपकरण - 1] को पट्टे पर दिया है। वहीं, गिफ्ट आईएफएससी में कुल पंजीकृत शिप लीजिंग/शिप फाइनेंसिंग संस्थाओं की संख्या मार्च 2026 तक बढ़कर 36 हो गई है। इसके अतिरिक्त, कुल 9 संस्थाओं को आईएफएससीए के साथ वैश्विक/क्षेत्रीय ट्रेजरी केंद्र के रूप में पंजीकृत किया गया है।

III.3.7 पेंशन निधि

3.99 इस अवधि की विशेषता 9.64 करोड़ से अधिक व्यक्तियों के लिए अभिदाता आधार (सब्सक्राइबर बेस) का विस्तार और ₹16 लाख करोड़ की सीमा से अधिक प्रबंधनाधीन आस्तियां (एयूएम) थी। एनपीएस और एपीवाई, दोनों में ग्राहकों की संख्या में 14.7 प्रतिशत और एयूएम में 14.1 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है। सबसे अधिक एयूएम राज्य सरकार (₹8.16 लाख करोड़) के तहत है, जबकि सबसे अधिक ग्राहक एपीवाई (7.5 करोड़) के अंतर्गत हैं। एपीवाई के तहत कुल नामांकन 8.96 करोड़ था (चार्ट 3.1 ए, बी, सी और डी), जिनमें सर्वाधिक नामांकन 21-25 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के थे। योगदान मुख्य रूप से निश्चित आय साधनों में निवेश किया जाता है (चार्ट 3.2)। सबसे अधिक नामांकन ₹1,000 के पेंशन स्लैब के तहत 86.91 प्रतिशत था।

3.100 यह स्वीकार करते हुए कि बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल लागत, संचित सेवानिवृत्ति बचत की पर्याप्तता के लिए प्रमुख खतरों में से एक है, प्राधिकरण ने अपने विनियामक सैंडबॉक्स

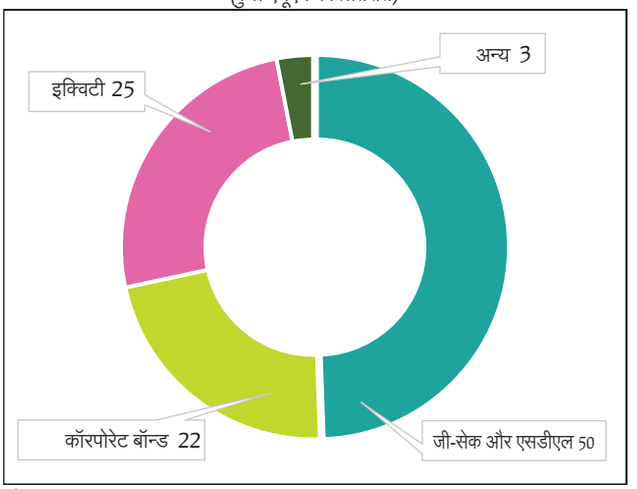
चार्ट 3.1: एनपीएस और एपीवाई – अभिदाता और एयूएम प्रवृत्ति



स्रोत: पीएफ़आरडीए।

चार्ट 3.2: एनपीएस एवं एपीवाई एयूएम: आस्ति श्रेणी-वार विभाजन

(कुल एयूएम का प्रतिशत)



स्रोत: पीएफ़आरडीए।

फ्रेमवर्क के तहत अवधारणा के प्रमाण के रूप में एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन योजना को मंजूरी दी। एनपीएस स्वास्थ्य एक स्वैच्छिक, अंशदायी, क्षेत्र-विशिष्ट योजना है जिसे मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क के तहत स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य विशेष रूप से नागरिकों को आउट-पेशेंट और इन-पेशेंट इलाज के खर्चों को पूरा करने में मदद करना है, जो एक एकल, विनियमित संरचना के अंतर्गत दीर्घकालिक पेंशन योजना के साथ स्वास्थ्य वित्तपोषण को एकीकृत करता है।

अनुबंध 1
कार्य-पद्धतियाँ

1.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(ए) बैंकिंग स्थिरता संकेतक (बीएसआई) एवं मानचित्र (मैप)

बैंकिंग स्थिरता मानचित्र और संकेतक, एक अवधि के दौरान बैंकिंग क्षेत्र की स्थिरता पर प्रभाव डालने वाली अंतर्निहित स्थितियों और जोखिम कारकों में परिवर्तन का समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत करते हैं। छह संयुक्त सूचकांक छह आयामों में जोखिम को दर्शाते हैं - सुदृढ़ता, आस्ति गुणवत्ता, लाभप्रदता, चलनिधि, दक्षता और बाजार जोखिम के प्रति संवेदनशीलता। प्रत्येक सम्मिश्र सूचकांक, इसके निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली नमूना अवधि के दौरान जोखिम का एक सापेक्ष माप है, जहाँ एक उच्च मान का तात्पर्य उस आयाम में उच्च जोखिम होगा।

सारणी 1 में प्रत्येक सम्मिश्र सूचकांक के निर्माण के लिए उपयोग किए गए वित्तीय अनुपात दिए गए हैं। प्रत्येक वित्तीय अनुपात को पहले निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके नमूना अवधि के लिए सामान्यीकृत किया जाता है:

$$Y_t = \frac{X_t - min(X_t)}{max(X_t) - min(X_t)}$$

जहां X_t, समय t पर अनुपात का मान है। यदि कोई चर जोखिम से ऋणात्मक रूप से संबंधित है, तो 1-Y_t का उपयोग करके सामान्यीकरण किया जाता है। प्रत्येक आयाम के सम्मिश्र सूचकांक की गणना उस आयाम में सामान्यीकृत अनुपात के एक सरल औसत के रूप में की जाती है। अंत में, बैंकिंग स्थिरता संकेतक का निर्माण इन छह सम्मिश्र सूचकांकों के एक साधारण औसत के रूप में किया जाता है। इस प्रकार, प्रत्येक सम्मिश्र सूचकांक और समग्र बैंकिंग स्थिरता संकेतक में शून्य एवं एक के बीच मान लिए जाते हैं।

सारणी 1: बैंकिंग स्थिरता संकेतक और मानचित्र (मैप) के निर्माण के लिए प्रयुक्त अनुपात

आयाम	अनुपात			
सुदृढ़ता	सीआरएआर #	पूंजी की तुलना में निवल एनपीए	आस्तियों की तुलना में टियर 1 पूंजी #	
आस्ति गुणवत्ता	कुल अग्रिमों की तुलना में सकल एनपीए	प्रावधान कवरेज अनुपात #	कुल अग्रिमों की तुलना में एसएमए-1 और एसएमए-2 ऋण	मानक अग्रिमों की तुलना में पुनर्रचित मानक अग्रिम
लाभप्रदता	आस्तियों पर प्रतिलाभ#	निवल ब्याज मार्जिन #	प्रावधान और कर पूर्व, अर्जन में संवृद्धि #	सकल आय की तुलना में ब्याज मार्जिन #
चलनिधि	कुल आस्तियों की तुलना में अर्थ सुलभ आस्तियां#	चलनिधि कवरेज अनुपात #	ग्राहक-जमा की तुलना में गैर-बैंक अग्रिम	
दक्षता	आय की तुलना में लागत	स्टाफ व्यय की तुलना में कारोबार (क्रेडिट+जमा)#	परिचालन व्यय की तुलना में स्टाफ व्यय	
बाजार जोखिम के प्रति संवेदनशीलता	पूंजी की तुलना में आरडब्ल्यूए (बाजार जोखिम)	कुल पूंजी की तुलना में एचएफटी और एएफएस निवेश का पीवी01	कुल पूंजी की तुलना में विदेशी मुद्रा में कुल निवल खुली स्थिति	

टिप्पणी : # नकारात्मक रूप से जोखिम से संबंधित।

(बी) समष्टि दबाव परीक्षण (मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट)

मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट प्रतिकूल समष्टि-आर्थिक (मैक्रोइकॉनॉमिक) आघातों के खिलाफ बैंकों की सुदृढ़ता का मूल्यांकन करता है। यह आधार रेखा और दो प्रतिकूल परिदृश्यों के तहत डेढ़ से दो वर्षों के हॉरीजॉन पर बैंकों[1] के पूंजी अनुपात पर प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करता है। इस परीक्षण में बैंकिंग बही में ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और ब्याज दर जोखिम शामिल हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

[1] समष्टि दबाव परीक्षण (मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट) चुनिंदा 46 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) पर किया जाता है।

I. **समष्टि-परिदृश्यों को डिजाइन करना:** परीक्षण में तीन परिदृश्यों की परिकल्पना की गई है - एक आधारभूत (बेसलाइन) और दो परिकल्पित प्रतिकूल समष्टि-आर्थिक परिदृश्य। जबकि आधारभूत परिदृश्य चुनिंदा समष्टि-आर्थिक चरों के पूर्वानुमानित पथ से लिया गया है, दो प्रतिकूल परिदृश्य परिकल्पित कठोर दबाव परिदृश्य विवरणों के आधार पर और बहिर्जात चरों (वीएआरएक्स) मॉडल के साथ निम्नलिखित वेक्टर ऑटोरिग्रेशन का उपयोग करके सिमुलेशन करके प्राप्त किए जाते हैं,

$$Y_t = \sum_{p=1}^{P} A_p Y_{t-p} + \sum_{s=0}^{S} B_s X_{t-s} + u_t \quad \ldots\ldots\ldots (1)$$

जिसमें जीडीपी वृद्धि के साथ, सीपीआई मुद्रास्फीति, रेपो दर और उधार स्प्रेड बहिर्जात चरों के रूप में हैं तथा अमेरिकी जीडीपी वृद्धि और यूएस वीआईएक्स बहिर्जात चर के रूप में शामिल हैं।

II. **प्रमुख वित्तीय चरों का पूर्वानुमान:** प्रत्येक बैंक समूह के लिए पैनल रिग्रेशन मॉडल का उपयोग करके बैंक स्तर पर गिरावट अनुपात, ब्याज आय और ब्याज व्यय का पूर्वानुमान लगाया जाता है। जीएनपीए अनुपात और प्रावधान का पूर्वानुमान संरचनात्मक मॉडलों का उपयोग करके लगाया जाता है। गैर-ब्याज आय [जिसमें (ए) शुल्क आय और (बी) शुल्क आय को छोड़कर अन्य परिचालन आय शामिल है] और गैर-ब्याज व्यय, प्रत्येक परिदृश्य के तहत इन चरों की अनुमानित वृद्धि दर के आधार पर अनुमानित हैं।

(i) **गिरावट अनुपात का पूर्वानुमान:** बैंक स्तर पर त्रैमासिक गिरावट अनुपात को निम्नलिखित पैनल रिग्रेशन मॉडल का उपयोग करके पूर्वामानित किया जाता है;

$$Z_{i,t} = \beta_Z * Z_{i,t-1} + \beta'_X * X_{t-s} + \mu'_i + \lambda'_{it} + \varepsilon'_{i,t} \quad \ldots\ldots\ldots (2)$$

जहां $t = 1,\ldots, T$ और $i = 1,\ldots,N$

तिमाही t के दौरान बैंक i का त्रैमासिक गिरावट अनुपात $Z_{i,t}$ है, X_t ऋण प्रसार और जीडीपी वृद्धि सहित समष्टि-आर्थिक चरों का एक वेक्टर है, μ'_i बैंक-विशिष्ट स्थिर प्रभावों को दर्शाता है, λ'_{it} विशिष्ट तिमाहियों के लिए समायोजन को दर्शाता है और $\varepsilon'_{i,t}$ एक i.i.d. एरर टर्म है। इसके बाद, तिमाही गिरावट अनुपात, $\hat{Z}_{i,t}$ की गणना प्रतिगमन समीकरण (2) के प्रथम अंतरों के आधार पर की जाती है,

$$\hat{Z}_{i,t} = \hat{Z}_{i,t-1} + \Delta\hat{Z}_{i,t} = \hat{Z}_{i,t-1} + \{\beta_Z \times \Delta\hat{Z}_{i,t-1} + \beta'_X \times \Delta\hat{X}_{i,t-1}\} \quad \ldots\ldots\ldots (3)$$

(ii) सकल ऋणों और अग्रिमों का पूर्वानुमान: बैंक स्तर के सकल ऋणों और अग्रिमों का पूर्वानुमान अंकित जीडीपी वृद्धि के समतुल्य संवृद्धि दर को लागू करके किया जाता है,

$$L_{i,t} = L_{i,t-1}(1 + g_t) \quad \ldots\ldots\ldots (4)$$

जहां $L_{i,t}$ तिमाही t के अंत में बैंक i के सकल ऋण और अग्रिमों को दर्शाता है, और g_t तिमाही (t-1, t) के दौरान अंकित जीडीपी वृद्धि दर का प्रतिनिधित्व करता है।

(iii) अनर्जक ऋणों (एनपीएल) या जीएनपीए का पूर्वानुमान: बैंक स्तर के जीएनपीए को समीकरण का उपयोग करके पूर्वानुमानित किया जाता है,

$$NPL_{i,t} = NPL_{i,t-1}(1 - WRO_{i,t} - CURER_{i,t} - RECR_{i,t}) + PD_{i,t}.PL_{i,t-1} \quad \ldots\ldots\ldots (5)$$

जहाँ $NPL_{i,t}$ तिमाही t के अंत में बैंक i के जीएनपीए के स्टॉक को दर्शाता है, और $WRO_{i,t}$, $CURER_{i,t}$ और $RECR_{i,t}$ क्रमशः तिमाही t के दौरान बैंक i की बट्टे-खाते में डालने, उन्नयन और सुधार की दरें हैं। $PD_{i,t}$ (3) में अनुमानित चूक (गिरावट अनुपात) की संभावना है और $PL_{i,t-1}$ तिमाही t-1 के अंत में अर्जक ऋणों का स्टॉक है।

(iv) निष्पादित ऋणों का पूर्वानुमान (पीएल): तिमाही t के अंत में बैंक i के लिए निष्पादित ऋणों का स्टॉक, $PL_{i,t}$ इस प्रकार पूर्वानुमानित है,

$$PL_{i,t} = L_{i,t} - NPL_{i,t} \quad \ldots\ldots\ldots (6)$$

(v) प्रावधानों का पूर्वानुमान: तिमाही t के लिए बैंक i के प्रावधान निम्नानुसार पूर्वानुमानित हैं,

$$Provisions_{i,t} = PD_{i,t}.LGD_t.PL_{i,t-1}.PCR \quad \ldots\ldots\ldots (7)$$

जहां प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 75 प्रतिशत पर धारित किया जाता है। तिमाही t के दौरान चूक पर हानि (एलजीडी), फ्राय एंड जेकब्स (2012) के मॉडल के आधार पर प्राप्त किया गया है, जो नीचे दिया गया है:

$$LGD_{i,t0+h} = \frac{\Phi\left(\Phi^{-1}\left(PD_{i,t0+h}\right)-k\right)}{PD_{i,t0+h}} \quad \ldots\ldots\ldots (8)$$

और मापदंड k के रूप में व्युत्पन्न किया गया है,

$$k = \frac{\Phi^{-1}\left(PD^*_{i,t0}\right)-\Phi^{-1}\left(PD^*_{i,t0}\times LGD^*_{i,t0}\right)}{\sqrt{1-\rho}} \quad \ldots\ldots\ldots (9)$$

पीडी* और एलजीडी* दीर्घकालिक औसत पीडी और एलजीडी हैं और Φ संचयी सामान्य वितरण फ़ंक्शन को दर्शाता है।

(vi) ब्याज आय और व्यय का पूर्वानुमान: ब्याज आय (ब्याज अर्जित करने वाली आस्तियों के हिस्से के रूप में) और ब्याज व्यय (ब्याज-वहन करने वाली देयताओं के हिस्से के रूप में) को समीकरण (2) के समान संरचना के साथ समष्टि-आर्थिक चरों (जीडीपी वृद्धि और कॉल दर) और बैंक निश्चित प्रभावों के फ़ंक्शन के रूप में तैयार किया जाता है। इन अनुपातों के बैंक-वार पूर्वानुमानों को प्रत्येक बैंक के लिए आस्तियों और निधियों की लागत पर प्रतिफल के प्रति आघातों को प्राप्त करने के लिए अनुप्रयुक्त किया जाता है।

(vii) बाजार जोखिम का पूर्वानुमान: बाजार जोखिम का अनुमान तीन इनपुट, (i) बॉन्ड एक्सपोजर, (ii) मैकाले अवधि, और (iii) ब्याज दर आघात का उपयोग करके, बैंकों के बॉन्ड एक्सपोजर (एएफएस और एचएफटी पोर्टफोलियो) के एमटीएम पुनर्मूल्यांकन को अनुप्रयुक्त करते हुए बॉन्ड पुनर्मूल्यांकन सूत्र का उपयोग करते हुए लगाया जाता है:

$$\Delta V_{t+1} = -V_t \frac{D}{(1+r_t+s_t)}(\Delta r_{t+1} + \Delta s_{t+1}) \quad \ldots\ldots\ldots (10)$$

जहां, D मैकाले अवधि है, r जोखिम-मुक्त दर है, s क्रेडिट स्प्रेड घटक है, t परिपक्वता तक का समय चरण है, V बाजार मूल्य है, $\Delta rt+1$ जोखिम-मुक्त दर बदलाव को एवं $\Delta st+1$ क्रेडिट स्प्रेड बदलाव को दर्शाता है। इसके अलावा, बाजार जोखिम में इक्विटी और विदेशी मुद्रा जोखिम को भी शामिल किया जाता है।

(viii) निवल लाभ का पूर्वानुमान: निवल लाभ का पूर्वानुमान इस प्रकार लगाया जाता है,

$$Net\ Profit = (Interest\ Income - Interest\ Expenses) + (Non\text{-}interest\ income - Non\text{-}interest\ expenses) + Trading\ income - Loss\ Provisions - Provisions\ for\ Income\ Tax$$

(ix) पूंजी का पूर्वानुमान: पूंजी इस प्रकार पूर्वानुमानित की जाती है,

$$Capital_{t+1} = Capital_t + Net\ Profit_{(t,t+1)} + Other\ Comprehensive\ Income_{(t,t+1)} - Dividend_{(t,t+1)}$$

(x) जोखिम भारित आस्तियों (आरडब्ल्यूए) का पूर्वानुमान: ऋण जोखिम के लिए आरडब्ल्यूए को इस प्रकार पूर्वानुमानित किया जाता है,

$$RWA_{t+1} = (RWA_t - Reduction\ in\ RWA_{(t,t+1)}\ due\ to\ new\ provisions).(1 + g_t) + Additional\ RWA\ due\ to\ new\ slippages_{(t,t+1)}$$

जहां, g_t इस अवधि के दौरान अंकित जीडीपी वृद्धि दर को दर्शाता है (t, t+1)।

बाजार जोखिम के लिए आरडब्ल्यूए और परिचालन जोखिम के लिए आरडब्ल्यूए के भी अंकित जीडीपी वृद्धि दर पर बढ़ने का अनुमान है।

III. प्रमुख धारणाएँ: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) और विदेशी बैंकों (एफबी) के लिए आयकर के प्रावधान को कर पूर्व लाभ का क्रमशः 30 प्रतिशत, 30 प्रतिशत और 35 प्रतिशत माना गया है। लाभांश भुगतान अनुपात को निवल लाभ का 30 प्रतिशत माना जाता है। तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) में अंकित जीडीपी संवृद्धि की दर से वृद्धि होने का अनुमान है।

(सी) एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण - दबाव परीक्षण

तिमाही निगरानी के भाग के रूप में, इन जोखिमों के प्रति अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की समुत्थानशीलता का आकलन करने के लिए ऋण जोखिम, ब्याज दर जोखिम, चलनिधि जोखिम और इक्विटी मूल्य जोखिम को शामिल करते हुए दबाव परीक्षण किए गए थे। दबाव परीक्षण एकल एससीबी के साथ-साथ प्रणाली स्तर पर भी किए जाते हैं।

I. ऋण जोखिम (संकेंद्रण जोखिम शामिल है)

बैंकों की सुदृढ़ता का पता लगाने के लिए, पूरे पोर्टफोलियो के लिए जीएनपीए अनुपात बढ़ाकर ऋण पोर्टफोलियो को आघात दिया गया था। ऋण संकेंद्रण जोखिम के परीक्षण के लिए, बकाया ऋण के संदर्भ में शीर्ष एकल उधारकर्ता(ओं) और सबसे बड़े समूह उधारकर्ता(ओं) की चूक को माना गया। ऋण जोखिम के मामले में, जीएनपीए में अनुमानित वृद्धि को उप-मानक, संदिग्ध और हानि श्रेणियों में उसी अनुपात में वितरित किया गया था जो प्रणाली स्तर पर जीएनपीए के मौजूदा स्टॉक में प्रचलित था। तथापि, ऋण संकेंद्रण जोखिम (एक्सपोजर आधारित) के लिए, अनुमानित आघातों के अंतर्गत अतिरिक्त जीएनपीए को केवल उप-मानक श्रेणी में आने वाला माना गया और ऋण संकेंद्रण जोखिम (दबावग्रस्त अग्रिमों पर आधारित) के लिए दबावग्रस्त अग्रिमों को हानि श्रेणी में माना गया। उप-मानक, संदिग्ध और हानि अग्रिमों के लिए प्रावधान आवश्यकताओं को क्रमशः 25 प्रतिशत, 75 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के रूप में माना गया था। इन मानदंडों को दबाव परिदृश्य के तहत गणना किए गए अतिरिक्त जीएनपीए पर लागू किया गया था। जीएनपीए में अनुमानित वृद्धि के परिणामस्वरूप, वृद्धिशील प्रावधान आवश्यकताओं के अलावा, एक तिमाही के लिए अतिरिक्त जीएनपीए पर आय की हानि को भी कुल घाटे में शामिल किया गया। इस प्रकार प्राप्त अनुमानित कुल हानि को बैंकों की पूंजी से घटाया गया, और दबावग्रस्त पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना की गई।

प्रणाली-व्यापी शीर्ष 100 उधारकर्ताओं के संकेंद्रण का मूल्यांकन मीट्रिक सीआर-100 का उपयोग करके किया गया था, जिसे एससीबी के कुल बकाया ऋण के लिए शीर्ष 100 उधारकर्ताओं को दिए गए बकाया ऋण के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। दूसरा मीट्रिक, ऋण संकेंद्रण जोखिम सूचकांक (सीसीआरआई), शीर्ष 100 उधारकर्ताओं के भीतर ऋण संकेंद्रण जोखिम को मापता है। इसे (i) अनुभवजन्य सीआरएआर अवक्षयी वक्र और मूल से उसके समापन बिंदु तक एक सीधी रेखा के बीच के क्षेत्र के अनुपात (ii) इस सीधी रेखा के ऊपर कुल क्षेत्र के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। एक उच्च सीसीआरआई मान बड़े उधारकर्ताओं के बीच उच्च संकेंद्रण का संकेत देगा।

लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए, ऋण जोखिम संवेदनशीलता विश्लेषण उसी पद्धति और समान परिदृश्यों का उपयोग करके किया जाता है, जैसा एससीबी के लिए किया जाता है।

II. क्षेत्रवार ऋण जोखिम

अलग-अलग बैंकों के क्षेत्रवार ऋण जोखिम का पता लगाने के लिए, क्षेत्रों के जीएनपीए अनुपात के मानक विचलन (एसडी) के आधार पर क्षेत्र के लिए जीएनपीए अनुपात में वृद्धि करके प्रत्येक क्षेत्र के ऋण पोर्टफोलियो को आघात दिया गया। अनुमानित आघातों के तहत अतिरिक्त जीएनपीए को केवल उप-मानक श्रेणी में आने वाला माना जाता था। पूंजी पर प्रभाव की गणना ऊपर वर्णित क्रेडिट जोखिम के लिए दबाव परीक्षण के समान है।

III. ब्याज दर जोखिम

भारतीय रुपये (आईएनआर) प्रतिफल वक्र में बदलाव के अनुमानित आघातों के तहत, पोर्टफोलियो के मूल्य में गिरावट या आय में गिरावट के कारण नुकसान हो सकता है।

निवेश पोर्टफोलियो में ब्याज दर जोखिम के लिए: एएफएस, एफवीटीपीएल (एचएफटी बुक सहित) और एचटीएम श्रेणियों, मूल्यांकन प्रभाव (पोर्टफोलियो घाटे) की गणना के लिए एक अवधि विश्लेषण दृष्टिकोण पर विचार किया गया। इन निवेशों पर पोर्टफोलियो घाटे की गणना अनुप्रयुक्त आघातों के आधार पर एएफएस, एफवीटीपीएल (एचएफटी बुक सहित), ब्याज दर डेरिवेटिव पोर्टफोलियो (बचाव/हेज सहित) और एचटीएम श्रेणियों - प्रत्येक की समय अवधि के लिए की गई थी। दबाव परिदृश्यों के तहत पूंजी अनुपात पर पहुंचने के लिए इन अनुमानित हानियों को बैंकों की पूंजी और आरडब्ल्यूए से बाजार जोखिम भारित हानियों से घटाया गया।

बैंकों का ब्याज दर जोखिम - बैंक की पूंजी और ब्याज दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ावों से उत्पन्न होने वाली आय के जोखिम को संदर्भित करता है जो बैंक के बही-खाते को प्रभावित करता है। अर्जन पर प्रभाव को पारंपरिक अंतराल विश्लेषण (टीजीए) का उपयोग करके मापा जाता है और पूंजी प्रभाव को अवधि अंतराल विश्लेषण (डीजीए) द्वारा मापा जाता है। टीजीए का मुख्य कार्य एक वर्ष की अवधि में ब्याज दर उतार-चढ़ाव के प्रति अपनी निवल ब्याज आय (एनआईआई) की संवेदनशीलता के संदर्भ में ब्याज दर जोखिम के लिए बैंक के जोखिम के स्तर को मापना है। इसमें विभिन्न समय अवधियों में सभी दर-संवेदनशील आस्तियों (आरएसए), दर-संवेदनशील देयताओं (आरएसएल) और ऑफ-बैलेंस शीट मदों की अवशिष्ट परिपक्वता/पुन: मूल्य निर्धारण तिथि के अनुसार बकेटिंग करना तथा जोखिम पर अर्जन (ईएआर) यानी एक वर्ष की समयावधि में विभिन्न ब्याज दर परिदृश्यों के तहत आय की हानि की गणना करना शामिल है। अग्रिम, निवेश, स्वैप/विदेशी मुद्रा स्वैप और रिवर्स रेपो आरएसए में प्रमुख योगदानकर्ता हैं जबकि जमा, स्वैप/विदेशी मुद्रा स्वैप और रेपो आरएसएल के तहत मुख्य तत्व हैं। डीजीए में विभिन्न समय अवधियों में अवशिष्ट परिपक्वता/पुन: मूल्य निर्धारण तिथियों के अनुसार सभी आरएसए और आरएसएल की बकेटिंग शामिल है। डीजीए में विभिन्न समय अवधियों में अवशिष्ट परिपक्वता/पुनः कीमत निर्धारण तिथियों के अनुसार सभी आरएसए और आरएसएल की बकेटिंग और इक्विटी के बाजार मूल्य पर प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए संशोधित अवधि अंतराल (एमडीजी) की गणना करना शामिल है। एमडीजी की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जाती है:- एमडीजी = [एमडीए - एमडीएल * (आरएसएल / आरएसए)], जहां एमडीए और एमडीएल क्रमशः आरएसए और आरएसएल की मदों की संशोधित अवधि (एमडी) के भारित औसत हैं। इसके बाद, इक्विटी के बाजार मूल्य (एमवीई) में परिवर्तन की गणना $\Delta E/E$ = -[एमडीजी]* आरएसए* $\Delta i/E$ के रूप में की जाती है, जहां Δi ब्याज दर में परिवर्तन है और E इक्विटी (यानी निवल मालियत) है।

IV. इक्विटी मूल्य जोखिम

इक्विटी मूल्य जोखिम के अंतर्गत, इक्विटी मूल्य सूचकांक में कतिपय प्रतिशत अंकों की गिरावट के दबाव का बैंक पूंजी पर प्रभाव जांचा गया। इक्विटी मूल्यों में परिवर्तन के कारण पोर्टफोलियो के मूल्य में गिरावट के कारण होने वाले घाटे को बैंक की पूंजी से घटाया जाता है, ताकि दबावग्रस्त पूंजी का पता लगाया जा सके।

V. चलनिधि जोखिम

चलनिधि दबाव परीक्षण, किसी बैंक की बाहरी चलनिधि सहायता लिए बिना अप्रत्याशित चलनिधि निकासी का सामना करने की क्षमता का आकलन करता है। दबाव परीक्षण चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) ढांचे पर आधारित है। दबाव परीक्षण के लिए आधारभूत परिदृश्य मौजूदा एलसीआर गणना दिशानिर्देशों को दर्शाता है और तदनुसार नकदी बहिर्वाह, अंतर्वाह और चल आस्तियों के प्रत्येक घटक पर एलसीआर गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले भार को लागू करता है। प्रतिकूल दबाव परिदृश्यों को कुछ नकदी बहिर्वाह (सारणी 2) के लिए आधारभूत परिदृश्य के सापेक्ष उच्च रन-ऑफ दरों को लागू करके डिज़ाइन किया गया है। प्रत्येक बैंक के लिए एलसीआर की गणना इनमें से प्रत्येक परिदृश्य के तहत की जाती है।

सारणी 2:- नकदी बहिर्वाह घटकों पर लागू रन-ऑफ कारक

(प्रतिशत में)

परिदृश्य	**आधार रेखा**	**दबाव परिदृश्य 1**	**दबाव परिदृश्य 2**
खुदरा जमा			
स्थिर जमा	5	6	7
कम स्थिर खुदरा जमा	10	11	12
असुरक्षित थोक वित्तपोषण			
मांग और मीयादी जमा, अवशिष्ट परिपक्वता < 30 दिन, लघु व्यवसाय			
स्थिर जमा	5	6	7
कम स्थिर जमा	10	11	12
गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट, संप्रभु, केंद्रीय बैंक, बहुपक्षीय विकास बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	40	42.5	45
वर्तमान में अप्रयुक्त लेकिन प्रतिबद्ध ऋण और चलनिधि सुविधाएं			
खुदरा और लघु व्यवसाय	5	10	12
गैर-वित्तीय कॉर्पोरेट, संप्रभु, केंद्रीय बैंक, बहुपक्षीय विकास बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम			
ऋण सुविधाएं	10	12	15
चलनिधि सुविधाएं	30	40	50

(डी) उर्ध्वगामी (बॉटम-अप) दबाव परीक्षण: ऋण, बाज़ार और चलनिधि जोखिम

ऋण, बाज़ार और चलनिधि जोखिमों के लिए उर्ध्वगामी दबाव परीक्षण 37 चयनित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किए गए थे। चयनित बैंकों को समान दबाव परिदृश्यों और आघातों का एक समूह दिया गया था। बैंकों द्वारा परीक्षण मार्च 2026 के अंत तक के प्रासंगिक डेटा और प्रत्येक मामले में नुकसान की गणना के लिए अपनी स्वयं की कार्यप्रणाली का उपयोग करके किए गए थे।

(डी) उर्ध्वगामी (बॉटम-अप) दबाव परीक्षण: ऋण, बाज़ार और चलनिधि जोखिम

डेरिवेटिव पोर्टफोलियो (अनुमानित मूल्य के संदर्भ में) पर दबाव परीक्षण 36 बैंकों के नमूने द्वारा किए गए, जिसमें प्रमुख सक्रिय प्राधिकृत व्यापारी और ब्याज दर स्वैप प्रतिपक्षकार शामिल थे। नमूने में प्रत्येक बैंक से उनके संबंधित डेरिवेटिव पोर्टफोलियो पर दबाव की स्थिति के प्रभाव का आकलन करने के लिए कहा गया ।

घरेलू बैंकों के मामले में, घरेलू और विदेशी दोनों परिचालनों के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो को शामिल किया गया । विदेशी बैंकों के मामले में, परीक्षण के लिए केवल घरेलू (भारतीय) स्थिति पर विचार किया गया । डेरिवेटिव ट्रेड्स जहां हेज प्रभावशीलता स्थापित की गई थी, उन्हें दबाव परीक्षणों से छूट दी गई, जबकि अन्य सभी ट्रेड्स को शामिल किया गया।

दबाव परिदृश्यों में चार आघात शामिल थे जिनमें स्पॉट यूएसडी-आईएनआर दर और घरेलू ब्याज दरें मापदंड के रूप में शामिल थीं (सारणी 3)।

सारणी 3:- संवेदनशीलता विश्लेषण के लिए आघात

	घरेलू ब्याज दरें	
आघात 1	एक दिवसीय	**+2.5 प्रतिशतता अंक**
	1 वर्ष तक	**+1.5 प्रतिशतता अंक**
	1 वर्ष से अधिक	**+1.0 प्रतिशतता अंक**
	घरेलू ब्याज दरें	
आघात 2	एक दिवसीय	**-2.5 प्रतिशतता अंक**
	1 वर्ष तक	**-1.5 प्रतिशतता अंक**
	1 वर्ष से अधिक	**-1.0 प्रतिशतता अंक**
	विनिमय दरें	
आघात 3	यूएस डालर/ भारतीय रुपया	**+20 प्रतिशत**
	विनिमय दरें	
आघात 4	यूएस डालर/ भारतीय रुपया	**-20 प्रतिशत**

1.2 प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

एकल कारक संवेदनशीलता विश्लेषण – दबाव परीक्षण

मार्च 2026 तक रिपोर्ट की गई स्थिति के संदर्भ में क्रेडिट जोखिम, बाज़ार जोखिम और चलनिधि जोखिम के प्रति उनकी आघात सहनीयता का आकलन करने के लिए यूसीबी का दबाव परीक्षण किया गया।

I. ऋण चूक जोखिम

ऋण चूक जोखिम के तहत, मॉडल का उद्देश्य किसी बैंक के सीआरएआर पर दबावग्रस्त क्रेडिट पोर्टफोलियो के प्रभाव का आकलन करना है। जीएनपीए की वार्षिक वृद्धि दर के अंकगणितीय माध्य की गणना प्रत्येक एनपीए वर्ग (अवमानक, संदिग्ध 1 (डी1), संदिग्ध 2 (डी2), संदिग्ध 3 (डी3) और हानि आस्ति) के लिए यूसीबी क्षेत्र के लिए समग्र रूप से 2009 और 2026 के बीच रिपोर्ट किए गए डेटा के आधार पर की गई। वार्षिक वृद्धि दर के अंकगणितीय माध्य से आधार दबाव परिदृश्य का निर्माण हुआ, जिसमें प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग मध्यम और गंभीर दबाव परिदृश्य उत्पन्न करने के लिए 1.5 मानक विचलन (एसडी) और 2.5 एसडी के आघात लगाकर और अधिक दबावग्रस्त किया गया। इन्हें एनपीए विचलन स्तर के आधार पर आगे समायोजित किया गया।उपरोक्त पद्धति के आधार पर, तीन दबाव परिदृश्यों के तहत प्राप्त वार्षिक एनपीए वृद्धि दर मैट्रिक्स सारणी में दी गई है ।

(प्रतिशत)

	अवमानक आस्तियों में वृद्धि	**डी 1 आस्तियों में वृद्धि**	**डी 2 आस्तियों में वृद्धि**	**डी 3 आस्तियों में वृद्धि**	**हानि आस्तियों में वृद्धि**
बेसलाइन दबाव	19.38	15.84	13.94	14.82	35.03
मध्यम दबाव	58.55	43.67	37.41	48.84	167.60
गंभीर दबाव	84.67	62.22	53.07	71.53	255.98

II. ऋण संकेन्द्रण जोखिम

शीर्ष 1, 2 और 3 एकल उधारकर्ता एक्सपोजरों के 'हानि अग्रिम' श्रेणी में चले जाने के कल्पित परिदृश्यों में, जिसके कारण 100 प्रतिशत प्रावधानीकरण करना पड़ता है, सीआरएआर पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया गया। ये जोखिम आवश्यक रूप से 'मानक अग्रिम' नहीं हो सकते हैं, लेकिन इनकी पहचान उच्च प्रावधान की आवश्यकता की उनकी क्षमता के आधार पर की गई है, जिससे अधिक प्रभावशाली दबाव परिदृश्य परिलक्षित होता है।

III. ट्रेडिंग (व्यापार) बही में ब्याज दर जोखिम

यूसीबी के एएफएस और एचएफटी पोर्टफोलियो की ब्याज दरों में वृद्धि के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए अवधि विश्लेषण पद्धति अपनाई गई। तीन दबाव परिदृश्यों के तहत ब्याज दरों में 50 बीपीएस, 100 बीपीएस और 150 बीपीएस की वृद्धि की कल्पना की गई और सीआरएआर पर प्रावधानीकरण के प्रभाव का आकलन किया गया।

IV. बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

यूसीबी की बैंकिंग बही को तीन दबाव परिदृश्यों के तहत 50 आधार अंक, 100 आधार अंक और 150 आधार अंक के ब्याज दर आघातों के अधीन रखा गया और इसकी निवल ब्याज आय पर इनके प्रभाव का आकलन किया गया।

V. चलनिधि जोखिम

दबाव परीक्षण 1-28 दिनों की समय अवधि में संचयी नकदी प्रवाहों के आधार पर किया गया। नकदी अंतर्वाह और बहिर्वाह को आधार, मध्यम और गंभीर परिदृश्यों के तहत दबाव दिया गया। जबकि सभी दबाव परिदृश्यों के तहत अंतर्वाह 5 प्रतिशत पर समान रूप से दबावग्रस्त है, पिछले दस वर्षों (2015 - 2025) की अवधि के लिए तिमाहियों में दर्ज सबसे खराब नकारात्मक जमा वृद्धि के आधार पर बहिर्वाह दबावग्रस्त है। चूंकि यूसीबी मुख्य रूप से निधियों के प्रमुख स्रोत के रूप में जमा पर निर्भर हैं, इसलिए जमा में नकारात्मक वृद्धि को दबावग्रस्त बहिर्वाह का प्रतिनिधि माना गया है। इसके अलावा, तीन माह की अवधि को 1-28 दिनों की बकेट के प्रतिनिधि के रूप में माना गया है क्योंकि यह निकटतम अल्पकालिक अवधि है जिसके लिए सभी बैंकों के लिए जमा डेटा उपलब्ध है (यह देखते हुए कि सभी बैंक तिमाही रिटर्न प्रस्तुत करते हैं)। दस वर्षों के लिए सबसे खराब नकारात्मक जमा वृद्धि दर का औसत आधार परिदृश्य माना गया है, जिसे बहिर्वाह के लिए मध्यम और गंभीर दबाव परिदृश्य उत्पन्न करने के लिए 1.5 एसडी और 2.5 एसडी द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। 17 सितंबर 2008 के परिपत्र संख्या आरबीआई/2008-09/174 यूबीडी पीसीबी.परि. सं.12/12.05.001/2008-09 , जो यह निर्धारित करता है कि सामान्य स्थिति में 1-14 दिवसीय तथा 15-28 दिवसीय अवधि वर्ग के दौरान असंतुलन (नकदी आवक और जावक के बीच नकारात्मक अंतर) प्रत्येक अवधि वर्ग में नकदी जावक के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, के आधार पर ऐसे बैंक जिनके बहिर्वाहों में 20 प्रतिशत से अधिक नकारात्मक संचयी असंतुलन (नकदी अंतर्वाह कम नकदी बहिर्वाह) था उन्हें दबावग्रस्त माना गया।

1.3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफ़सी)

(ए) गैर-बैंकिंग स्थिरता संकेतक (एनबीएसआई) और मानचित्र

गैर-बैंकिंग स्थिरता संकेतक (एनबीएसआई) अंतर्निहित स्थितियों और जोखिम कारकों, जो किसी अवधि के दौरान एनबीएफसी क्षेत्र की स्थिरता पर असर डालते हैं, में परिवर्तनों का एक समग्र मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। स्केल-आधारित विनियामकीय संरचना के अनुरूप, ऊपरी और मध्य लेयर (मूल निवेश कंपनियों (सीआईसी), प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को छोड़कर) में आने वाली एनबीएफसी को संकेतक और संबंधित स्थिरता मानचित्र के निर्माण के लिए माना गया है।

एनबीएसआई में पांच समग्र सूचकांक हैं जो पाँच आयामों में जोखिमों का प्रतिनिधित्व करते हैं - सुदृढ़ता, आस्ति-गुणवत्ता, लाभप्रदता, चलनिधि और दक्षता। प्रत्येक समग्र सूचकांक जोखिम का एक सापेक्ष माप है और संबंधित जोखिम आयाम (सारणी 4) में एकाधिक वित्तीय अनुपातों का उपयोग करके बनाया गया है। एक समग्र सूचकांक के उच्च मान का अर्थ उस आयाम में उच्च जोखिम होगा।

प्रत्येक वित्तीय अनुपात को पहले निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके नमूना अवधि के लिए सामान्यीकृत किया गया है:-

$$Y_t = \frac{X_t - min(X_t)}{max(X_t) - min(X_t)}$$

जहाँ X_t समय t पर वित्तीय अनुपात का मान है। यदि कोई चर जोखिम से नकारात्मक रूप से संबंधित है, तो इसे $1\text{-}Y_t$ का उपयोग करके सामान्यीकृत किया गया है। प्रत्येक आयाम का समग्र सूचकांक की गणना तब उस आयाम में सामान्यीकृत अनुपातों के सरल औसत के रूप में की गई है। अंत में, एनबीएसआई इन पाँच समग्र सूचकांकों के सरल औसत के रूप में बनाया गया है। प्रत्येक समग्र सूचकांक और समग्र एनबीएसआई शून्य और एक के बीच हैं।

सारणी 4:- गैर-बैंकिंग स्थिरता संकेतक और मानचित्र के निर्माण के लिए उपयोग किए गए अनुपात

	आयाम		
सुदृढ़ता	सीआरएआर #	पूंजी के अनुपात में निवल एनपीए	आस्तियों के अनुपात में टियर 1 पूंजी #
आस्ति गुणवत्ता	कुल अग्रिमों के अनुपात में सकल एनपीए	प्रावधानीकरण कवरेज अनुपात #	सकल एनपीए के अनुपात में अवमानक अग्रिम#
लाभप्रदता	आस्तियों पर प्रतिलाभ#	निवल ब्याज मार्जिन #	निवल स्वामित्व वाली निधियों पर प्रतिलाभ #
चलनिधि	कुल आस्तियों के अनुपात में अल्पकालिक देयता	कुल आस्तियों के अनुपात में दीर्घकालिक आस्तियां	गतिशील चलनिधि #
दक्षता	आय के अनुपात में लागत	कुल व्यय के अनुपात में कर्मचारी व्यय	कर्मचारी व्यय के अनुपात में व्यवसाय #

नोट:- # जोखिम से नकारात्मक रूप से संबंधित।

(बी) एकल घटक संवेदनशीलता विश्लेषण - दबाव परीक्षण

एनबीएफसी के लिए ऋण और चलनिधि जोखिम दबाव परीक्षण आधार, मध्यम और उच्च जोखिम परिदृश्यों के तहत किए गए है।

I. ऋण जोखिम

एक वर्ष की अवधि में एनबीएफसी के तुलन-पत्र की प्रमुख मदों को चल औसत और स्मूथिंग तकनीकों को लागू करके अनुमानित किया गया। अगले एक वर्ष में आस्तियों, कुल आस्तियों के अनुपात में अग्रिम, लाभ और कर से पहले की आय (ईबीपीटी) तथा कुल आस्तियों का अनुपात, जोखिम-भार घनत्व और गिरावट अनुपात का अनुमान लगाया गया; और उसके बाद, इन अनुमानों के आधार पर – आधार परिदृश्य के लिए नई गिरावट, प्रावधान, ईबीपीटी, जोखिम-भारित आस्तियों और पूंजी की गणना की गई। मध्यम और उच्च जोखिम परिदृश्यों के लिए, आधार परिदृश्य के तहत जीएनपीए में 1 एसडी और 2 एसडी की वृद्धि की गई और तदनुसार नई पूंजी और सीआरएआर की गणना की गई ।

II. ऋण संकेन्द्रण जोखिम

ऋण संकेंद्रण जोखिम का परीक्षण करने के लिए, शीर्ष व्यक्तिगत उधारकर्ता(ओं) और सबसे बड़े समूह उधारकर्ता(ओं) की बकाया ऋण के संदर्भ में चूक की कल्पना की गई। विश्लेषण को एकीकृत स्तर के साथ ही व्यक्तिगत एनबीएफसी स्तर पर भी किया गया। माने गए आघातों के तहत अतिरिक्त जीएनपीए को अवमानक श्रेणी में आने वाला माना गया और प्रावधानीकरण आवश्यकताओं को 25 प्रतिशत लिया गया। ये मानदंड दबाव परिदृश्य के तहत गणना किए गए अतिरिक्त जीएनपीए पर लागू किए गए। वृद्धिशील प्रावधानीकरण आवश्यकताओं के अलावा, अतिरिक्त जीएनपीए पर एक तिमाही

के लिए आय की हानि को कुल नुकसान में भी शामिल किया गया। इस प्रकार अनुमानित हानि को बैंक की पूंजी से घटा दिया गया और दबाव परिदृश्यों के तहत पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना की गई।

III. चलनिधि जोखिम

दबाव परिदृश्य के अंतर्गत नकदी प्रवाह और चलनिधि की स्थिति में असंतुलन की गणना अगले एक वर्ष के दौरान विभिन्न अवधि के समूहों में समग्र नकदी अंतर्वाहों और बहिर्वाहों को पूर्वनिर्धारित दबाव प्रतिशत निर्दिष्ट करके की गई। आधार परिदृश्य के तहत चलनिधि असंतुलन की गणना के लिए अगले एक वर्ष के दौरान मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार अनुमानित बहिर्वाहों और अंतर्वाहों पर विचार किया गया। नमूना एनबीएफसी के बहिर्वाहों और अंतर्वाह को अगले एक वर्ष में मध्यम और उच्च जोखिम वाले परिदृश्यों के लिए क्रमशः 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत का आघात लगाया गया । ऐसे आघातों के कारण संचयी चलनिधि असंतुलन की गणना संचयी वहिर्वाहों के प्रतिशत के रूप में की गई और नकारात्मक संचयी असंतुलन प्रदर्शित करने वाली एनबीएफसी की पहचान की गई।

1.4 म्यूचुअल फंड की दबाव परीक्षण पद्धति

सेबी ने सभी असीमित अवधि वाली (ओपन एंडेड) ऋण योजनाओं (एकदिवसीय योजनाओं को छोड़कर) का दबाब परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। तदनुसार, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) ने म्यूचुअल फंड की ऋण योजनाओं द्वारा दबाव परीक्षण पर सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। दबाव परीक्षण सभी आस्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) द्वारा मासिक आधार पर आंतरिक रूप से और बाज़ार की स्थितियों के अनुसार आवश्यक होने पर किया जाता है । दबाव परीक्षण हेतु संपूर्ण क्षेत्र में एक समान पद्धति अपनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत दबाव परीक्षण के परिणामस्वरूप एनएवी पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जाता है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) और प्रत्येक एएमसी जोखिम मापदंडों के प्रभाव की सीमाएँ निर्धारित करते हैं: एएमएफआई या एएमसी की सीमा का उल्लंघन होने पर रिपोर्टिंग और सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता होती है।

दबाव परीक्षण के मानदंड

दबाव परीक्षण तीन जोखिम मापदंडो पर आयोजित किया जाता है, अर्थात, ब्याज दर जोखिम, ऋण संबंधी जोखिम और चलनिधि जोखिम।

(ए) ब्याज दर जोखिम से संबंधित मानदंड

ब्याज दर जोखिम से संबंधित मानदंडों के लिए, एएमसी पोर्टफोलियो स्तर पर योजनाओं को ब्याज दर के उतार-चढ़ाव के निम्नलिखित परिदृश्यों के अधीन रखकर उसके एनएवी पर प्रभाव का आकलन करते हैं।

1) पिछले 120 महीनों में जी-सेक प्रतिफल में सबसे अधिक वृद्धि (1-वर्षीय जी-सेक या 10-वर्षीय जी-सेक, जो भी माह-दर-माह आधार पर अधिक हो, इसमें किसी माह की अधिकतम प्रतिफल की तुलना पिछले माह की न्यूनतम प्रतिफल से की जाती है).
2) पिछले 120 महीनों में जी-सेक प्रतिफल में उच्चतम वृद्धि का दो-तिहाई ।
3) पिछले 120 महीनों में जी-सेक प्रतिफल में उच्चतम वृद्धि का एक तिहाई।

(बी) ऋण संबंधी जोखिम मानदंड

ऋण संबंधी जोखिम मानदंड के लिए, एएमसी योजना द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों को निम्नलिखित प्रक्रिया के अंतर्गत रख सकते हैं:

1) प्रत्येक प्रतिभूति के डाउनग्रेड होने की संभावना की गणना करें। इस संबंध में, प्रत्येक प्रतिभूति के लिए सभी संभावित डाउनग्रेड परिदृश्यों (स्तर/नॉच) को शामिल करने के लिए, रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित संभाव्यता सारणियों का उपयोग किया जा रहा है।

2) इसके अलावा, प्रत्येक संभावित नोच्ड डाउन रेटिंग, रेटिंग में उस परिवर्तन के अनुरूप प्रतिभूति के लिए मूल्यांकन प्रतिफल में परिवर्तन के अनुरूप होगी। संबंधित रेटिंग परिवर्तनों के लिए मूल्यांकन प्रतिफल में परिवर्तन मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मूल्यांकन मैट्रिक्स से प्राप्त होता है।

3) इसके बाद निवेश ग्रेड के भीतर डाउनग्रेड की संभावना और किसी प्रतिभूति के डाउनग्रेड पर प्रतिफल में परिवर्तन के जोड़ को उत्पाद को उस प्रतिभूति की अवधि और पोर्टफोलियो में उस प्रतिभूति के भार से गुणा किया जाता है। अलग से, किसी भी प्रतिभूति के डाउनग्रेड पर लागू कटौती के साथ निवेश ग्रेड से नीचे की रेटिंग की संभावना के योगफल को पोर्टफोलियो में उस प्रतिभूति के भार से गुणा किया जाता है। प्रतिभूति स्तर पर समग्र संभावित प्रभाव प्राप्त करने के लिए इन दो योगफलों को जोड़ा जाता है।

4) प्रतिभूति स्तर के इन सभी उत्पादों के योग को पोर्टफोलियो स्तर का ऋण प्रभाव माना जाता है।

(सी) चलनिधि संबंधी जोखिम मानदंड

चलनिधि संबंधी जोखिम मानदंडो के लिए, निम्नलिखित विश्लेषण किया जा रहा है:-

1) संबंधित अवधि वर्ग के लिए संबंधित मैट्रिक्स में किसी दी गई क्रेडिट रेटिंग, प्रतिभूति के प्रकार आदि के लिए प्रतिफल में वृद्धि के साथ दबाव की पिछली अवधि (अर्थात वर्ष 2008, 2013, 2018, 2020 के दौरान दबाव परिदृश्य) के आंकड़ों पर विचार किया जाता है।

2) पूर्ववर्ती सामान्य अवधि (सामान्य अवधि दबाव अवधि की शुरुआत से 6 माह पहले शुरू होने वाली और दबाव अवधि की शुरुआत पर समाप्त होने वाली अवधि है) की तुलना में दबाव अवधि के दौरान जी-सेक पर औसत प्रतिफल अंतर में परिवर्तन को दबाव परीक्षण के उद्देश्य से स्प्रेड में वृद्धि के रूप में माना जाता है।

3) एएमसी बाज़ार परिदृश्यों के आधार पर दबाव परीक्षण के लिए प्रतिफल में बढ़ोतरी को एएमएफआई-निर्दिष्ट मूल्यों की तुलना में अधिक मानते हैं।

4) इन गणनाओं को संबंधित रेटिंग, मैट्रिक्स फ़ाइलों और अवधि वर्ग के अनुसार मैट्रिक्स-आधारित क्षेत्र के आधार पर अलग-अलग प्रतिभूतियों के लिए फिर से दोहराया जाता है और पोर्टफोलियो स्तर पर आउटपुट प्राप्त करने के लिए पोर्टफोलियो स्तर पर जोड़ा जाता है।

इसके अतिरिक्त एएमसी पूर्ण पोर्टफोलियो के समयबद्ध परिसमापन (अर्थात 5 दिन, 3 दिन और 1 दिन) पर उपयुक्त हेयरकट लागू करके और एनएवी पर इसके प्रभाव के अत्यधिक दबाव परिदृश्यों पर विचार करते हैं।

इसके अलावा, असीमित अवधि (ओपन-एंडेड) ऋण योजनाओं के लिए चलनिधि जोखिम प्रबंधन के हिस्से के रूप में, दो प्रकार के चलनिधि अनुपातों का उपयोग किया गया है, अर्थात् (i) जोखिम पर मोचन (एलआर-आरएआर), जो किसी दिए गए विश्वास अंतराल पर संभावित निकासी को दर्शाता है, और (ii) सशर्त जोखिम पर मोचन (एलआर-सीआरएआर), जो दिए गए विश्वास अंतराल पर ट्रेल के व्यवहार को दर्शाता है। सभी एएमसी के लिए इन चलनिधि अनुपातों को न्यूनतम सीमा से ऊपर बनाए रखना अनिवार्य किया गया है, जो योजना के प्रकार, योजना की आस्ति संरचना और संभावित निकासी (योजना में निवेशक संकेंद्रण से मॉडलित) पर आधारित होते हैं। म्यूचुअल फंड (एमएफ़) को सभी असीमित अवधि (ओपन-एंडेड) ऋण योजनाओं (एकदिवसीय फंड, गिल्ट फंड और 10-वर्ष की स्थिर अवधि वाले गिल्ट फंड के अलावा) के लिए इन चलनिधि अनुपातों की मासिक आधार पर बैक-टेस्टिंग करने की आवश्यकता है।

1.5 समाशोधन निगमों में दबाव परीक्षण विश्लेषण की पद्धति

सेबी ने मूल निपटान गारंटी निधि (एसजीएफ); एसजीएफ के भीतर एक मूल निधि (जिसे मूल एसजीएफ कहा जाता है), जिसके सापेक्ष कोई एक्सपोजर नहीं दिया जाता है और जो समाशोधन सदस्य (सदस्यों) द्वारा निपटान दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहने की स्थिति में समाशोधन निगम के निपटान दायित्वों को पूरा करने के लिए सुलभ और बिना शर्त उपलब्ध है, बनाने के लिए दबाव परीक्षण और डिफ़ॉल्ट प्रक्रियाएं; बाज़ार अवसंरचना के सिद्धांतों (ऋण संबंधी जोखिम के लिए दबाव परीक्षण, चलनिधि जोखिम के लिए दबाव परीक्षण तथा आवृत्ति और परिदृश्यों सहित प्रतिवर्ती दबाव परीक्षण संबंधी मानदंड) के साथ समाशोधन निगमों की दबाव परीक्षण पद्धतियों के संरेखण; दबाव परीक्षण में संस्थागत व्यापारों (ट्रेडस) में संभावित डिफ़ॉल्ट के कारण जोखिम की पहचान; समाशोधन निगमों में डिफ़ॉल्ट वाटरफाल्स को सुसंगत बनाने; केंद्रीय प्रतिपक्षकारों (सीसीपी) के प्रति एक्सपोज़र के लिए बासेल पूंजी पर्याप्तता आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नॉन-डिफॉल्टिंग सदस्यों की देयताओं को सीमित करने; समाशोधन निगम के प्रत्येक खंड को अन्य खंडों के डिफ़ाल्ट से सुरक्षित करने; और विभिन्न समाशोधन निगमों के दबाव परीक्षण और जोखिम प्रबंधन प्रथाओं में एकरूपता लाने, विशेष रूप से सदस्यों के डिफ़ॉल्ट के संबंध में, से संबंधित विस्तृत मानदंड निर्दिष्ट किए हैं।

न्यूनतम आवश्यक आधारभूत निधि (एमआरसी) निर्धारित करने के लिए समाशोधन निगमों (सीसी) में दबाव परीक्षण किया जाता है, जिसके लिए कोर एसजीएफ में समाशोधन सदस्यों (सीएम) द्वारा योगदान करने की आवश्यकता होती है। एमआरसी प्रत्येक खंड (अर्थात नकदी बाज़ार, इक्विटी डेरिवेटिव, मुद्रा डेरिवेटिव, कमोडिटी डेरिवेटिव, ऋण और त्रि-पक्षीय रेपो खंड) के लिए हर माह दबाव परीक्षण के आधार पर निम्नलिखित के अधीन अलग से निर्धारित किया जाता है:-

(ए) एमआरसी एक माह के लिए तय है।

(बी) हर माह की 15 तारीख तक, सीसी पिछले माह के दैनिक दबाव परीक्षणों के परिणामों के आधार पर अगले माह के लिए एमआरसी की समीक्षा और निर्धारण करते हैं।

(सी) पिछले माह के प्रत्येक दिन के लिए, दबाव परीक्षण के आधार पर प्रत्येक खंड के लिए अनारक्षित हानि मात्रा का अनुमान लगाया जाता है और ऐसी अधिकतम मात्रा को उस दिन की सर्वाधिक हानि की मात्रा के रूप में लिया जाता है।

(डी) ऊपर (iii) में निर्धारित सभी दैनिक सर्वाधिक हानि मात्राओं के औसत की गणना की जाती है।

(ई) अगले माह के लिए एमआरसी कम से कम उपरोक्त चरण (iv) में प्राप्त औसत और पिछली समीक्षा के अनुसार खंड एमआरसी से अधिक है।

नकदी, इक्विटी डेरिवेटिव और मुद्रा डेरिवेटिव खंड के लिए एमआरसी निर्धारित करने के लिए, सीसी, शीर्ष दो सीएम के एक साथ अनुमानित डिफ़ॉल्ट से उत्पन्न होने वाले क्रेडिट एक्सपोजर की गणना करते हैं। प्रत्येक सीएम के लिए क्रेडिट एक्सपोज़र का निर्धारण जोखिम की स्थिति (दबाव परीक्षण परिदृश्यों के तहत) को समाप्त करने से होने वाले क्लोज-आउट हानि और अपेक्षित मार्जिन और अन्य अनिवार्य जमाओं के लिए सीएम की निवल पे-इन/पे-आउट आवश्यकता का आकलन करके किया जाता है। एमआरसी या माह के दौरान औसत दबाव परीक्षण नुकसान, माह के सभी दैनिक सर्वाधिक खराब मामले के नुकसान परिदृश्यों के औसत के रूप में निर्धारित किया जाता है। किसी भी माह के लिए वास्तविक एमआरसी कम से कम उस माह के औसत दबाव परीक्षण हानि या अतीत में किसी भी समय निकाली गई एमआरसी से अधिक निर्धारित की जाती है। ऋण खंड के लिए, ट्रेडिंग वॉल्यूम न्यूनतम है, और इसलिए मूल एसजीएफ के लिए एमआरसी की गणना ₹4 करोड़ से अधिक या शीर्ष दो सीएम की कुल हानि के रूप में की जाती है, यह मानते हुए कि अपेक्षित मार्जिन से चार प्रतिशत कम के नुकसान पर दायित्वों का क्लोज आउट किया गया है। त्रि-पक्षीय रेपो खंड और कमोडिटी डेरिवेटिव खंड भी उन्हीं दबाव परीक्षण मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करते हैं जो इक्विटी नकदी, इक्विटी डेरिवेटिव और मुद्रा डेरिवेटिव खंड के लिए निर्धारित हैं। तथापि, कमोडिटी डेरिवेटिव खंड के लिए, एमआरसी की गणना शीर्ष दो सीएम के डिफॉल्ट के कारण अधिकतम क्रेडिट एक्सपोजर या सभी सीएम के एक साथ डिफॉल्ट

के कारण क्रेडिट एक्सपोजर के 50 प्रतिशत के रूप में की जाती है। इसके अलावा, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के कमोडिटी डेरिवेटिव वर्ग के लिए एमआरसी की न्यूनतम सीमा मूल्य ₹10 करोड़ है।

सीसी प्रत्येक खंड के लिए कम से कम सेबी द्वारा निर्धारित मानकीकृत दबाव परीक्षण पद्धति का उपयोग करके क्रेडिट जोखिम के लिए दैनिक दबाव परीक्षण करते हैं। नकदी बाज़ार और डेरिवेटिव बाज़ार खंडों के लिए निर्धारित दबाव परिदृश्यों के अलावा, सीसी विभिन्न प्रकार की 'चरम लेकिन तर्कसंगत बाज़ार स्थितियों' के लिए अपने स्वयं के परिदृश्य भी विकसित करते हैं (डिफॉल्टरों की स्थिति और परिसमापन अवधि में संभावित मूल्य परिवर्तन दोनों के संदर्भ में और इन पोजीशनों के परिसमापन से बाज़ार पर पड़ने वाले प्रभाव के जोखिम के साथ) और स्व-विकसित परिदृश्यों का उपयोग करके दबाव परीक्षण करते हैं। ऐसे परिदृश्यों में प्रासंगिक उच्चतम ऐतिहासिक मूल्य अस्थिरताएं, मूल्य निर्धारक और प्रतिफल वक्रों जैसे अन्य बाज़ार कारकों में बदलाव, विभिन्न अवधि वर्गों में कई चूक और विभिन्न उच्चतम लेकिन तर्कसंगत बाज़ार स्थितियों में भविष्योन्मुखी दबाव परिदृश्यों की एक श्रृंखला शामिल है। इसके अलावा, उन उत्पादों के लिए जिनके लिए निर्दिष्ट दबाव परीक्षण पद्धति निर्धारित नहीं की गई है, सीसी चरम लेकिन तर्कसंगत बाज़ार परिदृश्य (काल्पनिक और ऐतिहासिक दोनों) विकसित करते हैं और ऐसे परिदृश्यों के आधार पर दबाव परीक्षण करते हैं तथा एसजीएफ की आधारभूत निधि में वृद्धि करते हैं, जैसा कि ऐसे दबाव परीक्षण के परिणामों से अपेक्षित होता है।

1.6 अंतर-संबद्धता- नेटवर्क विश्लेषण

मैट्रिक्स अल्जेब्रा नेटवर्क विश्लेषण के मूल में है, जिसमें वित्तीय क्षेत्र में संस्थाओं के बीच द्विपक्षीय एक्सपोज़रों का उपयोग किया जाता है। वित्तीय प्रणाली में एक संस्था की सभी अन्य संस्थाओं को दिए गए उधारों अथवा लिए गए उधारों को स्कवायर मैट्रिक्स में रखा जाता है और फिर उन्हें एक नेटवर्क ग्राफ में मैप किया जाता है। प्रणाली में अतंर-संबंद्धता के स्तर को जानने के लिए नेटवर्क मॉडल में विभिन्न सांख्यिकीय मापों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण तरीके निम्नलिखित हैं :-

i) *संबद्धता अनुपात* : यह सांख्यिकी एक पूर्ण ग्राफ में सभी संभव श्रृंखलाओं से संबंधित नोड्स के बीच संबद्धताओं की सीमा को मापती है। एक निर्देशित ग्राफ में $K = \sum_{i=1}^{N} k_i$ के बराबर (आउट डिग्री) की कुल संख्या दर्शाती है और N नोड्स की कुल संख्या के रूप में है, संबद्धता अनुपात $\frac{K}{N(N-1)}$ के रूप में दी गई है।

ii) *क्लस्टर गुणांक* : नेटवर्क में क्लस्टरिंग यह माप करती है कि प्रत्येक नोड आपस में किस प्रकार अंतर-संबद्ध है। विशेष रूप से, इस बात की प्रबल संभावना होती है कि किसी नोड के दो पड़ोसी (वित्तीय नेटवर्क के मामले में बैंक के प्रतिपक्षी) आपस में भी पड़ोसी होंगे। किसी नेटवर्क के लिए उच्च क्लस्टरिंग गुणांक का अर्थ यह होता है कि प्रणाली में उच्च स्थानिक अंतर-संबद्धता मौजूद है। k_i पड़ोसी वाले प्रत्येक बैंक के लिए उनके बीच के सभी प्रकार के संभावित संबद्धताओं की कुल संख्या k_i (k_i-1) द्वारा दर्शाई जाती है। मान लेते हैं कि E_i एजेंट i बैंक के k_i पड़ोसीयों के बीच संबद्धताओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। i बैंक के लिए क्लस्टरिंग गुणांक C_i को इस सर्वसमिका (आइडेंटिटी) द्वारा व्यक्त गया है:-

$$C_i = \frac{E_i}{k_i(k_i - 1)}$$

समग्र रूप में नेटवर्क का क्लस्टरिंग गुणांक (C) सभी C_i का औसत निम्नलिखित है:-

$$C = \frac{\sum_{i=1}^{N} C_i}{N}$$

iii) *स्तरीय नेटवर्क संरचनाएं* : सामान्यतः वित्तीय नेटवर्कों में स्तरीय संरचना की प्रवृत्ति देखी जाती है। स्तरीय संरचना वह है जिसमें विभिन्न संस्थाओं की नेटवर्क में अन्य के साथ विविध अंशों पर या स्तरों पर संबद्धता होती है। मौजूदा विश्लेषण में सर्वाधिक संबद्ध बैंक सबसे भीतरी केंद्र (कोर) में होते हैं। इसके बाद बैंकों को मध्य-केंद्र, बाहरी केंद्र और परिधि में (चित्र में केंद्र के आस-पास संबंधित संकेंद्रिक वृत्तों में) उनकी सापेक्ष संबद्धता के आधार पर रखा जाता है। बैंकों की संबद्धता की रेंज को प्रत्येक बैंक के इन-डिग्री तथा आउट-डिग्री अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे सर्वाधिक संबद्ध

बैंक के अनुपात से विभाजित किया जाता है। इस अनुपात के शीर्ष 10 प्रतिशत (परसेंटाइल) वाले बैंक भीतरी केंद्र में आते हैं। 90 और 70 प्रतिशत (परसेंटाइल) के बीच आने वाले बैंक मध्य-केंद्र में आते हैं और एक तीसरा स्तर 40 और 70 प्रतिशत (परसेंटाइल) के बीच वाले बैंकों का होता है। 40 प्रतिशत से कम संबद्धता अनुपात वाले बैंकों को परिधि के रूप में श्रेणीकृत/वर्गीकृत किया जाता है।

iv) *नेटवर्क चार्ट में रंग संकेत-:* नेटवर्क चार्ट में नीली और लाल गेंदें क्रमश: निवल उधारदाता और निवल उधारकर्ता को दर्शाती हैं। स्तरीय नेटवर्क चित्र में संबद्धताओं के रंग संकेत नेटवर्क में मौजूद विभिन्न स्तरों से ली गई उधारियों को निरूपित करती हैं (उदाहरण के लिए हरे रंग की कड़ियां भीतरी केंद्र (इनर कोर) बैंकों से ली गई उधारियों को दर्शाती हैं)।

(ए) ऋण-शोधन क्षमता संक्रामक प्रभाव का विश्लेषण

संक्रामक प्रभाव विश्लेषण दबाव परीक्षण स्वरूप का होता है जिसमें एक या अधिक बैंकों के असफल हो जाने के कारण उत्पन्न प्रभावों के चलते आगे चलकर बैंकिंग प्रणाली को होने वाली सकल हानि का पता लगाया जाता है। अनुरूपता संक्रामकता के लिए हम चरण-दर-चरण या अनुक्रमिक (सीक्वेंशियल) अल्गोरथिम का उपयोग करते हैं जिसे अब फरफाइन (2003) से जाना जाता है। यदि एक ट्रिगर बैंक i से प्रारंभ करें जो 0 समय पर असफल होता है तो प्रत्येक चक्र या पुनरावृति में जो बैंक दबाव में आते हैं उन्हें Dq, q = 1,2, … के रूप में दिखाया जा सकता है। इस विश्लेषण के लिए, किसी बैंक को दबावग्रस्त तब माना जाता है जब इसका टियर-I पूंजी अनुपात 7 प्रतिशत से नीचे चला जाए। प्राप्तकर्ता बैंक के लिए निवल प्राप्य को घाटे के रूप में माना गया है।

(बी) चलनिधि संक्रामक प्रभाव विश्लेषण

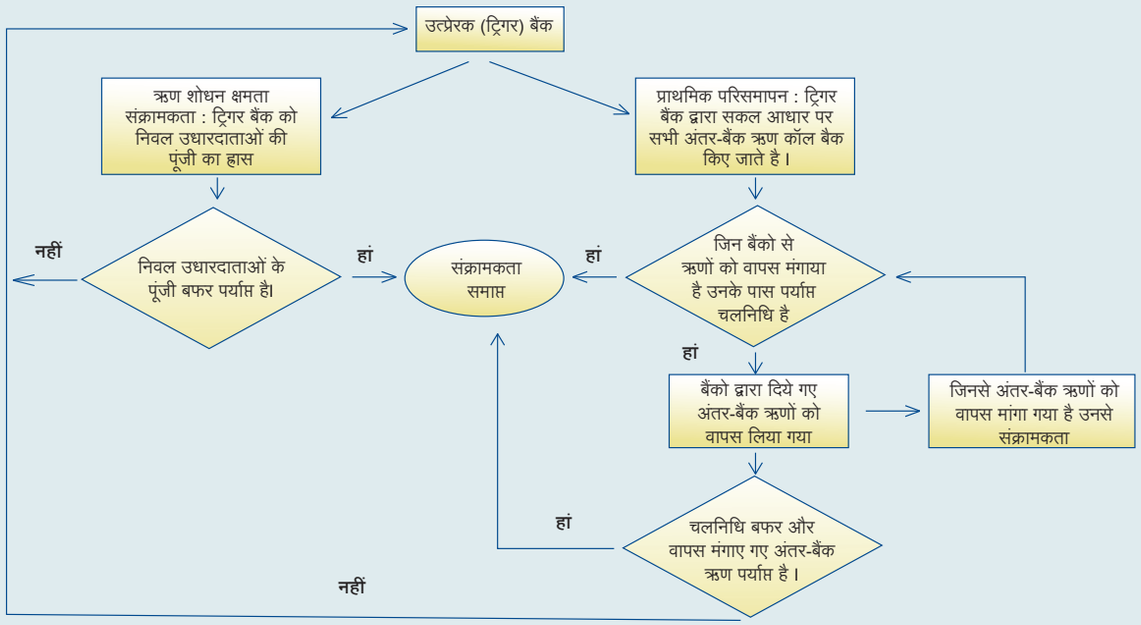
जहां ऋण शोधन क्षमता संक्रामक प्रभाव विश्लेषण किसी निवल उधारकर्ता के विफल हो जाने की स्थिति में प्रणाली को होने वाली संभावित हानि का आकलन करता है वहीं चलनिधि संक्रामक प्रभाव विश्लेषण किसी निवल उधारदाता के विफल हो जाने की स्थिति में इस प्रणाली को होने वाली संभावित हानि का अनुमान लगाता है। यह विश्लेषण बैंकों के बीच होने वाले सकल एक्सपोज़र के संबंध में किया जाता है जिसमें निधि आधारित और डेरिवेटिव दोनों शामिल होते हैं। इस विश्लेषण में मूलभूत मान्यता यह है कि किसी बड़े निवल उधारदाता के विफल होने की स्थिति से उत्पन्न होने वाले चलनिधि दबाव से निपटने के लिए बैंक पहले आरक्षित चलनिधि या बफर का उपयोग करेगा। आरक्षित चलनिधि के तहत विचारणीय मदें इस प्रकार हैं : (क) अतिरिक्त सीआरआर शेष (ख) अतिरिक्त एसएलआर बैलेंस और (ग) एनडीटीएल का 18 प्रतिशत। यदि कोई बैंक केवल चलनिधि बफर की मदद से ही दबाव से निपटने में सक्षम होता है तो ऐसी स्थिति में इसमें आगे कोई और संक्रामकता नहीं होती है।

तथापि, यदि केवल चलनिधि बफर पर्याप्त नहीं होते हैं तो बैंक को उन सभी ऋणों की मांग करेगा जो प्रतिदेय (कॉलेबल) हैं, जिसके चलते संक्रमण होगा। विश्लेषण के लिए केवल अल्पावधि की आस्तियां जैसे कि कॉल मार्केट में उधार दी गई राशि और अन्य बहुत ही अल्पावधि के लिए दिए गए ऋणों को ही प्रतिदेय (कॉलेबल) के रूप में लिया गया है। इसके पश्चात किसी बैंक का अस्तित्व या तो बचा रह सकता है अथवा उसका परिसमापन किया जाना होगा। इस मामले में इस प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं कि जहां ऋणों की मांग (कॉल) करने से बैंक बच जाए परंतु इसके परिणामस्वरूप आगे और संक्रमण हो सकता है जिससे अन्य बैंक दबाव में आ जाए । यहाँ प्रयुक्त दूसरा अनुमान यह है कि जब किसी बैंक का परिसमापन किया जाता है तो उस बैंक द्वारा उधार दिए गए ऋणों को सकल गणना के आधार पर कॉल किया जाता है, जबकि परिसमापन के बिना ही जब बैंक अल्पावधि ऋणों को कॉल करता है तो ऋण को निवल आधार पर वापस मांगा जाता है (इस अनुमान पर कि, प्रतिपक्षी अपने उसी प्रतिपक्षी के प्रति पहले अपनी अल्पावधि देयताओं को कम करना चाहेगा। इसे द्वितीयक परिसमापन के रूप में जाना जाता है)।

(सी) संयुक्त ऋणशोधन-चलनिधि संक्रामक प्रभाव का विश्लेषण

समान्यतः ऋण देने में किसी बैंक की कुछ बैंकों के प्रति सकारात्मक निवल स्थितियां और कुछ अन्य बैंकों के प्रति ऋणात्मक निवल स्थितियां दोनों ही होती हैं। इस प्रकार ऐसे किसी बैंक के विफल हो जाने पर ऋणशोधन तथा चलनिधि संक्रामकता दोनों साथ-साथ उत्पन्न हो जाएंगी। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित फ्लोचार्ट द्वारा बताया गया है:

किसी बैंक के दबाव में आने के कारण संयुक्त ऋणशोधन-चलनिधि संक्रामक प्रभाव संबंधी फ्लोचार्ट



यह माना गया है कि उत्प्रेरक (ट्रिगर) बैंक कुछ अंतर्जात कारण से विफल हुआ अर्थात यह दिवालिया हो गया है और इस प्रकार सभी उधारदाता बैंकों को प्रभावित करता है। साथ ही, यह अपनी आस्तियों का परिसमापन प्रारंभ करता है ताकि जहां तक संभव हो यह अपने दायित्वों को पूरा कर सके। परिसमापन की यह प्रक्रिया एक चलनिधि संक्रमण उत्पन्न करती है क्योंकि उत्प्रेरक (ट्रिगर) बैंक अपने दिए गए ऋणों को कॉल बैक करना प्रारंभ कर देता है।

चूंकि इक्विटी और लंबी अवधि के ऋण विफल संस्थाओं के प्रतिपक्षकारों के लिए चलनिधि जावक के रूप में घटित नहीं हो सकते हैं, इसलिए उन्हें प्राथमिक परिसमापन के मामले में प्रतिदेय (कॉलेबल) नहीं माना जाता है। साथ ही, जैसा कि 30 मार्च 2021 का आरबीआई का दिशानिर्देश प्रतिपक्ष स्तर पर डेरिवेटिव के मामले में एमटीएम मूल्यों के द्विपक्षीय नेटिंग की अनुमति देता है, प्राथमिक परिसमापन के मामले में डेरिवेटिव बाजारों से संबंधित एक्सपोजर को निवल आधार पर प्रतिदेय (कॉलेबल) माना जाता है।

उधारदाता/उधारकर्ता बैंक जो कि भली प्रकार पूँजीकृत होते हैं, वे आघात सहन कर लेते हैं और वे दूसरों को संक्रमित नहीं करते हैं। दूसरी तरफ, वे उधारदाता बैंक जिनकी पूंजी एक सीमा से कम हो जाती है उनसे एक नया संक्रमण प्रारंभ हो जाता हैं। इसी प्रकार ऐसे उधारकर्ता जिनकी चलनिधि बफर पर्याप्त है वे आगे कोई संक्रामकता फैलाए बिना दबाव सहन कर लेंगे। परंतु कुछ बैंक ऐसे हो सकते हैं जो चलनिधि दबाव का सामना करने में तभी सक्षम हों जब वो अपनी अल्पावधि आस्तियों को कॉल कर लेते हैं। अल्पावधि आस्तियों को वापस लेने की प्रक्रिया पुनः एक संक्रमण का प्रसार करेगा ।

ऋण-शोधन क्षमता और चलनिधि दोनों कारणों से उत्पन्न संक्रामकता तभी रुक पाएगी/स्थिर हो पाएगी जब, प्रणाली हानि/आघातों को आगे बिना विफलताओं के पूर्णतः अवशोषित कर सके ।

(डी) प्रभावशाली और संवेदनशील बैंकों की पहचान

वित्तीय प्रणाली की संस्थाओं के बीच द्विपक्षीय जोखिमों पर डेटा का उपयोग प्रभाव और संवेदनशीलता मैट्रिक की गणना के लिए किया जाता है ताकि उन संस्थाओं की पहचान की जा सके जो प्रभावशाली (अपने डिफ़ॉल्ट के कारण प्रणाली में दूसरों को बड़ी पूंजी हानि पहुँचा रही हैं) और संवेदनशील (अन्य संस्थाओं की असफलताओं पर अपनी स्वयं की पूंजी हानि की संवेदनशीलता) हैं, इसके लिए निम्नलिखित मैट्रिक और पद्धति का उपयोग किया जाता है (आईएमएफ, 2017):-

(i) किसी बैंक की संक्रामकता (प्रभाव) उस बैंक की विफलता के कारण अन्य बैंकों की होने वाली औसत हानि (उनकी टियर 1 पूंजी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त) का प्रतिनिधित्व करता है। बैंक i हेतु इसकी गणना इस प्रकार की जाती है:-

$$100 * \left(\sum_{j \neq i} L_{ji} / K_j \right) / (N-1)$$

जहाँ K_j बैंक $j's$ की पूंजी है , बैंक j के डिफ़ाल्ट के कारण L_{ji} बैंक की हानि है और N बैंक की कुल संख्या है।

(ii) बैंक की संवेदनशीलता का सूचकांक उस औसत हानि को दर्शाता है जो बैंक को सभी अन्य बैंकों के व्यक्तिगत रूप से उत्पन्न होने वाली विफलताओं के कारण हुई है (जो उसके टियर 1 पूंजी का प्रतिशत के रूप में व्यक्त है)। इसकी बैंक i के लिए इस प्रकार गणना की जाती है,

$$100 * \left(\sum_{j \neq i} L_{ij} / K_i \right) / (N-1)$$

जहाँ K_j बैंक i' की पूंजी है, बैंक j' के डिफ़ाल्ट के कारण L_{ji} बैंक की हानि है और N बैंक की कुल संख्या है।

(iii) ऋण आघात के प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए, यह अभ्यास प्रत्येक बैंक के लिए 100 प्रतिशत हानि- डिफ़ॉल्ट अनुरूपित करता है, जहां प्रतिपक्षकार की पूंजी हानि अवशोषित करता है। यदि किसी बैंक का टियर 1 पूंजी अनुपात 7 प्रतिशत से नीचे चला जाता है, तो उसे विफल माना जाता है। अगले चरणों में, यदि और असफलताएँ होती हैं, तो हानियों का समुच्चय बनता है।

गणना किए गए सूचकांकों के परिणामों का विश्लेषण किया जा सकता है ताकि उन संस्थाओं की पहचान की जा सके जो शीर्ष अत्यधिक प्रभावशाली बैंकों के समूह और शीर्ष अत्यधिक सुभेद्य बैंकों के समूह के बीच उभयनिष्ठ हैं।

1.7 वित्तीय प्रणाली दबाव संकेतक (एफएसएसआई)

एफएसएसआई को पांच वित्तीय बाज़ार खंडों (इक्विटी, विदेशी मुद्रा, मुद्रा, सरकारी ऋण और कॉर्पोरेट ऋण), तीन वित्तीय मध्यस्थ खंडों (बैंक, एनबीएफसी और एएमसी-एमएफ) के साथ-साथ वास्तविक क्षेत्र (सारणी 5) में फैले जोखिम कारकों का उपयोग करके संकलित किया गया है। एफएसएसआई शून्य और एक के बीच होता है, जिसमें उच्च मूल्य अधिक दबाव का संकेत देता है। इसके निर्माण के लिए, प्रत्येक घटक खंड से संबंधित जोखिम कारकों को पहले न्यूनतम-अधिकतम विधि का उपयोग करके सामान्यीकृत किया जाता है और उसके बाद i^{th} बाज़ार/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले उप-संकेतक 'y_i' में साधारण औसत के आधार पर एकत्र किया जाता है। अंत में, समग्र एफएसएसआई इस प्रकार प्राप्त किया जाता है,

$$FSSI_t = \sum_{i=1}^{9} w_i y_{it}$$

जहां प्रत्येक उप-संकेतक 'y_i' का वजन 'w_i' उसके नमूना मानक विचलन 's_i' से निर्धारित होता है, जैसे,

$$w_i = \frac{1/s_i}{\sum_{i=1}^{9}(1/s_i)}$$

सारणी 5 : एफएसएसआई के प्रत्येक घटक को गठित करने वाले जोखिम कारक

इक्विटी बाज़ार	1. निफ्टी 50 मासिक प्रतिलाभ और दो वर्ष की रोलिंग विंडो में इसके अधिकतम के बीच अंतर 2. निफ्टी 50 बाज़ार पूंजीकरण तथा जीडीपी का अनुपात 3. एनएसई-VIX सूचकांक 4. निवल इक्विटी एफपीआई प्रवाह	
सरकारी ऋण बाज़ार	5. 10-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल में दर्ज अस्थिरता 6. टर्म स्प्रेड:- 10 वर्ष की जी-सेक प्रतिफल और 3 माह की टी-बिल दर के बीच स्प्रेड 7. दो वर्ष की रोलिंग विंडो में न्यूनतम की तुलना में 10 वर्ष की जी-सेक प्रतिफल में वृद्धि 8. निवल ऋण एफपीआई प्रवाह	
विदेशी मुद्रा बाजार	9. दो वर्ष की रोलिंग विंडो में रुपया-डॉलर विनिमय दर और इसकी अधिकतम दर के बीच अंतर। 10. माह-दर-माह, डॉलर विनिमय दर की मूल्य वृद्धि/मूल्यह्रास 11. जीएआरसीएच (1,1) रुपया डॉलर विनिमय दर की अस्थिरता 12. 3 माह के फॉरवर्ड प्रीमिया और इसके ऐतिहासिक अधिकतम के बीच अंतर	
मुद्रा/अल्पावधि बाजार	13. भारित औसत मांग दर और भारित औसत बाज़ार रिपो दर के बीच स्प्रेड 14. 3 माह की सीडी दर और 3 माह की टी-बिल दर के बीच स्प्रेड 15. 3 माह की गैर-एनबीएफसी सीपी दर और 3 माह की टी-बिल दर के बीच स्प्रेड 16. 3 माह की सीपी दर की दर्ज की गई अस्थिरता 17. 3 माह की ओआईएस दर और 3 माह की टी-बिल दर के बीच स्प्रेड	
कॉर्पोरेट बॉन्ड बाज़ार	18. 3-वर्षीय एएए कॉरपोरेट बॉण्ड और 3-वर्षीय जी-सेक के बीच प्रतिफल का स्प्रेड 19. 3-वर्षीय बीबीबी और 3-वर्षीय एएए कॉर्पोरेट बॉण्ड प्रतिफल के बीच अंतर 20. 3-वर्षीय बीबीबी कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफल और इसकी अधिकतम के बीच अंतर	
बैंकिंग क्षेत्र	एससीबी	21. सीआरएआर (एससीबी) 22. आरओए (एससीबी) 23. एलसीआर (एससीबी) 24. लागत-पर-आय (एससीबी) 25. दबावग्रस्त आस्ति अनुपात (एससीबी) 26. बैंकिंग बीटा: सीओवी(आर,एम)/वेर(एम), 2 वर्ष की मूविंग विंडो पर। r= बैंक निफ्टी वर्ष-दर-वर्ष, m= निफ्टी 50 वर्ष-दर-वर्ष
	यूसीबी	27. जीएनपीए अनुपात (यूसीबी) 28. सीआरएआर (यूसीबी) 29. आरओए (यूसीबी)
एनबीएफसी क्षेत्र	30. जीएनपीए अनुपात 31. सीआरएआर 32. आरओए 33. 3 माह की एनबीएफसी सीपी दर और 3 माह की टी-बिल दर का स्प्रेड	
एएमसी-एमएफ क्षेत्र	34. म्यूचुअल फंड मोचन (रीडेंपशन): वर्ष-दर-वर्ष 35. म्यूचुअल फंड निवल प्रवाह	

अनुबंध 2

महत्वपूर्ण घरेलू विनियामकीय उपाय

I. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)

दिनांक	विनियम	औचित्य
14 जनवरी 2026	**भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक - आंतरिक ओम्बड्समैन) निदेश, 2026:** रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों में आंतरिक ओम्बड्समैन तंत्र की स्थापना संबंधी निदेश जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य आंतरिक शिकायत निवारण ढांचे को मजबूत करना है। निदेशों में आंतरिक ओम्बड्समैन की पात्रता मानदंड, नियुक्ति प्रक्रिया, कार्यकाल और कार्यात्मक दायरे के साथ-साथ जांच की जाने वाली शिकायतों की श्रेणियों का भी उल्लेख किया गया है। प्रमुख उपायों में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि बैंक द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से खारिज की गई शिकायतों की समीक्षा, ग्राहक को अंतिम निर्णय के संचार से पहले, आंतरिक ओम्बड्समैन द्वारा की जाए, जिससे आरबीआई ओम्बड्समैन के पास मामला जाने से पूर्व बैंक के अंदर ही एक अतिरिक्त स्वतंत्र समीक्षा का स्तर प्रदान किया जाए।	बैंक के भीतर आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने और ग्राहक शिकायतों के खारिज होने से पहले बैंक के भीतर एक शीर्ष स्तर के प्राधिकरण द्वारा समीक्षा को सक्षम करके त्वरित और सार्थक समाधान सुनिश्चित करने हेतु।
19 जनवरी 2026	**भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार – लक्ष्य और वर्गीकरण) (संशोधन) निदेश, 2026:** प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी मास्टर निदेश, 2025 में संशोधन किए गए, जिसमें एसएफबी के लिए समग्र पीएसएल लक्ष्य को 75 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत किया गया और पीएसएल ढांचे के आगे-उधार (ऑन-लेंडिंग) प्रावधानों के अंतर्गत एक पात्र इकाई के रूप में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को शामिल किया गया है।	अलग से अधिसूचित किए गए कुछ विनियामक परिवर्तनों के साथ संरेखण, कुछ विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन पीएसएल ढांचे के ऑन-लेंडिंग प्रावधानों के तहत एक पात्र इकाई के रूप में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) को शामिल करने, तथा कुछ मौजूदा प्रावधानों पर स्पष्टीकरण प्रदान करने के अलावा कुछ मौजूदा अनुदेशों से संबंधित संदर्भों को अद्यतन करने हेतु।

16 फरवरी 2026	**विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना तथा उधार देना) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2026:** रिज़र्व बैंक ने सीमापारीय उधार लेने और उधार देने संबंधी लेनदेन को नियंत्रित करने वाले ढांचे को और उदार बनाने तथा सुव्यवस्थित करने हेतु विदेशी मुद्रा प्रबंध (उधार लेना तथा उधार देना) विनियमावली में संशोधन किया है। संशोधन में पात्र उधारकर्ताओं, मान्यता प्राप्त ऋणदाताओं, अनुमत अंतिम उपयोगों और लागू सीमाओं से संबंधित मौजूदा प्रावधानों में संशोधन किए गए हैं, ताकि विनियामक ढांचे को उभरती कारोबारी अपेक्षाओं के साथ संरेखित किया जा सके और निवासी संस्थाओं के लिए कारोबार करने में अधिक आसानी हो सके।	पात्र उधारकर्ता और मान्यता प्राप्त ऋणदाता आधार के विस्तार, उधार सीमा और औसत परिपक्वता अवधि पर प्रतिबंधों के युक्तिकरण, ईसीबी के लिए उधार की लागत पर प्रतिबंधों को हटाने, अंतिम उपयोग प्रतिबंधों की समीक्षा और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के सरलीकरण द्वारा ईसीबी ढांचे को युक्तिसंगत बनाने हेतु।
31 मार्च 2026	**भारतीय रिज़र्व बैंक (व्यापार राहत उपाय) निदेश, 2026:** रिज़र्व बैंक ने व्यापार संबंधी दायित्वों में दबाव का सामना कर रहे निर्यातकों की सहायता के उद्देश्य से निदेश जारी किए।	पश्चिम एशियाई संकट के कारण व्यापार में आई बाधा को कम करने हेतु।
09 अप्रैल 2026	**आवक सीमा-पार भुगतानों को तेज और सुगम बनाने के लिए दिशानिर्देश:** रिज़र्व बैंक ने विदेशों से धन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के अनुभव में सुधार और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में आवक सीमा-पार भुगतानों के प्रसंस्करण में तेजी लाने के उद्देश्य से दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश, लाभार्थी के खाते में क्रेडिट होने में लगने वाले समय को कम करने के उद्देश्य से, प्रतिनिधि बैंकों, प्राधिकृत व्यापारी बैंकों और भुगतान प्रणाली संचालकों से जुड़ी पूरी (एंड-टू-एंड) भुगतान श्रृंखला का समाधान करते हैं।	जी20 के सीमा-पार भुगतान रोडमैप, जिसमें सस्ता, तेज़, अधिक पारदर्शी और अधिक सुलभ सीमा-पार भुगतान प्राप्त करने संबंधी लक्ष्य निर्धारित किए हैं, से संरेखित होते हुए सीमा-पार भुगतान में दक्षता लाने हेतु।

06 मई 2026	**विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राधिकृत व्यक्ति) विनियमावली, 2026:** रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के तहत प्राधिकृत व्यक्तियों के संबंध में संशोधित विनियम जारी किए, जो विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए प्राधिकृत संस्थाओं हेतु मौजूदा ढांचे को समेकित और अद्यतन करते हैं। ये विनियम सीमा-पार लेनदेन का प्रबंधन करने वाले प्राधिकृत व्यापारियों, मुद्रा परिवर्तकों और भुगतान समेककों (एग्रीगेटर्स) सहित प्राधिकृत व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों के लिए पात्रता मानदंड, प्राधिकरण की श्रेणियां और अनुमत गतिविधियों के दायरे को निर्धारित करते हैं।	प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए प्राधिकरण और नवीनीकरण ढांचे को युक्तिसंगत बनाने तथा उचित जांच और संतुलन बनाए रखते हुए विदेशी मुद्रा सुविधा की डिलिवरी के लिए प्रिंसिपल-एजेंट मॉडल का विस्तार करने हेतु।
08 मई 2026	**बैंकों के जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) की गणना हेतु सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) पूंजी में तिमाही लाभ के समावेशन से संबंधित दिशानिर्देशों की समीक्षा:** रिज़र्व बैंक ने बैंकों के जोखिम भारित आस्ति की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) की गणना के उद्देश्य हेतु सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी 1) पूंजी में तिमाही लाभ के समावेशन से संबंधित दिशानिर्देशों की समीक्षा की। सीआरएआर की गणना में तिमाही लाभ का अनुमान लगाने के लिए अब तक लागू एनपीए के संबंध में वृद्धिशील प्रावधानों की अर्हता संबंधी शर्त को हटाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, विनियामक पूंजी में तिमाही लाभ को शामिल करने से पहले, अब तिमाही वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा या सीमित समीक्षा भी आवश्यक है।	संशोधन का उद्देश्य विनियमित संस्थाओं में दिशानिर्देशों को सुसंगत बनाने और वैश्विक मानकों के साथ ढांचे को संरेखित करना है। यह बैंक की पूंजी स्थिति का सत्यापन योग्य और समय पर जानकारी सुनिश्चित करता है।

II. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)

दिनांक	विनियम	औचित्य
09 जनवरी 2026	**निवेशकों को आधिकारिक मान्यता प्रदान करने संबंधी आवश्यकताओं का सरलीकरण।**	निवेशक की गोपनीयता संबंधी चिंताओं को दूर करने और आधिकारिक मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु।

14 जनवरी 2026	**भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 की व्यापक समीक्षा तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनियम, 2026 की अधिसूचना**	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने विकसित होती बाजार प्रथाओं, प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग तथा निवेशकों के हितों की रक्षा की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए म्यूचुअल फंडों से संबंधित विनियामक ढाँचे की व्यापक समीक्षा की है।
21 जनवरी 2026	**ऋण निर्गमकर्ताओं को सार्वजनिक निर्गमों में निवेशकों की कुछ श्रेणियों को प्रोत्साहन देने की अनुमति – भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीकरण) विनियम, 2021 ("एनसीएस विनियम") में संशोधन:** ऋण निर्गमकर्ताओं को सार्वजनिक निर्गमों में निवेशकों की कुछ श्रेणियों, जैसे वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, सेवारत एवं सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों, रक्षा कर्मियों की विधवाओं एवं विधुरों, खुदरा व्यक्तिगत निवेशकों अथवा सेबी द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किसी अन्य निवेशक श्रेणी को अतिरिक्त ब्याज अथवा निर्गम मूल्य पर छूट के रूप में प्रोत्साहन देने की अनुमति दी गई है। उक्त प्रोत्साहन केवल मूल आवंटियों तक सीमित रहेगा तथा आवंटन के उपरांत ऋण प्रतिभूतियों के अंतरण की स्थिति में यह प्रोत्साहन लागू नहीं होगा।	ऋण प्रतिभूतियों में निवेशकों की कुछ श्रेणियों की भागीदारी को बढ़ावा देना जिससे कॉर्पोरेट ऋण बाजार में सार्वजनिक निर्गमों की संख्या को बढ़ावा मिले।
06 फरवरी 2026	**डिपॉजिटरी को वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ़) की इकाइयों के मूल्य की सूचना उपलब्ध कराना**	एआईएफ क्षेत्र में निवेशकों के हित में पारदर्शिता तथा परिचालन दक्षता को सुदृढ़ करने हेतु डिपॉजिटरी अवसंरचना का लाभ लेना।

11 फरवरी 2026	**बाजार अवसंरचना संस्थानों (एमआईआई) के पण्य डेरिवेटिव खंड हेतु क्षमता आयोजना एवं वास्तविक समय निष्पादन निगरानी रूपरेखा:** पण्य डेरिवेटिव खंड वाले स्टॉक एक्सचेंजों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर सेबी द्वारा इस खंड के लिए क्षमता आयोजना संबंधी रूपरेखा की समीक्षा की गई है। तदनुसार, सेबी ने बाजार अवसंरचना संस्थानों (एमआईआई) के पण्य डेरिवेटिव खंड में महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी प्रणालियों तथा उनसे संबद्ध सहायक अवयवों के लिए क्षमता आयोजना एवं निष्पादन की तत्काल निगरानी संबंधी एक रूपरेखा निर्धारित की है। उक्त रूपरेखा के अंतर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐतिहासिक उपयोग, अधिकतम भार वहन क्षमता तथा अनुमानित व्यावसायिक संवृद्धि के आधार पर अग्रसक्रिय क्षमता आयोजना दृष्टिकोण अपनाना, समय-समय पर तनाव परीक्षण करना तथा थ्रूपुट एवं विलंबता जैसे प्रणाली निष्पादन मानकों की वास्तविक समय में निगरानी अधिदेशित है, ताकि प्रणाली की आघातसहनीयता तथा निर्बाध बाजार परिचालन सुनिश्चित किया जा सके।	एमआईआई की क्षमता नियोजन का सुव्यवस्थीकरण तथा कमोडिटी डेरिवेटिव खंड के लिए वास्तविक समय निष्पादन निगरानी रूपरेखा तैयार करना

26 फरवरी 2026	**म्यूचुअल फंड योजनाओं द्वारा धारित भौतिक स्वर्ण एवं रजत का मूल्यांकन:** सेबी (म्यूचुअल फंड) विनियम, 2026 की सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट निवेश मूल्यांकन मानदंडों के अधीन, 01 अप्रैल 2026 से प्रभावी रूप से म्यूचुअल फंडों द्वारा धारित भौतिक स्वर्ण एवं रजत का मूल्यांकन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रकाशित समेकित स्पॉट कीमतों के आधार पर किया जाएगा। उक्त स्पॉट कीमतों का उपयोग भौतिक परिदान वाले स्वर्ण एवं रजत डेरिवेटिव्स संविदाओं के निपटान हेतु किया जाता है।	पूर्ववर्ती विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार, स्वर्ण एवं रजत एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ़) द्वारा धारित भौतिक स्वर्ण एवं रजत का मूल्यांकन लंदन बुलियन बाजार संघ के प्रातःकालीन निर्धारण मूल्यों के आधार पर किया जाता था। अंतिम मूल्यांकन निर्धारित करने के लिए एलबीएमए मूल्यों में आवश्यक मात्रकीय एवं मुद्रा रूपांतरण, परिवहन व्यय, सीमा शुल्क, लागू करों एवं अन्य अधिरोपणों को समायोजित करने के साथ-साथ घरेलू मूल्यांकन प्राप्त करने हेतु सांकेतिक प्रीमियम अथवा छूट को भी सम्मिलित किया जाता था। सेबी की म्यूचुअल फंड सलाहकार समिति में हुई चर्चाओं, सार्वजनिक परामर्श तथा सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि म्यूचुअल फंड योजनाओं द्वारा धारित भौतिक स्वर्ण एवं रजत के मूल्यांकन हेतु मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रकाशित समेकित (Polled) स्पॉट मूल्यों का उपयोग किया जा सकता है। चूँकि स्टॉक एक्सचेंज विनियामक ढाँचे के अंतर्गत पारदर्शिता एवं अनुपालन संबंधी अपेक्षाओं के अधीन कार्य करते हैं, अतः ऐसे विनियमित संस्थाओं द्वारा प्रकाशित स्पॉट मूल्यों का उपयोग घरेलू बाजार परिस्थितियों के अनुरूप अधिक यथार्थपरक मूल्यांकन सुनिश्चित करेगा तथा मूल्यांकन पद्धतियों में एकरूपता स्थापित करेगा।
26 फरवरी 2026	**म्यूचुअल फंड योजनाओं का वर्गीकरण एवं युक्तिसंगतीकरण**	संशोधित वर्गीकरण में महत्वपूर्ण विनियामक विकासों को सम्मिलित किया गया है तथा यह निवेशक-केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित है, जिसका उद्देश्य उत्पाद संरचना को सरल बनाना, योजनाओं की तुलनीयता में सुधार करना तथा पारदर्शिता को सुदृढ़ करना है।

04 मार्च 2026	**एआईएफ द्वारा विनियामक रिपोर्टिंग**	फंड प्रबंधकों पर अनुपालन संबंधी भार को युक्तिसंगत बनाने और साथ ही विनियामक पर्यवेक्षण के लिए एकत्रित किए जाने वाले आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से।
04 मार्च 2026	**अभिरक्षकों के लिए दिशानिर्देश**	अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाने तथा अभिरक्षकों के बीच जोखिम प्रबंधन एवं सुशासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से।
13 मार्च 2026	**प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 में न्यूनतम सार्वजनिक निर्गम तथा निर्गमकर्ताओं द्वारा न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता अनुपालन की समय-सीमा से संबंधित संशोधन, जिसका उद्देश्य सेबी की सिफ़ारिशों के आधार पर व्यापार सुगमता को बढ़ाना है।**	सेबी ने न्यूनतम सार्वजनिक निर्गम संबंधी आवश्यकताओं में आकार-आधारित छूट तथा निर्गमकर्ताओं द्वारा एमपीएस आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु समय-सीमा में रियायत प्रदान करने की अनुशंसा की।
16 मार्च 2026	**पण्य डेरिवेटिव खंड हेतु निपटान गारंटी निधि (एसजीएफ़) के कवरेज की समीक्षा:** सेबी द्वारा वस्तु डेरिवेटिव खंड के लिए एसजीएफ़ कवरेज आवश्यकताओं की समीक्षा की गई, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित संशोधन किए गए: 1) सभी समाशोधन सदस्यों की चूक के कारण उत्पन्न होने वाले 50 प्रतिशत क्रेडिट एक्सपोजर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। 2) समाशोधन निगम अब कम से कम तीन ऐसे समाशोधन सदस्यों (और उनके सहयोगियों) के एक साथ डिफॉल्ट के कारण उत्पन्न क्रेडिट एक्सपोजर की गणना करेंगे, जिनसे सर्वाधिक क्रेडिट एक्सपोजर उत्पन्न होता है।	यह उपाय जोखिम-आधारित दृष्टिकोण तथा इष्टतम विनियमन के माध्यम से कारोबार सुगमता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है।
April 07, 2026	**सेबी टिप्पणियों की वैधता के संबंध में एकबारगी रियायत** वर्तमान भू-राजनीतिक तनावों तथा निवेशकों की सीमित भागीदारी के कारण उत्पन्न अनिश्चित बाजार परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सेबी ने 01 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच समाप्त होने वाली सेबी टिप्पणियों संबंधी पत्रों की वैधता को एक बार के लिए 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।	इसका उद्देश्य भू-राजनीतिक तनावों, अनिश्चित बाजार परिस्थितियों तथा निवेशकों की कम भागीदारी से प्रभावित निर्गमकर्ताओं को एकबारगी राहत प्रदान करना है, जिससे वे विनियामक प्रक्रियाओं की पुनरावृत्ति से बच सकें तथा पूंजी बाजार तक अपनी पहुंच बनाए रख सकें।

15 अप्रैल 2026	**सोशल स्टॉक एक्सचेंज (एसएसई) पर गैर-लाभकारी संगठनों के पंजीकरण तथा शून्य कूपन शून्य मूलधन लिखतों के निर्गम हेतु न्यूनतम अभिदान आवश्यकता की समीक्षा**	इस उपाय का उद्देश्य एसएसई पर एनपीओ के पंजीकरण की वैधता अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष करना है, जो एसएसई के अनुमोदन के अधीन होगा। यह एनपीओ के समक्ष आने वाली चुनौतियों, जैसे आयकर अधिनियम अथवा अन्य वैधानिक अनुमोदनों के अंतर्गत पंजीकरण के नवीनीकरण में देरी, जिसके परिणामस्वरूप धन जुटाने की प्रक्रिया में विलंब होता है, को संबोधित करेगा।
16 अप्रैल 2026	**आईएनवीआईटी को रियायत अवधि के पश्चात एसपीवी को "अनुमत निवेश" के रूप में रखने की अनुमति**	यह उपाय आईएनवीआईटी को अपने समापन दायित्वों को विनियामक उल्लंघन के बिना पूरा करने में सक्षम बनाने तथा पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं के लिए एसपीवी के समापन संबंधी कार्यों में कारोबार सुगमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है।
16 अप्रैल 2026	**आरईआईटी और आईएनवीआईटी के लिए अनुमत तरल म्यूचुअल फंड निवेशों का विस्तार:** निवेश मानदंडों का विस्तार करते हुए ऐसे तरल म्यूचुअल फंड योजनाओं को शामिल किया गया है, जिनका क्रेडिट जोखिम मूल्य कम से कम 10 तथा संभावित जोखिम वर्ग कम से कम B-1 है।	इसका उद्देश्य आरईआईटी और आईएनवीआईटी को एए एवं उससे अधिक रेटिंग वाली ऋण प्रतिभूतियों के अतिरिक्त निवेश विकल्प उपलब्ध कराकर संकेंद्रण जोखिम को कम करना है, साथ ही निम्न से मध्यम क्रेडिट जोखिम बनाए रखना है।
16 अप्रैल 2026	**ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में निवेश के संबंध में निजी रूप से सूचीबद्ध आईएनवीआईटी के लिए निवेश शर्तों का सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध आईएनवीआईटी के साथ सामंजस्य** निजी रूप से सूचीबद्ध आईएनवीआईटी को अपनी आस्ति मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत तक ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है, जो सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध आईएनवीआईटी के लिए निर्धारित सीमा के अनुरूप है।	इसका उद्देश्य समान अवसर उपलब्ध कराना, निजी आईएनवीआईटी को अवसंरचना आस्तियों के प्रारंभिक चरण के विकास एवं वृद्धि में भाग लेने में सक्षम बनाना, दीर्घकालिक प्रतिफल की संभावनाओं को बढ़ाना तथा कारोबार सुगमता को प्रोत्साहित करना है।
16 अप्रैल 2026	**आईएनवीआईटी के लिए 49 प्रतिशत से अधिक लीवरेज होने की स्थिति में नए उधारों के अनुमत उपयोग के दायरे का विस्तार**	49 प्रतिशत से अधिक लीवरेज वाले आईएनवीआईटी द्वारा अतिरिक्त ऋण के उपयोग हेतु अनुमत उद्देश्यों का विस्तार किया गया है, जिससे आईएनवीआईटी के लिए कारोबार सुगमता को बढ़ावा मिलेगा।

18 अप्रैल 2026	**सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियम, 2012 ("एआईएफ़ विनियम") में संशोधन**	अन्य बातों के साथ-साथ, इन संशोधनों का उद्देश्य, सेबी (एआईएफ़) विनियमों में निर्धारित सोशल इम्पैक्ट फंड (एसआईएफ़) में व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा किए जाने वाले न्यूनतम निवेश मूल्य की आवश्यकता को सेबी (आईसीडीआर) विनियमों के अंतर्गत एसएसई पर जारी ज़ेडसीज़ेडपी लिखतों के लिए निर्धारित न्यूनतम आवेदन आकार की आवश्यकता के अनुरूप बनाना है। इस संशोधन का उद्देश्य एसआईएफ़ के माध्यम से एनपीओ की प्रतिभूतियों में निवेश करने के इच्छुक खुदरा निवेशकों/दाताओं की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
30 अप्रैल 2026	**सेबी के पास दाखिल एआईएफ़ के स्थानन ज्ञापन के प्रसंस्करण हेतु त्वरित प्रक्रिया**	मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए लार्ज वैल्यू फंड (अर्थात गैर-एलवीएफ़ योजनाओं) के अलावा एंजल फंडों और एआई एफ़ योजनाओं द्वारा पूंजी का कुशल परिनियोजन सुनिश्चित करना।

III. भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण

दिनांक	विनियमन	औचित्य
06 जनवरी 2026	**ट्राई के 1600 सीरीज़ को अनिवार्यत: अपनाने संबंधी निर्देश का कार्यान्वयन :** परिपत्र के माध्यम से सभी बीमाकर्ताओं एवं बीमा मध्यस्थों के लिए सभी सेवा एवं लेन-देन संबंधी वॉयस कॉलों हेतु 1600 सीरीज़ का अनिवार्य रूप से उपयोग करना निर्धारित किया गया है।	अनचाहा व्यावसायिक संचार (यूसीसी) पर नियंत्रण, प्रतिरूपण आधारित धोखाधड़ी की रोकथाम तथा उपभोक्ता विश्वास को सुदृढ़ करना।
28 जनवरी 2026	**पुनर्बीमा सलाहकार समिति (आरएसी) का पुनर्गठन:** बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101बी के प्रावधानों के अनुसार भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण ने पुनर्बीमा सलाहकार समिति (आरएसी) का अध्यक्ष एवं सदस्यों सहित तीन वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है।	प्रत्येक सामान्य बीमा पॉलिसी की बीमित राशि के उस प्रतिशत के संबंध में प्राधिकरण को अनुशंसा करना, जिसे भारतीय पुनर्बीमाकर्ता/ पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ अनिवार्य रूप से पुनर्बीमित किया जाना है।
11 फरवरी 2026	**भारत के बाहर पंजीकृत बीमा कंपनियों द्वारा भारत में संपर्क कार्यालय की स्थापना एवं बंद करने संबंधी दिशा-निर्देश:** आईआरडीएआई ने वर्ष 2022 के दिशा-निर्देशों के स्थान पर विदेशी बीमा कंपनियों के संपर्क कार्यालयों हेतु संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं।	संपर्क कार्यालय के लिए पात्रता मानदंड, अनुमत गतिविधियाँ, अनुमोदन की शर्तें, लेखा-पुस्तकों एवं अभिलेखों का रख-रखाव, वार्षिक गतिविधि प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना, कार्यालय बंद करने की प्रक्रिया तथा चूक अथवा अनुपालन न होने की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई का निर्धारण करना।

12 फरवरी 2026	**वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ़) में निवेश संबंधी प्रावधानों पर स्पष्टीकरण:** आईआरडीएआई ने बीमाकर्ताओं द्वारा वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ़) में निवेश संबंधी मानदंडों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। इससे आवश्यक सुरक्षा उपायों के साथ निवेश में भागीदारी संभव होगी तथा सेबी के छूट संबंधी परिपत्र को बीमा अधिनियम की धारा 27ई के अनुपालन प्रावधानों के साथ समन्वित किया जा सकेगा।	"Excuse Rights" युक्त एआईएफ़ में निवेश, Fund of Funds (एफ़ओएफ़) के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष निवेश सीमाओं के संबंध में स्पष्टता प्रदान करना तथा बीमाकर्ताओं के लिए एआईएफ़ में निवेश के अवसरों का विस्तार करना।
12 मार्च 2026	**बीमा सलाहकार समिति (आईएसी) का पुनर्गठन:** प्राधिकरण ने उद्योग के विभिन्न हितधारकों से सदस्यों को सम्मिलित करते हुए बीमा सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है।	बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 25 की उपधारा (1) तथा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमा सलाहकार समिति) विनियम, 2000 के विनियम 3ए के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईआरडीएआई ने बीमा सलाहकार समिति के पुनर्गठन संबंधी अधिसूचना जारी की है।
30 मार्च 2026	**आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के बीमांकिक, वित्त एवं निवेश कार्य) (संशोधन) विनियम, 2026:** संशोधन के अनुसार बीमाकर्ताओं को लागू भारतीय लेखा मानकों (Ind एएस) के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करना एवं प्रस्तुत करना अनिवार्य है।	यह संशोधन Ind एएस के अंतर्गत वित्तीय विवरणों की मान्यता, मापन, प्रस्तुतीकरण एवं प्रकटीकरण के लिए विनियामक ढाँचा निर्धारित करता है, जिससे वैश्विक मानकों के अनुरूप बीमा क्षेत्र में वित्तीय प्रतिवेदन की एकरूपता, पारदर्शिता एवं तुलनीयता को बढ़ावा दिया जा सके।
01 अप्रैल 2026	**Ind एएस पर संयुक्त विशेषज्ञ समूह (जेईजी) का गठन:** आदेश के तहत आईआरडीएआई ने आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के बीमांकित, वित्त और निवेश कार्य) (संशोधन) अधिनियम, 2026 के संशोधित विनियमों की अनुसूची IIA के भाग-I के खंड 6 के अंतर्गत संयुक्त विशेषज्ञ समूह (जेईजी) का गठन किया है।	बीमाकर्ताओं द्वारा भारतीय लेखा मानकों के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाले मुद्दों की जांच एवं समाधान करना।
02 अप्रैल 2026	**बीमा सलाहकार समिति की स्वास्थ्य बीमा उप-समिति का गठन:** भारत में निजी स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की समीक्षा हेतु स्वास्थ्य बीमा उप-समिति का गठन किया गया है।	स्वास्थ्य बीमा की कवरेज, पहुँच, दावा अनुभव, उत्पाद संरचना, शिकायत निवारण, उपभोक्ता अनुभव आदि की समीक्षा करना तथा नवाचार, व्यापक कवरेज, बेहतर जोखिम साझाकरण एवं वित्तीय सुरक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु विनियामक, नीतिगत एवं परिचालन संबंधी उपायों की अनुशंसा करना।

08 अप्रैल 2026	**आईआरडीएआई सूचना एवं साइबर सुरक्षा दिशा-निर्देश, 2026:** इन दिशा-निर्देशों में सभी विनियमित संस्थाओं द्वारा अपनाए जाने वाले न्यूनतम मानकों एवं शासन तंत्र का निर्धारण किया गया है।	उभरते साइबर खतरों का प्रभावी ढंग से सामना करने हेतु बीमा उद्योग को अपनी साइबर सुरक्षा एवं संबंधित शासन व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु सक्षम बनाना।
17 अप्रैल 2026	**वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु अनिवार्य पुनर्बीमा हस्तांतरण:** बीमा अधिनियम 1938 की धारा 101ए की उपधाराओं (2) एवं (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सलाहकार समिति से परामर्श के उपरांत अधिसूचना जारी की गई है।	प्रत्येक सामान्य बीमा पॉलिसी की बीमित राशि के उस प्रतिशत का निर्धारण करना जिसे भारतीय पुनर्बीमाकर्ता, अर्थात् जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (जीआईसी री), के साथ अनिवार्य रूप से पुनर्बीमित किया जाएगा।
21 अप्रैल 2026	**शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी राजपत्र अधिसूचना:** आईआरडीए अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 23(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34 के अंतर्गत शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी अधिसूचना जारी की गई है।	पहचाने गए उल्लंघनों से संबंधित प्रवर्तन कार्यवाहियों में किसी बीमाकर्ता अथवा बीमा मध्यस्थ को निर्देश जारी करने हेतु अध्यक्ष द्वारा गठित दो पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल को शक्तियों का प्रत्यायोजन करना तथा अन्य मामलों में बीमा अधिनियम 1938 की धारा 34 के अंतर्गत अध्यक्ष को निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करना।
25 मई 2026	**बीमाकर्ताओं के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर मास्टर परिपत्र, 2024 में संशोधन:** इस परिपत्र में बीमा कंपनियों के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) पर लागू निष्पादन मानकों में संशोधन निर्दिष्ट किए गए हैं।	ग्राहकों के विश्वास को सुदृढ़ करना, पारदर्शिता में वृद्धि करना तथा बीमा क्षेत्र में उत्तरदायित्व को और अधिक मजबूत बनाना। इन मानकों में वित्तीय सुदृढ़ता, उत्पादों का प्रदर्शन, दावों के निस्तारण की तत्परता, समयबद्ध शिकायत निवारण तथा बीमाकर्ताओं एवं उनके वितरकों की वेबसाइटों से "डार्क पैटर्न" हटाना शामिल है।

IV. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए)

तिथि	विनियमन	औचित्य
29 अक्तूबर 2025	**राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत प्लेटफ़ॉर्म सेवा भागीदार का समावेशन – "एनपीएस ई-श्रमिक (प्लेटफ़ॉर्म सेवा भागीदार) मॉडल"**	ऐप एग्रीगेटरों के माध्यम से प्लेटफ़ॉर्म श्रमिकों को एनपीएस के अंतर्गत सम्मिलित करना।

12 दिसंबर 2025	**पीएफ़आरडीए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास एवं प्रत्याहरण (संशोधन) संबंधी विनियम, 2025 (संशोधन):**	सामान्य निकास की स्थिति में गैर-सरकारी अभिदाताओं के लिए एकमुश्त आहरण की अनुमत सीमा को संचित पेंशन निधि के 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत करना तथा अनिवार्य वार्षिकीकरण की सीमा को 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत करना, जबकि सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए वर्तमान 60:40 का प्रावधान यथावत बनाए रखना।
06 मार्च 2026	**पेंशन निधियों के लिए निवेश प्रबंधन शुल्क (आईएमएफ़) एवं वार्षिक शुल्क:**	सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के बीच अंतर करना।
10 मार्च 2026	**एनपीएस की सामान्य योजनाओं (ऑल सिटिजन), जिसमें एनपीएस वात्सल्य एवं एनपीएस लाइट भी शामिल हैं, के लिए प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) की शुल्क संरचना**	प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) की शुल्क संरचना का युक्तिसंगतकरण करना तथा सभी पीओपी के लिए समान प्रतिस्पर्धी अवसर सुनिश्चित करना।
10 मार्च 2026	**एनपीएस के अंतर्गत विद्यमान कॉर्पोरेट प्रतिभागियों का सरकारी संस्थानों एवं विधिक संस्थानों (सरकारी संस्थानों से इतर) के रूप में पुनर्वर्गीकरण**	मौजूदा कॉर्पोरेट प्रतिभागियों का सरकारी संस्थानों तथा गैर-सरकारी विधिक संस्थाओं के रूप में पुनर्वर्गीकरण करना तथा सरकार के विस्तार के रूप में कार्यरत संस्थानों को सरकारी क्षेत्र के एनपीएस मॉडल में स्थानांतरित करना और साथ ही ऐसी संस्थानों की पूर्ववर्ती अधिवर्षिता निधियों की आस्तियों को एक वर्ष के भीतर विनियमित एनपीएस ढांचे में स्थानांतरित करना।
24 मार्च 2026	**मल्टीपल एनएवी व्यवस्था को लागू करना:**	सरकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के अभिदाताओं के लिए पृथक निवेश प्रबंधन शुल्क (आईएमएफ़) एवं पीओपी शुल्क संरचना को प्रभावी करने हेतु एक ही योजना के अंतर्गत एकाधिक एनएवी की व्यवस्था को 1 अप्रैल 2026 से लागू किया गया।

V. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई)

दिनांक	विनियम	औचित्य
02 जनवरी 2026	**परिसमापन प्रक्रिया विनियमों में संशोधन:** संशोधन के अनुसार परिसमापकों के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर परिसमापन प्रक्रिया से संबंधित प्रपत्रों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। संशोधित प्रपत्रों को सूचना की पुनरावृत्ति समाप्त करने तथा सूचना संबंधी आवश्यकताओं का युक्तिसंगतकरण करने के उद्देश्य से पुनः डिज़ाइन किया गया है।	अनुपालन संबंधी बोझ को उल्लेखनीय रूप से कम करना तथा यह सुनिश्चित करना कि बोर्ड को सभी आवश्यक सूचनाएँ समयबद्ध रूप से प्राप्त होती रहें।

25 फरवरी 2026	सीआईआरपी विनियमों में संशोधन: संशोधनों के अंतर्गत सूचना ज्ञापन (आईएम) में प्रकटीकरण संबंधी आवश्यकताओं को सुदृढ़ किया गया है। इसके अनुसार निम्नलिखित विवरणों को सम्मिलित करना अनिवार्य किया गया है—(i) सीडी की प्राप्य राशियाँ; (ii) संयुक्त विकास व्यवस्थाओं तथा अन्य समान सहयोगात्मक व्यवस्थाओं का विवरण; तथा (iii) प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कुर्क आस्तियों का विवरण। इसके अतिरिक्त, सूचना ज्ञापन (आईएम) में उन सभी आवंटियों का विवरण सम्मिलित करना अनिवार्य किया गया है- जैसे नाम, देय राशि एवं आवंटित इकाइयाँ जिनके दावे कॉर्पोरेट देनदार के लेखा अभिलेखों अथवा रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण के अभिलेखों में उपलब्ध हैं, किंतु जिन्होंने समाधान पेशेवर के समक्ष दावा प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा जहां सूचना ज्ञापन में ऐसे ब्योरे शामिल किए गए हैं, ऐसे मामलों में समाधान योजना में भी इन आवंटियों के हितों के निस्तारण का प्रावधान करना आवश्यक होगा।	प्रकटीकरण को सुदृढ़ कर सूचना विषमता को कम करना तथा सभी आवंटियों के साथ निष्पक्ष एवं समतामूलक व्यवहार सुनिश्चित करना।
30 मार्च 2026 / 01 अप्रैल 2026	**दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2026:** दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2026 को लोकसभा द्वारा 30 मार्च 2026 तथा राज्यसभा द्वारा 01 अप्रैल 2026 को पारित किया गया। इस अधिनियम को 06 अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। तत्पश्चात, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 22 मई 2026 की अधिसूचना के माध्यम से समूह दिवाला, सीमा-पार दिवाला, सीआईआईआरपी तथा दिवाला एवं शोधन अक्षमता निधि से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर अधिनियम के अन्य सभी प्रावधान 26 मई 2026 से प्रभावी किए गए।	विधायी सुधारों के माध्यम से दिवाला एवं शोधन अक्षमता ढाँचे को और अधिक सुदृढ़ बनाना।

13 मई 2026	आईबीबीआई (दिवाला पेशेवर एजेंसियों के मॉडल उपविधि एवं शासी बोर्ड) विनियमों में संशोधन: संशोधन, अन्य बातों के साथ-साथ, दिवाला पेशेवर अभिकरणों (आईपीए) के शासन ढाँचे को निम्नलिखित द्वारा सुदृढ़ करते हैं— (i) आईबीबीआई को किसी आईपीए के शासी बोर्ड पर एक नामित निदेशक नामित करने में सक्षम बनाकर, जिसे अन्य निदेशकों के समान अधिकार, शक्तियाँ, कर्तव्य और उत्तरदायित्व प्राप्त होंगे, (ii) स्वतंत्र निदेशकों की पुनर्नियुक्ति के लिए आईबीबीआई की पूर्व स्वीकृति अपेक्षित करके, (iii) यह उपबंध करके कि कोई स्वतंत्र निदेशक ऐसे किसी सांविधिक विनियामक का सदस्य नहीं होगा जिसने आईपीए को प्रायोजित या प्रवर्तित किया हो अथवा जो ऐसे आईपीए में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अंशधारिता रखता हो या उस पर नियंत्रण का प्रयोग करता हो, तथा वह किसी अन्य आईपीए में स्वतंत्र निदेशक का पद धारण नहीं करेगा, (iv) स्वतंत्र निदेशक की दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति को शासी बोर्ड द्वारा किए गए संतोषजनक कार्य-निष्पादन पुनर्विलोकन के अधीन बनाकर, तथा (v) आईपीए से यह अपेक्षा करके कि वे वर्तमान प्रबंध निदेशक के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व प्रबंध निदेशक की नियुक्ति के लिए पूर्व स्वीकृति हेतु आईबीबीआई को कम-से-कम दो नाम प्रस्तुत करेंगे।	दिवाला पेशेवर एजेंसियों के कार्य संचालन में सुशासन मानकों को सुदृढ़ करना तथा विनियामक पर्यवेक्षण को और अधिक प्रभावी बनाना।

02 जून 2026	**सूचना उपयोगिता विनियमों में संशोधन:** संशोधन अधिनियम में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी सूचना उपयोगिता (आईयू) में चूक अभिलेख (आरओडी) किसी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो वह न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के लिए चूक होने को स्थापित करने हेतु पर्याप्त होगा। तदनुसार, आईयू विनियमों में प्रयुक्त शब्दावली को संहिता के अनुरूप संशोधित करते हुए "भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित संदर्भ वित्तीय ऋणदाता" के स्थान पर "वित्तीय संस्था" शब्द का उपयोग किया गया है जैसा कि धारा 3(14) में भी परिभाषित है। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित परिस्थितियों में चूक अभिलेख (आरओडी) जारी करने का प्रावधान किया गया है— (i) जब देनदार चूक संबंधी सूचना की पुष्टि करता है; अथवा (ii) जब निर्धारित अनुस्मारकों के बावजूद देनदार कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं करता। साथ ही, विनियमों में संशोधन कर "विवाद संबंधी सूचना" (आईओडी) नामक एक पृथक मानकीकृत सूचनात्मक आउटपुट प्रारंभ किया गया है, जिसका उपयोग उन मामलों में किया जाएगा जहाँ देनदार डिफ़ाल्ट संबंधी सूचना का विवाद करता है।	सूचना उपयोगिताओं के अभिलेखों की विश्वसनीयता एवं साक्ष्यात्मक महत्त्व को सुदृढ़ करना तथा दिवाला समाधान प्रक्रिया में होने वाली विलंब की संभावना को कम करना।

VI. अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफ़एससीए)

दिनांक	विनियम	औचित्य
05 जनवरी 2026	**आईएफएससी में 'ऑयलफील्ड उपकरण' को वित्तीय उत्पाद के रूप में अधिसूचित करना:** प्राधिकरण (आईएफ़एससीए) ने आईएफएससीए अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "ऑयलफील्ड उपकरण" के संबंध में परिचालन लीज़ तथा परिचालन एवं वित्तीय लीज़ के किसी भी मिश्रित स्वरूप को वित्तीय उत्पाद के रूप में अधिसूचित किया है। "ऑयलफील्ड" एवं "ऑयलफील्ड उपकरण" की परिभाषा क्रमशः ऑयलफील्ड्स (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1948 तथा अधिसूचना संख्या 3/2017-केंद्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून 2017 (भाग II, अनुभाग 3, उप-अनुभाग (i), जीएआर 675ई के अंतर्गत) के अनुरूप होगी।	आईएफएससी के माध्यम से ऑयलफील्ड उपकरणों की लीजिंग को सुगम बनाना, जिससे भारतीय एवं वैश्विक संस्थाओं को तलीय एवं अपतटीय तेल उत्खनन सहित अन्य गतिविधियों के लिए ऐसे उपकरण लीज पर उपलब्ध हो सकें।
27 जनवरी 2026	**वेंचर कैपिटल योजनाओं एवं प्रतिबंधित योजनाओं के लिए निजी प्लेसमेंट ज्ञापन की वैधता बढ़ाने हेतु एकबारगी अवसर संबंधी परिपत्र:** आईएफएससीए ने एकबारगी उपाय के रूप में एफ़एमई को तीन माह की अवधि के भीतर उन वेंचर कैपिटल एवं प्रतिबंधित योजनाओं के निजी प्लेसमेंट ज्ञापनों (पीपीएम) की वैधता बढ़ाने का अवसर प्रदान किया है, जिनकी वैधता समाप्त हो चुकी है।	एफ़एमई को वेंचर कैपिटल एवं प्रतिबंधित योजनाओं के निजी प्लेसमेंट ज्ञापनों (पीपीएम) की वैधता में एकाधिक विस्तार प्राप्त करने हेतु लचीलापन प्रदान करना।